

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2016/फाल्गुन 25, 1937 No. 166] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2016/PHALGUNA 25, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

रक्षोपाय महानिदेशक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2016

(सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद कर)

विषय : "600 एमएम" या उससे अधिक की चौड़ाई के नॉन-अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के कॉइल्स में हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों" का भारत में आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच- अंतिम निष्कर्ष।

सा.का.नि. 308 (अ).—सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसके अंतर्गत बने सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997

क. प्रक्रिया:

- 1. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 (जिसे एतद्पश्चात "रक्षोपाय नियमावली" कहा गया है) के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष एक आवेदनपत्र मैसर्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड; मैसर्स एस्सर स्टील इंडिया लिमिटेड और मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड ने मैसर्स लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन अटार्नीज की मार्फत एक आवेदनपत्र "600 एमएम" या उससे अधिक की चौड़ाई के नॉन-अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के कॉइल्स में हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों" (जिसे एतद्पश्चात पीयूसी (विचाराधीन उत्पाद) कहा गया है) का भारत में आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की मांग करते हुए प्राप्त हुआ है। क्यों कि आयातों में यह वृद्धि घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित कर रही है अथवा गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर रही है।
- 2. बंतर्ग्रस्त उत्पाद: विचाराधीन उत्पाद "600 एमएम" या उससे अधिक की चौड़ाई के नॉन-अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के कॉइल्स में हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पाद" है, (जिन्हें एतद्पश्चात पीयूसी अथवा विचाराधीन उत्पाद कहा गया) और जिन्हें सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत प्रशुल्क शीर्षक संख्या 7208 और प्रशुल्क मद संख्या 72253090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि इन उत्पादों को और अधिक हाट रोल्ड नहीं किया जाता है और यह "ऐज रोल्ड" एज अथवा

1286 GI/2016 (1)

"ट्रिम्ड" एज अथवा "स्लिट" एज युक्त प्राइम अथवा गैर-प्राइम स्थिति में लोहा, अलॉय अथवा नॉन-अलॉय स्टील के फ्लैट उत्पाद हैं। यह उत्पाद (स्किन पास अथवा टेम्परिंग सहित अथवा उसके बिना) पिकॅल अथवा नॉन-पिकॅल स्लिट अथवा गैर-स्लिट के रूप में हो सकते हैं और उनकी 600 एमएम के बराबर अथवा उससे अधिक की नामिनल की चौड़ाई होती है। यह उत्पाद रोल्ड अथवा थर्मो-मैकेनिकली रोल्ड अथवा थर्मो-मैकेनिकली कंट्रोल्स रोल्ड अथवा कंट्रोल्ड रोल्ड हो सकते है। इन उत्पादों में रोलिंग से सीधे व्युत्पन्न रिलीफ में प्रतिकृतियां हो सकती है। इन उत्पादों की पिकलिंग, आयलिंग, रिवाइडिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि जैसे विभिन्न प्रसंसाधन प्रक्रिया हो सकती है।

इस विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है :

- (क) 600 एमएम से कम की मामूली सी चौड़ाई युक्त इस्पात के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद;
- (ख) एपीआई ग्रेड स्टील;
- (ग) सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील;
- (घ) स्प्रिंग स्टील क्वालिटी के इस्पात के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद;
- (ङ) इस्पात के ऐसे हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद जिनके ऊपर जस्ते की कोटिंग या इलेक्ट्रोलिटिकली प्लेटिंग की गई हैं;
- (च) जस्ता की अन्यथा कोटिंग अथवा प्लेटिंग किए हुए इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद।
- (छ) स्टेनलेस स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद।
- 3. उक्त रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों का स्थल दौरा करके आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया। इस सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में रखा गया। इस बाल से संतुष्ट होने पर कि नियम 5 के अंतर्गत अपेक्षाएं पूरी हो गई हैं। "600 एमएम" या उससे अधिक की चौड़ाई के नॉन-अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के कॉइल्स में हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पाद" का भारत में आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच शुरूआत का नोटिस सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन), नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत दिनांक 07 सितम्बर, 2015 को जारी किया गया और उसे उसी दिन भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित कराया गया।
- 4. दिनांक 07 सितम्बर, 2015 के इस जांच शुरूआत नोटिस की एक प्रति तथा घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति संबद्ध कार्य देखने वाले केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों को, प्रमुख निर्यातकर्ता देशों की सरकारों को उनके भारत स्थित राजदूतावासों के जरिए और अधोलिखित सूचीबद्ध हितबद्ध पक्षकारों को सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6(2) और 6(3) के अनुसार प्रेषित की गई। सभी घरेलू उत्पादकों, आयातकों और निर्यातकों को प्रश्नावलियां भी उसी दिन भेजी गई और उनसे, 30 दिनों के अंदर अपना उत्तर देने के लिए कहा गया।

4.1 घरेलू उत्पादक

- क. मैसर्स एस्सर स्टील इंडिया लिमिटेड
- ख. मैसर्स स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड
- ग. मैसर्स जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड
- घ. टाटा स्टील लिमिटेड, मुंबई
- ङ. मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, गुड़गांव
- च. मैसर्स भूषण स्टील लिमिटेड, नई दिल्ली

4.2 ज्ञात आयातक (मैसर्स):

- क. आल्स्टम इंडिया लिमिटेड, मुंबई
- ख. आर्सेलर नील टेलर्ड ब्लैंड प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- ग. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली
- घ. भिलाई इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भिलाई, छत्तीसगढ़
- ङ. सीआरआई पम्प्स प्राइवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर
- च. कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
- छ. डेनिस प्लास्ट लिमिटेड, गांधीनगर मेहसाणा, गुजरात

- ज. देस्मी इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटैड थाणे (पश्चिम) महाराष्ट्र
- झ. एस्कार्टस लिमिटेड, फरीदाबाद
- ञ. एक्सडी इंडिया लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
- ट. फाइन फोर्ज लिमिटेड, हैदराबाद
- ठ. फ्लाक्ट (इंडिया) लिमिटेड, चेन्नई
- ड. गमेसा विंड टर्बाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- ढ. गणपति इंटरप्राइजेज, जयपुर
- ण. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, डाकघर गांधीग्राम, विशाखापत्तनम
- त. हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, विक्रोली (पश्चिम) मुंबई
- थ. आईडीएल एक्सप्लोसिब्ज लिमिटेड, डाकघर कूकापट्टी, हैदराबाद
- द. आईएफबी आटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
- ध. जेबीएम इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली
- न. जेबीसी इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
- प. कलिंग फिक्शर्स लिमिटेड, परेल, मुंबई
- फ. कलतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, गांधीनगर, गुजरात
- ब. लारसेन एंड टुब्रो, मुंबई, महाराष्ट्र
- भ. लायड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई महाराष्ट्र
- म. मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
- य. एमपीपी टेक्नालोजीज प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर
- कक. एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद
- खख. नील मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली
- गग. ओरियंट इम्पेक्स, चेन्नई
- घघ. ओरियंट वीयरटेक, चेन्नई
- ड.ड. पीएंडएच जॉय माइनिंग इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, कोलकाता
- चच. पोस्को इलेक्ट्रिकल स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई
- छछ. रवि स्टील कंपनी अंधेरी (पूर्व) मुंबई
- जज. एस जी आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता
- झझ. शक्ति पम्पस इंडिया लिमिटेड, इंदौर
- **¥¥.** शेल्फ ड्रिलिंग आफ शोर सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, पवई, मुंबई
- टट. श्री चामुंडा इंटरप्राइजेज, नवी मुंबई
- ठठ. सुपीरियर स्टील इंडस्ट्रीज, मुंबई
- डड. ट्रांटेर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे
- ढढ. टीआरएफ लिमिटेड, जमशेदपुर
- णण. विराज इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई
- तत. विर्गो इंडस्ट्रीज, पंचकुला
- थथ वेल्स्पन कार्प लिमिटेड
- दद. वुडटूल्स मुंबई
- धध. यतिन स्टील्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई
- नन. वाईएसआई आटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
- पप. जाइफिक्स ट्रल्स प्राइवेटल लिमिटेड-2, बालानगर, हैदराबाद

4.3 ज्ञात निर्यातक (मैसर्स)

- क. निप्पन सुमिटोमा, जापान
- ख कोबे जापान
- ग. जेएफई स्टील कारपोरेशन, जापान

- घ. पोस्को कोरिया
- ङ. हुंडई स्टील कंपनी लिमिटेड, सियोल
- च. डांगकुक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड, सियोल
- छ. इलाईक आयरन एंड स्टील वर्क्स, उक्रैन
- ज. सिवरेस्टाल स्टील, बेलारूस
- झ. जैप्रोस्टाहल उक्रैन
- ञ. एज्वोस्टाह उक्रैन
- ट. एल्चेसेक उक्रैन
- ठ. मुबारकेह स्टील कंपनी, एस्फाहन
- ड. पीटी क्राकताऊ पोस्को स्टील, वर्क्स, इंडोनेशिया
- ढ. अर्सिलर मित्तल, लक्जेमबर्ग
- ण. दिलेन्गर एंड साल्जिटर, जर्मनी
- त. अर्सिलर मित्तल ब्राजील
- थ. रिझाऊ चीन
- द. बिताइ आयरन एंड स्टील, चीन
- ध. बाओतोऊ आयरन एंड स्टील ग्रुप, चीन
- न. जियांग्सु शागांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड, जियांग्शु प्राविन्स चीन जन गण.
- त. तोंग्हुआ आयरन स्टील ग्रुप कारपोरेशन, चीन
- प. आंगांग स्टील कंपनी, चीन
- फ. नान्जिंग आयरन एंड स्टील, नान्जिंग, चीन जनवादी गणराज्य
- ब. टंगशांग आयरन एंड स्टील, टांगशान, हीबेई
- भ. वुहाल आयरन एंड स्टील, चीन
- म. टियान्जिन आयरन एंड स्टील ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन

4.4 निर्यातकर्ता देशों की सरकार

- क. इंडोनेशिया का राजदूतावास
- ख. उक्रैन का राजदूतावास
- ग. रूसी परिसंघ का राजदूतावास
- घ. कोरिया गणराज्य का राजदूतावास
- ङ. चीन जनवादी गणराज्य का राजदूतावास
- च. जापान का राजदुतावास

5. निम्नलिखित पक्षकारों से यह अनुरोध प्राप्त हुआ कि उन्हें हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जाए।

- क. अर्सिलर मित्तल ब्राजील एसए ब्राजील
- ख. अर्सिलर मित्तल फ्लैट कार्बन यूरोप, एसएस लक्जमबर्ग
- ग. चीन आयरन एंड स्टील एसोसिएशन, चीन
- घ. कोर्समा, नई दिल्ली
- ङ. देवकी नंदन जे गुप्ता आयरन एंड स्टील मर्चेन्ट्स, मुंबई
- च. डैमसन्स मेटल प्राइवेट लिमिटेड अंधेरी (पश्चिम) मुंबई
- छ. ईईपीसी इंडिया, नई दिल्ली
- ज. ब्राजील का राजदूतावास, नई दिल्ली
- झ. तुर्की का राजदूतावास, नई दिल्ली
- ञ. भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व, नई दिल्ली
- ट. महाराष्ट्र एसोसिएशन परिसंघ (एफएएम)

- ठ. भारतीय उद्योग परिसंघ (एफआईआई), दिल्ली
- ड. हीरो स्टील लिमिटेड, हीरोनगर, लुधियाना
- ढ. होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर
- ण. हुंडई स्टील कंपनी, सियोल, कोरिया गणराज्य
- त. भारत में जापान वाणिज्य एंड उद्योग परिसंघ (जेसीसीआईआई), नई दिल्ली
- थ. जवाण्डामल छन्नामल आयरन एंड स्टील मर्चेंट्स, मुंबई
- द. जेएफई स्टील कारपोरेशन, जापान
- ध. कोबे स्टील लिमिटेड
- न. मैग्निटोगर्क्स आयरन एंड स्टील वर्क्स, किरोव स्ट्रीट, 93
- प. मैग्नम स्टील खार (पश्चिम) मुंबई
- फ. मानेकशा स्टील लिमिटेड, बीकानेर बिलिंडग, कोलकाता
- ब. मेटल वन कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- भ. आर्थिक विकास मंत्रालय, रूसी परिसंघ, नई दिल्ली
- म. उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, रूसी परिसंघ, नई दिल्ली
- य. मित्सुई एंड कपंनी लिमिटेड, जापान
- कक. मुद्रा फाइन ब्लैंड प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई
- खख. एनजोन स्ट्रिप्स लिमिटेड, कोलकाता
- गग. एनजोन ट्यूब्स लिमिटेड, कोलकाता
- घघ. निप्पन स्टील एंड सुमिकिन पाइप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नीयराना, जिला अलवर (राजस्थान)
- ड.ड. निप्पन स्टील एंड सुमिटोमा मेटल कारपोरेशन जापान
- चच. निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड, जापान
- छद. पोस्को इंडिया डेल्ही स्टील प्रासेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, रिवाड़ी
- जज. पोस्को इंटरनेशनल ट्रेड अफेयर्स ग्रुप, पोस्को सेंटर कोरिया
- झझ. पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड
- ¥¥. प्रभात स्टील ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
- टट. रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड, अहमदाबाद
- ठठ. आरकेबी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
- डड. आरएनवी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई
- ढढ. एसएम स्टील बोरिवली (पश्चिम) मुंबई
- णण. सेवरेस्टाल मैनेजमेंट, रसियन फेडरेशन, वोलोग्डा रेजिओ, चिरिपोवेट्स, मीरा स्ट्रीट, 30
- तत. श्री कृष्ण स्टील्स्स, कार्नेक बंदर, मुंबई
- थथ. एसएसजेड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जिला रायगढ़
- दद. स्टील इम एसोसिएशन आफ इंडिया, चैम्बूर, मुंबई
- घघ. दि बाम्बे आयरन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, कार्नेक बंदर, मुंबई
- नन. दि जापान आयरन एंड स्टील फेडरेशन, जापान
- पप. रूसी परिसंघ का व्यापार प्रतिनिधिमंडल. नई दिल्ली
- फफ. टीटी स्टील सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रामनगर, जिला विहारी
- बब. ट्यूब इन्वेस्टमेंट आफ इंडिया, चेन्नई
- भभ. तुराखिया फेरोमैट प्राइवेट लिमिटेड, कार्नेक बंदर, मस्जित (पूर्व), मुंबई
- मम. वी के इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कर्नेक बंदर, मुंबई
- यय. वान बैल एंड बेल्स, बेल्जियम (मेटिन्वेस्टमेंट होल्डिंग (3 उक्रैन) की ओर से)
- 6. उपर्युक्त सभी अनुरोध स्वीकार कर लिए गए। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने इस जांच शुरूआत नोटिस का प्रत्युत्तर दायर करने के लिए समय विस्तार करने का अनुरोध किया। उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें समय विस्तार दे दिया गया।

- 7. घरेलू उद्योग ने अपने दायर किए गए आवेदनपत्र में अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क लगाकर तत्काल अंतरिम राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है। इसके समर्थन में उन्होंने सूचीबद्ध आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर अपनी अनिश्चित स्थिति की ओर संकेत किया है जिसमें उनके द्वारा सामना की जा रही सम्बेदनशील परिस्थितियों की मौजूदगी का जिक्र है और उन्होंने अनुरोध किया है कि यदि अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण नहीं किया गया तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है।
- 8. अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध की जांच की गई और प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि ऐसी संवेदनशील परिस्थितियां मौजूद हैं जिनमें यह अधिपत्रित होता है कि अपूरणीय क्षति जिसमें सुधार किया जाना मुश्किल है, से ग्रस्त घरेलू उद्योग को अंतरिम राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना आवश्यक है।
- 9. तदनुसार, अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क के लिए प्रारंभिक जांच परिणाम सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 9(2) के अंतर्गत दिनांक 9 सितम्बर, 2015 को जारी किए गए और उन्हें उसी दिन अर्थात दिनांक 9 सितम्बर, 2015 को ही जीएसआर 690(ई) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया गया।
- 10. तदुपरांत वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 14 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या 02/2015-सीयूएस (एसजी) के तहत संबंधित अधिसूचना जारी करने की तारीख से 200 दिनों से अनधिक की अवधि के लिए 20 प्रतिशत की दर से रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करते हुए जारी की गई।
- 11. तत्पश्चात, 16 नवम्बर, 2015 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया। इस सार्वजनिक सुनवाई के समय हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग ने मौखिक प्रस्तुतिकरण किए। सीमाशुल्क प्रशुल्क (परिवर्ती उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क) नियमावली, 1997 के नियम 6 के उपनियम (6) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त अपने विचारें की लिखित अभिव्यक्ति भी करें।
- 12. एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण की प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण की प्रत्युक्ति, यदि कोई, दायर करने का अवसर भी प्रदान किया गया।
- 13. दिनांक 16 नवम्बर, 2015 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने लिखित प्रस्तुतिकरणों में अभिव्यक्त उनके सभी विचारों की जांच की गई और समुचित निर्धारण करते समय उन पर उचित ध्यान दिया गया। सूचना का अवाप्त अथवा प्राप्त अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में रखा गया।
- **ख. जांच शुरूआत के पश्चात किए गए प्रस्तुतिकरण** : जांच की शुरूआत के पश्चात परंतु सार्वजनिक सुनवाई से पहले किए गए प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं।

राजदूतावासों और देशों के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

I. रूसी परिसंघ का राजदूतावास और रूसी परिसंघ का व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय

- क. रूसी परिसंघ से भारत को इस वस्तु के निर्यात में भारी वृद्धि नहीं हुई है।
- ख. इसके अतिरिक्त, रूस से भारत को इस वस्तु का निर्यात भारतीय उत्पादकों को क्षति का कारण नहीं है।
- ग. रूसी परिसंघ की फेडरल एजेंसी से प्राप्त शासकीय आंकड़ों के अनुसार रूसी परिसंघ से इस वस्तु के निर्यात में गिरावट आई है।
- घ. विशेष रक्षोपाय जांच की शुरूआत करने के कारण पर्याप्त नहीं है और यह निम्नलिखित कारणों से अविश्वसनीय भी है :
 - कर्मचारियों की उपयुक्त संख्या और भारतीय घरेलू उद्योग की उत्पादकता के स्तर को संपूर्ण लोड क्षमता और पर्याप्त श्रमिक संसाधनों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है।
 - (ii) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में वृद्धि हुई है।
 - (iii) घरेलू उद्योग की मालसूची में हुई तीव्र बहुत अल्प (2-3 प्रतिशत) हैं।
 - (iv) भारत में इस वस्तु के आयातों की कुल मात्रा में रूसी परिसंघ से आयातों के अनुपात में गिरावट आई है।

- (v) रूस के विनिर्माताओं की बिक्री के हिस्से के कारण भारतीय बाजार बहुत कम प्रभाव पड़ा है।
- (vi) यह जांच रूसी परिसंघ पर कोई कार्रवाई किए बिना पूरी की जानी चाहिए।

इंडोनेशिया गणराज्य का राजदूतावास

- क. अर्जेन्टीना आयात फुटवीयर, डब्ल्यूटी/डीएस 121/आर में डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय रिपोर्ट के अनुसार रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 के आशय के अंतर्गत संवर्धित आयातों को गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों रूपों में "अभिनव, आकस्मिक, तीव्र एवं पर्याप्त" के रूप में परिभाषित किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आयातों की तुलना यह दर्शाती है कि आयातों में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों रूपों से कोई अभिनव, आकस्मिक, तीव्र एवं भारी वृद्धि नहीं हुई है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद के आयात वर्ष 2014-15 में 97 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) में 33 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 6 द्वारा यथापेक्षित अनन्तिम रक्षोपाय साधन का अधिरोपण करने के लिए संवेदनशील परिस्थितियां स्थापित करने का कोई वैध कारण नहीं है क्योंकि रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 के आशय के अंतर्गत कोई संवर्धित आयात नहीं हुए हैं।
- ग. यूएन कामट्रेड डाटा के अनुसार इंडोनेशिया से उदभवित इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों का हिस्सा वर्ष 2014 में 3 प्रतिशत से कम है। 7208 के सामान्य शीर्षक पर अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित है जिसमें "क्वाइल्स और प्लेट्स" दोनों शामिल हैं। इससे इंडोनेशिया के निर्यातकों को क्षति होगी क्योंकि इंडोनेशिया से इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों का हिसुसा 3 प्रतिशत से कम और वास्तव में भारत को समग्र विश्व के कुल आयातों की तुलना में केवल 0.75 प्रतिशत है।
- घ. इंडोनेशिया एक विकासशील देश है और इस विचाराधीन उत्पाद का निर्यातक है। तथापि, इंडोनेशिया से उदभवित विचाराधीन उत्पाद विशिष्ट प्रकार (क्वाइल्स और/अथवा हाट रोल्ड प्लेट में नहीं) का है और उसके आयातों का हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है। इसलिए इंडोनेशिया यह अनुरोध करता है कि उस पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से अपवर्जन कर दिया जाए।
- ड. पीटी कराकटाऊ पोस्को, इंडोनेशिया का एक निर्यातक, ने "क्वाइल और/अथवा हाट रोल्ड प्लेट में नहीं" के वर्गीकरण के अंतर्गत कतिपय उत्पादों का ही निर्यात किया है। प्राधिकारी को इस विचाराधीन उत्पाद के बारे में तत्काल एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए कि क्या "क्वाइल और प्लेट में नहीं" प्रकार को भी इस रक्षोपाय जांच में संबद्ध वस्तु के रूप में विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- च. चूंकि इंडोनेशिया में उदभवित "क्वाइल में और/अथवा प्लेट में नहीं" के वर्गीकरण के अंतर्गत भारत को इस विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात खासकर पीटी कराकटाऊ पोस्को से नहीं हुआ इसलिए इंडोनेशिया से भारत के घरेलू उद्योग को कोई क्षतिकारित नहीं हुई।
- छ. प्लेटों के कुल आयातों में इंडोनेशिया से आयातों का बाजार केवल 2 प्रतिशत है। इसलिए, इंडोनेशिया से आयात भारतीय घरेलू उद्योग का क्षति कारित नहीं कर सकते हैं।
- ज. हालांकि भारत ने वर्ष 2015 फ्लैट स्टील उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है फिर भी भारत में अधिकांश आयात, चीन को छोड़कर, भारत-आशियान एफटीए, भारत-जापान सीईपीए और भारत-कोरिया सीईपीए के अंतर्गत रियायती शुल्क पर किए जाते हैं।
- झ. अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना करार से संगत नहीं है और यह अनुरोध किया जाता है कि इंडोनेशिया को रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए।

।।।. कोरिया गणराज्य का राजदूतावास

- क. कोरिया से एचआर स्टील उत्पादों के आयातों के परिणामस्वरूप भारतीय घरेलू इस्पात उद्योग पर कोई ऋणात्मक प्रभाव, यदि कोई, नहीं होगा क्योंकि अधिकांश आयातित उत्पादों की खपत कोरियन कारपोरेशन में कच्चे माल के रूप में स्टील के उच्च गुणवत्ता वाले विशेष उत्पादों का उत्पादन करने के लिए भारत में आटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रयोग की जाती है।
- ख. कोरिया-भारत सीईपीए के अध्याय 2 (वस्तु व्यापार) की धारा ख-2 (व्यापार उपचार रक्षोपाय साधन) में यह विनिर्धारित है कि गाट 1994 के अनुच्छेद XIX और रक्षोपाय करार के अंतर्गत रक्षोपाय साधन प्रयोग करने वाला पक्षकार, डब्ल्युटीओ करार के अंतर्गत नैतिक दायित्व की संगत सीमा तक अन्य पक्षकार के यहां उदभवित वस्तु के आयातों का

अपवर्जन कर सकता है, यदि यह आयात पर्याप्त मात्रा में गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। कोरिया का विश्वास है कि कोरिया से आयातित एचआर स्टील उत्पाद इस खंड (क्लाज) के अध्यधीन है क्योंकि कोरिया से आयातों का निषेधात्मक प्रभाव भारतीय घरेलू बाजार में बहुत सीमित है।

- ग. कोरिया से एचआर स्टील उत्पादों के कोरिया कारपोरेशन के आयात "मेक इन इंडिया" में उनके योगदान के एक भाग के रूप में हैं क्योंकि वे भारतीय प्राधिकारियों को प्रदान करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले एचआर स्टील उत्पादों का उदाहरण के लिए, पोस्को महाराष्ट्र प्राइवेट लिमिटेड उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पादों, खासकर भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। एचआर स्टील का यह आयात अपरिहार्य है क्योंकि स्थानीय प्रापण बहुत सीमित है, उच्च गुणवत्ता वाली स्टील की मांग को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है और इसके प्रमुख ग्राहकों आटोमोबाइल उद्योग द्वारा इसकी भारी मांग की जाती है। कोरिया को डर है कि कोरिया से एचआर स्टील के आयातों पर रक्षोपाय साधन का अधिरोपण करने से भारत में उपभोक्ताओं और अनुप्रवाही उद्योग पर गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- घ. कोरिया कारपोरेशन की "मेक इन इंडिया" और "इन्वेस्ट इन इंडिया" का यथार्थ भागीदार होने और उसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए। भारत में एक प्रमुख कोरियाई कारपोरेशन के रूप में पोस्को ने 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का भारत में निवेश किया है और यह इस समय भारत में छह संयंत्र चल रहा है। पोस्को ने, विशेषत: भारत में अपनी एक अनुषंगी कंपनी (पोस्को महाराष्ट्र प्राइवेट लिमिटेड) के जरिए पोस्कों ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में 1.8 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले एक अनुप्रवाही स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा किया है जो विशेषकर भारत के आटोमोबाइल उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले इस्पात के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करता है।
- ङ. कोरिया से आयातों में वृद्धि और उस गंभीर क्षति, जिसका भारतीय उद्योग दावा करता है, के बीच कारणात्मक संबंध का अभाव है। यह कहना भी कठिन है कि आयातों में यह वृद्धि अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप हुई है।
- च. विश्व इस्पात की मौजूदा स्थिति और भारत में इस प्रश्नाधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि आयातों में वृद्धि का स्पष्टीकरण कर सकती है।
- छ. कोरिया से आयातित उत्पाद का अधिकांश भाग अनुप्रवाही उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से, पोस्को कोरिया द्वारा निर्यातित हॉट रोल्ड (एचआर) उत्पादों का 100 प्रतिशत भाग का प्रयोग भारतीय इस्पात मिलों में (अर्थात् पास्को-महाराष्ट्र) पुन: रोलिंग के लिए और पिकलिंग एवं आयलिंग (पीओ) के लिए प्रयोग किया जाता है। हुंडई स्टील कोरिया द्वारा निर्यातित स्टील का प्रयोग हुंडई मोटर्स इंडिया में मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में किया जाता है।
- ज. भारत में अनुप्रवाही उद्योगों, खासकर भारत के स्टील एवं आटोमोबाइल विनिर्माण उद्योगों के सार्वजनिक हित पर विचार करते हुए कोरियाई ईआईआरसी उत्पादों पर शुल्क उदग्रहण करना भारत के घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता है।
- झ. इस वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान संरक्षणवाद के निवारण करने के उद्देश्य से हम बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति अपनी वचनबद्धता का नवीकरण कर सकते हैं।

IV. सऊदी अरेबिया का शाही राजदूतावास

- क. भारत के वाणिज्य विभाग के निर्यात-आयात डाटाबैंक के अनुसार सऊदी अरेबिया साम्राज्य से इस विचाराधीन उत्पाद के आयात वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 (अप्रैल-जुलाई) की अवधि के दौरान भारत को हुए कुल आयातों का 3 प्रतिशत से भी कम है।
- ख. उन विकासशील देशों, जो डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं और जो इस संबद्ध उत्पाद के प्रमुख आपूर्तिकर्ता नहीं है, का आयात भारत को हुए कुल आयातों का 9 प्रतिशत से भी कम है।
- ग. चूंकि सऊदी अरेबिया साम्राज्य डब्ल्यूटीओ का सदस्य एक विकासशील देश है, इसलिए इसके निर्यातों को किसी भी रक्षोपाय साधन जिसका भारत रक्षोपाय जांच में इस संबद्ध उत्पाद के आयातों पर अधिरोपण करने का विचार करता है के दायरे से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए।
- घ. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 के अंतर्गत प्रतिबद्धता के अनुरूप सऊदी अरेबिया साम्राज्य से होने वाले आयातों पर उस रक्षोपाय साधन का अधिरोपण करने से अपवर्जित कर सकता है जिन्हें भारत को इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर अधिरोपित करने पर विचार है।

V. यूरोपियन यूनियन

क. रक्षोपाय साधन का प्रयोग केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। जब आयात एक या कई स्रोतों से हो रहे हों तो पाटनरोधी या सब्सिडीरोधी साधन, जो इन विशिष्ट देशों से अनुचित व्यवहार को लक्षित करते हैं, का प्रयोग किया जाना चाहिए जो अधिक कारगर होंगे। दूसरी ओर रक्षोपाय साधन, चूंकि इनका प्रयोग सभी स्रोतों से आयातों पर समान रूप से किया जाता है, कभी कभार ऐसी वैध बाजार पहुंच को सीमित कर देते हैं, जो क्षति कारित नहीं कर रहे होते हैं।

संवर्धित आयात

- ख. हालांकि आयातों में समग्र वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग द्वारा आयातों में विभंग का प्रावधान प्रारंभिक जांच परिणाम में नहीं किया गया है। तथापि, अनपेक्षित विकास के संबंध में चीन, रूस और उक्रैन जैसे स्रोतों का उल्लेख नहीं है। ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार ऐसे मामले में जहां आयातों में वृद्धि मुख्यत: एक या कई स्रोतों से होती है वहां पाटनरोधी या सब्सिडीरोधी साधन अधिक उपयुक्त होंगे।
- ग. आयोग से उपलब्ध सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग एचएस कोड 72253090,720 82590 और 72082790 के अंतर्गत आने वाले ग्रेडों का उत्पादन नहीं करता है। यदि यह सम्पुष्ठ है कि घरेलू उद्योग उत्पादन नहीं करता है तो इन ग्रेडों को इस उत्पाद के दायरे से अपवर्जित रखना चाहिए क्योंकि यह निष्कर्ष निकालना असंभव होगा कि इन ग्रेडों के कारण कोई क्षित हुई है। इन ग्रेडों पर लगाया गया कोई साधन अनुप्रवाही उद्योग को खासकर ऑटोमोटिव अंतिम प्रयोक्ता के अनिधकृत रूप में क्षिति पहुंचाएगा क्योंकि उन्हें कम विकल्प, न्यूनतर क्वालिटी और/या उच्चतर कीमतों का सामना करना पड़ेगा।

क्षति एवं कारणात्मक

- घ. वर्ष 2015-16 के आंकड़ों का, केवल पहली तिमाही के आंकड़ों के आधार पर बहिर्वेशन किया है। इस क्रियापद्धति से पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष निकलेंगे। उद्देश्यपरक विश्लेषण वास्तविक आंकड़ों का प्रयोग करके तुलनात्मक अवधि पर आधारित होना चाहिए। कम से कम द्वितीय तिमाही के वास्तविक आंकड़ों को तो शामिल किया जाना चाहिए था।
- ङ. वार्षिकीकृत आंकड़ों पर विचार करते हुए भी क्षति की स्थिति निर्णायक नहीं है। अधिकांश क्षति संकेतक जैसे उत्पादन, बिक्री, क्षमता, क्षमता उपयोग दर, मालूसची, रोजगार अथवा उत्पादकता स्थिर बनी रही।
- च. यद्यपि समान अवधि में मांग में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि के आलोक में बाजार हिस्से में 8 प्रतिशत की कमी आई फिर भी शिकायतकर्ता और अन्य भारतीय उत्पादकों का कुल मिलाकर हिस्सा अभी भी 88 प्रतिशत है।
- छ. लाभ हानि में परिवर्तित हो गया, परंतु ऐसा वर्ष 2015-16 की केवल पहली तिमाही में ही हुआ। विभिन्न तालिकाओं में लाभप्रदता के आंकड़े अलग-अलग हैं जो अनुक्रमणिकाकरण और संदर्भ के रूप में विभिन्न आधारों पर प्रयोग करने के कारण हो सकता है, परंतु इससे हितबद्ध पक्षकारों को हालात की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त नहीं होती है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- ज. उपर्युक्त के मद्देनजर यह तर्क देना मुश्किल है कि घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति उठानी पड़ रही है।
- झ. यह स्पष्ट करना कठिन है कि जब अधोरदन बहुत अधिक है, और सभी संकेतक स्थिर बने हुए है फिर घरेलू उद्योग का लाभ इतना अधिक कैसे है और इसमें निरंतर वृद्धि कैसे हो रही है।
- ञ. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अन्य कारक भी हैं जिनका भी घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। दुर्भाग्यवश, प्रारंभिक रिपोर्ट में अन्य कारकों से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(क) के अनुसार अन्य कारकों जैसे ग्राही बिक्री में वृद्धि और अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा बिक्री की भी जांच की जानी चाहिए।
- ट. हालांकि इस संपूर्ण अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री स्थिर बनी रही जबकि इसकी ग्राही बिक्रियों में 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इस बात की पुन: जांच करने की जरूरत है कि खासकर इस कारण की कि घरेलू उद्योग ने खुले बाजार में बिक्री करने के बजाय ग्राही बिक्री अधिक करने का निश्चय क्यों किया।
- ठ. एक महत्वपूर्ण तत्व जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि भारतीय उत्पादकों ने अपनी ग्राही बिक्री में न केवल 18 प्रतिशत की वृद्धि की है बल्कि उन्होंने खुला बाजार में भी अपनी बिक्री में 42 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसलिए, घरेलू उद्योग की स्थिति पर स्थानीय प्रतिस्पर्धा के प्रभाव का विश्लेषण करना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

- ड. निम्नलिखित मुद्दों का विश्लेषण करना अधिदेशित है:
 - (i) घरेलू उद्योग की स्थिति में लंबी अवधि तक विकास
 - (ii) खासकर घरेलू उद्योग के निष्पादन, घरेलू उद्योग की ग्राही बिक्रियों तथा अन्य भारतीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा जैसे अन्य कारकों का विश्लेषण करना अपेक्षित है।
 - (iii) जांच का दायरा और खासकर उन उत्पादों के बारे में जिनका भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है।

VI. तुर्की गणराज्य

- क. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 में यह प्रावधान है कि कोई डब्ल्यूटीओ सदस्य किसी विकासशील देश पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण तब तक नहीं कर सकता है जब तक संबद्ध उत्पाद के आयातकर्ता सदस्यों में उसके आयात का हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाता है बशर्ते कि 3 प्रतिशत से कम का आयात करने वाले विकासशील सदस्य देशों का सामूहिक रूप से कुल आयात संबद्ध उत्पाद के कुल आयातों का 9 प्रतिशत से अधिक न हो।
- ख. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की सांख्यिकी के अनुसार भारत की इस संबद्ध वस्तु के आयात में तुर्की के व्यक्तिगत आयातों का हिस्सा 3 प्रतिशत के स्तर से कम है (वर्ष 2011 में 0.18 प्रतिशत, वर्ष 2012 में 0.59 प्रतिशत, वर्ष 2013 में 0 प्रतिशत और वर्ष 2014 में 1.05 प्रतिशत है)। इसके अतिरिक्त, 3 प्रतिशत से कम के अनुपात युक्त विकासशील देशों के आयातों का सामूहिक हिस्सा इस विचाराधीन उत्पाद के भारत में हुए कुल आयातों का 9 प्रतिशत से बहुत कम है।
- ग. भारत में तुर्की से इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों के नगण्य स्तर के आलोक में भारत को चाहिए कि वह किसी संभावित रक्षोपाय साधन का प्रयोग करने से तुर्की का अपवर्जन कर दे।

उत्पादकों/निर्यातकों और एसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुतिकरण

VII. मेटिन्वेस्ट ग्रुप जिसका प्रतिनिधित्व वान बाइल एंड बेल्लस ने किया: मेटिन्वेस्ट ग्रुप स्टील एवं माइनिंग कंपनियों का एक उर्ध्वाधर रूप से समाकलित ग्रुप है जो लौह अयस्क और कोयले के उत्खनन और प्रसंस्करण से लेकर अर्ध-परिष्कृत और परिष्कृत इस्पात उत्पादों को बनाने एवं उसकी बिक्री करने की मूल्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी का प्रबंधन करता है। इसकी उक्रैन, यूरोप और यूएस में स्टील एवं खनन (माइनिंग) उत्पादन की सुविधाएं हैं और विश्व की सभी प्रमुख बाजारों में इसका बिक्री नेटवर्क है। मेटिन्वेस्ट ग्रुप इस्पात के अर्ध-परिष्कृत एवं परिष्कृत उत्पादों की एक विविधीकृत श्रृंखला का उत्पादन करता है जिनमें स्लैब्स, बिलेट्स, हाट रोल्ड प्लेट्स, हाट रोल्ड कॉइल्स, शेप्स एवं बार्स, रेल्स, ग्राइडिंग बाल्स, रेल फॉस्नर्स और बड़े व्यास के पाइप शामिल हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया है:

क. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण वार्षिकीकृत आंकड़ों पर आधारित नहीं हो सकता है :

- (i) एएस के अनुच्छेद 3.1 के अंतिम वाक्य में यह प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी के जांच परिणाम "तथ्यों एवं विधि के संगत मुद्दों" के अनुरूप हो। यूएस-लैम्ब में अपीलीय निकाय ने इस संबंध में यह उल्लेख किया है कि "चूंकि तथ्य, जो अपनी प्रकृति के अनुरूप वर्तमान और विगत से संबंधित है, इसलिए भविष्य की घटनाओं के लिए इन तथ्यों द्वारा निर्णायक रूप से कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।"
- (ii) वार्षिकीकरण में ऐसे चर का गणितीय परिकलन करना होता है जो उस चर का वार्षिक आधार पर मूल्य प्रदर्शित करता हो। इसलिए यह विगत के आधार पर भविष्य के मान का एक प्रक्षेपण मात्र ही है। यह प्रक्षेपण कभी भी ऐसा तथ्य नहीं माना जा सकता है जिस पर कोई जांचकर्ता प्राधिकारी अपना निर्णय स्थापित कर सकता हो, खासकर तब जबिक उक्त वार्षिकीकरण वित्त वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही के आंकड़ों पर ही आधारित हो।
- (iii) एएस का अनुच्छेद 4.1(ख), विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के संबंध में भी "भविष्योन्मुखी" निर्धारण, कि उसकी मौजूदगी है, भी "अभिकथन, अटकलबाजी अथवा दूर की संभावना" पर आधारित नहीं हो सकता है।
- (iv) इसके अतिरिक्त, अर्जेन्टीना-फुटवीयर में अपीलीय निकाय ने जोर दिया कि जांच की अवधि "(......) अभिनव विगत होना चाहिए।" यद्यपि यह तर्क नहीं दिया गया कि जांचकर्ता प्राधिकारी अत्यधिक अभिनव अवधि के आयात आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि यह आंकड़े अभिनव विगत के हो और इनमें भविष्य का प्रक्षेपण न किया गया हों।

ख. अनपेक्षित विकास का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है अथवा संगत गाट 1994 के दायित्वों का कोई प्रभाव नहीं है

(i) "अनपेक्षित विकास" और गाट 1994 के अनुच्छेद XIX : 1(क) में गाट 1994 के नैतिक दायित्वों का प्रभाव दोनों ऐसी परिस्थितियां है जिन्हें गाट 1994 के अनुच्छेद XIX के प्रावधानों से संगतरूप से रक्षोपाय शुल्क लागू करने के उद्देश्य से "तथ्य के रूप में" प्रदर्शित किया जाना चाहिए। वे "पूर्विपक्षाएं" हैं।

- (ii) इसके परिणामस्वरूप, गाट अनुच्छेद XIX : 1(क) के प्रथम खंड क पाठ में ऐसी अप्रत्याशित तथ्यात्मक परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके कारण क्षतिकारित करने वाले आयातों में वृद्धि हुई है और उसमें इन परिस्थितियों तथा क्षति कारित करने वाले आयातों में अनुवर्ती वृद्धि के बीच तर्कसंगत संबंध अभिव्यक्त किया गया है।
- (iii) प्रारंभिक निर्धारण में सामान्य रूप से स्टील सेक्टर के संबंध में कितपय विकास और विशिष्ट निर्यातक देशों से संबंधित कई विकासों के संबंध में एक तथ्यात्मक विवरण है। यह विकास कमोबेश रूप से आवेदन पत्र के "उन कारकों के संबंध में जो संवर्धित आयातों के लिए उत्तरदायी है" खंड को अतिच्छादित करता है।
- (iv) इस संपूर्ण वर्णित विकास में केंद्र बिंदु यह है कि (i) रूस, उक्रैन और चीन जनवादी गणराज्य ("चीन") की क्षमता और (ii) यूएस एवं ईयु में मांग में कमी हुई है और यह कि (iii) परिणामी बेशी क्षमता को प्राथमिकता भारत को विपथित कर दिया गया।
- (v) प्रारंभिक निर्धारण के जांच परिणाम के विपरीत यह उल्लेख करते हुए कि संयुक्त राज्य और यूरोपियन यूनियन ने आयातित स्टील पर अपनी निर्भरता कम कर दी है", मेटिन्वेस्ट द्वारा दी गई सूचना से ऐसा प्रतीत होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में वर्ष 2013 और 2014 के बीच इस्पात की खपत में वृद्धि हुई है।
- (vi) इसके अतिरिक्त, इस जांच परिणाम के विपरीत कि "स्टील की कीमतों को कम करने और अपनी बेशी स्टील को उन देशों को विपथित करने, जहां इसकी अच्छी मांग है, के अभियान में उक्रैन भी रूस और चीन जन गण. के साथ हो गया है। मेटिन्वेस्ट द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना अभिव्यक्त करती है कि इस संबंधित उत्पाद के उक्रैन से होने वाले आयातों 50 प्रतिशत तक कमी आई है।
- (vii) इस बात की कल्पना करते हुए भी कि प्रारंभिक निर्धारण में प्रदान कराया गया तथ्यात्मक विश्लेषण सही है, प्रारंभिक निर्धारण उपरिवर्णित विधिक अपेक्षाओं से असंगत ही रहता है।
- (viii) प्रथम, प्रारंभिक निर्धारण में वर्णित घटना यह बिल्कुल भी सिद्ध नहीं करती है कि उन्होंने संबंधित घरेलू उत्पाद तथा संबद्ध आयातित उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धात्मक संबंध किस तरह से परिवर्तित किए हैं। किसी भी ऐसी घटना का जिक्र नहीं किया गया है जो यह स्पष्ट कर सके कि संबद्ध उत्पाद के आयातों ने वह आधार कैसे प्राप्त कर लिया है संबद्ध घरेलू उत्पाद के विपरीत था।
- (ix) द्वितीय, यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रारंभिक निर्धारण में वर्णित विकास का लेखा में प्रतिस्पर्धात्मक संबंधों में परिवर्तन से संबंधित स्पष्टीकरण का उल्लेख है, फिर भी प्रारंभिक निर्धारण में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि यह विकास अप्रत्याशित विकास क्यों है। प्रारंभिक निर्धारण में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटित हुई जिसके कारण आयातों में वृद्धि हुई।
- (x) तृतीय, जांचकर्ता प्राधिकारी इस विकास एवं संवर्धित आयातों के बीच कोई तर्कसंगत संबंध स्थापित करने में असफल रहा। केवल यह उल्लेख किया गया कि बेहतर मांग प्रत्याशा (घरेलू मांग में 3.1 तक वृद्धि हुई) और उच्च घरेलू कीमतों के कारण भारत बेशी इस्पात की इन अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपनी बेशी क्षमताओं का सरलीकरण करने के लिए एक आकर्षक देश रहा है। यह वाक्य केवल यह संकेत देता है कि भारत आयातकों को अपनी ओर आकृष्ट करता रहा है, परंतु यह इस तथ्य को स्पष्ट नहीं करता है कि इस विकास से घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धात्मक संबंधों में परिवर्तन कैसे आया।
- (xi) इसलिए, अनपेक्षित विकास के प्रति जांचकर्ता प्राधिकारी का निर्धारण मुख्यत: त्रुटिपूर्ण है और यह डब्ल्यूटीओ की अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है।
- (xii) प्रारंभिक निर्धारण से यह स्पष्ट है कि जांचकर्ता प्राधिकारी ने रक्षोपाय करार और गाट, 1994 के अनुच्छेद XIX के अनुसार गाट, 1994 के अंतर्गत इस उत्पाद के संबंध में नैतिक दायित्वों (उदाहरणार्थ प्रशुल्क रियायतों) का अभिज्ञान नहीं किया है जिसका यह प्रभाव रहा है कि भारत को "अनपेक्षित विकास" अर्थात जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को इन आयातों के कारण भारी क्षति हुई, द्वारा जनित परिस्थितियों ने इस परिवर्तन को निवारित करने के लिए आवश्यक उपाय करने से प्रतिवारित कर दिया। वास्तव में, अपीलीय निकाय द्वारा किए गए उल्लेख के अनुरूप यह अनुच्छेद XIX :1(क) के प्रथम खंड में शामिल "परिस्थितिकी" में से एक है जिसे "एक तथ्य के रूप में वर्णित" किया जाना चाहिए।
- (xiii) इसके अतिरिक्त, मेटिन्वेस्ट जांचकर्ता प्राधिकारी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता है कि अनुच्छेद XIX :1(क) में प्रावधान है कि आयातों में यह वृद्धि गाट, 1994 के अंतर्गत सदस्य द्वारा उपगत प्रतिबद्धताओं के प्रभाव के "परिणामस्वरूप" हुई हो। तथापि, प्रारंभिक निर्धारण में गाट 1994 के अंतर्गत उपचित दायित्वों की कोई पहचान करने में न केवल असफल रहता है बिल्क इसमें किसी ऐसे "तर्कसंगत एवं उपयुक्त स्पष्टीकरण" का अभाव भी है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि इन दायित्वों के प्रभाव के परिणामस्वरूप इस उत्पाद का आयात इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी स्थितियों के अंतर्गत कैसे होने लगा जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने लगी अथवा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई। प्रारंभिक निर्धारण यह स्पष्ट करने में असफल रहता है कि इन दायित्वों के कारण भारत ऐसे उपाय जैसे आयात शुल्क में वृद्धि करने में प्रतिवारित क्यों रहा जिससे भारत आयातित और घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक संबंध में "अनपेक्षित विकास" द्वारा सृजित परिवर्तन को निवारित करने अथवा उसका कोई ऐसा समाधान निकालने में असफलत रहा जिससे वह पूर्व में मौजूद प्रतिस्पर्धी स्थिति की पुनर्बहाली कर पाता। इस स्पष्टीकरण द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए था कि इस मुद्दे में रक्षोपाय साधन के अंतर्गत

- अतिरिक्त शुल्क का अधिरोपण करना क्यों आवश्यक है; जहां यह निदर्शित किया गया कि अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप आयातों में इतनी अधिक वद्धि हुई कि उससे घरेल उत्पादकों को गंभीर क्षति होने लगी।
- (xiv) यह तथ्य कि "यह ज्ञात है अथवा जानने योग्य है" कि भारत ने जब डब्ल्यूटीओ की सदस्यता ग्रहण की तब उसने इस संबद्ध उत्पाद के संबंध में प्रशुल्क रियायतें प्रदान कीं परंतु इससे जांचकर्ता प्राधिकारी को ऊपर उल्लिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करने से छूट प्राप्त नहीं हो जाती है।
- (xv) स्पष्टत:, गाट 1994 के अंतर्गत उपचित दायित्वों के प्रभाव का उल्लेख करने की असफलता इस प्रारंभिक निर्धारण को डब्ल्यूटीओ विधि से असंगत बना देती है।

ग. संवर्धित आयातों का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है

- (i) वर्तमान मामले में, जांकर्ता प्राधिकारी ने इस प्रारंभिक निर्धारण में वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 (वार्षिकीकृत) के लिए समग्र एवं संगत आयात आंकड़ों की एक तालिका प्रदान कर दी है।
- (ii) इसके परिणामस्वरूप, जांचकर्ता प्राधिकारी ने यह निर्धारण करने के लिए कि इस संबद्ध उत्पाद के आयातों ने "निर्दूद रूप से और संगत रूप से बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है" अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु विश्लेषण किया अर्थात उसने एक ओर वित्तीय वर्ष 2013-14 के बीच तुलना में है और दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 (वार्षिकीकृत) के बीच तुलना की है।
- (iii) प्रथमतः, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयातों में समग्र रूप से बढ़ने की कोई प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं हुई है। अपीलीय निकाय द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु विश्लेषण अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013-14 और वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 (वार्षिकीकृत) के बीच तुलना करना कोई ऐसा विश्लेषण नहीं है जो रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 तथा गाट, 1994 के अनुच्छेद XIX: 1(क) के अंतर्गत जरूरतों के अनुरूप हो।
- (iv) यदि यह विश्लेषण रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 और गाट 1994 के अनुच्छेद XIX : 1(क) के अनुरूप किया गया है तो अधोलिखित ग्राफ 1 से यह प्रतीत होता है कि आयातों में घटने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2013-14 तक इस संबद्ध उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से लगभग 42 प्रतिशत की कमी आई है।
- (v) इन आंकड़ों से यह निदर्शित होता है कि वित्त वर्ष 2013-14 और वित्त वर्ष 2014-15 के बीच आयातों में यह वृद्धि लगभग उसी स्तर की है जिस स्तर की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2011-12 में हुई थी। इसलिए, इस संबद्ध उत्पाद के आयातों की प्रवृत्ति को इस रूप में अच्छी तरह से बताया जा सकता था कि पहले आयातों में भारी कमी हुई फिर आयात स्तर में कुछ सुधार हुआ जिसका स्तर आयातों में गिरावट के स्तर से पहले के स्तर के तुलनीय था।
- (vi) आयातों में संगत रूप से तथाकथित वृद्धि के संबंध में गिरावट की स्पष्ट प्रवृत्ति और भी अधिक स्पष्ट है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल घरेलू उत्पाद में आयातों का हिस्सा 11 प्रतिशत था वहीं इसमें वित्तीय वर्ष 2013-14 में केवल 5 प्रतिशत की गिरावट आई। यद्यपि कुल घरेलू उत्पादन में आयातों का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2014-15 में वास्तव में 10 प्रतिशत बढ़ा परंतु आयातों का यह भाग वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयातों के हिस्से से अभी भी कम है।
- (vii) वित्तीय वर्ष 2013-14 ओर 2014-15 के बीच आयातों में वृद्धि बहुत अधिक नहीं थी क्योंकि यह आयात वित्तीय वर्ष 2011-12 के आयातों के लगभग समान स्तर पर थे।
- (viii) इसके अतिरिक्त, दो लगातार वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2013-14 के बीच आयातों में भारी गिरावट के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 के बीच आयातों में हुई वृद्धि के संबंध में यह नहीं माना जा सकता है कि यह वृद्धि पूर्णतया अप्रत्याशित वृद्धि है। इसलिए यह वृद्धि "अचानक" नहीं हुई है।
- (ix) इसके अतिरिक्त, इन आयातों को अत्यधिक "तीव्र" आयात भी नहीं कहा जा सकता है। इस बात पर बल दिया जा सकता है कि इस तथ्य का आकलन भी विगत के संदर्भ में आलोक में किया जाना चाहिए।
- (x) आयातों में ऐसी वृद्धि के अभाव में जो तीव्र, अचानक एवं पर्याप्त मात्रा में हुई हो जैसा कि रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 और गाट 1994 के अनुच्छेद XIX : 1(क) के अनुसरण में होनी चाहिए, इस अनन्तिम शुल्क का अधिरोपण करना पूर्णतया विधि विरुद्ध है। आयातों में यह वृद्धि अनपेक्षित भी नहीं है।

घ. ऐसी कोई संवेदनशील परिस्थितियां नहीं थीं जिनसे प्रारंभिक रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग करना न्यायोचित ठहरता हो

(i) "संवेदनशील परिस्थितियों" की संकल्पना को रक्षोपाय करार में परिभाषित नहीं किया गया है। संवेदनशील का आशय है" वह परिस्थितियां जिनकी यह संभावना हों कि वे संकट के एक खास बिंदु पर पहुंचकर अनर्थकारी हो सकती हैं"। इसलिए इन परिस्थितियों में इस आशय के अंतर्गत अनर्थकारी होने की संभावना हो कि "एक ऐसी क्षति का जोखिम है जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल हो। क्षति का आशय है "ऐसी भौतिक क्षति जो किसी वस्तु के मूल्य, उपभोगिता अथवा उसके सामान्य कार्य को क्षीण करती हो" अथवा जिसका "अनर्थकारी प्रभाव" हो। "क्षति की यह संकल्पना जिसकी भरपाई करना मुश्कितल हो," यह सुझाव देती है कि यह "परिस्थितियां" ऐसी हों जिसमें किसी ऐसे अनर्थकारी प्रभाव से बचने के लिए, जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल हो, अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क के रूप में तुरंत हस्तक्षेप किया जाना अधिपत्रित हो।

- (ii) इसलिए, "संवेदनशील परिस्थितियां" और "ऐसी क्षति जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो" से तात्कालिकता को एक निश्चित भावना का उल्लेख मिलता है। वास्तव में, इस क्षति का वास्तविकीकरण ऐसी दर पर होना चाहिए जिसका हल एक निर्णायक रक्षोपाय साधन से किसी निश्चित समय पर नहीं निकाला जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप "ऐसी क्षति की संकल्पना जिसकी भरपाई कर पाना मुश्कित हो" संभवत: उन परिस्थितियों की ओर संकेत करता है जो इतनी संवेदनशील हों जिससे घरेलू उद्योग को पूर्णतया या आंशिक रूप से समाप्त हो जाने का जोखिम हो।
- (iii) यह कल्पना की जा सकती है कि "संवेदनशील परिस्थितियां और "क्षिति जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल हो" रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.1 के आशय के अंतर्गत "गंभीर क्षिति" अथवा "गंभीर क्षिति की चुनौती" के समकक्ष नहीं है क्योंकि रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 6 में इन संकल्पनाओं का समावेशन करना अन्यथा निरर्थक हो जाएगा। इसलिए "संवेदनशील परिस्थितियां" और "क्षिति जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो" ऐसी शर्ते हैं जो गंभीर क्षिति अथवा गंभीर क्षित की चुनौती की शर्तों के अतिरिक्त हैं और अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना न्यायोचित ठहराने के लिए इन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है।
- (iv) रक्षोपाय करार में किए गए उल्लेख और उसकी स्कीम के विपरीत प्रारंभिक निर्धारण "गंभीर क्षति" और "गंभीर क्षति की चुनौती " को "संवेदनशील परिस्थितियों" में साम्य स्थापित करते हुए प्रतीत होता है, जहां विलंब से ऐसी क्षतिकारित हो सकती है जिसका समाधान करना मुश्किल होगा।
- (v) इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक जांच परिणाम "किसी ऐसी क्षित को अभिज्ञात करने में असफल हो गया जिसकी भरपाई करना मुश्किल है"। यह आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि कोई ऐसी क्षित हुई ही नहीं जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो। आवेदन के संपूर्ण आंकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर उल्लिखित आंकड़ों के चुनिंदा प्रयोग से घरेलू उद्योग की स्थिति की अयथार्थ तस्वीर प्रदान की गई है क्योंकि आवेदकों पर किसी अनर्थकारी प्रभाव से संबंधित अधिकांश कारकों में ऐसे परिवर्तन हुए जो महत्वपूर्ण नहीं है अथवा जो स्थिर बन रहे।
 - आवेदकों का बाजार हिस्सा वित्तीय वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में अभी भी 58 प्रतिशत है ओर आयातों का बाजार हिस्सा केवल 16 प्रतिशत है।
 - वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में आयातों में तथाकथित वृद्धि के बावजूद, 4 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।
 - क्षमता उपयोग जो वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में 77 प्रतिशत था, घटकर वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में 76 प्रतिशत हो गया।
 - o वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही और वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में उत्पादन में केवल 2 प्रतिशत गिरावट
 - आवेदकों की बिक्री में वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही और वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही के बीच 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- (vi) ऊपर उल्लिखित आंकड़े बिना किसी त्रुटि के यह संकेत देते हैं कि ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं रहीं जिनके "अनर्थकारी होने की संभावना हो" और आयातों में इस आरोपित वृद्धि का घरेलु उद्योग पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा हो।
- (vii) इसलिए, यह असंदिग्ध रूप से स्पष्ट है कि "संवेदनशील परिस्थितियों की ऐसी क्षति, जहां विलंब से ऐसी क्षति कारित होगी जिसकी भरपाई होना मुश्किल है" को पूरा नहीं किया गया और इसके परिणामस्वरूप अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से डब्ल्यूटीओ विधि का सुस्पष्ट रूप से उल्लंघन होता है।
- ड. इस अनन्तिम निर्णय के विपरीत आवेदकों को न तो कोई गंभीर क्षति हुई और न ही गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हुई :
- (i) अन्य कारकों के साथ-साथ, प्रारंभिक निर्धारण में निम्नलिखित क्षति कारकों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा सकारात्मक (अथवा फ्लैट) निष्पादन रिपोर्ट किया गया :
 - उत्पादन
 - उत्पादकता

- रोजगार
- क्षमता उपयोग
- मालसूची
- (ii) इसके साथ ही, संवर्धित आयातों के अलावा वे कारक निम्नलिखित हैं जिनके लिए जांचकर्ता प्राधिकारी ने विपरीत प्रवृत्ति पाई है (1) घरेलु उत्पादकों का बाजार हिस्सा; (2) लाभ/हानि; और (3) कीमत अवमंदन।
- (iii) बाजार हिस्सा : यदि कोई, जांच की अधिक संगत अवधि, संपूर्ण अवधि के दौरान बाजार हिस्से पर विचार करता है तो वह नोट करेगा कि आयातों का बाजार हिस्सा करता है तो वह नोट करेगा कि आयातों का बाजार हिस्सा, जो वर्ष 2011-12 में 1.1 प्रतिशत था मामूली सा घटकर वर्ष 2014-15 में 10 प्रतिशत रह गया। एक अन्य तथ्य जो महत्वपूर्ण है, वह यह है कि उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा लगभग समान ही बना रहा और यह वर्ष 2011-12 में 40 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014-15 में 39 प्रतिशत रह गया।
- लाभ/हानि : प्रारंभ में यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रारंभिक निर्धारण में आवेदनपत्र में उल्लिखित सुचा का यह उल्लेख है कि (iv) घरेलु उद्योग की लाभप्रदत्ता में "वर्ष 2015-16 (प्रथम तिमाही) में तीव्र गिरावट आई ओर घरेलु उद्योग को क्षति हुई।" इसके साथ ही साथ, लाभप्रदता पर निष्कर्ष में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जांच की अवधि के दौरान अर्थात वर्ष 2013-14 और 2014-15 के बीच, घरेलू उद्योग के लाभ के स्तर में वृद्धि हुई और यह 35 प्रतिशत तक हो गया। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2013-14 की तुलना में लाभप्रदता में -55 (अनुक्रमित) में गिरावट केवल वर्ष 2015 की पहली तिमाही में आई है। इसके अलावा, घरेलु उद्योग की लाभप्रदता के संबंध में जांचकर्ता प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के बावजूद जेएसडबल्यु स्टील लिमिटेड और एस्सर स्टील इंडिया लिमिटेड ने स्वयं यह रिपोर्ट दी है कि उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है, खासकर घरेलु बाजार के संबंध में। यद्यपि, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस संबंधित अवधि के दौरान ऋणत्मक लाभप्रदता की सुचना दी हैं, फिर भी इसमें इसके लिए तृतीय देशों से आयातों के अलावा अन्य कारकों को उत्तरदायी माना है। अन्तत:, यह नोट किया जाना चाहिए कि आवेदकगण संबद्ध उत्पाद (एचआरसी) के अलावा अन्य उत्पादों का उत्पादन और निर्यात भी करते हैं और कंपनी के ग्रुप स्तर पर रिपोर्ट किए गए किसी घाटे से स्वत: ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि घरेलू उद्योग को इस संबद्ध उत्पाद के संबंध में घाटा हुआ है। इसके अतिरिक्त, ऐसी कोई सुचना नहीं थी जिसमें यह प्रदान किया गया हो कि क्या लाभप्रदता परिकलन के परिणामों में मुल्यह्नास लागत और अप्रत्यक्ष लागत को ध्यान में रखा जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि ऊपर उल्लिखित इन सभी कारणों पर ध्यान दिया जाता है तो इससे यह निदर्शन होगा कि भारतीय घरेलू उद्योग गंभीर क्षति नहीं हो रही है और न ही गंभीर क्षति की कोई चुनौती उत्पन्न हुई है।
- (v) कीमत अवमंदन : अपने प्रारंभिक जांच परिणाम में जांचकर्ता प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि "घरेलू उद्योग पर लगातार यह दबाव बना रहा कि अपनी कीमतें आयात कीमतों के बराबर बनाने के लिए या तो अपनी कीमतों में कमी करें या अपनी कीमतों पर स्थिर बने रहें।" उन संगत कारकों के अलावा जिन पर ऊपर चर्चा की गई यह नोट किया जाना चाहिए कि जांचकर्ता प्राधिकारी ने कई अन्य कारकों पर विचार नहीं किया है जिनका घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है। यह अन्य कारक निम्नलिखित हैं:
 - कच्चे माल की वैश्विक कीमतों और भारत में स्थानीय कीमतों में अपसरण: भारत की घरेलू बाजार में मुख्य कच्चे माल की उच्च कीमतों का ढांचागत एवं उपलब्धता मुद्दों के कारण भारत में घरेलू उद्योग की अर्थक्षमता एवं वित्तीय निष्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव है।
 - मुख्य भारतीय उत्पादकों की कीमत निर्धारण कार्यनीति घरेलू बाजार की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती है: भारत में स्टील के प्रमुख उत्पादकों की कीमत निर्धारण कार्यनीतियां बाजार की वास्तविक स्थिति के समरूप नहीं हैं क्योंकि स्टील के उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं थी। इसका घरेलू उद्योग के निष्पादन पर भी प्रभाव पड़ा जिसका न तो प्रारंभिक जांच परिणाम और न ही आवेदन में उल्लेख है।
- (vi) ऊपर उल्लिखित और जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए आठ क्षति कारकों में से, ऐसी सूचना दी गई कि, पांच कारकों उत्पादन, उत्पादकता, रोजगार, क्षमता उपयोग और मालसूची ने जांच की अवधि के दौरान अनुकूल (या स्पष्ट) निष्पादन किया : दूसरी ओर, ऐसी सूचना दी गई कि जांच की अवधि के दौरान केवल तीन कारकों : घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा, लाभ/हानि और कीमत अवमंदन ने नकारात्मक निष्पादन किया।
- (vii) जब उपर्युक्त क्षति कारकों और अन्य कारकों पर प्रारंभिक जांच परिणाम में ध्यान नहीं दिया गया और अब यदि इन पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जांचकर्ता प्राधिकारी का प्रारंभिक जांच परिणाम तथ्यों द्वारा विधिवत समर्थित नहीं है ओर न ही इसमें संगत कारकों का उपयुक्त मूल्यांकन किया गया है।
- (viii) वास्तव में, घरेलू उद्योग का उत्पादन, उत्पादकता, रोजगार क्षमता उपयोग और मालसूची संपूर्ण जांच अवधि के दौरान यथावत और बेहतर स्थिति में बना रहा। दूसरी ओर, ऊपर यह निदर्शन किया गया कि जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उद्योग की लाभप्रदता नकारात्मक रूप से निष्पादन कर रही है, यह एक सकारात्मक स्पष्टीकरण है और इससे भारत में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति और गंभीर क्षति की चुनौती की मौजूदगी के बारे में उपयुक्त एवं तर्कसंगत निष्कर्ष

निकाला जा सकता है। इसलिए यह माना जा सकता है कि डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(क) में यथाउल्लिखित गंभीर क्षति के संकेतकों का जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुचित ढंग से मूल्यांकन किया गया था और यह कि प्रारंभिक जांच परिणाम में उपलब्ध करार पर स्पष्टीकरण इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते हैं कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति से भारी समग्र क्षति का संकेत मिलता है।

च. आयातों में कथित वृद्धि तथा कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है:

- (i) आयातों के समग्र रूप से क्रम विकास का आकलन, डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(क) और डब्ल्यूटी वाद विधि द्वारा इस प्रावधान का दिए गए निर्वचन के अनसार इन आयातों की दर और राशि के आलोक में करना चाहिए।
- (ii) मेटिन्वेस्ट यह प्रस्तुत करता है और यह भरोसा करता है कि भारतीय जांचकर्ता प्राधिकारी इस बात को मानेंगे कि भारत में घरेलू उत्पादन के संबंध में वर्ष 2011-12 और 2014-15 के बीच आयातों में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई और वर्ष 2011-12 एवं 2014-15 के बीच आयातों के समग्र रूप से केवल 14 प्रतिशत की मामूली सी वृद्धि हुई इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014-15 में आयातों का वह स्तर बन गया जो वर्ष 2011-12 में रिकार्ड किए गए स्तर के अनुरूप था, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयातों में कथित वृद्धि और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंधी मौजूद नहीं है।
- (iii) यदि यह कल्पना की जाती है कि उपर्युक्त ग्राफ में बनाए गए आउटलाइन के अनुसार आयातों में यह क्रमिक वृद्धि ऐसी प्रवृत्ति की है कि इससे घरेलू उद्योग को कोई क्षति संभवत: ही कारित हो सकती है (क्वोडनान), कोई भी व्यिक्त उम्मीद कर सकता है कि यह क्षति वर्ष 2013-14 की तुलना में, जब आयातों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि होकर वे लगभग 97 प्रतिशत हो गए थे, वर्ष 2014-15 में मूर्त रूप हुई होगी।
- (iv) तथापि, आवेदनपत्र में प्रदान कराए गए आंकड़ों तथा सार्वजनिक स्रोत से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर क्षति संकेतकों का विश्लेषण यह प्रदर्शित करता है कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 में, आयातों में कथित वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की स्थिति में वास्तव में सुधार हुआ (अथवा कम से कम वह स्थिर बनी रही)।
- (v) इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 और वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2013-14 में आयातों में समग्र रूप से भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की स्थिति में सतत सुधार हुआ जिसे संबंधित संपूर्ण अविध में देखा जा सकता है (अर्थात वर्ष 2011-12 और 2014-15 के बीच), जिसमें क्षित पैरामीटर भी शामिल हैं जैसे उत्पादन (+35 प्रतिशत), (+26 प्रतिशत), घरेलू बिक्रियां (+23 प्रतिशत), निवेश (+41 प्रतिशत), जबिक अन्य कारक जैसे क्षमता उपयोग (+1 प्रतिशत) या तो स्थिर बना रहा या उसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ।
- (vi) इसलिए मेटिन्वेस्ट प्रस्तुत करता है कि वर्तमान मामले में वस्तुत: किसी कथित क्षति तथा आयातों में कथित वृद्धि के बीच कोई अनुरूपता नहीं है जैसाकि वर्ष 2013-14 से 2014-15 के दौरान, ऊपर प्रदर्शित किया गया, जब आयातों में कथित वृद्धि हुई (हालांकि यह वृद्धि उस ढंग से नहीं हुई जो गाट 1994 के अनुच्छेद XIX: 1(क) और डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 की अपेक्षा को पूरा करता है), क्षति संकेतकों में सुधार हुआ अथवा स्थिर बने रहे। स्पष्टत:, इससे यह प्रदर्शित होता है कि आयातों में कथित वृद्धि और कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- (vii) यदि कोई व्यक्ति वर्ष 2013-14 और 2014-14 के बीच के क्रमिक विकास की तुलना वर्ष 2011-12 और 2012-13 के बीच हुए क्रमिक विकास से करता है, जैसा कि आवेदन में प्रावधान किया गया है, तो वह यह नोट करेगा कि वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2014-15 में घरेलू उद्योग की स्थिति, आयात स्तर में कथित वृद्धि के बावजूद (लगभग सभी क्षति संकेतकों के लिए), बेहतर है।
- (viii) इसलिए, मेटिन्वेस्ट यह प्रस्तुतिकरण करता है कि आयात स्तर के क्रमिक विकास (समग्र एवं संगत दोनों रूपों में) और क्षति संकेतकों के क्रमिक विकास के बीच समय में अनुरूपता न होने के करण उनके बीच कोई भी कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं होता है। इसके परिणामस्वरूप, डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 और अनुच्छेद 4.2 में तथा गाट 1994 के अनुच्छेद XIX में निर्धारित कारणात्मकता की अपेक्षा पूरी नहीं होती है और इसलिए कोई भी रक्षोपाय साधन अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।
- (ix) मेटिन्वेस्ट का भरोसा है कि जांचकर्ता प्राधिकारी ऊपर वर्णित अपेक्षाओं के अनुरूप गहराई से गैर-उपरोपण विश्लेषण करेंगे और यह कि इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलेगा कि कोई कथित क्षति आयातों के अलावा अन्य कारकों से ही कारित हुई है। मेटिन्वेस्ट यह अनुरक्षित रखता है कि इस रक्षोपाय जांच के ढांचे के अंतर्गत यह पहलू अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- (x) विशेषकर जैसाकि ऊपर व्यापक रूप से स्पष्ट किया गया है, अन्य के साथ-साथ, कच्चे माल की वैश्विक कीमतों और भारत की स्थानीय बाजार में उसकी कीमतों के बीच अत्यधिक अपसारिता है। प्रथमत:, जांचाधीन उत्पाद के लिए कच्चे मालों में से एक कच्चे माल घरेलू रूप से उपलब्ध लौह अयस्क की भारत में संबंधित अवधि के दौरान उच्च लागत घरेलू उद्योग की अर्थक्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है जिसका जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया। द्वितीयत:, प्रमुख भारतीय उत्पादकों की कीमत-निर्धारण नीतियां घरेलू बाजार की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित नहीं करती है। अंतत:, परंतु जो महत्वपूर्ण है, वर्ष

- 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में भारत के आर्थिक विकास में स्पष्ट रूप से मंदी आई, इस पर भी भारत के घरेलू उद्योग को कथित गंभीर क्षति अथवा गंभीर की चुनौती का मूल्यांकन करते वक्त ध्यान दिया जाना चाहिए था।
- (xi) आवेदकगण स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि चीन उन प्रमुख कारणों में से एक है जिसकी वजह से भारत के घरेलू उद्योग को कथित क्षति हुई। अधिकांश प्रवस्तु जो आवेदन के साथ अनुबंध के रूप में लगाई गई (उदाहरण के लिए देखें। आवेदन के अगोपनीय पाठ का प्रदर्श 10 पृष्ठ 101-203) है भारत को चीन से आयातों, का उल्लेख करती है जो "20 वर्षों की न्यूनतम कीमत" पर किए गए हैं।
- (xii) वास्तव में, मंद आर्थिक विकास के कारण भारी उपरिक्षमता (44 मिलियन टन से अधिक) और चीन में कम होती घरेलू खपत (सराकर के प्रक्षेपित 71 प्रतिशत लक्ष्य से कम) के कारण उस देश से तृतीय देश को बाजार को संवर्धित आयात न्यून, अवमंदित कीमत पर हुआ।
- (xiii) मेटिन्वेस्ट यह प्रस्तुत करता है कि रक्षोपाय जांच के जरिए चीन से क्षतिकारी आयातों को लक्ष्य बनाना व्यापार रक्षा साधन का एक गलत विकल्प है, क्योंकि यह अन्य भरोसेमंद एवं भारत में संबद्ध उत्पाद के पुराने आपूर्तिकर्ताओं, जिसमें उक्रैन भी शामिल है, को दंडित करता है।

छ. रक्षोपाय साधन के स्वरूप और विकल्प के स्तर के लिए विधिक आधार

- (i) डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय अनुच्छेद 5.1 के प्रावधान सदस्यों पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व अधिरोपित करते हैं कि लगाया गया साधन गंभीर क्षति का निवारण करने अथवा उसका उपचार करने के लक्ष्य के अनुरूप है।
- (ii) कोरिया-डेयरी सेफगार्ड, अपीलीय निकाय द्वारा धारित, में भी यह उल्लेख है कि उत्पादों के आयातों पर अधिरोपित अंतिम रक्षोपाय साधन को निम्नलिखित तत्वों द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए : उत्पाद कवरेज, फार्म, अवधि एवं स्तर, इन सभी तत्वों पर अंतिम साधान के बारे में निर्णय करते समय उनकी पूर्णता पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए।
- (iii) इसलिए, रक्षोपाय साधन का अधिरोपण करके कोई सदस्य न केवल अपने स्तर ("की अनुरूपता") पर विचार करेगा बल्कि वह इसके स्वरूप पर भी विचार करेगा कि यह कथित गंभीर क्षति "का निवारण करने अथवा उसका उपचार करने के लिए आवश्यक से अधिक प्रतिबंधात्मक न हो, फिर चाहे यह रक्षोपाय शुल्क हो, या कोई परिमाणात्मक प्रतिबंध हो, जिसमें कोटा या प्रशुल्क कोटा शामिल हो अथवा किसी अन्य ऐसे फार्म में हो जो तृतीय देश से आयात को प्रतिबंधित करता हो।
- (iv) डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार का अनुच्छेद 5.1 में रक्षोपाय शुल्क के रूप में परिमाणात्मक प्रतिबंध अधिरोपित करने की स्पष्ट अनुमित दी गई है। यह प्रावधान रक्षोपाय शुल्क के रूप में अनुप्रयोग किए गए परिमाणात्मक प्रतिबंधों की रूपात्मकताओं को भी स्पष्ट करता है अर्थात यह कि "यह विगत तीन प्रतिनिधिक वर्षों में आयातों की मात्रा को (.......) के स्तर से कम नहीं करेगा"। डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 5.2 (क) में पुन: यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि परिमाणात्मक प्रतिबंधों का कोई विशिष्ट रूप अर्थात कोटा किस तरह निर्धारित किया जाएगा और कैसे उसका अधिरोपण किया जाएगा।
- (v) यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि गाट के अनुच्छेद XIX : 2 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि किसी उत्पाद सदस्य पर आयात प्रतिबंध लागू करने का "उद्देश्य इस व्यापार का इस तरह संवितरण करना होगा कि यह उत्पाद यथासंभव उतने ही हिस्सों में पहुंच जितना विभिन्न संविदाकारी पक्षकारों को उसकी हिस्सेदारी उस स्थिति में प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है, जब इस तरह का कोई प्रतिबंध न लगाया गया हो।"
- (vi) उपर्युक्त से यह अनुकृत होता है कि भारत का यह सुनिश्चित करने का नैतिक दायित्व है कि अन्यों के साथ-साथ उक्रैन से इस संबद्ध उत्पाद के आयातों पर अधिरोपित किया गया कोई भी रक्षोपाय साधन भारतीय घरेलू उद्योग की कथित गंभीर क्षिति का निवारण करने अथवा उसका समाधान करने के लक्ष्य के अनुरूप हो अर्थात वह प्रस्तावित साधन के स्वरूप और स्तर को ध्यान में रखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम व्यापार विकृतिकारी हो।

ज. इस संबद्ध उत्पाद की भारत को आपूर्ति करने में उक्रैन का पर्याप्त हित है

- (i) ऐतिहासिक रूप से उक्रैन भारतीय उपभोक्ताओं को इस संबद्ध उत्पाद की विश्वसनीय एवं नियमिमत आपूर्ति करता आया है। 20 प्रतिशत और जिसकी संभावित रूप से एक निर्णायक स्तर पर संपुष्टि की जा सकती है के स्तर पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से भारतीय बाजार में इस संबद्ध उत्पाद के उक्रैन से होने वाले आयात प्रतिबंधित होंगे क्योंकि उक्रैन के उत्पादक लाभ के बिना भारत को इसका निर्यात करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे।
- (ii) साथ ही, ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार, रक्षोपाय साधनों का लक्ष्य किसी तृतीय देश से आयातों को प्रतिबंधित कर देना बिल्कुल नहीं है परंतु स्थानीय घरेलू उद्योग को किसी कथित क्षति से निवारित करने अथवा उसका समाधान करने और तदनुसार समायोजन करने की अनुमति देता है।

- (iii) एतद्वारा यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि परिमाणात्मक प्रतिबंधों के माध्यम से अर्थात निम्नलिखित कारणों से रक्षोपाय साधन के रूप में टैरिफ रेट कोटा के माध्यम से यह उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं।
- (iv) प्रथमत:, टैरिफ रेट कोटा रक्षोपाय लागू करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध अन्य साधनों (उदाहरणार्थ: कोटा, प्रतिबंध, रक्षोपय शुल्क आदि) की तुलना कम व्यापार विकृतिकारी है। यह किसी आउट आफ कोटा शुल्क का अधिरोपण करके तृतीय देशों से आयात में सतत वृद्धि को सीमित करने की अनुमति देता है ओर इस प्रकार घरेलू उद्योग की रक्षा करता है एवं इसे तदनुसार समायोजित करने की अनुमति देता है। साथ ही, टैरिफ रेट कोटा ऐसे पुराने आपूर्तिकर्ताओं, जिनकी इस संबद्ध उत्पाद में पर्याप्त रूचि है, जैसे उक्रैन, को अपने पुराने इन कोटा राशि के अंदर भारत को अपना निर्यात जारी रखने की अनुमति देता है।
- (v) द्वितीयत:, पाटनरोधी शुल्क एवं प्रतिवलनकारी शुल्क, जिनको अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं (क्रमश: पाटन और सब्सिडाइजिंग) पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभिकल्पित किया गया है, के विपरीत रक्षोपाय साधनों का अधिरोपण तृतीय देशों के उचित व्यापार व्यवहारों पर किया जाता है। इसलिए, संबद्ध उत्पाद के आयातों के विरूद्ध किसी भी संभावित रक्षोपाय साधन का अनुप्रयोग, करते समय अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए और आपूर्तिकर्ता देश जैसे उक्रैन के विधिसम्मत हितों को समायोजित करना चाहिए।
- (vi) अंतत:, यह नोट किया जाना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद के प्रावधानों 5 और उसके समनुरूपी डब्ल्यूटीओ वाद-विधि में सदस्यों का रक्षोपाय साधन, यिद यह आयातों की मात्रा को विगत तीन प्रतिनिधिक वर्षों में हुए औसत आयातों से कम नहीं कर देता है तो, का अधिरोपण करने का निर्णय करते समय "स्पष्ट औचित्य" प्रदान करने का उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान मामले में यिद जांचकर्ता प्राधिकारी टैरिफ रेट कोटा के रूप में रक्षोपाय साधन और जो पिछले तीन प्रतिनिधिक वर्षों में प्रतिबिंबित स्तर पर सेट किया जाता है का अधिरोपण करने का निश्चय करता है तो उसका यह नैतिक दायित्व नहीं होगा कि वह इस निर्णय के लिए विस्तृत एवं पर्याप्त औचित्य प्रदान करे।

झ. उक्रैन की मौजूदा स्थिति:

- (i) उक्रैन के पूर्वी क्षेत्र (डोनेट्स्क और लुगान्स्क क्षेत्र) में स्थिति में हाल के महीनों में लगातार सुधार हुआ है ओर यह विधिक प्रत्याशाएं हैं कि यह सुधार इस वर्ष के अंत तक और उससे आगे भी जारी रहेगा जिससे इन क्षेत्रों में सामान्य जीवन बहाल होगा।
- (ii) इन क्षेत्रों की विशिष्ट स्थिति पर ध्यान देते हुए विनिर्माण व्यवसाय, जिसका उद्देश्य भारी क्षतिग्रस्त एवं विनष्ट अवसंरचना की पुनर्बहाली करना है, से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह उक्रैन के घरेलू उद्योग की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने में सक्षम होगा और यह भी हो सकता है कि एक बार इन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं राजनीतिक स्िथित में सामान्य होने पर यह इस समय हो रहे निर्यातक के कुछ हिस्से का भी अवशोषण कर ले।
- (iii) इस संबद्ध उत्पाद के लिए उक्रैन में घरेलू मांग में प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह उम्मीद नहीं है कि उक्रैन से किसी तृतीय देश, जिसमें भारत भी शामिल है, को आयातों में वृद्धि होना जारी रहेगी।
- VIII. **चीन इस्पात कारपोरेशन ("सीएससीस") :** सीएससी ताइवान आधारित इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक एवं निर्यातक है।
- क. ताइवान से होने वाला आयात भारत को आयात की कुल मात्रा का केवल 0.881, 0.25 प्रतिशत और 0.27 प्रतिशत है ओर यह आयात रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 के अंतर्गत 3 प्रतिशत की नगण्य सीमा से कम है। इसके अतिरिक्त, ताइवान को डब्ल्युटीओ के कई सदस्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विकासशील देश के रूप में माना जाता है।
 - (i) कतिपय स्टील उत्पादों, मंदारिन्स और अन्य सिट्स फलों तथा फ्रेम्ड सालमान पर ईयु रक्षोपाय साधन
 - (ii) गेहूं के आटे पर ईयू रक्षोपाय साधन
 - (iii) मलेशिया ने हाट-रोल्ड स्टील प्लेट्स पर प्रारंभिक रक्षोपाय साधन का अनुप्रयोग करने से ताइवान का अपवर्जन कर दिया है।
 - (iv) संयुक्त राष्ट : ताईवान को निम्नलिखित में विकासशील देश माना गया है :
 - एशिया एवं प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण
 - यूएन व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड)
 - आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी), और
 - पांचवा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन : ताईवान के आर्थिक मंत्री ने यह उद्घोषणा की कि ताइवान एक "नया उभरा विकासशील सदस्य है।

- ख. विकासशील देशों से इस विचाराधीन उत्पाद के आयात भारत को हुए कुल आयातों का सामूहिक रूप से नगण्य हिस्सा है जो (वर्ष 2013-14 में) 2.0 प्रतिशत, (वर्ष 2014-15 में), 0.9 प्रतिशत और (वर्ष 2015 प्रथम तिमाही में) 0.9 प्रतिशत रहा है। यह कि ताइवान से आयातों पर किसी रक्षोपाय साधन का अनुप्रयोग करने से छूट दी जानी चाहिए।
- ग. इस विचाराधीन उत्पाद से उच्च स्ट्रेंथ की स्टील (एचएसएस) का अपवर्जन करना क्योंकि इसका उपयोग भारतीय आटोमोबाइल उद्योग द्वारा किया जाता है।
- घ. ताईवान ने एचएसएस का निर्यात नहीं किया है जिसका एचएसएस की सुदृढ़ गुणवत्ता के कारण, इसकी आटोमोबाइल उद्योग में मांग तेजी से बढ़ रही है। एचएसएस की उपलब्धता स्थानीय मिलों से नहीं हो रही है और इस कारण भारतीय आटो उद्योग की जरूरतों की पूर्ति अन्य के साथ-साथ ताईवान से आयातों से ही जाती है।
- ङ. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 6 से असंगतता है क्योंकि ऐसी कोई संवेदनशील परिस्थितियां नहीं हैं जहां विलंब ऐसी क्षतिकारित कर सकता हो जिसकी भरपाई न हो सके। घरेलू उद्योग के प्रमुख आर्थिक संकेतक, जिनमें घरेलू उत्पादन, उत्पादकता और रोजगार, क्षमता उपयोग एवं मालसची शामिल हैं. इस संदर्भ अविध के दौरान वस्तृत: अपरिवर्तित बने रहे:
 - खुली बाजार में वाणिज्यिक बिक्री के संबंध में घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा जांच की अविध के दौरान अपरिवर्तित बना रहा।
 - अपीलीय निकाय के निर्वचन के अनुसार इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में इस तरह से वृद्धि नहीं हुई कि आयातों में "उद्रेक" बना रहा हो। आयातों में यह प्रोत्कर्ष परिमाणात्मक एवं परिणात्मक रूप से स्वत: "पर्याप्त अभिनव, पर्याप्त अचानक, पर्याप्त तीव्र और पर्याप्त महत्वपूर्ण" स्थिति में हुआ हो जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हो सकती हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सकती हो।
 - बाजार हिस्से में केवल 4.35 प्रतिशत वृद्धि के लिए साधारणत: "पर्याप्त हिस्सा" अथवा "पर्याप्त महत्वपूर्ण" वृद्धि नहीं कहा जा सकता है और इसलिए इसे किसी भी तरह से "प्रोत्कर्ष" नहीं कहा जा सकता है।
 - घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में विगत वर्ष 2013-14 के 100 अंक से बढ़कर वर्ष 2014-15 के दौरान 135 अंक हो गया। पहले दो संदर्भ वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग की सकारात्मक लाभप्रदता अभियान और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मामूली सी गिरावट पर विचार करते हुए इस मामले में रिकार्ड में कोई सिद्ध संवेदनशील परिस्थिति नहीं है।

IX. चाइना आयरन एंड स्टील एसोसिएशन ने अपना प्रस्तुतिकरण अपने प्रतिनिधि मैसर्स एथेना लॉ एसोसिएटस के माध्यम से किया

- क. इस एसोसिएशन ने अपना प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण जांच शुरूआत नोटिस ओर प्रारंभिक जांच परिणाम के आधार पर किया।
- ख. रक्षोपाय साधन "त्रुटिपूर्ण सिद्धांत" पर आधारित हैं और इनका प्रयोग उन आयातों पर आधारित है जो सदभाव से किए जाते हैं न कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के इरादे से। इसलिए, रक्षोपाय साधनों का आश्रय केवल उन मजबूत मामलों में ही लिया जाना चाहिए जहां डूबते उद्योग की रक्षा करने के लिए इस शुल्क का अधिरोपण करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न हो। कोरिया-डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि रक्षोपाय साधन असाधारण उपाय हैं जिनका प्रयोग आपातकालीन परिस्थिति के अंतर्गत ही करना चाहिए। वर्तमान याचिका किसी असाधारण अथवा आपातकालीन स्थिति का निदर्शन नहीं करती है और इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए।
- ग. माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरिदास एक्सपोर्टस बनाम आल इंडिया फ्लोट ग्लास मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन में यह धारित किया कि इस वस्तु की भारत से बाहर न्यूनतर कीमतों पर उपलब्धता परस्पर बुरी नहीं है बिल्क यह प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है।
- घ. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद XIX यह प्रावधान करता है कि रक्षोपाय साधनों का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अत्यधिक अभिनव अवधि के आयातों में अचानक एवं तीव्र वृद्धि हुई हो, घरेलू उद्योग को क्षति तथा इन संवर्धित आयातों के बीच स्पष्ट कारणात्मक संबंध हो; क्योंकि रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में नहीं होता है।
- ङ. रक्षोपाय जांच की शुरूआत नियम 5 के अंतर्गत वैध आवेदनपत्र की जरूरतों के विववरण की जांच किए बिना अथवा उसको पूरा किए बिना शुरू कर दी गई।
- च. अनन्तिम जांच परिणाम जल्दी-जल्दी में जारी किए और ऐसी को संवेदनशील सिथित नहीं है जिसके कारण अनन्तिम साधन का अधिरोपण करने में विलंब से अपूरणीय क्षति हो सकती है। अनंतिम साधन का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित संवेदनशील परिस्थितियों की शर्त को पूरा नहीं किया गया।

- छ. शुरूआती जांच अधिसूचना के पैराग्राफ 10 में यह उल्लेख किया गया कि हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचारों से प्राधिकारी को अवगत कराने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा परंतु किसी भी प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम जारी कर दिए।
- ज. आवेदन ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और उसने घरेलू उद्योग के मामले की तर्कसंगत एवं सार्थक समझ की अनुमति नहीं दी।
- झ. अनपेक्षित विकास अप्रत्याशित एवं अननुमेय है और इसलिए यह वह विकास एवं अग्रण हैं जो घरेलू उद्योग के समक्ष कुतूहल के रूप में उपस्थित हुए और जिसके कारण घरेलू उद्योग हक्का-बक्का रह गया। तथापि, याचिका में उल्लिखित विकास बाजार का केवल सामान्य उतार-चढ़ाव है जिसकी प्रत्येक उद्यमी द्वारा पहले से प्रत्याशा कर ली जानी चाहिए। व्यापार को मुक्त करना तथा उसके परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि भारतीय वार्ताकारों द्वारा गाट में प्रत्याशित एवं पूर्णवेक्षित थी जब देश प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क अवरोधों को कम करके मुक्त एवं पक्षपात रहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करने के लिए वार्ता कर रहे थे।
- ञ. प्राधिकारी को यह मूल्यांकन करते वक्त कि क्या संवर्धित आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हुई है, उन उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक प्रकृति के सभी संगत कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। निम्नलिखित तथ्य यह प्रदर्शित करते हैं कि आवेदक को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई और न ही गंभीरता क्षति की कोई चुनौती उत्पन्न हुई :
 - (i) आवेदकों की क्षमता में कोई भारी परिवर्तन नहीं
 - (ii) वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) के दौरान उत्पादन में मामूली सी वृद्धि
 - (iii) वर्ष 2013-14 से 2015-16 (वार्षिकीकृत) के दौरान क्षमता उपयोग समान बना रहा।
 - (iv) वर्ष 2013-14 से 2015-16 (प्रथम तिमाही) में घाटा प्रदर्शित किया है परंतु उसी अवधि के दौरान पीबीआईटी बहुत अधिक सकारात्मक रही। इसलिए घाटा ब्याज के बोझ के कारण हुआ, न कि आयात कीमतों के कारण जैसा कि ऋणात्मक कीमत अधोरदन से स्पष्ट है।
 - (v) मालूसची स्तर जो वर्ष 2013-14 में 100 बिंदु था, थोड़ा सा बढ़कर वर्ष 2015-16 (पहली तिमाही) में 103 बिंदु हो गया।
 - (vi) रोजगार एवं उत्पादकता संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान समान बनी रही।
 - (vii) वर्ष 2014-15 (तिमाही) में वर्ष 2015-16 (प्रथम तिमाही) के उपलब्ध आंकड़ों तक ऋणात्मक कीमत अधोरदन रहा है। तद्द्वारा उतराई कीमत आवेदकों की निवल बिक्री उगाही से अधिक थी। इसलिए, आवेदकों को ब्याज लागत एवं उनकी अकार्यकुशलता के कारण घाटा हुआ, न कि आयातों के कारण।
 - (viii) घरेलू मांग में घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से का निर्धारण प्रारंभिक जांच परिणाम में सही-सही नहीं किया गया क्योंकि भारत में कुल मांग का निर्धारण ग्राही खपत पर विचार करते हुए किया गया है। तथापि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की बिक्री पर विचार ग्राही खपत का अपवर्जन करते हुए किया गया।
- ट. इसलिए, घरेलू उद्योग को मात्रा और कीमत दोनों ही रूपों में क्षति हुई ही नहीं, गंभीर क्षति की बात तो छोड़ ही दीजिए।
- ठ. यदि यह मान भी लिया जाए कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है तो भी यह क्षति संवर्धित आयायातें के कारण नहीं हुई। आवेदकों ने यह सिद्ध करने का कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया कि दावाकृत क्षति संवर्धित आयातों के कारण हुई है।
- ड. घरेलू उद्योग को क्षति ब्याज लागत के बोझ के कारण हुई है और आयात कीमतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि कीमत अधोरदन सुसंगत रूप से ऋणात्मक रहा है।
- ढ. आवेदकों ने कोई समायोजन योजना प्रदान नहीं कराई है और प्रारंभिक जांच परिणाम में समायोजन योजना का उल्लेख भी नहीं किया गया है। यूनाइटेड फास्फोरस द्वारा रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए वर्ष 1999 में दायर किए गए एक आवेदनपत्र में प्राधिकारी ने समायोजन योजना न होने के आधार पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से मना कर दिया था।

ण. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं है। वाक्यांश जनहित को रक्षोपाय विधियों में परिभाषित नहीं किया गया है बल्कि शीर्ष न्यायालय ने इसकी विभिन्न विधियों के अंतर्गत व्याख्या की है। बिहार बनाम कामेश्वर सिंह में यह नोट किया गया कि "जनहित" अभिव्यक्ति की संक्षिप्त परिभाषा देना संभव नहीं है ओर इसका कोई कठोर अर्थ भी नहीं है और यह लोच्य है तथा वही रंग अखित्यार कर लेती है जिस संविधि में यह घटित होती है, इसकी संकल्पना में समय ओर समाज की स्थिति और इसकी जरूरत के मुताबिक परिवर्तन होता है। यूनाइटेड फास्फोरस द्वारा रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करान के लिए वर्ष 1999 में दायर आवेदन में प्राधिकारी ने रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से इस आधार पर मना कर दिया था कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं होगा।

X. जापान आयरन एंड स्टील फेडरेशन

- क. कुल खपत में आयातित स्टील उत्पादों का हिस्सा लगभग 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के आसपास है। इसका आशय यह है कि कुछ संख्या में ऐसे ग्राहक हैं जिन्हें आयातित उत्पादों की जरूरत पड़ती है।
- ख. घरेलू हाट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स बाजार में मांग आपूर्ति का संतुलन अत्यधिक टाइट हो गया। भारत में स्टील उत्पादकों की उत्पादन क्षमता देश में हाट रोल्ड फ्लैट उतपादों की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
- ग. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का इसके उन उपयोगकर्ताओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा जो आयातित हाट रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर निर्भर करते हैं।

XI. आर्सेनर मित्तन, ब्राजीन (ए एम ब्राजीन): रक्षोपाय जांच की शुरूआत करने के लिए अपेक्षित शर्तों को इस मामले में पूरा नहीं किया गया है:

- क. भारतीय प्राधिकारियों ने असामान्य रूप से समयपूर्व क्षति में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करके हितबद्ध पक्षकारों के अधिकारों को भंग किया है।
- ख. डब्ल्यूटीओ वाद-विधि में यथा निर्वचित डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के आशय के अंतर्गत आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
- ग. याचिकाकर्ता को न तो कोई गंभीर क्षति हुई और न ही किसी गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त, कथित गंभीर क्षति (यदि कोई) और आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- घ. उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय नियमावली के आशय के अंतर्गत आयातों में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई। भारत में इस संबद्ध उत्पाद के आयातों में वृद्धि न तो तीव्र हुई, न अभिनव है, न अचानक और न ही बहुत अधिक है।
- ङ. ए एम ब्राजील भारतीय प्राधिकारियों द्वारा चुनी गई जांच की अवधि को भारी चुनौती देता है जिसमें वार्षिकीकृत आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2015-16 को भी शामिल किया गया है। अत्यधिक अभिनव अवधि के आंकड़ों को जांच की अवधि के दौरान प्रवृत्तियों को सम्पृष्ट या अपृष्ट करने के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।
- च. हालांकि आयातों में वर्ष 2013-14 और 2014-15 के बीच भारी वृद्धि हुई, फिर भी अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु तक कील तुलना दर्शाती है कि यह आयात वर्ष 2011 से 2015 तक स्थिर बने रहे और इन आयातों में उसी अविध के दौरान 2,3 प्रतिशत की कमी भी आई है। इस संबंध में यह नोट किया जाना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ का न्यायविधान यह स्पष्ट कर देता है कि यह आकलन करने के लिए कि क्या आयातों में अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु तक वृद्धि संवर्धित आयातों के संबंध में अनुच्छेद 2.1 की जरूरतों को पूरा करती है, अंतिम बिंदु के रूप में प्रयोग किए गए विशिष्ट वर्ष की तुलना की संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट शुरूआती निष्कर्ष को सम्पुष्ट या इसके विपरीत कर सकती है।
- छ. वर्तमान मामले में, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में सभी संकेतक सकारात्मक हैं। भारतीय प्राधिकारी गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का निदर्शन कराने में असफल रहे हैं।
- ज. भारतीय घरेलू उद्योग के उत्पादन के क्रमिक विकास का लंबी अविध के दौरान सघन परीक्षण करने से प्रतीत होता है कि गंभीर क्षति का आरोप गलत है। वास्तव में स्थिर बने रहने के बजाय, शिकायत में उल्लिखित के दौरान उत्पाद में वृद्धि हुई है।
- झ. विश्लेषण किए गए अवधि में आवेदक के उत्पाद में 26 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, जबिक अन्य उत्पादकों ने अपने उत्पादन में 57 प्रतिशत तक की वृद्धि कर ली जिससे यह संकेत मिलता है कि आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण आवेदक के उत्पादक और उसकी बिक्री की वृद्धि सीमित हो गई हो।
- ज. हालांकि भारतीय प्राधिकारी केवल वर्ष 2013-14 से 2014-15 की अवधि पर भरोसा करके आयातों के बाजार हिस्से में बढ़ोरी का साक्ष्य प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, तथापि एक दीर्घतर अवधि का विश्लेषण (जैसा कि कोई अपनी याचिका

- में प्रयोगकर्ता है) दर्शाता है कि वर्ष 2011-15 की अवधि के दौरान आयातों का बाजार हिस्सा स्थिर बना रहा और यहां तक कि इसमें 1 प्रतिशत की कमी भी आई है।
- ट. भारतीय उद्योग के रूप में संघठित कंपनियों के अभिनव वित्तीय परिणाम और सार्वजनिक विवरण भारतीय उद्योग की स्वस्थ वित्तीय स्िथति दर्शाते हैं।
- ठ. कथित गंभीर क्षति (यदि कोई) और आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। आयातों में कथित वृद्धि और कथित गंभीर क्षति तथा कारणात्मक संबंधों की मौजूदगी का मृश्किल से ही कोई साक्ष्य मौजूद हो।
- ड. भारतीय प्राधिकारियों ने जांच शुरूआत करने के केवल 7 दिनों के पश्चात ही अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर दिया। किसी अनंतिम शुल्क का इतनी जल्दी अधिरोपण करना रक्षोपाय मामलों में भारतय प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए यह एक आपवादिक स्थिति है।
- ढ. ए.एम. ब्राजील डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 के अंतर्गत रक्षोपाय साधन के अनुप्रयोग के दायरे में ब्राजील से होने वाले आयातों को शामिल किए जाने पर संशय व्यक्त करता है।
- ण. याचिका के अगोपनीय पाठ में कुल आयातों में विकासशील देशों के हिस्से के संबंध में और इस संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं है जिस पर भारतीय प्राधिकारियों ने प्रारंभिक रूप से यह निष्कर्ष निकालने का भरोसा किया कि विकासशील देशों को इस अनंतिम साधन का अधिरोपण करने के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।
- त. भारतीय प्राधिकारियों ने अपने विश्लेषण के संबंध में कोई भी साक्ष्य न देकर डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.1 के अंतर्गत अपने नैतिक कर्तव्य को भंग किया है।
- थ. तत्काल अधिसूचित करने में असमर्थ रहने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 12(1) का उल्लंघन हुआ है। ए एम ब्राजील यह नोट करता है कि इस मामले की शुरूआत 7 सितम्बर को की गई थी और इसे रक्षोपायस संबंधी डब्ल्यूटीओ समिति के पास 15 सितम्बर को अर्थत जांच की शुरूआत होने के 8 दिन पश्चात ही अधिसूचित कर दिया गया था।
- द. अनंतिम रक्षोपाय साधन ग्रहण करने से पहले अधिसूचित करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 12(4) का उल्लंघना हुआ है।

XII. जेएफई स्टील कारपोरेशन, निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड, निप्पन स्टील और सुमिटोमो मेटल कारपोरेशन एवं कोबे स्टील लिमिटेड, जिनका प्रतिनिधित्व मैसर्स एजेड बी एंड पार्टनर्स द्वारा किया गया था

- क. महानिदेशक रक्षोपाय रक्षोपाय नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत यथापेक्षित साक्ष्य की यथार्थता एवं पर्याप्तता की जांच करने में असफल रहे।
- ख. संवेदनशील परिस्थितियों के अभाव में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करके महानिदेशक रक्षोपाय ने भूल की है। गंभीर क्षति कारित करने अथवा गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न करने के स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में संवेनदनशील परिस्थितियों की मौजूदगी स्वयं ही समर्थनीय नहीं है।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद की तुलना में समान उत्पाद नहीं है। याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण करने के लिए सुसंगत क्रियापद्धति प्रदान नहीं कराई है। महानिदेशक रक्षोपाय ने बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति का उद्देश्यपरक आकलन किए बिना इस विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा को स्वीकार कर लिया।
- घ. जापान की मिलों द्वारा निर्यातित उत्पादों का घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्माण/आपूर्ति नहीं की जाती है और इसलिए उसका विचारधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जापान की मिलों द्वारा भारत को निर्यातित कुछ हाट रोल्ड उत्पादों के संघटकों के कुछ रसायनिक संघटनों में अलग हैं।
- ङ. जापान ने आयातित हाट रोल्ड कॉइल्स एक ऐसी विशिष्ट क्वालिटी अपेक्षा को पूरा करती है जिसे घरेलू उद्योग पूरा करने में अक्षम हैं। जापान से निर्यातित हाट रोल्ड उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उन उत्पादों से काफी भिन्न हैं और उनका इस विचाराधीन उत्पाद से काफी भिन्न है और उसे विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से हटा दिया जाना चाहिए।
- च. यह स्पष्ट नहीं है कि महानिदेशक रक्षोपाय ने इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में आंकड़ों का सत्यापन कैसे किया क्योंकि इस विचाराधीन उत्पाद में अस्वीकृत उत्पादों के विशिष्ट सेट को शामिल किया गया है और यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ता इस विचाराधीन उत्पाद के आंकड़ों को अलग से अनुरक्षित करते हैं।

- छ. वर्तमान मामले में रक्षोपाय साधन का अनुप्रयोग करने की शर्तें पूरी नहीं होती है। महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा "अनपेक्षित विकास" के संबंध में जांच परिणाम गाट के अनुच्छेद XIX और एसजीए से असंगत हैं। अनपेक्षित विकास प्रत्येक विशिष्ट उत्पाद के लिए किया जाना चाहिए न कि केवल स्टील के लिए।
- ज. "अनपेक्षित विकास" के विश्लेषण में अन्य संगत घटनाओं जैसे भारतीय रुपए का अवमूल्यन, कच्चे माल की स्थानीय रूप से खरीद करने वाले औद्योगिक प्रयोक्ताओं द्वारा आयातों में कमी और भारत-जापान सीईपीए पर हस्ताक्षर होना को ध्यान में रखा गया।
- झ. महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा चयन की जांच की अवधि इतनी अधिक नहीं है कि उससे आयातों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जा सके।
- ञ. घरेलू उद्योग को न तो क्षति हुई और न ही गंभीर क्षति की कोई चुनौती उत्पन्न हुई। जांच की अवधि के दौरान उत्पादन के स्तर, रोजगार और क्षमता उपयोग में कोई गिरावट नहीं आई। याचिकाकर्ताओं के बाजार हिस्से में कमी भारतीय उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा और ग्राही खपत में वृद्धि के कारण आई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के उत्पादन का मौजूदा स्तर पहले ही काफी अधिक है।
- ट. लाभ/हानि की घटना का भी आयातों से कोई परस्पर संबंध नहीं है। वर्ष 2014-15 में आयातों में 97 प्रतिशत वृद्धि हुई और उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- ठ. घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षिति, यदि कोई, संवर्धित आयातों के कारण नहीं हुई है। घरेलू उद्योग आंतरिक ग्राही खपत के लिए आपूर्ति के विपथन, परियोजनाओं का कार्यान्वयन विलंब से होने, सरकार द्वारा कोई सहायता न दिए जाने, वैश्विक कीमत में वृद्धि के समक्ष प्रगोपन होने, क्षमता निर्माण एवं क्षमता सृजन में आशक्तता, अन्य देशों से प्रतिस्पर्धी उत्पादों, न्यूनतर क्वालिटी की लौह अयस्क जिसमें अधिक कोयले की जरूरत पड़ती है, कोयले की न्यूनतर गुणवत्ता कच्चे माल को प्राप्त करने में समस्याएं आदि के कारण भी कष्ट सहन कर रहा है।
- ड. उच्च परिवहन लागत और कमजोर अवसंरचना का भारतीय उत्पादकों की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है।
- ढ. भारत में इस विचाराधीन उत्पाद द्वारा कारित क्षति को संवर्धित आयातों द्वारा हुई कथित क्षति से पृथक की देना चाहिए।
- ण. रक्षोपाय साधन को अपनाना जनहित में नहीं है क्योंकि हाटरोल्ड फ्लैट उत्पादों का विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जाता है और अनुप्रवाही औद्योगिक प्रयोक्ताओं के लिए आयात करना अनिवार्य है। जेपीसी आंकड़ों के अनुासर, विगत 5 वर्षों में एचआर कॉइल्स के आयात घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए अनिवार्य है।
- त. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना भारतीय आटो उद्योग और कोल्ड रोल्ड उत्पादों के अनुप्रवाही उत्पादकों के लिए अनर्थकारी होगा।
- थ. डीजी रक्षोपाय से अनरोध है कि वह जापान की मिलों द्वारा निर्यातित हाट रोल्ड कॉइल्स का अपवर्जन कर दे।
- द. हम डीजी रक्षोपाय से निर्माण प्रयोग के लिए एचआरसी पर टैरिफ-रेट-कोटा (टीआरक्यू) लागू करने का अनुरोध करते हैं क्योंकि घरेलू उद्योग इन उत्पादों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं करता है।

XIII. पोस्को कोरिया और पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधिक मैसर्स शार्दूल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के जरिए दायर प्रस्तुतिकरण

- क. कंपनी ने आवेदक द्वारा दायर याचिका के प्रत्युत्तर में प्रस्तुतिकरण दायर किए।
- ख. आवेदक ने इस पीयूसी के अन्य उत्पादकों के बाजार हिस्से का गलत प्रतिनिधित्व किया है और घरेलू उद्योग के बराबर हिस्से को बाजार में इस पीयूसी के अन्य उत्पादकों के बाजार हिस्सों के रूप में दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप, टाटा स्टील लिमिटेड, भूषण स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड के बाजार हिस्से को अन्य उत्पादों के बाजार हिस्से में शामिल किया गया है।
- ग. व्यापार के समान स्तर पर आंकड़ों की पक्षपात रहित तुलना सुलभ बनाने के उद्देश्य से, ग्राही खपत के लिए प्रयोग किए जाने वाले आयात की मात्रा का कुल मांग से तब अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए जब घरेलू उत्पादकों की ग्राही खपत को कुल मांग से अलग कर दिया जाता है।
- घ. पीयूसी की कुल मांग गलत है क्योंकि इसमें अन्य उत्पादकों की बिक्री को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, चूंकि मांग अधिक है, आयातों के बाजार हिस्से में भी गिरावट आएगी।

- ङ. आयातों में थोड़ा सा उतार-चढ़ाव प्रदर्शित हुआ है, जिसमें अधिक वृद्धि नहीं हुई है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा अधिकांशत: छोटे-छोटे उत्पादकों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि जो लगभग 6 प्रतिशत थी।
- च. आवेदक को पिछले वित्त वर्ष में लाभ हुआ और बिक्री में कमी क्षमता का कम उपयोग करने एवं उच्च ऋण/वित्त लागत के कारण आई है।
- छ. आवेदकगण घरेलू बाजार में इस पीयूसी की बिक्री मंहगी दरों पर करते हैं जबिक उसी उत्पाद का निर्यात विश्व बाजार में प्रचलित कीमतों पर करते हैं।
- ज. घरेलू उद्योग के क्षति होने अथवा क्षति की चुनौती उत्पन्न होने तथा आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि आयातों में वृद्धि नगण्य हुई और इसके लिए घरेलू मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। घरेलू मांग को पूरा करने में अक्षम रहने के बावजूद उन्होंने अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा भारत से बाहर निर्यात करने का आश्रय लिया है।
- झ. डीजी रक्षोपाय द्वारा अधिरोपित अनन्तिम शुल्क इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का समुचित विश्लेषण किए बिना किया गया था। पुनश्च हितबद्ध पक्षकारों अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
- ञ. घरेलू उद्योग अनुप्रवाही उपभोक्ताओं की गुणवत्ता जरूरत को पूरा नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त, इस पीयूसी के तिपय ग्रेडों को जांच से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनका घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा है।
- ट. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी करार के अंतर्गत भारत की वचनबद्धता का उल्लंघ होगा क्योंकि इस करार के अंतर्गत इस पीयूसी पर शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इस करार में प्रावधान है कि अनुच्छेद XIX के अंतर्गत की गई रक्षोपाय कार्रवाई डब्ल्यू आओ करार के अंतर्गत दायित्वों से संगत होना चाहिए और इसमें उदभवन वस्तु के आयातों का अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए यदि वे आयात पर्याप्त गंभीर क्षति अथवा क्षति की चुनौती कारित नहीं कर रहे हैं। इसलिए, कोरिया से आयात इस शर्त के अंतर्गत कवर होते हैं।
- ठ. रक्षोपाय साधन आपातकालीन कार्रवाई होती है जिसका अधिरोपण विशेष और आपवादिक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए और इसका इरादा घरेलु उद्योग को अस्थायी एवं अल्प अवधि का संरक्षण देना होना चाहिए।
- ड. यूनाइटेड फास्फोरस बनाम महानिदेशक रक्षोपाय के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किए निर्णय के अनुसार घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की मौजूदगी और एक कारणात्मक संबंध स्थापित होना चाहिए परंतु आयातों में वृद्धि से प्राधिकारी रक्षोपाय शल्क अधिरोपित करने के लिए बाध्य नहीं है।
- ढ. आवेदक ने आयात प्रतिस्पर्धा का सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे किसी प्रयास अथवा किए जाने के लिए योजनाबद्ध अथवा दोनों का कोई उल्लेख नहीं किया है।
- ण. आवेदक ने किसी अनपेक्षित परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया है जिसके कारण भारत में इस पीयूसी के आयातों में वृद्धि हुई हो। आवेदक ने उल्लेख किया है कि आयातों में यह वृद्धि विभिन्न भौगोलिक राजनीतिक और आर्थिक हालातों के कारण हुई जैसे उक्रैन और रूस तथा यूरोप एवं रूस के बीच तनाव मांग में मंदी के कारण स्टील की वैश्विक बाजार की स्थिति आदि।
- त. कोरिया से आयातों को अनपेक्षित विकास नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वार्ताकारी पक्षों ने रियायतें प्रदान करते समय इस बात की पूर्वापेक्षा नहीं कर सके हों कि इस तरह का कोई विकास घटित नहीं होगा। जब इस करार पर हस्ताक्षर किए गए तो घरेलू एवं वैश्विक स्टील उत्पादक दोनों ही नई विनिर्माण सुविधाओं में भारी निवेशकर रहे थे और उद्योग का कोई न कोई व्यक्ति इस तथ्य के प्रति जागरूक रहा होगा कि तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयातों में वृद्धि होने लगेगी।
- थ. रक्षोपाय करार और अनुच्छेद XIX विशेष रूप से यह परिभाषित नहीं करता है कि जांच की अविध क्या है परंतु गंभीर क्षित गंभीर क्षित की चुनौती वाक्यांशों की परिभाषाएं यह संकेत देती हैं कि यह निर्धारण उद्देश्यपरक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और वे अभिकथन, विचार एवं निष्कर्ष जो तथ्यात्मक साक्ष्य पर आधारित नहीं है, उन्हें नामंजूर कर देना चाहिए। डीजी द्वारा अपनाई गई अविध वर्ष 2013-14 से 2015-16 है और इस अल्प अविध के आंकड़े कृत्रिम हैं। आंकड़ों को वर्ष 2010-11 से शुरू होकर 2015-16 तक की कम से कम पांच वर्श की अविध के लिए होना चाहिए। वर्ष 2013-14 की अविध को आधार वर्ष के रूप में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि यह वर्ष तो स्टील उद्योग के लिए शुरूआती वर्ष था।

XIV. हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया (दिनांक 18.11.2015) : हुंडई स्टील कोरिया आरपी से इस संबद्ध वस्तु की उत्पादक निर्यातक है। कंपनी ने उनके प्रस्तुतिकरण को गोपनीय मानने का अनुरोध किया है। इस अनुरोध के मद्देनजर उनके तर्कों को यथासंभव सीमा तक अगोपनीय मानते हुए संक्षेप में निम्नवत उल्लिखित किया गया है :

- क. प्रारंभिक जांच परिणाम की समीक्षा करने के पश्चात इस बात का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि हुंडई स्टील ने भारत में हाट-रोल्ड कॉइल के घरेलू उद्योग/ उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित की है।
- ख. हुंडई स्टील की निर्यात बिक्री कीमत भारत में घरेलू विनिर्माताओं और अन्य विदेशी निर्यातकों द्वारा पेशकश की जा रही कीमतों से कम थी। भारत को निर्यात की गई मात्रा औसत मात्रा थी और इसमें विगत कई वर्षों में कोई भारी वृद्धि नहीं की गई थी। इस नोटिस के अन्य निष्कर्ष एवं प्रेक्षण भी हुंडई स्टील के संबंध में असंगत प्रतीत होते हैं।
- ग. इन कारणों से हुंडई स्टील महानिदेशक से अनुरोध करती है कि इस रक्षोपाय जांच और 20 प्रतिशत अनन्तिम शुल्क को तत्काल समाप्त कर दिया जाए। इस अप्रत्याशित एवं अनुपयुक्त साधन के परिणामस्वरूप कई भारतीय विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता समाप्त हो रही है और वे अन्य वैश्विक निगमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन फर्मों को हुंडई स्टील की सेवाओं की जरूरत है क्योंकि यह कंपनी ऐसे पण्य का उत्पादन करती है जिसका विनिर्माण भारतीय कंपनियां नहीं कर सकती हैं। हुंडई स्टील समय पर आपूर्ति करती है और उचित कीमतों पर श्रेष्ठ क्वालिटी के हाँट रोल्ड काँइल्स का उत्पादन करती है।
- घ. हुंडई स्टील पिंकलिंग और आयलिंग युक्त हाट रोल्ड कॉइल्स की बिक्री हुंडई स्टील इंडिया लिमिटेड (एचएसआईएल) के लिए करती है और इन्हें इस जांच से छूट दी जानी चाहिए। यह उत्पाद मुख्यत: हुंडई मोटर्स आटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए विनिर्मित किए जाते हैं।
- ङ. इसके अतिरिक्त, एचएसआईएल, जो विधित: एक भारतीय निकाय है, प्रत्यक्षत: भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था और आम जनता के हित के लिए महत्वपूर्ण लाभ सृजित करती है। इसलिए इस साधन का उपयोग करना जनहित में नहीं होगा।
- च. इस जांच का जारी रहना और रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण पर विचार करने को जारी रखने से भारत की अर्थव्यवस्था को समग्र क्षति पहुंचेगी और हाट रोल्ड काइल के आयातकों तथा आम जनता पर इसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- छ गंभीर क्षति :
 - (i) **आयात वृद्धि**: महानिदेशक यह बताने में असफल रहे कि आयातों में यह वृद्धि कोरिया गणराज्य और हुंडई स्टील द्वारा कैसे की गई। महानिदेशक को न केवल संवर्धित आयातों की जांच करनी चाहिए बल्कि अन्य कारकों की भी जांच करनी चाहिए थी। क्योंकि डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अंतर्गत ऐसा करना उनका नैतिक दायित्व है।
 - (ii) **आयात कीमत**: प्रारंभिक जांच परिणाम में महानिदेशक ने आयातों में प्रोत्कर्ष का पता लगाने के लिए कम कीमत वाले आयातों में कथित वृद्धि पर भरोसा किया था। तथापि, रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने में जांचकर्ता प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी चाहिए कि क्या आयातों में प्रोत्कर्ष हुआ है, न कि कम कीमत वाले आयातों में।
 - (iii) **कारणात्मक संबंध**: जांचकर्ता प्राधिकारी को अन्य संभावित कारकों के क्षतिकारी प्रभाव को पृथक करने एवं उनमें उसका विभेद करने के लिए गैर-उपरोपण युक्त विश्लेषण प्रदान करना चाहिए, जो विधि द्वारा अपेक्षित है।
- ज. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत : प्रारंभिक जांच परिणाम सभी हितबद्ध पक्षकारों अवसर प्रदान किए बिना और याचिकाकर्ता के दावे पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने की अनुमित दिए बिना जारी नहीं किया जा सकता है। यह प्रथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है जिसमें विधिवत जांच की मांग की जाती है और जो अपनी रक्षा करने का अवसर प्रदान करती है।
- झ. अनपेक्षित विकास : कोरिया गणराज्य और हुंडई स्टील को अनपेक्षित विकास के संबंध में महानिदेशक के तर्कों के लिए उत्तरदायी होना मुश्किल है क्योंकि उन्होंने अपने जांच परिणाम में कहीं भी कोरिया और हुंडई द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख नहीं किया है।
- ञ. समायोजन योजना : रक्षोपाय जांच याचिकाकर्ताओं से एक व्यापक समायोजन योजना बनाने और यह स्पष्ट करने की अपेक्षा करती है कि उन्हें अपने संगठनों का पुनर्गठन करने के लिए समय और आपात राहत की जरूरत है।

- ट. अनुचित संरक्षण : भारत में अपने घरेलू उद्योग की अधिक रक्षा करने के लिए जाना जाता है। इससे कोरिया गणराज्य और शेष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उनके संबंध एवं भविष्य की व्यापार स्थिति को जोखिम उत्पन्न हो जाना चाहिए।
- ठ. जनिहत: हुंडई स्टील से इस संबद्ध वस्तु के आयातों ने भारतीय उद्योग की मांग को पूरा करने में अपना योगदान दिया है और विभिन्न देशों से आयातों के विरूद्ध घरेलू उत्पादकों को अधिक संरक्षण देकर याचिकाकर्ताओं की अभिभावी स्थिति को प्रबल बनाने के बजाय अंतिम प्रयोक्ताओं तथा उपभोक्ताओं के विभिन्न हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है।
- ड. पिकलिंग एवं आयालिंग युक्त हाट रोल्ड कॉइल : हुंडई स्टील कोरिया अपने पीओ उत्पाद की बिक्री एचएसआईएल को करती है जो इसके बदले में इस पण्य वस्तु की बिक्री एक सहबद्ध ग्राहक हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को आटोमोबाइल उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिए बेचती है। इन पीओ उत्पादों का विनिर्माण मुख्यत: और विशेषत: हुंडई मोटर के आटोमोबाइल्स के लिए किया जाता है। हुंडई स्टील हुंडई मोटर्स के लिए उत्पादित पीओ उत्पादों का विशेष परीक्षण होती है और उनकी विनिर्माण प्रक्रिया भी विशेष होती है। इसलिए वे अप्रतिस्थापनीय हैं, उन्हें किसी अन्य वस्तु से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने से हुंडई वाहन के लिए भारी गुणवत्ता निष्पादन मुद्दा उत्पन्न हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप भारत में आटोमोबाइल के चालकों की सुरक्षा को जोखिम उत्पन्न हो जाएगा। यह ही वह कारण जिसकी वजह से इन पीओ उत्पादों की कीमतें अन्य हाट रोल्ड कॉइल उत्पादों की कीमतों की तुलना में बहुत अधिक हैं। इसलिए, इन पीओ उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें एपीआई ग्रेड स्टील, सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील और (5) पांच अन्य अपवर्जित उत्पाद प्रकारों के साथ सुचीबद्ध किया जाना चाहिए।

आयातकों, प्रयोक्ताओं और एसोसिएशनों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

XV. महाराष्ट्र एसोसिएशन परिसंघ (एफएएम) : एफएएम मुंबई आधारित महाराष्ट्र की व्यापार एसोसिएशनों का शीर्ष संगठन है जिसमें 1000 ट्रांसपोर्ट, लघु उद्योग और महाराष्ट्र की एसोसिएशनें हैं।

- क. स्टील सेक्टर को कुछ ऐसे कारकों से ऋण एवं घाटा हो रहा जिनके लिए भारत में स्टील की आयात कीमतों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- ख. अग्रिम प्राधिकृतीकरण के अंतर्गत आयातित मात्रा से आयातकों को क्षति नहीं हो सकती है।
- ग. इस मामले में अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने में अनावश्यक शीघ्रता की गई।
- घ. यह पीयूसी आवेदकों की क्षमता की केवल 9 प्रतिशत है।
- ङ. भारत में आंकड़ों का संग्रहण एवं अनुरक्षण करने के लिए जेपीसी इस्पात मंत्रालय द्वारा शासकीय रूप से अधिकार प्राप्त एक एजेंसी है। जेपीसी आंकड़ों और इस आवेदन में भरोसा किए गए आईबीआईएस आंकड़ों में भारी अंतर है।
- च. यह आरोप लगाया गया है कि आयातों में भारी प्रोत्कर्ष बिक्री टर्नओवर में भारी गिरावट, क्षमता उपयोग में गिरावट संगत घाटे और रोजगार स्तर में कमी आई है जो क्षति संकेतकों से स्पष्ट है। यह सभी आधारभूत पैरामीटर आवेदकों के वर्तमान मामले में गुम हैं।

आयातकों में कथित प्रोत्कर्ष ('000 टन)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
जेपीसी के अनुसार आयात	1812	1871	1104	2006
अनुक्रमित	100	103	60	109

जेपीसी आंकड़ों के अनुसार 4 वर्षों की अवधि के दौरान (जो प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए अधिक तर्कसंगत अवधि है) वृद्धि केवल 9 प्रतिशत के लगभग है। वर्ष 2013-14 की अवधि की तुलना में वर्ष 2014-15 में आयातों के प्रोत्कर्ष का आरोप लगाते समय इस तथ्य पर उचित ध्यान नहीं दिया गया कि पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान डालर के अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव के कारण 40 प्रतिशत की एक असामान्य गिरावट आई थी।

इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने डालर की इस अस्थिरता एवं संवर्धित आयातों की स्थिति का लाभ उठाया और इसलिए भारतीय उपभोक्ताओं की लागत पर घरेलू कीमतें बहुत अधिक रखी गईं।

- छ. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के बिक्री आंकड़ों का अध्ययन करने पर इस अवधि में इसमें लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है। इसी तरह स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के आंकड़ों का अध्ययन करने से इसमें इसके बिक्री कारोबार की कमोवेश स्थिर स्थिति प्रदर्शित हुई है।
- ज. इन दोनों आवेदनकर्ताओं के मामले में प्रमुख कच्चे माल जैसे लौह अयस्क, कोकिंग कोल और कोक की कीमतों में लगभग 40-60 प्रतिशत की गिरावट होने के बावजूद उनकी वार्षिक बिक्री की प्रवृत्ति संवर्धित/स्थिर बनी रही।
- झ. इसी अवधि के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के क्षमता उपयोग में आधार वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 में लगभग 62 प्रतिशत का प्रोत्कर्ष हुआ और तद्वारा उन्होंने लगभग उत्पादकता का 88 प्रतिशत प्राप्त कर लिया।
- ञ. दूसरी ओर एस्सर स्टील इंडिया लिमिटेड ने अपनी क्षमता का कम उपयोग किया जिसको वित्तीय अनुशासनहीनता और कच्चे माल की अनुपलब्धता पर उपरोपित किया जा सकता है। तथापि, उन्होंने अपने निष्पादन को अन्य आवेदनों के निष्पादन आंकड़ों के साथ जोड़कर यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि घरेलु उद्योग की समग्र स्थिति बहत खराब है।
- ट. सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों ने ही अभिनव तिमाही में कुछ धुंधली स्थिति को छोड़कर पिछले चार वर्षों की अवधि में तर्कसंगत लाभ प्रदर्शित किया है। वास्तव में जेएसडब्ल्यू स्टील के मामले में विदेशी सब्सिडियों द्वारा उपचित घाटे को, जब भारतीय प्रचालनों के लिए समेकित/अंतरित किया जाए तो यह गलत स्थिति को प्रदर्शित करता है जैसाकि उसके वित्तीय विवरणों से देखा जा सकता है।
- ठ. इन आवेदकों की लाभप्रदता, विशेष कर ऐसे समय में जब विश्व में सपूर्ण इस्पात उद्योग को भारी घाटा हो रहा हों, केवल यह अभिव्यक्त करती है कि किस तरह भारतय उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूली की जा रही है।
- ड. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त आवेदकों में से कुछ आवेदक ऐसे हैं जिन्हें वित्तीय अनुशासनहीनता की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन कंपनियों की लेखा बहियां अपने कार्य व्यवहार की सही एवं स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर रही हैं और वे स्पष्टतया दिखावे की तकनीक अपना रही हैं। हितबद्ध पक्षकार इस प्राधिकारी से केवल यह अनुरोध करता है कि वह सीएजी ऑडिट का आदेश दे ताकि इन कंपनियों के मामलों की सच्चाई उजागर की जा सके।
- ढ. आधारभूत पारिश्रमिक एवं वेतन में कथित गिरावट के बावजूद पिछले चार वर्षों में इन आवेदकों की रोजगार लागत में सतत वृद्धि हुई है।
- ण. इस संबद्ध स्टील वस्तु का विनिर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख कच्चा माल लौह अयस्क और कोकिंग कोल है। इन कच्चे माल की कीमतों में 40-60 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- त. यह उपयुक्तत: तर्कसंगत है कि इन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत को भी तदनुसार ही समायोजित किया जाए। तथापि, यह नोट करना रूचिकार है कि इसके बावजूद इन आवेदकों की बिक्री में वृद्धि हुई।
- थ. संबद्ध वस्तु जिसका प्रयोग कितपय रोलर मिलों जैसे पोस्को, उत्तम स्टील, नेशनल स्टील्स, एशियन कलर कोटेड आदि में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, यह नोट किया जाना जरूरी है कि पीयूसी एक कच्चा माल है न कि व्यापार के लिए एक उत्पाद। इन मामलों में पीयूसी पर पुन: कार्य किया जाता है और उन्हें कोल्ड रोल्ड शीट्स/गाल्वनाइज्ड शीट्स/कोरूगेटेड शीट्स आदि के रूप में संपरिवर्तित किया जाता है। अकेले पोस्को ने ही महाराष्ट्र स्थित अपने निजी संयंत्र के लिए मई, 2014 से सितम्बर, 2015 के बीच की अवधि में इस प्रयोजनार्थ इस संबद्ध वस्तु की लगभग 0.95 मिलियन टन की मात्रा का आयात किया था।
- द. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि इन आयातों तथा अन्य कोल्ड रोलर मिल्स को उपरोपित किए गए आयातों की मात्रा को आवेदकों द्वारा यथा प्रस्तुत कुल आयात आंकड़ों में से हटा दिया जाए तो इस अविध के दौरान भारत में इस संबद्ध वस्तु के आयातों में वास्तव में गिरावट प्रतीत होगी। वास्तव में, स्थानीय संयंत्र यह संबद्ध उन्हें प्रदान करने के लिए पोस्को पर इस कारण से निर्भर हो गए क्योंकि वह इस वस्तु की अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा का उत्पादन करने में अक्षम थे। ऐसे कच्चे माल के आयातकों की कुल मात्रा भारत में इस पीयूसी के कुल आयातों का लगभग 35-40 प्रतिशत भाग होगा।
- ध. आवेदकों ने यह तर्क दिया है कि मलेशिया और थाइलैंड जैसे दोनों ने भी क्रमश: रक्षोपाय शुल्क तथा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करके इन प्रशुल्क अवरोधों का आश्रय लिया है। तथापि, एतद्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन देशों में उस विशिष्ट समय पर आयातों और अन्य पैरामीटरों में प्रोत्कर्ष बहुत अधिक संवेदनशील था। इनकी तुलना भारत की वर्तमान स्थिति से किसी भी रूप में नहीं की जा सकती है।

- न. तथ्यों एवं आंकड़ों से इन सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ कि अलाय स्टील के आयातों में कोई यकायक एवं तीव्र वृद्धि नहीं हुई जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई हो अथवा किसी गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।
- प. अलाय स्टील उत्पादों के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को न तो कोई गंभीर क्षति हुई और न ही गंभीर क्षति की कोई चुनौती उत्पन्न हुई और घरेलू उद्योग को किसी गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती के अभाव में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन होगा।
- फ. रक्षोपाय नियमावली में यथावर्णित पूर्वापेक्षाएं मौजूदा नहीं है और इस कारण घरेलू उद्योग का कोई भारी समग्र अपक्षयण खासकर संबद्ध उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से और निर्वाध रूप से आयातों की दर एवं मात्रा में वृद्धि घरेलू बाजार के हिस्से पर इन संवर्धित आयातों के कब्जे, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग लाभ और हानि एवं रोजगार में परिवर्तन के रूप में नहीं हुआ और इनमें से किसी पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा जैसा कि आवेदकों ने गलत प्रतिनिधित्व किया है।
- ब. आवेदकों ने ऐसे उत्पादों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की मांग की है जिनको अपनी पृथक पहचान से भिन्न उत्पादों के रूप में पृथकत: श्रेणीबद्ध किया गया है।
- भ. आवेदकों ने ग्राही खपत के लिए किए गए आयातों का भी अपवर्जन नहीं किया है, जिनका अपवर्जन संपूर्ण आयातों का संगणन करते समय किया जाना चाहिए था। आवेदकों ने अग्रिम प्राधिकृतीकरण के अंतर्गत किए गए आयातों अर्थात निर्यात के लिए किए गए आयातों का भी अपवर्जन नहीं किया है जिनका संपूर्ण आयातों का भी अपवर्जन नहीं किया है जिनका संपूर्ण आयातों का संगणन करते समय अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए था। किसी आपात स्थिति के अभाव में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने और ऐसे अधिरोपण द्वारा किसी उद्देश्य को प्राप्त किए जाने के बीच कोई संबंध नहीं है। आवेदकों का क्षमता उपयोग इष्टतम स्तर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड से ऊपर हो गया है। इष्टतम क्षमता उपयोग के बावजूद, घरेलू उद्योग द्वारा अलाय स्टील का उत्पादन नगण्य है। आवेदकों ने गलत ढंग से रक्षोपाय साधनों पर भरोसा किया है जैसािक अन्य देशों अर्थात थाईलैंड द्वारा रक्षोपाय शुल्क तथा मलेशिया द्वारा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करके किया है। परंतु यह पूर्णतया असंगत है और यह भारत में व्याप्त स्थिति पर लागू नहीं होता है।
- म. जिस रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की मांग की गई है उसकी प्रकृति एवं प्रमात्रा मनमानी है और इसका कोई आधार नहीं है। आवेदकगण रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कराके अप्रत्याशित लाभ कमाना चाहते हैं और उन्हें प्राधिकारी के समक्ष तथ्यों की गलतबयानी नहीं करनी चाहिए थी। उपर्युक्त सभी पहलू यह साक्ष्यांकित करते हैं कि अलाय स्टील के आयातों में कोई भी आयात अचानक एवं इतनी तीव्र गित से नहीं हुआ कि उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षित कारित हुई हो अथवा गंभीर क्षित की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।

XVI. पूर्वा मेटल सेक्सन्स प्राइवेट लिमिटेड

- क. हमें स्टील पाइप्स और ट्यूब्स का विनिर्माण करने क लिए कच्चे माल के रूप में एचआर कॉइल्स की जरूरत पड़ती है। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से हमारे कच्चे माल की अधिप्रापण लागत में भारी उछाल आ जाएगा और हमारे उत्पाद की लागत में अतर्कसंगत वृद्धि होगी, तद्वारा बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता समाप्त हो जाएगी।
- ख. एक ओर तो हमें उच्च उत्पादन लागत उपचित करनी होगी बही दूसरी ओर विदेशी निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा की चुनौती सदैव बनी रहेगी।
- ग. रक्षोपाय शुल्क का क्रियान्वयन करके आप जानबूझकर भारत में एकाधिकारवादी व्यापार प्रक्रिया का सृजन करेंगे एवं उसका समर्थन करेंगे।
- घ. यदि इस जांच में रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की जाती है तो हम आपसे भारत में स्टील पाइप्स और ट्यूब्स के आयातों पर भी रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का अनुरोध करते हैं।

XVII. भारत चैम्बर आफ कॉमर्स

- क. रक्षोपाय शुल्क को अधिरोपण का आटोमोबाइल, विनिर्माण और उन उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जो कच्चे माल के रूप में एचआर स्टील कॉइल्स का उपयोग करते हैं।
- ख. इंजीनियरिंग उद्योग संपूर्ण विश्व में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खो देगा।

ग. रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का विनिर्माण उद्योग पर भी प्रभाव पड़ेगा और इससे "मेक इन इंडिया" अभियान भी प्रभावित होगा।

XVIII. मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड: मित्सुई एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त उद्यम के रूप में आईएससी (इंडियन स्टील कारपोरेशन) में निवेश किया है। आईएससी कोल्ड रोलिंग, गाल्वनाइजिंग और पेटिंग स्टील मिल के कार्यों में अंतर्ग्रस्त है। वे जापान से एचआरसी का आयात कर रहे हैं। उनके प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं:

- क. आयातों के स्थान पर इतनी अल्प अवधि में एचआरसी का स्थानीय अधिप्रापण करना वित्तीय (भुगतान के रूप में) गुणवत्ता और विभिन्न साइजों की उपलब्धता तथा आर्थिक बिंदु (कीमत) के दृष्टिकोण से संभव नहीं होगा।
- ख. स्टील अथवा कच्चा माल है। तथापि, एचआरसी पर यदि रक्षोपाय शुल्क का क्रियान्वयन किया जाता है तो यह अनुप्रवाही उद्योग की अर्थक्षमता तथा विकास की संभावना को क्षतिग्रस्त कर देगा।

XIX. निजोन स्ट्रिप्स लिमिटेड एंड निजोन ट्यूब्स लिमिटेड : निजोन स्ट्रिप्स लिमिटेड और निजोन ट्यूब्स लिमिटेड ब्लैक पाइप्स, सीआर स्ट्रिप्स और प्रिसीजन ट्यूब्स के उत्पादक है। उनके प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित हैं :

- क. हम 2.00 एमएम और उससे कम की मोटाई के एचआर कॉइल का आयात करते हैं क्योंकि हमारे नियमित आपूर्तिकर्ता मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड ने कुछ अवरोधों के कारण इसकी आपूर्ति करना बंद कर दिया है। इसलिए, हम इस विशिष्ट उत्पाद का आयात करने पर मजबूर हैं और इसे उत्पाद के दायरे अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए।
- ख. हमने अपने निर्यातक के साथ एक समझौता पहले से ही कर रखा है और यह शुल्क उन लेनदेनों पर उदग्रहित किया जाता है जो शुल्क का अधिरोपण करने से पहले कारगर ढंग से पूरे कर लिए गए हों और इस प्रकार यह भूतलक्षी प्रकृति का होता है, हमारा विश्वास है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं होगी।
- ग. 76 प्रतिशत का क्षमता उपयोग यह दर्शाता है कि हालात इतने चुनौतीपूर्ण नहीं जितना चुनौतीपूर्ण उन्हें बना दिया गया है।
- घ. 12 प्रतिशत का बाजार हिस्सा चिंता का विषय नहीं है यदि हम इसे इस तथ्य के आलोक में देखते हैं कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पाद में वृद्धि नहीं हुई है।
- ङ. लौह अयस्क, कोयला और तेल की कीमतों में कमी होने के कारण इस्पात सामग्री की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय रूप से कमी आई है। चूंकि आधारभूत कच्चे माल की कीमत में गिरावट हुई है इसलिए घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी आने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।
- च. भारत में एचआर काइल के लिए मांग समाप्त हो जाएगी क्योंकि अनुप्रवाही उत्पादों का आयात होने लगेगा और इस प्रकार घरेलू उद्योग की संरक्षा करने का रक्षोपाय शुल्क का प्रयोजन ही निरर्थक हो जाएगा।
- छ. इससे सरकार की "मेक इन इंडिया" नीति भी प्रभावित होगी और भारत में अंतिम उपभोज्य उत्पाद का पाटन होने लगेगा और भारत के लाखों उद्योग समाप्त हो जाएंगे।

XX. प्रभात स्टील ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड

- क. पीएसयू बैंकों के स्टील एक्सयोजर का 1/5वां हिस्सा पहले से ही पुनर्गठित किया गया है। इस कार्य में 12 से 18 महीने का समय लगता है। इसका आशय यह है कि कंपनियां वर्षों पहले से ही त्रुटि कर रही हैं जिसके लिए लागत में अनुशासनहीनता, कच्चे माल की आपूर्ति का राजनीतिक मुद्दे के उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। स्टील उद्योग की इस हालत के लिए आयात उत्तरदायी नहीं है।
- ख. जेपीसी आंकड़े दर्शाते हैं कि लगभग 1 मिलियन टन का निर्यात घरेलू कीमतों से कम कीमतों पर हुआ जिसने एक ऐसा असंतुलन पैदा कर दिया जिसकी भरपाई आयातों द्वारा की गई।
- ग. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से परिष्कृत वस्तु का आयात बढ़ोग जिससे भारतीय विनिर्माता और अधिक गैर-प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे।

- घ. संवर्धित आयात आंकड़ों में सबसे बड़े संघटकों में से एक पोन्को और चाइना स्टील कारपोरेशन के आयात की मात्रा है जो अपनी पैरेंट कंपनियों से एचआर कॉइल का आयात क्रमश: महाराष्ट्र और गुजरात में अपने नए शुरू किए गए स्टील संयंत्रों में कोल्ड रोल्ड और इलेक्ट्रिकल शीट्स में संपरिवर्तित करने के लिए करते हैं।
- ङ. कुछ उद्योगों को सही आकार, गुणवत्ता और सही कीमतों में अपने उत्पादों की उपलब्धता न होने के कारण आयात करने को मजबूर होना पड़ा।

XXI. कोल्ड रोल्ड स्टील मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (कोर्समा)

- क. वर्ष 2014-15 के दौरान एचआर कॉइल्स का आयात बहुत अधिक था क्योंकि भारतीय उत्पादकों ने घरेलू बाजार में कमी होने की स्थिति क बावजूद घरेलू बाजार में कमी बनाए रखने के उद्देश्य से 1 मिलियन टन एचआर काइल्स का निर्यात वैश्विक कीमतों से कम कीमत पर किया।
- ख. परीक्षण किए गए आंकड़े वर्ष 2010-2011 से शुरू करके वर्ष 2015-16 तक के 5 वर्षों के आंकड़े होना चाहिए। यह उल्लेख किया जा सकता है कि 2013-14 स्टील उद्योग के सबसे अधिक बुरा वर्ष था क्योंकि उस वर्ष स्टील का आयात और उसकी खपत निचनोतम स्तर पर पहंच गई और इसे जांच के लिए आधार वर्ष के रूप में नहीं लिया जा सकता है।
- ग. एचआर काइल्स के उत्पादक पहले से ही 12.5 प्रतिशत सीमाशुल्क ड्यूटी द्वारा संरक्षित हैं। इस 12.5 प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क के साथ-साथ 30 यूएस डालर का समुद्री भाड़ा और लगभग 15 यूएस डालर का आकस्मिक प्रभार कुल मिलाकर लगभग 90 यूएस डालर प्रति टन हो जाता है और उतराई कीमत आधार पर निर्धारित घरेलू कीमतें लगभग 90 यूएस डालर प्रतिमीटर तक अधिक हो जाती हैं जिससे घरेलू और विश्व बाजार दोनों में विनिर्माण सेक्टर की वैश्विक प्रतिस्पर्धा का क्षरण होता है और इसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग की कीमत पर विनिर्मित स्टील उत्पादों का आयात होता है। 20 प्रतिशत की दर से रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से संरक्षा का स्तर और अधिक बढ़ जाएगा और घरेलू कीमतें 64 यूएस डालर बढ़ जाएंगी जो भारतीय विनिर्माण उद्योग तथा "मेक इन इंडिया" मिशन के लिए विनाशकारी होगा।
- घ. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के परिणामस्वरूप विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता का क्षरण होगा।
- ङ. पिछली तीन याचिकाएं पाटनरोधी निदेशालय, रक्षोपाय निदेशालय तथा कलकत्ता एवं दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यों की गलत बयानी के कारण खारिज कर दी गई थी।
- च. अनन्तिम शुल्क का अधिरोपण तथ्यों का सुनिश्चयन करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात किया जाना चाहिए था।
- छ. यह याचिका अधिकृत जेपीसी आंकड़ों पर आधारित नहीं है। इस्पात मंत्रालय के अधीन संयुक्त प्लांट समिति स्टील उद्योग के लिए सरकारी एवं प्रामाणिक डाटा बैंक हैं और एचआर काइल के उत्पादक व्यापक आंकड़े जेपीसी को उसकी रिपोर्ट में संकलित करने के लिए भेजते हैं। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कराने के लिए यह याचिका एक गैर-सरकारी एजेंसी से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है जो प्रामाणिक नहीं है और इन आंकड़ों को याचिकाकर्ताओं द्वारा परिवर्तित (मैनुपुबेट) भी किया गया है।
- ज. यह देखा गया कि जांच की अवधि को डीजीएसजी द्वारा कम करके 2 वर्ष और एक तिमाही कर दिया गया जो बहुत अल्प अवधि है और यह सुस्थापित प्रवृत्ति के विपरीत है। पीओआई बढ़ाकर कम से कम 5 वर्ष कर दी जानी चाहिए।
- झ. पीयूसी की अपवर्जन सूची में कम से कम 4 और ग्रेडों का जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारी कस्टम ड्यूटी के कारण एचआर काइल्स के बजाय विनिर्मित वस्तुओं का आयात न होने लगे।
- ञ. भारी आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि एचआर काइल्स के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, न तो क्षमता उपयोग में कोई कमी आई और न ही कामगारों की कामबंदी हुई है।
- ट. कच्चे माल की कीमतों में भारी कमी के कारण एचआर काइल्स की वैश्विक कीमतों में कमी हुई है स्टील विनिर्माण क लिए आधारभूत इनपुटों जैसे आयरन और, कोकिंग कोल, आयल एवं लुब्रीकेंट्स की वैश्विक एवं घरेलू कीमतों में प्रपाती कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप एचआर काइल्स की वैश्विक कीमतें भी कम हुई हैं।
- ठ. यह आरोप भी निराधार है कि चीन से स्टील के सस्ते आयात भारी मात्रा में हुए हैं क्योंकि अप्रैल-जून, 2015 में कुल आयातों में चीन के आयातों का हिस्सा केवल 28 प्रतिशत है जबकि एचआर काइल्स में इसका हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत है।
- ड. एचआर काइल्स के विनिर्माता भारी ऋण भार से दब गए क्योंकि उन्होंने अनुत्पादक निवेश अधिक किया।
- ढ. एचआर काइल्स के घरेलू विनिर्माता ग्राही लौह अयस्क और कोल माइन्स के होते हुए भी वैश्विक कीमतों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके क्योंकि उनके पास वह तकनीक और उत्पाद विकास नहीं था।

XXII. सूर्या रोशनी लिमिटेड

- क. यदि यह पाया गया कि एचआर काइल के विनिर्यात ख्ज्ञति सहन कर रहे हैं तो सभी अनुप्रवाही उत्पाद उद्योग जैसे कोल्ड रोल्ड, जीपी/जीसी शीट्स/काइल, एमएसईआरडब्ल्यू और स्पाइरल पाइप, कलर कोटेड स्टील आदि को भी शामिल करके रक्षोपाय शल्क पर विचार करना चाहिए।
- ख. यदि अनुप्रवाही उत्पादों पर शुल्क का अधिरोपण किए बिना एचआर काइल पर रक्षोपाय शुल्क लगा दिया जाता है तो इससे कच्चे माल के रूप में एचआर काइल को उपयोग करने वाले अनुप्रवाही उद्योग की भी गंभीर क्षति होगी।

XXIII. ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद) : ईईपीसी इंडिया के अधिकांश सदस्य, जो एमएसएमई इंजीनियरिंग विनिर्माता इकाइयां और निर्यातक हैं, ने एचआर काइल, जो संपूर्ण इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है, पर रक्षोपाय शुल्क के संभावित अधिरोपण पर चिंता जताई है।

- क. एचआर काइल पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपा करने का आटोमाबाइल, परिवहन उपकरण, विनिर्माण उपकरण, फेब्रीकेटेड स्टील उत्पाद आदि पर प्रभाव पड़ेगा।
- ख. कच्चे माल के रूप में एचआर काइल का प्रयोग करने वाला इंजीनियरिंग उद्योग संपूर्ण विश्व में अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा। परिष्कृत वस्तु के आयात बढ़ेंगे, इससे घरेलू विनिर्माता और मेक इन इंडिया पहल प्रभावित होगा।

XXIV. सुनील त्रिपाठी

- क. इस संबद्ध वस्तु केलिए सदैव ही कस्टम ड्यूटी में दो-स्तर की बढ़ोतरी हुई है, कोल्ड रोल्ड उत्पादों पर दो पाटनरोधी कार्रवाइयां पहले से ही प्रभावी है और उस पर गैर-टैरिफ अवरोध भी है जिसमें विदेशी आपूर्तिकर्ता को बीआईएस के पास पंजीकृत होना अपेक्षित है।
- ख. रक्षोपाय शुल्क लगाने से अनुप्रवाही उद्योग तथा अन्य लघु विनिर्माता प्रभावित होंगे।

XXV. गोदरेज एंड बायस मैन्यूफैक्टचरिंग लिमिटेड : गोदरेज एंड बायस मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड जांच की अविध के दौरान इस संबद्ध वस्तु का आयातक रहा है।

- क. 600 एमएम से अधिक के एचआर काइल्स पर लगे 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क से एकीकृत स्टील के कुछ बड़े विनिर्माताओं को ही लाभ होगा परंतु यह संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में स्टील के प्रयोक्ताओं के लिए अनर्थकारी होगा।
- ख. स्टील प्रयोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के जरिए सरकारी खजाने में किए गए योगदान स्टील विनिर्माताओं द्वारा किए गए योगदान से अधिक है। स्टील प्रयोक्ताओं द्वारा मिलियन्स की संख्या में रोजगार सृजित किया जाता है, सरकार को इन कारकों पर विचार करना चाहिए क्योंकि इन दोनों कारकों का आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
- ग. 12 प्रतिशत नियमित कस्टम ड्यूटी के अलावा 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क से चीन के अलावा अन्य सभी देशों से आयात प्रतिनिषिद्ध कर देगा। कीमतों में बेतहासा वृद्धि का स्टील प्रयोक्ता उद्योग के विकास पर प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही गिरावट और न्यून स्थिति में हैं।
- घ. एचआर स्टील की संपूर्ण रेंज अर्थात हाई टेन्साइल, हाई स्ट्रेंथ इम्पैक्ट रेजिस्टेंट जिसका इस समय भारतीय स्टील उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है और जिसका अंतिम प्रयोक्ता द्वारा आयात किया जाता पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का कोई औचित्य नहीं है।
- ङ. चीन स्टील का आयात एफओबी दर पर करता है सरकार चीन से आयातों को नियंत्रित कर सकती है परंतु जापान कोरिया जैसे अन्य देशों से ब्लैंकेट आयात को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है जिनके साथ हमारा मुक्त व्यापार करार है।
- च. रक्षोपाय शुल्क का हमारे एफटीए देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा और इन देशों को हमारे निर्यात भी प्रभावित होंगे।
- छ. एचआर काइल्स पर रक्षोपाय शुल्क और कस्टम ड्यूटी लगभग 32.5 प्रतिशत है, जबिक परिष्कृत वस्तु पर कस्टम्स ड्यूटी बहुत कम (औसत 10 प्रतिशत) है और इसलिए परिष्कृत उत्पाद का आभाव, खासकर चीन से बढ़ेगा जो हमारी मेक इन इंडिया नीति के विपरीत होगा।

XXVI. टेक्सटाइल्स मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन ("इंडिया") : इसके एक सदस्य लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड कोयम्बटूर, जोइस संबद्ध वस्तु का आयातक है, ने ही अभ्यावेदन किया है।

- क. देश में ऐसा कोई विनिर्माता नहीं है जो "एमएस मोटाई से अधिक की मोटाई के हाट रोल्ड स्किन पास्ड पिकल्ड एंड आयल्ड लेजर स्टैबिलाइज्ड शीट्स की आपूर्ति करता हो।
- ख. 600 एमएम अथवा उससे अधिक की मोटाई के सभी हाट रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क लगाना विवेकपूर्ण नहीं होगा।

XXVII. आटोमोटिव कम्पोनेंट्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एक्मा) : एक्मा इस संबद्ध वस्तु के आयातकों/प्रयोक्ताओं का एक एसोसिएशन है।

- क. कच्चे माल की कीमत का स्टील उद्योग पर भारी प्रभाव पड़ता है :
 - (i) अगस्त-सितम्बर, 2014, अक्तूबर-नवम्बर, 2014 में चीन में कम होती मांग और चीन के निर्यातकों के लिए बढ़ती वैश्विक बेशी के बीच एचआर की कीमतों में कमी आई। यूएस ऊर्जा सेक्टर में मांग में कमी तथा विश्व बाजार में अधिक आपूर्ति के कारण दिसम्बर, 2014, जनवरी, 2015 में कीमतें कम हुईं।
 - (ii) रक्षोपाय शुल्क घरेलू संघटक विनिर्माताओं के लिए कच्चे माल का प्रापण और भी अधिक मंहगा हो जाएगा। इससे वे घरेल बाजार में पर्णतया अप्रतिस्पर्धी हो जाएंगे और यही हाल निर्यात का भी होगा।
 - (iii) वित्त वर्ष 2015 की चौथी तिमाही में आटोमोटिव उद्योग ने 9 प्रतिशत की वाईओवाई उत्पादन वृद्धि (वाहन मात्रा) की सूचना दी जबिक दुपहिया और तिपहिया वाहन सेगमेंट ने भारी वृद्धि हुई और सुदृढ़ निर्यात हुआ।
 - (iv) आज भारतीय आटोमोटिव उद्योग कच्चे माल की उच्च कीमतों और गिरती लाभप्रदता के बोझ के तले दवा है।
 - (v) अनपेक्षित एवं अचानक कार्रवाई मेक इन इंडिया कार्यक्रम के विपरीत है।
 - (vi) एक ऐसे समय पर जब भारतीय आटो संघटक उद्योग भारत के साथ एफटीए वाले देशों से सर्वर्धित प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, यह आवश्यक है कि उद्योग को कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के विरूद्ध कुछ राहत प्रदान की जाए।
 - (vii) आटोमोटिव मिशन प्लान 2016-26 में भारतीय आटोमोटिव उद्योग का विजन है कि वह विश्व में इंजीनियरिंग तथा विनिर्माण में और वाहन तथा आटो संघटकों के निर्यात में चोटी के तीन देशों में शामिल हो। भारत की जीडीपी में 12 प्रतिशत की वृद्धि करने और 65 मिलियन अतिरिक्त रोजगार मृजित करने का भी लक्ष्य है। ऐसी उम्मीद है कि आटो संघटक उद्योग अगले 10 वर्षों में अपने वर्तमान निर्यात स्तर 11.2 बिलियन यूएसडी से बढ़कर वर्ष 20126 में 80 बिलियन यूएस डालर तक पहुंच कर वर्तमान 40 बिलियन यूएस डालर के मौजूदा कारोबार स्तर से बढ़कर 200 बिलियन यूएस डालर कारोबार करके पांच गुना वृद्धि करेगा।

XXVIII. **एचबी सन्स, नागौन (असम)** : वे नागौन में स्टील मदों के प्रयोक्ता/रिटेलर हैं। उनका तर्क है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने से मध्यम उद्योग इस स्थिति का लाभ उठाएंगे और वे अपनी कीमतों में असामान्य वृद्धि कर देंगे।

XXIX. एशियन कंटेनर्स (विराट इंडस्ट्रीज) : वे ऐरोसोल कैन्स का निर्माण करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेटों के प्रयोक्ता हैं।

- क. टिन प्लेट्स के स्थानीय विनिर्माता गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों रूपों में हमारी जरूरत को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। अतर्कसंगत कीमत निर्धारण करने से हमारे लिए उपभोक्ताओं के बजट के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है और हमारी सेवा एवं सुपुर्दगी कम पड़ जाती है।
- ख. टिन प्लेट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गई जिससे अन्य पैकेजिंग सामग्री की तुलना में टिन प्लेट्स अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई। इसके अतिरिक्त, स्थानीय टिन प्लेट्स की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है उनमें पिन होल्डस आदि होते हैं जो बाजार सुरक्षा एवं पर्यावरण के लिए अवरोधक होते हैं।

XXX. वर्ल्ड ट्रेड स्कैनर: यह एक साप्ताहिक पत्रिका है और तर्क देते हैं कि इस मामले में भारतीय उत्पादकों के तर्कों के अलावा अन्य दृष्टिकोणों से भी विचार करने की जरूरत है।

XXXI. यूनाइटेड स्यूमन राइट्स फेडरेशन (यूएचआरएफ): यूएचआरएफ लोगों की सामान्य समस्याओं को उसका निराकरण करने क लिए उठाती है और जनहित की रक्षा करने में लगी है। उसके प्रस्तुतिकरण मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (कोर्सया) द्वारा दायर पत्र पर आधारित हैं। यूएचआरएफ इस उत्पाद पर प्रारंभिक रक्षोपाय शुल्क लगाने के निर्णय के विरुद्ध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या (सिविल) 764 वर्ष 2015 दायर कर रखी है। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 30.10.2015 के आदेश के तहत वह रिट याचिका निस्तारित कर दी और याचिकाकर्ता/यएचआरएफ को उसे वापस लेने की अनुमति इस आजादी के साथ दे दी कि वह उचित राहत प्राप्त करने के लिए "समुचित फोरम/प्राधिकारी" से संपर्क कर सकता है। माननीय शीर्ष न्यायालय ने यह भी निदेश दिया कि "जब कभी ऐसी याचिका/याचिकाएं दायर की जाती है/हैं, हम समुचित फोरम/प्राधिकारी से यथासंभव शीघ्रता से उस पर विचार करने का अनुरोध करते हैं।" उनके प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

- क. यह शुल्क कंपनियों (मैसर्स सेल एवं अन्य) की गलत बयानी के आधार पर लगाया गया था।
- ख. रक्षोपाय महानिदेशक द्वारा जारी दिनांक 14.09.2015 की अधिसूचना का प्रशुल्क नियमावली में विहित परम्पराओं के अनुरूप नहीं किया गया। महानिदेशक (रक्षोपाय) की नियुक्ति 28.08.2015 को हुई और उन्होंने 7.09.2015 को कार्यभार ग्रहण किया और 7.9.2015 को ही जांच शुरूआत का नोटिस जारी कर दिया और 9.9.2015 को रक्षोपाय शुल्क लगाने की संस्तुति कर दी, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया।
- ग. घरेलू उद्योग की रक्षा करने के उद्देश्य से वह संगत जांच अवधि पर्याप्त लंबी होनी चाहिए जिसेस संवर्धित आयातों एवं गंभीर क्षति के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते।
- घ. दिनांक 9.9.2015 की अधिसूचना के लिए महानिदेशक रक्षोपाय ने जो सूचना का स्रोत लिया वह अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस सूचना सेवा थी और वह भी वर्ष 2013-14 और वर्ष 2015 की पहली तिमाही की सूचना थी।
- ङ. दिनांक 9.9.2015 की अधिसूचना के लिए महानिदेशक रक्षोपाय ने जो सूचना का स्रोत लिया वह अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस सूचना सेवा थी और वह भी वर्ष 2013-14 और वर्ष 2015 की पहली तिमाही की सूचना थी। यद्यपि रिपोर्ट में यह कहा गया था कि उसका स्थल दौरा करके सत्यापन कर लिया गया था पर दिनांक 9.9.2015 की अधिसूचना में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि किस स्थान का भ्रमण किया गया।
- च. रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए अधिसूचना में किसी तात्कालिकता में नहीं दर्शाया गया।
- छ. दिनांक 9.9.2015 की अधिसूचना के साथ पठित दिनांक 14.9.2015 की अधिसूचना में महानिदेशक रक्षोपाय इस रक्षोपाय शुल्क को लगाने के पीछे के कारण का औचित्य बताने में असफल रहे, ठी उस तरह जैसा आवेदक द्वारा पूछा गया था।
- ज. इस पर आश्रित होकर, स्थानीय इस्पात मिलें अपनी कीमत बढ़ा देंगी और उपयोक्ता उद्योग पर मुश्किल आ जाएगी। स्टील उद्योग के विशेषज्ञ यह भविष्यवाणी करते हैं कि छोटे एवं मध्यम उद्यमों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का इस तरह बंद होने से देश में लगभग 50000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
- झ. रक्षोपाय साधन के प्रयास के साथ-साथ निर्यातकों को शुल्क वापसी में भी वृद्धि की जानी चाहिए और चूंकि इन उदग्रहणों से घरेलू उद्योग प्रभावित होता है, इसलिए प्रति अदायगी दरें भी समान रूप से बढ़नी चाहिए।
- ञ. इसमें न तो विहित प्रक्रिया और न ही विहित समय-सीमा का पालन किया गया।
- ट. आवेदनकर्ता और संबद्ध देश के निर्यातकों की उत्पादन प्रक्रिया में कोई खास अंतर नहीं है।
- ठ. यह अधिसूचना उक्त संबद्ध वस्तु के संबंध में घरेलू बाजार के विचारों की पूर्ण अनदेखी करता है, इसने कच्चे माले की उच्चतर लागत के कारण अंतिम उत्पाद पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन नहीं किया ओर अंतिम प्रयोक्ता को अर्थदंड लगा दिया।
- ड. हाट रोल्ड काइल्स के घरेलू विनिर्माताओं के उदाहरण पर किसी मद पर आयात शुल्क का उदग्रहण वह आधार नहीं हो सकता है जिससे समसुत उद्योग को क्षति हो।
- ढ. हितबद्ध पक्षकारों के विचारों को ध्यान में नहीं रखा गया।
- ण. उक्त आवेदक आयातों तथा गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित करने में असफल रहे हैं और इसलिए उक्त अधिसूचना सीमाशुल्क प्रशुल्क नियमावली का उल्लंघन करके जारी की गई।
- त. अधिसूचना में इस तथ्य का कोई आधार नहीं है कि आवेदकों द्वारा की गई मांग के अनुरूप 20 प्रतिशत शुल्क कैसे लगा दिया गया। वर्ष 2009-10 और 2014-15 के बीच उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आयातों में भारी गिरावट आई।

- थ. अनुचित शीघ्रता दर्शाई गई जिसमें बढ़ा चढ़ाकर रक्षोपाय शुल्क लगाने की प्रक्रिया को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क प्रशुल्क नियमावली में विहित प्रक्रिया एवं समय-सीमा का पालन नहीं किया गया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस कार्रवाई के पीछे कोई बड़ी साजिश रही होगी, जिससे जानबूझकर कुछ लाभग्राहियों का पक्ष लिया गया।
- द. रक्षोपाय शुल्क लगाना मेक इन इंडिया के विपरीत है और यह डम्प इन इंडिया को बढ़ावा देता है।
- ध. जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भी इस मुद्दे पर अपना विरोध जताया है। उन्हें स्टील आयातों पर भारी शुल्क लाभ मिल रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनियों पोस्को, होंडा, टोयोटा और सुजुकी आदि के माध्यम से भारत में भारी निवेश कर रखा है. यह भी इस उदग्रहण से प्रभावित होंगे।
- न. आवेदकों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए आधे अधूरे आंकड़े देकर और वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 का संदर्भ वर्ष के रूप में प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाल कर कि आयातों में भारी प्रोत्कर्ष के कारण उनको "गंभीर क्षति" हो रही है महानिदेशक रक्षोपाय को गुमराह किया है।
- प. जांच की अवधि कम से कम छह वर्ष होनी चाहिए। इस जांच के लिए जांच की अवधि पर विचार वर्ष 2009-10 और 2015 के बीच उद्योग की स्थित की तुलना करके किया गया है क्योंकि वर्ष 2009-10 में महानिदेशक द्वारा इसी आधार पर एक आवेदन खारिज कर दिया था।
- फ. प्राधिकारी ने दिनांक 9 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना के पेज संख्या 5 पर स्वयं यह संपुष्टि की है कि उक्त आवेदक के संयंत्र की क्षमता उपयोग पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा और यह संपूर्ण जांच अवधि में अपरिवर्तित रहा है।
- ब. इस अधिसूचना में स्वयं यह उल्लेख किया गया कि जांच की अवधि के दौरान उक्त आवेदक के लाभ में वास्तव में भारी वृद्धि हुई जबिक अनुक्रमित लाभ जो वर्ष 2013-14 में 100 प्रतिशत रुपया प्रति टन था बढ़कर वर्ष 2014-15 में 135/-रुपए प्रति टन हो गया। उनका कहना है कि आगे अपने वाले वर्षों अर्थात वर्ष 2015-16 में, पहली तिमाही के वार्षिकीकरण के आधार पर प्रति टन लाभ में भारी गिरावट आई है। यह गिरावट मुख्यत: संपूर्ण विश्व में गिरती बाजार स्थिति के कारण बिक्री प्रापण में कमी के कारण आई है।
- भ. जांच अवधि के दौरान मालसूची के स्तर में प्रोत्कर्ष पूर्णतया असत्य एवं भ्रामक कथन है क्योंकि वास्तविक रूप से वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में मालसूची स्तर केवल 11411 रहा जबिक वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही के 8809 एमटी को इसमें शामिल कर दिया गया था।
- म. बाजार हिस्से में गिरावट और राजस्व/लाभ में गिरावट वह वैश्विक स्थितियां हैं, जिनका सामना विश्व के बड़े-बड़े स्टील उत्पादकों द्वारा भी किया जाता है।
- य. यह रक्षोपाय शुल्क औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और इसके बदले सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने के राष्ट्रीय उद्देश्य के विपरीत है और यह केंद्रीय सरकारी एक महत्वाकांक्षी योजना "मेक इन इंडिया" की मखौल उड़ता है।
- कक. अंतिम प्रयोक्ता गण हाट रोल्ड काइल्स के स्रोत (चाहे वह भारतीय हो या विदेशी) पर तब तक चिंतित नहीं होते है जब तक कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाता और कीमतें प्रतिस्पर्धात्मक बनी रहती है।
- खख. उक्त आवेदक कतिपय विशेष स्टील ग्रेडों की भारी माप का उत्पादन नहीं करते हैं जिसके कारण अंतिम प्रयोक्ताओं को मजबूरन आयात जारी रखना होता है, जैसाकि वे प्राचीन समय से करते चले आ रहे हैं और इन्हीं अंतिम प्रयोक्ताओं को प्रपाती रक्षोपाय शुल्क लगाकर दंडित किया जाएगा। जब उनकी जरूरतों के मुताबिक घरेलू आपूर्ति नहीं होगी तो उपभोक्तागण अधिक भुगतान करके अपना उद्देश्य पूरा करेंगे, इससे महानिदेशक रक्षोपाय के समक्ष आवेदकगण अधिक लाभ अर्जित करेंगे।
- गग. आंकड़े संयुक्त प्लांट सिमिति, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से लिए जाने चाहिए थे और आकलन/निर्णय उसी पर आधारित होना चाहिए था।
- घघ. पंजीयन की नई प्रक्रिया में 10-12 महीनों की जरूरत पड़ेगी और इससे हाट रोल्ड स्टील के आयात प्रभावित होंगे, चूंकि व्यापारियों को स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को 20 प्रतिशत अधिक का भुगतान करना होगा। इससे स्थानीय मिलों के व्यवसाय की एकाधिकारिता होगी और अप्रतिस्पर्धी प्रक्रियाएं बढ़ेंगी।
- इन्छ. दायर की गई इस याचिका में कोई दम नहीं है और अनुत्क्रमणीय क्षति संबंधित उनके निष्कर्ष भी गलत पाए गए हैं :
 - (i) याचिकाकर्ताओं द्वारा धारित स्टॉक की मालसूची और शुल्क की दर के बीच प्रतिलोमित सह-संबंध है। हालांकि कस्टम ड्यूटी की दर जो वर्ष 2011-12 में 5 प्रतिशत थी, बढ़कर वर्ष 2015-16 में 12.5 प्रतिशत हो गई, वहीं आवेदक द्वारा

- धारित मालूसची जो 331101 एमटी थी बढ़कर 31 मार्च, 2015 को 648290 एमटी हो गई इससे इंडेक्स 100 से बढ़कर 196 हो गया।
- (ii) चूंकि शुल्क दर में 16.06.2015 से 12.08.2015 तक के बीच दो चरणों में वृद्धि 7.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत हुई। आवेदक अपने भंडार की रक्षा अपने लाभ की इच्छा से कर रहा था न कि उच्चतर आयातों के कारण किसी वास्तविक क्षति के डर से क्योंकि वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की अविध के दौरान उनके उत्पादन में वृद्धि हुई और यह 100 से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गया।
- (iii) उच्चतर शुल्क से केवल उच्चतर मालसूची होती है क्योंकि उक्त आवेदकों को यह उम्मीद थी कि आयात भारी मात्रा में ब्लाक हो जाएंगे और उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से कोई लेना देना नहीं रहेगा तथा उनका लाभ सुनिश्चित हो जाएगा।
- (iv) यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं है कि कोई देश अपनी कीमतों में कटौती कर रहा है अथवा भारतीय बाजार में अपने उत्पादन का पाटन कर रहा है।
- (v) 20 प्रतिशत शुल्क अपने विनिर्माण सेक्टर जो स्टील की खपत करता है की प्रतिस्पर्धात्मकता को नियंत्रित करके और अवसंरचना बनाने की लागत बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा।
- (vi) रक्षोपाय शुल्क से आवेदकों की मोनोपोली हो जाएगी।
- (vii) रक्षोपाय शुल्क से इंजीनियरिंग के छोटे-छोटे निर्यातकों को क्षति होगी क्योंकि इससे इनपुट लागत बढ़ेगी और चीन से परिष्कृत इंजीनियरिंग उत्पादों का सस्ता आयात बढ़ेगा जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता का क्षरण होगा।

XXXII. श्री जगन्नाथ स्टील कंपनी : रक्षोपाय शुल्क इस देश के विकास का निम्नलिखित कारणों से बाधक होगा :

- क. 38 स्टील कंपनियों में से 25 पर ऋण है। इस सेगमेंट द्वारा लिया गया ऋण का प्रभावी मूल्य उसके कुल कारोबार के बराबर होगा। रक्षोपाय शुल्क के लिए लागत में अनियमितता, कच्चे माल की आपूर्ति के राजनीतिक करण आदि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- ख. जेपीसी में इस तथ्य के स्पष्ट साक्ष्य हैं कि लगभग एक मिलियन टन का निर्यात आयात कीमत और वैश्विक व्याप्त कीमत के अनुरूप किया गया। यह कीमतें घरेलू कीमतों से कम थी और इससे एक अभाव सृजित हो गया, जो काफी बड़ी अंतराल है, इस अंतराल को आयातों द्वारा भरा गया।
- ग. यह प्रशुल्क अवरोध कम करने तथा प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध कराने की संकल्पना "मेक इन इंडिया" के विपरीत है।
- घ. सबसे बड़ा संघटक पोस्को/इंडिया और चाइना स्टील कारपोरेशन से होने वाली आयात मात्रा का था। यदि इन आयात आंकड़ों को उनसे हटा दिया जाए तो आयात की मात्रा काफी कम हो जाएगी।
- ङ. यह आयात कई मात्राओं में उपलब्ध हैं जिनका भारत में आकार, गुणवत्ता, विनिर्देशन आदि के कारण उत्पादन नहीं किया जाता है।

XXXIII. **मानेकसिया स्टील लिमिटेड** : मानेकसिया स्टील लिमिटेड इस संबद्ध वस्तु की भारत में आयातक हैं। उनका तर्क है कि :

- क. 🛾 इस संबद्ध वस्तु, जो अधिरोपण, उन्हें अपने प्रचालन बंद कर देने पर मजबूर करेगा।
- ख. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना, "मेक इन इंडिया'" अभियान के प्रयोजन के विपरीत होगा और यह परिष्कृत उत्पाद के आयात को चरम पर पहुंचा देगा।

XXXIV. हर्बलपूल इंडिया लिमिटेड: वे इस संबद्ध वस्तु के भारत में प्रयोक्ता हैं:

- क. पिछले एक वर्ष में संपूर्ण विश्व में स्टील की कीमतों में गिरावट आई है :
 - चीन में 34 प्रतिशत
 - यूएसए में 22 प्रतिशत
 - यूरोप में 10 प्रतिशत

- भारत में 10 प्रतिशत
- ख भारत में यह गिरावट सबसे कम है क्योंकि :
 - वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमी
 - लौह अयस्क की कीमत में गिरावट आई है
- ग. भारत के उपभोक्तागण भारत में स्टील की कीमतों में गिरावट का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
- घ. इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त के आलोक में निम्नलिखित प्रश्न महत्वपूर्ण हैं :
 - क्या भारतीय उद्योग की कीमतें अंतर्निहित अक्षमताओं के कारण अधिक हैं और इसी कारण से वे वैश्विक रूप से अप्रतिस्पर्धी अधिक हैं।
 - क्या भारतीय उद्योग को विश्व स्टील उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार से सहायता मांगने के बजाय अपना सुधार नहीं करना चाहिए।
- ङ. सरकार को स्टील की वैश्विक कीमतों का संज्ञान लेना चाहिए और भारत में स्टील की कीमतों की तुलना अन्य क्षेत्रों में व्याप्त कीमतों से करना चाहिए।
- च. सरकार को स्टील उद्योग से यह आश्वासन लेना चाहिए कि उस अवधि के दौरान, जिसके लिए रक्षोपाय शुल्क लगाया गया है (200 दिन), स्टील की कीमतों से कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

XXXV. मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड: मारूति सुजुकि इंडिया लिमिटेड भारत में इस संबद्ध वस्तु की आयातक है। उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिया है:

- क. डीजी रक्षोपाय ने जांच शुरूआत प्रारंभ करने के 2 दिन पश्चात ही प्रारंभिक जांच परिणाम जारी कर दिए और उन्होंने आयातकों, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सुनने का कोई अवसर नहीं दिया। उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम जल्दी-जल्दी में जारी किए हैं। उन्होंने निम्नलिखित पर भरोसा किया है:
 - सीमेंस इंजीनियरिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड बनाम भारत सरकार एवं अन्य (1976) सप्ली.एस.सी.आर.489
 - सी बी गौतम बनाम भारत संघ (1993)1 एससी 78
 - स्वदेशी काटन मिल बनाम भारत संघ 1981 एससीआर (2) 533
 - आटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य 2011. टीआईओएल-03 एससी. सीसयुएस।
- ख. इस मामले में महानिदेशक रक्षोपाय की नियुक्ति 7 सितम्बर, 2015 को की गई थी। आटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्सचरर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य पर भरोसा किया गया था, जिसके द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि नए निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक अलग सुनवाई प्रदान करनी चाहिए।
- ग. भारत को व्यापक आर्थिक भागीदारी करार के सदस्य होने के नाते, एफटीए के अनुच्छेद 23 का पालन करना चाहिए जिसमें यह उल्लेख है कि भारत को इस एफटीए के अंतर्गत शुरू किए गए रक्षोपाय जांच के मामलों में कुछ विशिष्ट दिशानिर्देशों का अनुसरण करने की जरूरत है। इस एफटीए में द्विपक्षीय रक्षोपाय साधन की शुरूआत के लिए भिन्न प्रणाली का प्रावधान है जिसमें अनुपालन के लिए कुछ अनिवार्य अतिरिक्त जरूरते हैं। प्राधिकारी ने द्विपक्षीय रक्षोपायों तथा विशेष शर्तों एवं उसमें निर्धारित प्रक्रियाओं के संबंध में एफटीए के प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी की है।
- घ. वर्तमान मामले में जापान से इस विचाराधीन उत्पाद का आयात किए जाने के संबंध में जांच शुरूआत प्रक्रिया के संबंध में जापान के राजदूतावास/जापान की सरकार को कोई सूचना प्रदान नहीं कराई गई थी। जापान के राजदूतावास/जापान की सरकार को बिना कोई सूचना/जानकारी दिए प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने का कार्य एफटीए के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करने का कार्य है। यूएस –अंडरवीयर, अपीलीय निकाय रिपोर्ट पर भरोसा किया गया। यूएस अंडरवीयर, जहां यह धारित किया गया था कि साधन का प्रकाशन करने से पहले, गाट के अनुच्छे-X के अंतर्गत यथापेक्षित,

स्वत: ही कोटा के प्रकाशन की बारी से पहले शुरूआत की अवधि के दौरान आयातों के संबंध में आयात कोटा लागू करने के पूर्व व्यापी प्रभाव को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

- इ. इस विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण करने के लिए कोई क्रियापद्धित नहीं अपनाई गई। याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए लेनदेनवार आयात आंकड़ों में ढेर सारी विसंगतियां हैं ओर कई स्थानों पर याचिकाकर्ता ने आयातित उतपाद का समुचित ग्रेडेशन और सीरीज़ अभिज्ञान नहीं किया है। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में अभिज्ञात किए गए कतिपय उत्पादों और तत्पश्चात उन पर प्रारंभिक जांच परिणाम में जिन आयात आंकड़ों पर भरोसा किया गया है वे सही आंकड़े नहीं हैं ओर इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत शामिल नहीं है।
- च. विगत में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांच में चीन जन.गण., जापान, कोरिया, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान (चाइनीज ताइपेई), थाइलैंड और यूएसए से आयातित कोल्ड रोल्ड स्टील उत्पादों का इस कारण से जांच के दायरे से अपवर्जन किया है कि उन्हें रक्षोपाय नियमावली के आशय के अंतर्गत समान वस्तु नहीं माना गया।
- छ. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने सभी ग्रेडों का समावेशन करने की मांग की है जिसमें ऐसे ग्रेड भी शामिल हैं जिनका विशेष रूप से अपवर्जन कर दिया गया था जिन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत समान उत्पाद नहीं माना गया था।
- ज. इस विचाराधीन उत्पाद के याचिकाकर्ता द्वारा यथा प्रदत्त आयात आंकड़ों को कोरैबोरेट करने ओर उन्हें प्रमाणित करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से परामर्श किया जाना चाहिए।
- झ. प्राधिकारी ने कहीं भी इस विचाराधीन उत्पाद को आयातकों द्वारा आयातित उत्पादों के समान रिकार्ड करने के लिए कहीं भी रक्षोपाय नियमावली के नियम 2(ड.) के अंतर्गत यथा-प्राविधानित "समान उत्पाद" की परिभाषा को कसौटी नहीं माना है।
 - कोरिया और जापान से हुए आयात रक्षोपाय नियमावली के नियम 2(ड.) के अनुसार समाना उत्पाद नहीं हैं और इसलिए वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के पृथक उत्पाद है।
 - जापान से इस विचाराधीन उत्पाद का आयात करने की जरूरत इसलिए है क्योंिक घरेलू उत्पादक प्रतिवादी द्वारा यथा-अपेक्षित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद की आपूर्ति करने में अक्षम है। प्राधिकारी को ऐसी आयातित वस्तु का अपवर्जन कर देना चाहिए जिनका विनिर्माण याचिकाकर्ताओं द्वारा नहीं किया जाता है। माननीय सीमाशुल्क, उत्पादकर एवं सेवाकर अपीलीय अधिकरण पर मैग्नेट यूजर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2003 (157) ईएलटी 150 (ट्री-दिल्ली) पर भरोसा किया गया, इस केस में यह धारित किया गया था कि उन ग्रेडों का इसमें शामिल करने का औचित्य क्या है जिसका भारत में विनिर्माण नहीं किया जाता है।
 - यह विचाराधीन उत्पाद आयातित उत्पादों का विषमांग सेट है और इसलिए उन्हें घरेलू उत्पादकों/याचिकाकर्ताओं द्वारा विनिर्मित उत्पादों के साथ तुलना करने के लिए समान ग्रेड में शामिल नहीं किया जा सकता है। डब्ल्यूटीओ द्वारा डीएस 427-चीन-यूनाइटेड स्टेट्स से ब्रायलर उत्पादों पर पाटनरोधी एवं प्रतिसंतुलकारी शुल्क में जारी पैनल रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है।
 - प्राधिकारी द्वारा नॉन-फिनष्ड विचाराधीन उत्पाद का समावेशन किया जाना न्यायोचित नहीं है और अनपेक्षित है
 क्योंकि इन उत्पादों का आयात भिन्न-भिन्न मात्रा में और अलग-अलग कीमतों पर किया जाता है।
- ञ. प्रतिवादी निम्नलिखित से इस्पात उत्पादों की खरीद करता है :
 - जेएसडब्लू स्टील लिमिटेड
 - एस्सार स्टील लिमिटेड
 - भूषण स्टील लिमिटेड
 - टाटा स्टील लिमिटेड
 - हीरो स्टील लिमिटेड
- ट. प्रतिवादी द्वारा उपभोग किए गए कच्चे माल एवं संघटकों में से 93 प्रतिशत का अधिप्रापण उपरिवर्णित घरेलू उत्पादकों में से किया गया है जिनमें दो याचिकाकर्ता भी शामिल हैं। शेष बची केवल 7 प्रतिशत विशेष प्रकार की स्टील ऐसी है जिसकी मांग की पूर्ति घरेलू उद्योग द्वारा नहीं की जाती है और जिसका आयात प्रतिवादी द्वारा जापान और कोरिया से किया जाता है। भारतीय उत्पाद इन देशों में उत्पादित उत्पाद से भिन्न है।
 - आयातित उत्पादों का विनिर्माण जापानीज औद्योगिक स्टैंडर्ड द्वारा किया जाता है।
 - इसमें बेहतर मेकिंग स्टैंडर्ड, रसायनिक संघटन, श्रेणीकरण, टेन्साइल स्ट्रैन्ज्थ खिंचाव क्षमता और झुकने की क्षमता होती है।

- भारतीय उत्पादों में होल एक्सपैंशन रोल का कहीं उल्लेख नहीं है।
- एक ही ग्रेड की स्टील में विभिन्न स्टील विनिर्माताओं के क्वालिटी स्तर (फार्मेबिलिटी, रोलिंग के दौरान क्रैक जनरेशन आदि) में अंतर होता है।
- चूंिक प्रतिवादी आटोमोबाइल का सबसे बड़ा उत्पादक और विनिर्माता है इसलिए आटोमोटिव अनुप्रयोग के लिए गुणवत्ता का स्तर उसके लिए चिंता का मुख्य विषय होता है जिससे कि किसी वाणिज्यिक समस्या या उलझन से बचा जा सके।
- आयातित उत्पाद का निर्माण पेटेंट अत्याधुनिक तकनीकी से किया जाता है और उसके पृथक गुण होते हैं।
- ठ. याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और उन्होंने घरेलू बाजार के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री का निर्धारण करेन के उद्देश्य से पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं की है। याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी को प्रदान की गई सूचना पर गोपनीयता का दावा करने का कोई कारण प्रदान नहीं किया है। प्रतिवादी ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी पर भरोसा किया है।
- ड. प्राधिकारी ने आयातकों तथा हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रदान कराई गई सूचना की जांच करने और उसकी परिपुष्टि करने के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं कराई। घरेलू उत्पादकों द्वारा दिए गए साक्ष्य की परिपुष्टि किए बिना ही प्राधिकारी ने उक्त सूचना पर भरोसा कर लिया और 20 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश कर दी।
- ढ. प्राधिकारी ने संस्तुत रक्षोपाय शुल्क के स्तर का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई क्रियापद्धित का प्रकटन नहीं किया है। प्राधिकारी ने गाट 1994 के अनुच्छेद-XIX में विनिर्धारित सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। जांच शुरूआत नोटिस में उस अनपेक्षित विकास के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया था जिसके कारण इस विचाराधीन उत्पादन के आयातों में वृद्धि हुई। याचिकाकर्ता यह दर्शाने के लिए कि वर्तमान मामले में अनपेक्षित विकास मौजूद है कोई तथ्यात्मक या विधिक आधार प्रस्तुत नहीं कर सका।
- ण. याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराए गए आयात आंकड़ों में मामूली सी वृद्धि हुई है। यह दर्शाने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया कि किस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2015 के संपूर्ण वर्ष के लिए आयातों का वार्षिकीकरण किया है। इस विचाराधीन उत्पाद के आयात में क्रमिक वृद्धि हुई है और आयातों में कोई "अतितीव्र" बहुत अधिक अथवा आकस्मिक वृद्धि" नहीं हुई।
- त. इस विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों का इस वस्तु के घरेलू उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 25(क) में यह सिफारिश की है कि घरेलू उत्पादकों का उत्पादन समान स्तर पर बना रहा। प्राधिकारी ने इस तथ्य का कोई साक्ष्यांकन नहीं किया कि ऐसी संवेदनशील पिरिस्थितयां कौन सी हैं जिनकी वजह से यह प्रारंभिक जांच करनी पड़ी। प्राधिकारी ने रक्षोपाय जांच के सिद्धांतों का उल्लंघन करके कार्रवाई की है।
- थ. याचिकाकर्ताओं ने गंभीर क्षति दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में इस तथ्य की अनदेखी की है कि रक्षोपाय नियमावली के अंतर्गत किसी जांच की शुरूआत करना तभी अपेक्षित है जब यह सुझाव देना का "पर्याप्त साक्ष्य" हो कि इस उत्पाद के संवर्धित आयातों ने घरेलू उत्पादकों को क्षति कारित की है।
- द. प्राधिकारी ने रक्षोपाय नियमावली के अनुबंध के पैरा 1 और 2 का उल्लंघन करके कार्य किया है। प्रतिवादी ने यूएस-काटन यार्न पर अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। उपर्युक्त उदधृत मामले के आधार पर निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए :
 - याचिका में किसी भी क्षति को नहीं दर्शाया गया है।
 - याचिकाकर्ताओं ने उत्पादन घरेलु बिक्रियां और कुल बिक्री तथा लाभप्रदता के रूप में बेहतर प्रदर्शन किया है।
 - इस विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता का कुल क्षमता से पृथक्करण करने के लिए विहित क्रियापद्धित अभी भी स्पष्ट नहीं है।
 - एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड ने कम्पलीट टर्न अराउंड किया है और अपने प्रचालनों से लाभार्जन किया है।

विवरण	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	
	2014-2015	2013-2014	
	(करोड़ रुपए)	(करोड़ रुपए)	
सकल राजस्व	19,258.50	16,286.59	

निवल राजस्व	17,162.39	14,348.55
आपवादिक मदों और कराधान से पूर्व लाभ/(हानि)	334.29	(3,916.21)
कराधान पूर्व लाभ/(हानि)	1,008.96	(2,314.74)
प्रतिशेयर अर्जन (तनुकृत)	2.26 रुपए	(5.70) रुपए

ध. जेएसडब्ल्यू की लाभप्रदता बढ़ी है

विवरण	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	वृद्धि %
	2014-2015	2013-2014	-
	(करोड़ रुपए)	(करोड़ रुपए)	
सकल टर्नओवर	49,658	48,527	2%
निवल टर्नओवर	45,352	44,529	2%
प्रचालनरत ईबीआईडीटीए	8,872	8,783	1%
पीएटी	2,166	1,335	62%
प्रतिशेयर अर्जन (तनुकृत)	88.24 रुपए	53.86 रुपए	64%

- सेल को लगातार लाभ होता रहा।
- कीमत अधोविक्रयण, अवमंदन एवं निग्रहण आंकड़ों का याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका के एनसीवी में विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है।
- प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 25(घ) के अनुसार घरेलू उत्पादकों के क्षमता उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं आया है।
- प्राधिकारी ने भी अपनी प्रारंभिक जांच परिणाम में घरेलू उत्पादकों के क्षमता उपयोग में गिरावट की संभावना का कोई
 उल्लेख नहीं किया है।
- प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराई गई सूचना के किसी भी भाग की परिपुष्टि नहीं की है और बिना कोई कारण बताए यह मान लिया कि यह एक मामला है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी।
- इस रक्षोपाय शुल्क का वाहनों तथा आटोमोबाइल उद्योग के अनुषंगी सामान पर क्रमिक प्रभाव पड़ेगा।
- न. कई आटोमोबाइल कंपनियां और ओईएम इस संबद्ध वस्तु के बड़े आयातक हैं और रक्षोपाय शुल्क की वसूली का उक्त आयातकों के व्यवसाय हितों पर भारी प्रभाव पड़ेगा। रक्षोपाय शुल्क भारत सरकार द्वारा रूग्ण आटोमोबाइल उद्योग का जीर्णोद्वार करने के लिए शुरू किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों से असंगत होगा।

XXXV।. वी के इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड:

- क. भारत में स्टील की कुल खपत में स्टील आयातों का प्रतिशत केवल 10 प्रतिशत है। यह कुल आयातों का बहुत ही अल्प हिस्सा है।
- ख. सरकार ने स्टील मिलों को पहले ही कई लाभ प्रदान किए हैं।
- ग. आयातकगण कुल बाजार का बहुत अल्प प्रतिशत हैं और वे लघु एवं मध्यम आकार के व्यवसाय और स्टार्ट-अप कंपनियों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं जिन्हें क्रेडिट आधार पर वस्तु की जरूरत पड़ती है। घरेलू विनिर्माता इन छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में अक्षम हैं।
- घ. कच्चे माल की कीमतों में प्रपाती गिरावट आई है। इसलिए घरेलू मिलों को भी अपनी कीमतें कम करना चाहिए। कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के कारण ही अन्य देशों से कम कीमत पर आपूर्ति हो रही है।

- ङ. घरेलू उत्पादक स्टील का निर्यात घरेलू कीमतों से कम कीमत पर कर रहे हैं। इसलिए घरेलू मिलें विश्व की अन्य सस्ती स्टील मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं ओर अपना लाभ अनुरक्षित रख सकते हैं।
- च. छोटी-छोटी इंजीनियरिंग और उपभोक्ता फर्में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं परिणामत: यह उद्योग बंद हो रहे हैं।

XXXVII. लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड: लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड भारत में वस्त्र मशीनों का विनिर्माता है।

- क. भारत में कोई भी विनिर्माता 4एमएम से अधिक हाट रोल्ड स्किन पास्ड पिक्ल्ड एवं आयल्ड लेजर स्टैबिलाइज्ड शीटों की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। स्किन पास्ड की जरूरत हमारे पार्टस में फ्लैटनेस के लिए अपेक्षपित होती है।
- ख. कोई भी विनिर्माता भारत में लेजर स्टैबिलाइज्ड सामग्री की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। हमारे पार्टस का विनिर्माण लेजर कटिंग में किया जाता है जिसके लिए स्टैबिलाइज्ड सामग्री अपेक्षित होती है।
- ग. इन शीट्स से बनी अधिकांश मदें नियमनिष्ठ सहिष्णुता युक्त प्रकार्यात्मक संघटक होते हैं।
- घ. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से वैश्विक बाजार में अप्रतिस्पर्धात्मक आएगी।

XXXVIII. जेबीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- क. आटोमोटिव उद्योग में उच्च दृढ़ता के संघटकों का विनिर्माण करने के लिए डामेक्स 650 ग्रेड के अलाय का प्रयोग किया जाता है। घरेलू मिलों ने आज की तारीख तक कोई वैकल्पिक ग्रेड विकसित नहीं किया है इसलिए हम इन ग्रेडों का आयात करना जारी रखेंगे। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से हमारी लागत बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप अंतिम उत्पाद की लागत में वृद्धि होगी।
- ख. द्वितीयक मिलों, प्रत्यक्ष प्रयोक्ताओं और ओईएम द्वारा स्पेशल ग्रेड की स्टील का भारी मात्रा में आयात किया जाता है। रक्षोपाय शुल्क लगाने से कच्चे माल की लागत में वृद्धि होगी जिससे वाहनों की कीमत बढ़ेगी। इसका आटोमोटिव उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

XXXIX. नील मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड

- क. द्वितीयक मिलों, प्रत्यक्ष प्रयोक्ताओं और ओईएम द्वारा स्पेशल ग्रेड की स्टील का भारी मात्रा में आयात किया जाता है। रक्षोपाय शुल्क लगाने से कच्चे माल की लागत में वृद्धि होगी जिससे वाहनों की कीमत बढ़ेगी। इसका आटोमोटिव उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- ख. नील उत्पाद भविष्य में एचआर सामग्री ग्रेड का आयात कर सकते हैं जो वाहनों के सुरक्षा संघटक बनाने के लिए आवश्यक है। रक्षोपाय शुल्क लगाने से कच्चे माल की कीमत बढ़ी है और इससे वाहनों की लागत में वृद्धि होगी।
- ग. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कष्टकल्पित आटोमोटिव उद्योग पर और अवसंरचना उद्योग पर विपरीत प्रभाव डालेगा जहां इन परियोजनाओं में फेब्रीकेशन कार्य के लिए भारी मात्रा में इस्पात का प्रयोग किया जाता है।

XL. लार्सेन एंड दुब्रो लिमिटेड

क. लार्सेन एंड टुब्रो लिमिटेड के पास कुछ निर्यात उपकरण आदेश हैं जो शून्य प्रतिशत शुल्क की दर पर कच्चे माल का आयात करने के लिए अग्रिम प्राधिकृतीकरण के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं, परंतु उसने एफओबी मूल्य पर निर्यात करने के लिए 1.9 प्रतिशत की दर से "अखिल उद्योग दर ड्राबैक स्कीम" के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त करने का विकल्प दिया है। 20 प्रतिशत के अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क के कारण इन उपकरणों के कच्चे माल की लागत बढ़ी है। लार्सेन एंड टुर्बो डीजी रक्षोपाय से यह अनुरोध करता है कि निर्यात उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए अपेक्षित इनपुटों के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क से छूट प्रदान करे।

XLI. उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड: यह कंपनी इन संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन प्रदान करती है।

XLII. ट्यूब इन्वेस्टमेंट आफ इंडिया (टीआईआई)

- क. टीआईआई द्वारा आयात प्रदायकों के सहमत विनिर्देशनों पर आधारित होते हैं। एक आटो संघटक आपूर्तिकर्ता होने के नाते टीआईआई के उत्पादों को कई वैधीकरण प्रक्रियाओं से गुजरना होता है और यह आयात अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू स्टील की कीमतों पर विचार किए बिना किए जाते हैं।
- ख. हाट रोल्ड काइल्स पर रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण कोल्ड रोलिंग व्यवसाय को अत्यधिक प्रभावित करेगा क्योंकि उपभोक्तागण कोल्ड रोल्ड काइल्स की ओर उन्मुख होंगे।
- ग. डीजी रक्षोपाय को एचआर काइल्स पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए उचित फ्लोर कीमत तंत्र पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, रक्षोपाय शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ एचआर के साथ-साथ सीआर/सीआरसीए पर भी विचार करना चाहिए।

XLIII. निप्पन स्टील पाइप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एनपीआई) जिसका एजेड बी एंड पार्टनर्स द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया

- क. एनपीआई इस पीयूसी के 22 अलग-अलग विनिर्देशनों का आयात करता है जिनका प्रयोग आटोमोबाइल विनिर्माण के लिए ट्यूब्स का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। एनपीआई द्वारा आयातित हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद इन संघटकों के रसायनिक गठन में अलग होते हैं जैसे कार्बन, मैंगनीज, सिलिकन, बोरोन और फास्फोरस, जिन्हें अंतिम प्रयोक्ता की जरूरत को पुरा करने के लिए बनाया जाता है।
- ख. भारतीय स्टील मिलें एनपीआई द्वारा आयातित विशेष हाट रोल्ड कॉइल्स का उत्पादन करने में अक्षम हैं। इस पीयूसीस का आयात अनुप्रवाही उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
- ग. रक्षोपाय साधन को अपनाना भारतीय आटो उद्योग जिसका भारत की जीडीपी में 7 प्रतिशत हिस्सा है के लिए अनर्थकर होगा, और जो लगभग 19 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।
- घ. पीयूसी पर रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण एनपीआई आपूर्ति चैन को विपरीत ढंग से प्रभावित करेगा। यह उत्पादन मात्रा को इस सीमा तक कम कर देगा जिसके कि भारतीय आटोमोबाइल उद्योग के लिए ग्राहकों की मांग को पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, कम लाभप्रदता के मद्देनजर, कंपनी के रूप में एनपीआई को भी अपने कर्मचारी हटाने पड़ेंगे।
- ङ. एनपीआई डीजी रक्षोपाय से पीयूसी के स्कोप से उन आयातों का अपवर्जन करने का अनुरोध करता है जिनका प्रयोग टोर्शन बीम, डोर इम्पैक्ट बीम, आटोमोबाइल्स में स्टैबिलाइजर्स, मोटर बाइक्स में फ्रंट फोर्क्स का विनिर्माण करने और एनपीआई द्वारा आयातित अन्य उत्पादों का आयात करने के लिए किया जाता है। इन उत्पादों का घरेलू उद्योग द्वारा या तो इस पीयूसी के भारतीय औद्योगिक प्रयोक्ताओं की जरूरत के अनुरूप अपेक्षित गुणवत्ता विनिर्देशनों पूर्ण स्थानीय रूप से उत्पादन नहीं किया जाता है या उन्हें ओईएम से अनुमोदन नहीं मिल पाता है।

XLIV. दि बाम्बे आयरन एंड मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (बीमा) जिसका प्रतिनिधित्व मैसर्स वी. के. किनी लॉ फर्म द्वारा किया गया।

- क. घरेलू उद्योग भारी ऋणभार, लागत में अनुशासनहीनता, कच्चे माल की आपूर्ति के राजनीतिक मुद्दों के कारण कष्ट सहन कर रहा है।
- ख. घरेलू उद्योग ने आयात कीमतों और वैश्विक रूप से प्रचलित कीमतों के अनुरूप लगभग 1 मिलियन टन का निर्यात किया है। यह कीमतें घरेलू कीमतों की तुलना में कम थीं।
- ग. मौजूदा 12.5 प्रतिशत शुल्क के अवरोध एवं उच्च ब्याज दर के कारण भारतीय विनिर्माता ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिससे वे अप्रतिस्पर्धी हो रहे हैं और इससे परिष्कृतवस्तु का आयात बढ़ेगा।
- घ. आयात आंकड़ों में पोस्को इंडिया और चीन स्टील कारपोरेशन द्वारा ग्राही खपत के लिए किए गए आयात एक बड़ा संघटक हैं। यदि इन आंकड़ों को हटा दिया जाए तो आयातों में भारी वृद्धि की मात्रा कम लगने लगेगी।
- ङ. आयातों में ऐसी विभिन्न वस्तुएं शामिल होती हैं जिनका उत्पादन आकार, क्वालिटी, विनिर्देशन आदि के कारण भारतीय उत्पादकों द्वारा नहीं किया जाता है।

- च. आवेदक घरेलू उद्योग नहीं है। आवेदकों ने अलाय ओर नॉन अलाय उत्पादों के बीच कोई अंतर नहीं किया है। इन्हें विभिन्न अभिज्ञान एवं कस्टम्स वर्गीकरण के बीच अलग-अलग वर्गीकृत किया गया है।
- छ. आवेदकों द्वारा भरोसा किए गए आंकड़ों की प्रामाणिकता संदेहास्पद है क्योंकि यह आंकड़े किसी सरकारी मान्यताप्राप्त ऐसी एजेंसी से नहीं लिए गए हैं जिसे इन आंकड़ों को एकत्र करने और उनका अनुरक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद की छंटनी करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति इस विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित का ही पुनरूत्पादन है और इसमें यथादावाकृत उत्पाद को नहीं बताया गया है।
- ज. आवेदकों ने प्राधिकारी के समक्ष यह प्रस्तुतिकरण करके गलत प्रतिनिधित्व किया है कि संबद्ध वस्तु के प्रयोग में से इसका एक प्रयोग आटोमोटिव उद्योग में भी होता है। आटोमोटिव उद्योग अलाय स्टील उत्पादों पर आश्रित होता है जिसका घरेलू उत्पादन नगण्य है।
- झ. यदि कुल आयातों में से अलाय स्टील आयातों को हटा दिया जाता है तो आयातों में पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अलावा वर्ष 2013-14 को बेंचमार्क वर्ष नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह एक असामान्य वर्ष था।
- ट. ग्राही खपत के लिए किए गए आयातों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए नियमित मांग का निर्धारण नहीं करते हैं। पोस्को महाराष्ट्र और चाइना स्टील द्वारा वर्ष 2014-15 में क्योंकि यह औद्योगिक सेटअप के लिए खपत का निर्धारण नहीं करते हैं, इसलिए कुल आयातों से इन्हें अलग किया जाना चाहिए।
- ठ. आवेदकों नरे अग्रिम प्राधिकृतीकरण के अंतर्गत किए गए आयातों अर्थात निर्यात के लिए किए गए आयातों का अपवर्जन नहीं किया है जबकि कुल आयातों की संगणना करते समय इन्हें हटा दिया जाना चाहिए था।
- ड. आवेदकों के बाजार हिस्से में गिरावट याचिका के समर्थकों को बाजार हिस्से में वृद्धि के कारण आई है।
- ढ. अनपेक्षित विकास का विनिर्दिष्ट कारण केवल घटनाओं का वैश्विक परिदृश्य है जिसका "केवल भारत" पर ही प्रभाव नहीं हैं।
- ण. आवेदकों का क्षमता उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप अपने इष्टतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा, यदि घरेलू उद्योग 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त भी कर लेती है तब भी अलाय स्टील उत्पादों की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है।
- त. आवेदकों की वार्षिक रिपोर्टों का अध्ययन यह दर्शाता है कि रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए कोई भी पूर्वापेक्षा मौजूद नहीं है।
- थ. आवेदकों ने अपनी ऋणग्रस्तता से उत्पन्न उच्च वित्त लागत को ध्यान में नहीं रखा है।
- द. थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों द्वारा व्यापार साधनों के साथ तुलना करना असंधारणीय है और भ्रामक है क्योंकि आयातों एवं अन्य पैरामीटरों में प्रोत्कर्ष इन देशों में बहुत अधिक संवेदनशील है।
- ध. आवेदकों ने अपनी याचिका के जरिए कहीं भी उस साधन को विनिर्दिष्ट नहीं किया है जिसकी पीड़ित पक्ष द्वारा जांच किया जाना और संकल्पित प्रोत्कर्ष का प्रतिरोध किया जाना अपेक्षित हो।
- न. आवेदक चाहते हैं कि घरेलू बाजार में उच्च कीमतें बनी रहें ओर निर्यात का आश्रय लेकर वे कृत्रिम अभाव सृजित करते रहें। यह तथ्य घरेलू कीमत की तुलना सामान्य आयात कीमत और आवेदकों की निर्यात कीमत से करने से स्पष्ट है।
- प. आवेदकों ने फिनिष्ड वस्तु की कीमत स्थिर रखी और वे लौह अयस्क की कीमत में गिरावट का लाभ लेकर आंधी के दाम कमा रहे हैं।
- फ. कीमत अधोरदन, कीमत अवमंदन और कीमत में वृद्धि होने से रोकने के आरोप गलत है और आवेदकों को इसका सख्त प्रमाण देना चाहिए।
- ब. आवेदकों की वार्षिक रिपोर्टों का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि लाभप्रदता में कोई कमी नहीं आई है। सूचीबद्ध कंपनियां होने के बावजूद आवेदकों ने गोपनीयता के आधार पर वास्तविक लाभ की हिस्सेदारी नहीं की है। यद्यपि एक सूचीबद्ध कंपनी के लाभ से संबंधित सूचना को गोपनीयता के अध्यधीन नहीं किया जा सकता है।
- भ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता ओर आरओसीई का अलाय स्टील पर कोई प्रभाव नहीं है। आवेदकों ने एक अस्पष्ट विवरण दिया है कि अगस्त, 2015 के दौरान 320-350/-एमटी यूएस डालर की रेंज में थे। आवेदकों ने अलाय स्टील उत्पादों के संबंध में विवरण नहीं दिया है क्योंकि दो भिन्न उत्पादों की कीमत समान नहीं हो सकती है।

य. दावाकृत रक्षोपाय शुल्क की प्रकृति एवं प्रमात्रा मनमानी है और निराधार है। अलाय स्टील उत्पादों जिसका उत्पादन लगभग नगण्य प्रकृति का है पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण, हितबद्ध पक्षकारों की आजीविका के अधिकारों का उल्लंघन होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14.19 और 21 के विपरीत होगा।

XLV. होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड

- क. एचससीआईएली स्टीदल उत्पादों का प्रयोग इसके वैश्विक होंडा इंजीनियरिंग स्टैंडर्डस के अनुरूप करती है। एचसीआईएल ने इन विभिन्न वैश्विक स्टील मिलों के साथ मिलकर इन मानकों के अनुरूप स्टील ग्रेड विकसित किए हैं जिनमें से कई भारतीय स्टील मिलें जैसे टाटा, जेसीए पीसीपीएल, जेएसडब्ल्यु, पोस्को आदि शामिल हैं।
- ख. एचसीआईएल अपने कच्चे माल को स्थानीय रूप से प्राप्त करने का संभव सीमा तक प्रयास करता है। तथापि, भारी स्थानीयकरण के बावजूद स्थानीय स्टील मिलें एचसीआईएल की संपूर्ण ग्रेड स्टील की जरूरत के पूरा करने में सक्षम नहीं रही है। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए एचसीआईएल कुछ एचआर सामग्री का आयात जापान और कोरिया से करता है जिससे वह स्थानीय मिलों पोस्को महाराष्ट्र और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी स्थानीय मिलों द्वारा कोल्ड रोलिंग के लिए कच्चे माल के रूप में अथवा प्रत्यक्ष अनुप्रयोग कर सके।
- ग. आटोमोटिव ओईएम के लिए यह संभव नहीं है कि वह माडल लाइफ के दौरान कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत को स्विच करे। सभी सामग्री स्रोतों का निर्णय मॉडल विकास के दौरान हो जाता है और उत्पाद गुणवत्ता का वैधीकरण तदनुसार परीक्षण करके किया जाता है। इसलिए विनिर्मितकारों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्टील सामग्री के स्रोतों को मॉडल लाइफ के दौरान बदला नहीं जा सकता है।
- घ. इसलिए रक्षोपाय शुल्क का अचानक अधिरोपण कर दिए जाने से एचसीआईएल आयातित एचआर सामग्री का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करना जारी रखेगा जिस पर भारी लागत आएगी और इससे एचसीआईएफ की कारों की विनिर्माण लागत बढेगी।
- ड. एचसीआईएल यह मानता है कि रक्षोपाय साधन का प्रयोग भारतीय बाजार में आयातित स्टील की पाटित मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है जो स्थानीय स्टील मिलों के हित में होगा, परंतु आटोमोटिव के कुछ ग्रेडों पर विचार करते हुए उचित प्रतिस्थानी उपलब्ध न होने के कारण स्थानीय स्टील मिलों अथवा स्थानीय स्टील का प्रयोग कुछ तकनीकी कारणों से नहीं किया जा सकता है जो इस श्रेणी में आते हैं और जिनका आटोमोटिव उद्योग पर सीधी प्रभाव पड़ेगा।
- च. यह अनुरोध है कि भारत सरकार को आटोमोटिव अनुप्रयोग के लिए एचआर ग्रेडों को रक्षोपाय साधन से छूट प्रदान कर दे जिससे आटोमोटिव उद्योग के संधारणीय विकास को बढावा मिल सके।

XLVI. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

- क. सीमाशुल्क प्राधिकारी दिनांक 14 सितम्बर, 2015 की रक्षोपाय शुल्क अधिसूचना का प्रयोग सीटीएच 7208 के अंतर्गत आने वाली स्टील प्लेटों के आयातों पर कर रहे हैं। भेल की 160 एमएम मोटी एएसटीएम 537 क्लास-1 प्लेटों के अभिनव आयात पर मुंबई कस्टम्स द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2015 की बीई संख्या 2699772 के अंतर्गत 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क का आकलन किया गया। यद्यपि इन प्लेटों का कस्टम्स क्लीयरेंस निर्यात कार्य के लिए अग्रिम प्राधिकृतीकरण संख्या 1110027559 के अंतर्गत शून्य शुल्क पर था, फिर भी 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क सहिट बांड मूल्य को डेबिट कर दिया गया और यह माना जाता है कि उत्तरवर्ती आयातों पर सीमाशुल्क द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाया जा सकता है।
- ख. घरेलु उद्योग के पास निम्नलिखित श्रेणी की कार्बन स्टील प्लेटों का विनिर्माण करने की क्षमता नहीं है :
 - (i) 120 एमएम और उससे अधिक की मोटाई की आईएस 2002 (एएसटीएम 515 ग्रेड-70) की बीक्यू स्टील प्लेट्स।
 - (ii) प्रेसर वेसेल्स के लिए 100 एमएम और उससे अधिक की मोटाई की आईएस 20141 (एएसटीएम 516 ग्रेड 70 और ए 537 क्लास-1) कार्बन स्टील प्लेंटें।
 - (iii) 80 एमएम और उससे अधिक की एएसटीएम 537 क्लास-2 (कोई समकक्ष आईएस उपलब्ध नहीं) की कार्बन स्टील प्लेटें।
- ग. दिनांक 14 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना का आशय हाट रोल्ड काइल्स पर 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क वसूलना है जिससे कि घरेलू उद्योग की रक्षा की जा सके, न कि सीटीएच 7208 के अंतर्गत फ्लैट उत्पादों के रूप में वर्णित प्लेटों की इसके

- अतिरिक्त, ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार इन प्लेटों का विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और इसलिए इन पर रक्षोपाय शुल्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
- घ. यह अनुरोध किया जाता है कि 14 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या 02/2015 के अंतर्गत कोई उपयुक्त संशोधन/अनुदेश जारी किया जाना चाहिए जिससे कि इन रक्षोपाय साधनों का गलत निर्वचन करने से बचा जा सके और सीटीएच 7208 के अंतर्गत आने वाले स्टील प्लेटों (फ्लैट उत्पादों) के आयातों पर 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने से छूट दी जा सके।

सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात् किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण

घरेलू उद्योग

- क. घरेलू उद्योग याचिका में प्रस्तुत किए गए सभी तथ्यों, तर्कों प्रकथनों और अभिकथनों को पुन: दोहराता है और यह अनुरोध करता है कि विगत में किए गए इन प्रस्तुतिकरणों को इसके अंतर्गत निगमित किए गए के रूप में माना जाए। घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विगत प्रस्तुतिकरणों को वर्तमान प्रस्तुतिकरणों का अभिन्न अंग माना जाए।
- ख. अक्तूबर, 2015 तक के आयात आंकड़े और लागत निर्धारण सूचना प्रदान कराई गई है।
- ग. घरेलू उद्योग ने भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए एसीआई ग्रेड स्टील की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पीयूसी के दायरे से एपीआई ग्रेड स्टील का अपवर्जन किया है।
- घ. मीडिया की विभिन्न रिपोर्टों के जरिए घरेलू उद्योग के यह संज्ञान में आया है कि कुछ भारतीय आयातक/विदेशी निर्यातक वाणिज्यिक/बेस ग्रेड की ढांचागत स्टीलों (जो परम्परागत ढांचागत अनुप्रयोगों के लिए हैं) पर, एपीआई 5एल ग्रेड, जिस पर रक्षोपाय शुल्क से छूट है, के छद्म रूप में, लागू अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क की प्रवंचना कर रहे है। इसलिए, घरेलू उद्योग डीजी रक्षोपाय से निम्नलिखित स्पष्टीकरण देकर एपीआई ग्रेड की स्टील के अपवर्जन को स्पष्ट करें:

<u>"एपीआई ग्रेड स्टील में वह स्टील शामिल है जिसका प्रयोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योगों में पाइपलाइन परिवहन</u> प्रणाली के लिए वेल्डेड स्टील पाइप्स में किया जाता है।

आवेदकों का उत्पादन भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक बैठता है और यह देश में इस विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादन के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करता है।

- ङ. आवेदकों का उत्पादन भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक बैठता है और यह देश में इस विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादन के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करता है।
- च. आयात जो वर्ष 2011-12 में 2219711 एमटी था, बढ़कर वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) में 4167886 एमटी हो गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 की तुलना में आयातों में वर्ष 2015-16 के दौरान तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई।
- छ. वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान औसत तिमाही आयात 550000 एमटी के थे। इस स्तर से औसत तिमाही आयात वर्ष 2013-14 के दौरान घटकर 323023 एमटी रह गए। इतने न्यून स्तर से यह आयात वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 1239103 एमटी हो गए।
- ज. वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही के आयात आंकड़ों का मासिक विश्लेषण दर्शाता है कि प्रत्येक माह में आयातों में भारी वृद्धि हुई।
- झ. इस पीयूसी की आयात कीमतों में सतत गिरावट आई है।
- ञ. आयातों का वर्षवार विश्लेषण, तिमाहीवार विश्लेषण और माहवार विश्लेषण इस पीयूसी के आयातों में तीव्र, आकस्मिक और भारी प्रोत्कर्ष दर्शाता है।
- ट. इस पीयूसी के संवर्धित आयात घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हैं और उनका आवेदकों के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और लाभ पर भारी प्रभाव है।
- ठ. इस पीयूसी के आयातों का बाजार हिस्सा विगत वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15 में ग्राही खपत सहित बढ़कर कुल मांग का लगभग दो गुना हो गया। इस पीयूसी के बाजार हिस्से में, ग्राही को छोड़कर, समान प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है। आयातों ने इस पीयूसी को समस्त संवर्धित मांग पर कब्जा कर लिया है।

- ड. अभिनव अवधि के लिए तिमाही प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि ग्राही सहित कुल मांग में आयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में 7 प्रतिशत था, बढ़कर चौथा तिमाही में 13 प्रतिशत हो गया। ग्राही को छोड़कर कुल मांग में आयातों का बाजार हिस्सा 2014-15 की पहली तिमाही में 11 प्रतिशत था, से बढ़कर चौथी तिमाही में 21 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में कुल मांग में आयातों का बाजार हिस्सा इससे भी अधिक हो गया। यदि आयातों में इसी तरह वृद्धि होती रही तो शीघ्र ही घरेल उद्योग समाप्त हो जाएगा।
- ढ. वर्ष 2014-15 के दौरान मांग में वर्ष 2013-14 की तुलना में (ग्राही को छोड़कर) वृद्धि हुई और यह 1158614 एमटी हो गई। साथ ही, आवेदक घरेलू उद्योग की बिक्रियां उसी अवधि के दौरान घटकर 393351 एमटी रह गईं। घरेलू उद्योग अपनी बिक्री में घरेलू मांग की तुलना में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ।
- ण. घरेलू उद्योग भारत में इस संबद्ध वस्तु की बढ़ती मांग को देखते हुए वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान भारी निवेश किया। तथापि, घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग संपूर्ण जांच अवधि के दौरान स्थिर बना रहा।
- त. घरेलू उद्योग की मालसूची में संवर्धित आयातों के सतत दबाव के कारण आधार वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि हुई।
- थ. घरेलू उद्योग को वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में घाटा हुआ। इसके अतिरिक्त, यह घाटा वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में और भी अधिक बढ़ गया। घरेलू उद्योग के आरओसीई में भारी गिरावट आई है।
- द. घरेलू उद्योग पर निरंतर यह दबाव डाला गया कि वह अपनी कीमतें आयातों के उतराई मूल्य के बराबर करने के लिए उनमें कमी करे। यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करके आयातों का प्रत्युत्तर नहीं देता है तो इसके ग्राहक समाप्त हो जाएंगे और इसके गंभीर क्षति होगी।
- ध. कीमत अधोविक्रयण जो 2014-15 की पहली दो तिमाहियों के दौरान ऋणात्मक थी, चौंकाने वाली कम कीमत पर बढ़ते आयातों के कारण 2014-15 की पिछली दो तिमाहियों के दौरान सकारात्मक हो गई।
- न. वह निम्नलिखित कारण हैं जिन्हें संवर्धित आयातों के लिए उत्तरदायी ठहरया जा सकता है :
 - मंदी मांग की वजह से स्टील की विश्व बाजार में संकट
 - यूरोपीय यूनियन और रूस के बीच भौगोलिक तनाव
 - रूबल और रिव्निया का अवमुल्यन
 - चीन जन.गण. में मंदी ने कम घरेलू मांग और निर्यातों में भारी प्रोत्कर्ष को बढ़ावा दिया।
 - चीन जन.गण. और जापान में भारी बेशी क्षमताएं तथा भारत में स्टील की बढ़ती खपत।
 - यूएस, तुर्की, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों द्वारा अपनाए गए व्यापार उपचारी साधन के परिणामस्वरूप बड़े निर्यातक देशों के निर्यातों का भारत की ओर विपथन हुआ।
- प. इस संबद्ध वस्तु के आयातों में तीव्र एवं एकाएक वृद्धि और घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जार ही गंभीर क्षति के बीच भारी संबंध मौजूद हैं।
- फ. आयातों के उतराई मूल्य में निरंतर कमी आ रही है। अप्रैल, 2014 से सितम्बर, 2015 तक आयातों के उतराई मूल्य में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आई।
- ब. वर्ष 2015 के अक्तूबर माह से भारत को कोरिया आरपी से आयात 224 यूएस डालर प्रति एमटी के मूल्य की दर से आ रहे है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार द्वारा अधिरोपित अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का निर्यातकों द्वारा अवशोषण कर लिया गया।

राजदूतावासों तथा देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

भारत गणराज्य में रूसी परिसंघ का व्यापार प्रतिनिधित्वमंडल

- क. रूसी पक्ष हाट रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर रक्षोपाय शुल्क की शुरूआत करने पर अत्यधिक चिंतित है।
- ख. भारत में इस पीयूसी के आयातों की मुख्य मात्रा पहले चरण में चीन जन गण., कोरिया आरपी और जापान से आई।
- ग. इस उत्पादन की भारत में की गई रूस की सुपुर्दगियां उल्लिखित अवधि के लिए महत्वपूर्ण नहीं थीं और इनका भारतीय उत्पादों के आर्थिक निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका।

- घ. रूस के आयातों के हिस्से में कमी रूस के उत्पादकों के भारत में अपनी सुपुर्दगियां बढ़ाने के इरादे में कमी प्रदर्शित करता है। इसका अधिकांश भाग यह तथ्य है कि रूस के उत्पादकों के पास हाट रोल्ड फ्लैट उत्पादों की सुपुर्दगी करने की भारी निर्यात संभावनाएं नहीं है।
- ङ. यह तथ्य कि डब्ल्यूटीओ का विनियम उल्लेख करता है कि प्रतिस्पर्धा के अनुचित तरीके का न्यूट्रीलाइजेशन करने से पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों का आश्रय लेने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, भारत का कोरिया आरपी और जापान के साथ मुक्त व्यापार करार है और भारतीय पक्ष के मुद्दे का हल करार में निर्धारित द्विपक्षीय तंत्र का उपयोग करके किया जा सकता है।
- च. विशेष रक्षोपाय साधनों के संबंध में डब्ल्यूटीओ करार क्षति/क्षति की चुनौती के साक्ष्यों के उच्चयनिक निर्धारित करता है, जिसे, करार के अनुसार, किसी प्रकार के साधन का लाभ उठाने के लिए गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
- छ. चीन जन.गण., जापान और कोरिया आरपी से बदी सुपुर्दगियों के बावजूद राष्ट्रीय उद्योग का आर्थिक निष्पादन समान स्तर पर बना रहा। भारतीय उत्पादकों के निवेश स्तर में वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

III. फेडरेटिव रिपब्लिक <mark>ऑफ</mark> ब्राजील

- क. रक्षोपाय साधन आपातकालीन साधन हैं और इनका प्रयोग डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करके ही किया जाना चाहिए।
- ख. भारत अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से पहले इसे अधिसूचित करने में असफल रहा, और इसके अधिरोपण से पहले भारत रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 12.4 के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा।
- ग. प्राधिकारी ने वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 की अवधि के लिए घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने 2015-16 की पहली तिमाही के आधार पर क्षित पैरामीटरों को चार से गुणा कर दिया। ब्राजील यह तर्क देता है कि यह अधिगम गलत है क्योंकि यह सामान्य लेखाकरा सिद्धांतों से असंगत है और यह भी कि वर्ष 2015-16 की एक तिमाही वर्ष 2015-16 के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन को संकेत देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि वह वित्तीय वर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। ब्राजील पुन: यह तर्क देता है कि भारतीय प्राधिकारियों ने अप्रैल, 2011 से मार्च 2012 की अवधि के लिए आंकड़ों का चयन करने की अनदेखी इस तथ्य के बावजूद की हैं कि यह आंकड़े प्राधिकारी को उपलब्ध थे। ब्राजील के अनुसार यह रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(क) का उल्लंघन है। पुन: ब्राजील यह तर्क देता है कि गंभीर पूर्वपिक्षा की जांच की अवधि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी समिति की सिफारिशों के अनुसार तीन वर्ष होनी चाहिए और इस मामले के संबंध में दो वर्षों और एक तिमाही की अवधि पर्याप्त नहीं है। ब्राजील यह तर्क देता है कि जांच की अवधि को इस औचित्य के साथ कम नहीं किया जा सकता है कि अधिकतम अभिनव अवधि के लिए वास्तविक आंकड़े जांच की कार्रवाई के दौरान इकट्ठे किए जाएंगे। इन तर्कों के आलोक में ब्राजील यह तर्क देता है कि भारत रक्षोपाय करार में निर्धारित उद्देश्यों का पालन करने में असफल रहा।
- घ. घरेलू उद्योग के क्षति पैरामीटर गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती की मौजूदगी का संकेत नहीं देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राजील ने प्रारंभिक जांच परिणाम में ही उल्लिखित क्षति पैरामीटरों का उल्लेख किया है न कि याचिका में उल्लिखित क्षति पैरामीटरों का।
- ङ. इस मामले में कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, क्योंकि अन्य कारकों का विश्लेषण यह संकेत देता है कि घरेलू उद्योग को क्षति आयातों के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से हुई है।
- च. प्राधिकारी ने प्रत्येक निर्यातक देश के शेयर की सूचना नहीं दी है और विकासशील देशों की सूची भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। ब्राजील यह तर्क भी देता है कि प्रत्येक स्रोत से आयातित मात्रा का परिकलन करने के लिए मिली समयाविध का उल्लेख नहीं किया गया है। इस अनिवार्य सूचना के अभाव के कारण ब्राजील का यह तर्क है कि वह रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.1 के अंतर्गत रक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम नहीं रहा।
- छ. ब्राजील यह तर्क देता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षिति होने अथवा गंभीर क्षिति की कोई चुनौती नहीं है और कारणात्मक संबंध भी नहीं हैं। पुनश्च, ब्राजील यह तर्क देता है कि औपचारिक सूचना का प्रकाशन का इस मामले में अनुपालन नहीं किया गया है।

IV. चीन जन.गण.

- क. गाट के अनुच्छेद XIX के अनुसार कोई अनपेक्षित विकास नहीं हुआ और याचिकाकर्ताओं द्वारा जो अनुभव किया गया वह है सामान्य बाजार उतार-चढ़ाव जिसे अनपेक्षित नहीं कहा जा सकता है।
- ख. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 6 के आशय के अंतर्गत कोई संवेदनशील परिस्थितियां नहीं हैं जो रक्षोपाय शुल्क लगाने को अधिपत्रित करती है।
- ग. घरेलू उद्योग को न तो गंभीर क्षति हुई और न ही गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हुई।
- घ. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जनहित में नहीं है क्योंकि आटोमोटिव और उपभोक्ता डयूरेबल्स जैसे अनुप्रवाही उद्योगों को क्षति होगी।
- ङ. अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का तत्काल प्रतिसंहरण कर लेना चाहिए।

V. चाइनीज ताइपेई

ताईवान की प्राथमिक चिंता यह है कि उसका नाम विकासशील देशों की सूची में शामिल नहीं है, जिसे भारत में दिनांक 14 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या 103/98-सीयूएस के तहत अधिसूचित किया। ताईवान यह विश्वास करता है कि चूंकि वह सूची में नहीं हैं इसलिए यदि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किया जाता है तो ताईवान से हुए आयातों पर तब भी रक्षोपाय शुल्क लगेगा जब उसके आयात वर्ल्ड ट्रेड एटलस स्टेटिस्टिक्स के अनुसार अत्यधिक अभिनव समय में 3 प्रतिशत से कम होंगे। ताईवान ने माननीय महानिदेशक से पूर्वोक्त अधिसूचना को अद्यतन करने का अनुरोध किया है ताकि विकासशील देश के रूप में ताईवान की आर्थिक स्थिति स्पष्ट हो सके।

VI. यूरोपीय कमीशन

- क. रक्षोपाय साधन का प्रयोग केवल अपवादिक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए और वर्तमान मामला पाटनरोधी और सब्सिडी रोधी जांच के लिए उपयक्त है।
- ख. इस संबद्ध वस्तु के कतिपय विशिष्ट ग्रेडों का अपवर्जन उत्पाद के दायरे से कर देना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग उनका विनिर्माण नहीं करते हैं।
- ग. वर्ष 2015-16 के वार्षिकीकृत आंकड़ों का प्रयोग उद्देश्यपरक नहीं है और वार्षिकीकृत आंकड़ों के आधार पर क्षति विश्लेषण एवं कारणात्मक निर्णायक नहीं हो सकती है।
- घ. वर्ष 2015-16 की दीर्घतर अवधि के आंकड़ों पर विचार करना चाहिए। गंभीर क्षति और बाजार हिस्सा, उत्पादन, क्षमता उपयोग दर, रोजगार, लाभ, बाजार हिस्सा आदि सहित कारणात्मक का निर्धारण करने के लिए जिन तथ्यों पर विचार किया गया वे पर्याप्त नहीं हैं और यह कारक क्षति एवं कारणात्मक का संकेत नहीं देते हैं।
- ङ. ग्राही बिक्री तथा अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा की गई बिक्री की जांच की जानी चाहिए। भारतीय उत्पादकों ने खुले बाजार में अपनी बिक्री 42 प्रतिशत तक बढ़ा दी है।

VII. इंडोनेशिया सरकार

- क. इंडोनेशिया यह नोट करता है कि अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क से भारत को उनके निर्यात प्रभावित होंगे।
- ख. आयातों में वर्ष 2013-14 और 2014-15 के बीच 97 प्रतिशत तक वृद्धि हुई परंतु वर्ष 2014-15 और 2015-16 (वार्षिकीकृत) के बीच वृद्धि केवल 33 प्रतिशत ही है। अत:, वृद्धि के स्तर में सामान्य गिरावट आई है और ऐसे आयातों को अचानक, तीव्र, बहुत अधिक एवं अभिनव के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ग. ऐसी कोई संवेदनशील परिस्थिति नहीं थी जिसके कारण अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना आवश्यक हो गया हो।
- घ. यूएन कामट्रेड आंकड़े दर्शाते हैं कि इंडोनेशिया से इस संबद्ध वस्तु के आयात 3 प्रतिशत से कम थे और इसलिए इंडोनेशिया को रक्षोपाय शुल्क के परिक्षेत्र से अलग रखना चाहिए क्योंकि यह एक विकासशील देश है।

- ङ. इंडोनेशिया कंपनी पीटी कराकताऊ पास्कों केवल "नाट इन कॉइल एंड/और हाट रोल्ड प्लेट" के वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले उत्पाद का ही उत्पादन करती है। इंडोनेशिया से "इन काइल्स" के विशिष्ट प्रकार के स्टील उत्पाद का कोई निर्यात नहीं हुआ।
- च. परिणामत:, इंडोनेशिया से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई।
- छ. भारत ने अभी हाल ही में स्टील पर आयात शुल्क बढ़ाया है परंतु कुछ एशियाई देशों से आयात भारत-आशियान एफटीए, भारत-जापान सीईपीए और भारत-कोरिया सीईपीए के अंतर्गत द्विपक्षीय व्यापार के न्यून शुल्क पर हो रहे है।

VIII. तुर्की गणराज्य

- क. डब्ल्यूटीओ नियमावली के अनुार सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे "अनपेक्षित विकास" की मौजूदगी की पहचान करने जिनके कारण संगत घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित करते हुए अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न करते हुए संवर्धित आयात हुए।
- ख. भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ को अधिसूचना में अनपेक्षित विकास के संबंध में तर्कसंगत या पर्याप्त स्पष्टीकरण/विश्लेषण नहीं है। भारतीय प्राधिकारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे कौन से अनपेक्षित विकास हुए जिनके कारण संबद्ध वस्तु के आयातों में तथाकथित वृद्धि हुई।
- ग. वर्ष 2015-16 में वार्षिकीकृत आधार पर आयातों में वृद्धि सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती है। वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में आंकड़ों का बहिर्वेशन और वर्ष 2011-13 की अविध की अनदेखी करने से शंका उत्पन्न होती है और भारतीय घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव का विश्लेषण करने में भ्रामक अबवोधन का रास्ता साफ होता है।
- घ. वर्ष 2011-12 और 2012-13 की अवधि के लिए क्षति पैरामीटरों में बदलाव की भी जांच की जानी चाहिए। अभिनव अवधि में आयात में छोटी-मोटी वृद्धि को सामान्य वृद्धि के रूप में मानना चाहिए।
- ङ. 2013-14 और 2014-15 में लाभप्रदता में वृद्धि और क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान बिक्री में वृद्धि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का संकेत प्रदान नहीं करती है।
- च. संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग को अन्य कारणों से क्षति हो रही है। उदाहरण के लिए, सेल की वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि स्थिर बिक्रियों, उच्चतर वेतन और मजूदरी, आयातित कोयले का अधिक प्रयोग तथा नई सुविधाओं को पूंजीकरण का उच्चत अवक्षयण एवं सावधि जमा पर ब्याज अर्जन में कमी के कारण उसकी लाभप्रदता प्रभावित हुई।
- छ. तुर्की के आयात 3 प्रतिशत की सीमा से कम हैं और इसलिए रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 के अनुसार तुर्की को रक्षोपाय शुल्क के दायरे से बाहर रखना चाहिए क्योंकि यह एक विकासशील देश है।

IX. उक्रैन का राजदूतावास

- क. संबद्ध वस्तु के आयातों में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष2014-15 में केवल 14 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। आयातों में इतनी सी मामूली वृद्धि इतनी पर्याप्त नहीं मानी जा सकती है कि उससे गंभीर क्षति कारित हुई हो अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।
- ख. प्राधिकारी ने इस जांच की शुरूआत वर्ष 2015-16 के पूर्वानुमानित आंकड़ों जिनका वर्ष 2015-16 के पूर्वानुमानित आंकड़ों जिनका वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही के आधार पर वार्षिकीकरण करके शुरू कर दी। अत:, प्राधिकारी ने इस रक्षोपाय जांच की शुरूआत करने और पूर्वानुमानित आंकड़ों के आधार पर अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का निर्णय लेते समय रक्षोपाय करार के अनुच्छेद-2 का उल्लंघन किया है।
- ग. उक्रैन यह प्रदर्शित करने के लिए कि क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान भारत में शीर्षक 7208 और 72253090 के अंतर्गत हाट रोल उत्पादों के आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई। इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष2010 के स्तर की तुलना में वर्ष 2014 में आयातों में 41 प्रतिशत की कमी आई।
- घ. इसके परिणामस्वरूप, भारत के लिए जांच शुरू करने अथवा एओएस के अनुच्छेद 2.1 के आशय के अंतर्गत अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

- ङ. औद्योगिक संकेतक, घरेलू बिक्रियों, उत्पादन, बाजार हिस्सा, क्षमता, क्षमता उपयोग के लिए, जब इनकी तुलना वर्ष 2011-12 के साथ-साथ वर्ष 2014-15 से की जाती है तब सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। इसलिए, भारत के लिए एओएस के अनुच्छेद 4.1 (क) के अंतर्गत गंभीर क्षति का सकारात्मक निर्धारण करने का कोई कारण नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, ऐसी कोई संवेदनशील परिस्थितियां नहीं थी जिनके कारण एओएस के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण करना अधिपात्रित हो गया हो।
- च. इस मामले में एओएस के अनुच्छेद 2.1 और 4.2 (ख) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से की क्षति के कारण हुईा परिणामत:, घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा एक अन्य कारक है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई।

उत्पादकों/निर्यातकों/एसोसिएशनों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

- X. चाइना आयरन एंड स्टील एसोसिएशन; अनगांग ग्रुप हांगकांग कंपनी लिमिटेड, अनगांग स्टील कंपनी लिमिटेड; शंघाई मैशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड; अनगांग ग्रुप इंटरनेशनल ट्रेड कारपोरेशन; बायोस्टील सिंगापुर पीटीई लिमिटेड; मानशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड; बैन्स्की आयरन एंड स्टील (ग्रुप) इंटरनेशनल इकनामिक एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड; जियांग्शु शांगांग ग्रुप; हान्दान आयरन एंड स्टील ग्रुप कंपनी लिमिटेड; जिनका प्रतिनिधित्व एथेना लॉ एसोसिएट ने किया।
 - क. रक्षोपाय साधन "नो फाल्ट" सिद्धांत पर आधारित हैं और उन आयातों पर लगाए जाते हैं जिनको सदभाव से किया जाता है, न कि घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से। इसलिए रक्षोपाय साधनों का आश्रय केवल ऐसे सख्त मामलों में ही लिया जाना चाहिए जहां डूबते उद्योग को बचाने के लिए कोई अन्य विकल्प शेष न रह गया हो। कोरिया डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि रक्षोपाय साधन असाधारण उपाय हैं जिनको केवल आपातकालीन स्थिति में ही अपनाया जाना चाहिए। वर्तमान याचिका किसी असाधारण या आपातकालीन स्थिति का निदर्शन नहीं करती है और इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए।
 - ख. चयनित पीयूसी बहुत व्यापक है और इसमें समरूपी उत्पादों को भी साथ-साथ रखा गया है। नियम 4 के साथ पठित अधिनियम की धारा 8ख (1) के अनुसार यह डीजी का कर्तव्य है कि वह विशेष रूप ऐसी वस्तुओं की पहचान करें जिन पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जा सकता है। पीयूसी की पहचान विलक्षणता में की जानी चाहिए और कुछ ऐसी वस्तुओं की बहुलता हो जिन्हें समान उत्पाद कहा जा सके। आंध्र पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तर्क का समर्थन किया है। मौजूदा जांच में उपशीर्षक 7225 के अंतर्गत वर्गीकृत उत्पाद उपशीर्षक 7208 के अंतर्गत वर्गीकृत उत्पाद समान नहीं हैं और बहुल हैं अथवा समरूपी प्रवृत्ति के हैं जिन्हें एकल पीयूसी मानने के लिए एक साथ नहीं रखा जा सकता है।
 - ग. रक्षोपाय नियमावली के साथ पठित सीटीए की धारा 8ख इस करार के अनुच्छेद का डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्वचन यह दर्शाता है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए मौलिक पूर्वापेक्षाएं हैं आयातों में अचानक एवं तीव्र वृद्धि; यह अचानक वृद्धि अनपेक्षित विकास के कारण होनी चाहिए; घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो; क्षति और संवर्धित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध हों; शुल्क की वापसी के पश्चात प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए स्वयं को समायोजित करने की घरेलू उद्योग में क्षमता हो; और शुल्क जनहित के विपरीत न हो। वर्तमान जांच में उपर्युक्त विधिक मानकों को पूरा नहीं किया गया है।
 - घ. पीयूसी के आयातों में अचानक एवं तीव्र वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2013-14 में आयात 1.29 मिलियन एमटी थे और यह वित्त वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) में बढ़कर 3.38 मिलियन एमटी हो गए। अद्यतन अविध के साथ अंतिम बिंदु विश्लेषण भ्रामक है और प्राधिकारी को व्यापक एवं वास्तविक विश्लेषण पर विचार करना चाहिए। यूएस कतिपय स्टील उत्पादों में अपीलीय निकाय ने धारित किया कि परीक्षण केवल अंतिम बिंदु तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि मामलों के तथ्यों पर विचार करते हुए व्यापक जांच पर विचार करना चाहिए।
 - ङ. वर्षों के दौरान आयातों से संबंधित सूचना और वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान आयातों की तिमाही जांच भी यह दर्शाती है कि आयातों में अभिनव अविध में अचानक एवं तीव्र वृद्धि नहीं हुई। बल्कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में आयातों में जो विगत तिमाही में 3.38 मिलियन एमटी थे घटकर 3.60 मिलियन एमटी रह गए। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के बीच तीव्र वृद्धि हुई परंतु उस समय घरेलू उद्योग को लाभ हो रहा था। यह वृद्धि, यदि कोई, अस्थायी प्रकृति की थी इसकी प्रकृति अत्यधिक विपर्यय थी जैसािक वित्त वर्ष 2015-16 (प्रथम तिमाही) के दौरान स्पष्ट है।
 - च. रक्षोपाय करार का अनुच्छेद XIX और अजेन्टीना फुटवीयर में पैनल द्वार किए गए निर्वचन तथा यूएस कतिपय स्टील उत्पादों में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि रक्षोपाय कार्रवाई आपवादिक प्रकृति की है जिसे केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही अपनाया जाना चाहिए। आवेदकों ने असाक्ष्यांकित दावों का आश्रय लिया है जैसे स्टील की विश्व बाजार में संकट,

जियोपोलिटिकल तनाव, मुद्रा का अवमूल्यन, चीन में मंदी, चीन और जापान में भारी बेशी क्षमताएं, अन्य देशों द्वारा व्यापार उपचार तथापि, यह दावे इस उत्पाद के संबंध में अनपेक्षित विकास की मौजूदगी को स्थापित नहीं करते हैं। आवेदक यह दावा करते हैं कि रूस, उक्रैन, चीन और ईयू से आयातों में वृद्धि भू-राजनीतिक तनाव, बेशी क्षमता और मुद्रा का अवमूल्यन होने के कारण अचानक हुई परंतु यह सभी अभिकथन झूठ हैं। चीन से आयातों में वर्ष वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2015-16 (प्रथम तिमाही) के बीच लगभग 50 प्रतिशत की कमी आई है। इसी तरह वर्ष 2011-12 और वित्त वर्ष 2015-16 (प्रथम तिमाही) के बीच 4.22 प्रतिशत की गिरावट आई। इसलिए, आयातों में वृद्धि तथा कथित कारित क्षति के बीच कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।

- छ. प्राधिकारी को, यह मूल्यांकन करते समय कि क्या संवर्धित आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित की है अथवा गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर दी है, उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक प्रकृति के सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते रखना चाहिए। अधोलिखित तथ्य यह निदर्शन करते हैं कि आवेदकों को गंभीर क्षति कारित नहीं हुई और न ही उनके समक्ष गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हुई।
 - (i) घरेलू उद्योग का उत्पादन स्थिर बना रहा परंतु अन्य उत्पादकों के उत्पादन में लगभग 15 बिंदुओं की वृद्धि हुई।
 - (ii) आवेदक की क्षमता में कोई भारी अंतर नहीं आया। यद्यपि संपूर्ण मांग को भारतीय उत्पादकों द्वारा पूरा किया गया था, तथापि भारत में बेशी क्षमता भी होगी। इस बेशी क्षमता से निर्यात बाजार को लक्ष्य बनाया गया।
 - (iii) घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई और यह अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री बहुत उच्चतर है।
 - (iv) भारतीय उत्पादक 88 प्रतिशत भारतीय मांग को पूरा करते हैं और केवल 12 प्रतिशत मांग की आयातों के लिए बचती है।
 - (v) आरओसीई में खासकर वित्त वर्ष 2012-13 की तुलना में वित्त वर्ष 2015-16 (प्रथम तिमाही) में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2015-16 (पहली तिमाही) में गिरावट की जांच रोस में ऐसे समय में वृद्धि के बीच प्रतिलोमित संबंधों द्वारा की जानी चाहिए जब घरेलू उद्योग को तथाकथित गंभीर क्षति हो रही थी।
 - (vi) बिक्री कीमत और आयातों की उतराई कीमत के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। वास्तव में, उनके बीच एक प्रतिलोमित संबंध है, एक ओर जहां वित्त वर्ष 2014-15 (प्रथम तिमाही) के दौरान उतराई कीमत में वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई। वित्त वर्ष 2014-15 (प्रथम तिमाही) में उतराई कीमत में गिरावट होने पर उसके लाभ में वृद्धि हुई।
 - (vii) मालसूची स्तर कोई प्रतिलोमित स्थिति नहीं दर्शाता है।
 - (viii) उत्पादकता एवं रोजगार का स्तर सुदृढ़ बना रहा।
- ज. भारतीय उत्पादकों ने क्षति आंकड़े न देते हुए चुनिंदा रूप से टाटा स्टील, भूषण स्टील जैसी कंपनियों के साथ प्रतिभागिता की है। इसलिए, डीजी को सहयोगकर्ता उत्पादकों के क्षति आंकड़ों की भी जांच करनी चाहिए जिससे घरेलू उद्योग की कथित क्षति स्थिति की व्यापक जांच हो सके।
- झ. आवेदकों ने यह स्थापित करने के लिए कोई सूचना नहीं दी है कि उसे क्षति हो रही है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को कथित क्षति और आयातों में कथित संवृद्धि के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- ञ. जेएसडब्ल्यू की वार्षिकी रिपोर्ट यह संकेत देती है कि अन्य कारणों का उनके कार्यनिष्पादन पर गंभीर प्रभाव है। प्राधिकारी द्वारा इन अन्य कारणों को भी जांच की जानी चाहिए थी।
- ट. अनन्तिम जांच परिणाम जल्दी-जल्दी में जारी किए गए और ऐसी कोई संवेदनशील परिस्थिति मौजूद नहीं है कि इस अनंतिम साधन का अधिरोपण में विलंब करने से अपूरणीय क्षति हो जाती। अनन्तिम साधनों के लिए अपेक्षित गंभीर क्षति को पूरा नहीं किया गया है।
- ठ. जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 10 में यह उल्लेख किया गया कि हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारियों के समक्ष अपने विचार रखने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाना चाहिए परंतु प्राधिकारी ने उनके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही प्रारंभिक जांच परिणाम जारी कर दिए।
- ड. आवेदकगण सीटीए की धारा 6(घ) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में अर्ह नहीं हैं क्योंकि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आवेदकों का इस संबद्ध वस्तु का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 50 प्रतिशत उत्पादन है।
- ढ. आवेदकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और उन्होंने घरेलू उद्योग के मामले में तर्कसंगत एवं सार्थक समझ की अनुमति नहीं दी है।

ण. आवेदकों ने कोई समायोजन योजना नहीं बताई है और प्रारंभिक जांच परिणाम भी किसी समायोजन योजना का उल्लेख नहीं करते हैं। यूनाइटेड फास्फोरस द्वारा रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कराने के लिए 1999 में दायर किए गए आवेदन में प्राधिकारी ने रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण शुल्क का अधिरोपण इस आधार पर करने से मना कर दिया था कि समायोजन योजना का प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं है। वाक्यांश "जनहित" को रक्षोपाय विधि में परिभाषित नहीं किया गया है परंतु इसकी शीर्ष न्यायालय द्वारा विभिन्न विधियों के अंतर्गत व्याख्या की गई है। यूनाइटेड फास्फोरस द्वारा 1999 में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कराने के लिए दायर एक आवेदन पत्र में, प्राधिकारी ने इस आधार पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से मना कर दिया कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं है।

XI. मेटिन्वेस्ट ग्रुप वैन बायल बेलिस द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया जिसका मेटिन्वेस्ट ग्रुप ने सुनवाई पूर्व अपने प्रस्तुतिकरणों जिनका विगत में व्यापक रूप से सारांशीकरण किया गया है को ध्यान में रखते हुए अपने तकों को सार रूप में प्रस्तुत किया हैं संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए यहां दोहराया नहीं गया है।

XII. दिल्लिंगर हटेनवेर्क

- क. हमारे पास प्राधिकारी द्वारा भेजे गए नोटिस में कंपनी का नाम "दिलिंगर एंड सालिजटर" है, जबकि सही नाम "दिलिंगर हटेनवेर्क" है।
- ख. हम इस संबद्ध वस्तु का उत्पादन अथवा भारत को उसका निर्यात नहीं करते हैं। हम हैवी स्टील प्लेट्स का उत्पादन करते हैं जो इस पीयूसी से भिन्न है।

XIII. जेईई स्टील कारपोरेशन, निसिन स्टील कंपनी लिमिटेड निप्पन स्टील एवं सुमिटोयो मेटल कारपोरेशन और कोबे स्टील लिमिटेड, जिनका प्रतिनिधित्व एजेडबी एंड पार्टनर्स द्वारा किया गया।

- क. डीजी रक्षोपाय, रक्षोपाय नियमावली के नियम 5(3) में उल्लिखित उपयुक्तता एवं यथार्थता के साक्ष्य की जांच करने में असफल रहे।
- ख. डीजी से फगार्ड ने रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 6 और रक्षोपाय नियमावली के नियम 2(ख) में यथाउल्लिखित संवेदनशील परिस्थितियों के अभाव में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने की गलती की है।
- ग. याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण करने के लिए किसी संगत क्रियापद्धति को प्रदान नहीं किया है। जिस एचआरसी का आयात किया जा रहा है उसका प्रयोग कई अनुप्रवाही उद्योगों में किया जाता है जैसे आटोमोबाइल्स, होम अप्लायन्सेस, परिवहन उपकरण, फेब्रिकेटेड स्टील उत्पाद और निर्माण सामग्री।
- घ. इस विशिष्ट ग्रेड की पीयूसी जिसका जापान की मिलों से निर्यात किया जाता है की आपूर्ति करने वाले भारत में कोई विनिर्माता नहीं है।
- ङ. भारत को जापान की मिलों द्वारा निर्यातित एचआर उत्पाद संघटकों को रासायनिक संरचना (अंतर्वस्तु प्रतिशत) में भिन्न है जैसे कार्बन, मैंगनीज, सिलिकान, बोरोन और फास्फोरस शुद्धताएं, जिन्हें अशुद्धता से बचने तथा अंतिम प्रयोक्ता द्वारा विहित विनिर्देशनों के अनुरूप बनाया जाता है।
- च. भारत को निर्यातित हाट रोल्ड उत्पाद कुछ ओईएम अपेक्षित विनिर्देशनों को भी पूरा करते हैं हाई होल एक्सपैन्सन दर, उच्च फार्मेबिलिटी, अपेक्षित टेन्साइल स्ट्रेंथ, कंडीशन्स आफ सफेस आदि, जिसका घरेल उद्योग आज की तारीख तक सफलतापूर्वक उत्पादन करने में सक्षम नहीं रहा है। भारतीय ग्राहक कितपय जापानी मिलों द्वारा आपूरित हाट रोल्ड स्टील काइल पर अनन्यत: भरोसा करते हैं क्योंकि यह निर्माण अनुप्रयोग के लिए संवेदनशील है और किसी भी घरेलू विनिर्माता द्वारा पूर्णतया प्रतिस्थानीय उत्पाद उत्पादित नहीं किया जाता है।
- छ. िकसी एचआरसी प्रदाय का चयन करने की प्रक्रिया एक दीर्घ एवं महंगी प्रक्रिया है और इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कई परीक्षण किए जाते हैं कि क्या उत्पाद सख्त क्वालिटी मानकों को पूरा करता है जिससे कि उसका भार कम किया जा सके और उच्च सुदृढ़ता के आटोमोबाइल संघटकों का सुनिश्चयन किया जा सके। सभी मैटीरियल स्रोतों का निर्णय मॉडल विकास करते समय जल्दी ही कर लिया गया और एक ऑटोमोटिव ओईएस के लिए माडल के लाइफटाइम के दौरान एचआरसी स्रोतों को बदलना (स्विच करना) बहुत कठिन है जिससे कि विनिर्मित कार की गुणवत्ता की सुसंगतता सुनिश्चित की जा सके। इसलिए, रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात भी आटो विनिर्माताओं को एचआरसी का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आयात करने की जरूरत पड़ेगी, जिसक कारण आटोमोबाइल्स की विनिर्माण लागत बहुत अधिक बढ़ जाएगी।

- ज. डीजी रक्षोपाय ने सभी ग्रेडों के हाट रोल्ड कॉइल उत्पादों को एक पीयूसी में क्लब कर दिया। आवेदन और प्रारंभिक जांच परिणाम से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इस पीयूसी से हॉट रोल्ड काइल उत्पादों का अपवर्जन कर दिया गया है, जिनका आयात जापान से किया जाता है और जिनका भारत के घरेलू उद्योग एवं याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है।
- झ. गाट के अनुच्छेद XIX -1(क) के अनुसार कोई भी अनपेक्षित विकास नहीं है और इसी तरह रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 के अनुसार कोई भी संवर्धित आयात नहीं हुआ।
- ञ. घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षित नहीं हुई। घरेलू उद्योग के उत्पादन स्तर में कोई गिरावट नहीं आई। ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार हिस्से में गिरावट आई है परंतु यह विश्लेषण वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही के लिए वार्षिकीकृत किए गए आंकड़ों पर आधारित है, जो सही तस्वीर नहीं दर्शाता है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण आई है। याचिकाकर्ताओं की ग्राही खपत में वृद्धि हुई है। उत्पादकता एवं रोजगार, क्षमता उपयोग और लाभ में कोई कमी नहीं आई बल्कि वर्ष 2014-15 में इसमें वृद्धि हुई है जब उसी अविध में आयातों में भी वृद्धि हुई थी। घरेलू उद्योग एचआर काइल्स पर उच्च कस्टम्स ड्यूटी द्वारा पहले ही संरक्षित है।
- ट. इस मामले में कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। घरेलू उद्योग उन अन्य कारकों को भी अभिज्ञात करने में असफल रहा है जिसके कारण उसे क्षति हुई है।
- ठ. घरेलू उद्योग कच्चे माल की अनुपलब्धता और उसकी उच्च लागत के कारण आर्थिक कार्य कुशलता और लागत प्रभावोत्पादकता युक्त फिनिस्ड स्टील उत्पादों का उत्पादन करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उच्च परिवहन लागत और कमजोर अवसंरचना भी घरेलू उद्योग को प्रभावित कर रही है।
- ड. हाट रोल्ड उत्पादों का घरेलू उद्योग द्वारा पर्याप्त मात्रा में विनिर्माण नहीं किया जाता है और अनुप्रवाही उद्योग प्रयोक्ताओं के लिए आयात आवश्यक हैं। भारतीय उत्पादकों ने घरेलू बाजार में इस कमी को बनाए रखने और उच्च कीमतों का अनुरक्षण करने के उद्देश्य से 1.3 मिलियन टन एचआर काइल्स का आयात निर्यात किया है। इस पीयूसी की घरेलू बाजार में आपूर्ति की कमी जेपीसी आंकड़ों में स्पष्ट है, जो इस्पात मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। इसलिए, रक्षोपाय शुल्क जनहित में नहीं होगा और विशेषकर यह भारतीय आटो उद्योग के लिए अनर्थकारी है। यह भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी हतोत्साहित करेगा। रक्षोपाय शुल्क कोल्ड रोल्ड उत्पादों के अनुप्रवाही उत्पादकों के लिए भी अनर्थकर होगा।

डीजी रक्षोपाय विनिर्माण के लिए एचआरसी पर टैरिफ रेट कोटा का अनुप्रयोग करने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि घरेलू उद्योग इन उत्पादों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं करता है।

XIV. आर्सेलर मित्तल ब्रासिल एसए

- क. प्रारंभिक रिमार्क के रूप में जब याचिकाकर्ता ने वर्ष 2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिए आयातों की यात्रा प्रदान की तो भारतीय प्राधिकारियों ने, अपने जांच शुरूआत नोटिस में जांच की अवधि 2013-14 से 2015-16 तक बनाए रखने का निश्चय किया था। एएस ब्रासिल भारतीय प्राधिकारियों द्वारा चयन की गई जांचावधि को चुनौती देता है जिसमें वर्ष 2015-16 के वार्षिकीकृत आधार पर दिए आंकड़ों को भी शामिल किया गया है।
- ख. वास्तव में आयातों की स्थिति वर्ष 2011 से 2014 तक भारी गिरावट दर्शाती है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 में यह गिरावट 13 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 और 2014 के बीच आयातों में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आई है।
- ग. वर्ष 2013-14 में गिरावट के पश्चात आयातों के स्तर में कुछ सुधार हुआ और यह गिरावट से पहले के स्तर तक पहुंच गए और इन आयातों के "तीव्र, अत्यधिक, अभिनव और अचानक" के रूप में भी नहीं देखा जा सकता है जैसाकि डब्ल्यूटीओ मामला विधि के अंतर्गत परिभाषित है।
- घ. वह तरीका जिससे आयातों की मात्रा की संगणना अत्यधिक अभिनव अवधि के लिए वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही के वार्षिकीकृत आंकड़ों के आधार पर की गई, उससे पक्षपातपूर्ण नतीजा निकलने की उम्मीद है।
- ङ. यदि आयातों में (14 प्रतिशत तक की) वृद्धि हुई है तो उसका विश्लेषण खपत की क्रमिक विकास (+29 प्रतिशत) के साथ संयोजन करके किया जाना चाहिए था।
- च. जांच की एक तिमाही के लिए वार्षिक आधार पर लाभ पर (अत्यधिक) बल दिए जाने से पूर्वाग्रहित परिणाम आने की संभावना है। इससे भी बेहतर है कि अन्य सभी कारक स्थिरता या सकारात्मक उदभवन प्रदर्शित करते हैं।
- छ. याचिकाकर्ताओं को 5 प्रतिशत बाजार हिस्से की क्षति हुई जबिक गैस याचिकाकर्ताओं के 5 प्रतिशत बाजार हिस्से में वृद्धि हुई। यह कथित क्षति और आयातों के बीच अनुरूपता में कमी दर्शाता है और यह कि वास्तव में यह आंतरिक प्रतिस्पर्धा का मुद्दा है।

- ज. यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्रियां इस संपूर्ण अवधि के दौरान स्थिर बनी रहीं वहीं इसकी ग्राही बिक्री में 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इससे गंभीर क्षति का प्रदर्शन नहीं होता है।
- झ. इस तथ्य के तर्कसंगत एवं पर्याप्त स्पष्टीकरण का अभाव है कि इस मामले में रक्षोपाय शुल्क क्यों लगाया जाए।
- ञ. ब्राजील से होने वाले आयातों को विकासशील देशों के खंड में शामिल किया जाना चाहिए।
- ट. इसकी भारतीय संबद्ध अनुप्रवाही कंपनी को किए गए आयातों को हर हाल में रक्षोपाय शुल्क से हटा देना चाहिए क्योंकि यह मुद्दा जनहित समानुपातिकता के सिद्धांत (डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 5.1) से जुड़ा हुआ है और निवेश की रक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

XV. चीन स्टील कारपोरेशन

- क. महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा अपनाई गई जांच प्रक्रिया जांच शुरूआत प्रत्युत्तर दायर करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को दिए गए अनुदेशों के पूर्णतया विपरीत है।
- ख. व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/1/97 दिनांक 06.09.1997 महानिदेशक (रक्षोपाय) पर प्रतिबद्धता आरोपित करता है कि वह अपने जांच परिणाम (चाहे वह प्रारंभिक हों या अंतिम) विधिवत जांच के पश्चात ही जारी करें। कोई भी जांच तब तक पूरी नहीं माना जीत है जब तक हितबद्ध पक्षकारों को उसमें प्रतिभागिता करने का अवसर न दिया जाए।
- ग. महानिदेशक (रक्षोपाय) एक न्यायिक कल्प निकाय होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के लिए बाध्य है। इस जांच में जारी किए गए प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सकल उल्लंघन किया गया है जैसाकि निदेशालय द्वारा जारी व्यापार नोटिस और नियमावली के अंतर्गत स्पष्ट है।
- घर चरेलू उद्योग आधार वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में अपनाया है परंतु डीजी रक्षोपाय ने अपनी ओर से आधार वर्ष बदल दिया। यदि डीजी रक्षोपाय ने वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में अपनाया होता तो आयातों में कोई वृद्धि नहीं होती बल्कि कुल मांग में चीन से आयातों के बाजार हिस्सों में 20 प्रतिशत से कमी होकर बाजार हिस्सा केवल 12 प्रतिशत रह जाना ही प्रदर्शित किया गया होता। इसके विपरीत डीजी रक्षोपाय ने 6 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत वृद्धि दर्शाने के लिए वर्ष 2012-13 को आधार वर्ष के रूप में अपनाया। संख्याओं का यह खेल स्पष्टतया दर्शाता है कि डीजी रक्षोपाय ने घरेलू उद्योग के साथ पक्षपात करते हुए कार्य किया है।
- ङ. घरेलू उद्योग अनुचित एवं अनधिपत्रित संरक्षण की मांग समय-समय पर सरकार से करती रही है।
- च. समायोजन योजना का अगोपनीय पाठ भी घरेलू उद्योग द्वारा कभी फाइल नहीं किया गया।
- छ. रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3(1) में यह अपेक्षा की जाती है कि जांचकर्ता प्राधिकारी अपने जांच परिणाम इस आधार पर रिकार्ड करेंगे कि क्या रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में होगा या नहीं। प्रारंभिक जांच परिणाम में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है।
- ज. ताईवान को डब्ल्यूटीओ सदस्यों और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विकासशील देश के रूप में माना जाता है और इसलिए ताईवान से आयातों को "विकासशील देशों" से आयात के खंड में रखा जाता है।
- झ. भारतीय आटोमोबाइल उद्योगों द्वारा प्राथमिकता प्रयोगकी जाने वाली हाई स्ट्रैंथ स्टील (एचएसएस) में ई 34 एसएस 4012ए, जेएसएच 780 आरएनएन 220020 पी, एसएई 1005 एम, एसएई 1006, एसएई 1006एम, एसएई 1008, एसएई 1040, एससीएम 435, एसपीए एच, एसएस 400, एसएस 490, सीयूएसटी-एस 235 जेएसएच 590 आरएनएन 220020पी, जेएसएच 780 आरएनएन-220020 पी, एसएई 1010, एसएई 2010, एसएपीएच 440 और एसपीएचसी ग्रेड शामिल है, परंतु यह ग्रेड इतने तक ही सीमित नहीं है, इसके साथ-साथ सीएससी के अपने मानक भी शामिल है जो आटो उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं इसलिए उन्हें रक्षोपाय साधन से अपवर्जित कर देना चाहिए।
- ञ. बाजार हिस्से में केवल 4.35 प्रतिशत बढोतरी को "अत्यधिक तीव्र" अथवा "अत्यधिक महत्वपूर्ण" वृद्धि नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, यह आयातों में किसी भी तरह से प्रोत्कर्ष नहीं कहा जा सकता है।¹ इस कारण ऐसी कोई संवेदनशील परिस्थिति मौजूद नहीं है, इस मामले में रिकार्ड में नहीं है जो प्रारंभिक रक्षोपाय शुल्क को न्यायोचित ठहराती हो।

¹ अर्जेन्टीना फ्टवीयर (ईसी) अपीलीय निकाय, पैराग्राफ 131 देखें

XVI. **हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया**: मैसर्स हुंडई स्टील कंपनी कोरिया ने अपने ई-मेल से यह सूचित किया कि उनके दिनांक 01.11.2015 को प्रस्तुतिकरणों (जिन्हें संक्षेप में अपर बताया गया है) को ही इस मामले में अंतिम प्रस्तुतिकरण के रूप में माना जाए।

आयातकों, प्रयोक्ताओं और एसोसिएशनों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

XVII. मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, जापान

- क. मित्मुई के भारत में 23 संयुक्त उद्यम है और मैसर्स इंडियन स्टील कारपोरेशन (आईएससी) गुजरात राज्य उनमें से एक है।
- ख. इस समय आईएससी रक्षोपाय शुल्क से पीड़ित है। एचआरसी पर रक्षोपाय शुल्क एक पक्षीय है और यह घरेलू एकीकृत स्टील मिलों का पक्ष लेती है। अनुप्रवाही उद्योगों के हितों पर भी समुचित ढंग से विचार किया जाना चाहिए।
- ग. जापान से एचआरसी का आयात होने की कुछ निश्चित जरूरतें हैं जैसे भारत में एचआरसी की मांग एवं आपूर्ति में अंतर क्वालिटी में अंतर जैसे कम कमियां होना, सरफेस क्वालिटी, उच्चतर उत्पादकता, साइज ग्रेड उपलब्धता आदि।
- घ. आईएससी के पास रक्षोपाय शुल्क को एब्जार्ब करने के लिए पर्याप्त साइज नहीं है जैसाकि सेल, जेएसडब्ल्यू टाटा आदि एकीकृत मिलों के पास हैं और अब आईएससी को एक गभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि जापान से एचआरसी एमओयू के आधार पर प्रमुख रिरोलर्स के लिए है, इसलिए आपूर्ति और खरीद की एक प्रकार से यह दीर्घावधिक सूझ है।
- ङ. विदेशी निवेशकों के दृष्टिकोण से अथवा आईएससीस के शेयरहोल्डरों के रूप में यदि स्टील प्रयोक्ता संगमेंट अथवा विनिर्माताओं की कीमत पर रक्षोपाय शुल्क के जरिए एचआरसी अथसवा कच्चे माल उद्योग का पक्ष लिया जाता है तो यह विनिर्माण उद्योग की वृद्धि के लिए विपरीत दृष्टिकोण होगा तथा विदेशी निवेश और मेक इन इंडिया विजन में एक अवरोध होगा।

XVIII. भारतीय उद्योग परिसंघ (एफआईआई)

- क. एचआर काइल एक आधारभूत कच्चा माल है जिसकी देश की हजारों अनुप्रवाही इंजीनियरिंग उद्योगों की इकाइयों द्वारा खपत की जाती है।
- ख. एचआर काइल पर 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क तथा 12.5 प्रतिशत कस्टम्स ड्यूटी जो कुल मिलाकर 32.5 प्रतिशत बनता है और परिष्कृत अनुप्रवाही उत्पादों पर 10 प्रतिशत के न्यूनतर औसत से आयात शुल्क से भारत में फिनस्ड वस्तु के आयातों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ग. भारत में अनुप्रवाही उद्योग एचआर काइल्स का सीआर काइल, जीपी/जीसी शीट, पाइप और ट्यूब्स, कलर कोरेड शीट्स आदि का उत्पादन करने के लिए प्रोसेस करते हैं।
- घ. अनुप्रवाही उत्पादों पर कोई भी शुल्क अधिरोपित किए बिना एचआर फाइल पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का कोई अर्थ ही नहीं है और इससे भारत में मुल्य वर्धित अनुप्रवाही उद्योग समाप्त हो जाएगा।

XIX. निप्पन स्टील और सुमिकिन पाइप इंडिया कंपनी लिमिटेड

- क. एसजीए के अनुच्छेद 2(1) के साथ-साथ एसजी नियमावली के नियम 2 के साधारण पाठन से यह स्पष्ट है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण उन आयातों पर नहीं किया जा सकता है जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों के पूर्णतया समान या समरूप न हों।
- ख. एनपीआई द्वारा आयातित हाट रोल्ड काइल्स को पीयूसी के दायरे से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों के समान या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धा वस्तुएं नहीं हैं।
- ग. एनपीआई भारत में ग्राहकों द्वारा अपेक्षित आटोमोटिव पाइप्स और ट्यूब्स को बनाने के लिए अपेक्षित बहुत ही विशिष्ट प्रकार के एचआरसी का आयात करता है।

- घ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एचआरसी एनपीआई द्वारा आयातित एचआरसी से रसायनिक कम्पोजीशन में बहुत अधिक भिन्न है।
- ङ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एचआरसी एनपीआई द्वारा आयातित एचआरसी की गुणवत्ता में बहुत अंतर है।
- च. एनपीआई आटोमोटिव पाइप्स का विनिर्माण करने में प्रयोग होने वाली ऐसी एचआरसी का आयात करता है जिसका भारतीय घरेलू उद्योग स्टील विनिर्माताओं द्वारा (i) पर्याप्त गुणवत्ता की एचआरसी की आपूर्ति नहीं की जाती है अथवा (ii) उन्होंने अंतिम प्रयोक्ताओं से अनुमोदन नहीं प्राप्त किया (अर्थात आटोमोबाइल विनिर्माताओं से)। एनपीआई घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एचआरसी का प्रयोग करने में अक्षम है क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादों के लिए औद्योगिक प्रयोक्ता अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है।

XX. कोल्ड रोल्ड स्टील मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन इन इंडिया (कोर्समा)

- क. डीजी रक्षोपाय ने अपनी दिनांक 09 सितम्बर, 2015 की रिपोर्ट में एचआर काइल्स के आयातों पर 20 प्रतिशत अननरितम रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करते समय अपना निर्णय मानकों का उल्लंघन करते हुए केवल ढाई वर्षों के आंकड़ों पर आधारित रखा था।
- ख. याचिका में एचआर काइल्स के उत्पादन, निर्यात, आयात ओर मालसूची से संबंधित आंकड़ों की सरसरी छानबीन यह व्यक्त करती है कि उन्होंने आंकड़ों को समूहों और उप-समूहों में विभाजित करके और वास्तविक आंकड़ों के बजाय अंतर को प्रतिशत के दर्शाकर इस मृद्दे को संभ्रमित किया है।
- ग. सरकार द्वारा इस याचिका पर औचित्यपूर्ण निर्णय के लिए उपचारी कार्रवाई हेतु किसी भिन्नता के कारणों को अभिज्ञात करने का विश्लेषण नहीं किया गया है।
- घ. अप्रैल-जुलाई, 2015 में आयातों में प्रोत्कर्ष के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया विवरण पूर्णतया भ्रामक है और इसमें अप्रैल-जुलाई, 2015 में आयातों में वृद्धि के कारणों को नहीं दर्शाया गया है, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया गया विश्लेषण साधारण रूप से यह व्यक्त करेगा कि आयात जो अप्रैल-जुलाई, 2014 में 4.71 लाख टन थे बढ़कर अप्रैल-जुलाई 2015 में 1.144 मिलियन टन हो गए। इस प्रकार घरेलू उत्पादन में गिरावट होने तथा खपत में वृद्धि होने के कारण आयातों में 673000 टन की वृद्धि हुई।
- ङ. याचिकाकर्ताओं, ने यह अभिकथन किया है कि घरेलू उत्पादकों को उच्च आयातों से मालसूची में हुई वृद्धि के कारण क्षति सहन करनी पड़ी परंतु जेपीसी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार मालसूची में कोई वृद्धि हुई ही नहीं।
- च. याचिकाकर्ताओं ने यह धारित किया है कि आयातों के लाभप्रदता का नुकसान हुआ परंतु जेपीसी आंकड़ों के अनुसार यह मानने योग्य नहीं है।
- छ. कुछ उत्पादकों द्वारा यह धारित किया गया कि भारत में एचआर काइल्स की कीमतें बिजली की अधिक लागत, ब्याज पर दर और भूमि की अधिक लागत के कारण बढ़ी हैं। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अधिकतर याचिकाकर्ताओं के अपने निजी ग्राही पावर प्लांट हैं और वास्तविक मुद्रा प्रति टन स्टील में विद्युत की उच्च खपत लगभग 30 प्रतिशत के साथ-साथ विश्वस्तरीय मानकों का है जिसमें कमी किए जाने की आवश्यकता है।
- ज. हाट रोल्ड काइल्स के आपात अनिवार्य विविधीकृत थे और यह घरेलू उपलब्धता तथा उत्पादन की बीच अंतर को मात्रा और गुणवत्ता दोनों रूपों में दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर किए गए थे।
- झ. वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में आयातों में वृद्धि इस तथ्य के कारण हुई कि एक और एचआर काइल्स की घरेलू खपत बढ़कर 362000 हो गई वहीं इसका उत्पादन घटकर 263000 रह गया इसके परिणामस्वरूप अधिक आयात हुए।
- ञ. यह आयात वैश्विक कीमतों के अनुरूप तथा भारतीय उत्पादकों द्वारा वर्ष 2014-15 में 1 मिलियन एचआर काइल तथा अप्रैल-सितम्बर, 2015-16 में 2 लाख 30 हजार टन एचआर काइल के निर्यात कीमत के समान थे।
- ट. हाट रोल्ड काइल के उत्पादक अपनी घरेलू कीमत उतराई लागत आधार पर निर्धारित करके पिछले पांच वर्षों से उच्च लाभ अर्जित कर रहे थे और उनमें से कुछ के द्वारा उपचित घाटे को भारत में और विदेश में स्टील तथा अन्य उद्योगों में किए गए अविवेकपूर्ण निवेश के कारण हुआ जिस पर उन्हें भारी ऋण लेना पड़ा और बाजार देना पड़ा।
- ठ. वित्तीय स्थिति में सुधार आरबीआई द्वारा यथाधारित स्टाक की बिक्री करके किया जाना चाहिए न कि स्टील के आयातों को रोककर और घरेलू उत्पादकों द्वारा एकाधिकारवादी कीमत निर्धारण के जरिए देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को अस्थिर बनाकर।

ड. एचआर काइल्स के आयातों पर अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से प्रतिलोमित शुल्क ढांचा बना है जबिक एक मध्यवर्ती उत्पाद एचआर काइल पर कुल आयात शुल्क 32.5 प्रतिशत बनता है और परिष्कृत कोल्ड रोल्ड उत्पादों शुल्क केवल 12.5 प्रतिशत है और इससे मूल्य वर्धित कोल्ड रोल्ड उत्पादों का आयात बढ़ा है एवं घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

XXI. ट्यूब्स लिमिटेड एवं निजोन स्ट्रिप्स लिमिटेड

- क. वे ब्लैक पाइप्स, आयताकार एवं वर्गाकार हालों सेक्सन्स ओर गाल्वनाइज्ड पाइप्स का निर्माण दकुनी, हुगली, पश्चिम बंगाल और रानीपेट, वेल्लौर तमिलनाड़ स्थित अपने संयंत्र में करते हैं।
- ख. उन्होंने दिनांक 21.07.2015 को एलसी खोली। उक्त संविदा में पोतलदान की अंतिम तारीख और एलसी 30.09.2015 थी और यह माल 29.09.2015 को पोत पर लादा गया और 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क 14.09.2015 को लगाया गया।
- ग. इस अधिरोपण के परिणामस्वरूप भारी अनपेक्षित लाभ बढ़ी जो उनकी मौजूदगी के लिए एक चुनौती है।
- घ. सभी समन्वित संयंत्र की अनुप्रवाही उत्पादों का उत्पादन करते हैं और वे एचआर काइल की कच्चे माल के रूप में ग्राही रूप से खपत करते हैं इसलिए वे अपनी तरह स्टैंड अलोन अनुप्रवाही उद्योगों को एचआर काइल की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है जो कच्चे माल के रूप में एचआर काइल का उपभोग करती हैं।
- ङ. अन्य घरेलू उद्योग अर्थात एसएमई जैसे एनटीएल को 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क और 12.5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी का भगतान करके समन्वित संयंत्रों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी।
- च. एसएमई उद्योग द्वारा अनुप्रवाही उत्पादों का निर्यात असंभव होगा क्योंकि एचआर काइल जो उनका कच्चा माल हैं, की कीमतें रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव से मनमाने रूप से बढ़ा जाएगी।
- छ. 600 एमएम से अधिक की चौड़ाई वाले एचआर काइल्स पर रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण करने से 600 एमएम से कम की चौड़ाई वाले उप-स्टैडर्ड एचआर स्ट्रिप का आयात प्रोत्साहन होगा।
- ज. रक्षोपाय शुल्क से लंबे उत्पादों जैसे बिलेट आदि का री-रोलर्स के लिए आयात प्रोत्साहित होगा, जिससे क्वालिटी पुन: प्रभावित होगी।
- झ. भारत में एचआर काइल्स के लिए मांग कम होगी क्योंकि सभी अनुप्रवाही उत्पादों का आयात किया जाने लगेगा और इस प्रकार रक्षोपाय शुल्क का घरेलू उद्योग की रक्षा करने का प्रयोजन समाप्त हो जाएगा।

XXII. पोस्को कोरिया और पोस्को स्टील, महाराष्ट्र

- क. इस विचाराधीन उत्पाद के भारी प्रतिशत (लगभग 90 प्रतिशत) का आयात अनन्यत: पोस्को कोरिया से पोस्को महाराष्ट्र द्वारा अपने अनुप्रवाही उत्पादों अथवा कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। इसलिए इस पीयूसीस की 90 प्रतिशत पोस्को द्वारा गा्रही रूप से खपत की जाती है और यह भारत की घरेलू बाजार में समान वस्तु के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है।
- ख. आयातों की वह मात्रा जिसकी ग्राही रूप से खपत की जाती है, उसे आयातों की कुल मात्रा से अलग कर दिया जाना चाहिए ताकि आयातों की मात्रा में से बाजार में प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी आयातों की मात्रा की सही तस्वीर चित्रित की जा सके ओर हम आंकड़ों की तुलना सही-सही कर सकें।
- ग. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और घरेलू उद्योग के समर्थक उद्योग द्वारा इस पीयूसी की ग्राही खपत को शामिल किया है जिससे बाजार में इस पीयूसी की कुल मांग को आहरित किया जा सके। घरेलू बाजार में प्रतिशत बाजार हिस्से का परिकलन करते वक्त घरेलु उद्योग की ग्राही खपत का अपवर्जन कर दिया।
- घ. तथापि, उसी समय, आयातों के बाजार हिस्से के प्रतिशत का परिकलन करने के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाया गया क्योंकि ग्राही रूप से खपत की गई आयातों की मात्रा (जो एक बड़ा भाग है) पर घरेलू बाजार में आयातों के प्रतिशत बाजार हिस्से का परिकलन करने के लिए विचार किया गया है।
- ङ. अन्य उत्पादकों का बाजार हिस्सा (जो वर्ष 2011-12 में) 25 प्रतिशत था, बढ़कर (वर्ष 2014-15 में) 35 प्रतिशत हो गया। वह बाजार हिस्सा जिसके लिए कहा जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने खो दिया उसे अन्य उत्पादकों द्वारा ग्रहण कर लिया गया।

- च. डीआई द्वारा आपूरित पीयूसी की सराफेस क्वालिटी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और इसे न्यून गुणवत्ता के कारण अक्सर नामंजुर कर दिया जाता है।
- छ. पीयूसी के यथातथ्य ग्रेड, जो अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं उन्हें सारणीबद्ध किया गया है और वे इस प्रस्तुतिकरण के प्रदर्श-5 के रूप में संलग्न हैं।
- ज. घरेलू उद्योग की बिक्री में कथित गिरावट के कारण हैं (क) अला उपयोग; (ख) अधिक ऋण/वित्त लागत (पूंजी गहन उद्योग होने के कारण); (ग) डीआई द्वारा आयात के समय पीयूसी वह है जो विश्व बाजार में प्रचलित थी; (घ) घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में बेची गई पीयूसी वैश्विक/अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक थीं।
- झ. क्षति का विश्लेषण वर्ष 2015 की प्रथम तिमाही में आधार पर किया गया क्षति विश्लेषण का यह उचित तरीका नहीं है और इस उद्देश्य के लिए काफी लम्बी अवधि के समय पर विचार करना चाहिए।
- ञ. बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा प्रकाशित और जेएसडब्ल्यू की वेबसाइट पर अपलोडेड दिनांक 05.06.2015 का एक लेख स्पष्टत: यह उल्लेख करता है कि जेएसडब्ल्यू के निवल लाभ में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबिक सेल के लाभ में 24 प्रतिशत की गिरावट आई जिसे उच्च वित्त लागत पर उपरोपित किया जा सकता है।
- ट. वर्ष 2009 में हस्ताक्षरित भारत-कोरिया साझेदारी करार (सीईपीए) जहां भारत ने इस पीयूसी पर शुल्क को घटाकर शून्य करने की वचनबद्धता की है का प्रत्यक्ष उल्लंघ्जन करके रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना।
- ठ. आयातों में कथित प्रोत्कर्ष और घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

XXIII. वी.के. इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड

- क. कंपनी एक आयातक है और फ्लैट स्टील उत्पादों का स्टॉक करती है।
- ख. घरेलू स्टील फार्मों का क्षमता उपयोग 76 प्रतिशत है जो विश्व के औसत क्षमता उपयोग 72.86 प्रतिशत से अधिक है। क्षमता उपयोग में कोई गिरावट नहीं आई है।
- ग. घरेलू स्टील फर्मों के उत्पादन में क्षमता में वृद्धि के अनुरूप नहीं वृद्धि हुई।
- घ. वर्ष 2014-15 में नौकरियों की कोई क्षति नहीं हुई परंतु इनमें 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- ङ. घरेलू विनिर्माताओं को शायद ही कोई बाजार क्षति हुई हो। आयातकों के बाजार हिस्से के तीन वर्ष का औसत 9 प्रतिशत था जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया। 1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह क्षति कारित कर रही है।
- च. हाट रोल्ड काइल्स की कीमतें पिछले संपूर्ण विश्व में अचानक कम हुई है। कीमतों में इस गिरावट का कारण लोहा एवं कोयला की कीमतों में कमी होना जो इस्पात उत्पादन के लिए अपेक्षित सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। वर्ष 2014-15 में लौह अयस्क की कीमतों में 41 प्रतिशत की कमी और कोयले की कीमतों में 21 प्रतिशत तक की कमी आई है।
- छ. घरेलू उत्पादकों को अपने वैश्विक प्रतिद्वन्दियों की तुलना में निम्नलिखित कारणों से उच्च कीमतों का सामना करना पड़ रहा है :
 - (i) उच्च मालभाड़ा लागत क्योंकि भारत में संभारतंत्रीय लागत बहुत अधिक है। वैश्विक स्टील उत्पादक समुद्र के किनारे अवस्थित हैं जिससे उनकी लागत कम हो जाती है।
 - (ii) भारत में लौह अयस्क की खानों पर प्रतिबंध से लौह अयस्क के उत्पादन में कमी आई है इसके परिणामस्वरूप भारत में लौह अयस्क की कीमतों में गिरावट अल्पतम हुई है। सभी घरेलू उत्पादकों की ग्राही लौह अयस्क खानें नहीं हैं और जिनकी अयस्क की ग्राही खाने हैं, उनको भी लागत रायल्टी शुल्कों और उच्चतर कीमत निर्धारण बोली की वजह से उच्चतर लागत होती है।
 - (iii) भारत में पूंजी लागत चीन जैसे देशों में पूंजी लागत की तुलना में बहुत अधिक है।
- ज. रक्षोपाय साधन से भारत के घरेलू उद्योग की अस्थायी तौर पर रक्षा करेगा न कि इससे उद्योग स्थाई रूप से सुदृढ़ होगा।

- झ. घरेलू उत्पादक लाभ अर्जन कर रहे हैं और उच्च कारोबार कर रहे हैं। विश्व स्टील एसोसिएशन ने यह रिपोर्ट किया कि भारत की स्टील आउटपुट में 2.8 वृद्धि है जबकि वर्ष 2014-15 में विश्व में स्टील के उत्पादन में 3 प्रतिशत की कमी आई थी।
- ञ. आयात एसएमई के लिए जीवन रेखा हैं जो एमएनसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास कर रहे हैं। रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण ने आपूर्ति श्रृंखला के भागीदारों को गहरे घाटे में ला छोड़ा है।
- ट. भारत पूंजीगत वस्तुओं के निर्यातों पर फल फूल रहा है और इन पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल में से प्रमुख कच्चा माल स्टील है। इसलिए इन उत्पादों के निर्यातकों को उच्च उत्पादन लागत सहन करना पड़ेगी और वे अक्षम हो जाएंगे। स्टील पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात को 25 प्रतिशत तक कम कर देगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में इसकी लागत में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर देगा।
- ठ. रक्षोपाय शुल्क ने कई विदेशी निवेशकों को निराश किया है और कोरिया के साथ भारत के संबंधों को जोखिम में डाल दिया है। इसलिए भारत में विदेशी निवेश कम होगा।
- ड. रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से भारत में इंजीनियरिंग फर्मों की लागत 33-35 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। इसलिए, पूंजीगत वस्तुओं के आयात में आर्थिक भावना बनती है, न कि विनिर्माण करने में।

XXIV. हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड

- क. यदि स्टील की एचआर काइल्स जैसे कच्चे माल पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो वह अवनतिशील कदम होगा क्योंकि इससे पैसेन्जरकारों की कीमत बढ़ जाएगी। और उन्होंने वे भारत में तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने योग्य नहीं रहेंगी और इससे हमारे निर्यात और भी कम हो जाएंगे।
- ख. पैसेंजरकार की अधिकांश कंपनियां क्वालिटी कारणों से आटोमोटिव ग्रेड के एचआर कॉइल्स का आयाय करती हैं, चूंकि आयातित स्टील को "उच्च तनन शक्ति" और "फार्मेबिलिटी" (आकृति ग्रहण करने की क्षमता) के बीच हल्का सा संतुलन रखना अपेक्षित होता है। हम इस ग्रेड का आयात करना जारी रखेंगे क्योंकि रक्षोपाय शुल्क हमारे लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा कि हम अपनी खरीद को विदेशी स्रोत से शिफ्ट करके भारतीय मिल निर्माताओं की ओर कर दें।
- ग. आटोमोटिव ग्रेड की स्टील का आयात 600 यूएसडी 700 यूएसडी प्रति टन पर किया जाता है और रक्षोपाय शुल्क लगाकर इस कीमत को और अधिक बढ़ा देने का कोई तर्क प्रतीत नहीं होता है।
- घ. भारत-कोरिया सीईपीए के अंतर्गत कस्टम्स ड्यूटी लगभग शून्य होने वाली हैं और इसकी प्रत्याशा में कोरियाई कंपनियों ने भारत में भारी निवेश किया है। अब उन कोरियाई फर्मों पर 20 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क लगाना, जो यूएसडी 600-यूएसडी 700 प्रति टन की कीमत रेंज पर आयात कर रही हैं, उचित नहीं होगा।
- ङ. कार विनिर्माताओं ओईएम द्वारा आयातित कोरियाई आटोमोटिव ग्रेड की स्टील को इस जांच के दायर से अलग कर देना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो प्राधिकारी यूएसडी 450 - यूएसडी 500 प्रति टन की संदर्भ कीमत निर्धारित कर सकते हैं ताकि इस कीमत से अधिक कीमत से सभी आयातों को रक्षोपाय शुल्क का भुगतान करने से छूट मिल जाए। इससे उच्च क्वालिटी की सामग्री के वास्तविक आयातकों और निर्यात मात्रा से प्रभावित हुए बिना घरेलू उद्योग की रक्षा हो जाएगी।

XXV. मानेकसिया स्टील लिमिटेड

मानेकसिया स्टील लिमिटेड भारत में इस संबद्ध वस्त की आयातक है। उन्होंने निम्नलिखित प्रस्ततिकरण किए हैं :

- क. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण उद्योग को अपने प्रचालन बंद कर देने को मजबूर कर रहा है क्योंकि यह विचाराधीन उत्पाद परिष्कृत उत्पादों के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है।
- ख. हमारे कच्चे माल "हाट रोल्ड स्टील काइल्स" की उतराई लागत आयातित "हाट रोल्ड स्टील काइल्स" जो हमारा परिष्कृत उत्पाद है की उतराई लागत की तुलना में बहुत अधिक है।
- ग. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से प्री-पेंटेड गोल्वेनाइज्ड काइल्स की आयात कीमत कच्चे माल के रूप में आयातित हाट रोल्ड स्टील काइल्स की तलना में बहत कम है।
- घ. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण "मेक इन इंडिया" संकल्पना के विपरीत है।

XXV।. मारूति सुजुजी इंडिया लिमिटेड

- क. डीजी रक्षोपाय ने जांच शुरूआत प्रारंभ करने के 2 दिन पश्चात ही प्रारंभिक जांच परिणाम जारी कर दिए और उन्होंने आयातकों, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सुनने का कोई अवसर नहीं दिया। उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम जल्दी-जल्दी में जारी किए हैं। उन्होंने निम्नलिखित पर भरोसा किया है:
 - सीमेंस इंजीनियरिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड बनाम भारत सरकार एवं अन्य (1976) सप्ली.एस.सी.आर.489
 - सी बी गौतम बनाम भारत संघ (1993)1 एससी 78
 - स्वदेशी काटन मिल बनाम भारत संघ 1981 एससीआर (2) 533
 - आटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य 2011. टीआईओएल-03 एससी. सीसयुएस।
- ख. इस मामले में महानिदेशक रक्षोपाय की नियुक्ति 7 सितम्बर, 2015 को की गई थी। आटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्सचरर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य पर भरोसा किया गया था, जिसके द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि नए निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक अलग सुनवाई प्रदान करनी चाहिए।
- ग. भारत को व्यापक आर्थिक भागीदारी करार के सदस्य होने के नाते, एफटीए के अनुच्छेद 23 का पालन करना चाहिए जिसमें यह उल्लेख है कि भारत को इस एफटीए के अंतर्गत शुरू किए गए रक्षोपाय जांच के मामलों में कुछ विशिष्ट दिशानिर्देशों का अनुसरण करने की जरूरत है। इस एफटीए में द्विपक्षीय रक्षोपाय साधन की शुरूआत के लिए भिन्न प्रणाली का प्रावधान है जिसमें अनुपालन के लिए कुछ अनिवार्य अतिरिक्त जरूरते हैं। प्राधिकारी ने द्विपक्षीय रक्षोपायों तथा विशेष शर्तों एवं उसमें निर्धारित प्रक्रियाओं के संबंध में एफटीए के प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी की है।
- घ. वर्तमान मामले में जापान से इस विचाराधीन उत्पाद का आयात किए जाने के संबंध में जांच शुरूआत प्रक्रिया के संबंध में जापान के राजदूतावास/जापान की सरकार को कोई सूचना प्रदान नहीं कराई गई थी। जापान के राजदूतावास/जापान की सरकार को बिना कोई सूचना/जानकारी दिए प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने का कार्य एफटीए के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करने का कार्य है। यूएस –अंडरवीयर, अपीलीय निकाय रिपोर्ट पर भरोसा किया गया। यूएस अंडरवीयर, जहां यह धारित किया गया था कि साधन का प्रकाशन करने से पहले, गाट के अनुच्छे-X के अंतर्गत यथापेक्षित, स्वत: ही कोटा के प्रकाशन की बारी से पहले शुरूआत की अविध के दौरान आयातों के संबंध में आयात कोटा लागू करने के पूर्व व्यापी प्रभाव को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।
- ङ. इस विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण करने के लिए कोई क्रियापद्धित नहीं अपनाई गई। याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए लेनदेनवार आयात आंकड़ों में ढेर सारी विसंगतियां हैं ओर कई स्थानों पर याचिकाकर्ता ने आयातित उत्पाद का समुचित ग्रेडेशन और सीरीज़ अभिज्ञान नहीं किया है। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में अभिज्ञात किए गए कतिपय उत्पादों और तत्पश्चात उन पर प्रारंभिक जांच परिणाम में जिन आयात आंकड़ों पर भरोसा किया गया है वे सही आंकड़े नहीं हैं ओर इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत शामिल नहीं है
- च. विगत में भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांच में चीन जन.गण., जापान, कोरिया, यूरोपीय यूनियन, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान (चाइनीज ताइपेई), थाइलैंड और यूएसए से आयातित कोल्ड रोल्ड स्टील उत्पादों का इस कारण से जांच के दायरे से अपवर्जन किया है कि उन्हें रक्षोपाय नियमावली के आशय के अंतर्गत समान वस्तु नहीं माना गया।
- छ. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने सभी ग्रेडों का समावेशन करने की मांग की है जिसमें ऐसे ग्रेड भी शामिल हैं जिनका विशेष रूप से अपवर्जन कर दिया गया था जिन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत समान उत्पाद नहीं माना गया था।
- ज. इस विचाराधीन उत्पाद के याचिकाकर्ता द्वारा यथा प्रदत्त आयात आंकड़ों को कोरैबोरेट करने और उन्हें प्रमाणित करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से परामर्श किया जाना चाहिए।
- झ. प्राधिकारी ने कहीं भी इस विचाराधीन उत्पाद को आयातकों द्वारा आयातित उत्पादों के समान रिकार्ड करने के लिए कहीं भी रक्षोपाय नियमावली के नियम 2(ड.) के अंतर्गत यथा-प्राविधानित "समान उत्पाद" की परिभाषा को कसौटी नहीं माना है।

- कोरिया और जापान से हुए आयात रक्षोपाय नियमावली के नियम 2(ड.) के अनुसार समाना उत्पाद नहीं हैं और इसलिए वे घरेलु उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के पृथक उत्पाद है।
- जापान से इस विचाराधीन उत्पाद का आयात करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि घरेलू उत्पादक प्रतिवादी द्वारा यथा-अपेक्षित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद की आपूर्ति करने में अक्षम है। प्राधिकारी को ऐसी आयातित वस्तु का अपवर्जन कर देना चाहिए जिनका विनिर्माण याचिकाकर्ताओं द्वारा नहीं किया जाता है। माननीय सीमाशुल्क, उत्पादकर एवं सेवाकर अपीलीय अधिकरण पर मैग्नेट यूजर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2003 (157) ईएलटी 150 (ट्री-दिल्ली) पर भरोसा किया गया, इस केस में यह धारित किया गया था कि उन ग्रेडों का इसमें शामिल करने का औचित्य क्या है जिसका भारत में विनिर्माण नहीं किया जाता है।
- यह विचाराधीन उत्पाद आयातित उत्पादों का विषमांग सेट है और इसलिए उन्हें घरेलू उत्पादकों/याचिकाकर्ताओं द्वारा विनिर्मित उत्पादों के साथ तुलना करने के लिए समान ग्रेड में शामिल नहीं किया जा सकता है। डब्ल्यूटीओ द्वारा डीएस 427-चीन-यूनाइटेड स्टेट्स से ब्रायलर उत्पादों पर पाटनरोधी एवं प्रतिसंतुलकारी शुल्क में जारी पैनल रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है।
- प्राधिकारी द्वारा नॉन-फिनष्ड विचाराधीन उत्पाद का समावेशन किया जाना न्यायोचित नहीं है और अनपेक्षित है
 क्योंकि इन उत्पादों का आयात भिन्न-भिन्न मात्रा में और अलग-अलग कीमतों पर किया जाता है।
- ञ. प्रतिवादी निम्नलिखित से इस्पात उत्पादों की खरीद करता है:
 - जेएसडब्लु स्टील लिमिटेड
 - एस्सार स्टील लिमिटेड
 - भूषण स्टील लिमिटेड
 - टाटा स्टील लिमिटेड
 - हीरो स्टील लिमिटेड
- ट. प्रतिवादी द्वारा उपभोग किए गए कच्चे माल एवं संघटकों में से 93 प्रतिशत का अधिप्रापण उपरिवर्णित घरेलू उत्पादकों में से किया गया है जिनमें दो याचिकाकर्ता भी शामिल है। शेष बची केवल 7 प्रतिशत विशेष प्रकार की स्टील ऐसी है जिसकी मांग की पूर्ति घरेलू उद्योग द्वारा नहीं की जाती है और जिसका आयात प्रतिवादी द्वारा जापान और कोरिया से किया जाता है। भारतीय उत्पाद इन देशों में उत्पादित उत्पाद से भिन्न है।
 - आयातित उत्पादों का विनिर्माण जापानीज औद्योगिक स्टैंडर्ड द्वारा किया जाता है।
 - इसमें बेहतर मेकिंग स्टैंडर्ड, रसायनिक संघटन, श्रेणीकरण, टेन्साइल स्टैन्ज्थ खिंचाव क्षमता और झकने की क्षमता होती है।
 - भारतीय उत्पादों में होल एक्सपैंशन रोल का कहीं उल्लेख नहीं है।
 - एक ही ग्रेड की स्टील में विभिन्न स्टील विनिर्माताओं के क्वालिटी स्तर (फार्मेबिलिटी, रोलिंग के दौरान क्रैक जनरेशन आदि) में अंतर होता है।
 - चूंिक प्रतिवादी आटोमोबाइल का सबसे बड़ा उत्पादक और विनिर्माता है इसलिए आटोमोटिव अनुप्रयोग के लिए गुणवत्ता का स्तर उसके लिए चिंता का मुख्य विषय होता है जिससे कि किसी वाणिज्यिक समस्या या उलझन से बचा जा सके।
 - आयातित उत्पाद का निर्माण पेटेंट अत्याधुनिक तकनीकी से किया जाता है और उसके पृथक गुण होते हैं।
- ठ. याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और उन्होंने घरेलू बाजार के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री का निर्धारण करेन के उद्देश्य से पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं की है। याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी को प्रदान की गई सूचना पर गोपनीयता का दावा करने का कोई कारण प्रदान नहीं किया है। प्रतिवादी ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी पर भरोसा किया है।
- ड. प्राधिकारी ने आयातकों तथा हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रदान कराई गई सूचना की जांच करने और उसकी परिपुष्टि करने के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं कराई। घरेलू उत्पादकों द्वारा दिए गए साक्ष्य की परिपुष्टि किए बिना ही प्राधिकारी ने उक्त सूचना पर भरोसा कर लिया और 20 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश कर दी।
- ढ. प्राधिकारी ने संस्तुत रक्षोपाय शुल्क के स्तर का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई क्रियापद्धति का प्रकटन नहीं किया है। प्राधिकारी ने गाट 1994 के अनुच्छेद-XIX में विनिर्धारित सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। जांच शुरूआत

- नोटिस में उस अनपेक्षित विकास के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया था जिसके कारण इस विचाराधीन उत्पादन के आयातों में वृद्धि हुई। याचिकाकर्ता यह दर्शाने के लिए कि वर्तमान मामले में अनपेक्षित विकास मौजूद है कोई तथ्यात्मक या विधिक आधार प्रस्तुत नहीं कर सका।
- ण. याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराए गए आयात आंकड़ों में मामूली सी वृद्धि हुई है। यह दर्शाने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया कि किस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2015 के संपूर्ण वर्ष के लिए आयातों का वार्षिकीकरण किया है। इस विचाराधीन उत्पाद के आयात में क्रमिक वृद्धि हुई है और आयातों में कोई "अतितीव्र" बहुत अधिक अथवा आकस्मिक वृद्धि" नहीं हुई।
- त. इस विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों का इस वस्तु के घरेलू उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 25(क) में यह सिफारिश की है कि घरेलू उत्पादकों का उत्पादन समान स्तर पर बना रहा। प्राधिकारी ने इस तथ्य का कोई साक्ष्यांकन नहीं किया कि ऐसी संवेदनशील पिरिस्थितयां कौन सी हैं जिनकी वजह से यह प्रारंभिक जांच करनी पड़ी। प्राधिकारी ने रक्षोपाय जांच के सिद्धांतों का उल्लंघन करके कार्रवाई की है।
- थ. याचिकाकर्ताओं ने गंभीर क्षति दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में इस तथ्य की अनदेखी की है कि रक्षोपाय नियमावली के अंतर्गत किसी जांच की शुरूआत करना तभी अपेक्षित है जब यह सुझाव देना का "पर्याप्त साक्ष्य" हो कि इस उत्पाद के संवर्धित आयातों ने घरेलू उत्पादकों को क्षति कारित की है।
- द. प्राधिकारी ने रक्षोपाय नियमावली के अनुबंध के पैरा 1 और 2 का उल्लंघन करके कार्य किया है। प्रतिवादी ने यूएस-काटन यार्न पर अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। उपर्युक्त उदधृत मामले के आधार पर निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए गए :
 - याचिका में किसी भी क्षति को नहीं दर्शाया गया है
 - याचिकाकर्ताओं ने उत्पादन घरेलु बिक्रियां और कुल बिक्री तथा लाभप्रदता के रूप में बेहतर प्रदर्शन किया है।
 - इस विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता का कुल क्षमता से पृथक्करण करने के लिए विहित क्रियापद्धित अभी भी स्पष्ट नहीं है।
 - एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड ने कम्पलीट टर्न अराउंड किया है और अपने प्रचालनों से लाभार्जन किया है।

विवरण	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	
	2014-2015	2013-2014	
	(करोड़ रुपए)	(करोड़ रुपए)	
सकल राजस्व	19,258.50	16,286.59	
निवल राजस्व	17,162.39	14,348.55	
आपवादिक मदों और कराधान से पूर्व लाभ/(हानि)	334.29	(3,916.21)	
कराधान पूर्व लाभ/(हानि)	1,008.96	(2,314.74)	
प्रतिशेयर अर्जन (तनुकृत)	2.26 रुपए	(5.70) रुपए	

न. जेएसडब्ल्यू की लाभप्रदता बढ़ी है

विवरण	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	वृद्धि %
	2014-2015	2013-2014	
	(करोड़ रुपए)	(करोड़ रुपए)	
सकल टर्नओवर	49,658	48,527	2%
निवल टर्नओवर	45,352	44,529	2%
प्रचालनरत ईबीआईडीटीए	8,872	8,783	1%
पीएटी	2,166	1,335	62%
प्रतिशेयर अर्जन (तनुकृत)	88.24 रुपए	53.86 रुपए	64%

- सेल को लगातार लाभ होता रहा।
- कीमत अधोविक्रयण, अवमंदन एवं निग्रहण आंकड़ों का याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका के एनसीवी में विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है।
- प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 25(घ) के अनुसार घरेलू उत्पादकों के क्षमता उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं आया है।
- प्राधिकारी ने भी अपनी प्रारंभिक जांच परिणाम में घरेलू उत्पादकों के क्षमता उपयोग में गिरावट की संभावना का कोई उल्लेख नहीं किया है।
- प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान कराई गई सूचना के किसी भी भाग की परिपुष्टि नहीं की है और बिना कोई कारण बताए यह मान लिया कि यह एक मामला है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी।
- इस रक्षोपाय शुल्क का वाहनों तथा आटोमोबाइल उद्योग के अनुषंगी सामान पर क्रमिक प्रभाव पड़ेगा।
- ध. कई आटोमोबाइल कंपनियां और ओईएम इस संबद्ध वस्तु के बड़े आयातक हैं और रक्षोपाय शुल्क की वसूली का उक्त आयातकों के व्यवसाय हितों पर भारी प्रभाव पड़ेगा। रक्षोपाय शुल्क भारत सरकार द्वारा रूग्ण आटोमोबाइल उद्योग का जीर्णोद्वार करने के लिए शुरू किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों से असंगत होगा।

XXVII. ट्यूब इन्वेस्टमेंट आफ इंडिया लिमिटेड (टीआईआई)

- क. आटोमोटिव अनुप्रयोगों में प्रयोग किए गए कुछ ग्रेडों का आयात ग्राहक अनुमोदित स्रोत, ग्राहक की पसंद, संगत क्वालिटी, सीमित उपलब्धता आदि के कारण किया जाता है। निम्नलिखित ग्रेडों को छुट दी जानी चाहिए।
 - (i) एएसएई 1541
 - (ii) एसएई 1020/1040/1045/1050/1055
 - (iii) एससीएम 35
 - (iv) बोरोन स्टील
 - (v) 16 एमएनसीआर 5
 - (vi) एसएई 1006/1010
 - (vii) एसटी 52.3
- ख. सस्ते आयातों को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम कीमत तंत्र को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
- ग. सीआर/सीआरसीए को भी रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव के लिए एचआर के साथ शामिल किया जाना चाहिए।
- घ. अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का क्रियान्वयन करने की तारीख पर पहले से संविदाकृत संबद्ध वस्तु की मात्रा का अपवजन कर देना चाहिए।

XXVIII. बाम्बे आयरन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (बीमा) जिसका प्रतिनिधित्व एमवी किनी लॉ फर्म द्वारा किया गया।

- क. प्रत्येक उत्पाद के संबंध में किए गए आयातों को किसी कथित प्रोत्कर्ष की संपुष्टि करनी होगी। पृथक प्रकृति एवं सांख्यिकी के उत्पादों को समान विश्लेषण के अध्यधीन रखा गया है। आवेदकों द्वारा जोड़ दिए गए उत्पादों का पृथक्करण अधिदेशित है क्योंकि आवेदकों की अलाय स्टील का उत्पादन करने की क्षमता नगण्य है।
- ख. आवेदकों द्वारा जिस समस्या का सामना किया जा रहा है वह संवर्धित आयातों के कारण नहीं है बल्कि उच्च ऋण, भूषण स्टील के संबंध में दमन और कुप्रबंधन के कारण और एस्सर स्टील के मामले में कच्चे माल का अधिप्रापण करने की समस्या के कारण है।
- ग. आवेदकों ने घरेलू कीमतें बहुत अधिक रखी और वैश्विक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर निर्यात बढ़ाया। आवेदकों ने अपनी निर्यात कीमत लगभग 35 प्रतिशत तक घटा दी जबिक घरेलू कीमतों में केवल 4 प्रतिशत की कमी हुई।

- घ. वर्ष 2014-15 में आयातों में प्रोत्कर्ष पोस्को द्वारा महाराष्ट्र में वर्ष 2014 में स्थापित अपने संयंत्र के संबंध में थी (लगभग 1 मिलियन टन)। यदि पोस्को के इस आयात को अलग कर दिया जाता है तो यह आयातों में कमी तक प्रदर्शित करेगा।
- ङ. ज्यादातर आवेदकों ने अपने बिक्री कारोबार में वृद्धि प्रदर्शित की है। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के बिक्री आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेल के बिक्री आंकड़े भी सिंथर प्रवृत्ति दर्शाते हैं।
- च. वित्तीय विवरण दर्शाते हैं कि पारिश्रमिक एवं वेतन में कथित गिरावट के बजाय आवेदकों की रोजगार लागत में कोई संगत वृद्धि नहीं हुई है।
- छ. अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयात जिनका प्रयोग निर्यातों के लिए परिष्कृत वस्तु का विनिर्माण करेन के लिए किया जाता है, उन्हें आयात आंकड़ों से अलग कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे घरेलू बाजार के अंतर्गत नहीं आते हैं और उनका भार की घरेलू बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- ज. आवेदकों ने आईबीआईएस के जिन आंकड़ों की जेपीसी आंकड़ों से तुलना करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए हैं।
- झ. प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में 40-60 प्रतिशत की गिरावट आई है और संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत को तदनुसार ही समायोजित किया जाना चाहिए।
- ञ. थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों द्वारा अपनाए गए व्यापार साधनों से तुलना करना असंधारणीय एवं भ्रामक होगी क्योंकि इन देशों में आयातों में प्रोत्कर्ष और अन्य पैरामीटरों बड़े संवेदनशील थे।
- ट. आवेदक स्वयं ही सस्ते कच्चे माल और इस पीयूसी का आयात कर रहे हैं। जुलाई-सितम्बर, 2015 में आयातों में कथित प्रोत्कर्ष आवेदकों द्वारा खासकर जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा संबद्ध पीयूसी का भारी आयात किए जाने के कारण हुआ है।
- ठ. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण, पणधारियों के प्रतिनिधिक समृहों से परामर्श किए बिना, अनुचित जल्दी में किया गया है।

XXIX. फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ महाराष्ट्र (एफएएम)

एफएएम द्वारा सुनवाई पूर्व किए गए अपने प्रस्तुतिकरणों के अलावा, एफएएम ने निम्नलिखित तर्कों पर जोर दिया है :

- क. स्टील सेक्टर को ऐसे कारकों से भारी क्षति एवं ऋण ग्रस्तता का सामना करना पड़ रहा है जिनके लिए भारत में स्टील की आयात कीमतों पर उपरोपित नहीं किया जा सकता है।
- ख. अग्रिम प्राधिकृतीकरण के अंतर्गत आयातित मात्रा से आवेदकों को क्षति नहीं हो सकती है।
- ग. इस मामले में अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने में अनावश्यक जल्दी की गई।
- घ. यह पीयूसी आवेदकों की केवल 9 प्रतिशत क्षमता के लिए ही उत्तरदायी है।
- ङ. भारत में आंकड़ों का संग्रहण करने और उनका अनुरक्षण करने के लिए जेपीसी इस्पात मंत्रालय द्वारा भरोसा किए गए आईबीआईएस आंकड़ों तथा जेपीसी आंकड़ों के बीच भारी विसामान्यता है।
- च. ऐसा अभिकथन किया गया है कि आयातों में प्रोत्कर्ष हुआ, बिक्री कारोबार में भारी गिरावट आई, क्षमता उपयोग में कमी हुई, निरंतर घाटा हुआ और रोजगार के स्तर में कमी आई। यह सब क्षति के स्पष्ट संकेतक हैं। इस मामले में यह सभी आधारभूत पैरामीटर मौज़द नहीं हैं।

आयातों में अभिकथित प्रोत्कर्ष ('000 टन)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
जेपीसी के अनुसार आयात	1812	1871	1104	2006
अनुक्रमित	100	103	60	109

जेपीसी आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों (जो प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए अधिक तर्कसंगत अविध है) की अविध के दौरान आयातों में केवल 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में आयातों के प्रोत्कर्ष का अभिकथन करते समय इस तथ्य पर विधिवत विचार नहीं किया गया इससे पिछले वर्ष असामान्य कारणों से लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट आई जो इस अविध के दौरान डालर अभूतपूर्व अस्थिरता के कारण आई है।

इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने डालर की इस अस्थिरता का एवं संवर्धित आयतों का लाभ उठाया और उन्होंने घरेलू कीमतों को भारतीय उपभोक्ताओं की कीमत पर काफी अधिक रखा।

- छ. वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में आयातों में भारी प्रोत्कर्ष का अभिकथन करते समय इस तथ्य पर विधिवत विचार नहीं किया गया इससे पिछले वर्ष असामान्य कारणों से लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट आई जो इस अविध के दौरान डालर अभूतपूर्व अस्थिरता के कारण आई है। दिलचस्प बात यह है कि आवेदकों ने डालर के इस उतार चढ़ाव का फायदा उठाया और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपने निर्यात में वृद्धि की जबिक उन्होंने भारतीय उपभोक्ताओं और भारत में अवसंरचना विकास की कीमत पर अपनी घरेलू कीमतें बहुत अधिक रखीं ओर दूसरी ओर उन्होंने अपने लिए असामान्य लाभ अर्जित किया। यह सब जेपीसी के आंकड़ों से स्पष्ट है।
- ज. यह संबद्ध वस्तु जिसका प्रयोग कुछ रि-रोलर मिलों जैसे पोस्को, उत्तम स्टील, नेशनल स्टील्स, एशिययन कलर कोटेड आदि, द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह नोट किए जाने की जरूरत है कि यह विचाराधीन उत्पाद एक कच्च माल है न कि व्यापार के लिए उत्पादित उत्पाद। ऐसे मामलों में इस पीयूसी पर अन्य कार्रवाई की जाती है और इसे कोल्ड रोल्ड शीट्स/कलईदार शीट्स/ कोरूगेटेड शीट्स आदि में संपरिवर्तित किया जाता है। अकेले पोस्कों ने ही महाराष्ट्र स्थित अपने निजी स्टील संयंत्र के लिए मई, 2014 से सितम्बर, 2015 के बीच इस प्रयोजन के लिए इस संबद्ध वस्तु का लगभग 0.95 मिलियन टन का आयात किया था।
- झ. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि इन आयातों तथा अन्य कोल्ड रोलर मिलों द्वारा किए गए आयातों का आवेदकों द्वारा यथाप्रस्तुत आयात के कुल आंकड़ों से अपवर्जन कर दिया जाता है तो यह प्रदर्शित होगा कि इस अविध के दौरान भारत में इस संबद्ध वस्तु के आयातों में तो वास्तव में कमी आई है। वास्तव, स्थानीय संयंत्रों ने यह संबंध वस्तु प्रदान करने के लिए पोस्कों पर निर्भरता प्रदर्शित की क्योंकि वे इस संबद्ध वस्तु का अपेक्षित क्लालिटी और मात्रा में उत्पादन करने में अक्षम थे। इस कच्चे माल के आयात की भारत में इस पीयूसी के कुल आयातों में से हिस्सा लगभग 35-40 प्रतिशत होगा।
- ञ. आदवेदकों ने यह तर्क दिया है कि थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों ने भी क्रमश: रक्षोपाय और पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करके इस प्रशुल्क अवरोधों का आश्रय लिया है। तथापि, एतद्वारा यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि आयातों में प्रोत्कर्ष तथा अन्य पैरामीटरों का परिदृश्य इन देशों में उस समय अत्यधिक नाजुक रहा था। यह परिस्थिति किसी भी रूप में भारत की वर्तमान स्थिति से तलनीय नहीं है।
- ट. रक्षोपाय नियम के अंतर्गत यथाप्रस्तावित पूर्वापेक्षा भी मौजूदा नहीं है और इस कारण घरेलू उद्योग का भारी समग्र अवक्षयण, खासकर इस संबद्ध उत्पाद के आयातों में वृद्धि की दर एवं मात्रा में समग्र एवं संगत रूप से नहीं हुआ जैसे संवर्धित आयातों द्वारा घरेलू बाजार के हिस्से पर किया गया कब्जा, बिक्रियों के स्तर में परिवर्तन, उत्पादक, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ एवं हानि तथा रोजगार, इसमें से किसी पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा जैसाकि आवेदकों द्वारा गलत बयानी की गई है।
- ठ. आवेदकों ने ग्राही खपत के लिए किए गए आयातों का अपजर्वन नहीं किया है जिनका कुल आयातों की संगणना करते समय अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए था। आवेदकों ने अग्रिम प्राधिकृतीकरण के अंतर्गत किए गए आयातों अर्थात निर्यात के लिए किए गए आयातों का अपवर्जन नहीं किया जिन्हों कुल आयातों की संगणना करते वक्त अपवर्जितकर दिया जाना चाहिए था। किसी भी आकस्मिकता के अभाव में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने और इस अधिरोपण से अपेक्षित प्रयोजन पूरा करने का कोई संबंध नहीं है।

घ. प्रत्युत्तर प्रस्तुतिकरण

1. सार्वजिनक सुनवाई के पश्चात हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का घरेलू उद्योग द्वारा प्रत्युत्तर याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी याचिका, अपने लिखित प्रस्तुतिकरणों द्वारा और जांच की कार्रवाई के दौरान उठाए गए सभी तर्क हितबद्ध द्वारा अपने लिखित प्रस्तुतिकरणों में दिए गए सभी तर्कों का खंड करते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी याचिका, अपने लिखित प्रस्तुतिकरणों द्वारा और जांच की कार्रवाई के दौरान उठाए गए सभी तर्क इस प्रत्युक्ति का अभिन्न अंग माने जाएं और ऐसे तर्क जिनकों वर्तमान प्रस्तुतिकरणों में संक्षिप्तता के कारण दोहराया नहीं गया है, उनके लिए यह नहीं मानना चाहिए कि वह याचिकाकर्ताओं के साथ पूर्वाग्रह है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए अन्य सभी मुद्दों के लिए याचिकाकर्ताओं ने अपने निम्नलिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए हैं -

क. विकासशील देशों से वे आयात जो 3 प्रतिशत से कम हैं रक्षोपाय शुल्क के अध्यधीन नहीं होना चाहिए।

कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि उन विकासशील देशों को इस रक्षोपाय शुल्क के परिक्षेत्र से बाहर रखा जाए जिनके अपने अपने अपने आयात 3 प्रतिशत से अधिक ओर इन देशों के कुल मिलाकर आयात 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि ब्राजील एवं ताईवान उक्त अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, याचिकाकर्ताओं ने इस तर्क का ताईवान के राजूदतावास को दिए अपने विशिष्ट प्रत्युत्तर में समाधान पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। तथापि, याचिकाकर्ता अपना तर्क यहां संक्षेप में फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि भारत ने अधिसूचना संख्या 103/98 सीयूएस के तहत दिनांक 14 दिसम्बर, 1998 की अपनी विकासशील देशों की सूची जारी की है। यह नोट करना संगत होगा कि इस सूची में ताइवान का नाम नहीं है। इसलिए, तर्क को ध्यान में रखते हुए यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाता है कि ताईवान से आयात 3 प्रतिशत से कम हैं और विकासशील देशों से आयात का औसत 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है फिर भी ताइवान को रक्षोपाय शुल्क के परिक्षेत्र से अपवर्जित नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत सरकार ने उसे आज तक विकासशील देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। इसलिए ताइवान को रक्षोपाय शुल्क के दायरे से बाहर रखने के लिए दिया गया तर्क भारत सरकार द्वारा 14 दिसम्बर, 2014 को जारी अधिसूचना संख्या 103/98-सीयूएस के आलोक में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलए इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि ब्राजील को रक्षोपाय शुल्क के अध्यधीन नहीं रखा जाना चाहिए।

ख. गाट के अनुच्छेद XIX और रक्षोपाय करार ("एसए") के आशय के अंतर्गत आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई।

कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि इस संबद्ध वस्तु के आयात गाट के अनुच्छेद XIX और रक्षोपाय करार के आशय के अंतर्गत पर्याप्त अचानक पर्याप्त तीव्र, पर्याप्त महत्वपूर्ण और पर्याप्त अभिनव नहीं है। इसलिए इस मामले में रक्षोपाय शुल्क अधिपत्रित नहीं है। याचिकाकर्ता इस तर्क का पूर्णतया विरोध करते हैं। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान इस संबद्ध वस्तु के आयातों में तीव्रता से वृद्धि हुई है। वास्तव में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2013-14 में आयात केवल 7 प्रतिशत हुआ करते थे जो वर्ष 2014-15 में दोगुने होकर 14 प्रतिशत हो गए। यह स्थिति वर्ष 2015-16 में ओर भी अधिक गंभीर हो गई जब वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में आयात 19 प्रतिशत हो गए। वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही के दौरान इन आयातों में और वृद्धि हुई तथा घरेलू उद्योग के उत्पादन में यह 31 प्रतिशत हो गए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 में यह आयात मांग का 9 प्रतिशत (ग्राही को छोड़कर) थे जो बढ़कर वर्ष 2014-15 में 16 प्रतिशत हो गए। इनमें 2015-16 में और भी अधिक वृद्धि हुई तथा 2015-16 की पहली तिमाही में यह आयात मांग का 19 प्रतिशत (ग्राही को छोड़कर) हो गए जिनमें तीव्रता में वृद्धि हुई और बढ़कर 2015-16 की इसी तिमाही में 24 प्रतिशत हो गए। यदि इन्हें आयातों में अचानक, तीव्र, अत्यधिक अभिनव वृद्धि नहीं कहा जा सकता है तो याचिकाकर्ता इस बात से अनभिज्ञ है कि आयातों में अचानक प्रोत्कर्ष किसे कहा जाएगा। घरेल उद्योग आपातस्थिति का सामना कर रहा है। वर्ष 2015-16 की पहली दो तिमाहियों में इस संबद्ध वस्तु के आयात पहले ही चरम पर पहुंच गए और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2015-16 के दौरान आयात वर्ष 2014-15 के आयातों की सीमा को पार कर जाएंगे। वर्ष 2015-16 की पहली दो तिमाहियों के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ऐसी उम्मीद की जाती है कि इस संबद्ध वस्त के आयात वार्षिकीकत आधार पर 4167884 एमटी हो जाएंगे जो वर्ष 2014-15 के स्तर से 160 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है क्योंकि वर्ष 2014-15 में आयात 2540114 एमटी थे। यह आयात अत्यधिक कम कीमतों पर हो रहे हैं और कीमत अधोरदन, कीमत अधोविक्रयण, कीमत निग्रहण और कीमत अवमंदन कारित कर रहे हैं। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण ही घरेलु उद्योग को इस स्थिति से उबार सकता है।

ग. आयात आंकड़ों का स्रोत, आयात सांख्यिकी का वर्गीकरण करने में अपनाई गई क्रियापद्धति और सूचना की यथार्थता

कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि आईबीआईएस जैसी गैर-सरकारी एजेंसी के आयात आंकड़े प्रामाणिक और समर्थनीय नहीं हैं ओर प्राधिकारी को केवल जेपीसी आंकड़ों पर विचार करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकार यह तर्क भी देते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धित का विस्तृत उल्लेख इस में नहीं किया गया है। हितबद्ध पक्षकार यह तर्क भी देते हैं कि याचिका में प्रयोग किए गए आईबीआईएस आंकड़ों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने के लिए डीजीपीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क भी दिया है कि कुछ आयात इस उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। याचिकाकर्ता इन सभी तर्कों का विरोध करते हैं। यह निवेदन किया जाता है कि आईबीआईएस एक प्रख्यात एजेंसी है और इसके आंकड़ों का प्रयोग नियमित रूप से कई व्यापार उपचारी जांचों में किया जाता है फिर चाहे वह रक्षोपाय जांच हो या पाटनरोधी जांच। पुनश्च, प्राधिकारी की यह मानक प्रक्रिया है कि वह डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े प्राप्त करें और सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करने के लिए उन आंकड़ों की तुलना आईबीआईएस से प्राप्त आंकड़ों से करें। प्राधिकारी को यह विवेकाधिकार है कि वह आईबीआईएस के आंकड़े प्रयोग करें या डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े। पुनश्च, याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि इस जांच में जेपीसी आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंक यह आंकड़े केवल स्टील सेक्टर के लिए व्यापक स्तर पर उपलब्ध होते हैं न कि इस पीयूसी के स्तर पर जो इस जांच के प्रयोजनार्थ संगत है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकार यह स्पष्ट करने में असफल रहे कि किस तरह के आयात इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर आते हैं। इस तरह का दावा अत्यधिक अस्पष्ट है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता

है। हितबद्ध पक्षकारों को उन आयातों के ग्रेड अथवा विनिर्देशन तो उपलब्ध कराने चाहिए थे जिनका वे उल्लेख कर रहे हैं। ऐसी किसी सुचना के अभाव में हितबद्ध पक्षकारों के इन अस्पष्ट दावों को अस्वीकार किया जाता है।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया

कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह शिकायत की है कि याचिका में कई पैरामीटरों को गोपनीय के रूप में माना गया है और घरेलू उद्योग ने उनके गोपनीय के रूप में मानने का कोई तर्क नहीं दिया है। हितबद्ध पक्षकार पुन: यह तर्क देते हैं कि यहां तक कि प्राधिकारी ने भी उन्हें गोपनीयता प्रदान करने का अपने प्रारंभिक जांच परिणाम में कोई कारण नहीं दिया है। याचिकाकर्ता उक्त तर्क का सख्ती से विरोध करते हैं। याचिकाकर्ता यह निवेदन करते हैं कि उन्होंने याचिका में गोपनीयता का दावा करते समय पूरी सावधानी बरती है और केवल ऐसी सूचना को ही गोपनीय के रूप में माना है जिसका प्रकटन करने से याचिकाकर्ताओं को हित पर विपरीत प्रभाव पड़ता। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने गोपनीयता का दावा करने के लिए अपनी याचिका में कारणों का विधिवत उल्लेख किया है। हितबद्ध पक्षकार यह गलत तर्क देते हैं कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की गोपनीयता के दावे को स्वीकार करते समय अपने प्रारंभिक जांच परिणाम में कोई काण प्रदान नहीं किया है। इस संबंध में याचिकाकर्ता प्रारंभिक जांच परिणाम के निम्नलिखित उदधारण का उल्लेख करते हैं:

11. घरेलू उद्योग ने कुछ सूचना गोपनीय आधार पर प्रदान की है और प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों की गोपनीयता की मांग की है। घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय साधन के लिए रक्षोपाय नियमावली 1997 और 06.09.1997 के व्यापार नोटिस सं.एसजी/टीएन/1/97 के प्रावधानों के अनुरूप अपने आवेदन पत्र का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है। **इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने आवेदनपत्र दायर करते समय** गोपनीयता की मांग करने के लिए कारण भी प्रस्तुत किए हैं।

12. रक्षोपाय नियमावली, 1997 के नियम 7 ओर डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.2 में भी गोपनीयता के लिए प्रावधान है। आवेदकों को ऐसी सूचना का प्रकटन करना अपेक्षित नहीं है जो कंपनी के लिए गोपनीय सूचना है और जिसका प्रकटन करना कंपनी के व्यवसाय हितों को ऐसे गंभीर पूर्वाग्रह कारित कर सकते हैं, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और जिनका आवेदक ने विगत में सार्वजनिक खुलासा कभी भी नहीं किया है। तदनुसार घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन के अनुसार उद्योग को गोपनीयता प्रदान कर दी गई। (जो दिया गया)

प्राधिकारी ने स्पष्टत: यह प्रेक्षा की कि याचिकाकर्ताओं से ऐसी सूचना का प्रकटन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो घरेलू उद्योग के व्यवसाय हितों को गंभीर क्षिति कारित कर सकते हों। इस संबंध में प्राधिकारी ने रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.2 के साथ पठित रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 7 का अनुपालन विधिक अपेक्षाओं को पूरा करना प्रदर्शित करने के लिए किया है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं को गोपनीयता दावे को स्वीकार कर लिया। इसलिए, हितबद्ध पक्षकार यह तर्क देने में गलती कर रहे हैं कि प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के गोपनीयता के दावसे को मंजूर करते समय कोई कारण प्रदान नहीं किया है।

ड. याचिका में त्रुटियां

कई हितबद्ध पक्षकार यह तर्क देते हैं कि घरेलू उद्योग के संघटकों ने अतिरिक्त प्रश्नावली दायर नहीं की है। इसलिए, प्राधिकारी के पास, प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करते समय संपूर्ण सूचना नहीं थी। हितबद्ध पक्षकार पुन: यह तर्क देते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा कोई विश्वसनीय समायोजना भी प्रदान नहीं कराई गई है और उसका प्रारंभिक जांच परिणाम में कोई उल्लेख नहीं है। याचिकाकर्ता उक्त तर्क का कड़ा विरोध करते हैं। यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने-अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर अपनी याचिका के साथ गोपनीय और अगोपनीय दोनों पाठों में प्रस्तुत किए हैं। प्रश्नावली प्रत्युत्तर का अगोपनीयय पाठ सार्वजनिक फाइल मे भी उपलब्ध है। यदि हितबद्ध पक्षकार इस सार्वजनिक फाइल से प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो यह उनकी लापरवाही है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के सभी संघटकों ने अपने-अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर के साथ समुचित समायोजन योजना भी प्रदान कराई है। प्राधिकारी ने भी समायोजन योजना की व्यवहार्यता की सत्यापन घरेलू उद्योग के संघटकों के सत्यापन दौरों के दौरान संतुष्टि की है। केवल इस कारण से कि प्रारंभिक जांच परिणाम में समायोजन योजना का कुछ विशेषण नहीं किया गया है, इसका आशय यह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी को यह सूचना प्रदान ही नहीं की है। इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि याचिका में त्रुटियां है सही नहीं है और उसे नामंजुर कर दिया जाना चाहिए।

च. घरेलू उद्योग का आधार

हितबद्ध पक्षकार यह तर्क देते हैं कि इस मामले याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के रूप में क्वालीफाई नहीं करते हैं। हितबद्ध पक्षकार प्रारंभिक जांच परिणाम के पैराग्राफ 25(ख) के अंतर्गत दी गई तालिका यह भरोसा करते है और यह तर्क देते हैं कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्ष 2013-14 में 45 प्रतिशत था और अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा 51 प्रतिशत था। इसी तरह यह तर्क दिया जाता है कि 2014-15 और 2015-16 (वार्षिकीकृत) में अन्य उत्पादकों का बाजार हिस्सा 51 प्रतिशत था। याचिकाकर्ता इसका कड़ा विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क उठाकर जो गलती की है उससे बड़ी कोई अन्य गलती नहीं हो सकती है। पैरा 25(ख) के नीचे दी गई तालिका में दिया गया बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग की बिक्रियों तथा घरेलू मांग का अनुपात है। तथापि, यह बाजार हिस्सा आधार पर मापन नहीं है। आधार का निर्धारण सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप किया जाता है, जिसमें घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है:

"घरेलू उद्योग" का आशय

- (i) भारत में समान वस्तु अथवा प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु के समग्र रूप से उत्पादनकर्ताओं; अथवा
- (ii) उन उत्पादकर्ताओं से है जिनका समान वस्तु या भारत में प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु का कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार याचिकाकर्ताओं का उत्पादन वर्ष 2013-14 के दौरान कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत, 2014-15 में कुल उत्पादन का 68 प्रतिशत और 2015-16 की प्रथम तिमाही में कुल उत्पादन का 67 प्रतिशत था। अत: याचिकाकर्ता स्पष्टत: घरेलू उद्योग के रूप में क्वालीफाई करते हैं। इसलिए घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों का तर्क अनुचित है ओर इसे सीधे ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।

छ. घरेलू उद्योग का आयात

हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही के दौरान आयातों में प्रोत्कर्ष घरेलू उद्योग के कारण, खासकर जेएसडब्ल्यू स्टील के कारण आया जिसने इस अवधि के दौरान भारी मात्रा में इस संबद्ध वस्तु का आयात किया है। याचिकाकर्ता इस तर्क का कड़ा विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार निराधार तर्क दे रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी को अपने आंकड़े प्रदान कर दिए जिनका विधिवत सत्यापन भी किया गया। इस क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आयात अल्प मात्रा में थे, यह तथ्य भी उनके आंकड़ों द्वारा समर्थित है। लघु मात्रा में किए गए यह आयात आंतरिक खपत के लिए थे, न कि खुली बाजार में बिक्री करने के लिए। अत:, हितबद्ध पक्षकारों का उपर्युक्त तथ्य गलत है और उसे नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।

ज. विचाराधीन उत्पाद का दायरा

कई हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्रश्न उठाया है। इन सभी मुद्दों का समाधान अधोलिखित है :

- (i) 2.00 एमएम और उससे कम की मोटाई के एचआर काइल्स : मैसर्स निजोन सिस्ट्रप्स लिमिटेड और मैसर्स निजोम ट्यूब लिमिटेड ने तर्क दिया है कि वे 2.00 एमएम तथा उससे कम की मोटाई के एचआर काइल्स का निरंतर आयात कर रहे हैं क्योंकि उनके नियमित प्रदायक मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड ने अवरोध उत्पन्न हो जाने के कारण अपनी आपूर्ति बंद कर दी है। इसलिए, उन्हें मजबूत इस विशिष्ट उत्पाद का आयात करना पड़ता है और इन उत्पादों को विचाराधीन के दायरे से अलग रखना चाहिए। याचिकाकर्ता इस तर्क का कड़ाई से विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि कंपनियां भारत में किसी अन्य ऐसे उत्पादक से संपर्क कर सकती थी जो उनको इतने पतले गाज की उक्त सामग्री की आसानी से आपूर्ति करने में सक्षम हो। केवल इस कारण से कि एक भारतीय विनिर्माता ने इन कंपनियों को प्रदाय करना बंद कर दिया है, इन उत्पादों से अपवर्जन करने का आधार नहीं हो सकता है। इन दोनों कंपनियों की जरूरत को याचिकाकर्ताओं सहित भारत में अन्य स्टील विनिर्माताओं द्वारा आसानी से पूरा किया जा सकता है। इसलिए, इस विशिष्ट उत्पाद को इस उत्पाद के दायरे से अलग नहीं किया जा सकता है।
- (ii) एचआर काइल्स का आटोमोटिव ग्रेड: मैसर्स हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड यह तर्क देता है कि कोरियाई आटोमोटिव ग्रेड की स्टील को रक्षोपाय शुल्क से छूट प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किए जाने के पश्चात भी उन्हें इस उत्पाद का अनिवार्यत: आयात करना पड़ेगा। पुन:, उन्होंने यह तर्क दिया कि उनका नानयांग आर एंड डी केंद्र भारत में कार बनाने के लिए विनिर्देशनों में परिवर्तन करने की उन्हें अनुमित नहीं देता है। इसलिए, उन्हें इस ग्रेड का आयात करना ही पड़ेगा। याचिकाकर्ता इस तर्क का विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं मैसर्स हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड उस ग्रेड की पहचान करने में असफल रहे हैं जिसका वह आयात करते हैं। एचआर काइल्स का आटोमोटिव ग्रेड एक बहुत ही अविशिष्ट विवरण है और उन्हें तब तक अपवर्जित नहीं किया जा सकता है जब तक वह यह प्रमाण नहीं देते हैं कि भारत के स्टील उत्पादक इस ग्रेड का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। केवल इस कारण से कि उनका आरएंडडी केंद्र कहीं अन्य से प्रापण करने की अनुमित नहीं देगा, इसका आशय यह नहीं है कि इस ग्रेड के आयातों को रक्षोपाय शुल्क से छूट देकर घरेलू उद्योग को कष्ट सहन करने दिया जाए। यह अनुरोध किया गया कि मैसर्स हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड को यह निदेश दिया जा सकता है कि वह ग्रेड का विशिष्टीकरण करे और अपने रासायनिक एवं भौतिक पैरामीटर्स भी बताएं जिसके लिए वे घरेलू उद्योग के साथ परस्पर चर्चा के अध्यधीन छूट का दावा करने रासायनिक एवं भौतिक पैरामीटर्स भी बताएं जिसके लिए वे घरेलू उद्योग के साथ परस्पर चर्चा के अध्यधीन छूट का दावा करने

की वांछा करते हैं। यदि यह सूचना प्रदान नहीं की जाती है तो उनका दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता पुन: यह प्रस्तुत करते हैं कि वे कई आटोमोबाइल निर्माताओं उनके वेंडर्स और आटो संघटक विनिर्माताओं की वेंडर लिस्ट में हैं। इन आटोमोबाइल विनिर्माताओं, उनके वेंडरों और आटो संघटक विनिर्माताओं, जिनको याचिकाकर्ता इस संबद्ध वस्तु का प्रदाय करता है के नाम प्राधिकारी को प्रदान करा दिए गए हैं।

- (iii) टीआईआई का दावा: टीआईआई का तर्क है कि निम्नलिखित ग्रेडों उत्पाद दायरे से उनकी सीमित उपलब्धता, गुणवत्ता मुद्दे के कारण हटा देना चाहिए ओर क्योंकि टीआईआई ने पहले से ही आपूर्ति के स्रोतों की पहचान एवं उनका अनुमोदन कर दिया है जिन्हें वे अब परिवर्तित नहीं कर सकते हैं:
 - क. एएसई 1541
 - ख. एसएई 1020/1040/1045/1050/1055
 - ग. एससीएम 435
 - घ. बोरोन स्टील
 - ङ. 16 एमएन सीआर 5
 - च. एसएई 1006/1010
 - छ. एसटी 52.3

टीआईआई का यह दावा निराधार है उपलब्धता और क्वालिटी मुद्दे का प्रमाण देने में असफल रहे है जिनका वे घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उनके सामने आने वाली सदस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यदि टीआईआई ने अपने प्रदाय स्रोत का अनुमोदन कर दिया है तब भी वे समान ग्रेड का प्रदाय करने के लिए किसी घरेलू विनिर्माता का अनुमोदन कर सकते हैं। यह निवेदन किया जाता है कि घरेलू उद्योग 4 के पास ऊपर सूचीबद्ध सभी ग्रेडों का विनिर्माण करने की सिद्ध क्षमता है और उसने आवश्यक गुणवत्ता मानक भी प्राप्त कर लिए है। घरेलू उद्योग टीआईआई की जरूरत के मुताबिक विनिर्माण करने और आपूर्ति करने में सक्षम है। इसलिए, इन ग्रेडों को इस उत्पाद के दायरे से अलग नहीं किया जा सकता है।

- (iv) पिकलिंग एवं आयिलंग ("पीओ") युक्त हाट रोल्ड काइल: मैसर्स हुंडई स्टील कोरिया का यह तर्क है कि उनके द्वारा विनिर्मित पीओ उत्पादों की बिक्री मैसर्स हुंडई स्टील इंडिया लिमिटेड को की जाती है जो बदले में इसकी बिक्री मैसर्स हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को करती है। उनका तर्क है कि यह आयात अनिवार्य हैं क्योंकि इनको बंद कर देने का आशय होगा। आटोमोबाइल्स में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना। उनका तर्क है कि पीओ उत्पादों को इस उत्पाद के दायरे से अलग रखा जाए। याचिकाकर्ता इस तर्क का कड़ाई से विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने उच्चतर स्ट्रेंथ स्तर के लिए उपयुक्त इस्पात सहित आटो ग्रेड की स्टील का विनिर्माण करने की सिद्धहस्त क्षमता प्राप्त कर ली है। घरेलू उद्योग विभिन्न श्रेणी के इस्पात का विनिर्माण कर सकता है जिसमें मैसर्स हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड सहित आटो कंपनियों द्वारा अपेक्षित पिक्ल और आयल्ड स्टील को उत्पादन करना भी शामिल है। संपूर्ण घरेलू उद्योग के पास पिकलिंग एवं आयालिंग प्रक्रिया के लिए अपेक्षित सुविधा है और घरेलू उद्योग इन उत्पादों का नियमित विनिर्माण कर रहा है। इसलिए इन उत्पादों को उत्पाद के दायरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि वे कई आटोमोबाइल निर्माताओं उनके वेंडर्स और आटो संघटक विनिर्माताओं की वेंडर लिस्ट में हैं। इन आटोमोबाइल विनिर्माताओं, उनके वेंडरों और आटो संघटक विनिर्माताओं, जिनको याचिकाकर्ता इस संबद्ध वस्तु का प्रदाय करता है के नाम प्राधिकारी को प्रदान करा दिए गए हैं।
- (v) संकुचित रूप से परिभाषित ग्राहक विनिर्देशनों के आधार पर हाट रोल्ड काइल्स : मैसर्स निप्पन स्टील एंड समुकिन पाइप इंडिया कंपनी लिमिटैड का तर्क है कि संकुचित रूप से परिभाषित ग्राहक विनिर्देशनों के आधार पर हाट रोल्ड काइल्स को इस उत्पाद के दायरे से अलग कर देना चाहिए क्योंकि यह आयात तनन स्ट्रेंथ इस्पात की सफाई, ग्रेन आकार और रासायनिक संघटन में अलग होती है। मैसर्स निप्पन स्टील और सुमिकिन पाइप इंडिया कंपनी लिमिटेड ने उस आयात के विवरण और उत्पाद प्रकार की गोपनीयता का दावा किया है जिसका वे आयात करते हैं परंतु उन्होंने इस उत्पादों को उत्पाद के दायरे से किसी भी तरह से अलग रखने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता इस तर्क का कड़ा विरोध करते हैं। याचिकाकर्ताओं से उपर्युक्त तर्कों का खंडन करने की प्रत्याशा कैसे की जा सकती है जब मैसर्स निप्पन स्टील एंड सुमिकिन पाइप इंडिया कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्पाद प्रकारों अथवा विशिष्ट ग्रेडों का प्रकटन भी नहीं किया है। इस तरह की सूचना के बिना याचिकाकर्ता उपर्युक्त तर्कों का उचित प्रत्युत्तर देने की स्थिति में नहीं है। प्राधिकारी से मैसर्स निप्पन स्टील एंड सुमिकिन पाइप इंडिया कंपनी लिमिटेड को यह निदेश देने का अनुरोध किया जाता है कि वे रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों मुक्त उन विशिष्ट ग्रेडों का खुलासा करे जिसका यह कंपनी आयात करती है ताकि याचिकाकर्ता उसकी सही से जांच कर सकें और अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सके। यदि मैसर्स निप्पन स्टील एंड सुमिकिन पाइप इंडिया कंपनी लिमिटेड इस मामूली सी सूचना का भी प्रकटन नहीं कर सकती है तो उनके दावे को तत्काल खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ताओं को अपने मामले की प्रभावकारी ढंग से रक्षा करने का अवसर नहीं किया गया।

- **ग्रेड जेएसएच 270/370 और ग्रेड जेएसएच 590 :** मैसर्स मारूति सुजुकी लिमिटेड का तर्क है कि इन दो ग्रेडों को उत्पाद के दायरे (vi) से अलग कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इन ग्रेडों का आयात ग्राहकों की सरक्षा जरूरतों ओर उत्सर्जन मानकों को परा करने के लिए अपेक्षित है। उनका तर्क है कि घरेल विनिर्माता अपेक्षित क्वालिटी मानकों को पूरा नहीं कर सकते हैं और वे कच्चे माल के परस्पर विरोधी आपूर्तिकर्ता हैं। याचिकाकर्ता इस तर्क का बड़ा विरोध करते हैं। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान मैसर्स मारूति सुजुकी लिमिटेड ने यह स्वीकार किया था कि वे अपने प्रापण को स्थानीय रूप से प्राप्त करने का अधिकतम सीमा तक प्रयास कर रहे हैं। तथापि याचिकाकर्ता यह प्रस्तत करते हैं कि इन ग्रेडों का विनिर्माण करने की प्रमाणिक क्षमताओं के बावजद मैसर्स मारूति सुजुकी लिमिटेड ने घरेलु विनिर्माताओं को इन ग्रेडों की आपूर्ति करने का मुश्किल से ही कोई अवसर दिया हो। यह मारूति सुजुकी के इस दावे के विपरीत है कि वे अपना संपूर्ण कच्चा माल स्थानीय रूप से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मैसर्स मारूति सुजुकी लिमिटेड को घरेल विनिर्माताओं को इन ग्रेडों की आपर्ति करने का अवसर देना चाहिए जो उस गणवत्ता को परा कर सकें जिसे मैसर्स मारूति सजकी लिमिटेड चाहता है। पनश्च, याचिकाकर्ता यह प्रस्तत करते हैं कि मैसर्स निप्पन स्टील एंड समिकिन पाइप इंडिया कंपनी लिमिटेड इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाना चाहिए कि यदि मैसर्स मारूति सुजुकी लिमिटेड जेएसएच 270/370 और ग्रेड जेएसएच 590 का आयात अपनी पैरेंट कंपनी मारूति सुज़ुकी जापान से कर रही है तो यह उनके हित में होगा कि वह मारूति सुजुकी जापान से इनका आयात जारी रखे और स्थानीय रूप से इनकी तलाशन करे। इसलिए उनका यह दावा कि वे इनका स्थानीय रूप से प्रापण करने का प्रयास कर रहे हैं प्राधिकारी के समक्ष मिथ्या निरूपण करने के अलावा और कुछ नहीं है। यह माना जाता है कि मैसर्स मारूति सुजुकी लिमिटेड का मैसर्स मारूति सुजुकी, जापान से उपर्युक्त ग्रेडों का प्रापण करने का लंबी अवधि का अधिप्रापण करार है। तथापि. इन तथ्यों का प्राधिकारी के सक्षम प्रकटन नहीं किया। इसके आलोक में. मैसर्स मारूति सजुकी लिमिटेड का यह दावा गलत है कि वे इन ग्रेडों का प्रापण स्थानीय रूप से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं परंतु वे ऐसा करने में असमर्थ हैं क्योंकि घरेलु विनिर्माता उनकी जरूरतों को पुरा करने में सक्षम नहीं है।
- अलाय स्टील : फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ महाराष्ट्र ("एफएएम") का यह तर्क है कि अलाय स्टील का भारत में नगण्य (vii) मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इसलिए अलाय स्टील पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने पुन: यह तर्क दिया कि नॉन-आलय स्टील का आयात कुल घरेलु उत्पाद का केवल 7-8 प्रतिशत है और नॉन-अलाय स्टील की 90 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्से पर घरेलू युनिटों का कब्जा है। एफएएम का यह तर्क भी है कि नॉन-अलाय स्टील के इसने न्यन आयात पर रक्षोपाय शल्क अधिरोपण करना अधिपत्रित नहीं हैं। याचिकाकर्ता इस तर्क का कड़ा विरोध करते हैं। एफएएम जेपीसी आंकड़ों पर भरोसा कर रहा है जो पीयसी स्तर पर नहीं है। इसलिए एफएएम द्वारा अपने विश्लेषण में किया गया पूर्वानुमान गलत है। इसके अतिरिक्त अपने प्रस्तुतिकरण में आगे यह बताया कि यह देखा जा सकता है कि इन आयातों का बाजार हिस्सा घरेलु उत्पादन और मांग में बहुत अधिक है और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त इस उत्पाद में केवल एक प्रशुल्क मद 7225.30.90 को कवर किया जाता है न कि संपूर्ण अलाय स्टील शीर्षक को। इसलिए, एफएएम का यह उल्लेख गलत है कि इस उत्पाद के दायरे में अलाय स्टील की संपुर्ण श्रेणी को शामिल किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अपने दिनांक 8 अगस्त, 2015 के पत्र में इस तथ्य के विस्तृत कारण बता दिए हैं कि सीमा शुल्क वर्गीक्रण 7225.30.90 के अंतर्गत आने वाले अलाय स्टील को इस उत्पाद के दायरे में क्यों शामिल नहीं किया जा सकता है। इस मृद्दे को संक्षेप में फिर से बताने के लिए यह उल्लेख किया जाता है कि जिन आयातों को प्रशुल्क मद 7225.30.90 के अंतर्गत अलाय स्टील के रूप में वर्णित किया गया है, उनमें बोरोन की बहुत कम मात्रा होती है जिसके कारण उन्हें इस प्रशुल्क मद के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। यह आयात अलाय स्टील के रूप में प्रच्छन्न हैं और वे घरेल उद्योग पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं. क्योंकि यह आयात घरेल उद्योग द्वारा उत्पादित हाट रोल्ड स्टील काइल्स के नॉन-अलाय फ्लैट उत्पादों से वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस कारण से याचिकाकर्ताओं ने प्रशुल्क मद 7225.30.90 के अंतर्गत होने वाले आयातों को इस उत्पाद के दायरे में शामिल किया है। उपर्युक्त के आलोक में एफएएम का तर्क सीधे-सीधे नामंजूर कर दिया गया है। चीन आयरन एंड स्टील एसोसिएशन ने भी यह प्रश्न किया है कि सीमाशल्क प्रशल्क शीर्षक 7225 के अंतर्गत अपने वाले अलाय स्टील को भी इस उत्पाद के दायरे में क्यों न शामिल कर दिया जाए। उपर्युक्त विश्लेषण चीन आयरन एंड स्टील एसोसिएशन द्वारा दिए गए तर्क का समाधान भी हो गया है।
- (viii) **हाई स्ट्रेंय स्टील ("एचएसएस"):** चीन इस्पात कारपोरेशन ताइवान का तर्क है कि आटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में प्रयोग किए जाने वाले एचएसएस ग्रेड का इस उत्पाद के दायरे से अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ताओं की हायर स्ट्रेंथ लेवल सहित आटो ग्रेड हाई स्ट्रेंथ स्टील (एचएसएस) का विनिर्माण करने प्रमाणित क्षमता है। इसलिए, एचएसएस ग्रेड को इस उत्पाद के दायरे से अलग नहीं किया जा सकता है।
- (ix) जापान की मिलों द्वारा उत्पादित स्टील: मैसर्स जेईई स्टील कारपोरेशन, मैसर्स निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड, मैसर्स निप्पन स्टील एंड सुमिटोमा मेटल कारपोरेशन और कोबे स्टील लिमिटेड ने मिलकर यह तर्क दिया है कि जापान की मिलों द्वारा उत्पादित इस्पात को इस रक्षोपाय शुल्क के अधीन नहीं रखना चाहिए और उसे इस उत्पाद के दायरे से अलग कर देना चाहिए। याचिकाकर्ता का यह दावा है कि यह तर्क अस्पष्ट हैं और उन्हें स्वीकार करना कठिन है। उन कंपनियों ने अपने उन उत्पादों के ग्रेडों के नाम अथवा विनिर्देशनों का विवरण प्रदान नहीं किया है जिनके लिए वे अपवर्जन चाहते हैं। इस सूचना के बिना ऐसे तर्कों का कोई महत्व नहीं है और उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन कंपनियों का यह तर्क भी है कि घरेलू उद्योग आटोमोटिव ग्रेड स्टील का उत्पादन नहीं कर सकता है। यह तर्क भी गलत है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही साक्ष्य दे रखे हैं कि वे आटोमोटिव ग्रेड की स्टील का उत्पादन भी कर सकते हैं।

- **झ.** संवेदनशील परिस्थितियां जो अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क के उदग्रहण को न्यायोचित ठहराती हैं: कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि मौजूदा मामले में ऐसी कोई संवेदनशील परिस्थितियां नहीं थी जिनके कारण अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क लगाना अधिपत्रित हो गया। यह तर्क दिया गया कि प्राधिकारी भी अपने विश्लेषण यह प्रदर्शित करने में असफल रहे कि ऐसी कोई संवेदनशील परिस्थितियां मौजूद हैं। याचिकाकर्ता उक्त तर्क का विरोध करते है और यह प्रस्तुत करते हैं कि याचिका तथा प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 34 में उन संवेदनशील परिस्थितियों पर व्यापक प्राकश डाला गया जिनके कारण इस मामले में रक्षोपाय शुल्क आरोपित करना अधिपत्रित हो गया। इस प्रकार, प्राधिकारी ने रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 6 और रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 9 का इस मामले में पूर्ण अनुपालन किया है।
- **ञ. एफटीए और अन्य द्विपक्षीय करारों से अननुरूपता** : हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि इस संबद्ध वस्तु पर आयात शुल्क भारत-कोरिया सीईपीए और भारत जापान सीईपीए में लगभग समाप्त होने वाला है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि भारत को इस संबद्ध वस्तु के कोरिया आरपी और जापान से हो रहे आयातों पर रक्षोपाय शुल्क वसूल नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह आयात इन देशों से न्यून सीमाशुल्क के कारण हुए है। यह भी तर्क दिया जाता है कि भारत इन दोनों देशों के साथ, कोरिया आरपी और जापान पर सामान्य रक्षोपाय शल्क का अधिरोपण करने के बजाय अपने-अपने एफटीए के अंतर्गत किसी द्विपक्षीय तंत्र का समन्वेषण करें। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क भी दिया है कि भारत-कोरिया सीईपीए में यह प्रावधान है कि यदि कोरिया आरपी से होने वाले आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है तो इन आयातों को रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता इन तर्कों का कड़ा विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि कोरिया आरपी और जापान दोनों ही देशों के आयातों से घरेल उद्योग को क्षति हुई। इस तथ्य का कोई महत्व नहीं है कि कोरिया आरपी और जापान से आयातों में वृद्धि संबंधित एफटीए के अंतर्गत न्यून सीमा शुल्क के कारण हुई है। इन दोनों देशों से आयात अभी हाल ही में भारी मात्रा में हुए हैं और इन आयातों की कीमत असाधारण रूप से कम है जिससे घरेलु उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई है। इसके अलावा, यह भारत सरकार के विवेक पर है कि वह इस मामले में संबंधित एफटीए के अंतर्गत द्विपक्षीय तंत्र का समन्वेशन करे अथवा सामान्य रक्षोपाय शुल्क को अपनाए। दोनों ही एफटीए में कहीं भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि भारत को पहले द्विपक्षीय तंत्र का समन्वेशन करना होगा और उसके पश्चात इस तंत्र के असफल रहने पर सामान्य रक्षोपाय साधन अपनाया जाएगा। पुनश्च, इन एफटीए में कुछ ऐसे विशिष्ट प्रावधान हैं जो भारत को सामान्य रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की अनुमति देते हैं। एसए और रक्षोपाय शुल्क नियमावली में केवल एक ही अपवाद है कि ऐसे विकासशील देशों का अपवर्जन किया जाए जिनका आयातों में व्यक्तिगत हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है और जिनका कुल आयातों में औसत हिस्सा 9 प्रतिशत से कम है। कोरिया आरपी और जापान दोनों ही इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि दोनों ही विकसित देश हैं। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों का तर्क गलत है और उसे नामंजुर किया जाना चाहिए।
- ट. कच्चे माल की कीमतों में गिरावट इस्पात की कीमतों में गिरावट को न्यायोचित ठहराती है: हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि लौह अयस्क और कोयले की कीमतों में वर्ष 2014-15 में क्रमश: 42 प्रतिशत और 21 प्रतिशत की गिरावट आई और इसके परिणामस्वरूप इस संबद्ध वस्तु की कीमतों में भी गिरावट आई है। इसलिए आयात कीमतों को न्यून के रूप में नहीं माना जा सकता है और घरेलू उद्योग भी कच्चे माल की कीमतों में इस कमी का हाट रोल्ड उत्पादों पर फायदा उठाए। हितबद्ध पक्षकार पुन: यह तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ताओं की घरेलु कीमतें निर्यात कीमतों की तुलना में बहुत अधिक हैं। याचिकाकार्त इन तर्कों का कड़ा विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने कच्चे माल की कीमतों में कमी के अनुरूप अपने उत्पाद की कीमतों में पहले ही कमी कर रखी है। परंतु पक्षकारों का यह तर्क गलत है कि कच्चे माल की कीमतों में प्रपाती गिरावट आई है क्योंकि इसमें कच्चे माल को फैक्टरी तक ले जाने की परिवहन लागत पर विचार नहीं किया गया। यह लागत भी उत्पादन लागत में शामिल होती है। इसके अलावा, संपूर्ण क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान इस परिवहन लागत में निरंतर वृद्धि हुई है। इसलिए, कच्चे माल की कीमतों में समग्र गिरावट हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावाकृत कीमतों की तुलना में बहुत कम है। यह नोट करना भी संगत है कि अभिनव अवधि में इस संबद्ध वस्तु के उतराई मुल्य में गिरावट कच्चे माल की कीमतों में आई गिरावट की तुलना में कहीं अधिक है। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य की भी अनुदेखी नहीं करनी चाहिए कि यह आयात सकल रूप से कम कीमतों पर हुए और घरेलू उद्योग पर अपनी कीमतें उस सीमा तक कम करने को मजबूर होना पड़ा कि उसकी कीमतें घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से भी कम हो गई। याचिकाकर्ता इस बात का उल्लेख करना भी चाहेंगे कि अभी हाल ही में कुछ देशों से निर्यात उत्पादन लागत से भी कम लागत पर किए जा रहें जो भारत को प्रमुख निर्यातक भी हैं। इससे अनुचित व्यापार प्रक्रिया की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। अत: हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा गलत है कि घरेलु उद्योग की निर्यात कीमतें घरेलु कीमतों की तुलना में कम है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि स्टील उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का चीन जन गण., रूस और उक्रैन जैसे देशों द्वारा भारी पाटन के कारण निग्रहण किया जा रहा है। घरेलू उद्योग की निर्यात कीमतों का भी निग्रहण किया गया। इसका आशय यह नहीं है कि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपने उत्पाद की बिक्री भी निग्रहित कीमतों पर करें।
- ठ. क्षिति की जांच करने के लिए वर्ष 2013-14 को आधार वर्ष के रूप में नहीं मानना चाहिए: हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि वर्ष 2013-14 को आधार वर्ष के रूप में नहीं मानना चाहिए क्योंकि इसमें वर्ष 2012-13 और 2013-14 के बीच आयातों की अधोग्रामीण प्रवृत्ति पर विचार नहीं किया गया। कुछ हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि विश्लेषण की अविध 5 वर्ष होनी चाहिए और उससे कम का समय वृिटपूर्ण है। याचिकाकर्ता इस तर्क का कड़ा विरोध करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विधिक प्रावधानों में कहीं भी यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि वह न्यूनतम अविध कौन सी होनी चाहिए जिसके लिए गंभीर क्षिति की जांच की गई है। इस संबंध में उपलब्ध केवल एकमात्र मार्गदर्शन गाट के अनुच्छेद XIX का है जहां उल्लेख किया गया है कि आयात अत्यधिक अभिनव अविध में अत्यधिक तीन्न, अचानक और भारी मात्रा में हए हों। इसके अतिरिक्त, उस अविध की सीमा, जिसके लिए पक्षकारों द्वारा आंकड़े प्रदान कराए जाने चाहिए, के संबंध में

मार्गदर्शन दिनांक 06.09.1997 के व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/1/97 में दिया गया है जिसके पैराग्राफ 5(1) में यह उल्लेख है कि पक्षकारों की तीन वर्षों (अथवा उससे अधिक) की अत्यधिक अभिनव अविध की सूचना प्रदान करानी चाहिए जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हों। तथापि, व्यापार नोटिस में यह विनिर्धारित नहीं है कि क्षति विश्लेषण अविध की लंबाई क्या होनी चाहिए, जिसकी प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए। उपर्युक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही तक के आंकड़े अपनी याचिका में प्रदान कराए हैं जो इस जांच की शुरूआत करने के लिए निकटतम आंकड़े हैं। याचिकाकर्ताओं के लिखित प्रस्तुतिकरण में अब वर्ष 2015-16 की द्वितीय तिमाही तक के आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। इसलिए यह याचिका और लिखित प्रस्तुतिकरण गाट के अनुच्छेद- XIX और अपरोक्त व्यापार नोटिस की अपेक्षाओं को पूरा करता है। वर्ष 2013-14 को आधार वर्ष माने जाने के संबंध में दिए गए तर्क के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर होता है कि वह उस ढंग से विश्लेषण करे जिससे वह ठीक समझे। वर्ष 2013-14 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग करने में कुछ भी गलत नहीं है। उपर्युक्त की पूर्वावधारणा के बिना याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि यदि वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मान लिया जाता है तब भी रूझान यही प्रदर्शित करेंगे कि घरेलू उद्योग को आयातों में अचानक, तीव्र, भारी एवं अभिनव वृद्धि होने से गंभीर क्षति की रही है।

- **ड. विचाराधीन उत्पाद की ग्राही खपत :** कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अनुप्रवाही इकाइयों द्वारा ग्राही आयातों को रक्षोपाय शुल्क से मुक्त कर देना चाहिए। अधिकांशत: यह दावे पोस्को कोरिया, पोस्को महाराष्ट्र और हुंडई स्टील कोरिया तथा इसकी भारत स्थित सहबद्ध कंपनियों जैसी कंपनियों द्वारा किए गए हैं। यहां कार्यप्रणाली यह है कि विदेशी स्टील उत्पादक इस संबद्ध वस्तु की आपूर्ति अपनी भारत स्थित सहबद्ध कंपनियों/एफिलिएट्स को कर रहे हैं। इन कंपनियों का एक अत्यधिक आश्चर्यजनक दावा यह है कि भारतीय विनिर्माता उस उच्च क्वालिटी, विनिदेशनों, स्ट्रेंथ की हाट रोल्ड स्टील की आपूर्ति नहीं कर सकते है और यह कंपनियां पर्यावरणीय एवं सुरक्षा मानकों को पूरा करने में असमर्थ हैं। आधारभूत रूप से, किसी न किसी बहाने से, इन कंपनियों का विचार यह है कि घरेलू उद्योग किसी भी तरह से इन भारत स्थित उनकी कंपनियों की जरूरत को पूरा नहीं कर सकती हैं। याचिकाकर्ता इन पक्षकारों की इस प्रकल्पना का कग्र विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु इन सभी जरूरतों को पूर्णतया पूरा करती है जिनकी इन कंपनियों द्वारा अपेक्षा की जाती है। इन कंपनियों की एकमात्र चिंता यह है कि रक्षोपाय शुल्क उन्हें कोरिया आरपी से बहुत ही कम कीमत पर इस संबद्ध वस्तु का आयात कर देने से वंचित कर देगा। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि विधि के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ग्राही खपत के लिए आयातित वस्तु को रक्षोपाय शुल्क के दायरे से छूट देता हो। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के उपर्युक्त तर्कों को सही नहीं माना जा सकता है।
- **ढ. कोई अनपेक्षित विकास नहीं**: कई हितबद्ध पक्षकारों का यह विचार है कि याचिकाकर्ताओं अनपेक्षित विकास की पहचान करने में असफल रहे हैं जिसके कारण इस संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि हुई। कुछ हितबद्ध पक्षकार यह दावा भी करते हैं कि प्राधिकारी अपने प्रारंभिक जांच परिणाम में अनपेक्षित विकास पर चर्चा करने में असफल हो गए। कुछ हितबद्ध पक्षकार यह दावा भी करते हैं कि अनपेक्षित विकास की पहचान की गई परंतु उसे संबद्ध वस्तु से जोड़ा नहीं गया। कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि भारतीय रुपए का अवमूल्यन और प्रायोक्तओं द्वारा स्थानीय अधिप्रापण इस अनपेक्षित विकास को दूर कर देता है। याचिकाकर्ताओं का यह विश्वास है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वास्तव में याचिका का गहन अध्ययन नहीं किया और प्रारंभिक जांच परिणाम को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है। हितबद्ध पक्षकारों की ओर से यह लापरवाही इस तथ्य पर विचार करते हुए आश्चर्यजनक है कि उन्होंने याचिकाकर्ता के दावों का खंडन करने का भारी प्रयास किया है। याचिका दस्तावेज में इस अनपेक्षित विकास का यथातथ्य रूप से उल्लेख किया गया है और यह कहा गया है कि इसके कारण ही इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक, तीव्र भारी एवं अभिनव वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई। प्रारंभिक जांच परिणाम में भी इस अनपेक्षित विकास पर विवेकपूर्ण ढंग से विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे यह सुझाव मिलता हो कि क्या कोई एक विकास हितबद्ध पक्षकारों द्वारा स्थाउल्लिखित अनपेक्षित विकास के प्रभाव को समाप्त कर सकता है। इसलिए, भारतीय रुपए का अवमूल्यन और प्रयोक्ता उद्योग द्वारा स्थानीय असंगत है और अनपेक्षित विकास के प्रभाव को दर करने में अपर्याप्त है।
- ण. संबद्ध अनुप्रवाही उद्योग को किए गए आयातों का समावेशन: कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि भारत में अपनी अनुप्रवाही कंपनियों को किए गए आयातों को बाजार खंडीकरण की प्रक्रिया द्वारा रक्षोपाय शुल्क के दायरे से अपवर्जन कर देना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने रक्षोपाय शुल्क के संबंध में इस प्रक्रिया के बारे में पहली बार सुना है। यह अप्रासंगिक है कि क्या आयात संबद्ध पक्षकार को किए गए हैं या असंबद्ध पक्षकार को। यहां मुख्य बात यह है कि इन वस्तुओं का आयात अचानक, तीव्र, भारी और अभिनव अविध में हुआ हो जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षित कारित हुई हो अथवा गंभीर क्षित कारित करने की चुनौती उत्पन्न हो गई हो, जिसके कारण रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण करना पड़ा। आयातों का गुणधर्म (कि क्या वह असंबद्ध पक्षकारों को किए गए या संबद्ध पक्षकारों) इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों के इन तर्कों को अस्वीकार कर देना चाहिए।
- त. अनुप्रवाही उद्योग पर विपरीत प्रभाव: कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से अनुप्रवाही उद्योग प्रभावित होगा। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि यदि अनुप्रवाही उद्योगों ने अनुचित रूप से कम कीमत पर भारी मात्रा में आयातों को प्रोत्साहित नहीं किया होता तो यह परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई होती। यह तो इसलिए हुआ है कि चूंकि घरेलू उद्योग इतनी अधिक खराब स्थिति में पहुंच गया है कि उसका जीवित रहना दुष्कर हो गया और उसे अपनी रक्षा करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष आना पड़ा। केवल रक्षोपाय शुल्क ही बाजार बलों में संतुलन ला सकता है। रक्षोपाय शुल्क के बिना बाजार में प्रतिस्पर्धा का रूप विकृत ही रहेगा और अनुप्रवाही उद्योग की अधिमानताएं स्थिर रहेंगी तथा वह अनुचित रूप से कम कीमत वाले आयातों की मांग करते रहेंगे। इसके

अतिरिक्त, मित्सुई एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यह प्रस्तुत किया है कि वे इस संबद्ध वस्तु के रि-रोलर्स हैं और उनका इस संबद्ध वस्तु का अधिप्रापण करने के लिए जापान के आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घावधिक संविदाएं है। उनका कहना है कि उनके प्रचालन का आकार इतना अधिक नहीं है कि वह रक्षोपाय शुल्क का बोझ सहन कर सके। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि रक्षोपाय शुल्क सभी के लिए समान अवसर सृजित करेगा और बाजार में विकृतिकारी प्रतिस्पर्धा को दूर करेगा। रक्षोपाय शुल्क किसी भी रूप में लघु रि-रोलर्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि यह तो वह साधन है जो घरेलू उद्योग को कम कीमत वाले आयातों से छुटकारा दिलाएगा जिनका भारत में संवर्धित मात्रा में आयात हो रहा है।

- थ. काइल रूप में उन हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर रक्षोपाय शुल्क अननुप्रयोज्यता जिनकी संविदाएं अंतिम रक्षोपाय शुल्क उदग्रहण करने से पहले कर दी गई थी: कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि इससे वह संविदाएं जिनके लिए एलसी अभी हाल ही में, अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से पहले की गई अथवा उस दिन की गई जिस दिन यह शुल्क अधिरोपित किया गया था, भी प्रभावित होंगी, इस कारण उनके आयात भी रक्षोपाय शुल्क के अध्यधीन होंगे। वास्तव में इन पक्षकारों ने तो रक्षोपाय शुल्क का प्रतिदाय करने का भी अनुरोध किया है क्योंकि उनका विचार है कि इस अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण उनके लिए अनपेक्षित था। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि इस तर्क को नहीं माना जा सकता है। विधि के अंतर्गत ऐसा कोई तर्क नहीं है जो इस छूट की अनुमति देता हो। यह आयात इस संबद्ध वस्तु के अन्य सभी आयातों की तरह ही रक्षोपाय शुल्क के अध्यधीन होंगे।
- द. थाईलैंड और मलेशिया की स्िथित से तुलना नहीं की जा सकती है: हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क है कि थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों ने इस संबद्ध वस्तु पर ऐसी स्थिति में क्रमश: पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क का तब अधिरोपण किया जब आयातों में भारी प्रोत्कर्ष हुआ और इनमें 1350 प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी, परंतु वर्तमान मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। अत: हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि इन देशों के साथ तुलना करना उचित नहीं है। याचिकाकर्ता इस तर्क का विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते है कि यदि भारतीय उद्योग उद्योग तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक भारत में आयात बढ़कर 1350 प्रतिशत नहीं हो जाते हैं तो उस समय तक तो घरेलू उद्योग बचेगा ही नहीं फिर रक्षा किसी की जाएगी। घरेलू उद्योग इन आयातों से अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि की घातक स्थिति का पहले से ही सामना कर रहा है। घरेलू उद्योग से यह उम्मीद नहीं की की जा सकती है कि वह आयातों में ओर अधिक वृद्धि होने की प्रतीक्षा करे क्योंकि घरेलु उद्योग को इन आयातों के कारण पहले से ही गंभीर क्षति हो रही है। उपर्युक्त के पूर्वाग्रह के बिना, यह स्पष्ट किया जाता है कि मलेशिया और थाईलैंड में दी गई याचिका किसी अन्य संदर्भ में थी न कि उस संदर्भ में जिसका आरोप हितबद्ध पक्षकारों ने लगाया है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में मलेशिया और थाईलैंड में इस संबद्ध वस्तु पर क्रमश: पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण करने की याचिका इस तर्क पर दी थी कि अनपेक्षित घटना हुई है। इस अनपेक्षित घटना के कारण निर्यातकगण इन देशों को अपना निर्यात कर सकने में समर्थ नहीं रहे और उन्होंने भारत जैसे देश को भारी मात्रा में निर्यात करना शुरू कर दिया, जहां मांग अच्छी थी और अभी भी अच्छी बनी हुई है। उपर्युक्त के आलोक में यह प्रस्तुत किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकार वह संदर्भ समझने में असफल रहे जिसके आधार पर याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि अनपेक्षित विकास के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क गलत हैं और उन्हें नामंजुर कर देना चाहिए अत:, हितबद्ध पक्षकारों के उपर्युक्त तर्क अस्वीकार्य हैं और उन्हें खारिज कर देना चाहिए।
- **ध. ग्राही खपत के निवल और अग्रिम प्राधिकृतीकरण/ईपीसीजी के निवल आयात:** कई हितबद्ध पक्षकार यह तर्क देते हैं कि आयात मात्रा पर विचार ग्राही खपत अथवा अग्रिम प्राधिकृतीकरण/ ईपीसीजी के आशय से किए गए आयातों का अपवर्जन करके करना चाहिए। याचिकाकर्ता इस तर्क का कड़ा विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि रक्षोपाय जांच के प्रयोजनार्थ कुल आयातों की जांच की जाती है। आयातों के गुणधर्म, कि क्या ये ग्राही खपत के लिए हैं अथवा अग्रिम प्राधिकृतीकरण/ईपीसीजी के अंतर्गत किए गए हैं, इसका कोई महत्व नहीं होता है।
- न. शुल्क प्रतिअदायगी का दावा करने की जटिल प्रक्रिया : मैसर्स हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड यह दावा करता है कि भारत में शुल्क प्रति अदायगी का दावा करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और जब तक यह प्रक्रिया सरल नहीं कर दी जाती तब तक रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण नहीं करना चाहिए। यह तर्क इस जांच से अप्रासंगिक है और उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- प. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव: हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क भी दिया है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को क्षति पहुंचाएगा। याचिकाकर्ता इस तर्क का पूर्णतया विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता आहत नहीं होगी क्योंकि भारत में उत्पादकों/निर्यातकों को सदैव ही अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत इस संबद्ध वस्तु को रक्षोपाय शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है। अत:, हितबद्ध पक्षकारों का उपर्युक्त तर्क अस्वीकार्य है और उसे नामंजुर कर देना चाहिए।
- फ. रक्षोपाय शुल्क से रोजगार कम होगा और एकाधिकारिता बढ़ेगी : कई हितबद्ध पक्षकारों का यह गलत दावा है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से भारत में रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि यदि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जाता है तो घरेलू उद्योग का रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। रक्षोपाय शुल्क तत्काल अधिरोपित करना जनहित में है और इससे घरेलू

उद्योग की रक्षा होगी। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से एकाधिपत्य नहीं होगा क्योंकि भारत में इस संबद्ध वस्तु के कई विनिर्माता हैं और उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। इस संबद्ध वस्तु के वे आयात जो इस प्रतिस्पर्धा को विकृत कर रहे हैं रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण हो जाने से कम होंगे। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे। रक्षोपाय शुल्क से भारत में इस संबद्ध वस्तु के न्यून कीमत वाले आयातों का भारी मात्रा में आयातों से उत्पन्न बाजार विकृति दूर होगी और घरेलू उद्योग का अस्थायी संरक्षण प्राप्त होगा।

ब. जांच के अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दे : कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह चिंता व्यक्त की है कि भारत अन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से पहले डब्ल्यूटीओ की इसकी अधिसूचना देने से असफल रहा है। यहां तक कि निर्यातकों को भी अधिसूचना की इस अपेक्षा का अनुपालन न किए जाने की चिंता है। इसके अतिरिक्त, कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि उन विकासशील देशों की सूची जिनके अयात 3 प्रतिशत की विधिक सीमा से कम हैं, उपलब्ध है और उन्हें रक्षोपाय शुल्क के दायरे से अपवर्जित कर देना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों का यह विचार भी है कि अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना जल्दी-जल्दी में अधिरोपित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता इन तर्कों का खंडन करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि केवल इस कारण से भारत द्वारा इस साधन को अपनाने की डब्ल्युटीओ को अधिसुचना कुछ विलंब से दिए जाने का आशय यह नहीं है कि अनन्तिम रक्षोपाय शल्क का अधिरोपण ही एसए के अनुच्छेद 12.4 के प्रावधानों के विपरीत है। किसी प्रक्रियात्मक जरूरत, जैसे डब्ल्यूटीओ को अधिसूचना देर से करने का पालन न करने से अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क के गुणों से समझौता नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों को भारत द्वारा इस अधिसूचना अपेक्षा के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह डब्ल्यूटीओ सदस्य देश का विशेषाधिकार होता है कि वह इन मुद्दों को भारत सरकार की जानकारी में लाए न कि विदेशी निर्यातकों की जानकारी में। याचिकाकर्ता पुन: यह प्रस्तुत करते हैं कि प्राधिकारी के पास प्रत्येक निर्यातक देश से निर्यातों की मात्रा के रिकार्ड के पूरे आंकड़े पहले से ही मौजूदा हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं में इस संबंध में प्राधिकारी को अपना स्पष्टीकरण अपने दिनांक 9 नवम्बर, 2015 के पत्र के तहत दे दिया है। इसलिए प्राधिकारी इस मामले को अंतिम रूप देते समय इसकी जांच कर सकते हैं और विकासशील देशों की सूची अधिसुचित कर सकते हैं जिन्हें रक्षोपाय शुल्क के अनुप्रयोग से छुट दी जानी है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के सभी स्तरों पर अपनी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में पूर्ण समर्थ रहे हैं। अत: यह तर्क देना गलत है कि कुछ दिनों के अंदर ही रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कर देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने अपने दिनांक 27 जुलाई, 2015 के पत्र के तहत वे उदाहरण बताए जहां डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों ने अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क उसी दिन अधिरोपित कर दिया जिस दिन रक्षोपाय जांच प्रारंभ की गई थी। इस मामले में अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जांच शुरू करने के पूरे एक सप्ताह के बाद किया गया था। यह किसी भी रूप में किसी भी डब्ल्युटीओ प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 9(1) प्राधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह जांच की कार्रवाई पर जल्दी-जल्दी आगे बढ़े और संवेदनशील परिस्थितियों में गंभीर क्षति होने अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न होने के संबंध में अपना अंतिम जांच परिणाम अतिशीघ्र रिकार्ड करें। चूंकि इस मामले में संवेदनशील परिस्थितियां मौजूद थीं, इसलिए प्राधिकारी ने इस मामले में शीघ्रता से प्रारंभिक जांच परिणाम जारी कर दिए और तत्पश्चात इस जांच के प्रारंभ होने के एक सप्ताह के उपरांत सीमा शुल्क अधिसुचना जारी की गई थी। इसलिए इस मामले में अत्यधिक संवेदनशील परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी विधिक अपेक्षाओं को पूरा किया गया है।

क्षति पैरामीटरों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क :

याचिकाकर्ता क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का विरोध करते हैं और इस संबंध में निम्नलिखित प्रमुख प्रस्तुतिकरणों की ओर प्राधिकारी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

(i) बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता, निवेश स्तर, मालसूची, रोजगार सहित सभी संकेतक स्थिर बने रहे और कुछ संकेतकों ने तो सकारात्मक प्रवृत्ति भी प्रदर्शित की।

याचिकाकर्ताओं ने सभी आर्थिक पैरामीटरों पर अद्यतन सूचना उसकी प्रत्युक्ति सहित प्रदान कराई है।

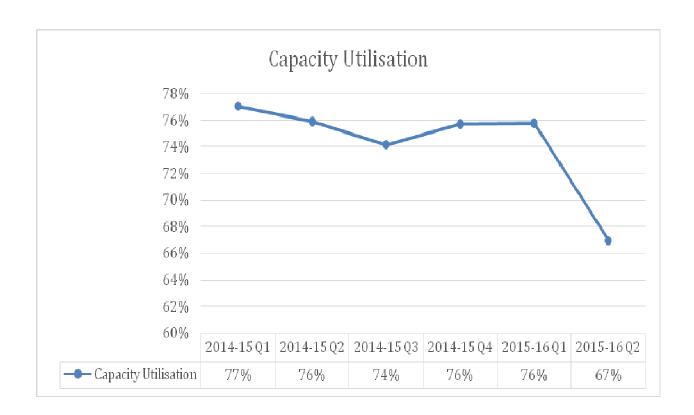
- भ. याचिकाकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का विरोध करते हैं कि बिक्री उत्पादन, क्षमता, निवेश स्तर, मालसूची, रोजगार सहित सभी क्षति संकेतक स्थिर बन रहे और कुछ संकेतकों ने तो सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित की है।
- म. इस संबद्ध वस्तु के लिए भारत में मांग में क्षति विश्लेषण अविध के दौरान वृद्धि हुई है। मांग में इस वृद्धि के बावजूद याचिकाकर्ताओं का उत्पादन, रोजगार और बिक्री सतर स्थिर बना रहा। यद्यिप मालसूची में वृद्धि हुई तथापि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। इस संबद्ध वस्तु की समस्त संवर्धित मांग पर आयातों ने अपना कब्जा कर लिया। वर्ष 2014-15 में ग्राही को छोड़कर मांग में वृद्धि होकर यह 1158614 एमटी हो गई और आयातों में इससे कहीं अधिक वृद्धि हुई तथा वे 1248015 एमटी हो गए। यह उस आक्रामक तरीके को दर्शाता है जिससे इस संबद्ध वस्तु के आयातों ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है।

य. इसके अतिरिक्त, पोस्को महाराष्ट्र ने यह तर्क दिया है कि वर्ष 2014-15 में आयातों में यह प्रोत्कर्ष उनके द्वारा विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए किए गए आयातों के कारण हुआ और यदि उसका अपवर्जन कर दिया जाता है कि आयातों में मंदी प्रदर्शित होगी। याचिकाकर्ता इस तर्क का कड़ा विरोध करते हैं कि यह प्रस्तुत करते हैं कि आयातों में यह प्रोत्कर्ष न केवल 2014-15 में हुआ बल्कि यह वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही और द्वितीय तिमाही में भी हुआ है। इसके अतिरिक्त, पोस्को स्वयं यह स्वीकार कर रहा है कि उसने अपने अधिकांश आयात वर्ष 2015-16 की पहली दो तिमाहियों में ही किए हैं, जिससे इस बिंदु को साक्ष्य मिलता है कि वे इस संबद्ध वस्तु का कोरिया आरपी से असामान्य रूप से कम कीमतों पर भारी मात्रा में आयात करके घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित कर रहे थे अथवा गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर रहे थे।

कक. यदि इस संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण गंभीर क्षति नहीं हुई होती तो क्षमता उपयोग, रोजगार और बिक्री में भारत में मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप ही वृद्धि हुई होती। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री और रोजगार संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान स्थिर बने रहे।

खख. क्षमता उपयोग जो वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में 77 प्रतिशत था, कम होकर वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में 67 प्रतिशत ही रह गया जैसाकि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है।

विवरण	यूनिट	2014-15 पहली तिमाही	2014-15 दूसरी तिमाही	2014-15 तीसरी तिमाही	2014-15 चौथी तिमाही	2015-16 पहली तिमाही	2015-16 दूसरी तिमाही
घरेलू उद्योग की क्षमता	МТ	5,884,372	5,915,879	5,915,879	5,852,865	5,884,372	5,884,372
आवेदक घरेलू उद्योग का उत्पादन	МТ	4,532,770	4,488,093	4,386,470	4,429,604	4,456,795	3,941,208
क्षमता उपयोग	%	77%	76%	74%	76%	76%	67%



गग. घरेलू उद्योग ने संवर्धित आयातों के सतत दबाव के कारण आधार वर्ष की तुलना में अपने मालसूची स्तर में पर्याप्त वृद्धि कर ली है। भारत में बढ़ती मांग की पहले से ही कल्पना करते हुए घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता बढ़ा ली है। तथापि, घरेलू उद्योग अपना उत्पादन और अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं है जिसके कारण क्षति अविध के दौरान एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जब मालसूची का संग्रह हो गया।

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 पहली तिमाही	2015-16 दूसरी तिमाही	
मालसूची (एमटी)	331,101	583,311	636,879	648,290	657,099	871,440	ì
अनुक्रमित	100	176	192	196	198	263	l

घघ. इसलिए यह स्पष्ट है कि हितबद्ध पक्षकारों के तर्क गलत हैं। बिक्री उत्पादन, क्षमता उपयोग, निवेश स्तर और रोजगार ऋणात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत मिल रहा है।

(ii) घरेलू उद्योग को वर्ष 2014-15 तक लाभ हुआ जब कि वर्ष 2015-16 की केवल पहली तिमाही में घाटा उपचित हुआ।

ड.ड. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के लाभ ने उर्ध्वगामी प्रवृत्ति अपनाई है और उसे घाटा वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में ही हुआ और इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। याचिकाकर्ता इस उपर्युक्त तर्क का विरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई क्योंकि उसके लाभ में वृद्धि हुई। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि घरेलू उद्योग को केवल 2015-16 की प्रथम तिमाही में ही घाटा नहीं हुआ बल्कि उसे यह घाटा वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में भी हुआ। यह नोट किया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग का न केवल संपूर्ण लाभ समाप्त हो गया बल्कि उसे भारी घाटा भी हो रहा है। तद्वारा याचिकाकर्ताओं के इस दावे का साक्ष्यांकन हो रहा है कि ऐसी असामान्य परिस्थितियों में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना लाजमी है। लाभ की प्रवृत्ति अधोलिखित तालिका में दर्शाए गई है:

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 पहली तिमाही	2015-16 दूसरी तिमाही
लाभ (करोड़ भारतीय रुपए)	****	***	***	***	****	****
लाभ (आईएनआर अनुक्रमित)	100	34	96	79	(59)	(87)
लाभ (आईएनआर प्रति एमटी)	****	****	****	****	****	****
लाभ (आईएनआर प्रति एमटी अनुक्रमित)	100	27	68	95	(90)	(227)

चच. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अभिनव अवधि में याचिकाकर्ताओं की लाभप्रदता में भारी कमी आई है। घरेलू उद्योग को वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही से गंभीर घाटा हो रहा है। इसके अतिरिक्त, इस घाटे में वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में और भी अधिक वृद्धि हुई है। लाभ जो वर्ष 2011-12 में 100 अनुक्रमित यूनिट प्रति एमटी था, वहीं घरेलू उद्योग वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही से (90) अनुक्रमित यूनिट का घाटा सहन कर रहा है और इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही के दौरान यह घाटा बढ़कर (227) अनुक्रमित यूनिट हो गया।

छछ. वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के पहले छह महीने का तिमाहीवार विश्लेषण अशुभ तस्वीर दर्शाता है। लाभ में कमी आना वर्ष 2014-15 से ही शुरू हो गई थी और घरेलू उद्योग की यह स्थित वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में और भी अधिक खराब हो गई। वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में लाभ 100 अनुक्रमित बिंदु था, जिसमें तीव्रतापूर्वक गिरावट आई और यह घटकर वर्ष 2014-15 की चौथी तिमाही में 52 अनुक्रमित बिंदु रह गया। घरेलू उद्योग को वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में भीषण घाटा हुआ जब इसका घाटा बढ़कर (36) अनुक्रमित बिंदुओं तक पहुंच गया। घाटे की यह स्थिति वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में और भी अधिक खराब हो गई जब यह घाटा बढ़कर 52 अनुक्रमित बिंदु हो गया।

विवरण	यूनिट	2014-15 पहली तिमाही	2014-15 दूसरी तिमाही	2014-15 तीसरी तिमाही	2014-15 चौथी तिमाही	2015-16 पहली तिमाही	2015-16 दूसरी तिमाही
लाभ	आई एन आर (करोड़)	***	****	***	****	****	***
अनुक्रमित		100	118	42	52	(36)	(52)
लाभ प्रति एमटी	आई एन आर/ एमटी	****	****	***	****	****	***
अनुक्रमित		100	111	48	45	(17)	(42)

जज. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट होने और घाटा होने का मुख्य कारण कम कीमतों वाले आयातों में वृद्धि होना है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो घरेलू उद्योग को डर है कि उन्हें मजबूरन अपने प्रचालन बंद करने पड़ेंगे। यदि समुचित उपचारी उपाय तत्काल नहीं किए गए तो घरेलू उद्योग को यह डर है कि बैंकों/वित्तीय संस्थान अपना ऋण वापस करने की मांग करने लगेंगी और एतदद्वारा घरेलू उद्योग की अचानक समाप्ति हो जाएगी।

(iii) आयातों का बाजार हिस्सा इतना अधिक नहीं है कि वह क्षति कारित कर सके।

झझ. कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आयातों में अचानक और तीव्र कोई ऐसी वृद्धि नहीं हुई जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित कर सकती हो। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क भी दिया कि आयातों का बाजार हिस्सा इतना अधिक नहीं है कि उससे क्षति कारित हो सके। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क भी दिया है कि आयातों में समग्र रूप से कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, कुछेक हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क भी दिया कि आयातों में यह वृद्धि अस्थायी प्रकृति की है और आयातों में प्रोत्कर्ष का अभिकथन भ्रामक है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि कोरिया आरपी, रूस और जापान से आयात इतनी कम मात्रा में हुए कि उनसे गंभीर क्षति हो ही नहीं सकती है।

जज. याचिकाकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के उक्त तर्कों का पूरी तरह से विरोध करते हैं कि आयात, अति महत्वपूर्ण न होने के कारण, घरेलू उद्योग को क्षितिकारित नहीं कर रहे है और यह कि इस संबद्ध वस्तु के आयातों में कोई तीव्र वृद्धि हुई ही नहीं है। वास्तव में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षित केवल तभी हो सकती है जब आयातों में अचानक वृद्धि हुई हो। अभिनव अविध के तिमाही रूझान यह दर्शाते हैं कि कुल मांग में, जिसमें ग्राही मांग भी शामिल है, आयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में 7 प्रतिशत था, बढ़कर चौथी तिमाही में 13 प्रतिशत हो गया। कुल मांग (ग्राही मांग को छोड़कर) में आयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में 11 प्रतिशत था, बढ़कर चौथी तिमाही में 21 प्रतिशत हो गया। कुल मांग में आयातों का बाजार हिस्सा वर्ष 2015-16 की पहली और दूसरी तिमाही में उच्च बना रहा। रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2014-15 की सभी तिमाहियों में और 2015-16 की पहली एवं दूसरी तिमाही में मांग में क्रमित वृद्धि हुई है। इसके विपरीत आयातों ने वर्ष 2014-15 की हर तिमाही में और वर्ष 2015-16 की पहली और दूसरी तिमाही में तीव्र वृद्धि प्रदर्शित की है। कुल मांग में (ग्राही मांग को छोड़कर) आयातों का हिस्सा जो वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में 11 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में 19 प्रतिशत हो गया और पुन: बढ़कर वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में 24 प्रतिशत हो गया। यदि आयात इसी गित से बढ़ना जारी रहे तो घरेलू उद्योग जल्दी ही समाप्त हो जाएगा।

टट. इसके अतिरिक्त, इस प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में िक कोरिया आरपी, जापान और रूस से आयात बहुत अधिक नहीं हुए, याचिकाकर्ता इसका कड़ा विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं िक उपरिलिखित देशों से आयात बहुत अधिक मात्रा में हुए हैं जैसा िक अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, विधि यह प्रावधान करती है िक केवल एक विकासशील देश जो 3 प्रतिशत/9 प्रतिशत के मापदंड को पूरा करता है, उसका ही अपवर्जन किया जा सकता है। इसलिए यह तर्क िक कोरिया आरपी, जापान और रूस का अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए सही नहीं है क्योंकि यह देश विकासशील देश न होकर विकसित देश हैं और इसके साथ ही साथ इन देशों से आयात भी बहुत अधिक मात्रा में हुए हैं।

देश	आयात मात्रा (एमटी)	कुल आयातों में हिस्सेदारी
जापान	1,957,260	33.08%
कोरिया	1,586,318	26.81%
रूस	361,511	6.11%

कुल योग	5,916,155	100.00%
अन्य	2,011,066	33.99%

(iv) क्षति आंतरिक समस्याओं तथा आयातों के अलावा अन्य कारकों से हुई है।

ठठ. हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा सहन की जा रही क्षति निम्नलिखित सहित उसके अपने आंतरिक कारकों के कारण हुई है :

- उच्च ब्याज लागत, अवक्षयण और नियम लागत भार
- उच्च मालभाड़ा लागत और कमजोर अवसंरचना
- कच्चे माल का संकट
- विशिष्ट अनुप्रवाही उद्योग की क्वालिटी जरूरतों को पूरा करने की अक्षमता

डड. याचिकाकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के उपर्युक्त दावों का खंडन करते हैं। यह दावे आम प्रवृत्ति के हैं और इनके समर्थन में कोई तथ्य या कोई आंकड़े नहीं हैं। यह तथ्य कि भारत में इस संबद्ध वस्तु के आयातों की बढ़ती मात्रा के कारण क्षित कारित हुई है ऊपर पहले ही सिद्ध कर दिया गया है। घरेलू उद्योग बहुत लंबे समय से मौजूद है और तब से सही-सलामत काम कर रही है। घरेलू उद्योग के पास इतनी अवसंरचना और इतनी क्षमताएं हैं कि वह इस संबद्ध वस्तु की मांग को पूरा कर सकता है। परंतु अब यह आरोप लगाया जाता है कि घरेलू उद्योग को अब उपरिलिखित आंतरिक मुद्दों को कारण घाटे का सामना करना पड़ रहा है। यदि यह आंतरिक मुद्दे वास्तव में हैं तो घरेलू उद्योग ने विगत में भी अच्छा कार्य नहीं किया होना चाहिए था। इसलिए यह आरोप है कि घरेलू उद्योग को घाटे का सामना उपर्युक्त आंतरिक समस्याओं के कारण करना पड़ रहा है, सही नहीं है। यह तो इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक एवं तीव्र प्रोत्कर्ष है जिसने घरेलू उद्योग को क्षित कारित की है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकार, अपने तर्कों में क्वालिटी अपेक्षाओं को साक्ष्यांकित करने में असमर्थ रहे, जिसे घरेलू उद्योग उत्पादित कर सकता है।

(v) घरेलू उद्योग को अन्य भारतीय विनिर्माताओं से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए सहन की गई क्षति संवर्धित मात्रा में हुए आयातों के कारण नहीं हुई।

ढढ. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अन्य भारतीय उत्पादक घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अन्य भारतीय उत्पादकों ने अपनी खुली बाजार बिक्रियां 42 प्रतिशत (वर्ष 2013-14 में 2994323 एमटी से बढ़कर वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) में 4263888 एमटी हो गई) बढ़ा दीं। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि अन्य भारतीय उत्पादकों का हिस्सा समग्र रूप से बहुत कम है और इसलिए उनकी खुली बाजार में बिक्रियों में वृद्धि समग्र रूप से भी सीमित ही है।

वित्तीय वर्ष	कुल	घरेलू उद्योग	अन्य	घरेलू	अन्यों की	कुल मांग	बाजार हिस्सा (प्रतिशत)	
	आयात (एमटी)	की बिक्री (एमटी)	भारतीय उत्पादकों की बिक्री (एमटी)	उद्योग की ग्राही बिक्री (एमटी)	ग्राही बिक्री (एमटी)	(एमटी)	घरेलू उ द्यो ग	आयात
2013-14	1292099	10342565	2994323	4274000	4000724	22903711	45	6
2014-15	2540114	9949214	3298273	5019741	4615864	25423206	39	10
2015-16 (पहली तिमाही)	844840	2589929	1065972	1321497	1180681	7002919		
2015-16 (वार्षिकीकृत)	3379360	10359716	4263888	5285988	4722724	28011676	37	12

णण. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 (वार्षिकीकृत) तक सभी भारतीय उत्पादकों की संयुक्त खुली बाजार बिक्री में केवल 9.6 प्रतिशत (समग्र रूप से 1286716) वृद्धि हुई है जबिक उसी अविध के दौरान आयातों में 160 प्रतिशत की भारी वृद्धि (समग्र रूप से 2087261 एमटी) हुई।

तत. हितबद्ध पक्षकार अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री में 42 प्रतिशत की वृद्धि उजागर करके प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं जबकि आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन यह दर्शाता है कि बिक्री में यह वृद्धि भारत में मांग की तुलना में कुछ भी नहीं है।

VI. अन्य मुद्दे

1) वर्ष 2015-16 के आंकड़ों का वार्षिकीकरण करने के लिए पहली तिमाही के आंकड़ों का प्रयोग

थथ. हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि वर्ष 2015-16 के वार्षिकीकृत आंकड़ों पर पहुंचने के लिए वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही के आंकड़ों का वार्षिकीकरण करना क्षति विश्लेषण का उचित तरीका नहीं है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कहा कि यह तरीका क्षति विश्लेषण का उद्देश्यपरक एवं तर्कसंगत आधार पर प्रदान नहीं करता है और भ्रामक है। हितबद्ध पक्षकारों में से एक ने यह प्रस्तुतिकरण किया कि वार्षिकीकरण करने के लिए अधिक लंबी अविध पर विचार करना चाहिए था।

दद. इस संबंध में याचिकाकर्ता यह प्रस्तुतिकरण करते हैं कि प्राधिकारी के समक्ष दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने जनवरी, 2015 से जून, 2015 (6 माह) की अवधि के आंकड़े प्रदान कराए हैं, इनके आधार पर वर्ष 2015 के लिए आंकड़ों का वार्षिकीकरण किया गया है। यह नोट करने योग्य है कि गाट के अनुच्छेद XIX, रक्षोपाय करार, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और रक्षोपाय शुल्क नियमावली में कहीं भी वार्षिकीकरण का तरीका नहीं दिया गया है। केवल विधिक अपेक्षा यह है कि ऐसी अवधि के आंकड़े दिए जाएं जो यथासंभव अभिनव अवधि हो और घरेलू उद्योग ने इसी का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात किए गए लिखित प्रस्तुतिकरण में याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही दोनों तिमाहियों के आंकड़े प्रदान कराए हैं। अब वर्ष 2015-16 के पहले छह महीनों के आंकड़ों के आधार पर वार्षिकीकरण किया गया है जो इस वार्षिकीकरण के प्रयोजनार्थ पर्याप्त है।

2) सस्ते आयातों का प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव

धध. चीन आयरन एंड स्टील एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि भारत में सस्ते आयात भारतीय उद्योग में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करेंगे और इसलिए आयातों में वृद्धि अथवा कम कीमत वाली वस्तु की उपलब्धता खराब नहीं है और उसे हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता इस तर्क का पूरी तरह से विरोध करते हैं। किसी संबद्ध वस्तु के आयात तब तक खराब नहीं हैं जब तक वे आयात अनुचित कीमतों पर नहीं किए जाते और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षित कारित नहीं कर देते हो अथवा गंभीर क्षित कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर रहे हों तब इन आयातों को रक्षोपाय साधन का प्रयोग करके नियंत्रित करने की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करेगा। समुचित शुल्क का भुगतान करने के अध्यधीन आयात तब भी किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी कि यह कोई स्थायी साधन नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उद्योग का एक अस्थायी संरक्षण है कि इस संबद्ध वस्तु के अनुचित रूप से कम कीमत वाले आयातों की भारी यात्रा भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा विकृत न कर दे। रक्षोपाय शुल्क वास्तव में भारतीय बाजार में स्वस्थ एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा।

3) न्यूनतम कीमत पर रक्षोपाय शुल्क

नन. मैसर्स ट्यूब इन्वेस्टमेंट और मैसर्स हुंडई मोटर्स ने सुझाव दिया है कि सस्ते आयातों को नियंत्रित करने के लिए फ्लोर प्राइस तंत्र का प्रयोग करना चाहिए। याचिकाकर्ता इस प्रस्ताव से सहमत हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि घरेलू उद्योग की विनिर्माण लागत और कम कीमतों वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई गंभीर क्षति को ध्यान में रखकर फ्लोर प्राइस तंत्र का आश्रय लिया जा सकता है। यदि इस तंत्र का प्रयोग करना अपेक्षित हो तो प्राधिकारी घरेलू उद्योग से विचार आमंत्रित कर सकते हैं।

पप. उपर्यक्त तर्कों के आलोक में याचिकाकर्ता यह प्रसुत्त करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई दम नहीं है।

II. सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात फेडरेटिव रिपब्लिक आफ ब्राजील द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का घरेलू उद्योग द्वारा प्रत्युत्तर

याचिकाकर्ता फेडरेटिव रिपब्लिक आफ ब्राजील ("ब्राजील") द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों का उत्तरवर्ती पैराग्राफों में दिया गया प्रत्युत्तर।

लिखित प्रस्तुतिकरणों के पहले दो पैराग्राफ : अपने लिखित प्रस्तुतिकरणों के पहले दो पैराग्राफों में ब्राजील ने गाट 1994 ("गाट") के अनुच्छेद XIX और रक्षोपाय करार ("एसए") का अनुपालन करने की जरूरत से संबंधित बहुत ही सामान्य प्रस्तुतिकरण किया। इसके पश्चात, ब्राजील ने भारत को चेतावनी दी कि चूंकि रक्षोपाय साधन आपातकालीन साधन हैं इसलिए उनको डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय द्वारा स्थापित उच्च मानकों का अनुपालन करने के पश्चात ही लागू करना चाहिए। याचिकाकर्ता ब्राजील की सामान्य टिप्पणी से सहमत हैं और यह प्रस्तुतिकरण करते हैं कि प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में गाट के अनुच्छेद XIX और रक्षोपाय करार के अंतर्गत सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। याचिका में वह सब संगत जानकारी दी गई है जिसके कारण रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना उपयुक्त है। प्राधिकारी ने इस सूचना की गाट, रक्षोपाय करार, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 ("रक्षोपाय शुल्क नियमावली") के अंतर्गत अपेक्षित सभी अपेक्षाओं के अनुरूप जांच की है। कठोर विधिक मानकों से संतुष्ट होने के पश्चात ही प्राधिकारी ने यह जांच प्रारंभ की।

- क. डब्ल्यूटीओ को अधिसूचना : ब्राजील ने अपने लिखित प्रस्तुतिकरणों के पैरा 3 से 8 में यह तर्क दिया है कि चूंकि भारत अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से पहले इसको अधिसूचित करने में असफल रहा है इसलिए भारत रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 12.4 के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा। याचिकाकर्ता इस तर्क का विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि भारत द्वारा इस साधन को डब्ल्यूटीओ में अधिसूचित करने में हुए थोड़े से विलंब के कारण ही यह आशय नहीं निकाला जा सकता है कि अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना ही स्वयं में रक्षोपाय करार के प्रावधानों से असंगत नहीं है। किसी प्रकार्यात्मक जरूरत का अनुपालन जैसे डब्ल्यूटीओ को अधिसूचना, न करने से अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क के पर्याप्त लाभों से समझौता नहीं किया जा सकता है। ब्राजील का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- गंभीर क्षति (और उसकी चनौती) ओर संवर्धित आयातों की जांच की अवधि लिखित प्रसततिकरण के पैराग्राफ 9 से 16 में. ब्राजील ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने घरेलु उद्योग के केवल 2013-14, 2014-15 और 2015-16 की अवधि के आंकड़ों पर ही विचार किया है, प्राधिकारी ने वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही के आधार पर क्षति पैरामीटरों को साधारणत: चार से गुणा कर दिया। ब्राजील का यह तर्क है कि यह तरीका गलत है क्योंकि यह सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों से असंगत है और इस कारण से भी कि वर्ष 2015-16 की एक तिमाही वर्ष 2015-16 के दौरान घरेल उद्योग के निष्पादन को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ब्राजील ने इसके आगे यह तर्क दिया कि भारतीय प्राधिकारियों ने अप्रैल 2011 से मार्च 2012 की अवधि के लिए आंकड़ों की इस तथ्य के बावजूद अनदेखी कर दी कि यह आंकड़े प्राधिकारी के पास उपलब्ध हैं। ब्राजील के अनुसार यह रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2 का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त ब्राजील ने यह तर्क भी दिया कि गंभीर क्षति के लिए जांच की अवधि डब्ल्यटीओ पाटनरोधी समिति की सिफारिशों के अनुसार तीन वर्ष की होनी चाहिए और इस मामले में दो वर्ष एवं एक तिमाही की अवधि पर्यापत अवधि नहीं है। ब्राजील का तर्क है कि जांच की अवधि को इस औचित्य के साथ नहीं घटाया जा सकता है कि जांच की कार्रवाई के दौरान अत्यधिक अभिनव अवधि के लिए वास्तविक आंकड़ों को एकत्र करना चाहिए। इन तर्कों के आलोक में ब्राजील यह तर्क देता है कि भारत रक्षोपाय करार में निर्धारित उद्देश्यों का अनुपालन करने में असफल रहा है। याचिकाकर्ता ब्राजील के इन सभी तर्कों का विरोध करते हैं। याचिकाकर्ता यह प्रस्तृत करते हैं कि यद्यपि डब्ल्युटीओ की पाटनरोधी समिति ने विशेष रूप से यह सुझाव दिया है कि किसी पाटनरोधी जांच में क्षति विश्लेषण के लिए आंकड़ों का संग्रहण करने की अवधि तीन वर्ष होनी चाहिए, तथापि, इस अपेक्षा को साधारणत: रक्षोपाय जांच पर पक्षांतरित नहीं किया जा सकता है। ब्राजील का यह तर्क सही नहीं है कि वर्तमान जांच में चूंकि प्राधिकारी ने केवल दो वर्ष ओर एक तिमाही की अवधि के लिए ही आंकड़ों पर विचार किया है इसलिए प्राधिकारी तीन वर्षों के आंकड़ों की जांच करने की जरूरत का पालन करने में असफल हो गया है। गाट, रक्षोपाय करार, अधिनियम और रक्षेपाय शुल्क नियमावली के अंतर्गत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि प्राधिकारी को घरेलु उद्योग की गंभीर क्षति का विश्लेषण करेन के लिए कम से कम तीन वर्षों के आंकड़ों को एकत्र करना और उनकी जांच करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ब्राजील सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अंतर्गत विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख करने में भी असफल रहता है जिनको इस मामले में पुरा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि अनुच्छेद XIX के अंतर्गत अपेक्षा यह है कि आयात अत्यधिक अभिनव होने चाहिए और घरेलु उद्योग द्वारा अपनी याचिका में वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही तक के आंकड़े प्रदान करके इस अपेक्षा को परा किया गया है। केवल इस कारण से कि प्राधिकारी ने एक तिमाही के आंकड़ों का संपूर्ण वर्ष के लिए बहिर्वेशन किया है, इसका आशय से यह तो नहीं हो जाता है कि इससे रक्षोपाय करार, गाट, अधिनियम अथवा रक्षोपाय शुल्क नियमावली के किसी प्रावधान का उल्लंघन होता है। याचिकाकर्ता इस जांच की कार्रवाई के दौरान प्राधिकारी को नियमित रूप से सहायता प्रदान करते रहे हैं और उन्होंने अत्यधिक नूतन अवधि की तिमाही के आयात आंकड़े भी प्रदान कराए हैं। वर्ष 2015-16 की द्वितीय तिमाही तक के अद्यतन क्षति आंकड़ों की सूचना भी याचिकाकर्ताओं ने अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में प्रदान कराई है। हितबद्ध पक्षकारों को इस अद्यतनीकृत सुचना पर टिप्पणी करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। इन तर्कों के आलोक में याचिकाकर्ता बड़ी विनम्रतापूर्वक यह प्रस्तुत करते हैं कि पैराग्राफ 9 से 16 तक किया गया ब्राजील का तर्क अनधिपत्रित है और उसे नामंजुर कर देना चाहिए।
- ग. गंभीर क्षति और उसकी चुनौती : ब्राजील ने अपने लिखित प्रस्तुतिकरण के पैरा 17 से 23 तक यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के क्षिति पैरामीटर गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न होने की मौजूदगी का संकेत नहीं देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राजील ने केवल प्रारंभिक जांच परिणाम में दिए गए क्षति पैरामीटरों का ही उल्लेख किया न कि याचिका में दिए गए क्षति पैरामीटरों का। याचिकाकर्ता ब्राजील के इस तर्क को नामंजूर कर देते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति की चुनौती भी उत्पन्न हो गई है। यह प्राधिकारी के पास रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट है। इसलिए ब्राजील के इस तर्क को नामंजूर कर देना चाहिए।

- घ. कारणात्मक संबंध : ब्राजील ने अपने लिखित प्रस्तुतिकरणों के पैराग्राफ 24 से 28 में यह तर्क दिया है कि इस मामले में कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, जैसािक अन्य कारकों का एक विश्लेषण दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को क्षित आयातों के कारण न होकर अन्य कारकों के कारण हुई है। याचिकाकर्ता इस तर्क का कड़ा विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले में कारणात्मक संबंध बिल्कुल स्पष्ट है। याचिकाकर्ताओं ने इस जांच के दौरान विस्तार से यह स्पष्ट किया है कि इस संबद्ध वस्तु के आयातों में भारत में उत्पादन और उपयोग दोनों के संबंध में वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में घरेलू उद्योग के उत्पादन के बल 7 प्रतिशत के थे जो वर्ष 2014-15 में दोगुने बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही तथा दूसरी तिमाही का तिमाहीवार विश्लेषण भी दर्शाता है कि आयातों की इस हिस्सेदारी में घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल मांग में भी आयातों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप अपना उत्पादन और अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं हुए। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता को भी नुकसान हुआ। इस संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण भारी कीमत अवमंदन, निग्रहण, अधोरदन और अधोविक्रयण हुआ है। वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में भी भारी क्षति हुई है। घरेलू उद्योग की मालसूची भी बढ़ी है। यह सभी कारक स्पष्टत: यह सिद्ध करते हैं कि इस मामले में कारणात्मक संबंधी मौजूद है। इस संबद्ध वस्तु के अचानक, तीव्र, पर्याप्त ओर अत्यधिक अभिनव अविध में आयातों में हुई वृद्धि के अलावा अन्य कोई ऐसे कारक नहीं हैं जिनसे घरेलु उद्योग को को क्षति हुई हो।
- ङ. विकासशील देशों को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। ब्राजील ने अपने लिखित प्रस्तुतिकरण के पैराग्राफ 29 से 31 तक यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने प्रत्येक निर्यातक देश के हिस्से की सूचना नहीं दी है और विकासशील देशों की सूची भी प्रदान नहीं कराई गई है। ब्राजील ने यह तर्क भी दिया है कि प्रत्येक स्रोत से आयातित मात्रा का परिकलन करने के लिए जिस अविध को ध्यान में रखा गया है उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी अनिवार्य सूचनाओं के अभाव में, ब्राजील यह तर्क देता है कि वह रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.1 के अंतर्गत अपनी रक्षा करने के अधिकार का उपयोग में सक्षम नहीं रहा। याचिकाकर्ता इस तर्क का विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि प्राधिकारी के पास प्रत्येक निर्यातक देश द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा रिकार्ड में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारी को अपने दिनांक 9 नवम्बर, 2015 के एक पत्र इसे स्पष्ट कर दिया है। इसलिए प्राधिकारी इस मामले की अंतिम जांच करते समय ओर इस सूचना को अपने अंतिम जांच परिणाम में अधिसूचित करते समय इसकी जांच कर सकते हैं। पुनश्च, ब्राजील अपने रक्षा के अधिकार के इस जांच के हर स्तर पर पूरी तरह से प्रयोग करने में समर्थ रहा है। इसलिए रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार कोई असंगतता नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त चूंकि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल आयातों में ब्राजील के आयातों की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से अधिक है इसलिए इसके रक्षोपाय शुल्क के दायरे से अपवर्जित नहीं किया जा सकता है।
- च. निष्कर्ष: ब्राजील ने अपने लिखित प्रस्तुतिकरण के पैरा 32 एवं 33 में यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को न तो कोई गंभीर क्षित हुई है और न ही उसके समक्ष गंभीर क्षित की कोई चुनौती उत्पन्न हुई है और इसमें कोई कारणात्मक संबंधी भी नहीं है। इसके अतिरिक्त, ब्राजील यह तर्क भी देता है कि इस मामले में औपचारिक आवश्यकताएं जैसे डब्ल्यूटीओ को अधिसूचना भेजना और अनिवार्य सूचना का विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़े विस्तृत रूप से यह सिद्ध करते हैं कि इस मामले में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षित हुई है और उसके समक्ष गंभीर क्षित की चुनौती भी उत्पन्न हो गई है। इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक, तीव्र, भारी एवं अभिनव वृद्धि तथा घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षित के बीच कारणात्मक संबंधी भी मौजूद हैं। भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ को इस साधन की अधिसूचना करने में हुई थोड़ी सी देरी का आशय यह नहीं लगाया जा सकता है कि अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना ही एसए के प्रावधानों से असंगत है। याचिकाकार्त यह प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले में सभी आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन किया गया जिससे हितबद्ध पक्षकारों को अपनी रक्षा करने के अधिकार प्रयोग करने में समर्थता प्राप्त हुई।

उपर्युक्त तर्कों के आलोक में, याचिकाकर्ताओं यह प्रस्तुत करते हैं कि ब्राजील के तर्कों में कोई दम नहीं है।

III. सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात चीन जन.गण. द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरणों का घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया प्रत्युत्तर

याचिकाकर्ता चीन जन.गण. द्वारा किए गए सभी तर्कों का विरोध करते हैं। चीन जन.गण. के प्रस्तुतिकरणों केवल सामान्य अभिकथन है और उनके समर्थन में कोई ठोस आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। याचिकाकर्ता चीन जन.गण. द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों पर अपना प्रत्युत्तर निम्नलिखित रूप में दायर करते हैं।

- क. ऐसे अनपेक्षित विकास हुए जिनके कारण भारत में इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक, तीव्र, भारी और अभिनव वृद्धि हुई। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में इस संबंध में एक विस्तृत विश्लेषण दिया है। चीन जन.गण. ने उस याचिका में दिए गए विश्लेषण को ध्यान से नहीं पढ़ा है।
- ख. यह याचिका और उसके साथ ही प्रारंभिक जांच परिणाम भी इस मामले में उन संवेदनशील परिस्थितियों पर प्रकाश डालती हैं जो रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए अधिपत्रित हैं। चीन जन.गण. ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। प्राधिकारी ने इस मामले में एसए के अनुच्छेद 6 की जरूरतों को पुरा किया है।

- ग. याचिका और प्रारंभिक जांच परिणाम स्वयं ही यह सिद्ध करते हैं कि इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक, तीव्र, भारी एवं अभिनव ऐसी वृद्धि हुई जिसके घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और घरेलू उद्योग के समक्ष गंभीर क्षति की चुनौती भी उत्पन्न हो गई है। इस मामले में कारणात्मक संबंध बिल्कुल स्पष्ट है। इस कारण चीन जन.गण. के तर्कों में कोई दम नहीं है।
- घ. यदि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जाता हे तो घरेलू उद्योग के लिए जीवित रहना ही असंभव हो जाएगा। अनुप्रवाही उद्योग का जनहित ही इस मामले में एकमात्र निकष नहीं हो सकता हे। भारतीय इस्पात उद्योग की इस संबद्ध वस्तु के आयातों में हुई अचानक तीव्र, भारी एवं अभिनव वृद्धि से रक्षा करना जनहित में है अन्यथा घरेलू उद्योग का सफाया हो जाएगा।
- ङ. अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का प्रतिसंहरण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी संवेदनशील परिस्िथतियों मौजूद हैं जो 200 दिनों के लिए अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क को जारी रखना वारंट करती है।

उपर्युक्त के आलोक में याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि चीन जन गण. के तर्कों में कोई दम नहीं है।

IV. सार्वजिनक सुनवाई के पश्चात चाइनीज ताइपेई के प्रस्तुतिकरणों पर घरेलू उद्योग का प्रत्युत्तर: याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि प्राधिकारी ताइवान के इस अनुरोध की जांच कर सकते हैं कि उसे एक विकासशील देश माना जाए और उस पर समुचित कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ताईवान से आपात 3 प्रतिशत से कम हैं या नहीं इसकी जांच रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़ों से की जी सकती है ओर उसके पश्चात ही कोई उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है। चूंकि ताइवान ने इस याचिका के गुणवगुण पर अथवा किसी अन्य पहलू पर कोई साक्ष्यांकित टिप्पणी नहीं की है इसलिए याचिकाकर्ताओं को ताइवान के लिखित प्रस्तुतिकरणों पर कोई अन्य टिप्पणी नहीं करनी है।

V. सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात यूरोपीय कमीशन के प्रस्तुतिकरणों पर घरेलू उद्योग का प्रत्युत्तर : याचिकाकर्ता यूरोपीय कमीशन द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों पर निम्नलिखित के पैराग्राफों में अपना प्रत्युत्तर देते हैं :

- क. कमीशन के शुरूआती पंक्तियों में यह प्रस्तुत किया है कि रक्षोपाय साधन का प्रयोग केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए और यह मामला पाटनरोधी जांच अथवा इस तर्क का विरोध करते हैं क्योंकि इस समय इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक, तीव्र, भारी और अभिनव वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग अत्यधिक नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। भारतीय इस्पात उत्पादकों को अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप हुए इन आयातों के कारण गंभीर क्षति सहन करनी पड़ रही है और आयातों में हुए इस अचानक प्रोत्कर्ष से अपनी रक्षा करने के लिए रक्षोपाय शुल्क ही एकमात्र उपयुक्त साधन है। इस कारण से घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए कोई आपात कार्रवाई करने हेतु प्राधिकारी से गुहार की है।
- ख. कमीशन के इस तर्क के संबंध में कि इस संबद्ध वस्तु के कुछ विशिष्ट ग्रेडों को इस उत्पाद के दायरे से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए क्योंिक घरेलू उद्योग उनका विनिर्माण नहीं कर सकता है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कमीशन यह अभिज्ञात करने में असफल रहा है कि वे कौन-कौन से ग्रेड है जिनका विनिर्माण घरेलू उद्योग नहीं कर सकता है और जिनके लिए अपवर्जन अपेक्षित है। विशिष्ट ग्रेडों के संबंध में सूचना न होने पर, याचिकाकर्ता ऐसे अस्पष्ट तर्क का खंडन कैसे कर सकता है। कमीशन को चाहिए कि वह इस संबद्ध वस्तु के उन सब ग्रेडों का स्पष्टीकरण दे जिनसे उसक संबंध है, अन्यथा प्राधिकारी को कमीशन का उपर्युक्त तर्क नामंजूर कर देना चाहिए।
- ग. कमीशन ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए कई मुद्दे उठाए हैं कि कोई क्षति अथवा कारणात्मकता नहीं है। कमीशन यह तर्क देता है कि वर्ष 2015-16 के वार्षिकीकृत आंकड़े प्रयोजन मुलक नहीं हैं और क्षति विश्लेषण तथा कारणात्मकता इन वार्षिकीकृत आंकड़ों के आधार पर निर्णायक नहीं हो सकती है। कमीशन यह तर्क देता है कि वर्ष 2015-16 के लिए किसी लंबी अवधि के आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए था। कमीशन यह तर्क भी देता है कि गंभीर क्षति और कारणात्मकता का निर्धारण करने के लिए बाजार हिस्सा, उत्पादन, क्षमता उपयोग दर रोजगार, लाभ, बाजार हिस्सा आदि सहित जिन कारकों पर विचार किया गया है, वह अपर्याप्त है और यह कारक घरेलू उद्योग को क्षति अथवा कारणात्मक का संकेतम नहीं देते है। याचिकाकर्ता इस कमीशन द्वारा उठान गए मुद्दों का विरोध करते हैं। गंभीर क्षति और कारणात्मक और याचिका में दिए गए तथ्यों एवं आंकड़ों से तथा 16 नवम्बर, 2015 के लिखित प्रस्तुतिकरणों से स्पष्टत: प्रमाणित है। याचिकाकर्ताओं ने इस जांच की निरंतरता के दौरान विस्तार से यह सिद्ध कर दिया है कि इस संबद्ध वस्तु के आयातों में भारत में उत्पादन और उपभोग दोनों से संगत रूप से भारी वृद्धि हुई है। इन आयातों की वर्ष 2013-14 में उत्पादन में हिस्सेदारी 7 प्रतिशत थी जो वर्ष 2014-15 में दोगुनी बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2014-15 का तिमाहीवार विश्लेषण और 2015-16 की पहली तिमाही तथा दूसरी तिमाही का तिमाहीवार विश्लेषण भी दर्शाता है कि आयातों की इस हिस्सेदारी में घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल मांग में भी आयातों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप अपना उत्पादन और अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं हुए। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता को भी नुकसान हुआ। इस संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण भारी कीमत अवमंदन, निग्रहण, अधोरदन और अधोविक्रयण हुआ है। वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में घरेलू उद्योग की

- लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में भी भारी क्षति हुई है। घरेलू उद्योग की मालसूची भी बढ़ी है। यह सभी कारक स्पष्टत: यह सिद्ध करते हैं कि इस मामले में कारणात्मक संबंधी मौजूद है। इस संबद्ध वस्तु के अचानक, तीव्र, पर्याप्त ओर अत्यधिक अभिनव अवधि में आयातों में हुई वृद्धि के अलावा अन्य कोई ऐसे कारक नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। इसके परिणामस्वरूप, रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(क) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
- घ. कमीशन का यह तर्क है कि ग्राही बिक्रियों तथा अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियों की भी जांच करनी चाहिए। इसके अितरिक्त, कमीशन ने यह भी कहा कि भारतीय उत्पादकों ने खुले बाजार में अपनी बिक्री 42 प्रतिशत बढ़ा दी है। याचिकाकर्ता इस तर्क का विरोध करते हैं और यह प्रस्तुत करते हैं कि अन्य भारतीय उत्पादकों की हिस्सेदारी समग्र रूप से बहुत कम हैं। इसके अलावा, आयातों ने संबद्ध वस्तु की इस बढ़ी हुई मांग पर अपना कब्जा कर लिया। वर्ष 2014-15 में मांग (ग्राही को छोड़कर) में 1158614 एमटी की वृद्धि हुई और आयातों में 1248015 एमटी की वृद्धि हुई। जब वर्ष 2014-15 में मांग (ग्राही सिहत) बढ़कर 25423206 एमटी हो गई और (ग्राही को छोड़कर) 15787601 एमटी हो गई तब आयातों में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई और वह 2540114 एमटी हो गए। यह उस आक्रामक ढंग को प्रदर्शित करता है जिसपर इस संबद्ध वस्तु के आयातों का भारत में प्रवेश हो रहा है। प्राधिकारी को कमीशन द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार घरेलू उद्योग के विकास के लिए और अधिक लंबी अविध तक प्रतीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग काफी लंबे समय पहले ही स्थापित हो गया था। घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर घरेलू उद्योग की स्थिति की निष्पक्ष एवं यथातथ्य तस्वीर प्रस्तुत कर रहे है।

उपर्युक्त तर्कों के आलोक में याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि कमीशन के तर्कों में कोई दम नहीं है।

VI. सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात इंडोनेशिया सरकार के प्रस्तुतिकरणों पर घरेलू उद्योग का प्रत्युत्तर : याचिकाकर्ता इंडोनेशिया के तर्कों पर अपना अधोलिखित प्रत्युत्तर प्रदान करते है :

- क. वर्ष 2013-14 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में आयातों की हिस्सेदारी 7 प्रतिशत थी जो वर्ष 2014-15 में दोगुनी बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2014-15 का तिमाहीबार विश्लेषण तथा 2015-16 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही का विश्लेषण भी दर्शाता है कि आयातों की हिस्सेदारी में घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 की कुल मांग में भी आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। इसलिए इंडोनेशिया का यह विश्लेषण गलत है। आयात वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) में लगभग दोगुने बढ़ गए।
- ख. याचिका तथा प्रारंभिक जांच परिणाम दोनों उन संवेदनशील परिस्थितियों पर विस्तृत प्रकाश डालते हैं जिनके कारण इस मामले में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना पड़ा। उक्रैन उस पर ध्यान देने में असफल रहा है। प्राधिकारी ने इस मामले में एसए के अनुच्छेद 6 की जरूरतों को पुरा किया है।
- ग. इंडोनेशिया ने यूएन कामट्रेड द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों पर भरोसा किया है जो सही नहीं है क्योंकि यह इस विचाराधीन उत्पाद के आंकड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इन आंकड़ों पर आधारित कोई भी आंकड़ा अस्पष्ट तस्वीर ही प्रस्तुत करेगा।
- घ. इंडोनेशियाई कंपनी पीटी क्राकटाऊ पोस्को को चाहिए कि वह भारत को किए गए अपने निर्यातों के पूर्ण आंकड़े याह साक्ष्यांकित करने के लिए प्रदान कराए कि उसने भारत को इस संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है। पुनश्च, इंडोनेशिया को ठोस आंकड़ों के आधार पर यह भी साक्ष्यांकित करना चाहिए कि उसके उत्पादकों/निर्यातकों ने भारत को इस संबद्ध वस्तु का कभी निर्यात नहीं किया है। यह आंकड़े याचिकाकर्ताओं को भी उनकी जांच करने और अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए प्रदान कराए जाने चाहिए। इन आंकड़ों के अभाव में इंडोनेशिया के इन दावों का कोई अर्थत नहीं है।
- ङ. घरेलू उद्योग मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप अपने उत्पादन और बिक्री में वृद्धि करने में असमर्थ रहा।
- च. भारत की निर्यात नीति और स्टील पर कस्टम्स ड्यटी में सामान्य वृद्धि अथवा कमी होना का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। याचिकाकर्ता इस बात के प्रति जागरूक हैं कि कोरिया आरपी, जापान जैसे कुछ एशियाई देशों और आशियान देशों जिनमें इंडोनेशिया भी शामिल है से आयात शुल्क की रियायती दरों पर हो रहे हैं। तथापि, यह केवल तथ्यात्मक सूचना है और इंडोनेशिया ने इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि इस सूचना का संबंध इस मामले से कैसे है।

VII. सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात रूसी परिसंघ द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का घरेलू उद्योग द्वारा प्रत्युत्तर : याचिकाकर्ता रूस के तर्कों का प्रत्युत्तर निम्नवत देते हैं :

क. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (1) में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी विकासशील देश से आयात की किसी मद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है यदि उस देश से आयातों में हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है ओर इन सब देशों से संचयी आयात एक साथ मिलाकर कुल आयातों का 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।

- याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में रूस एक विकसित देश है, इसलिए इसे रक्षोपाय शुल्क के दायरे से अपवर्जित नहीं किया जा सकता है।
- ख. इस मामले में रक्षोपाय शुल्क का अधियाचन करने के पर्याप्तकरण मौजूद हैं क्योंकि चीन जन.गण., कोरिया आरपी, और जापान से पर्याप्त आयात रक्षोपाय शुल्क का अधियाचन करते हैं।
- ग. याचिकाकर्ता विनम्रतापूर्व यह प्रस्तुत करते हैं कि डब्ल्यूटीओ सदस्य देश जैसे रूस का घरेलू उद्योग अथवा किसी अन्य देश के जांचकर्ता प्राधिकारी को यह बताने का अधिकार नहीं है कि इस मामले में रक्षोपाय साधनों की तुलना में पाटनरोधी शुल्क अथवा प्रतिवलनकारी शुल्क अधिक उपयुक्त होता। याचिकाकर्ताओं को इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक, तीव्र, भारी और अभिनव वृद्धि होने के कारण गंभीर क्षति हुई है। परिस्थितियां अत्यधिक संवेदनशील थीं और उनसे यह अधिपत्रित हो रहा था कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करके उस स्थिति से तत्काल निजात पाई जाए। भारत को भी कोरिया आरपी और जापान के साथ द्विपक्षीय तंत्र का समन्वेषण करना चाहिए या नहीं यह भारत सरकार के विवेक पर निर्भर करता है।
- घ. इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक, तीव्र, भारी और अभिनव वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग के आर्थिक निष्पादन में वास्तव में गिरावट आई है। याचिकाकर्ताओं ने इस जांच के दौरान विस्तार से यह सिद्ध किया है कि इस संबद्ध वस्तु के आयातों में भारत में उत्पादन और खपत दोनों के संबंध में वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में आयात केवल 7 प्रतिशत थे जो वर्ष 2014-15 में दोगुने होकर 14 प्रतिशत हो गए वर्ष 2014-15 का तिमाहीवार विश्लेषण और 2015-16 की पहली तिमाही तथा दूसरी तिमाही का तिमाहीवार विश्लेषण यह दर्शाता कि आयातों की इस हिस्सेदारी में घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल मांग में भी आयातों की हिस्सेदारी बढ़ी है। घरेलू उद्योग मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप अपना उत्पादन और अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं हुए है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता को भी क्षति हुई है। संबद्ध वस्तु के इन आयातों के कारण भारी कीमत निग्रहण, अवमंदन, अधोरदन और अधोविक्रयण हुआ है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और रोस में वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही दोनों में गहन गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की मालसूची भी बढ़ी है। यह सभी कारक स्पष्टत: इस मामले में कारणात्मक संबंध स्थापित करते हैं इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक, तीव्र, भारी और अभिनव वृद्धि होने के कारण के अलावा अन्य कोई ऐसा कारक नहीं है जिससे घरेल उद्योग को क्षति कारित हो रही हो।
- ङ. इस मामले में अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण संवेदनशील परिस्थितियों की पूर्ण जांच करने के पश्चात किया गया। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए यह जांच शुरू करके एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। प्राधिकारी की यह परम्परा रही है कि वह रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की जांच करते समय जनहित का ध्यान अवश्य रखते हैं। रक्षोपाय शुल्क की संस्तुति की जानी चाहिए या नहीं इसका निर्णय सभी पणधारियों की टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात ही लिया जा सकता है। इसलिए रूस को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या प्राधिकारी ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है या नहीं क्योंकि प्राधिकारी रक्षोपाय शुल्क की जरूरत का निर्णय तथ्यों एवं विचारों की कड़ी जांच करने के पश्चात ही लेते हैं।

उपर्युक्त के आलोक में याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते हैं कि रूस के तर्कों में कोई दम नहीं है।

VIII. सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात तुर्की गणराज्य के प्रस्तुतिकरण पर घरेलू उद्योग के प्रत्युत्तर : याचिकाकर्ता तुर्की के तर्कों का निम्नवत प्रत्युत्तर देते हैं :

- क. प्राधिकारी ने वह अनपेक्षित विकास देखा जिसकी वजह से इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक तीव्र भारी एवं अभिनव वृद्धि हुई है। इस प्रकार प्राधिकारी ने एसए के अनुच्छेद XIX के अंतर्गत अपेक्षित जरूरतों को पूरा किया है।
- ख. भारत ने एसए के अंतर्गत अधिसूचना की अपेक्षा के मुताबिक अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क की जांच शुरू करने और उदग्रहण करने के बारे में डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित किया था। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस अधिसूचना में अनपेक्षित विकास की विस्तृत जांच का उल्लेख नहीं है। इस अधिसूचना में प्राधिकारी की दिनांक 9 सितम्बर, 2015 के प्रारंभिक जांच परिणामों का अभिन्यक्त उल्लेख है। हितबद्ध पक्षकार और उनकी सरकारें इस प्रारंभिक जांच परिणाम को प्राधिकारी की वेबसाइट पर देख सकती है। प्राधिकारी की प्रारंभिक जांच परिणाम सहित भारत की डब्ल्यूटीओ को अधिसूचना बड़े स्पष्ट ढंग से विनिर्दिष्ट करती है कि इस मामले में अनपेक्षित विकास सहित सभी पैरामीटरों की जांच की गई है।
- ग. यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही के आधार पर याचिका में आंकड़ों का वार्षिकीकरण नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2015 की छमाही के आधार पर किया है जो इस जांच के रिकार्ड में उपलब्ध है। याचिकाकर्ताओं ने अब वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही के लिए आंकड़े भी अपने दिनांक 16 नवम्बर, 2015 को लिखित प्रस्तुतीकरणों के तहत प्रस्तुत कर दिए हैं। अब आंकड़ों का वार्षिकीकरण वर्ष 2015-16 के पहले छह महीनों के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इसमें भी यह दर्शाया गया है कि घरेलु उद्योग को गंभीर क्षति हुई है।

- घ. याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए क्षति पैरामीटरों का भी विधिवत रिकार्ड रखा है। प्राधिकारी ने भी इस सूचना का विधिवत सत्यापन किया है। प्राधिकारी को यह विवेकाधिकार है कि वह उस अवधि के आंकड़ों पर भी विचार करें और उसकी जांच करें। यह विश्लेषण पुन: दर्शाएगा कि घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है और यदि निर्णायक रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जाता है तो यह क्षति होना जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त, आयात आंकड़े यह नहीं दर्शाते हैं कि आयातों में मामूली वृद्धि हुई है बल्कि वह भारी वृद्धि के सूचक है। वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में आयातों में दोगुनी वृद्धि हुई। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2015-16 में यह आयात वर्ष 2014-15 की तुलना में दोगुने बढ़ जाएंगे जैसाकि वर्ष 2015-16 के पहले छह महीने के आंकड़ों से स्पष्ट होता है।
- ङ. वर्ष 2013-14 और 2014-15 की लाभप्रदता की जांच अकेले नहीं की जा सकती है। लाभप्रदता के आंकड़ों की जांच अभिनव अविध के लिए भी की जानी चाहिए। वर्ष 2015-16 की पहली दो तिमाहियों में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तीव्र कमी (613) ओर (1547) आई है। चूंकि आयात अभी भी भारी मात्रा में हो रहे है और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, इसलिए इसमें और भी अधिक कमी आएगी। इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक, तीव्र, भारी और अभिनव वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग क्षति विश्लेषण अविध के दौरान अपनी बिक्री बढ़ाने में असमर्थ रहा।
- च. इस विचाराधीन उत्पाद के लिए याचिका में यथाविनिर्दिष्ट घरेलू उद्योग के क्षति पैरामीटरों की भी जांच की जानी चाहिए। अलग-अलग याचिकाकर्ताओं की वार्षिक रिपोर्टों का आस-पास की परिस्थितियों का मूल्यांकन किए बिना संदर्भ दे देने मात्र से सही तस्वीर उभर कर नहीं आएगी।
- छ. याचिकाकर्ताओं ने इस संबद्ध वस्तु के सभी स्रोतों से आयातों के विस्तृत विवरण का रिकार्ड पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। प्राधिकारी उसकी जांच करके यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या तुर्की पर रक्षोपाय शुल्क का अर्धिरोपण करने से उसे अपवर्जित करना चाहिए या नहीं।
- ज. तुर्की का यह तर्क गलत है कि उसे रक्षोपाय शुल्क के दायरे से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वह एक विकासशील देश है। भारत ने दिनांक 14 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या 103/98-सीयूएस में तुर्की को विकासशील देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। इसलिए तुर्की को रक्षोपाय शुल्क के दायरे से अपवर्जित नहीं करना चाहिए।

उपर्युक्त के आलोक में याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते है कि तुर्की के तर्क में कोई दम नहीं है।

IX. सार्वजिनक सुनवाई के पश्चात उक्रैन के राजदूतावास द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों पर घरेलू उद्योग के प्रत्युत्तर : याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि उक्रैन ने घरेलू उद्योग के वर्ष 2011-12 के साथ-साथ वर्ष 2014-15 की अविध के लिए पैरामीटरों इंड-टू-इंड विश्लेषण किया है। इस तरह के चुनिंदा विश्लेषण से उल्टे सीधे प्रेक्षण निकलते हैं। डाभिनिकल रिपब्लिक – पालीप्रोपाइलीन बैग्स एंड टयुबुल फेब्रिक्स पर रक्षोपाय साधन में डब्ल्यूटीओ पैनल ने स्पष्ट नोट किया है कि अकेले इंड-टू-इंड विश्लेषण करना गलत है। इस पैनल रिपोर्ट के अनुसार जांचकर्ता प्राधिकारी को वर्ष-दर-वर्ष विश्लेषण पर भी विचार करना चाहिए जिससे कि घरेलू उद्योग के पैरामीटरों विभिन्नताओं की संपूर्ण जांच हो सके। चूंकि उक्रैन के सभी प्रस्तुतिकरण केवल इंड-टू-इंड विश्लेषण पर आधारित है इसलिए उक्रैन द्वारा उठाए गए सभी तर्क उपरिलिखित डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट से असंगत है। अकेले इंड-टू-इंड विश्लेषण गलत है। इंड-टू-इंड विश्लेषण के साथ-साथ वर्ष-दरवर्ष विश्लेषण करना, उपर्युक्त मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा स्थापित विधिसम्मत सही क्रियापद्धित है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में और दिनांक 16 नवम्बर, 2015 के अपने पत्र में इंड-टू-इंड तथा वर्ष-दर-वर्ष दोनों तरह के विश्लेषण किए हैं। उपर्युक्त विश्लेषणों के आधार पर निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किया जाता है:

- क. घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2013-14 में आयात 7 प्रतिशत थे जो वर्ष 2014-15 में दोगुने बढ़कर 14 प्रतिशत हो गए। वर्ष 2014-15 का तिमाहीवार विश्लेषण और वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही/दूसरी तिमाही का विश्लेषण दर्शाता है कि आयातों की इस हिस्सेदारी में घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2015-16 के दौरान कुल मांग में भी आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
- ख. घरेलू उद्योग मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप अपने उत्पादन और बिक्री में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ।
- ग. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री और लाभप्रदता में कमी आई है।
- घ. संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण कीममत अवमंदन, निग्रहण अधोरदन एवं अधोविक्रयण हुआ है।
- ङ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और रोस में वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की मालसूची में भी वृद्धि हुई है।
- च. इस मामले में यह सभी कारक कारणात्मक संबंध की स्पष्ट मौजूदगी सिद्ध करते हैं इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक, तीव्र, भारी और अभिनव वृद्धि होने के कारण के अलावा कोई अन्य ऐसे कारक नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों।

- छ. इस याचिका में यथा प्रारंभिक जांच परिणाम में उन संवेदनशील परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है जिनके कारण इस मामले में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना पड़ा। उक्रैन यह नोटिस नहीं कर पाया। प्राधिकारी ने एसए के अनुच्छेद 6 की सभी अपेक्षाओं को पूरा किया है।
- ज. उक्रैन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र से प्राप्त आंकड़ों पर भरोसा किया है जो गलत है क्योंकि वह आंकड़े इस विचाराधीन उत्पाद के आंकड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर किया गया कोई भी विश्लेषण गलत होगा।

उपर्युक्त तर्कों के आलोक में याचिकाकर्ता प्रस्तुत करते है कि उक्रैन के किसी भी तर्क में कोई जान नहीं है। अत: भारत ने एसए के अनुच्छेद 2.1, 4.1(क), 4.2(ख) और 6 का उल्लंघन नहीं किया है।

- X. सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात दिलिंगर हटेनवर्क के प्रस्तुतिकरणों की घरेलू उद्योग द्वारा प्रत्युत्तर : याचिकाकर्ताओं ने दिलिंगर हटेनवर्क द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का प्रत्युत्तर अधोलिखित पैराग्राफों में दिया है :
 - क. दिलिंगर ने यह प्रस्तुत किया है कि प्राधिकारी द्वारा उन्हें भेजे गए नोटिस में कंपनी का नाम "दिलिंगर एंड सालिजटर" लिखा है जबिक उनका सही नाम "दिलिंगर हटेनवर्क" है। पुनश्च, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिलिंगर इस संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने अथवा भारत को उसका निर्यात करने में अंतर्ग्रस्त नहीं है। दिलिंगर ने रिकार्ड में यह स्वीकार किया है कि वह हैवी स्टील प्लेट्स का उत्पादन करते हैं।
 - ख. याचिकाकर्ता प्राधिकारी दिलिंगर द्वारा किए गए उपर्युक्त दावे की यथार्थता की जांच करने और यह जांच करने का भी अनुरोध करते हैं कि क्या दिलिंगर इस संबद्ध वस्तु की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले किसी अन्य उत्पाद का उत्पादन कर रहा है जिसका उसने भारत को निर्यात किया हो। याचिकाकर्ता प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि यदि दिलिंगर द्वारा कोई अन्य सूचना प्रदान कराई जाती है तो उसकी जांच करने तथा उस पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए वह जानकारी याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाए।

XI. जेएफई स्टील कारपोरेशन, निसिन स्टील कंपनी लिमिटेड निप्पन स्टील एंड सुमिटोमों मेटल कारपोरेशन और कोबे स्टील लिमिटेड (जिनका उल्लेख "जापान की मिलों" के रूप में किया गया है) के प्रत्युत्तर जिनका प्रतिनिधित्व मैसर्स एजेडबी एंड पार्टनर्स द्वारा किया गया।

- क. जापानी मिलें घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरणों में किए गए सभी प्रकथनों को अस्वीकार करती है और यह प्रस्तुत करती हैं कि इस प्रत्युत्तर के किसी भी भाग को तथ्यों और घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरणों में दिए गए तर्कों की स्वीकृति के रूप में न पढ़ा जाए अथवा न माना जाए जब तक कि उन्हें इस प्रत्युत्तर में विशेष रूप से स्वीकार न किया जाए।
- ख. घरेलू उद्योग के सुनवाई पश्चात प्रस्तुतिकरण इस बात का पर्याप्त साक्ष्य प्रदान नहीं करते हैं जो इस संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में रक्षोपाय शुल्क जांच की शुरूआत करने के लिए आवश्यक हैं।
- ग. घरेलू उद्योग उस प्रकार की एचआरसी का विनिर्माण नहीं करता है जो जापानी मिलों द्वारा निर्यातित उत्पाद के पूर्णतया समरूप या समान हो।
- घ. घरेलू उद्योग ने एपीआई ग्रेड स्टील का अंतिम प्रयोग प्रतिस्थापनीयता के आधार पर अपवर्जन करने का अनुरोध किया है। इसी तरह, जापानी मिलों ने भी अनुरोध किया है कि उनके द्वारा विनिर्मित और निर्यातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों से प्रतिस्थापनीय नहीं है क्योंकि उन्हें अंतिम उपभोक्ता की अधिमानताओं और विनिर्देशनों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शित और टेलर्ड किया जाता हैं। इसलिए जापानी मिलों द्वारा आपूर्ति की गई एचआरसी का प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एचआरसी के समान अथवा प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी उत्पाद नहीं है। प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग उसी विशिष्ट एचआरसी का उत्पादन करता है जिसका जापानी मिलों द्वारा निर्यात किया जाता है और तदनुसार उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग कर दिया जाना चाहिए।
- ह. आयातों में वृद्धि की कोई संगत प्रवृत्ति नहीं है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि जेएसडब्ल्यू स्टील चीन से भारत को एचआरसी का लगभग 150000 एमटी का आयात कर रहा है, जिससे कि आयात आंकड़े कृत्रिम रूप से बढ़ जाएं। यदि आयातों में कोई वृद्धि है भी तो वह घरेलू बाजार में एचआरसी की बढ़ती मांग ओर एचआरसी की वैश्विक कीमतों में होती कमी और औद्योगिक उपयोक्ताओं की जरूरत को पूरा करने में पर्याप्त मात्रा ओर गुणवत्ता के उत्पादों की आपूर्ति करके घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण हुई है।

विवरण (ग्राही खपत को छोड़कर)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	66%	68%	71%	63%
अन्य घरेलू उत्पादों का बाजार हिस्सा	15%	17%	20%	21%
आयातों का बाजार हिस्सा	18%	14%	9%	16%

- च. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2011-12, 2012-13 ओर 2013-14 के दौरान लगातार वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में केवल 2014-15 के दौरान कमी आई थी। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा, ग्राही खपत को छोड़कर, वर्ष 2011-12 में 66 प्रतिशत था, यह घटकर वर्ष 2014-15 में 63 रह गया। जब कि अन्य घरेलू उत्पादों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है जो वर्ष 2011-12 में 15 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 21 प्रतिशत हो गया।
- छ. अन्य घरेलू उत्पादों की घरेलू बिक्रियां जो वर्ष 2011-12 में 1880877 एमटी थीं बढ़कर वर्ष 2013-14 में 2994323 एमटी और वर्ष 2014-15 में 329873 एमटी हो गई। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण आई है।
- ज. घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरणों के विपरीत, आयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2011-12 में 18 प्रतिशत था घटकर वर्ष 2013-14 में 9 प्रतिशत रह गया और वर्ष 2014-15 में फिर बढ़कर 16 प्रतिशत हो गया जो वर्ष 2011-12 के आयातों की तुलना में अभी भी कम था। यहां तक कि आयात आंकड़ों का वार्षिक विश्लेषण से भी आयातों के सतत प्रोत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं निकलता है। उदाहरण के लिए यह आयात जो अप्रैल 2014 में 153500 एमटी थे, घटकर मई 2014 में 98192 एमटी रह गए और अक्तूबर 2014 में यह बढ़कर 277891 एमटी हो गए और नवम्बर 2014 में यह आयात एक बार फिर घटकर 171927 एमटी रह गए।
- झ. घरेलू उद्योग के वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक के घरेलू उद्योग के लिखित प्रस्तुतिकरणों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों में निर्वाध रूप से वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 और 2014-15 के बीच बिक्रियों में हुई किसी भी कमी को घरेलू उद्योग की घरेलू बाजार में एचआरसी की बिक्री ग्राही खपत की ओर मोड़ने की इच्छा पर उपरोपित किया जा सकता है यह घरेलू उद्योग की ग्राही खपत जो 2013 में 4274000 एमटी थी, बढ़कर वर्ष 2014-15 में 5019741 एमटी होने से स्पष्ट हो जाता है।
- ज. घरेलू उद्योग की बिक्री जो वर्ष 2012-13 में 10039219 एमटी थी, मामूली सी बढ़कर वर्ष 2013-14 में 10342565 एमटी हो गई, जबिक आयात जो वर्ष 2012-13 में 2120996 एमटी थे घटकर वर्ष 2013-14 में 1292099 एमटी रह गए। डीआई घरेलू बाजार में एचआरसी की आपूर्ति बढ़ाने में अक्षम था, जो आयातों में भारी कीम से आए अंतराल को भर पाता। यह संवर्धित आयातों और घरेलू बिक्रियों के बीच सह-संबंध की कमी का एक स्पष्ट उदाहरण है।
- ट. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जो वर्ष 2014-15 की चौथी तिमाही में 4429604 एमटी था बढ़कर वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में 4456795 एमटी हो गया। यह नोट करना संगत होता कि जेएसडब्ल्यू, जो इन याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता/आवेदक है, ने क्षमता उपयोग में इस उद्योग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2014 की चौथी तिमाही में इसने अपने संयंत्र का प्रचालन 90 प्रतिशत रेटेड क्षमता पर किया। जेएसडब्ल्यू का राजस्व रन-रेट स्पष्टत: यह संकेत करता है कि इसका उपयोगि स्तर अन्यों की तुलना में अधिक था।
- ठ.
 इसके अतिरिक्त, स्टील अथारिटी आफ इंडिया ("सेल") जो इस जांच के याचिकाकर्ताओं में से एक है, ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 15.4 मिलियन टन (एमटी) हाट मेटल के उत्पादन की घोषणा की थी, जो वित्त वर्ष 2013-14 के उत्पादन से 7 प्रतिशत अधिक है और इसका बिक्री योग्य उत्पादन 13.5 एमटी था जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक था।
- ड. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में गिरावट, यदि कोई घरेलू उद्योग द्वारा अधिक मांग में वृद्धि के अनुरूप नई जोड़ी गई क्षमता के कारण आई है। इंडियन रेटिंग एवं रिसर्च (इंड-आरए) जिसे भारतीय स्टील विनिर्माताओं की क्षमता में गिरावट की उम्मीद थी, जबिक 12-14 मिलियन क्रूड स्टील क्षमता एफवाई 2016 तक आने की उम्मीद है जबिक मांग खपत में भारी वृद्धि नहीं हुई। रिपोर्ट में यह प्राप्त हुआ कि एफवाई 15 में कुछ भारतीय क्षमता एफवाई 10 की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक थी, जबिक घरेलू स्टील की खपत में वृद्धि हुई जिसमें एफवाई 11 के दौरान 11.9 प्रतिशत की भारी वृद्धि के बाद प्रति वर्ष 2.4 प्रतिशत की गिरावट विनिर्माण, पूंजीगत वस्तुओं और आटोमोबाइल उद्योग में

- आई मंदी के कारण हुई थी। इससे यह प्रदर्शित होता है कि डीआई की बढ़ी हुई मालसूची बढ़ते आयातों के दबाव के कारण नहीं बल्कि डीआई द्वारा अधिक उत्पादन के कारण हुई थी।
- ढ. घटा हुआ क्षमता उपयोग भी भारतीय स्टील मिलों की अकार्यकुशलता और अवसंरचना की चुनौतियों, बिल्डिंग डिजाइन तथा इंजीनियरिंग क्षमताओं एवं कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि से हुआ था।
- ण. उच्च आपरेटिंग व्यय को क्षमतमा निर्माण एवं सृजन में अक्षमता भू-अधिग्रहण एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस के कारण उनकी परियोजनाओं की विलंब से क्रियान्वयन, सरकार द्वारा कम या शून्य ऋण सहायता, वैश्विक कीमत में कमी के प्रति विगोपन, अन्य देशों से कीमत ओर गुणवत्ता दोनों ही रूपों में प्रतिस्पर्धी उत्पादन, लौह अयस्क की लो-क्वालिटी जिसके लिए अधिक कोयले की जरूरत होती है और कोयले की न्यून गुणवत्ता पर उपरोपित किया जा सकता है।
- त. यह वह चुनौतियां हैं जिनका समाधान आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करके नहीं किया जा सकता है। यह नोट करने योग्य है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात भी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने जेएसडब्ल्यू लिमिटेड के आउटलुक को इस नवम्बर में ऋणात्मक करार दे दिया और फिच रेटिंग्स ने भी यह प्रेक्षण किया है कि कुछ स्टील उत्पादों पर रक्षोपाय शुल्क स्टील सेक्टर में सुधार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
- थ. डीआई ने सुनवाई पश्चात प्राधिकारी के समक्ष किए लिखित प्रस्तुतिकरण के अगोपनीय पाठ पर भारी गोपनीयता का दावा उसकी अनबिक्री माल सूची के संबंध में किया है। डीआई ने भी यह आंकड़े प्रदान नहीं किए कि डीआई अपनी मालसूची की बिक्री करने के लिए कितना समय लेगा ताकि "मालसूची पर दिनों की बिक्री" मूल्य का सुनिश्चयन किया जा सके। आंकड़ों के अभाव आलोक में प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह डीआई से स्पष्ट सबूत देने को कहे।
- द. डीआई ने इस तथ्य के बावजूद कि सभी कंपनियां सूचीबद्ध कंपनियां हैं वास्तविक आंकड़ देने के बजाय लाभ के अनुक्रमित आंकड़े दिए हैं।
- ध. डीआई को ऐसा सकारात्मक ही नहीं रहा परंतु इसने वित्त वर्ष 2012-13 की तुलना में वित्त वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में सुधार एवं पुनर्बहाली के आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं।
- न. डीआई द्वारा अपने प्रस्तुतिकरणों में किए गए अनपेक्षित विकास न तो प्रत्याशित है, न तर्कसंगत और न ही उपयुक्त और प्राधिकारी यह दिखाने में भी अक्षम रहा है कि कथित अनपेक्षित विकास के कारण ही इस विचाराधीन उत्पाद के विशिष्ट उत्पादों के आयातों में प्रोत्कर्ष आया।
- प. डीआई ने स्टील के संबंध में समग्र रूप से सामान्य तर्क दिए हैं जो स्पष्टत: पीयूसी नहीं है और यह पीयूसी के अंतर्गत प्रत्येक विशिष्ट उत्पाद का निराकरण करने में सक्षम हुआ है। डीआई द्वारा उल्लिखित कथित विकास का वैश्विक परिदृष्य है और इस कारण उनका प्रभाव केवल "भारत विशिष्ट" नहीं है।
- फ. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना भारत-कोरिया सीईपीए के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धताओं से असंगत है। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ सकता है और भारत में जापान से अगले किसी निवेश के न होने की जोखिम भी है।
- ब. उपर्युक्त के आलोक में प्राधिकारी इस जांच को खारिज दें और प्रारंभिक जांच परिणाम वापस ले लें तथा इस पीयूसी पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण समाप्त कर दें। वैकल्पिक रूप में प्राधिकारी जापान की मिलों द्वारा निर्यातित हाट रोल्ड काइल्स का इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन कर दें जैसाकि सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात दिनांक 23 नवम्बर, 2015 के लिखित प्रस्तुतिकरण के अनुबंध 1 में अभिज्ञात है क्योंकि जापान की मिलों द्वारा निर्यातित उत्पाद भारत में इन उत्पादों से क्वालिटी और विनिर्देशन दोनों रूपों में भिन्न हैं।

XII. निप्पन स्टील एंड सुमिकिन पाइप इंडिया कंपनी लिमिटेड (एनपीआई) का प्रत्युत्तर जिसका प्रतिनिधित्व मैसर्स एजेडबी एंड पार्टनर्स द्वारा किया गया था।

- म. डीआई के सुनवाई पश्चात प्रस्तुतिकरणों में इस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि संबद्ध वस्तु के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क जांच की शुरूआत करना आवश्यक है।
- य. डीआई उस प्रकार की एचआरसी का विनिर्माण नहीं करते हैं जो एनपीआई द्वारा आयातित उत्पादों के समरूप अथवा समान हो।
- कक. डीआई ने एपीआई ग्रेड स्टील का अंतिम उपयोग प्रतिस्थापनीयता के आधार पर अपवर्जन करने का अनुरोध किया है। इसी तरह, एनपीआई भी अनुरोध करता है कि उनके द्वारा आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद से

प्रतिस्थापनीय नहीं है क्योंकि इनका मार्गदर्शन अपने अंतिम प्रयोक्ताओं की अधिमानताओं और विनिर्देशनों के अनुरूप किया जाता है। इसलिए एनपीआई द्वारा जिस प्रकार की एचआरसी का आयात किया जाता है डीआई द्वारा उत्पादित एचआरसी के समान अथवा प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी उत्पाद नहीं है। प्राधिकारी को यह जांच करना चाहिए कि क्या डीआई-एनपीआई द्वारा आयातित एचआरसी के विशिष्ट ग्रेडों का विनिर्माण कर रहा है और तदनुसार ही उसे इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग कर देना चाहिए।

- खख. एनपीआई के ग्राहक मूल उपकरण विनिर्माता और टायर 1 पार्टस विनिर्माता हैं जो *** सहित आटोमोबाइल विनिर्माताओं को पार्टस की आपूर्ति करते हैं। एनपीआई के ग्राहकों उच्च कस्टुमाइज्ड उत्पादों की जरूरत होती है जिनका ग्राहकों द्वारा अनुमोदन किए जाने से पहले जापान में विभिन्न स्तर का परीक्षण किया जाता है। एनपीआई बहुत विशिष्ट प्रकार की एचआरसी का आयात करता है जिसकी भारत में इसके ग्राहकों द्वारा आटोमोटिव पाइप्स और ट्यूब्स का निर्माण करने में जरूरत पड़ती है।
- गग. एनपीआई द्वारा जापान से जिन विनिर्देशनों के उत्पादों का आयात किया जाता उनका घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है अथवा उन्हें स्थानीय उपलब्धता होने के बावजूद अंतिम ग्राहक से अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है।
- घघ. एनपीआई द्वारा भारत में आयातित एचआरसी "टेन्साइल स्ट्रेंथ", "स्टील क्लीननेस", "ग्रेन साइज" और "कैमिकन कम्पोजीशन" (खासकर नत्रजन, नियंत्रित रेंज घरेलू से कहीं अधिक संकुचित है) में भिन्न होती है, इन सबकों अंतिम प्रयोक्ता द्वारा विनिर्धारित विनिर्देशनों के अनुरूप बनाया जाता है। भारत में आयातित प्रत्येक उत्पाद प्रकार की अत्यधिक विशिष्ट एवं विशेषीकृत प्रकृति होने के कारण, छोटा सा अंतर भी क्वालिटी में भारी अंतर ला सकता है।
- ङङ. डीआई सभी प्रकार की आटोमोटिव ग्रेड स्टील का विनिर्माण नहीं करता है और यह कि औद्योगिक प्रयोक्ताओं को अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए इसका आयात करना अनिवार्य है। इस पीयूसी का भारत में आयात किया जाना अनुप्रवाही आटो उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
- चच. एनपीआई आटोमोटिव पाइप्स का विनिर्माण करने में प्रयोग की जाने वाली ऐसी एचआरसी का आयात करता है जिसे घरेलू स्टील विनिर्माता (1) पर्याप्त गुणवत्ता विनिर्देशनों सिहत प्रदान कराने में अक्षम हैं अथवा (2) उन्होंने अंतिम प्रयोक्ता (अर्थात आटोमोबाइल विनिर्माताओं) से अनुमोदन नहीं प्राप्त किया है। इन आयातित काइल्स का अधिकांश भाग आटोमोटिव पार्टस में प्रयोग किए जाने वाले आटोमोटिव पाइप्स और ऐसे पार्टस का विनिर्माण करने में कच्चे माल की तरह प्रयोग किया जाता है जो वाहन के वजन को कम करने ईंधन बचत और आटोमोबाइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं।
- छछ. यह कड़े विनिर्देशन आटोमोटिव पार्टस की फार्मेबिलिटी, ऐपीयरेंस और आकार की संगतता से संबंधित होते हैं। निप्पन स्टील और सुमिटोमों मेटल कारपोरेशन ("एनएसएसएमसी") जो इस एनपीआई की पैरंट कंपनी है और हाट रोल्ड काइल्स का उत्पादक एवं निर्यातक है, इन विनिर्देशनों को उनके कैमिकल कम्पोजीशन को यथातथ्य रूप से नियंत्रित करके, मैकेनिकल गुणधर्म, उत्पाद की सरफेस क्वालिटी और साइज देकर पूरा करता है। अत:, जब एनपीआई को इन विशेष काइल्स का आयात करने की जरूरत पड़ती है तो वह एनएसएसएमसी द्वारा उत्पादित काइल्स का ही आयात करता है। इन विशिष्ट काइल्स के अलावा एनपीआई आटोमोटिव पाइप का उत्पादन करने के लिए अन्य सामग्री का प्रापण भारत के घरेलू स्टील विनिर्माताओं से करता है।
- जज. एनपीआई घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सभी एचआरसी प्रयोग करने में सक्षम नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादों के लिए औद्योगिक प्रयोक्ता अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि अंतिम ग्राहक द्वारा किसी आपूर्तिकर्ता का एक बार चयन कर लिए जाने पर वह अपने माडल में उत्पाद क्वालिटी में लाइफ टाइम संगतता बनाए रखने और आपूर्ति संविदाएं दीर्घकालीन अविध की होने के कारण आपूर्तिकर्ता को बदल नहीं सकता है। यदि रक्षोपाय साधन अधिरोपित किए जाते हैं, तो आटोमोटिव प्रयोक्ता इस पीयूसी का उच्चतर कीमतों पर आयात करना जारी रखेंगे और उन्हें अधिक कीमत का भगतान करना पड़ेगा जिसका भार ग्राहकों पर पड़ेगा।
- झझ. डीआई ने जापान से एनपीआई द्वारा भारत में आयात किए जा रहे विशिष्ट प्रकार के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पादों का वास्तविक विनिर्माण का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यह स्थापित करने के लिए कि इन उत्पादों का उनके द्वारा विनिर्माण किया गया था डीआई को अपने उत्पाद की आयातित हाट रोल्ड फ्लैट उत्पादों से समानता (सभी रूपों में) की समुष्टि की तकनीकी सूचना देनी होगी। इस अत्यावश्यक जरूरत के संबंध में डीआई की असफलता चल रही जांच के लिए घातक है और केवल इस कारण से ही इस जांच को समाप्त कर देना चाहिए।
- ञञ. इस प्रस्तुतिकरण के होते हुए भी एनपीआई यह प्रस्तुत करते हैं कि उनके द्वारा आयातित एचआरसी घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों से भिन्न है। एनपीआई द्वारा आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों से उनके भौतिक गुणधर्म, कैमिकल कम्पोजीशन एवं इंड यूसेज के रूप में भिन्न है। विशेष रूप से, एनपीआई द्वारा भारत में आयातित

एचआरसी "टेन्साइल स्ट्रेंथ", "स्टील क्लीननेस", "ग्रेन साइज" और "कैमिकन कम्पोजीशन" (खासकर नत्रजन, नियंत्रित रेंज घरेलू से कहीं अधिक संकृचित है) में भिन्न होती है।

टट. इसलिए एनपीआई प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि टोर्शनबीम डोर इम्पैक्ट बीम, आटोमोबाइल्स में स्टैबिलाइजर्स, मोटर बाइक्स में फ्रष्ट फोर्क्स का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त उत्पादों और एनपीआई द्वारा आयातित अन्य उत्पादों जिनकी सूची सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात एनपीआई द्वारा के दिनांक 23 नवम्बर, 2015 के लिखित प्रस्तुतिकरण को गोपनीय पाठ के अनुबंध-1 में दी गई है, के आयातों को इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए। इन आयातों का या तो घरेलू उद्योग द्वारा इस पीयूसी के भारतीय औद्योगिक उपयोक्ताओं द्वारा अपेक्षित क्वालिटी विनिर्देशनों सहित स्थानीय रूप से उत्पादन नहीं किया जाता है अथवा उन्हें ओईएम ने अभी तक अनुमोदन नहीं दिया है।

XIII. चाइना आयरन एंड स्टील एसोसिएशन; अनगांग ग्रुप हांगकांग कंपनी लिमिटेड; अनगांग स्टील कंपनी लिमिटेड; शंघाई मैशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड; अनगांग ग्रुप इंटरनेशनल ट्रेड कारपोरेशन; बाओस्टील सिंगापुर पीटीई लिमिटेड; मानशान आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड; बैन्स्की आयरन एंड स्टील (ग्रुप) इंटरनेशनल इकानामिक एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड; जिआंग्सु सागांग ग्रुप; हांडान आयरन एंड स्टील ग्रुप कंपनी लिमिटेड और रिझाओ स्टील वायर कंपनी लिमिटेड, जिसका प्रतिनिधित्व मैसर्स एथेना लॉ एसोसिएट्स द्वारा किया गया।

- क. उपर्युक्त कंपनियों ने अपने पिछले प्रस्तुतिकरणों में किए गए निवेदनों को संक्षिप्तता के कारण दोहराया नहीं गया है।
- ख. आवेदक ने अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में भारी गोपनीयता का सहारा लिया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को निस्सार संक्षिप्तीकरण प्रदान कराए गए हैं। आवेदन ने संवेदनशील मुद्दों पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया को विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों को न्युनतम सुचना देने तक प्रतिबंधित करके इसे एक निरर्थक कार्रवाई बना दिया है।
- ग. आवेदक अर्थक्षम एवं भरोसेमंद समायोजन योजना पर बिल्कुल चुप हैं। आवेदकों ने यह उल्लेख िकया है कि उन्होंने अपनी याचिका के पृष्ठ 39 पर उत्पादक प्रश्नावली प्रत्युत्तर के साथ एक समायोजन पोनजा अलग से प्रदान कराई है परंतु उत्पादक विशिष्ट प्रश्नावली याचिका का भाग नहीं है परंतु यह एक पृथक दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक विशिष्ट प्रश्नावली में भी भरोसेमंद समायोजन योजना नहीं है। यूनाइटेड फास्फोरस द्वारा रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कराने के लिए 1999 में दायर एक आवेदनपत्र में प्राधिकारी ने समायोजन योजना न होने के आधार पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से मना कर दिया था।
- घ. प्रारंभिक निर्धारण में तात्कालिकता एवं संवेदनशील परिस्थितियां दर्शाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण प्रारंभिक शल्क का अधिरोपण करना अधिपत्रित हो।
- ङ. उत्पाद दायरे में कई विशिष्टता ग्रेड हैं जो सजातीय मदें नहीं हैं जिन्हें एक ही श्रेणी में रखा जा सके। शुल्क की प्रवंचना रोकने के लिए उत्पाद के दायरे में विस्तार करना न तो उपचार है और न ही यह अनुमेय तरीका है।
- च. आवेदक को कथित क्षति की स्थिति विवादित होने के कारण अन्य उत्पादकों को भी क्षति संबंधी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है।
- छ. कथित क्षति तो उच्च ब्याज भार, क्षमता दबाव, पाटन, एफटीए, कच्चे माल का संकट, आदि के कारण स्वनिर्मित है जिसकी वजह से आवेदक पर दबाव बढ़ गया जैसाकि उसकी वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है।
- ज. अधोलिखित बिंदु यह सिद्ध करते हैं कि आवेदक को न तो गंभीर क्षति हो रही है और न ही उसके समक्ष गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही है :
 - (i) उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, मालसूची, रोजगार, उत्पादकता और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (रोस) जैसे प्रमुख पैरामीटरों में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है।
 - (ii) भारतीय उत्पादकों का 88 प्रतिशत घरेलू मांग पर कब्जा है और आयात केवल 12 प्रतिशत जो घरेलू उद्योग को क्षतिकारित करने में सक्षम नहीं है।
 - (iii) कथित क्षति बेशी क्षमता के कारण उच्च ब्याज और नियम लागत बोझ की वजह से हुई है।
 - (iv) आयातित उत्पाद से कीमतों का कोई दबाव नहीं क्योंकि आयातों की उतराई कीमत बिक्री कीमत से अधिक है।
 - (v) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उतराई कीमत से कम होने के कारण इस बात का प्रथम दृष्टया संकेत है कि भारतीय उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा है।

- झ. आवेदकों ने कीमत अधोरदन/अधोविक्रयण की संगणना करने के लिए उतराई कीमत की क्रियापद्धित पर कुछ दावे किए हैं जिनका कोई तथ्यात्मक या विधिक आधार नहीं है। उतराई कीमत की संगणना संगत प्रथा के अनुरूप की जानी चाहिए।
- ञ. आवेदक ने अनपेक्षित विकास के संबंध में 4 उदाहरण दिए हैं और उनमें से 3 उदाहरण पाटनरोधी शुल्क के है। आवेदकगण अनपेक्षित विकास को सिद्ध करने में असफल रहे जिनके कारण आवेदक को तथाकथित क्षति की स्थिति पैदा हो गई।
- ट. रूस, उक्रैन, चीन और ईयू से आयातों से वृद्धि भू-राजनीतिक दबाव, अत्यधिक क्षमता और मुद्रा अवमूल्यन के कारण हुई है, इसे अनपेक्षित विकास कहा गया है। तथापि, उक्त देशों से आयातों के शेयर की प्रवृत्ति आवेदक के प्रस्तुतिकरण के विपरीत हैं :-

देशों की हिस्सेदारी	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (पहली तिमाही)
चीन	18.94%	14.01%	24.06%	28.65%	14.72%
ईयू-27	15.82	10.38%	1.20%	0.67%	0.74%
जापान	18.34%	29.25%	36.50%	30.79%	35.15%
कोरिया	14.94%	18.53%	12.97%	25.70%	41.11%
रूस	12.88%	10.56%	3.62%	5.55%	4.56%
उक्रैन	7.92%	0.67%	6.34%	3.08%	3.63%

- ठ. उपर्युक्त आंकड़े पर दर्शाते हैं कि चीन से आयातों में वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2015-16 (पहली तिमाही) में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आई है)। इसलिए अनपेक्षित विकास के कारण चीन से आयातों में अचानक और तीव्र वृद्धि नहीं हुई।
- ड. आवेदकों ने ऐसे किसी कारण का उल्लेख नहीं किया जिसके लिए उन्हें अपने उत्पाद की बिक्री आयात की कीमत की तुलना में कम कीमत पर करने के लिए मजबूर होना पड़ा जबकि कीमतें अधिक बनाए रखने के पर्याप्त अवसर थे।
- ढ. जेएसडब्ल्यू की वार्षिक रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि अन्य कारणों का उनके निष्पादन पर भारी प्रभाव पड़ा। प्राधिकारी द्वारा इन अन्य कारणों की जांच गैर-उपरोपण विश्लेषण के अंतर्गत की जानी चाहिए।
- ण. इसलिए कोई कारणात्मक संबंध नहीं है जैसाकि वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि क्षति का कारण पाटन है और एफटीए प्रणाली, कीमत अधोरदन से संबंधित मुद्दे भी ऋणात्मक है, क्षति का दावा वर्ष 2015-16 में किया गया जब आयात कम हो रहे थे, आयातों में वृद्धि 2014-15 में नई, उस समय घरेलू उद्योग को लाभ हुआ। किसी कथित क्षति का कारण पूर्णतया अन्य कारण है और आयातों को अचानक एवं तीव्र वृद्धि से ऐसी कोई क्षति नहीं हुई है।

XIV. पोस्को कोरिया और पोस्को महाराष्ट्र स्टील प्राइवेट लिमिटेड के प्रत्युत्तर, जिनका प्रतिनिधित्व शार्दूल अमरचंद मंगलदास द्वारा किया गया।

- क. पक्षकारों ने अपने सभी पिछले प्रस्तुतिकरणों पर भरोसा किया है।
- ख. याचिका में प्रदान कराए गए आंकड़े किसी प्रामाणिक स्रोत से नहीं हैं। यह याचिका एक गैर-सरकारी एजेंसी से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है न कि जेपीसी के आंकड़ों पर। जेपीसी आंकड़े आवेदकों द्वारा और टाटा स्टील द्वारा प्रदान कराए गए सूचना पर आधारित है।
- ग. क्षति विश्लेषण केवल वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही के लिए प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया और वर्ष 2013-14 को आधार वर्ष के रूप में चुना गया जो कि स्टील उद्योग के इतिहास में सबसे खराब वर्ष है।
- घ. आयातित पीयूसी की मात्रा और पेस्को द्वारा उपभोग की गई ग्राही की मात्रा का आयातों के बाजार हिस्से का परिकलन करते समय अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए।

ङ. आवेदकगण इस पीयूसी का लगभग 34 प्रतिशत अपनी अनुप्रवाही वस्तु का उत्पादन करने के लिए ग्राही रूप से उपभोग करते हैं और इसलिए पीयूसी की उक्त मात्रा घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करती है और इसका बाजार में पीयूसी की कुल मांग से अपवर्जन कर देना चाहिए प्राधिकारी ने सोडियम डाइ-क्रोमेट के आयातों से संबंधित एक रक्षोपाय जांच में समान परिस्थितियों पर जांच खारिज कर दी थी।

	घरेलू बिक्रिया	ग्राही खपत	ग्राही रूप से उपभोग की गई पीयूसी का प्रतिशत
2013-14	10,342,565 एमटी	4,274,000 एमटी	30%
2014-15	9,949,214 एमटी	5,019,741 एमटी	34%

- च. आवेदकगण इस पीयूसी के आयातों पर लागू कस्टम ड्यूटी की उच्च दर के रूप में संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं।
- छ. इस पीयूसी का दायरा बहुत लंबा है और उप-शीर्षक संख्या 7225 एवं 7208 के अंतर्गत आने वाले उत्पाद समरूप उत्पाद नहीं हैं और वे प्ल्युरल तथा विषमांग प्रकृति के हैं। इसलिए उन्हें एक साथ नहीं रखा जा सकता है।
- ज. इस पीयूसी के आयातों का इंड-टू-इंड प्वाइंट विश्लेषण आयातों के प्रोत्कर्ष का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त क्रियापद्धति नहीं है। यूएस सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स के जांच परिणाम यह स्पष्ट कर देते हैं कि आयातों में वृद्धि की जांच केवल अंतिम बिंदु तक ही प्रतिबंधित नहीं रहनी चाहिए बल्कि तथ्यों की एक व्यापक जांच की जानी चाहिए।
- झ. पोस्को द्वारा आयातित इस पीयूसी की मात्रा को पीओआई के दौरान पीयूसी के आयातों में अचानक प्रोत्कर्ष का मूल्यांकन करते समय अपवर्जित कर देना चाहिए। पोस्को महाराष्ट्र इसके द्वारा आयातित पीयूसीस के 90 प्रतिशत की ग्राही रूप से खपत करता है और वह घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। आयात आंकड़ों में व्यापारी बाजार में सीधी बिक्री के लिए किए गए आयातों को ग्राही खपत के लिए प्रयोग की गई मात्रा से अलग रखना चाहिए। पोस्को महाराष्ट्र ने पोस्को कोरिया से वर्ष 2014 में 427800 एमटी और वर्ष 2015 की पहली तिमाही में 118132 एमटी का आयात किया जिसमें से अधिकांश की ग्राही रूप से खपत की गई। यदि इस मात्रा को आयातों की कुल मात्रा से हटा दिया जाता है तो आयातों में कोई प्रोत्कर्ष नहीं होगा। ग्राही खपत का साक्ष्य फार्म ईआर-1 में प्रदान करा दिया गया है।
- ञ. प्राधिकारी अपनी प्रारंभिक जांच परिणाम में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से के प्रतिशत और आयातों के बाजार हिस्से का प्रतिशत निकालने के लिए परिकलन का समरूप तरीका अपनाने में असफल रहे हैं। घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों की ग्राही खपत को बाजार में इस पीयूसी की कुल मांग का परिकलन करते समय मिला दिया गया है परंतु घरेलू उद्योग की ग्राही खपत का अपवर्जन बाजार हिस्से का परिकलन करते समय नहीं किया गया है। इसलिए, ग्राही खपत का समावेशन करके कुल मांग को बढ़ा दिया गया है ओर बाजार हिस्से को घटा दिया गया है तथा ग्राही खपत का समावेशन करके उसे विकृत कर दिया गया है।
- ट. आवेदकों द्वारा खोए बाजार हिस्से को घरेलू उत्पादकों द्वारा पुन: प्राप्त कर लिया गया है।
- ठ. आवेदकों को कारित कथित क्षति स्वयं मृजित की हुई क्षति है। घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आवेदकों द्वारा आपूरित पीयूसी की क्वालिटी के कारण आई है। घरेलू उद्योग द्वारा आपूरित पीयूसी का पोस्को द्वारा उन उद्योगों के लिए विनिर्माण करने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है जिन्हें न्यून क्वालिटी की चीजों की जरूरत होती है जैसे निर्माण और सामान्य इंजीनियरिंग। सामना किए गए क्वालिटी मुद्दों से संबंधित प्रदर्श प्रदान कराए गए हैं और वह ग्रेड भी बताएं गए हैं जिनके लिए क्वालिटी अपेक्षाओं की जरूरत नहीं पड़ती है।
- ड. घरेलू उद्योग की बिक्री में कथित गिरावट के कुछ मुख्य कारण है : (क) कम उपयोग (ख) उच्च ऋण/वित्त लागत (ग्राही बहुल उद्योग होने के कारण); (ग) घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात किए जाने पर पीयूसी की कीमत वैश्विक बाजार की कीमतों के अनुरूप होना; (घ) घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी की बिक्री किए जाने पर उसकी कीमत वैश्विक/ अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक होना।
- ढ. आयातों की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है जैसाकि नकारात्मक कीमत अधोरदन से स्प्ष्ट है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय बाजार में पहुंच बनाने के लिए आयातों का स्तर कम नहीं किया गया।
- ण. रक्षोपाय कार्रवाई एक निष्पक्ष व्यापार साधन है और इस साधन का अधिरोपण करते समय देशों के इसकी आपवादिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखना चाहिए। इसका प्रयोग केवल आपातसरिथित में ही करना चाहिए।
- त. आवेदकों द्वारा अनपेक्षित विकास के लिए जिन दावों पर भरोसा किया गया है जैसे विश्व स्टील बाजार में संकट, भू-राजनीतिक तनाव, मुद्रा का अवमूल्यन, चीन में मंदी, चीन और जापान में भारी बेशी क्षमताएं अन्य देशों द्वारा अपनाए गए

- व्यापार साधन आदि अनपेक्षित विकास की मौजूदगी को स्पष्ट नहीं करते हैं। उपर्युक्त परिस्थितियों और अनपेक्षित विकास के बीच कोई विधिक संबंध नहीं है।
- थ. शुल्क का अधिरोपण करना इंडिया कोरिया सीईपीए का स्पष्ट उल्लंघन करना होगा। सीईपीए के अनुच्छेद 22.7 में यह अधिदेश है कि गाट 1994 के अनुच्छेद XIX और रक्षोपाय करार के अंतर्गत रक्षोपाय साधनों का प्रयोग करने वाला पक्षकार यथासंगत सीमा तक डब्ल्यूटीओ करार के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा, यदि उन आयातों के किसी गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का प्रमाण नहीं मिलता है तो अन्य पक्षकार की उदयवनकारी वस्तु का अपवर्जन करेगा। इस पीयुसी के कोरिया से होने वाले आयात इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
- द. इस पीयूसी के आयात वैश्विक कीमतों पर किए गए जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारतीय एचआर काइल्स के उत्पादकों ने भी इस उत्पाद का निर्यात वैश्विक कीमतों पर किया था, जो कि घरेलू कीमतों से कम है; इससे स्पष्ट है कि घरेलू बाजार में कमी बनी रही और कीमतें अधिक रहीं।

XV. सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात घरेलू उद्योग के प्रस्तुतिकरणों पर भारतीय उद्योग परिसंघ का प्रत्युत्तर

- क. 1.2 एमएम, 1.4 एमएम और 1.6 एमएम की मोटाई की एचआर काइल्स के आयात, क्योंकि इस मोटाई के काइल या तो घरेलू स्टील उत्पादकों द्वारा उत्पादित नहीं किए जाते हैं या कम उपलब्ध हैं, को रक्षोपाय शुल्क अधिसूचना में छूट की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
- ख. आटोमोबाइल्स अनुप्रयोग के लिए आयातित एसएसई 1541, एसएई 1020/1040/ 1050/1055 एससीएम 435, बोरोन स्टील, 16 एमएनसीआर 5, एसएई1006/1010 और एसटी 52.3 जैसे ग्रेडों के एचआर काइल्स को, जिनकी घरेलू उपलब्धता न केवल सीमित है बल्कि त्रुटिपूर्ण भी है, रक्षोपाय शुल्क अधिसूचना के अंतर्गत छूट की श्रेणी में रखना चाहिए।
- ग. वे एचआर काइल्स जिनके लिए आयात संविधाएं हस्ताक्षिरत कर दी गई और जिनके लिए एसजीडी अधिसूचना जारी होने की तारीख से पहले ही अप्रतिसंहरणीय वित्तीय व्यवस्थाएं कर दी गई थीं और आयातित सामग्री भी मार्गस्थ थी, उन पर रक्षोपाय शुल्क नहीं लगना चाहिए।
- घ. ग्राही खपत के लिए आयातित एचआर काइल्स को क्षति सिद्ध करने के लिए घरेलू उत्पादकों द्वारा अपनी याचिका में आयात आंकड़ों में नहीं दर्शाना चाहिए।

XVI. कोल्ड रोल्ड स्टील मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (कोर्समा) द्वारा प्रत्युत्तर

- क. डीजी रक्षोपाय में प्रारंभिक जांच के लिए विनिर्धारित प्रक्रिया और इस मामले में औचित्यपूर्ण निर्णय के लिए सभी पणधारियों के विचार मांगने का अनुपालन न करके और 3 दिनों के अंदर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करेन का निर्णय ले लेने डीजी रक्षोपाय के पास उपलब्ध उस सूचना तक की अनदेखी करने की एचआर काइल्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के लिए विगत में दायर दो याचिकाओं को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तथा तथ्यों की गलतब्यानी करने के कारण कलकत्ता और दिल्ली उच्च न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिए जाने, से डीजी रक्षोपाय ने नियमों का पालन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय महानिदेशालय ने उचआर काइल के उत्पादकों द्वारा दायर एक याचिका को वर्ष 2009 में इसी आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इसमें गाट करारों के अनुच्छेद X और अनुच्छेद XIX तथा भारतीय कस्टम्स टैरिफ एक्ट का उल्लंघन किया गया है।
- ख. उपर्युक्त के अलावा, डीजी रक्षोपाय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई मांग के अनुसार 20 प्रतिशत अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करते समय मनमाने ढंग से जांच अविध को 5 वर्षों के मानक जो घरेलू उत्पादन और आयातों के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने, आयातों में प्रोत्कर्ष तथा उनके कारणों को स्पष्ट करने के लिए अनिवार्य है के विपरीत घटाकर 2.5 वर्ष कर दिया।
- ग. यह याचिका सरकारी डाटाबैंक अर्थात संयुक्त संयंत्र समिति/इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित नहीं है जिसका प्रयोग इस्पात मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा नीतिगत निर्णय करने के लिए किया जाता है, पर आधारित नहीं है बल्किक यह एक गैर-सरकारी एजेंसी के आंकड़ों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, इस आंकड़ों को समूहों ओर उपसमूहों में विभाजित करके उसे तोड़-मरोड़ कर तथा उसके साथ छेड़छाड़ करके अभिव्यक्त किया गया जिससे प्रामणिक आंकड़े प्राप्त होने के बजाय प्रतिशत में अंतर व्यक्त हुआ।

- घ. याचिकाकर्ताओं ने ऐसे छह विनिर्देशनों का उल्लेख किया है जिन्हें रक्षोपाय शुल्क से छूट दी जा सकती है क्योंकि घरेलू उद्योग अपेक्षित क्वालिटी की वस्तु का उत्पादन करने और मांग को पूरा करने में अक्षम रही है। तथापि, आधा दर्जन से अधिक क्वालिटी/ मोटाई है जिसे घरेलू स्रोतों से उपलब्ध नहीं कराया गया।
- ड. घरेलू उपलब्ध और उपभोज के बीच अप्रैल-सितम्बर, 2015 के दौरान अंतराल, जेपीसी रिपोर्ट के अनुसार 1.757 मिलियन टन था, इस कारण 1.852 मिलियन टन का आयात करना अनिवार्य हो गया जिसमें वह शामिल थे जिनकी क्वालिटी घरेलू स्रोतों से उपलब्ध नहीं होती है और आयातों को निर्यातों के लिए किया जाता है।
- च. यह आरोप भी निराधार है कि भारतीय बाजार चीन के सस्ते आयोग से भरे पड़े हैं। चूंकि अप्रैल-जून 2015 में चीन के आयात कुल आयातों का केवल 28 प्रतिशत थे जबकि एचआर काइल्स का आयात 30 प्रतिशत है।
- छ. अप्रैल-जुलाई, 2015 में आयातों में भारी प्रोत्कर्ष होने का अभिकथान भ्रामक है क्योंकि इसमें अप्रैल-जुलाई 2015 में वर्ष-दर-वर्ष आयातों में वृद्धि होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
- ज. इस्पात एक कच्चा माल आधारित उद्योग है और स्टील, जिसमें एचआर काइल्स भी शामिल है, की कुल उत्पादन लागत का 70 प्रतिशत कच्चे माल पर व्यय होता है। स्टील निर्माण के लिए आधारभूत इनपुटों की वैश्विक और घरेलू कीमत में पिछले एक वर्ष में प्रपाती गिरावट आई है जिसके कारण एचआर काइल्स की वैश्विक कीमतों में कमी हुई है। एचआर काइल्स का आयात वैश्विक कीमतों पर किया गया।
- झ. आयातों में भारी बढ़त नहीं आई जैसाकि याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है और औद्योगिक विकास के लिए किए गए आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं की है।
- ञ. याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उत्पादकों को मालसूची में वृद्धि के कारण क्षति हुई, न कि बढ़ते आयातों के कारण, क्योंकि जेपीसी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार मालसूची में वृद्धि हुई है।
- ट. यह स्प्ष्ट किया जा सकता है कि वर्ष 2014-16 में वैश्विक स्टील उद्योग में कोई अचानक एवं अनपेक्षित विकास नहीं हुआ।
- ठ. उन आयातों ने जो देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं, भारतीय एचआर काइल्स के उत्पादकों को कोई क्षति कारित नहीं की है और उनको हुई क्षति स्वयं द्वारा उपगत की गई है जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन की अवहेलना करना, भारी ऋण और ब्याज भार।
- ड. याचिकाकर्ताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्षति की चुनौती सदैव एचआर काइल्स तक ही सीमिमत क्यों रहती है तथा अन्य स्टील उत्पादों को क्षिति क्यों नहीं होती है। वास्तव में व्याप्त मंदी की स्थिति में विदेशी उत्पादक हाटरोलिंग और कोल्ड रोलिंग मिलों दोनों का इष्टतम क्षमता उपयोग करके कोल्ड रोल्ड उत्पादों का निर्यात करना अधिक पसंद करते हैं और सरकारें भी कोल्ड रोल्ड उत्पादों के निर्यातों को अधिक प्रोत्साहन देती हैं। याचिकाकर्ता भी कोल्ड रोल्ड उत्पादों के बड़े उत्पादक हैं परंतु एचआर काइल्स पर ही शुल्क में वृद्धि करने के लिए याचिका एकाधिकारवादी संभावना का दोहन करने के लिए दायर की जाती है।
- ढ. भारत के एचआर काइल्स उत्पादकों को 12.5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी अथवा 300 यूएसडी पीएमटी की मौजूदा वैश्विक कीमतों पर 40 यूएसडी पीएमटी, 30 यूएसडी प्रति एमटी का औसत समुद्री भाड़ा, पत्तन, 15 यूएसडी प्रति एमटी का पत्तन वित्तीय और प्रासंगिक प्रभार, इन सबको कुल मिलाकर 85 यूएसडी (5500/-रुपए) प्रति एमटी का संरक्षण पहले से ही प्राप्त है।
- ण. 20 प्रतिशत अतिरिक्त रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से इसमें 60 यूएसडी प्रति एमटी और जुड़ जाएंगे तथा घरेलू उत्पादक आयात समानता आधार पर वैश्विक कीमतों के अलावा 149 यूएसडी (10000/-रुपए) तक कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम हो जाएंगे। यह स्थिति विनिर्माण सेक्टर के लिए घातक होगी और इससे एचआर काइल्स के बजाय मूल्य वर्धित कोल्ड रोल्ड उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का आयात बढ़ेगा और निर्यातों में तीव्र कमी आएगी। कस्टम ड्यूटी के अलावा एचआर काइल्स को आयातों पर तकनीकी अवरोध द्वारा आयातों से संरक्षा भी प्राप्त है।
- त. एचआर काइल्स की उच्च कीमातें ने अनुप्रवाही कोल्ड रोलिंग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक का क्षरण कर दिया है तथा विनिर्माण सेक्टर मूल्यवर्धित स्टील और विनिर्मित उत्पादों, जिनमें इंजीनियरिंग का सामान संघटक एवं कलपुर्जे, संयंत्र एवं उपकरण शामिल हैं, का आयात करना शुरू कर देंगा, जिससे भारतीय उद्योग खासकर एसएमई को नुकसान होगा तथा कामगारों की छंटनी होगी।
- थ. केंद्रीय बजट 2015 के पश्चात कस्टम ड्यूटी में मनमानी वृद्धि तथा जल्दी-जल्दी में अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से अनुप्रवाही उद्योग अस्थिर हो गए हैं।
- द. भारतीय उत्पादक दक्षिण कोरिया, चीन तथा अन्य देशों से संरक्षण नीतियों एवं आरएंडडी की अवहेलना के कारण पिछले एक दशक में पिछड़ गए हैं। प्रौद्योगिकी के जरिए उत्पादन लागत में कमी करने का पर्याप्त दायरा है जिससे इसे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है।

- ध. याचिकाकर्ताओं ने एचआर काइल्स के छह ऐसे ग्रेडों का उल्लेख किया है जिन्हें रक्षोपाय शुल्क से छूट दी जा सकती है क्योंकि यह ग्रेड स्वदेशी स्रोतों से उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, एसएई 1541; एसएई 1040/1050/1055 और आटो बीम्स का उत्पादन करने की स्टील आदि जैसे कुछ अन्य ग्रेड भी हैं जो घरेलू स्रोतों से उपलब्ध नहीं है।
- न. स्टील औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक विकास करने के लिए एक आधारभूत इनपुट और कच्चा माल है परंतु इस समय यह करों के भारी बोझ से दबा हुआ है जिसमें लौह अयस्क पर रायल्टी का उदग्रहण, 12 प्रतिशत उत्पाद कर का उदग्रहण और राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए अन्य कर शामिल हैं। औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने तथा अवसंरचना विकास करने एवं स्टील एवं स्टील उत्पादों का आम आदमी द्वारा अधिक उपभोग किए जाने को बढ़ावा देने के लिए करों के बोझ को कम करना आवश्यक है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टील के उत्पादों से उत्पाद कर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

XVII. बाम्बे आयरन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन का प्रत्युत्तर जिसका प्रतिनिधित्व मैसर्स एमवी किनी लॉ फर्म द्वारा किया गया

- क. उपर्युक्त पक्षकार द्वारा अपने पिछले प्रस्तुतिकरणों में किए गए निवेदनों को संक्षिप्तता का ध्यान रखते हुए यहां दोहराया नहीं जा रहा है।
- ख. एपीआई ग्रेड का अपवर्जन करने के संबंध में केवल मीडिया रिपोर्टों पर ही आरोप नहीं लगाया जा सकता है। हर प्रयोक्ता को अपने परियोजना प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमत सामग्री का प्रयोग करने का विकल्प होता है और आयातक इस पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते हैं कि कौन सा सामान कहां प्रयोग होता है।
- ग. डीजी रक्षोपाय को कस्टम्स मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि कस्टम्स ऐसा करने के लिए पूर्णतया सक्षम है।
- घ. याचिकाकर्ता किसी विशिष्ट ग्रेड के अंतिम प्रयोग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। अंतिम निर्णय प्रयोगकर्ता का ही होता है। अंतिम प्रयोग सदैव ही संकेतात्मक प्रवृत्ति का होता है और यह बाध्यकारी होता है। यह सुझाव देना अनर्मल है कि कुछ भारतीय आयातक इस पीयुसी का आयात एपीआई के छदय रूप से कर रहे हैं।
- ङ. वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में आयातों में अभिनव प्रोत्कर्ष के लिए डीजी को उस अवधि के तथ्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने चाहिएं जब घरेलू उद्योग के संयंत्र अनुरक्षण के अधीन थे अथवा प्रतिबंधित उत्पादन क्षमता के अधीन थे। घटी हुई उपलब्धता तथा उनके अपने आयात इन संवर्धित आयातों का प्रमुख कारण रहे होंगे।
- च. वर्ष 2015-16 में हुए आयातों पर अन्य कई कारकों जैसे ग्राही खपत के लिए आयात, याचिकाकर्ताओं द्वारा आयात तथा निर्यात के लिए किए गए आयात और अंतिम लाइसेंस पर किए गए आयात तथा अलाय एवं गैर अलाय में भेद करने के आलोक में विचार किया जाना चाहिए।
- छ. 2 से 3 वर्षों की मूल्यांकन अवधि कम लगती है। अचानक एवं तीव्र प्रोत्कर्ष का मूल्यांकन इस अवधि से किया जा सकता है न कि एक या दो तिमाहियों से।
- ज. यूएस और तुर्की में साधन पाटरोधी शुल्क के रहे हैं जो कि रक्षोपाय शुल्क के लिए अपेक्षित स्थिति से पूर्ण तथा भिन्न स्थिति हैं।
- झ. आवेदकों ने उत्पादों के एक क्लस्टर पर विचार किया है। रक्षोपाय रक्षा का अधिरोपण करने की जरूरत का सुनिश्चियन करने के लिए इनमें से प्रत्येक उत्पाद के संबंध में किए गए आयातों की संपुष्टि की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह महत्वपूर्ण है कि आवेदकों द्वारा कम्बाइन किए गए उत्पादों को अलग-अलग करना चाहिए क्योंकि अलाय स्टील के उत्पादों का उत्पादन करने की आवेदकों की उत्पादन क्षमता नगण्य है।
- ञ. आवेदकों द्वारा सामना की जा रही समस्या आयातों में वृद्धि से संबंधित न होकर अन्य कारकों जैसे उच्च ऋण, भूषण स्टील में दमन एवं कुप्रबंधन का मुद्दा, एस्सार स्टील के मामले में कच्चे माल के प्रापण की समस्या के कारण हैं।
- ट. अलाय स्टील का भारत में नगण्य मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इसलिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का मुद्दा ही नहीं उठता है। गैर-अलाय स्टील के संबंध में, आवेदकगण घरेलू मांग के कुल बाजार हिस्से के लगभग 92-93 प्रतिशत की मांग को पूरा करते हैं। अत:, पीयूसी की उस श्रेणी पर भी रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना अपेक्षित नहीं है।
- ठ. यदि वर्ष 2014-15 में हुए आयातों की तुलना वर्ष 2011-12 से की जाती है तो यह वृद्धि केवल 9 प्रतिशत के बराबर है और इसे प्रोत्कर्ष नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में आयातों में भारी प्रोत्कर्ष होने का अभिकथन करते समय इसी अविध के दौरान अमुलन 40 प्रतिशत की असामान्य गिरावट पर उचित ध्यान नहीं दिया गया।
- ड. यदि पोस्को महाराष्ट्र द्वारा किए गए आयातों को हटा दिया जाता है तो फिर तो आयातों में कमी प्रदर्शित होने लगेगी।

- ढ. अधिकांश आवेदकों ने अपने टर्नओवर में वृद्धि प्रदर्शित की है इसलिए कथित क्षति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। आवेदकों की रोजगार लागत में सतत वृद्धि हुई है।
- ण. अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयातित कच्चे माल का उन परिष्कृत वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है जिनका निर्यात किया जाता है। ऐसे आयात भारत की घरेलू बाजार को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।
- त. आवेदकों ने शासकीय रूप से उपलब्ध जेपीसी आंकड़ों की अनदेखी करके एक गैर-मान्यताप्राप्त निजी एजेंसी आईबीआईएस द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- थ. कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के बावजूद घरेलू बाजार में कीमतें कम नहीं हुई हैं ओर वे निर्यात कीमतों की तुलना में बहुत अधिक हैं।
- द. आवेदक स्वयं इस सस्ते कच्चे माल का आयात कर रहे हैं।
- ध. जुलाई-सितम्बर 2015 में आयातों में कथित प्रोत्कर्ष स्वयं आवेदकों, खासकर जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा इस संबद्ध विचाराधीन उत्पाद का भारी मात्रा में आयात किए जाने के कारण हुआ है।
- न. वर्तमान मामले में अपनाई गई समय-सीमा को देखते हुए यह स्पष्टत: प्रदर्शित होता है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने में अनुचित जल्दी की गई।

XVIII. फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता तविन्दर सिध द्वारा किया गया।

- क. उपर्युक्त पक्षकार द्वारा अपने पिछले प्रस्तुतिकरणों में किए गए निवेदनों को संक्षिप्तता का ध्यान रखते हुए यहां दोहराया नहीं जा रहा है।
- ख. एपीआई ग्रेड का अपवर्जन करने के संबंध में केवल मीडिया रिपोर्टों पर ही आरोप नहीं लगाया जा सकता है। हर प्रयोक्ता को अपने परियोजना प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमत सामग्री का प्रयोग करने का विकल्प होता है और आयातक इस पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते हैं कि कौन सा सामान कहां प्रयोग होता है।
- ग. याचिकाकर्ता किसी विशिष्ट ग्रेड के अंतिम प्रयोग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। अंतिम निर्णय प्रयोगकर्ता का ही होता है। अंतिम प्रयोग सदैव ही संकेतात्मक प्रवृत्ति का होता है और यह बाध्यकारी होता है। यह सुझाव देना अनर्गल है कि कुछ भारतीय आयातक इस पीयुसी का आयात एपीआई के छदय रूप से कर रहे हैं।
- घ. वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में आयातों में अभिनव प्रोत्कर्ष के लिए डीजी को उस अवधि के तथ्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने चाहिएं जब घरेलू उद्योग के संयंत्र अनुरक्षण के अधीन थे अथवा प्रतिबंधित उत्पादन क्षमता के अधीन थे। घटी हुई उपलब्धता तथा उनके अपने आयात इन संवर्धित आयातों का प्रमुख कारण रहे होंगे।
- ङ. वर्ष 2015-16 में हुए आयातों पर अन्य कई कारकों जैसे ग्राही खपत के लिए आयात, याचिकाकर्ताओं द्वारा आयात तथा निर्यात के लिए किए गए आयात और अंतिम लाइसेंस पर किए गए आयात तथा अलाय एवं गैर अलाय में भेद करने के आलोक में विचार किया जाना चाहिए।
- च. 2 से 3 वर्षों की मूल्यांकन अवधि कम लगती है। अचानक एवं तीव्र प्रोत्कर्ष का मूल्यांकन इस अवधि से किया जा सकता है न कि एक या दो तिमाहियों से।
- छ. यूएस और तुर्की में साधन पाटरोधी शुल्क के रहे हैं जो कि रक्षोपाय शुल्क के लिए अपेक्षित स्थिति से पूर्ण तथा भिन्न स्थिति हैं।
- ज. आवेदकों द्वारा सामना की जा रही समस्या आयातों में वृद्धि से संबंधित न होकर अन्य कारकों जैसे उच्च ऋण, भूषण स्टील में दमन एवं कुप्रबंधन का मुद्दा, एस्सार स्टील के मामले में कच्चे माल के प्रापण की समस्या के कारण हैं।
- झ. अलाय स्टील का भारत में नगण्य मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इसलिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का मुद्दा ही नहीं उठता है। गैर-अलाय स्टील के संबंध में, आवेदकगण घरेलू मांग के कुल बाजार हिस्से के लगभग 92-93 प्रतिशत की मांग को पूरा करते हैं। अत:, पीयूसी की उस श्रेणी पर भी रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना अपेक्षित नहीं है।
- ञ. यदि वर्ष 2014-15 में हुए आयातों की तुलना वर्ष 2011-12 से की जाती है तो यह वृद्धि केवल 9 प्रतिशत के बराबर है और इसे प्रोत्कर्ष नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में आयातों में भारी

प्रोत्कर्ष होने का अभिकथन करते समय इसी अवधि के दौरान अमूलन 40 प्रतिशत की असामान्य गिरावट पर उचित ध्यान नहीं दिया गया।

- ट. यदि पोस्को महाराष्ट्र द्वारा किए गए आयातों को हटा दिया जाता है तो फिर तो आयातों में कमी प्रदर्शित होने लगेगी।
- ठ. अधिकांश आवेदकों ने अपने टर्नओवर में वृद्धि प्रदर्शित की है इसलिए कथित क्षति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। आवेदकों की रोजगार लागत में सतत वृद्धि हुई है।
- ड. अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत आयातित कच्चे माल का उन परिष्कृत वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है जिनका निर्यात किया जाता है। ऐसे आयात भारत की घरेलू बाजार को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।
- ढ. आवेदकों ने शासकीय रूप से उपलब्ध जेपीसी आंकड़ों की अनदेखी करके एक गैर-मान्यताप्राप्त निजी एजेंसी आईबीआईएस द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- ण. कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के बावजूद घरेलू बाजार में कीमतें कम नहीं हुई हैं और वे निर्यात कीमतों की तुलना में बहुत अधिक हैं।
- त. आवेदक स्वयं इस सस्ते कच्चे माल का आयात कर रहे हैं।
- थ. जुलाई-सितम्बर 2015 में आयातों में कथित प्रोत्कर्ष स्वयं आवेदकों, खासकर जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा इस संबद्घ विचाराधीन उत्पाद का भारी मात्रा में आयात किए जाने के कारण हुआ है।
- द. वर्तमान मामले में अपनाई गई समय-सीमा को देखते हुए यह स्पष्टत: प्रदर्शित होता है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने में अनुचित जल्दी की गई।

XIX. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा न्यूनतम आयात कीमत शुरू किए जाने के पश्चात घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2016 को अधिसूचा संख्या 38/2015-2020 के तहत स्टील उत्पादों पर एमआईपी की शुरूआत करने के पश्चात घरेलू उद्योग ने अपने प्रत्युत्तर में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण किए हैं :

क. घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 17.02.2016 के पत्र के तहत यह उल्लेख किया है कि :

"अभी हाल ही में डीजीएफटी में अपनी दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 38/2015-2020 के तहत आईटीसी (एचएस), 2012 के अध्याय 72 के अंतर्गत आयात की जा रही मदों पर न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) जारी की है। यह नोट करना संगत है कि यह एमआईपी छह महीनों की अवधि के लिए अथवा डीजीएफटी द्वारा किए गए अगले आदेशों इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए प्रभावी होगी। इसका आशय यह है कि इस एमआईपी का छह माह की अवधि पूरी होने से पहले किसी भी समय प्रतिसंहरण किया जा सकता है।

यह नोट करने योग्य है कि घरेलू उद्योग ने 3 माह की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का अनुरोध किया है। यद्यपि इस एमआईपी में घरेलू उद्योग की अधिकांश समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है परंतु यह केवल छह माह के लिए अथवा उससे कम की अवधि के लिए ही प्रभावी रहेगी। एक बार एमआईपी के समाप्त हो जाने पर घरेलू उद्योग को मनमानी कीमतों पर प्रोत्किर्षित आयातों से संरक्षण किए बिना छोड़ दिया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल रक्षोपाय शुल्क ही अधिक प्रभावोत्पादक और घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए एक दीर्घाविधि उपचार है। इसके परिप्रेक्ष्य में अति विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध किया जाता है कि डीजी रक्षोपाय शुल्क की गई इस जांच को अंतिम रूप प्रदान करें और इस संबद्ध वस्तु पर निर्णायक रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करें।

अनुप्रयोज्य शुल्क के उदग्रहण के किसी भी संभ्रम से बचने के लिए रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण उस तारीख से किया जा सकता है जब से एमआईपी समाप्त हो रही हो।"

ख. घरेलू उद्योग ने अपने एक अन्य पत्र दिनांक 17.2.2016 के तहत यह उल्लेख किया है कि:

''अति विनम्रतापूर्व यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण घरेलू उद्योग की रक्षा करने में समर्थ नहीं रहा है क्योंकि इस संबद्ध वस्तु के निर्यातक अपनी कीमतों में 20 प्रतिशत के यथामूल्य शुल्क का अवशोण कर लेंगे। इसके अतिरिक्त, भारत में कई प्रयोक्ताओं ने यह चिंता भी व्यक्त की है कि जब वे इस संबद्ध वस्तु (स्पेशन ग्रेड की स्टील सहित) का आयात हैं तब भी वे 20 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क के अध्यधीन होंगे। घरेलू उद्योग और भारत में प्रयोक्ताओं दोनों की चिंताओं का निराकरण करने के लिए यह अनुरोध है कि डीजी रक्षोपाय कृपया संदर्भ कीमत आधार पर रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण करें।

महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जांच और जांच परिणाम

- 14. इस मामले के रिकार्डों, में मैंने घरेलू, उत्पादकों/आयातकों/ ओंउपयोक्ता, निर्यातकों और निर्यातक राष्ट्रों द्वारा दायर प्रत्युत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच की है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनमें उठाए गए मुद्दों का इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर विचार किया गया है।
- 15. सीमाशुल्क प्रशुल्क अिधनयम, 1975 की धारा 8बी का अिधरोपण शुल्क विभेदाकारी ढंग से रक्षोपाय-ख में भारत में आयातों पर गैर 8 (ख8 करने का विवरण है। का भारत वस्तु का अिधरोपण करने का प्रावधान है यिद उक्त पर रक्षोपाय शुल्क में किसी वस्तु) में आयात इतनी अिधक संविर्धत मात्रा में औश्र ऐसी पिरिस्थितयों में किया जाए कि उसके घरेलू उद्योग को गंभीर क्षित हो या गंभीर क्षित की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।
- 16. नियमावली (की पहचानएवं आकलनरक्षोपाय शुल्क) प्रशुल्कसीमाशुल्क 1997 में जांच को शामिल करने वाले ढंग एंव सिदधांतों का विवरण है।
- 17. यह जांच उक्त नियमों के अनुसार आयोजित की गई है इस अधिसूचना के तहत अंतिम जांच परिणाम रिकार्डकर दिए गए हैं।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

18. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "600 एमएम" या उससे अधिक की चौड़ाई के नॉन-अलॉय और अन्य अलाय स्टील के काइल्स में हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद है, (जिन्हें एतद्वारा पीयूसी अथवा विचाराधीन उत्पाद कहा गया) और जिन्हें सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत प्रशुल्क शिर्षक संख्या 7208 और प्रशुल्क मद संख्या 72253090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि इन उत्पादों को और अधिक हाट रोल्ड नहीं किया जाता है और यह "ऐज रोल्ड" एज अथवा "ट्रिम्ड" एज अथवा "स्लिट" एज युक्त प्राइप अथवा गैर-पाइम स्थिति में लोहा, अलाय अथवा नॉन अलाय स्टी के फ्लैट उत्पाद हैं। यह उत्पाद स्किन पास अथवा टेम्पिरेंग सहित अथवा उसके बिना) पिकल अथवा नॉन पिकल स्लिट अथवा गैर स्लिट के रूप में हो सकते हैं और उनकी 600 एमएम के बराबर अथवा उससे अधिक की नामिनल चौड़ाई होती हैं। यह उत्पाद रोल्ड अथवा थर्मों मैकेनिकली रोल्ड अथवा कंट्रोल्ड रोल्ड हो सकते हैं। इन उत्पादों में रोलिंग से सीधे व्युत्पन्न रिलीफ में प्रतिकृतियां हो सकती हैं। इन उत्पादों की पिकलिंग आयालिंग, रिवाइडिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि जैसे विभिन्न प्रसंसाधन प्रक्रिया हो सकती है।

इस विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है:

- क. 600 एमएम से कम की मामूली सी चौड़ाई युक्त इस्पात के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद;
- ख. एपीआई ग्रेड स्टील
- ग. सिलिकान इलेक्ट्रिकल स्टील;
- घ. स्प्रिंग स्टील क्वालिटी के इस्पात के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद;
- ङ. इस्पात के ऐसे हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद जिनके ऊपर जस्ते की कोटिंग या इलेक्ट्रालिटिकली प्लेटिंग की गई है;
- च. जस्ता की अन्यथा कोटिंग अथवा प्लेटिंग किए हुए इस्पात के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद।
- छ. स्टेनलेस स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद।
- 19. घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि मीडिया की विभिन्न रिपोर्टों के जरिए घरेलू उद्योग के यह संज्ञान में आया है कि कुछ भारतीय आयातक/विदेशी निर्यातक वाणिज्यिक/बेस ग्रेड की ढांचागत स्टीलों (जो परम्परागत ढांचागत अनुप्रयोगों के लिए हैं), पर, एपीआई 5 एल ग्रेड, जिस पर रक्षोपाय शुल्क से छूट है, के छदम रूप में, लागू अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क की प्रवंचना कर रहे हैं। इसलिए, घरेलू उद्योग डीजी रक्षोपाय से निम्नलिखित स्पष्टीकरण देकर एपीआई ग्रेड की स्टील के अपवर्जन को स्पष्ट करें:

"एपीआई ग्रेड स्टील मे वह स्टील शामिल है, जिसका प्रयोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योगों में पाइप लाइन परिवहन प्रणाली के लिए वेल्डेड स्टील पाइप्स में किया जाता है।

- 20. इस संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने इसका विरोध किया है और यह प्रस्तुतिकरण किया है कि केवल मीडिया रिपोर्टों पर ही दोषरोपण नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक प्रयोक्ता को उनके परियोजना प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमत सामग्री का प्रयोग करने का विकल्प होता है और आयातक का इस तथ्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता है कि वास्तव में उस सामग्री का प्रयोग कहां किया जा रहा है और यह कि याचिकाकर्ता किसी विशिष्ट ग्रेड के अंतिम प्रयोग का निश्चय नहीं कर सकता है। अंतिम निर्णय तो प्रयोक्ता का रहता है। अंतिम प्रयोग सदैव ही प्रकृति में संकेतात्मक होता है न कि बाध्यकारी प्रकृति का। यह सुझाव देना निरर्थक है कि कुछ भारतीय आयातक इस पीयूसी का एपीआई के छदम रूप में आयात कर रहे हैं। मैंने यह पाया है कि इस पीयूसी के दायरे को जांच शुरूआत का नोटिस जारी करने के पश्चात बाद की तारीख में नहीं बढ़ाया जा सकता है। एपीआई ग्रेड को प्रकाशित एपीआई विनिर्देशनों से ही निर्धारित किया जा सकता है। कि उस प्रकार से जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस मामले में पीयूसी वही है जिसका ऊपर वर्णन किया गया है।
- 21. कई हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्रश्न उठाया है। इन सभी मुद्दों का समाधान अधोलिखित है :
- (i) 2.00 एमएम और उससे कम की मोटाई के एचआर काइल्स: मैसर्स निजोन सिस्ट्रप्स लिमिटेड और मैसर्स निजोम ट्यूब लिमिटेड ने तर्क दिया है कि वे 2.00 एमएम तथा उससे कम की मोटाई के एचआर काइल्स का निरंतर आयात कर रहे हैं क्योंकि उनके नियमित प्रदायक मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड ने अवरोध उत्पन्न हो जाने के कारण अपनी आपूर्ति बंद कर दी है। इसलिए, उन्हें मजबूत इस विशिष्ट उत्पाद का आयात करना पड़ता है और इन उत्पादों को विचाराधीन के दायरे से अलग रखना चाहिए। मैंने यह प्रेक्षण किया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने उसका घरेलू बाजार से प्रापण करने का कोई प्रयास नहीं किया है और न ही उन्होंने कहीं इस बात का उल्लेख किया है कि अन्य घरेलू उत्पादक उनको इस वस्तु की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनके तर्क को स्वीकार नहीं किया जाता है।

(ii) एचआर काइल्स का आटोमोटिव ग्रेड:

क) मैसर्स हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड यह तर्क देता है कि कोरियाई आटोमोटिव ग्रेड की स्टील को रक्षोपाय शुल्क से छूट प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किए जाने के पश्चात भी उन्हें इस उत्पाद का अनिवार्यत: आयात करना पड़ेगा क्योंकि उनका नानयांग अनुसंधान एवं विकास केंद्र भारत में कार बनाने के लिए विनिर्देशनों में परिवर्तन करने की उन्हें अनुमित नहीं देता है। आवेदकों ने अपने प्रस्तुतिकरणों में आपित व्यक्त की है कि एचआर काइल्स का आटोमोटिव ग्रेड एक बहुत ही अविशिष्ट विवरण है और इसे तब तक अपवर्जित नहीं किया जा सकता है जब तक वह यह प्रमाण नहीं देते हैं कि भारत के स्टील उत्पादक इस ग्रेड की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। केवल इस कारण से कि उनका आरएंडडी केंद्र कहीं अन्य से प्रापण करने की अनुमित नहीं देगा, इसका आशय यह नहीं है कि इस ग्रेड के आयातों को रक्षोपाय शुल्क से छूट देकर घरेलू उद्योग को कष्ट सहन करने दिया जाए। मैं घरेलू उद्योग के इस तर्क से असहमत होने का कोई कारण नहीं पाते है।

(iii) ट्यूब इन्वेस्टमेंट आफ इंडिया लिमिटेड (टीआईआई) का दावा :

- क) टीआईआई का तर्क है कि निम्नलिखित ग्रेडों उत्पाद दायरे से उनकी सीमित उपलब्धता, गुणवत्ता मुद्दे के कारण हटा देना चाहिए ओर क्योंकि टीआईआई ने पहले से ही आपूर्ति के स्रोतों की पहचान एवं उनका अनुमोदन कर दिया है जिन्हें वे अब परिवर्तित नहीं कर सकते हैं :
 - क. एएसई 1541
 - ख. एसएई 1020/1040/1045/1050/1055
 - ग. एससीएम 435
 - घ. बोरोन स्टील
 - ङ. 16 एमएन सीआर 5
 - च. एसएई 1006/1010
 - छ. एसटी 52.3
- ख) इस संबंध में घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि उन्होंने उत्पाद के दायरे से अपवर्जन करने के लिए अपने दावे को साक्ष्यांकित करने हेतु कोई वास्तविक साक्ष्य दायर नहीं किया है और इसलिए उनके यह दावे अथवा मुद्दे केवल कल्पना पर आधारित हैं। इसलिए इन ग्रेडों का उत्पाद के दायरे से अपवर्जन नहीं किया जा सकता है। मैंने यह प्रेक्षण किया है कि केवल इस कारण से कि हितबद्ध पक्षकार ने उनकी आपूर्ति के स्रोत का अनुमोदन नहीं किया है, उन्हें रक्षोपाय शुल्क से अपवर्जित करने का कारण नहीं हो सकता है। वे भी आपूर्ति के घरेलु स्रोतों का अनुमोदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं।

- (iv) **पिकलिंग एवं आयर्लिंग ("पीओ") युक्त हाट रोल्ड काइल**: मैसर्स हुंडई स्टील कोरिया का यह तर्क है कि उनके द्वारा विनिर्मित पीओ उत्पादों की बिक्री मैसर्स हुंडई स्टील इंडिया लिमिटेड को की जाती है जो बदले में इसकी बिक्री मैसर्स हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को करती है। उनका तर्क है कि यह आयात अनिवार्य हैं क्योंकि इनको बंद कर देने का आशय होगा आटोमोबाइल्स में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना। उनका तर्क है कि पीओ उत्पादों को इस उत्पाद के दायरे से अलग रखा जाए। घरेलू उद्योग इस तर्क का कड़ाई से विरोध करता है और यह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने उच्चतर स्ट्रेंथ स्तर के लिए उपयुक्त इस्पात सहित आटो ग्रेड की स्टील का विनिर्माण करने की सिद्धहस्त क्षमता प्राप्त कर ली है। मैं यह पाता हूं कि भारतीय इस्पात उद्योग आवश्यक ग्रेड की स्टील प्रदान कराने के लिए पर्याप्तत: उन्नत स्थिति में है और मैसर्स हुंडई स्टील कोरिया का तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है।
- (v) संकुचित रूप से परिभाषित ग्राहक विनिर्देशनों के आधार पर हाट रोल्ड काइल्स: मैसर्स निप्पन स्टील एंड सुमिकिन पाइप इंडिया कंपनी लिमिटेड का तर्क है कि संकुचित रूप से परिभाषित ग्राहक विनिर्देशनों के आधार पर हाट रोल्ड काइल्स को इस उत्पाद के दायरे से अलग कर देना चाहिए क्योंकि यह आयात तनन स्ट्रेंथ, इस्पात की सफाई, ग्रेन आकार और रासायनिक संघटन में अलग होती है। मैसर्स निप्पन स्टील और सुमिकिन पाइप इंडिया कंपनी लिमिटेड ने उस आयात के विवरण और उत्पाद प्रकार की गोपनीयता का दावा किया है जिसका वे आयात करते हैं परंतु उन्होंने इस उत्पाद को उत्पाद के दायरे से अलग रखने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने अपने प्रत्युत्तर उपर्युक्त तर्कों का खंडन करते हुए उल्लेख किया है कि इन विशिष्ट ग्रेडों और उत्पाद प्रकारों को घरेलू उद्योग के साथ शेयर नहीं किया गया है और इसलिए वे उनका हित रक्षित करने की स्थिति में नहीं है। इस संबंध में मैं अपने प्रेक्षणों को पुन: दोहराता हूं कि भारतीय उद्योग इस्पात के विभिन्न ग्रेडों की आपूर्ति करने के पर्याप्तत: उन्नतिशील स्थिति में है।
- (vi) ग्रेड जेएसएच 270/370 और ग्रेड जेएसएच 590: मैसर्स मारूति सुजुकी लिमिटेड का तर्क है कि इन दो ग्रेडों को उत्पाद के दायरे से अलग कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इन ग्रेडों का आयात ग्राहकों की सुरक्षा जरूरतों और उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए किया जाना अपेक्षित है। उनका तर्क है कि घरेलू विनिर्माता अपेक्षित क्वालिटी मानकों को पूरा नहीं कर सकते हैं और वे कच्चे माल के असंगत आपूर्तिकर्ता हैं। याचिकाकर्ता इस तर्क का कड़ा विरोध करते हैं। मैं यह पाता हूं कि भारतीय इस्पात उद्योग विभिन्न ग्रेड की सामग्री की आपूर्ति करने में सक्षम है और पर्याप्तत: उन्नतिशील स्थिति में है।
- (vii) **अलाय स्टील :** फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ महाराष्ट्र ("एफएएम") का यह तर्क है कि अलाय स्टील का भारत में नगण्य मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इसलिए अलाय स्टील पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने पुन: यह तर्क दिया कि नॉन-आलय स्टील का आयात कुल घरेलु उत्पाद का केवल 7-8 प्रतिशत है और नॉन-अलाय स्टील की 90 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्से पर घरेलु यूनिटों का कब्जा है। एफएएम का यह तर्क भी है कि नॉन-अलाय स्टील के इसने न्यून आयात पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण करना अधिपत्रित नहीं हैं। मैंने यह पाया है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का निर्णय करने के लिए मुख्य निर्णायक करके घरेल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात नहीं है बल्कि यह है कि क्या घरेल उद्योग को इन संवर्धित आयातों के कारण गंभीर क्षति हो रही है। जहां तक अलाय स्टील का संबंध है, इस उत्पाद के दायरे में केवल एक टैरिफ मद 7225.30.90 को कवर किया गया है न कि अलाय स्टील के संपूर्ण शीर्षक को। इसके अतिरिक्त यह नोट किया जाता है कि घरेलु उद्योग ने अपने दिनांक 08 अगस्त 2015 के पत्र में इस तथ्य के विस्तृत कारण पहले ही प्रदान करा दिए हैं कि सीमा शुल्क वर्गीकरण संख्या 7225.30.90 के अंतर्गत आने वाले अलाय स्टील को इस उत्पाद के दायरे में शामिल क्यों किया जाना चाहिए। प्रशुल्क मद संख्या 7225.30.90 के अंतर्गत अलाय स्टील के रूप में वर्गीकत आयातों में बोरोन तथा अन्य अलाइंग तत्व की बहुत कम मात्रा होती है इसलिए उन्हें गैर-अलाय के रूप में वर्गीकृत किया जाता हे। यह आयात घरेलु उद्योग पर गंभीर प्रभाव डालते हैं क्योंकि यह आयात घरेलु उद्योग द्वारा उत्पादित क्वाइल्स में हाट रोल्ड नान अलाय फ्लैट उत्पादों के तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय होते हैं। इस कारण से घरेल उद्योग ने प्रशल्क मद संख्या 7225.30.90 के अंतर्गत होने वाले आयातों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत शामिल किया है। इस मुद्दे पर मैं डीआई के तर्क को स्वीकार करता हूं। चीन आयरन एंड स्टील एसोसिएशन ने भी यह प्रश्न किया है कि सीमाशुल्क प्रशुल्क के मद 7225 के अंतर्गत आने वाले अलाय स्टील को इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल क्यों किया गया है। उपर्युक्त विश्लेषण से चाइना आयरन एंड स्टील एसोसिएशन द्वारा उठाए गए तर्कों का भी समाधान हो जाता है।
- (viii) **हाई स्ट्रेंथ स्टील ("एचएसएस"):** चीन इस्पात कारपोरेशन, ताइवान का यह तर्क है कि आटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में प्रयोग किए जाने वाले एचएसएस ग्रेड का इस उत्पाद के दायरे से अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए। इस उत्पाद के दायरे से अपवर्जन करने के लिए उनके दावे के साक्ष्यांकन में कोई वास्तविक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया। पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई चर्चा के अनुसार भारतीय उद्योग इस सामग्री की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्तत: उन्नत स्थिति में है।
- (ix) **जापान की मिलों द्वारा उत्पादित स्टील:** मैसर्स जेईई स्टील कारपोरेशन, मैसर्स निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड, मैसर्स निप्पन स्टील एंड सुमिटोमो मेटल कारपोरेशन और कोबे स्टील लिमिटेड ने मिलकर यह तर्क दिया है कि उनके द्वारा उत्पादित इस्पात को इस रक्षोपाय शुल्क के अधीन नहीं रखना चाहिए और उसे इस उत्पाद के दायरे से अलग कर देना चाहिए। तथापि, उन्होंने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है

जिससे यह सुझाव मिलता हो कि उसकी आपूर्ति भारतीय उद्योग द्वारा नहीं की जा सकती है। इसलिए उनके द्वारा दिए गए तर्क स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

22. उपर्युक्त के मद्देनजर यह संपुष्टि की जाती है कि इस जांच के अधीन उत्पाद "600 एमएम" या उससे अधिक की चौड़ाई के नॉन-अलॉय और अन्य अलाय स्टील के काइल्स में हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद है, (जिन्हें एतद्वारा पीयूसी अथवा विचाराधीन उत्पाद कहा गया) और जिन्हें सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत प्रशुल्क शीर्षक संख्या 7208 और प्रशुल्क मद संख्या 72253090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि इन उत्पादों को और अधिक हाट रोल्ड नहीं किया जाता है और यह "ऐज रोल्ड" एज अथवा "ट्रिम्ड" एज अथवा "स्लिट" एज युक्त प्राइप अथवा गैर-पाइम स्थिति में लोहा, अलाय अथवा नॉन अलाय स्टी के फ्लैट उत्पाद हैं। यह उत्पाद स्किन पास अथवा टेम्परिंग सहित अथवा उसके बिना) पिकल अथवा नॉन पिकल स्लिट अथवा गैर स्लिट के रूप में हो सकते हैं और उनकी 600 एमएम के बराबर अथवा उससे अधिक की नामिनल चौड़ाई होती है। यह उत्पाद रोल्ड अथवा थर्मो मैकेनिकली रोल्ड अथवा थर्मो मैकेनिकली कंट्रोल रोल्ड अथवा कंट्रोल्ड रोल्ड हो सकते है। इन उत्पादों में रोलिंग से सीधे व्युत्पन्न रिलीफ में प्रतिकृतियां हो सकती है। इन उत्पादों की पिकलिंग आयालिंग, रिवाइडिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि जैसे विभिन्न प्रसंसाधन प्रक्रिया हो सकती है।

इस विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है :

- क. 600 एमएम से कम की मामूली सी चौड़ाई युक्त इस्पात के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद;
- ख. एपीआई ग्रेड स्टील;
- ग. सिलिकान इलेक्ट्रिकल स्टील;
- घ स्प्रिंग स्टील क्वालिटी के इस्पात के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद ;
- ङ. इस्पात के ऐसे हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद जिनके ऊपर जस्ते की कोटिंग या इलेक्ट्रालिटिकली प्लेटिंग की गई है;
- च. जस्ता की अन्यथा कोटिंग अथवा प्लेटिंग किए हुए इस्पात के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद;
- छ. स्टेनलेस स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद।"
 - (x) 23. तदनुसार, यह धारित किया जाता है कि घरेलू रूप से उत्पादित "600एमएम या उससे अधिक की चौड़ाई के नान अलाय स्टील के काइल्स में हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद" इस जांच के अंतर्गत आयातित उत्पादों के सभी तरह से समान या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी मदों के दायरे के अंतर्गत आते हैं और यह कि घरेलू रूप से उत्पादित "600एमएम या उससे अधिक की चौड़ाई के नान अलाय स्टील के काइल्स में हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद आयातित "600एमएम या उससे अधिक की चौड़ाई के नान अलाय और अन्य अलाय स्टील के काइल्स में हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद (पीयूसी के रूप में पूर्णतया परिभाषित) सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षापाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 के नियम 2(ड.) के आशय के अंतर्गत समान वस्तुएं हैं।

ख. घरेलू उद्योग (डीआई)

24. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख (6) (ख) में घरेलु उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है :

"घरेलू उद्योग" का आशय

- (i) भारत में समान वस्तु अथवा प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु के समग्र रूप से उत्पादनकर्ताओं; अथवा
- (ii) उन उत्पादकर्ताओं से है जिनका समान वस्तु या भारत में प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।
- 25. हितबद्ध पक्षकार यह तर्क देते हैं कि इस मामले में आवेदक घरेलू उद्योग के रूप अर्ह नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 25(ख) के अंतर्गत दी गई तालिका पर भरोसा किया है और यह तर्क देते हैं कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्ष 2013-14 में 45 प्रतिशत था और अन्य उत्पादकों का बाजार हिस्सा 51 प्रतिशत था। इसी तरह, यह तर्क भी दिया गया कि वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) में अन्य उत्पादकों का बाजार हिस्सा 51 प्रतिशत था। इस संबंध में, मुझे इस आपत्ति में को गुण प्रतीत नहीं होता क्योंकि पैरा 25(ख) के नीचे तालिका में दिया गया बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग की बिक्री और घरेलू मांग का अनुपात दिया गया है। तथापि, यह बाजार हिस्सा आधार का मापक नहीं है क्योंकि घरेलू मांग के आंकड़ों में आयातों के आंकड़े भी शामिल किए हैं और घरेलू उद्योग की बिक्री में ग्राही खपत को शामिल नहीं किया गया है।

26. यह आवेदन पत्र मैसर्स स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड; मैसर्स एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड और मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और एक साथ मिलकर उनका उत्पादन भारतीय उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है और इसलिए वे इस उत्पाद के बड़े उत्पादक हैं। यह प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 13 और पैरा 25(ख) के नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है। तदनुसार यह धारित किया जाता है कि आवेदक घरेलू उत्पादक सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख)6)(ख) के अंतर्गत दी गई डीआई की परिभाषा के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग (डीआई) है और घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ग. सूचना का स्रोत

- 27. इस विचाराधीन उत्पाद का आयात भारत में सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 72 के सीमाशुल्क प्रशुल्क शीर्षक 7208 और 72253090 के अंतर्गत किया जाता है। यह रक्षोपाय जांच वर्ष 2013-14 से 2015-16 (अप्रैल से जून, 2015) के लिए आईबीआईएस (इंटरनेशनल बिजनेस इंफारमेशन सर्विसेज) के आयात आंकड़ों के आधार पर शुरू की गई थी। वर्ष 2011-12 से 2015-16 (जून 2015 तक) तक के घरेलू आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं ओर उनका इस विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल दौरा करके एक्साइज रिकार्डों के आधार पर आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया है। जुलाई, 2015 से सितम्बर, 2015 तक के विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में आयात आंकड़े तथा घरेलू आंकड़े आवेदकों द्वारा अपने लिखित प्रस्तुतिकरणों/प्रत्युत्तरों में प्रस्तुत किए हैं। कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आईबीआईएस जैसी एक गैर-सरकारी एजेंसी से लिए गए आयात आंकड़े प्रामाणिक और समर्थनीय नहीं हैं और प्राधिकारी को केवल जेपीसी आंकड़ों पर ही विचार करना चाहिए और यह कि याचिका में विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण करने की विस्तृत किया पद्धित नहीं दी गई है। हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह तर्क दिया है कि याचिका में प्रयुक्त आईबीआईएस आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए।
- 28. यह उल्लेख किया जा सकता है कि आईबीआईएस आंकड़ों का प्रयोग डीजी (रक्षोपाय) द्वारा इससे पहले की गई कई जांचों में प्रयोग किया गया है। आईबीआईएस व्यापार सूचना का एक जाना माना स्रोत है और यह आरोप समर्थनीय नहीं है कि इसके आंकड़े प्रामाणिक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, कई बार, यह आवश्यक हो जाता है कि किसी भरोसेमंद गैर-सरकारी स्रोत से आंकड़े प्राप्त कर लिए जाएं। तथापि, अंतिम सिफारिश के लिए किए गए विश्लेषण में आयात आंकड़े डीजीसीआईएंडएस (वाणिज्य मंत्रालय) से लिए गए हैं और वह आंकड़े भी समान प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं।
- 29. कुछ हितबद्ध पक्षकार यह तर्क देते हैं कि घरेलू उद्योग के संघटकों द्वारा अतिरिक्त प्रश्नावली दायर की गई थी। इसलिए, प्राधिकारी के पास प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करते समय संपूर्ण जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त वे यह तर्क भी देते हैं कि घरेलू उद्योग ने कोई श्रेयस्कर समायोजन योजना प्रदान नहीं की है और प्रारंभिक जांच परिणाम में उसका कोई उल्लेख नहीं है। इस संबंध में यह प्रेक्षा किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपने-अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर अपने आवेदन पत्र के साथ गोपनीय और अगोपनीय दोनों रूपों में दायर किए हैं। इन प्रश्नावली प्रत्युत्तरों का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराया गया है। हालांकि आवेदन में समायोजन योजना नहीं दी गई थी, परंतु घरेलू उद्योग के सभी संघटकों ने अपने-अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तरों में समुचित समायोजित योजना प्रदान कराई है।

छ. जांच की अवधि (पीओआई)

30. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि वर्ष 2013-14 को आधार वर्ष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इसमें वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 के बीच आयतों की अधोगामी प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखा गया है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि विश्लेषण की अविध 5 वर्ष की होनी चाहिए और छोटी अविध गलत है। इस संबंध में यह प्रेक्षा की गई कि न तो सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और न ही सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 में विशेष रूप से "जांच की अविध" को अथवा रक्षोपाय जांच के लिए अपेक्षित न्यूनतम अविध को परिभाषित किया गया है। रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में भी जांच की अविध का चयन करने के लिए कोई सामान्य या विशिष्ट प्रावधान या दिशानिर्देश नहीं दिया गया है। तथापि, जांच की अविध के मुद्दे को कोरिया के विरूद्ध यूएस लाइन पाइप मामले में (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201) में पैनल ने अपने निष्कर्ष में विस्तार से निपटारा किया है। इस मामले में पैनल ने यह निर्णय दिया कि यह आयातकर्ता सदस्य के जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि वह यह निश्चय करे कि "जांच की अविध की दीर्घता" तथा उसके "विभज्जन" की अविध क्या होगी:

'हम नोट करते हैं कि इस करार में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि रक्षोपाय जांच में जांच की अविध कितनी लंबी होनी चाहिए, और न ही यह उल्लेख है कि विश्लेषण के प्रयोजनार्थ भंग की अविध क्या होनी चाहिए। इस प्रकार जांच की अविध और इसके भंग होने की अविध जांचकर्ता प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दी गई है। हमारे समक्ष उपस्थित मामले में आईटीसी द्वारा चीन की गई अविध पांच वर्ष और छह माह थी, यह अविध अर्जेन्टीना फुटवीयर रक्षोपाय में अर्जेन्टीना की जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की गई जांच की अविध के समकक्ष है। तथापि, हम नोट करते हैं कि अपीलीय निकाय ने अपने जांच परिणाम में जांच की अविध की लंबाई के संबंध में तर्क देने के लिए कोरिया पर भरोसा किया है, उसमें न केवल अविध की लंबाई पर बल दिया गया है परंतु अभिनव आयातों पर फोकस होना चाहिए और न कि जांच की गई अविध पर। लाइन पाइप जांच में आईटीसी ने न केवल

अंतिम बिन्दु की तुलना में या जांच की अविध की समग्र प्रवृत्ति की जांच की (जैसा कि अर्जेन्टीना ने अर्जेन्टीना फुटवीयर रक्षोपाय में जांच के लिए किया था)। इसने पूरे 5 वर्षों के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आयातों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया और यह भी विचार किया कि क्या अंतिरम 1998 की तुलना में अंतिरम 1999 में वृद्धि हुई थी। हमारा विचार है कि एक ऐसी अविध का चयन करके जो 5 वर्ष छह माह की थी आईटीसी ने अनुच्छेद XIX और अनुच्छेद 2.1 से असंगत कार्य नहीं किया। यह निष्कर्ष निम्नलिखित विचारों पर आधारित है : प्रथम करार में ऐसा कोई विशिष्ट नियम नहीं है जिसमें जांच की अविध की लंबाई वताई गई हों; द्वितीय, आईटीसी द्वारा चयनित अविध अभिनव आयातों पर प्रकाश डालती है; और तृतीय, आईटीसी द्वारा चयनित अविध से निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त दीर्घ है।" (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201)

31. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इन तथ्यों तथा ऊपर उल्लिखित सूचना के स्रोत पर विचार करते हुए यह उचित माना जाता है कि वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 (पहली तिमाही के आधर पर वार्षिकीकृत) की अविध के लिए आंकड़ों को अपनाया जाए।

ड. प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता

रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.2 तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली,1997 के नियम 7 में कितपय सूचना को गोपनीय मानने का प्रावधान है। नियम में प्रावधान है कि किसी हितबद्ध पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन वास्तविक आधार पर करना अपेक्षित नहीं है जो कंपनी की गोपनीय सूचना हो और जिसका प्रकटन करने उक्त पक्षकार के व्यापारिक हितों को गंभीर क्षित पहुंचने की पूर्वावधारणा हो, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो और जिसका याचिकाकर्ता ने विगत में कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकटन न किया हो।

33. कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह आपत्ति व्यक्त की है कि याचिका में कई पैरामीटरों को गोपनीय के रूप में माना गया है और उन्हें गोपनीय के रूप में मानने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा कोई कारण नहीं बताए गए हैं। हितबद्ध पक्षकार यह तर्क भी देते हैं कि यहां तक कि प्राधिकारी ने भी प्रारंभिक जांच परिणाम में उन्हें गोपनीयता प्रदान करने का कोई कारण रिकार्ड नहीं किया है। मैं यह पाता हूं कि घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय नियमावली 1997 और दिनांक 06.09.1997 के व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/1/97 के प्रावधानों के अनुासर रक्षोपाय साधन का अनुप्रयोग करने के लिए आवेदनपत्र के गोपनीय और अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने अपने अगोपनीय पाठ में वित्तीय और लागत निर्धारण आंकड़ों को छिपाकर उनकी गोपनीयता का दावा किया है, जिसे मैं उपयुक्त पाता हूं।

च. संवर्धित आयात:

- 34. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की केंद्रीय सरकार के अधिकारों का उल्लेख करता है और इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है :
 - "(1) यदि केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच जिसे वह उचित समझे करने के पश्चात इस तथ्य से संतुष्ट है कि किसी वस्तु का भारत में इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जा रहा है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो तो यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकती है।"
- 35. नियमों में यह अधिदेशित किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग करने के लिए आयातों में वृद्धि होना एक आधारभूत पूर्वापेक्षा है। अत: यह निर्धारित करना कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि "इतनी अधिक मात्रा" में वृद्धि हुई है" कि उस पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना जरूरी हो, तो नियमों में यह विश्लेषण करने की अपेक्षा की गई है कि आयातों में यह वृद्धि संपूर्ण रूप में अथवा घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में हुई है।
- 36. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 2 में "संवर्धित मात्रा" की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है :
 - "(ग) संवर्धित मात्रा में आयातों में वृद्धि संपूर्ण रूप में या घरेलू उद्योग के संगत रूप में हुई वृद्धि होती है।"

37ना फुटवीयर ईसी में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया है कि पैनल के विपरीत अर्जेन्टी ,आयातों में वृद्धि की प्रकृति के संबंध में . आयातों में यह वृद्धिअभिनवत हो सके या गंभीर क्षति कारित तीव्र और इतनी अधिक होनी चाहिए कि उससे गंभीर क्षति कारि ,अचानक , : लिखित है हो सके। संगत उद्धरण निम्नन्नकरने की चुनौती उत्प

"131की अपेक्षा पूरी होती है "में इतनी अधिक मात्रा में बृद्धि" आयातोंकि क्या ,यह निर्धारण . या नहीं केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण नहीं है। दूसरे शब्दों मेंद के इस नहीं है कि इस उत्पाकिसी जांच में साधारण रूप से यह दर्शाना ही पर्याप्त , वर्ष किए गए आयात पिछले वर्ष या पांच वर्ष पहले हुए आयातों की तुलना में अधिक हैं। पुन :, ऐसा पुनरावृत्तिक लगता है कि , रक्षोपाय ,नहीं होगा। यह वृद्धि इतनी अधिक मात्रा में हो कि उससे त मात्रा में वृद्धि होना ही पर्याप्तआयातों में किसी निश्चि घरेलू उद्योग को क्षति कारित हुई हो या गंभीर क्षति कारित होने की ,साधन का अनुप्रयोग करने के लिए यह अपेक्षा पूरी होती हो चुनौती उत्पन्न हो गई हो और यह भाषा रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2. दके अनुच्छे 1994 टतथा गा 1XIX : 1 दोनों में (क) पर्याप्त ,क दोनों रूपों मेंक और गुणात्मपरिमाणात्म ,अपेक्षा करती है कि आयातों में यह वृद्धि ,स है किऔर हमारा विश्वा पर्, अचानकपर्याप्त ,अभिनवयाप्त तीव्र और पर्याप्ट महत्वपूर्ण हो जिससे कि रित हो सके या उसकी चुनौती का "गंभीर क्षति" "हो सके।ननउत्प

38: वत किया हैश का निर्वचन निम्नऐसी संवर्धित मात्रा में वाक्यां" टेन संबंधी पैनल नेट ग्लूयुएस व्ही .

8. 31[गाट दका अनुच्छे 1994XIX: 1) और रक्षोपाय करार (क)"एसए") का अनुच्छेद 2.1]में आयातों में केवल का "वृद्धि" के संबंध में विशिष्ट "वृद्धि" प्रकृति की क एवं गुणवत्ताद के आयातों में परिमाणात्मउनमें संबंधित उत्पा, ख नहीं है। बिल्कउल्ले का 1994 ख है। गाटजरूरत का उल्लेअनुच्छेद XIX: 12 दऔर एसए का अनुच्छे (क).बंधित दोनों यह अपेक्षा करते हैं कि सं 1 में किया जा (दन में संगत एवं समग्र रूप सेघरेलू उत्पा) द का आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा के भूभाग में किसी उत्पासदस्य रहा हो कि उससे गंभीर क्षित कारित हुई हो या गंभीर क्षित की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। अतआयातों में केवल कोई वृद्धि ही : ना फुटवीयर रक्षोपाय मामले में अपीलीय निकाय के जांच परिणाम से सहमत है कि यह हम अर्जेन्टी, नहीं होगी। बिल्क पर्याप्त अचानक तीव्र, अभिनवपर्याप्त, क दोनों रूपों मेंक और परिमाणात्मगुणात्म, वृद्धि और इतनी महत्वपूर्ण हो कि उससे "गंभीर क्षिति" कारित हो या गंभीर क्षिति की चुनौती उत्पन्न हो सके। "

39. इस विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों का विश्लेषण उपर्युक्त विधि और डब्ल्युटीओ न्याय शास्त्र के अनुरूप किया गया है।

समग्र रूप में संवर्धित आयात

40. उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है। इस पीयूसी का भारत में कई देशों से आयात किया जाता है जिनमें चीन जन.गण., रूस, उक्रैन, जापान और कोरिया शामिल हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह आपित्तयां उठाई हैं कि इस संबद्ध वस्तु के आयात गाट के अनुच्छेद XIX और एसए के आशय के अंतर्गत पर्याप्त अचानक पर्याप्त तीव्र, पर्याप्त अधिक और पर्याप्ट अभिनव नहीं है और इसलिए इस मामले में रक्षोपाय शुल्क अधिपत्रित नहीं है।

41. इस संबंध में मुझे हितबद्ध पक्षकारों के इस ऐतराज में कोई दम प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जांच की अवधि (15-16 की पहली तिमाही तक) के लिए डीजीसीआईएंडएस के आायत आंकड़ों का विश्लेषण अधोलिखित को दर्शाता है :

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	प्रवृत्ति
2013-14	1252441	100
2014-15	2644911	211
2015-16 (पहली तिमाही)	881233	70
2015-16 (वार्षिकीकृत)	3524932	281

42. उपर्युक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि आयातों में समग्र रूप से प्रोत्कर्ष हुआ है अर्थात आयात जो वर्ष 2013-14 की अविध के दौरान 1252441 एमटी थे बढ़कर वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) की अविध के दौरान 3524932 एमटी हो गए।

उत्पादन के संबंध में आयात

43. जांच की अवधि के दौरान भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में संपूर्ण भारतीय उत्पादन के संबंध में वृद्धि हुई है। संपूर्ण उत्पादन के संबंध में आयात वर्ष 2013-14 में 5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) में 13 प्रतिशत हो गए।

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	अखिल भारतीय उत्पादन (एमटी)	उत्पादन के संबंध में आयातों का प्रतिशत
2013-14	1252441	25510777	5
2014-15	2644911	26395795	10
2015-16 (पहली तिमाही)	881233	6646258	
2015-16 (वार्षिकीकृत)	3524932	26585032	13

44. उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि जांच की अविध के दौरान इन आयातों में कुल घरेलू उत्पादन की तुलना में समग्र रूप से एवं संगत रूप से, दोनों रूपों में अचानक तीव्र और भारी प्रोत्कर्ष हुआ है।

छ. गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण

- 45. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख की उपधारा 6(ग) में गंभीर क्षति को परिभाषित किया गया है।
 "गंभीर क्षति" का आशय उस क्षति से है जिससे घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र ह्वास होता हो।
- 46. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा 6(घ) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

"गंभीर क्षति की चुनौती" का आशय गंभीर क्षति के स्पष्ट एवं आसन्न खतरे से हैं।

47. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियम, 1997 के नियम 8 के अनुबंध के पैरा 1 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :

"जांच में यह निर्धारण करने के लिए कि क्या निरूपित उद्योग को गंभीर क्षति संवर्धित आयातों से हुई अथवा संवर्धित आयात गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं, महानिदेशक उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिमाणनीय प्रकृति का मूल्यांकन करेंगे जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो; और इसमें खासकर संबंधित वस्तु के आयातों में संपूर्ण एवं संगत रूप से दर एवं राशि में वृद्धि, बढ़े हुए आयातों द्वारा घरेलू उद्योग में हासिल किया गया हिस्सा, विक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ एवं हानि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन के संबंध में जांच शामिल होगी।"

48. घरेलू उद्योग के समग्र अवक्षयण के संबंध में इस पैनल के विपरीत अर्जेन्टीना फुटवीयर (ईसी) में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि प्रत्येक सूचीबद्ध फैक्टर का विश्लेषण अनिवार्यत- यह नहीं दर्शाएगा कि ऐसे प्रत्येक कारक में "गिरावट" आ रही है जिससे कि गंभीर क्षति का निर्धारण किया जा सके। संगत उद्धरण निम्नलिखित है:

जब उन सभी संगतकारकों क"े आलोक मेंति का घरेलू उद्योग की समग्र स्थि ,ित पर प्रभाव पड़ता हैिजनका उस उद्योग की स्थि ,
"भारी समग्र परिक्षयण" ति में उस उद्योग की स्थिकन किया जाता है तभी यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्यामूल्यांहुआ
है। यद्यपि अनुच्छेद 4.2(ककन किया जाना में तकनीकी रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि कितपय सूचीबद्ध कारकों का मूल्यां (
रूप से यह नहीं कन किया जाना चाहिए परंतु यह प्रावधान विशिष्टसंगत कारकों का मूल्यां सभीचाहिए और यह कि अन्य
कनबताता है कि इस मूल्यांमें क्या प्रदर्शित होना चाहिए। स्पष्टतः, ऐसा कोई भी मूल्यांकन किसी विशिष्ट मामले के कारकों
तथा संबंधित उद्योग की स्थिति के आधार पर भिन्नक होगा। प्रत्येभिन्न- उद्योगों के लिए भिन्नभिन्न-भिन्न , मामलों मेंभिन्नकन अनिवासूचीबद्ध कारक का मूल्यांर्यतक कारक में गिरावट आ रही है। उदाहरण के लिए यह प्रदर्शित नहीं करेगा कि ऐसे प्रत्ये :
भारी समग्र " ति मेरावट हो सकती है जो घरेलू उद्योग की स्थिदकता में भारी गिकिसी एक मामले में बिक्री रोजगार और उत्पा
दर्शाएगी और इसलिए यह गंभीर क्षति के कितिपय "परिक्षयण मामलों में गिरावट न हो परंतु ऐसे होते हुए भी समग्र तस्वीर उस

उद्योग की स्थिति में :करेगी। अत "भारी समग्र परिक्षयण प्रदर्शित", इस तकनीकी परीक्षण के अलावा कि क्या किसी विशिष्ट मामले में सक्षम प्राधिकारी ने सभी सूचीबद्ध कारकों और कितपय अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया हैस करते हैं हम विश्वा, दकरार के अनुच्छे, रक्षोपायक है कि वह गंभीर क्षति के निर्धारण की ऐसी कोई समीक्षा करते वक्तिक पैनल के लिए यह आवश्य 4. 1(क"न में रखेंगे।की परिभाषा को ध्या "गंभीर क्षति" में (

- 49. तदनुसार, गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का विश्लेषण करते समय उन सभी संगत कारकों पर विचार किया गया है, जिनका उल्लेख नियमावली में किया गया है और उन अन्य कारकों पर भी विचार किया गया जो गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए संगत है। गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का उन सभी संगत कारकों के आलोक में मूल्यांकन पर आधारित है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, जो निम्नलिखित हैं:
- **क. उत्पादन** : जैसा कि अधोलिखित तालिका में स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन जो वर्ष 2013-14 में 17881187 एमटी था, मामूली सा घटकर वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) में 17827180 एमटी रह गया।

वर्ष	घरेलू उद्योग का उत्पादन (एमटी)	प्रवृत्ति
2013-14	17881187	100
2014-15	17836937	100
2015-16 (पहली तिमाही)	4456795	
2015-16 (वार्षिकीकृत)	17827180	100

ख. बिक्री के स्तर में परिवर्तन : अधोलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री जो 2013-14 में 10342565 एमटी थी, घटकर वर्ष 2014-15 में 9949214 एमटी रह गई। इसके अतिरिक्त, आवेदक की बिक्री वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) के दौरान बढ़कर 10359716 एमटी हो गई जैसाकि अधोलिखित तालिका में देखा जा सकता है। बिक्री के स्तर में कोई भारी अंतर नहीं आया है :

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	घरेलू उद्योग की बिक्री (एमटी)	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री (एमटी)	घरेलू उद्योग की ग्राही बिक्री (एमटी)	अन्यों की ग्राही बिक्री (एमटी)	कुल मांग (एमटी)		ार हिस्सा (%)
							घ. उ.	आयात
2013-14	12,52,441	1,03,42,565	29,94,323	42,74,000	40,00,724	2,28,64,053	45	5
2014-15	26,44,911	99,49,214	32,98,273	50,19,741	46,15,864	2,55,28,003	39	10
2015-16 (पहली तिमाही)	8,81,233	25,89,929	10,65,972	13,21,497	11,80,681	70,39,312		
2015-16(वा.)	35,24,932	1,03,59,716	42,63,888	52,85,988	47,22,724	2,81,57,248	37	13

- ग. बाजार हिस्सा : उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि आयातों का वर्ष 2013-14 बाजार हिस्सा 5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) के दौरान 13 प्रतिशत हो गया, जबिक घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा उसी अवधि के दौरान 45 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशत रह गया।
- **घ. क्षमता उपयोग** : घरेलु उद्योग का क्षमता उपयोग कमोवेश रूप से उसी स्तर पर बना रहा, जैसा कि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है :

वित्तीय वर्ष	संस्थापित क्षमता (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)
2013-14	23568996	75.9
2014-15	23568996	75.7
2015-16 (पहली तिमाही)	5884372	
2015-16 (वार्षिकीकृत)	23537488	75.7

ड. रोजगार एवं उत्पादकता : क्षति अवधि के दौरान रोजगार और उत्पादकता की प्रवृत्ति समान बनी रही, जैसाकि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है :

वित्तीय वर्ष	कर्मचारियों की संख्या (अनुक्रमित)	प्रति कर्मचारी उत्पादकता (एमटी) (अनुक्रमित)
2013-14	100	100
2014-15	100	100
2015-16 (पहली तिमाही)	100	
2015-16 (वार्षिकीकृत)	100	100

च. **लाभ एवं हानि (अनुक्रमित)** : घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2015-16 (पहली तिमाही) के दौरान गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ। यह अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है :

वित्तीय वर्ष	लाभप्रदता (रुपए/एमटी) (अनुक्रमित)
2013-14	100
2014-15	136
2015-16 (पहली तिमाही)	(114)

छ. अन्य महत्वपूर्ण कारक:

(i) मालसूची : मालसूची जो वर्ष 2013-14 में 100 बिंदु थी बढ़कर वर्ष 2015-16 (पहली तिमाही) में 103 बिंदु हो गई जैसाकि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

वित्तीय वर्ष	माल सूची (एमटी)	मालसूची (एमटी) (अनुक्रमित)
2013-14	636879	100
2014-15	648290	102
2015-16 (पहली तिमाही)	657099	103

(ii) कीमत अधोरदन, निग्रहण/अवमंदन

क. आयातों की उतराई कीमत का परिकलन आयातों के कर निर्धार्य मूल्य पर अप्रैल 2013 से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत की दर से कस्टम ड्यूटी और शेष अवधि के लिए 10 प्रतिशत की दर से (औसतन) कस्टम ड्यूटी पर विचार करते हुए और फिर इन शुल्कों को आयातों के सीआईएफ मूल्य में जोड़कर किया गया है जो यह व्यक्त करता है कि घरेलू उद्योग हमेशा इस दबाव में रहा कि वह अपनी कीमतों आयात कीमतों के समान बनाने के लिए घटा दें अथवा अपनी कीमतों को स्थिर कर दें। इन संवर्धित आयातों का प्रवेशन अभूतपूर्व ढंग से इतने उच्च स्तर पर हुआ कि अपनी कीमतों में कमी कर देने के पश्चात् भी घरेलू उद्योग अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने मे सक्षम नहीं रह सका। आयातों की उतराई कीमत, बिक्री लागत, बिक्री कीमत का अंतर निम्नवत है:

संघटक (अनुक्रमित)	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	
				(पहली तिमाही)	
बिक्री लागत	रुपए/एमटी	100	97	94	
भारित औसत बिक्री प्रापण	रुपए/एमटी	100	99	83	
आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	100	95	78	
लाभ/(हानि)	रुपए/एमटी	100	136	(114)	

- ख. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि यद्यपि बिक्री लागत का इंडेक्स 100 से घटकर 94 पर आ गया, आयातों की उतराई कीमत 100 से तीव्रता से घटकर 78 रह गई, जिसके कारण बिक्री प्रापण में कमी आई जो 100 से घटकर 83 रह गया। बिक्री प्रापण के साथ-साथ बिक्री प्रापण में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट की तुलना में अधिक तेजी से हुई। लाभप्रदता इंडेक्स में भारी गिरावट आई। यह वर्ष 2014-15 में 136 था जो घटकर वर्ष 2015-16 (पहली तिमाही) में (114) रह गया।
- 50. उपर्युक्त सभी कारकों की जांच यह दर्शाती है कि यद्यपि कुछ कारक जैसे क्षमता उपयोग, मालसूची, रोजगार आदि स्थिर बने रहे वहीं लाभप्रदता में भारी गिरावट आई जिससे आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आई और आयात कीमतों में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे के रूप में गंभीर क्षति हुई।
- 51. हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा सहन की जा रही गंभीर क्षति उनके अपने आंतरिक कारकों के कारण आई है जिनमें निम्नलिखित कारक शामिल हैं :
 - उच्च ब्याज लागत, मूल्यह्रास और नियम लागत का बोझ
 - उच्च मालभाड़ा लागत तथा कमजोर अवसंरचना
 - कच्चे माल का संकट
 - क्षमताओं का कम उपयोग
 - विशिष्ट अनुप्रवाही उद्योगों की गुणवत्ता जरूरत को पूरा करने में अक्षमता।
- 52. यह सब दावे सामान्य प्रवृत्ति के हैं और उनके समर्थन में कोई तथ्य एवं आंकड़े नहीं दिए गए हैं। यह तथ्य पहले ही स्थापित हो चुका है कि घरेल उद्योग को क्षित भारत में इस पीयूसी के संवर्धित मात्रा में हुए आयातों के कारण हुई है। मैं यह पाता हूं कि घरेलू उद्योग कई वर्षों से मौजूद है और उसने विगत में अच्छा निष्पादन किया है। घरेलू उद्योग का अवसंरचना और क्षमताएं इस विचाराधीन वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। किसी इकाई की कार्यक्षमता कई कारकों पर निर्भर करती है और यदि उसकी कार्य क्षमता अधिक अच्छी होती तो संभवत: घरेलू उद्योग को रक्षोपाय कार्रवाई की मांग करने की जरूरत नहीं पड़ती। किन्हीं निश्चित क्षेत्रों में अकुशलता होना घरेलू उद्योग को रक्षोपाय साधन का संरक्षण प्रदान करने से मना करने का एक कारण नहीं हो सकता है। रक्षोपाय संरक्षण की मांग किए जाने, रक्षोपाय संरक्षण दिए जाने और दिया गया है उसके कारणों का उल्लेख रक्षोपाय करार के अंतर्गत यह है कि घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा कर सकने में सक्षम नहीं है और उसे इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से समायोजन करने में सक्षम बनने के लिए कुछ समय दिया जा सकता है। मुख्य निर्धारक कारक यह है कि गंभीर क्षति अथवा किसी गंभीर क्षति की चुनौती होनी चाहिए और इन संवर्धित आयातों के बीच उसका कारणात्मक संबंध हो। मैंने यह प्रेक्षण किया है कि इस संबद्ध वस्तु के आयातों में भारी वृद्धि हुई है जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है जिसका पीछे दिए गए पैराग्राफों में विधिवत साक्ष्यांकन कर दिया गया है।
- 53. इसके अतिरिक्त, पोस्को महाराष्ट्र ने यह तर्क दिया है कि वर्ष 2014-15 में आयातों में प्रोत्कर्ष मुख्यत: उनके द्वारा भारत में विनिर्माण क्रियाकलापों में प्रयोग करने के लिए किए गए आयातों के कारण आया है और यदि उसका अपवर्जन कर दिया जाता है तो आयातों में कमी हो जाएगी। इस संबंध में यह प्रेक्षण किया गया है कि आयातों में यह प्रोत्कर्ष न केवल 2014-15 में आया बल्कि यह वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में भी बना रहा। इसके अतिरिक्त, पोस्को ने यह उल्लेख किया है कि उसने अधिकतर आयात वर्ष 2015-16 की पहली दो तिमाहियों के दौरान किए हैं। एचआरसी, और प्रकृति से ही अनुप्रवाही उद्योग के लिए एक कच्चा माल है और इसका अधिकतर प्रयोग आगे विनिर्माण करने के लिए ही किया जाता है। इसलिए, पोस्को का मामला इस एचआरसी के अन्य उपभोक्ताओं से भिन्न नहीं है और इसलिए उनके द्वारा किए गए आयातों का, संवर्धित आयातों का निर्धारण करते समय कुल आयातों से अपवर्जन नहीं किया जा सकता है।

- 54. **विचाराधीन उत्पाद की ग्राही खपत:** कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि अनुप्रवाही इकाइयों के ग्राही आयातों को रक्षोपाय शुल्क से छूट देनी चाहिए। अधिकांशत: यह दावे पोस्को कोरिया और पोस्को महाराष्ट्र तथा हुंडई स्टील कोरिया और इसकी सहबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए हैं। इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि विधि के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें ग्राही उपभोग के लिए आयातित वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क से छूट देने का प्रावधान किया गया हो।
- 55. एफटीए तथा अन्य द्विपक्षीय करारों से असंगतता : हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि भारत कोरिया सीईपीए और भारत जापान सीईपीए में इस पीयुसी पर आयात शुल्क समाप्त करने का प्रावधान है। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि भारत को कोरिया आरपी एवं जापान से इस संबद्ध वस्तु के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आयात इन देशों से न्यून कस्टम्स ड्यूटी के कारण किए गए हैं। यह भी तर्क दिया गया कि भारत इन दोनों देशों के साथ अपने-अपने संबंधित एफटीए के अंतर्गत किसी द्विपक्षीय तंत्र का समन्वेषण कर सकता है, बजाय इसके कि वह कोरिया आरपी और जापान पर सामान्य रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करे। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क भी दिया कि भारत कोरिया सीईपीए में प्रावधान है कि यदि कोरिया आरपी से किए गए आयातों को रक्षोपाय का शुल्क का अधिरोपण करने से छूट दी जा सकती है। घरेलु उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि कोरिया आरपी और जापान दोनों देशों से हुए आयातों से घरेलू उद्योग और जापान दोनों देशों से हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। इस तथ्य का कोई महत्व नहीं है कि कोरिया आरपी और जापान से आयातों में संबंधित एफटीए के अंतर्गत न्यून कस्टम ड्यूटी के कारण वृद्धि हुई है। इन दोनों देशों से आयात अत्यधिक अभिनव अवधि में भारी मात्रा में हुए हैं और यह आयात बहुत की कम कीमत पर किए गए हैं जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है। इसके अतिरिक्त, यह भारत सरकार का विवेकाधिकार है कि वह संबंधित एफटीए के अंतर्गत किसी द्विपक्षीय तंत्र का समन्वेषण करे या इस मामले में सामान्य रक्षोपाय शुल्क को अपनाए। दोनों ही एफटीए में कहीं भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि भारत का यह दायित्व है कि वह पहले द्विपक्षीय तंत्र का समन्वेषण करे और उस तंत्र के असफल रहने पर ही सामान्य रक्षोपय शुल्क का प्रयोग किया जा सकता है। गैर-एफटीए वाले देशों से भी आयातों में भारी वृद्धि हुई है, इसलिए एफटीए के अंतर्गत रक्षोपाय कार्रवाई गैर एफटीए वाले देशों को अपने आयात और अधिक मात्रा में बढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। द्वितीयत:, एफटीए पर रक्षोपाय कार्रवाई शुल्क को केवल एमएफएन दरों से अनधिक तक ही समिति कर देती है, जो स्वयं में वर्तमान स्थिति का प्रशमन कर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह नोट किया जाता है कि इन एफटीए में विशिष्ट प्रावधान हैं जिनसे भारत को रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की अनुमति मिल जाती है। एसए और रक्षोपाय नियमावली के अंतर्गत केवल एक मात्र अपवाद उन विकासशील देशों का अपवर्जन करने का है जिनका आयातों में व्यक्तिगत हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है और जिनका आयातों में औसत हिस्सा 9 प्रतिशत से कम हो। कोरिया आरपी और जापान इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि उनमें से दोनों ही विकसित देश हैं। इस संबंध में घरेलु उद्योग के उत्तर से सहमत हं।
- 56. उपर्युक्त विश्लेषण से यह देखा जाता है कि इस पीयूसी की भारत में मांग क्षति विश्लेषण अविध के दौरान बढ़ी है। मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग के उत्पादन, रोजगार और बिक्री स्थिर ही बनी रही, जबिक मालसूची में कुछ वृद्धि रही। आयातों ने इस संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। वर्ष 2014-15 में ग्राही का अपवर्जन करते हुए मांग 1303069 एमटी थी और आयात इससे कहीं अधिक 1392470 एमटी थे। इससे वह आक्रामक तरीका प्रदर्शित होता है जिससे इस पीयूसी के आयात भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे है। घरेलू उद्योग ने भारत में मांग बढ़ने की संभावना का अनुमान लगाते हुए अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर ली। तथापि, घरेलू उद्योग अपना क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री बढ़ाने में असमर्थ रहे। उनकी लाभप्रदता में भारी कमी आई और इसमें वर्ष 2015-16 (पहली तिमाही) में भारी घाटा भी होने लगा। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट का मुख्य कारण कम कीमतों पर संवर्धित आयात है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो घरेलू उद्योग को आशंका है कि उसे बाजार दबाव के समक्ष अपने प्रचालन बंद करने पड़ेगे।
- 57. इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन एवं उपभोग के संगत रूप से भारी वृद्धि हुई है। आयातों में भारी प्रोत्कर्ष के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। घरेलू उद्योग ने अपने वित्त को लाभ के घाटे में बदलकर आयातों को विपरीत कार्य किया है।
- 58. अत: उन सभी संगत कारकों, जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, के आलोक में घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन "भारी समग्र अवक्षयण" दर्शाता है। अत: यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस पीयूसी के संवर्धित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति सहन करनी पड़ी है।
- 59. घरेलू उद्योग को आयातों में प्रोत्कर्ष और भारत में प्रवेश कर रही आयात मात्रा की सर्वाधिक अभिनव अविध की प्रवृत्ति के कारण गंभीर क्षित हुई है। आयातों की मात्रा पहले से ही उच्च स्तर पर होने के बावजूद निरंतर बढ़ती रही है। इस अविध के दौरान आयातों के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है। विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध बेशी उत्पादन क्षमता पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि आयातों में निरंतर वृद्धि होती रहेगी जैसािक पीओआई के पश्चात पैरा 100 के विश्लेषण से स्पष्ट है, इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को और अधिक क्षित होगी। आयातों में और अधिक वृद्धि होने की संभावना से यह निष्कर्ष निकलता है कि घरेलू उद्योग को अधिक गंभीर क्षिति होने की चुनौती उत्पन्न हो रही है। इस तथ्य के मद्देनजर कि घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में लाभप्रद बिक्रियां करने मे असमर्थ रहे हैं, मेरा यह विचार है कि रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण करने के अभाव में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षित का सामना करना पड़ रहा है और उसके समक्ष गंभीर क्षित की चुनौती भी उत्पन्न हो गई है।

ज. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे

60. काइल फार्म में इन हाट रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर रक्षोपाय शुल्क की अनुप्रयोज्यता जिनके लिए इस रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण करने से पहले संविदा कर ली गई थी:

कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से पहले, जिन संविदाओं पर एलसी अभी हाल में खोले गए हैं उनको रक्षोपाय शुल्क से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि, उनका विचार है कि अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण होना एक अनपेक्षित घटना है और इस अतिरिक्त शुल्क का प्रभाव अत्यधिक कटु होगा। तथापि, मैंने यह पाया है कि विधि अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिसमें इस छूट की अनुमति हो।

- 61. इस जांच के अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दे : कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह चिंता व्यक्त की है कि भारत ने अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के संबंध में डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित करने में समय लगाया। हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण भी किया है कि अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण सुनवाई का अवसर दिए बिना ही जल्दी जल्दी में कर दिया गया। इस संबंध में यह प्रेक्षण किया जाता है कि कुछ विलंब हुआ था तथापि, इसका आशय यह नहीं है कि अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करा ही रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 12.4 के प्रावधानों से असंगत है। प्रक्रियात्मक जरूरतों जैसे डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित करना को पूरा करने में हुआ मामूली सा विलंब के कारण अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क के गुणों से समझौता नहीं किया जा सकता है।
- 62. रक्षोपाय शुल्क नियमावली का नियम 9(1) प्राधिकारी को जांच की कार्रवाई शीघ्रता से आयोजित करने और संवेदनशील परिस्थितियों में, गंभीर क्षित तथा गंभीर क्षित की चुनौती से संबंधित प्रारंभिक जांच परिणाम रिकार्ड करने की अनुमित देता है। चूंकि इस मामले में संवेदनशील परिस्थितियां मौजूद है, इसलिए प्रारंभिक जांच परिणाम जारी कर दिया गया। इन परिस्थितियों के अंतर्गत, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन करें अथवा अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क कार्रवाई करने से पहले अन्य हितबद्ध पक्षकारों से परामर्श करें। मैं पाता हूं कि यह कार्रवाई एसए के प्रावधान के दायरे के अंतर्गत है।

झ. संवर्धित आयातों तथा गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध

63. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुसार महानिदेशक (रक्षोपाय), अन्य बातों के साथ-साथ, इन नियमों के अनुबंध में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करना होगा।" इसके अतिरिक्त अनुबंध का पैराग्राफ 2 में यह अपेक्षा या की जाती है कि आयातों में कथित वृद्धि और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करना भी अपेक्षित होता है। नियमावली के अनुबंध में पैराग्राफ 2 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"पैराग्राफ (1) में उल्लिखित निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि, उद्देश्यपरक साक्ष्य के आधार पर, जांच से यह स्पष्ट नहीं होता है कि संवर्धित वस्तु के संवर्धित आयातों तथा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध है। साथ ही, जब संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हो तो उस क्षति के लिए संवर्धित आयातों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।"

64. कोरिया डेयरी पैनल ने "कारणात्मकता" का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित आधारभूत अधिगम निर्धारित किया है।

"अपना कारणात्मक संबंध आकलन करने में हमारा विचार है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी को यह विश्लेषण करना और यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि क्या उद्योग में हुआ विकस, जिसे राष्ट्रीय प्राधिकारी ने गंभीर क्षति का प्रदर्शन करने के लिए विचारा है, संवर्धित आयातों के कारण कारित किया गया है। अपने कारणात्मक आकलन में राष्ट्रीय प्राधिकारी को उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक प्रकृति का मूल्यांकन करना होता है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी ने संवर्धित आयातों के अलावा कुछ अन्य ऐसे कारक अभिज्ञात कर लिए हों जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इन कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए यह नहीं माना जाएगा कि वह क्षति संवर्धित आयातों द्वारा कारित की गई है।

एक कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए कोरिया को यह प्रदर्शित करना कि इसकी घरेलू उद्योग को क्षति संवर्धित आयातों के कारण हुई है। दूसरे शब्दों में, कोरिया को यह प्रदर्शित करना पड़ा कि एसएमपीपी के आयातों द्वारा दुग्ध पावडर और अपरिष्कृत दुग्ध का उत्पादन करने वाली घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के उपरांत कोरियाई प्राधिकारियों की यह प्रतिबद्धता थी कि वह अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए संवर्धित आयातों को उत्तरदायी न ठहराएं।

- 65. कारणात्मक का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक प्रकृति के उन सभी संगत कारकों का मूल्यांकन किया गया जिनका घरेलू उद्योग की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। पिछले पैराग्राफों में गिनाए गए पैरामीटरों का विस्तृत मूल्यांकन करने से यह निदर्शित होता है कि इन संवर्धित आयातों द्वारा गंभीर क्षति की जा रही है और गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न हो गई है। वर्तमान मामले में निम्नलिखित तथ्य इस संबंध में महत्वपूर्ण हैं, जब वर्ष 2013-14 के आंकड़ों की तुलना वर्ष 2015-16 (पहली तिमाही के आधार पर वार्षिकीकृत) से की जाए:
 - (i) आयात की मात्रा 100 बिंदु (1252441 एमटी) से बढ़कर 281 बिंदु (3524932 एमटी) हो गई।
 - (ii) आयातों का बाजार हिस्सा 5 प्रतिशत से बढ़कर 13 प्रतिशत हो गया और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 45 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशत हो गया।
 - (iii) कम होती आयात कीमतें घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कायम रखने से निवारित कर रही है।
 - (iv) कम कीमत पर संवर्धित आयातों के कारण घरेलू उद्योग भारत में इस विचाराधीन उत्पाद की मांग/खपत में हुई वृद्धि की दर से अपने उत्पादन और उसकी बिक्री में वृद्धि करने में अक्षम रहा है।
 - (v) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष् 2015-16 (पहली तिमाही) के दौरान भारी गिरावट आई है और इन संवर्धित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भारी घाटा हुआ है।
- 66. उपर्युक्त के मद्देनजर में यह पाता हूं कि आयातों में संवृद्धि तथा घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति के बीच एक प्रत्यक्ष सह संबंध है क्योंकि समग्र रूप से इन आयातों में वर्ष 2015-16 (पहली तिमाही के आधार पर वार्षिकीकृत) के दौरान आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में लगभग तीन गुणा वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा धीरे-धीरे कम हो रहा है अर्थात यह 45 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशत हो गया है। आयात की प्रति टन उतराई कीमत में तेजी से गिरावट आई है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को भारी घाटा हुआ है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को यह क्षति संवर्धित आयातों द्वारा कारित की गई है।

ञ. समायोजन योजना

- 67. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5(2)(ख) में "आयात प्रतिस्पर्धा के साथ सकारात्मक समायोजन करने के लिए बनाई गई योजना या किए जा रहे प्रयासों या दोनों" के संबंध में प्रस्तुतिकरण करना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 7.1 में प्रावधान है कि कोई सदस्य रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग समायोजन को सुलभ बनाने तथा गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए आवश्यकतानुसार कर सकता है।
- 68. निर्णयात्मक रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को एक सीमित समयाविध प्रदान करना है जिसके अंदर वे अपना इस तरह पुनर्गठन कर सकें जिससे कि वे आयातों के साथ कारगर ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख(4) तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 के नियम 16(2) में ऐसे साधन का उपयोग करने का निषेध किया गया है तब ऐसे साक्ष्य हों कि घरेलू उद्योग समायोजन का प्रयास नहीं कर रहा है।
- 69. घरेलू उद्योग ने घरेलू उत्पादों की प्रश्नावली में अपनी-अपनी समायोजन योजना प्रस्तुत की है, जिसमें वर्षवार प्रक्षेपित बचत को दर्शाया गया है। निर्धारित समायोजन योजना का विवरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

क. स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

- (i) कोकिंग कोल लौह अयस्क, फ्लक्सेस और फेरो अलाय की प्रापण लागत में बचत करना।
- (ii) स्टोर्स एवं स्पेयर्स, रिफ्रैक्टरीज, रोल्स, लुब्रीकेन्ट्स आदि जैसी विभिन्न मदों की प्रापण लागत को कम करने और उतराई लागत को न्यून बनाने के लिए कच्चे माल के स्नोतों को संयंत्र से इष्टतम रूप से जोड़ना।
- (iii) उपलब्ध परिसंपत्तियों की प्रचालन कुशलता में सुधार करना।
- (iv) आयातित हार्ड कोकिंग कोल के प्रतिस्थापन के रूप में प्रत्येक संयंत्र में आयातित साफ्ट कोकिंग कोल के प्रयोग में वृद्धि करके कोल ब्लेंड लागत में कमी करना।
- (v) सकल धात्विक यूनिट में कमी और कान्कास्ट उत्पादन में वृद्धि करना।

- (vi) बॉयलर कोल के स्थान पर ग्राही/जेवी पावर प्लांट लगाकर गैसों जैसे सीओ गैस, बीएफ गैस और एलडी गैस की रिकवरी अधिकतम करके विद्यत तथा अन्य ईंधन लागत में कमी करना।
- (vii) ब्लुमिंग मिल्स/स्लैबिंग मिल के उत्पादन में सुधार करके विभिन्न प्रक्रियाओं की कार्यकृशलता बढ़ाना।
- (viii) सेल की आधुनिकीकरण योजना से उत्पादन, उपज में सुधार उर्जा संपरिवर्तन और उत्पाद क्वालिटी में सुधार होगा।

ख. एस्सर स्टील लिमिटेड

- (i) हजारिया में मल्टी फ्यूल पावर प्लांट की शुरूआत करने से बेशी कोरेक्स गैस और कोल फिन्स का उपयोग करके लागत में कमी करने में सहायता मिलेगी।
- (ii) सरकारी नीलामी स्कीम के अंतर्गत अवाप्स खानों से उच्च क्वालिटी के लौह अयस्क फिन्स से कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार करने की नम्यता प्राप्त होगी और तदद्वारा उत्पादकता में सुधार होगा एवं कीमत कम होगी।
- (iii) एस्सार ओडिसा में अवस्थित अपनी सुस्थापित परिष्करणों और पैलेट सुविधाओं के आसपास की माइन्स का अधिग्रहण करने और स्लरी पाइपलाइन का उपयोग करके उसका परिवहन करने की योजना बना रहा है। परिवहन के लिए स्लरी पाइपलाइन का प्रयोग करने से लागत में काफी कमी आएगी।
- (iv) पारादीप में पैलेट प्लांट 2 की शुरूआत करने से पैलेट्स की इन-हाउस कम लागत पर इन-हाउस उपलब्धता बढ़ेगी।
- (v) कैप्टिव कोक ओवन की शुरूआत करने के परिणामस्वरूप कोक की लागत में कमी आएगी और उसकी गुणवत्ता संगत होगी।
- (vi) टेक्नांलोजिकल यूनिट्स की स्किन्फर्मिंग करना और संबंधित सुविधाओं का संस्थापन करना जिससे प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम होगी और स्टील निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी।

ग. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

- (i) हाट ब्लास्ट तापमान में सुधार करके, ईटीए सीओ में वृद्धि करके ईंधन की खपत में कमी करना।
- (ii) आइडल भाड़ा, गोवा से अतिरिक्त संचलन में कमी करके और मंगलौर पत्तन से आवाजाही में कमी करके सभारतंत्र लागत में कमी करना।
- (iii) एसएमएस 1 पर फ्लेयर स्टैक बर्नर्स को एलपीजी से कोक ओवन गैस में परिवर्तित करके एलपीजी की खपत को कम
- (iv) कोबल्स में कमी करके और स्केल क्षति, साल्वेज क्षति और क्राप इंड क्षति में कमी करके एचएसएम यील्ड में सुधार
- (v) बेहतर एलडी गैस रिकवरी के लिए स्टील मेटल शाप से कोरेक्स गैस होल्डर तक नई लाइन की शुरूआत करना।
- (vi) सिंटर प्लांट्स में माइक्रो पैलेट्स में सीडीक्यू फिन्स का प्रयोग करके ठोस ईंधन में कमी करना।
- (vii) सिंटर में एन्थ्रासाइट खपत में कमी करना, अल्युमीनियम खपत में कमी करना।
- (viii) इन्वेंट कंडीशन मानिटरिंग, निवारणात्मक अनुरक्षण और भविष्यसूचक (ब्रेकडाउन) अनुरक्षण।

70. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा यह उल्लेख भी किया गया कि उपर्युक्त समायोजन योजनाओं से कंपनियों को अपनी लागत में कमी करने की अच्छी स्थिति प्राप्त होगी, इससे बेहतर मार्जिन मिलेगा और बिक्री प्राप्ण में वृद्धि होगी। मैंने यह पाया है कि आवेदकों ने व्यवहार्य समायोजन योजनाएं प्रदान की हैं जिनमें लागत कम करने, इष्टतम उपयोग करने और उत्पादन क्षमताओं में विस्तार करने पर प्रकाश डाला गया है, इससे वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के साथ समायोजन करने में सक्षम होंगे।

ट. अनपेक्षित विकास

71. गाट के अनुच्छेद XIX के साथ पठित रक्षोपाय करार में राष्ट्रीय प्राधिकारियों को उस "अनपेक्षित विकास" की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। इसलिए उन परिस्थितियों या "अनपेक्षित विकास" की जांच करना जरूरी माना गया है जिनसे आयातों में वृद्धि हुई है।

- 72. अर्जेन्टीना फुटवियर (ई सी मामला) में अपीलीय निकाय ने धारित किया कि पदबंध अनपेक्षित विकास का आशय उस विकास से है जो अप्रत्याशित हो। "अनपेक्षित विकास" यह अपेक्षा करता है कि वह विकास जिसके कारण किसी उत्पाद का इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में निर्यात किया जा रहा हो कि घरेलू उत्पादकों को अप्रत्याशित गंभीर क्षति होने लगी हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।
- 73. अर्जेन्टीना फुटवियर मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि अनपेक्षित विकास की जरूरत रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए कोई पृथक "शर्त" स्थापित नहीं करता है, परंतु यह केवल परिस्थितियों के एक निश्चित "समूह" को वर्णित करता है।
- 74. पैनल ने यूएस स्टील रक्षोपाय के संबंध में यह निष्कर्ष दिया कि कई घटनाओं का समग्र संगठित होकर अनपेक्षित विकास का आधार बन सकता है :

".......संयुक्त राज्य यह तर्क देता है कि यूएस डालर में मजबूती होना ऐसा विकास था जिसने अन्य विकासों नामश: एशिया और पूर्ववर्ती यूएसएसआर में मुद्रा संकट और संयुक्त राज्य बाजार में स्टील की मांग में निरंतर वृद्धि जबिक अन्य बाजारों में गिरावट आई के साथ मिलकर आयातों में वृद्धि कर दी।"

- 75. आवेदकों ने यह उल्लेख किया है कि कई देशों में स्टील विनिर्माताओं, जिनमें चीन जन.गण. रूस, उक्रैन, जापान और कोरिया शामिल हैं, ने विकासत देशों और शेष विश्व द्वारा स्टील की मांग को पूरा करने की भारी क्षमताओं का विकास किया है। अधिकांश विकसित देश जो स्टील के परम्परागत रूप से सबसे बड़े आयातक थे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने आयातित स्टील पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। इस विकास ने चीन जन.गण., उक्रैन आदि से विकसित देशों को निर्यातों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इन देशों के विनिर्माताओं को अपना उत्पादन बेचने के तरीके सोचने पड़े। एक विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत इन विनिर्माताओं को अपनी बेशी क्षमताओं को बेचने के लिए एक प्राकृतिक विकल्प लगा।
- 76. एक प्रख्यात जर्नल स्टील 360 की रिपोर्ट के अनुसार, रूस के स्टील निर्यातक अपनी मुद्रा, जो अभी हाल ही में दुर्बल पड़ गई थी, के कारण अपने निर्यातों के लिए उच्च प्रापण प्राप्त करने का अनुभव कर रहे हैं। तेल की कीमतों में कमी के कारण मुद्रा दुर्बल होना एक अनपेक्षित घटना है। कमजोर मुद्रा से रूसी स्टील द्वारा निर्यातों में वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त, रूस के निर्यातकों को, उक्रैन में संकट के कारण यूरोपियन यूनियन और उक्रैन जैसी परम्परागत बाजारें तक प्रतिबंधित पहुंच प्राप्त हुई, इसके परिणामस्वरूप भारत को इसके निर्यातों में वृद्धि हुई। यह सभी घटनाएं अनपेक्षित हैं।
- 77. रूस के हस्तक्षेप के कारण उक्रैन में हुई राजनीतिक अशांति के परिणामस्वरूप वर्ष 2014 के दौरान ही उक्रैन की मुद्रा "हरिटिनया" में लगभग 60 प्रतिशत की तीव्र मूल्यह्रास हुआ। यह एक अनपेक्षित विकास था। उक्रैन में लंबी अशांति के कारण इसकी अर्थव्यवस्था में संकुचन आ गया और इसकी मुद्रा का यूएस डालर की तुलना में तेजी से अवमूल्यन हुआ। तथापि, उक्रैन की मुद्रा का अवमूल्यन होने से उसके स्टील उत्पादकों/निर्यातकों को अपने कम कीमत वाले निर्यातों से विश्व स्टील बाजार में और अधिक दबाव बनाने में सहयोग मिला। इस तथ्य का कोई अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और जर्नल्स में सुस्पष्ट प्रलेखन है कि उक्रैन ने स्टील की कीमतों को कम करने और अपनी बेशी स्टील को उन देशों को विपथित करने जहां अच्छी मांग थी, में रूस और चीन जनगण का साथ दिया।
- 78. चीन जन.गण. की घरेलू मांग बहुत कम है हालांकि पिछले कई दशकों से इसकी वृद्धि दर निरंतर बढ़ रही थी। वृद्धि दर में यह गिरावट अचानक और अप्रत्याशित थी। अवसंरचना सेक्टर, खासकर हाउसिंग, जो चीन जन.गण. में स्टील का सबसे बड़ा उपभोक्ता था, मंदी के दौर से गुजर रहा था। चीन जन.गण. के विनिर्माता अपने उत्पादन की घरेलू उद्योग में बिक्री करने में असमर्थ रहे। इसके परिणामस्वरूप, चीन में इस समय कुछ सौ मिलियन टन की बेशी क्षमता है। ऐसी संभावना है कि आने वाले कुछ समय में इस स्थिति में

कोई परिवर्तन नहीं आएगा और चीन का स्टील प्रयोग ऋणात्मक वृद्धि होने लगेगी जो वर्ष 2015 और 2016 में -0.5 प्रतिशत थी। इसके परिणामस्वरूप भारत जैसे देशों को निर्यात एक स्वाभाविक विकल्प है क्योंकि भारत में स्टील की मांग सदैव ही बढ़ती रही है। चीन जन.गण. में ऐसी आंतरिक कारकों से चीन जन.गण. से आयातों में अचानक प्रोत्कर्ष हुआ।

- 79. कई हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि याचिकाकर्ता उस अनपेक्षित विकास के अभिज्ञात करने में असफल रहे जिसके कारण इस संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि हुई। कुछ हितबद्ध पक्षकार यह दावा करते हैं कि प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणाम में अनपेक्षित विकास पर चर्चा करने में असफल रहे और कुछ हितबद्ध पक्षकार यह दावा भी करते हैं कि अनपेक्षित विकास का अभिज्ञान तो किया गया परंतु वह इसका इस संबद्ध वस्तु से सह संबंध स्थापित नहीं कर सके। कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि भारतीय रुपए का अवमूल्यन और उपयोक्ताओं द्वारा उसका स्थानीय अधिप्रापण इस अनपेक्षित विकास को दूर कर देगा। इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि याचिका में उन सभी अनपेक्षित विकास का विस्तार से उल्लेख किया गया है जिनके कारण इस पीयूसी के आयातों में अचानक, तीव्र, भारी और अभिनव वृद्धि हुई जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई अथवा क्षति की गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई। प्रारंभिक जांच परिणाम और वर्तमान जांच परिणाम में भी इस अनपेक्षित विकास पर काफी विस्तार से ओर तर्कसंगत ढंग से चर्चा हुई।
- 80. कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि प्राधिकारी को गाट के अनुच्छेद XIX में उल्लिखित शर्तों के अनुसार जांच करनी चाहिए कि भारत द्वारा गाट के अंतर्गत उपचित दायित्वों के प्रभाव जिनमें टैरिफ रियायतें, भी शामिल है, इस पीयूसी के आयातों में कैसे अचानक, तीव्र, भारी और अभिनव वृद्धि हुई। यद्यपि रक्षोपाय करार और रक्षोपाय शुल्क नियमावली प्राधिकारी को यह विश्लेषण करना अधिदेशित नहीं करते हैं तथापित गाट के अनुच्छेद XIX से यह कर्तव्य उत्पन्न होता है। अपीलीय निकाय ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रेक्षण किया हैं :

"यह पदावली कि "इस करार के अंतर्गत सदस्य द्वारा उपिचत दायित्वों, जिनमें टैरिफ रियायतें भी शामिल हैं, के प्रभाव" का आशय यह है कि, वास्तव में, यह निदर्शन होना चाहिए कि आयातक **देश को गाट यह दायित्व, जिनमें टैरिफ रियायतें शामिल हैं,** गाट 1994 के अंतर्गत निदर्शित हुए है"

(कोरिया – डेयरी मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय रिपोर्ट)

- 81. इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि डब्ल्यूटीओ को रियायतों की अनुसूची के अनुसार इस पीयूसी पर भारत की बाध्य पर यथामूल्य 40 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रेक्षण किया गया कि भारत कई सेक्टरों में वस्तुओं पर अपने अनुप्रयुक्त टैरिफ दरों में कमी करता रहा है। इस कार्य का एकमात्र उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है ताकि भारत विश्व व्यापार में बेहतर ढंग से समावेशित है। यह इस पीयूसी के लिए विशेष रूप से सच है जिसके भारत ने लागू दर को कम करके 2013-14 और 2014-15 में 7.5 प्रतिशत कर दिया। यह देखा जा सकता है कि इस लागू न्यून प्रशुल्क दर के प्रभाव से, इस पीयूसी का वर्तमान परिस्थितियों और बाजार स्थिति के अंतर्गत आयातों का होना एक चांस है जिससे इतनी अधिक मात्रा में अचानक, तीव्र और भारी आयात होने लगे।
- 82. उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप और गाट अंतर्गत दायित्वों, जिनमें प्रशुल्क रियायतें भी शामिल हैं, के प्रभाव के कारण इस पीयूसी के आयातों में भारत में आयात इतनी अधिक अचानक, तीव्र, भारी मात्रा में हुए।

ठ. जनहित

83. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित उल्लेख है :

"कोई भी सदस्य रक्षोपाय साधन का प्रयोग विगत में स्थापित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके उस सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच करके ही किया जा सकता है और गाट 1994 के अनुच्छेद X के साथ तालमेल में सार्वजनिक किया जाएगा। इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों उपयुक्त सार्वजनिक नोटिस देना, सार्वजनिक सुनवाई करना अथवा कोई अन्य उपयुक्त उपाय शामिल होंगे जिनमें आयातक, निर्यातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने साक्ष्य और अपने विचार व्यक्त कर सकें, इसमें अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का प्रत्युत्तर देने तथा अपने विचार व्यक्त करने का अवसर भी शामिल हो कि क्या इस रक्षोपाय साधन का प्रयोग करना जनहित में होगा या नहीं। सक्षम प्राधिकारी अपने जांच परिणाम देते हुए तथा विधि एवं तथ्यों के संगत मुद्दों पर तर्कयुक्त निष्कर्ष देते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।

- 84. कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से अनुप्रवाही उद्योग प्रभावित होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से अनुप्रवाही उत्पादों का आयात बढ़ जाएगा।
- 85. इस संबंध में मैं यह प्रेक्षण करता हूं कि भारत में भारी संख्या में ऐसे अनुप्रवाही उद्योग हैं जो सीआर कॉइल, पीसी/जीसी शीट्स पाइप्स एवं ट्यूब्स कलर कोटेड शीट्स आदि का उत्पादन करने के लिए एचआर काइल्स का प्रसंस्करण करते हैं। स्टील एक आधारभूत कच्चा माल है और इसकी खपत आटोमोबाइल मशीनरी, अवसंरचना, निर्माण, ऑयल एवं गैस उद्योग जैसे भारी संख्या में उत्पादों में किया जाता है। इसलिए एचआर काइल्स की कीमतों में कोई बढ़ोतरी करने का सीधा प्रभाव अनुप्रवाही उद्योगों पर पड़ेगा। अनुप्रवाही उत्पादों पर किसी भी प्रकार के शुल्क का अधिरोपण किए बिना एचआर काइल्स पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का भारत में मूल्यवर्द्धनकारी अनुप्रवाही उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से इन वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त, अनुप्रवाही उद्योगों को कोई समान सुरक्षा प्रदान किए बिना, केवल कच्चे माल पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से एक प्रतिलोमित शुल्क ढांचा तैयार हो जाएगा जिससे अनुप्रवाही उत्पाद महंगे हो जाएंगे और आयात संगतत: अधिक सस्ते हो जाएंगे। यह विशेष रूप से उस उद्योग के मामले में अधिक सच होगा जहां एचआर काइल इनपुट की लागत तथा उस उत्पाद का एक प्रमुख संघटक है। सीआर काइल, पाइप्स और ट्यूब्स आदि उद्योग, जिनकी एचआर काइल इसकी बड़ी लागत होती है, सर्वाधिक प्रभावित होंगे। इन कारणों से इन अनुप्रवाही उद्योगों की लाभप्रदता पर भारी प्रभाव पड़ेगा।
- 86. रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का इंजीनियरिंग के सामान के उन छोटे-छोटे निर्यातकों पर भी प्रभाव पड़ेगा जो अपनी जरूरत की एचआर काइल्स की तलाश स्थानीय बाजार में करते है। रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कर देने से कच्चे माल के रूप में एचआर काइल अधिक मंहगी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, शुल्क प्रति अदायगी का कोई ऐसा सामान्य नियम नहीं है जो रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव की रक्षा कर सके। इससे यह निर्यातक विश्व बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे।
- 87. दूसरी ओर स्टील उद्योग में लाखों करोड़ रुपए का सार्वजनिक निवेश को गैर-कार्यनिष्पादन करने वाली परिसंपत्ति बनने का जोखिम है। इसलिए, घरेलू उद्योग को परिरक्षण का उपयुक्त कवच प्रदान कराना आवश्यक है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो घरेलू उद्योग की कीमतों और बाजार हिस्से दोनों में गिरावट आ जाएगी। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को इस हद तक वित्तीय घाटा होगा कि घरेलू उद्योग अर्थक्षम ही नहीं रहेगा। साथ ही इससे बेरोजगारी बढ़ेगी तथा देश के कार्यनीतिक एवं आर्थिक हित को क्षति पहुंचेगी।
- 88. इसलिए, एक युक्तियुक्त स्तर पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना उचित होगा क्योंकि यह उपभोक्ताओं के दीर्घावधिक हित में होगा कि भारतीय घरेलू उद्योग को इतना प्रतिस्पर्धी एवं प्रदीप्यमान बनाना कि वह इस विचाराधीन उत्पाद का उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने में सक्षम बन सके और विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। यह तभी संभव है जब घरेलू उद्योग को संवर्धित आयातों द्वारा सहन की गई क्षति की भरपाई करने के लिए कुछ अस्थायी सहायता प्राप्त करें। अंतत: यह जनहित में है कि भारतीय घरेलू उद्योग सशक्त एवं प्रतिस्पर्धी हो।

ड. विकासशील राष्ट्र

89. विकासशील देशों से वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 (पहली तिमाही) की अविध के दौरान आयातों के प्रतिशत की भी जांच की गई। चीन जन.गण. और उक्रैन जिनका भारत में कुल आयातों में हिस्सा क्रमश: 24 प्रतिशत और 4 प्रतिशत है, को छोड़कर, अन्य सभी विकासशील राष्ट्रों का भारत के कुल आयातों में उनका व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से क्रमश: 3 प्रतिशत और 9 प्रतिशत से कम हिस्सा है। इसलिए दिनांक 05.02.2016 की अधिसूचना संख्या 19/2016-कस्टम्स (एनटी) के साथ पाठित दिनांक 14.12.1988 की यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 103/98 कस. में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, चीन जन.गण. और उक्रैन को छोड़कर अन्य सभी विकासशील देशों में उदभवित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(1) के परंतुक में उल्लिखित शर्तों के अनुसार रक्षोपाय शुल्क आकृष्ट नहीं होगा।

ढ. अनन्तिम साधन

90. प्रारंभिक जांच पड़ताली परिणाम में यह धारित किया गया था कि इस पीयूसी के संवर्धित आयातों के पीयूसी के घरेलू उत्पादों को गंभीर क्षित कारित की है और गंभीर क्षित कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर दी है। यह भी प्रेक्षण किया गया कि कुछ ऐसी संवेदनशील परिस्थितियां मौजूद हैं जहां इस रक्षोपाय साधन को लागू करने में हुआ थोड़ा सा विलंब भी घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षित कारित करेगा। घरेलू उद्योग द्वारा वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही के दौरान कई क्षित पैरामीटरों, जिनका उल्लेख उपरिवर्णित एक पैराग्राफ में किया गया है, में सहन की गई क्षित पर विचार करते हुए, यह धारित किया जाता है कि आपूरणीय क्षित की संभावना को दूर करने के लिए इस मामले में अनन्तिम साधन का प्रयोग किया जाना न्यायोचित है।

ण. विदेशी सरकारों/राजदूतावासों द्वारा उठाई गई उन विशिष्ट आपत्तियों का उत्तर जिन पर उपर्युक्त जांच परिणाम में चर्चा नहीं की गई थी।

तुर्की गणराज्य

- 91. तुर्की का यह तर्क है कि उसे रक्षोपाय शुल्क के दायरे से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वह एक विकासशील देश है। इस संबंध में, मैं यह पाता हूं कि भारत की दिनांक 14 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या 103/98-सीयूएस के तहत तुर्की को विकासशील देश के रूप में नहीं माना गया है। तथापि, दिनांक 05.02.2016 की अधिसूचना संख्या 19/2016-कस्टम्स (एनटी) के तहत तुर्की को विकासशील देशों की सूची में शामिल कर लिया गया है और वर्ष 2013-14 से 2015-16 (पहली तिमाही) के दौरान भारत को हुए कुल आयातों में तुर्की के आयातों की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत से कम है, इसलिए इस विचाराधीन उत्पादन के तुर्की मूल के आयातों पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(1) के परंतृक के अनुसार दिनांक 05.02.2016 से रक्षोपाय शुल्क आकृष्ट नहीं होता है।
- 92. तुर्की के इस तर्क के संबंध में कि भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ को गई गई अधिसूचना में अनपेक्षित विकास की मौजूदगी के संबंध में कि स्पष्टीकरण/विश्लेषण युक्तियुक्त अथवा उपयुक्त नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, मैं यह पाता है कि इस मामले में दिनांक 01.09.2015 के प्रारंभिक जांच परिणाम में सभी पैरामीटरों की स्पष्ट जांच की गई है और इस मामले में अनपेक्षित विकास सहित सभी विषयों पर चर्चा की गई है।

चाइनीज ताइपेई

93. ताइवान ने यह तर्क दिया है कि उसका नाम दिनांक 14 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या 109/98-सीयूएस के तहत अधिसूचित विकासशील देशों की सूची में नहीं है और यह अनुरोध किया है कि उपर्युक्त अधिसूचना को अद्यतन बनाया जाए ताकि एक विकासशील देश के रूप में ताइवान की आर्थिक स्थिति सही-सही प्रतिबिंबित हो सके जिससे कि विकासशील राष्ट्रों को उपलब्ध छूट उसे भी उपलब्ध हो सके। तथापि, चूंकि ताईवान को अभी तक दिनांक 05.02.2016 की अधिसूचना संख्या 19/2016-कस्टम्स (एनटी) के साथ पाठित दिनांक 14.12.1998 की अधिसूचना संख्या 103/98-सीयूएस के अंतर्गत भारत सरकार ने विकासशील राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है, इसलिए विकासशील राष्ट्रों को प्राप्त छूट का लाभ ताइवान प्राप्त नहीं होगा।

उक्रैन का राजदूतावास

94. उक्रैन ने वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए पैरामीटरों की इंड-टू-इंड आधार पर जांच की है और यह तर्क दिया है कि उसके आयात इतने अधिक नहीं हैं कि वे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षित संकेतक घरेलू विक्रियों, उत्पादन, बाजार हिस्सा, क्षमता उपयोग के लिए सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं और इस मामले में रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 और 4.2 (ख) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग को क्षित अपने, बाजार हिस्से को अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा के लिए जाने के कारण हुई है। इस संबंध में उक्रैन के तर्क को स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि जांच की अवधि 2013-14 से 2015-16 (पहली तिमाही के आधार पर वार्षिकीकृत) तक की ली गई है और इस अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद के आयात में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है जबिक घरेलू संकेतक जैसे बाजार हिस्सा एवं लाभप्रदता ऋणात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं जैसािक आगामी पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है। प्रश्न यह है कि क्षति निर्धारण पर विचार करने के लिए स्वीकार करने पर तब तक कोई प्रतिबंध नहीं है जब तक कि क्षति विश्लेषण भी उसी अवधि से संबंधित हो और आयातों में प्रोत्कर्ष अभिनव एवं अत्यधिक हो।

यूरोपीय कमीशन

- 95. कमीशन ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि रक्षोपाय साधन का प्रयोग केवल आपवादित स्थितियों में ही किया जाना चाहिए और यह मामला तो पाटनरोधी अथवा सब्सिडी रोधी जांच के लिए उपयुक्त है। इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि, इस समय, इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक, तीव्र, अत्यधिक एवं अभिनव वृद्धि होने से भारतीय स्टील उद्योग बड़ी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। भारतीय इस्पात उद्योग को पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई चर्चा के अनुसार अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप इन आयातों के कारण गंभीर क्षति सहन कर रहे हैं। मैं यह पाता हूं कि इस मामले में रक्षोपाय शुल्क की सही ही सिफारिश की गई है और यह सिफारिश आयातों के इस अचानक प्रोत्कर्ष से घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए की गई है।
- 96. कमीशन के इस तर्क के संबंध में कि इस संबद्ध वस्तु के कितपय विशिष्ट ग्रेडों को इस उत्पाद के दायरे से अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग उनका विनिर्माण नहीं कर रहा है, मैं यह प्रेक्षण करता हूं कि कमीशन ने उन विशिष्ट ग्रेडों की पहचान नहीं की है जिनका घरेलू उद्योग उत्पादन नहीं करता है और जिसके लिए अपवर्जन अपेक्षित है। विशिष्ट ग्रेडों के संबंध में सूचना के अभाव में घरेलू उद्योग इस स्थिति में नहीं है कि वह उनके तर्कों का उत्तर दे सके और इसलिए कमीशन के सुझाव पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

97. कमीशन का यह तर्क है कि ग्राही बिक्री तथा अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा की गई बिक्री की जांच की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, कमीशन यह भी करता है कि अन्य भारतीय उत्पादकों ने अपनी खुली बाजार बिक्री में 42 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर ली है। इस संबंध में, मैं यह प्रेक्षण करता हूं कि अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी आई है, जबिक, घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में वर्ष 2014-15 और 2015-16 (पहली तिमाही) की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2 प्रतिशत की गिरावट आई है। (जांच परिणाम का पैरा 49(ख)। इसके अतिरिक्त, आयातों ने इस संबद्ध वस्तु की बढ़ी हुई समस्त मांग पर कब्जा कर लिया है। वर्ष 2014-15 में मांग में (ग्राही को छोड़कर) 1303069 एमटी की वृद्धि हुई वहीं आयातों में 1392470 एमटी की वृद्धि हुई।

ब्राजील गणराज्य

98. ब्राजील ने यह तर्क दिया है कि चूंकि भारत अनित्तम रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की अधिसूचना को इसक अधिरोपण से पहले अधिसूचित करने में असफल रहा है, भारत एसए के अनुच्छेद 12.4 के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा है। इस संबंध में मेरी राय यह है कि एक प्रक्रियात्मक जरूरत जैसे डब्ल्यूटीओ को अधिसूचना से अनित्तम रक्षोपाय शुल्क के गुणों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। इस मद्दे पर पैरा 61 में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है।

99. ब्राजील ने यह मुद्दा उठाया है कि प्राधिकारी ने प्रत्येक निर्यातक देश के हिस्से की सूचना नहीं दी है और विकासशील देशों की सूची भी प्रदान नहीं कराई गई है। ब्राजील यह तर्क भी देता है कि प्रत्येक स्रोत से आयात की मात्रा का परिकलन करने के लिए जिस अवधि पर विचार किया गया है उसे भी विशेषीकृत नहीं किया गया है। ब्राजील यह तर्क देता है कि उसको यह सूचना प्रदान कराए जाने के कारण वह एसए के अनुच्छेद 3.1 के अंतर्गत रक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में सफल नहीं हो पाया है। इस संबंध में मैं यह प्रेक्षण् करता हूं कि भारत में होने वाले आयातों के देशवार संव्यवहार की जानकारी घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदनपत्र के साथ दी गई थी और इस जानकारी को इस मामले में जांच शुरूआत नोटिस का परिचालन करते समय सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की गई थी। इस दस्तावेज को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल में भी रखा गया। अत:, एसए के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार कोई असंगतता नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 (पहली तिमाही) की अवधि में कुल आयातों का 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है इसलिए इस पीयूसी के ब्राजील से होने वाले आयातों को रक्षोपाय शुल्क के दायरे से अलग कर दिया गया है।

त. पीओआई के पश्चात के आंकड़ों की जांच

100. इन हालातों में जांच की अवधि के पश्चात की अवधि अर्थात वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही तक के आंकड़ों की प्रवृत्ति का विश्लेषण घरेलू उद्योग को क्षति के प्रवलन की संभावना के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष निकालने के लिए किया गया। घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात किए गए प्रस्तुतिकरणों में भारत में आयातित इस "विचाराधीन उत्पाद" के लिए कुछ आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में घरेलू आंकड़े प्रस्तुत किए है। आंकड़ों का यह विश्लेषण निम्नलिखित है:

	2013-14	2014-15	2015-16 (पहली तिमाही के आधार पर वार्षिकीकृत)	2015-16 (पहली तथा दूसरी तिमाही के आधार पर वार्षिकीकृत)
कुल आयात (एमटी)	1252441	2644911	3524932	4587168
उत्पादन (एमटी)	17881187	17836937	17827180	16796006
घरेलू बिक्रियां (एमटी)	10342565	9949214	10359716	10504640
कुल मांग (एमटी)	22864053	25528003	28157248	30268388
आयातों का बाजार हिस्सा (%)	5	10	13	15
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा (%)	45	39	37	35
मालसूची (एमटी)	636879	648290	657099	871440

लाभ/(हानि) अनुक्रमित	100	136	(114)	(120)

101. उपर्युक्त आंकड़ों की संवीक्षा करने से यह प्रेक्षण किया गया कि जांच की अविध के पश्चात की अविध अर्थात 2015-16 (पहली तिमाही + दूसरी तिमाही) (वार्षिकीकृत) के दौरान, पहली से दूसरी तिमाही की अविध के बीच आयातों में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अविध के दौरान आयातों का बाजार हिस्सा 2 प्रतिशत बढ़ गया और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2 प्रतिशत की कमी आ गई। इसके अतिरिक्त उत्पादन में लगभग 6 प्रतिशत की कमी आई जबिक पोस्ट पीओआई के दौरान घरेल बिक्रियों में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे यह प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के बीच औद्योगिक पैरामीटरों में तीव्र गिरावट आई है।

थ. निष्कर्ष

102. उपर्युक्त जांच और विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि :

- (i) इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन के संबंध में और संगत रूप में भारी वृद्धि हुई है। कुल मांग के संबंध में भी आयातों मे भारी प्रोत्कर्ष हुआ है।
- (ii) इस जांच से यह संकेत मिलता है कि सूचीबद्ध आर्थिक पैरामीटरों जैसे बाजार हिस्सा, लाभप्रदता जिसमें आधार वर्ष से लेकर वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) से तीव्र गिराव आई के आधार पर समग्र निष्पादन पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति हुई है जबिक उसी अविध के दौरान आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। इससे घरेलू उद्योग का भारी समग्र अवक्षयणकारित हुआ है। इससे जांच की अविध के दौरान घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति और बढ़ते आयातों के बीच कारणात्मक संबंध स्पष्ट हो जाता है।
- (iii) घरेलू उद्योग यह निदर्शन करने में समर्थ रहा है कि इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में प्रोत्कर्ष के लिए बाजार विकास बिल्कुल अनपेक्षित है।
- (iv) इस पीयूसी, जो अनुप्रवाही उद्योगों के लिए एक कच्चा माल है, पर रक्षोपाय शुल्क के परिणामस्वरूप अनुप्रवाही उद्योगों पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- (v) यह भी सिद्ध किया जाता है कि इस मामले में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जनहित में होगा क्योंकि इससे घरेलू उद्योग को अपनी स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि अंतिम प्रयोक्ता घरेलू उद्योग से इस संबद्ध वस्तु की स्थिर आपूर्ति प्राप्त करेंगे।
- (vi) जांच की अविध के पश्चात की अविध के आंकड़ों का विश्लेषण करने से यह प्रेक्षण किया गया कि घरेलू उद्योग की स्थिति में बिक्री उत्पादन और बाजार हिस्से के रूप में और भी अधिक गिरावट आई। इस प्रकार में यह निष्कर्ष निकालता हूं कि गंभीर क्षति/गंभीर क्षति की चुनौती मौजूद है और घरेलू उद्योग को इस संरक्षण में और अधिक विस्तार किए जाने की जरूरत है।

द. सिफारिश

इस "विचाराधीन उत्पाद" के भारत में संवर्धित आयातों से इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षित कारित हुई है और गंभीर क्षित कारित होने की चुनौती उत्पन्न हो गई है और सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 12 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार दो वर्ष और छह माह की अविध के लिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में होगा। इस अविध की संगणना दिनांक 14.09.2015 की अधिसुचना संख्या 2/2015-सीयुएस (एसजी)

के तहत रक्षोपाय का अनन्तिम उदग्रहण करने की तारीख से की जाएगी। बिक्री लागत पर तर्कसंगत प्रतिलाभ की अनुमित देने के पश्चात, घरेलू उत्पादकों द्वारा इस विचाराधीन उत्पाद की औसत बिक्री लागत पर विचार करते हुए, अधोलिखित रक्षोपाय शुल्क, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के उपशीर्षक 7208 और 72253090 के अंतर्गत आने आने वाले इस विचाराधीन उत्पाद पर, घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित के रूप में माना जाता है, अधिरोपित करने की सिफारिश की जाती है।

वर्ष	संस्तुत रक्षोपाय शुल्क	अवधि
पहला वर्ष	20% की दर से यथामूल्य रक्षोपाय शुल्क (पाटनरोधी शुल्क यदि कोई, को घटाकर),	14.09.2015 से 13.09.2016
दूसरा वर्ष(प्रथम छह	18% की दर से यथामूल्य रक्षोपाय शुल्क (पाटनरोधी शुल्क यदि कोई, को	14.09.2016 से
माह के लिए)	घटाकर),	13.03.2017
दूसरा वर्ष(अगले छह	15% की दर से यथामूल्य रक्षोपाय शुल्क (पाटनरोधी शुल्क यदि कोई, को	14.03.2017 से
माह के लिए)	घटाकर),	13.09.2017
तीसरे वर्ष (छह माह के	10% की दर से यथामूल्य रक्षोपाय शुल्क (पाटनरोधी शुल्क यदि कोई, को	14.09.2017 से
लिए)	घटाकर),	13.03.2018

क. चूंकि चीन जन.गण. और उक्रैन को छोड़कर अन्य विकासशील देशों से आयात व्यक्तिगत रूप से 3 प्रतिशत से अधिक और सामूहिक रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होते हैं इसिलए, चीन जन.गण. और उक्रैन को छोड़कर अन्य विकासशील देशों से उदभवित इस विचाराधीन उत्पाद के आयात सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) के परंतुक में उल्लिखित शर्तों के अनुसार रक्षोपाय शुल्क आकृष्ट नहीं होगा। तुर्की को दिनांक 05.02.2016 की अधिसूचना संख्या 19/2016-कस्टम्स (एनटी) के तहत विकासशील देश के रूप में मान्यता दी गई है। इसिलए, तुर्की के मूल के विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर दिनांक 15.02.2016 से रक्षोपाय शुल्क आकृष्ट नहीं होगा।

[फा. सं. डी-22011/26/2015-पार्ट-III] विनय छाबड़ा, महानिदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF SAFEGUARDS

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2016

Subject: Safeguard investigation concerning imports of "Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more" **into India Final Findings.**

G.S.R. 308(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 thereof.

A. PROCEDURE

- 1. An application was filed under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as "Safeguard Rules"] by M/S Steel Authority of India Limited; M/S Essar Steel India Limited, and M/S JSW Steel Limited through M/S Lakshmi Kumaran & Sridharan Attorneys, New Delhi seeking imposition of Safeguard Duty on imports of "Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more", as increase in imports is causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producers.
- 2. The product under consideration is "Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more" hereinafter referred to as 'PUC' (Product under consideration) classifiable under Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975, under tariff heading 7208 and tariff item 72253090. The applicant has claimed that these products are not further worked than hot-rolled and are flat products of iron, alloy or non-alloy steel, in prime or non-prime condition having 'as-rolled' edge or 'trimmed' edge or 'slit' edge. These products may be pickled or non-pickled (with or without skin-pass or tempering), slit or non-slit and having nominal width of greater than or equal to 600mm. These products may be as-rolled or thermo-mechanically rolled or thermo-mechanically controlled rolled or controlled rolled. These products may have patterns in relief derived directly from rolling. These products may have been subjected to various processing steps like pickling, oiling, rewinding, temper rolling, heat treatment, etc.

The following are not included in the scope of the product under consideration:

- a) Hot-rolled flat products of steel with nominal width less than 600mm;
- b) API grade steel;
- c) Silicon electrical steel;
- d) Hot-rolled flat products of steel of spring steel quality;
- e) Hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc;
- f) Hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc; and
- g) Hot-rolled flat products of stainless steel.
- 3. In order to satisfy the requirements under Rule 5 of the said Safeguard Rules, the information presented by the applicant was verified by on-site visit to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. The non-confidential version of verification report was kept in the public file. On being satisfied that the requirements of Rule 5 were satisfied, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of "Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more" into India was issued under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 7th September, 2015 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day.
- 4. A copy of the Notice of Initiation dated 7th September, 2015 along with copy of non-confidential version of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government, in the Ministry of Commerce, and other Ministries concerned, Governments of major exporting countries through their Embassies in India, and the Interested Parties listed below, in accordance with Rule 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. Questionnaires were also sent, on the same day, to all known domestic producers and importers and exporters and they were asked to submit their response within 30 days.

4.1 Domestic Producers

- a. M/s Essar Steel India Limited,
- b. M/s Steel Authority of India Limited,
- c. M/s JSW Steel Limited,
- d. TATA Steel Limited, Mumbai,
- e. M/s Jindal Steel & Power Limited, Gurgaon,
- f. M/s Bhushan Steel Limited, New Delhi.

4.2 Known Importers (M/s):

- a. Alstom India Ltd., Mumbai
- b. Arcelor Neel Tailored Blank Private Limited, New Delhi
- c. Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi
- d. Bhilai Engineering Corporation Ltd., Bhilai, Chattisgarh
- e. C.R.I. Pumps Private Limited, Coimbatore
- f. Caterpillar India Pvt. Ltd., Chennai
- g. Denis Plast Limited, Gandhinagar Mehsana, Gujarat
- h. Desmi Equipments Pvt.Ltd., Thane(W), Maharashtra
- i. Escorts Ltd., Faridabad
- j. Exedy India Limited, Aurangabad, Maharashtra
- k. Fine Forge Limited., Hyderabad
- 1. Flakt (India) Limited, Chennai
- m. Gamesa Wind Turbines P.Ltd, New Delhi
- n. Ganpati Enterprises, Jaipur
- o. Hindustan Shipyard Ltd., P.O. Gandhigram, Visakhapatnam
- p. Hindustan Construction Co. Ltd., Vikhroli(W), Mumbai
- q. IDL Explosives Limited PO Kukatpally, Hyderabad,
- r. IFB Automotive Private, Kolkata(W.B.)
- s. JBM Industries Ltd., New Delhi
- t. JCB India Limited, New Delhi
- u. Kalinga Fixtures Ltd. Parel, Mumbai
- v. Kalpataru Power Transmission Ltd., Gandhinagar, Gujarat
- w. Larsen & Toubro, Mumbai, Maharashtra
- x. Lloyds Steel Industries Ltd, Mumbai, Maharashtra
- y. Maruti Suzuki India Limited, New Delhi
- z. MPP Technologies Private Ltd., Bangalore
- aa. NCL Indutries Limited, Hyderabad
- bb. Neel Metal Products Ltd., New Delhi
- cc. Orient Impex, Chennai
- dd. Orient Weartech, Chennai
- ee. P & H Joy Mining Equipment India Limited, Kolkata
- ff. POSCO Electrical Steel India Pvt. Ltd., Mumbai
- gg. Ravi Steel Co., Andher(E), Mumbai
- hh. SG Iron Works Private Limited, Kolkata
- ii. Shakti Pumps (India) Ltd., Indore
- jj. Shelf Drilling Offshore Services (India) Pvt.Ltd, Powai, Mumbai
- kk. Shree Chamunda Enterprises, Navi Mumbai
- 11. Superior Steel Industries, Mumbai
- mm. Tranter India Private Limited, Pune
- nn. TRF Limited, Jamshedpur
- oo. Viraj Impex Pvt.Ltd., Mumbai
- pp. Virgo Industries, Panchkula.
- qq. Welspun Corp Ltd., Dist-Kutch, Gujarat
- rr. Wudtools, Mumbai
- ss. Yatin Steels India Pvt. Ltd., Mumbai
- tt. YSI Automotive P Ltd, Chennai
- uu. Zyfix Tools Private Limited-II, Balanagar, Hyderabad

4.3 Known Exporters (M/s):

- a. Nippon Sumitomo, Japan.
- b. Kobe, Japan
- c. JFE Steel Corporation, Japan
- d. POSCO, Korea
- e. Hyundai Steel Co Ltd, Seoul
- f. Dongkuk Steel Mill Col Ltd., Seoul
- g. Ilyich Iron & Steel Works, Ukraine
- h. Severstal Steel, Belarus
- i. Zaprostahl, Ukraine
- i. Azvostah, Ukraine
- k. Alchesck, Ukraine
- 1. Mobarakeh Steel Company, Esfahan
- m. Pt.KrakatauPosco Steel works, Indonesia
- n. Arcelor Mittal, Luxembourg
- o. Dillenger and Salzitter, Germany
- p. Arcelor Mittal, Brazil
- q. Rizhao, China
- r. Betai Iron & steel, China
- s. Baotou Iron and Steel Group, China
- t. Jiangsu Shagang Group Company Limited, Jiangsu Province, PRC.
- u. Tonghua Iron Steel Group Corporation, China
- v. Angang Steel Company, China
- w. Nanjing Iron and Steel, Nanjing, People's Republic of China
- x. Tangshang Iron & Steel, Tangshan, Hebei.
- y. Wuhan Iron and Steel, China
- z. Tianjin Iron & Steel Group Co Ltd, China

4.4 Exporting country Government

- a. Embassy of Indonesia
- b. Embassy of Ukraine
- c. Embassy of the Russian Federation
- d. Embassy of Korea RP
- e. The Embassy of People's Republic of China
- f. Embassy of Japan

5. Request to consider as an interested parties were received from the following parties:

- a. ArcelorMittal Brasil S.A., Brazil
- b. ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. Luxembourg
- c. China Iron and Steel Association, China
- d. CORSMA, New Delhi
- e. Devki Nandan J. Gupta Iron and Steel Merchants, Mumbai
- f. Dmson's Metal Pvt. Ltd., Andheri (West), Mumbai
- g. EEPC India, New Delhi
- h. Embassy of Brazil, New Delhi
- i. Embassy of Turkey, New Delhi
- j. European Union Delegation to India, New Delhi
- k. Federation of Association of Maharashtra (FAM)
- 1. Federation of Industries of India (FII), Delhi
- m. Hero Steels Limited, Hero Nagar, Ludhiana
- n. Honda Cars India Limited, GNOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)
- o. Hyndai Steel Company, Seoul, Republic of Korea
- p. Japan Chamber of Commerce and Industry in India (JCCII), New Delhi

- q. Jawandamal Dhanamal Iron and Steel Merchants, Mumbai
- r. JFE Steel Corporation, Japan
- Kobe Steel Ltd.
- t. Magnitogorsk Iron & Steel Works, Kirov stret, 93
- u. Magnum Steels, Khar (W), Mumbai
- v. Manaksia Steels Ltd, Bikaner Building, Kolkata
- w. Metal One Corporation India Pvt. Ltd., New Delhi
- x. Ministry of Economic Development of Russian Federation, New Delhi
- y. Ministry of Industry and Trade, Russian Federation, New Delhi
- z. Mitsui & Co. Ltd, Japan
- aa. Mudhra Fine Blanc Pvt Ltd, Chennai
- bb. Nezone Strips Limited, Kolkata
- cc. Nezone Tubes Limited, Kolkata
- dd. Nippon Steel & Sumikin Pipe India Pvt. Ltd., Neemrana Dist. Alwar (Raj.)
- ee. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Japan
- ff. Nisshin Steel Co. Ltd., Japan
- gg. POSCO India Delhi Steel Processing Centre Pvt. Ltd., Rewari
- hh. POSCO International Trade Affairs Group, POSCO Centre, Korea
- ii. Posco-Maharashtra Steel Pvt. Ltd.,
- ji. Prabhat Steel Traders Pvt. Ltd., Mumbai
- kk. Ratnamani Metals & Tubes Ltd., Ahemdabad
- ll. RKB Global Pvt Ltd.
- mm. RNV Industries Pvt. Ltd., Mumbai
 - nn. S M Steels, Borivali (W), Mumbai
 - oo. Severstal Management, Russian Federation, Vologda Regio, Cherepovets Mira Str., 30
 - pp. Shree Krishna Steels, Carnac Bunder, Mumbai
 - qq. SSZ Commodities Pvt. Ltd., Dist. Raigad
 - rr. Steel Drum Association of India, Chembur, Mumbai
 - ss. The Bombay Iron Merchants' Association, Carnac Bunder, Mumbai
 - tt. The Japan Iron and Steel Federation, Japan
 - uu. Trade Representation of Russian Federation, New Delhi
 - vv. TT Steel Service India Pvt. Ltd., Ramanagara Distt. Bidadi
- ww. Tube Investment of India, Chennai
- xx. Turakhia Ferromet Pvt. Ltd., Carnac Bunder, Masjit (E) Mumbai
- yy. V.K. Industrial Corporation Limited, Carnac Bunder, Mumbai
- zz. Van Bael & Bells, Belgium [on behalf of Metinvest Holding (Ukraine)]
- 6. All the above requests were accepted. Some of the interested parties requested for grant of extension for filing their reply to the notice of initiation. Their requests were accepted and they were granted extension.
- 7. The Domestic Industry has made a request for immediate interim relief by way of provisional safeguard duty in their application filed. In support of the same they have submitted details of their precarious condition based on listed economic parameters showing existence of critical circumstances being faced by them and prayed that in case provisional safeguard duty is not levied they would face irreparable damage, difficult to repair.
- 8. The request made by the domestic industry for imposition of provisional safeguard duty was examined and it was prima facie found that there exist critical circumstances which warranted imposition of provisional safeguard duty in order to provide interim relief to the domestic industry from suffering irreparable damage, which could have been difficult to repair.

- 9. Accordingly, the Preliminary Findings for Provisional safeguard duty was issued under Rule 9 (2) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 9th September, 2015 and was published in the Gazette of India vide G.S.R.690(E) on the same day i.e. 9th September, 2015.
- 10. Provisional safeguard duty was subsequently imposed vide Ministry of Finance, department of revenue Notification No. 02/2015-Cus (SG) dated 14th September, 2015 imposing Safeguard duty @20% for a period not exceeding 200 days from the date of issue of the Notification concerned.
- 11. Thereafter, a public hearing was held on 16th November, 2015. The interested parties, along with the Domestic Industry made oral submissions at the time of Public hearing. In terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 1997, all the interested parties who participated in the public hearing were requested to file written submission of the views presented orally.
- 12. Copy of written submissions filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties.
- 13. All the views expressed by the interested parties in their written submissions in pursuant to the public hearing held on 16th November, 2015 were examined and have been taken into account in making appropriate determination. The non confidential version of the information received or acquired has been kept in the public file.
- **B. POST INITIATION SUBMISSIONS:** The submissions received post initiation but prior to the Public Hearing are summarized as under:

Submissions by Embassies and Delegations from countries

I. The Embassy of the Russian Federation and the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation

- a. Substantial increase of the export of commodity from the Russian Federation to India did not happen.
- b. In addition, the export of commodity from Russia to India is not the reason of Indian producers' damage.
- c. According to official data with the Russian Federation from its federal agency, export of the commodity from the Russian Federation has fallen.
- d. The reasons for initiation of a special safeguard investigation are insufficient and unconvincing for the following reasons:
 - i. Stable number of employees and level of productivity of the India domestic industry may be associated with a full load capacity and sufficient labour resources.
 - ii. Profitability of the Indian domestic industry increase in 2014-15 in comparison to 2013-14.
 - iii. Increase in inventory of the domestic industry is very small (2-3%)
 - iv. There is decline in the proportion of imports from the Russian Federation in total volume of imports of the commodity into India.
 - v. There is insignificant effect due to share of sales of Russian manufacturers on the Indian market.
 - vi. The investigation should be completed with respect to the Russian Federation without taking action.

II. Embassy of the Republic of Indonesia

- a. As per the WTO Appellate Body Report in Argentina Import Footwear, WT/DS121/R, increased imports within the meaning of Article 2.1 of the Agreement on Safeguards has been defined as "recent, sudden, sharp and significant", both qualitatively and quantitatively. The comparison of imports as per the data on record shows no recent, sudden, sharp and significant increase at all both quantitatively and qualitatively.
- b. Imports of PUC have decreased by 97% on 2014-15 to 33% on 2015-16 (Annualised). Thus, there is no valid reason to establish critical circumstances for the imposition of provisional safeguard measure as required by Article 6 of the Agreement on Safeguards since no increased import within the meaning of Article 2.1 of the Agreement on Safeguards has taken place.
- c. As per UN Comtrade data, the share of imports of the PUC originating from Indonesia in 2014 is less than 3%. Provisional safeguard duty has been imposed on a general heading of 7208, which includes both "coils and plates". This will cause loss to Indonesia's exporters, since Indonesia's share of imports of PUC is less than 3%, in fact only 0.75% compared to the total world import into India.
- d. Indonesia is a developing country and exporter of the PUC. However, PUC originating from Indonesia has specific types (not in coil and/or hot rolled plate) and the share of imports is less than 3%. Therefore, Indonesia strongly requests to exclude it from the imposition of safeguard duty.

- e. PT Krakatau POSCO, an exporter from Indonesia has only exported certain products under the classification of "not in coil and/or hot-rolled plate". Therefore, it is clear that there is no export of the steel product with specific type of "in coils" from Indonesia. The Authority should issue an immediate clarification about the classification of the PUC on whether the type of not in coil and plate are also included under the PUC as the subject goods in this safeguard investigation.
- f. Since there is no import of the PUC under the classification of "not in coil and/or plate" originating from Indonesia into India, especially from PT Karakatau POSCO, imports from Indonesia cannot cause injury to India's domestic industry.
- g. Indonesia's import market share is only 2% in total imports of plates. Therefore, imports from Indonesia cannot cause serious injury to Indian domestic market.
- h. Most of the imports into India, except China, is happening from Asian countries under India-ASEAN FTA, India-Japan CEPA and India-Korea CEPA on concessional duty, even though India had increased import duty on flat steel product in 2015.
- i. Imposition of provisional safeguard measure is inconsistent with the Agreement, and it is requested that Indonesia should be excluded from imposition of safeguard duty.

III. Embassy of the Republic of Korea

- a. There would be little negative impacts, if any, on the Indian domestic steel industry resulting from imports of HR steel products from Korea, since most of imported products are consumed for raw materials in Korean corporation, to produce high quality steel products specially used for automobile industry in India.
- b. Chapter 2 (Trade in Goods) Section B-2 (Trade Remedies Safeguard Measures) Article 2.27 (Global Safeguard Measures) in the Korea-India CEPA stipulates that a party taking a safeguard measure under Article XIX of GATT 1994 and the Safeguards Agreement may, to the extent consistent with the obligation under the WTO Agreement, exclude imports of an originating good of the other Party, if such imports are not a substantial cause of serious injury or threat thereof. Korea believes that HR steel products imported from Korea are subject to this clause since the negative impact of the imports from Korea on the Indian domestic market is limited.
- c. Korean corporations' import of HR steel products from Korea is part of their contribution toward 'Make in India', as they are importing high quality HR steel products to provide to the Indian authorities. For instance, POSCO-Maharashtra Pvt. Ltd. produces high quality steel products specially used for automobile industry in India. The import of HR steel is unavoidable since local procurement is limited considering the need to meet the high quality and sufficient quantity demanded by its key customer, automobile industry. Korea fears that the imposition of the safeguard measures on imports of HR steel from Korea will cause a severely adverse effect on downstream industries and consumers in India.
- d. Korean corporations' commitment and contribution to be a genuine partner of 'Make in India' and 'Invest in India' should be fully considered. POSCO, as one of the major Korean corporations in India, has invested more than USD 1 billion and is currently operating 6 plants in India. Especially, through its subsidiary company in India (POSCO-Maharashtra Pvt. Ltd.), POSCO recently completed the construction for 1.8 MTPA downstream steel plant in the State of Maharashtra to produce high quality steel products specially used for automobile industry in India.
- e. Causal link is lacking between increase in imports from Korea and the serious injury that the Indian industry claims to have suffered. It is also difficult to acknowledge that the increase in imports is a result of unforeseen development.
- f. The current situation in the global steel industry and the increase in demand of the product in question in India could explain the increase of imports.
- g. A great majority of the product imports from Korea is used by downstream industries. In particular, 100% of the hot-rolled (HR) products exported by POSCO Korea are used for re-rolling in Indian steel mills (i.e. POSCO Maharashtra), and pickling and oiling (P0) steel exported by Hyundai Steel Korea are used as intermediary products in Hyundai Motors India.
- h. Considering the public interest of India's downstream industries, particularly India's steel and automobile manufacturing industries, the levying of duties on Korean EIRC products may harm India's domestic industry.
- i. We must renew our commitment to the multilateral trading system in order to prevent protectionism during this global economic slowdown.

IV. The Royal Embassy of Saudi Arabia

- a. According to the Export-Import Data Bank of the Department of Commerce of India, imports of the product under consideration from the Kingdom of Saudi Arabia account for significantly less than 3 percent of total imports into India during the period from 2013-14 to 2015-16 (Apr Jul.).
- b. Imports from developing countries that are members of the WTO and that are not major suppliers of the product concerned to India account for less than 9 percent of total imports.

- c. Because the Kingdom of Saudi Arabia is a developing country WTO member, its exports should be excluded from the scope of any safeguard measure India may decide to impose on imports of the product concerned further to the safeguard investigation.
- d. In line with the obligations under Article 9.1 of the Agreement on Safeguards, imports from the Kingdom of Saudi Arabia should be exempted from any safeguard measure India may impose on the product under consideration.

V. European Union

a. The safeguard instrument should be used in exceptional circumstances only. When imports come from one or several sources, the anti-dumping or anti-subsidy instrument, which targets unfair practices from these specific countries, would be more effective. Safeguard measures on the other hand, since they are applied equally to imports from all sources, often limit legitimate market access to imports that are not causing injury.

Increased imports

- b. While imports increased overall, a breakdown of imports by domestic is not provided in the report on preliminary findings. However, in relation to the unforeseen development, sources such as China, Russia and Ukraine are mentioned. As indicated above, in cases where imports increase mainly from one or several sources, the anti-dumping or anti-subsidy instrument would be more suitable.
- c. The domestic industry does not produce grades falling under HS codes 72253090, 72082590 and 72082790, as per the information available with the Commission. If the absence of domestic production is confirmed, these grades should be excluded from the product scope as it would be impossible to conclude that these grades can be the cause of any injury. Any measures on these grades would unduly harm the downstream industry, in particular, automotive end users, as they would confront a limited choice, lesser quality and/or higher prices.

Injury and causality

- d. The data for 2015-16 has been extrapolated based on 1st quarter only. This methodology is likely to lead to biased conclusions. An objective analysis should be based on comparative periods using actual figures. At the very least, the actual data for the second quarter should have been included.
- e. Even when taking into account the annualised data, the injury picture is not conclusive. Most injury indicators such as production, sales, capacity, capacity utilisation rate, inventories, employment or productivity remain stable.
- f. Though market share decreased by 8%, when viewed in light of increase in demand of around 20% over the same period, the complainant and other Indian producers together, still hold 88% market share.
- g. Profits turned into losses but only in Q1 of 2015-16. Profitability figures in different tables are different, which may be due to indexation and the use of a different basis as reference, but it does not allow interested parties to have a clear picture of the situation. This should be clarified.
- h. In view of the above, it is difficult to argue that the domestic industry is suffering any serious injury.
- It is difficult to explain how the domestic industry's profits are very high and increasing when undercutting is high, with all indicators remaining stable.
- j. It seems that there are other factors that have had an impact on the situation of the domestic industry. Unfortunately, no information on other factors has been provided in the preliminary report. In terms of Article 4.2(a) of the Safeguards Agreement, other factors such as the development of captive sales and sales by other Indian producers should be examined.
- k. While the domestic industry's sales remained stable throughout the period, its captive sales increased by 24%. This should be further investigated, in particular the reasons why the domestic industry decided to sell more captively than on the open market.
- 1. An important element that should be taken into account is that other Indian producers increased not only their captive sales by 18%, but also their sales on the open market by 42%. Therefore, it is necessary to analyse the impact of the local competition on the situation of the domestic industry.

Conclusion

- m. Analysis on the following issues is warranted:
 - i. The development of the situation of the domestic industry for a longer period;
 - ii. An in depth analysis of other factors, in particular, the performance of the domestic industry, the impact of captive sales and of competition from other Indian producers;
 - iii. The scope of the investigation and in particular the product types not produced in India.

VI. Republic of Turkey

- a. Article 9.1 of the Agreement on Safeguards provides that a WTO member shall not impose a safeguard measure to a developing country so long as its share of imports of the product concerned in the importing member does not exceed 3%, provided that developing country members with less than 3% of import share collectively do not account for more than 9% of total imports of the product concerned.
- b. According to the International Trade Centre statistics, Turkey's individual share in India's subject merchandise imports in terms of quantity corresponds to levels under 3% (1.05% in 2014, 0% in 2013, 0.59% in 2012 and 0.18% in 2011). In addition, the collective imports share of developing countries with a ratio below 3% is far from reaching 9% of India's total imports of the product under consideration.
- c. In light of the negligible import levels of the PUC from Turkey into India, India should exclude Turkey from the application of any possible safeguard measure.

Submissions by Producers/Exporters and Associations

- VII. Metinvest Group represented by Van Bael& Bellis: Metinvest Group is a vertically integrated group of steel and mining companies that manages every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. It has steel and mining production facilities in Ukraine, Europe and the US, as well as a sales network covering all key global markets. Metinvest Group produces a diversified range of semi-finished and finished steel products including slabs, billets, hot-rolled plates, hot-rolled coils, shapes and bars, rails, grinding balls, rail fasteners and large diameter pipes. There submissions are as below:
 - a. <u>Imposition of a safeguard measure cannot be based on annualised data:</u>
 - i. Article 3.1 of the AS, last sentence, provides that the findings of the competent authority are to consist of "pertinent issues of fact and law". The Appellate Body in US Lamb underlined in this regard that, "[a]s facts, by their very nature, pertain to the present and the past, the occurrence of future events can never be definitively proven by facts."
 - ii. Annualisation entails the mathematical calculation of a variable to reflect a value for that variable on a yearly basis. It is therefore a projection of a future value based on the past. Such projection cannot be held to be a "fact" on which the Investigating Authority can establish its determination, especially when that annualisation is based on data from only the first quarter of the financial year 2015-16.
 - iii. In particular, Article 4 1(b) of the AS provides even in relation to the determination of a threat of serious injury, a "future-oriented" determination, that the existence thereof is not to be based on "allegation, conjecture or remote possibility".
 - iv. In addition, the Appellate Body in Argentina Footwear (EC) emphasized that the investigation period "[...] should be the recent past." Whilst it is not contested that the Investigating Authority can rely on the most recent available import data, this data should be the recent past and not a future projection.
 - b. There is no clear evidence of unforeseen developments or of any effect of relevant GATT 1994 obligations:
 - i. The "unforeseen developments" and the effect of GATT 1994 obligations in Article XIX:1(a) of the GATT 1994 are both "circumstances" which must be demonstrated "as a matter of fact" in order for a safeguard measure to be applied consistently with the provisions of Article XIX of the GATT 1994. They constitute "prerequisites".
 - ii. Consequently, the text of the first clause of Article XIX:1(a) of the GATT refers to unexpected factual circumstances due to which the increase in imports causing injury has taken place and expresses a logical relationship between these circumstances and the ensuing increase in imports causing injury.
 - iii. The Preliminary Determination contains a factual description of certain developments with respect to the steel sector in general and a number of developments concerning specific exporting countries. These developments largely overlap with the section "on factors that may be attributing to increased imports" in the Application.
 - iv. The central thread throughout the described developments is that (i) capacity in Russia, Ukraine and the People's Republic of China ("China") and(ii) demand in the US and the EU have decreased, and that (ii) the resulting excess capacity was primarily diverted to India.
 - v. In contrast with the findings of the Preliminary Determination stating that "the United States and the European Union have reduced their dependence on imported stee1", it appears from the information given by Metinvest that the consumption of steel has increased in the United States and Europe between 2013 and 2014.
 - vi. Furthermore, contrary to the finding that "Ukraine has joined Russia and China PR to drive down steel prices and divert its surplus steel to countries with good demand", the information submitted by Metinvest demonstrates that imports of the product concerned from Ukraine have decreased by 50%.
 - vii. Even assuming that the factual analysis provided in the Preliminary Determination is correct, the Preliminary Determination remains fundamentally inconsistent with the legal requirements set out above.

- viii. First, the events described in the Preliminary Determination do not at all establish how they have changed the competitive relationship between the domestic product concerned and the imported product concerned. There is no account of any development which could explain why imports of the product concerned have gained ground to the detriment of the domestic product concerned.
- ix. Second, even if it were to be held that the account of the developments in the Preliminary Determination consists of an explanation pertaining to the change in the competitive relationship, quod non, the Preliminary Determination does not contain any explanation as to why the developments were unexpected. It is not indicated anywhere in the Preliminary Determination that there was an unexpected event which led to an increase in imports.
- x. Third, the Investigating Authority has failed to establish any logical connection between the developments and the increase in imports. It is merely stated that "India, with relatively better demand prospects (domestic demand up by 3.1%) and high domestic prices, has remained an attraction for these steel surplus economies to channelize their excess capacities".24 This sentence only indicates that India has remained attractive for importers, but does not explain how this development led to a change in the competitive relationship between the domestic and the imported product.
- xi. The Investigating Authority's determination with respect to unforeseen developments is therefore largely deficient and in violation of VVTO requirements.
- xii. It is apparent from the Preliminary Determination that the Investigating Authority has not identified, in accordance with Article XIX of the GATT 1994 and of the AS, the obligations under GATT 1994 (for example, tariff concessions) with respect to the product concerned that have had the effect of precluding India from taking the measures necessary to prevent the change generated by the "unforeseen development", i.e. resulted in the increase in imports causing serious injury to the domestic industry. Indeed, as underlined by the Appellate Body, this is one of the "circumstances" included in the first clause of Article XIX:1(a) which "must be demonstrated as a matter of fact."
- xiii. Furthermore, Metinvest would like to draw the Investigating Authority's attention to the fact that the wording of Article XIX:1(a) provides that the increase in imports must have come about "as a result" of the effect of the obligations incurred by the Member under the GATT 1994. However, the Preliminary Determination not only lacks any identification of the obligations incurred under the GATT 1994, but also lacks a "reasoned and adequate explanation" of how the effect of these obligations resulted in the product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry. The Preliminary Determination fails to explain how these obligations have the effect of precluding India from taking measures, such as an increase in import duties, in order to prevent or remedy the change generated by the "unforeseen development" in the competitive relationship between the imports and the domestic products with a view to restoring the pre-existing competitive condition. This explanation would also have clarified why the imposition of additional duties under the safeguard measures at issue is necessary, if it is demonstrated that the unforeseen development resulted in an increase in imports causing serious injury to the domestic producers.
- xiv. The fact that it is "known or knowable that India has made tariff concessions with regard to the product concerned when it joined the WTO does not exonerate the Investigating Authority from complying with the aforementioned requirements.
- xv. In conclusion, the failure to indicate the effect of the obligations incurred under the GATT 1994 renders the Preliminary Determination inconsistent with WTO law.

c. There is no clear evidence of increased imports:

- i. In the present case, the Investigating Authority merely provided a table in its Preliminary Determination with absolute and relative import figures for the financial years 2013-14, 2014-15 and 2015-16 (annualised).
- ii. As a result, the Investigating Authority relied on an end-point-to-end-point analysis, namely a comparison between financial year 2013-14 on the one hand, and financial years 2014-15 and 2015-16 (annualised) on the other hand, to determine that the imports of the product concerned "have shown an increasing trend in absolute terms as well as in relative terms".
- iii. First, it is submitted that there is no increasing trend in imports in absolute terms. As stated by the Appellate Body, an end-point-to-end-point analysis, namely a comparison between financial year 2013-2014 and financial years 2014-2015 and 2015-2016 (annualized) is not an analysis in accordance with the requirements under Article 2.1 of the AS and Article XIX:1(a) of the GATT 1994.
- iv. If the analysis is made in accordance with Article 2.1 of the AS and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, it appears form Graph 1 below that the trend in imports shows a decrease. From financial year 2011-12 to financial year 2013-14 there is a significant decrease of almost 42% in imports of the product concerned in absolute terms.

- v. The figures demonstrate that the increase in imports between financial year 2013-14 and financial year 2014-15 is around the same level as the imports in financial year 2011-12. It is therefore more appropriate to qualify the trend in imports of the product concerned in terms of a significant decrease, followed by a recovery of the import levels, to a level comparable to the level prior to the decrease in imports.
- vi. With respect to the alleged increase in imports in relative terms, the clear decreasing trend is even more apparent. While the share of imports in total domestic production was 11% in the financial year 2011-12, it decreased to only 5% in the financial year 2013-14. While the share of imports in total domestic production indeed rose to 10% in the financial year 2014-15 this share is still below the share of the financial year 2011-12.
- vii. The increase in imports between the financial years 2013-2014 and 2014-15 was not significant at all, since the imports were approximately at the same level as in the financial year 2011-2012.
- viii. Furthermore, in light of the sharp decrease in imports in two consecutive financial years, i.e. between financial years 2011-2012 and 2013-2014, the increase in imports between the financial years 2013-2014 and 2014-15 cannot considered to be wholly unexpected. The increase is therefore not "sudden" enough.
- ix. In addition, the imports cannot be held to be "sharp" enough. It must be emphasised that this factor should also be assessed in light of the historical context.
- x. In absence of an increase in imports that is sharp, sudden and significant enough as required pursuant to Article 2.1 of the AS and Article XIX.1(a) of the GATT 1994, the imposition of the provisional duty is manifestly unlawful. The increase in imports is also not unexpected.
- d. There were no critical circumstances justifying the application of preliminary safeguard duties:
 - i. The concept of "critical circumstances" is not further defined in the AS. Critical means "having the potential to become disastrous; at a point of crisis". The circumstances must therefore have the potential to become disastrous in the sense that there is a risk of "damage which it would be difficult to repair". "Damage" means "physical harm that impairs the value, usefulness, or normal function of something" or "detrimental effects". The concept of "damage which it would be difficult to repair" suggests that the "circumstances" must be such as to warrant expeditious intervention in the form of a provisional safeguard duty in order to prevent any detrimental effects that would be difficult to repair.
 - ii. The "critical circumstances" and the "damage which it would be difficult to repair" therefore indicate a certain sense of urgency. Indeed, the materialisation of the damage must occur at a rate which cannot be addressed timely enough by a definitive safeguard measure. Consequently the concept of "damage which it would be difficult to repair" possibly points to circumstances so critical where the domestic industry risks being wiped out completely or partially.
 - iii. It can be assumed that the "critical circumstances" and the "damage which it would be difficult to repair" are not the equivalent of "serious injury" or "threat of serious injury" within the meaning of Article 4.1 of the AS, as the inclusion of these concepts in Article 6 of the AS would otherwise be redundant. The "critical circumstances" and the "damage which it would be difficult to repair" are therefore conditions in addition to serious injury or threat of serious injury, and these conditions must also be met in order to justify the imposition of a provisional safeguard duty.
 - iv. Contrary to the wording and scheme of the AS, the Preliminary Determination seems to equate "serious injury" and "threat of serious injury" with "critical circumstances, where delay would cause damage which it would be difficult to repair".
 - v. Furthermore, the Preliminary Determination fails to identify any "damage which it would be difficult to repair". This is not surprising, since there is no damage which it would be difficult to repair" to speak of. It appears from the complete data of the Application that the above-mentioned selective use of data provides an inaccurate picture of the state of the domestic industry, since most factors pertaining to any detrimental effect on the Applicants have changed insignificantly or have remained stable:
 - the market share of the Applicants is still 58% in Q1 of financial year 2015-2016 and the market share of imports is only 16%;
 - the market share of other domestic producers has increased by 4% between Q1 of 2014-15 and Q1 of 2015-16, despite the alleged increase in imports;
 - capacity utilization has dropped from 77% to only 76% between Q1 of 2014-15 and Q1 of 2015-16;
 - production has dropped by only 2% between Q1 of 2014-15 and Q1 of 2015-16;
 - sales of the applicants increased by 2% between Q1 of 2014-15 and Q1 of 2015-16.
 - vi. The above-mentioned figures unmistakably indicate that there are no circumstances "having the potential to become disastrous" and the alleged increase in imports has barely had an impact on the domestic industry.
 - vii. It is therefore unequivocally clear that the condition of "critical circumstances, where delay would cause damage which it would be difficult to repair" has not been met and, as a result, the imposition of the provisional safeguard duty is flagrantly in violation of WTO law.

- e. The Applicants do not suffer serious injury or threat thereof contrary to the provisional determination:
 - i. Among the factors, the Preliminary Determination reported a positive (or flat) performance by the domestic industry with regard the following injury factors:
 - Production;
 - Productivity;
 - Employment;
 - Capacity utilization;
 - Inventory.
 - ii. At the same time, factors which the investigating authority found to have an adverse trend, apart from increased imports, are: 1) Market share of domestic producers; 2) Profit/loss; and 3) Price depression.
 - iii. Market share: If one were to consider the market shares during the complete, more relevant period of the investigation, he would note that import market share in fact decreased marginally from 11% in 2011-12 to 10% in 2014-15. What's also important is that market share of the domestic industry during the same period stayed almost flat, decreasing marginally from 40% in 2011-12 to 39% in 2014-15:
 - Profit/Loss: At the outset, it should be recalled that the Provisional Determination refers to information contained in the Application that the profitability of the domestic industry "has declined sharply in 2015-16(Q1) and the domestic industry recorded losses". At the same time, the conclusion on profitability does not mention the fact that profit levels of the domestic industry increased during the POI between 2013-14 and 2014-15 financial years by 35%. Moreover, a decrease of profitability to -55 (indexed) is reported only for Q1 of 2015 compared to financial year 2013-14. Moreover, despite the above-mentioned conclusions of the Investigating Authority with regard to domestic industry's profitability, JSW Steel Limited and Essar Steel India Limited, reported themselves that they enjoy a healthy and stable financial performance, especially on the domestic market. Although Steel Authority of India Limited reported negative profitability during the period concerned, it explicitly attributed it to factors other than imports from third countries. Finally, it should be noted that the Applicants also produce and export other products apart from the product concerned (HRC), and that any losses reported at the companies' group level should not automatically explain the losses of the domestic industry with respect to the product concerned. Moreover, there was no information providing whether the profitability calculation results take into account depreciation costs and indirect costs. It is submitted that if all these factors, mentioned above, are taken into account, this will demonstrate that the domestic industry in India is not suffering serious injury or threat thereof.
 - v. <u>Price depression</u>: In its Preliminary Determination the Investigating Authority notes that "the domestic industry was always under consistent pressure to either reduce their prices to match the import prices or to hold on to their prices". Apart from the relevant factors discussed above, it should be noted that the Investigating Authority didn't consider a number of other factors which have a bearing on the domestic industry's performance. This are as below:
 - Divergence between global prices of raw materials and local prices in India: High prices for the main raw material on the domestic market in India, due to structural and availability issues have a direct impact on the viability and financial performance of the domestic industry in India.
 - Pricing strategies of the main Indian producers did not reflect the actual situation on the domestic
 market: The pricing strategies of the main steel producers in India did not correspond to the actual
 market situation, as there was no preconditions for increase in prices of steel products. This also had an
 impact on the performance of the domestic industry, which neither the Preliminary Determination, nor
 the Application accounted for.
 - vi. Out of the eight injury factors mentioned above and which were considered by the Investigating Authority, five factors were reported as performing favourably (or flat) during the POI: production, productivity, employment, capacity utilization and inventory. On the other hand, only three factors were reported as performing negatively during the POI: market share of domestic producers, profit/loss and price depression.
 - vii. When the above-mentioned injury factors, as well as other factors not taken into account in the Preliminary Determination, are taken into account, the Preliminary Determination of the Investigating Authority does not appear to be duly supported by the facts at hand, nor by the adequate evaluation of the relevant factors.
 - viii. Indeed, the production of the domestic industry, productivity, employment, capacity utilization and inventories remained flat and at healthy levels during the POI. On the other hand, it was demonstrated above that the profitability of the domestic industry in India reported by the Investigating Authority as negatively performing is in fact positive explanation, can result in an adequate and reasoned conclusion with respect to the existence of serious injury or threat thereof to the domestic industry in India. It is therefore maintained that the indicators of serious injury mentioned in Article 4.2(a) of the WTO Safeguards Agreement were inadequately evaluated by the Investigating Authority and that the explanations provided in the Preliminary Determination do not support the conclusion that the overall position of the domestic industry indicated significant overall impairment.

- f. There is no causal link between the alleged increase in imports and the alleged injury:
 - i. The evolution of imports in absolute terms should be assessed in light of the rate and amount of such imports, in accordance with Article 4.2(a) of the WTO Safeguards Agreement and the interpretation given to this provision by WTO case law.
 - ii. Metinvest submits and trusts that the Indian Investigating Authority will acknowledge that the decrease in imports by almost 10% between 2011-12 and 2014-15 in relation to domestic production in India, as well as the insignificant increase by 14% only between 2011-12 and 2014-15 in absolute terms resulting in an import level in 2014-15 which is almost identical to that recorded in 2011-12, should lead to the conclusion that no causal link between the alleged increase in imports and the alleged serious injury can be established.
 - iii. If one were to assume that the evolution of imports as outlined in the above graphs would be of such a nature that it could possibly cause any injury to the domestic industry (quod non), one would expect such injury to materialize in 2014-15, as compared to 2013-14 when imports increased almost 97% year-on-year.
 - iv. However, an analysis of the injury indicators on the basis of figures provided in the Application, as well as from public sources, demonstrates that the situation of the domestic industry had in fact improved (or at least, remained stable) from 2011-12 to 2014-15, despite the alleged increase in imports.
 - v. Furthermore, the important decrease of imports in absolute terms in 2013-14, as compared to 2012-13 and 2011-12 has resulted in a continued improvement of the state of the domestic industry seen throughout the period concerned (i.e. between 2011-12 and 2014-15), including for injury parameters such as production (+35%), capacity (+26%), domestic sales (+23%), investments (+41%) whereas other factors remained flat to little changed such as capacity utilization (+1%).
 - vi. Metinvest therefore submits that there is no coincidence in time between any alleged increase in imports and any alleged injury in the present case Indeed, as was demonstrated above, from 2013-14 to 2014-15, when the imports allegedly increased (even though not in a way which satisfies the requirements of Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 of the VVTO Safeguards Agreement), the injury indicators improved or remained stable. Clearly, this demonstrates that there is no causal link between the alleged increase in imports and the alleged injury.
 - vii. If one compares the evolution between 2013-14 and 2014-15 with the evolution between 2011-12 and 2012-13, as provided in the Application, he would note that the situation of the domestic industry in 2014-15, as compared to 2011-12 is (for almost all injury indicators) better, despite the alleged increase in imports levels.
- viii. Metinvest therefore submits that, in view of the striking lack of coincidence in time between the evolution of the import level (both in absolute and in relative terms) and the evolution of the injury indicators, no causal link between them can be found. Consequently, the causation requirement laid down in Article XIX of the GATT 1994 and in Articles 2.1 and 4.2 of the WTO Safeguards Agreement is not met and no safeguard measures can be imposed.
- ix. Metinvest trusts that the Investigating Authority will carry out an in-depth non-attribution analysis in line with the requirements described above and that this analysis will lead to the conclusion that any alleged injury is caused by factors other than imports. Metinvest maintains that this aspect is of the utmost importance in the framework of this safeguard investigation.
- x. In particular, as was extensively explained above, there was, among others, a striking divergence between global prices for raw materials and the prices on local market in India. First, the high cost of domestically available iron ore, the main raw material for the product under investigation, in India during the period concerned is an important factor for the viability of the domestic industry, which was not evaluated by the Investigating Authority. Second, the pricing policies of the main Indian producers didn't reflect the actual situation on the domestic market.Last, but not least, the apparent slowdown in economic growth of India in 2015 as compared to 2014 should also be taken into account in the evaluation of the alleged serious injury or threat thereof to the domestic industry of India.
- xi. The Applicants admit themselves that China is one of the key reasons leading to alleged injury of the domestic industry in India. Most of the articles which are annexed to the Application (see e.g. Exhibit 10 of the non-confidential version of the Application, pp. 101-203) refer to Chinese imports to India surging at "prices lowest in over 20 years".
- xii. Indeed, the significant overcapacity (more than 44 million tons83) and slowing domestic consumption in China due to sluggish economy growth (projected to be below the government target of 7%) leads to increasing exports from this country to third country markets at low, depressed prices.
- xiii. Metinvest submits that targeting the injurious imports from China through a safeguard investigation is a wrong choice of trade defence instrument, since it punishes other reliable and historical suppliers of the product concerned to India, including Ukraine.

g. Legal basis for choice of level and form of the safeguard measure:

- i. The provisions of Article 5.1 of the WTO Safeguard Agreement imposes an obligation upon the Members to ensure that the measure applied is commensurate with the goals of preventing or remedying serious injury.
- ii. The Panel in Korea Dairy Safeguards, upheld by the Appellate Body, also added that the final safeguard measure to be imposed upon importation of the products must be defined by the following elements: product coverage, form, duration and level, which altogether must be considered in their totality when making decision about the final measure.
- iii. Therefore, by imposing a safeguard measure a Member shall consider not only its level ("is commensurate"), but also its form in order to be "no more restrictive than is necessary to prevent or remedy' any alleged serious injury, be it a safeguard duty, a quantitative restriction, including quotas or tariff quotas, or any other forms restricting the imports from third countries.
- iv. Article 5.1 of the WTO Safeguard Agreement explicitly allows a quantitative restriction to be imposed as a form of a safeguard measure. This provision also clarifies the modalities of a quantitative restriction to be applied as a safeguard measure, i.e. that it "shall not reduce the quantity of imports below the level [...] in the last three representative years". Article 5.2(a) of the WTO Safeguard Agreement further details how a particular form of a quantitative restriction, i.e. quotas, shall be determined and imposed.
- v. It should also be added that Article XIII:2 of GATT further clarifies that in applying import restrictions to any product Members "shall aim at a distribution of trade in such product approaching as closely as possible the shares which the various contracting parties might be expected to obtain in the absence of such restrictions".
- vi. It follows from the above that India has an obligation to ensure that any safeguard measure to be imposed upon importation of the product concerned from, inter alia, Ukraine must be commensurate with the goals of preventing or remedying the alleged serious injury of Indian domestic industry, i.e. being least trade-distorting, taking into account, inter alia, the form and level of the proposed measure.

h. Ukraine has substantial interest in supplying the product concerned to India:

- i. Ukraine has been historically a reliable and regular supplier of the product concerned to Indian consumers. Imposition of a provisional safeguard duty at a level of 20% and which can be potentially confirmed at a definitive stage, effectively bars Ukrainian imports of the product concerned into the Indian market, as producers in Ukraine will not be able to continue exporting to India with profit.
- ii. At the same time, as was mentioned above, the goal of the safeguard measure is not to ban imports from third countries altogether, but rather to allow the local domestic industry to remedy or prevent any alleged serious injury, and to adjust accordingly.
- iii. It is submitted hereby that these objectives can be achieved through a quantitative restriction, e.g. through a tariff rate quota as a form of safeguard measure, for the following reasons.
- iv. First, a tariff rate quota is the least trade-distorting measure out of any other available for the purposes of safeguard application (e.g. quotas, bans, safeguard duties, etc.). It allows to limit any continued increase in imports from third countries by imposing an out-of-quota duty, thus shielding the domestic industry and allowing it to adjust accordingly. At the same time, tariff rate quota allows the historical suppliers having substantial interest in the product concerned, including Ukraine, to continue exporting to India within their historical in-quota amounts.
- v. Second, unlike anti-dumping and countervailing duties which are designed to sanction unfair trade practices (dumping and subsidizing, respectively), safeguard measures are imposed against fair trade practices of third countries. Therefore, any potential safeguard measure against imports of the product concerned from, inter alia, Ukraine must take into account this fact and accommodate the legitimate interests of the supplying countries.
- vi. Finally, it should be noted that provisions of Article 5 of the VVTO Safeguard Agreement and the corresponding VVTO case-law release the Members from the responsibility to provide a "clear justification", at a time of a decision, for a safeguard measure if it doesn't reduce the quantity of imports below the average imports in the last three representative years. In other words, should the Investigating Authority in the present case decide to impose safeguard measures in the form of a tariff rate quota, which is set at a level reflecting the last three representative years, there will be no obligation on its part to provide detailed and substantial justifications for such decision.

i. Current situation in Ukraine:

- i. The situation in the Eastern regions of Ukraine (Donetsk and Lugansk areas) has continued to improve in recent months and there are legitimate expectations that this will continue to the end of the year and beyond, bringing normalization of life in these regions.
- ii. Given the particular situation in these areas, the construction business, aimed at restoring the heavily damaged and destroyed infrastructure, could be expected to absorb any additional capacities of the

- Ukrainian domestic industry and even take part of the current export quantities, once the security and political situation in those areas normalizes.
- iii. Given the expected increase in domestic demand in Ukraine for the product concerned, as explained above, it can be concluded that any continued alleged increase of imports from Ukraine to third markets, including to India, is not to be expected.
- VIII. China Steel Corporation ("CSC"): CSC is a producer and exporter of the product under consideration based in Taiwan.
 - a. The imports from Taiwan only amounts for 0.88%, 0.25%, and 0.27% of the total import volumes and all are below the negligible threshold 3% under Article 9.1 of the Agreement on Safeguard. Further Taiwan is considered as developing country by multiple WTO members and international organisation:
 - i. EU safeguard measure's on certain steel products mandarins and other citrus fruits, and farmed salmon
 - ii. Indonesia Safeguard measure's on wheat flour.
 - iii. Malaysia excluded Taiwan from the application of preliminary safeguard measure on hot-rolled steel plate.
 - iv. United Nations: Taiwan was granted as developing country in:
 - The Economic and Social survey of Asia and Pacific,
 - UN Conference on Trade and Development (UNCTAD),
 - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and
 - The International Bank for reconstruction and development (IBRD)
 - Fifth Ministerial Conference: The Economic Minister of Taiwan pronounced that Taiwan is "newly acceded developing Member".
 - b. The imports from the developing countries with negligible import collectively account for only 2.0% (2013-14), 0.9% (2014-15), and 0.9% (2015-Q1) of the total import of PUC. That the import from Taiwan should be exempted from any safeguard measure.
 - c. Exclusion of High strength Steel ("HSS") from the PUC as it is used by the Indian Automobile Industries.
 - d. Taiwan has been exporting HSS, which is rapidly growing demand of the automobiles industry for stringent quality HSS. HSS are not available from the local mills and, as such, HSS needs of the Indian auto industry must be filled by imports from inter alia, Taiwan.
 - e. There is inconsistency with Article 6 of agreement on safeguard as there are no critical circumstances where delay would cause damage which will be difficult to repair. The key economic indicators of the domestic industry, including domestic production, productivity and employment, capacity utilisation and inventory remained virtually unchanged in the reference period:
 - The market share of domestic producers in respect to their commercial sales to the open market remained unchanged during the POI.
 - PUC import did not increase in such a way to continue an import "surge", according the Appellate Body
 interpretation. That import surge must present itself in a state of "recent enough, sudden enough, sharp
 enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively to cause or threaten to cause serious
 injury.
 - Mere 4.35% increase in market share simply cannot be "share enough" or "significant enough" and hence cannot constitute "surge" by any count.
 - Profitability of the domestic industry, increased substantially during 2014-2015 from the preceding years 2013-14 i.e. from 100 to 135 by index. Given the positive movement on profitability of DI, and only a marginal decline in DI's market share during the first two full references years, there is no critical circumstance proven to exist on the case record.

IX. China Iron and Steel Association filed submissions through their representative M/s. Athena Law Associates

- a. The Association has filed preliminary submissions based on the material in the initiation notification and the preliminary findings.
- b. Safeguard measures are based on a "no fault principle" and applied on imports that are made fairly and not with the intention of hurting the domestic industry. Therefore, recourse to safeguard measures should be taken only in strong cases where there is no other alternative other than imposition of duty to save a dying industry. The

Appellate Body in Korea – Dairy held that safeguard measures are extraordinary remedies which should be adopted only in emergency situations. The present petition does not demonstrate an extraordinary or emergency situation and thus should be dismissed.

- c. The Supreme Court in Haridas Exports v. All India Float Glass Manufacturers Association held that the availability of goods outside India at lower prices is not per se bad and encourages competition.
- d. Article XIX of the Safeguards Agreement provides that safeguard measures can be imposed only if there is a sudden and share increase in imports in the most recent period; there is a clear causal linkage between injury to the domestic industry and such increased imports; safeguards duty is not in public interest.
- e. The safeguard investigation has been initiated without examining the details or satisfying the requirements of a valid application under Rule 5.
- f. The provisional findings were issued in haste and there did not exist a situation so critical that any delay in imposing provisional measures would cause irreparable damages. The critical circumstances required for provisional measures have not been fulfilled.
- g. Paragraph 10 of initiation notification stated that interested parties were to be given 30 days to make their views known to the authorities but without waiting for any response the authority issued the preliminary findings.
- h. The Applicant has claimed excessive confidentiality and does not allow a reasonable and meaningful understanding of the domestic industry's case.
- i. Unforeseen developments are unexpected and unpredictable and hence are developments or advancements that come as a surprise before the domestic industry and due to which the domestic industry is taken aback. However, the developments referred to in the petition are merely normal market fluctuation which every entrepreneur could have foreseen. The freeing of trade and the consequential increase in imports was expected an foreseen by Indian negotiators in GATT when countries were negotiating to ensure free and fair international trade by reducing tariff and non-tariff barriers.
- j. The Authority should take into account all relevant factors of an objective and quantifiable nature while evaluating whether the increased imports have caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry. The following facts demonstrate that no serious injury or threat of injury has been caused to Applicant:
 - i. No significant changes in the capacity of the Applicants.
 - ii. Slight increase in the production during 2015-16 (annualized) as compared to 2013-14.
 - iii. Capacity utilization has remained the same during the period 2013-14 to 2015-16 (annualized)
 - iv. Applicants have shown losses in 2015-16 (01) but during the same period PBIT was significantly positive. Therefore, losses are on account of interest burden and not due to import price as evidence from negative price undercutting.
 - v. Inventory levels slightly increased from 100 points in 2013-14 to 103 points in 2015-16 (01) but the same was not considerable as significant.
 - vi. The employment and productivity remained the same throughout the injury period.
 - vii. There is negative price undercutting since 2014-15 (quarterly) till available data 2015-16(Q1) thereby the landed price was higher than the net sales realization of the Applicants. Hence, the losses to the Applicants are due interest cost and their inefficiencies and not on account of imports.
 - viii. Market share of domestic producers in domestic demand were not determined correctly in the preliminary findings as total demand in India was determined considering captive consumption. However, sales of the domestic industry were considered excluding captive consumption for the purpose of market share of the domestic industry.
- k. Therefore, in terms of both volume and price, no injury is apparent to the domestic industry, leave aside serious injury.
- 1. Even if serious injury were assumed to the domestic industry, such injury was not because of the increased imports. Applicant has not provided evidence to establish that injury claimed is due to the increased imports.
- m. Injury to the domestic industry is due to the burden of interest cost and there is no influence of import prices as the price undercutting has been consistently negative.

- n. Applicant has not provided any adjustment plan and the preliminary findings also do not mention an adjustment plan. In an application filed by United Phosphorus in 1999 for safeguards duty imposition, the authority refused to impose a safeguard duty on the ground of lack of an adjustment plan.
- o. Imposition of the safeguard duty is not in public interest. The term "public interest" has not been defined in the safeguards laws but has been interpreted by the Apex Court under different laws. In *Bihar v. Kameshwar Singh* it was noted that expression "public interest" is not capable of precise definition and has not a rigid meaning and is elastic and takes its colours form the statute in which it occurs, the concept varying with the time and state for society and its needs. In an application filed by United Phosphorus in 1999 for safeguards duty imposition, the authority refused to impose a safeguard duty on the ground that imposition of the duty would not be public interest.

X. The Japan Iron and Steel Federation

- a. The share of imported steel products in total consumption is around 10% to 15%. This means there are a certain number of customers who need imported products.
- b. The supply demand balance in the domestic hot rolled flat products market has become extremely tight. The production capacity of steel producers in India is insufficient to meet the demand for hot rolled flat products in the country.
- c. Imposition of safeguard duty is likely to have serious impact on users which depend on imported hot rolled flat products.

XI. **Arcelor Mittal, Brasil (AM Brasil):** The conditions required to initiate a safeguard investigation are not fulfilled in this case.

- a. Indian authorities breached the right of defense of interested parties by imposing safeguard duty at abnormally early stage.
- b. There has been no increase of imports within the meaning of the WTO safeguard Agreement as interpreted by the WTO case-law.
- c. The Petitioner has not suffered serious injury or a threat of serious injury. In addition there is no causal link between the alleged serious injury (if any) and imports.
- d. Available information shows that there had not been any significant increase in imports within the meaning of WTO Safeguard rules. The increase in imports of the product concerned to India is far from being sharp, recent, sudden and significant.
- e. AM Brasil highly challenges the investigation period selected by the Indian authorities which also includes 2015-2016 based on annualized data. Most recent data should only serve to confirm or infirm trends evidenced during the period of investigation.
- f. While imports increased quite significantly between 2013-14 and 2014-15, an end-to-end comparison shows that imports remained in fact stable during the whole period 2011-2015, and even decreased by 2,3% during the same period. In this respect, it should be noted that the WTO jurisprudence makes clear that in assessing whether an end-point-to-end-point increase in imports satisfies the increased imports requirement of Article 2.1, the sensitivity of the comparison to the specific years used as the end-points is important as it might confirm or reverse the apparent initial conclusion.
- g. In the present case, it appears prima facie that all indicators regarding the situation of the Indian domestic industry are positive. The Indian Authority failed to demonstrate the existence of a serious injury or a threat thereof.
- h. A closer look at the evolution of the production of the Indian domestic industry during a longer period seems to reverse the allegation of serious injury. Indeed, instead of remaining stable, the data contained in the complaint reveals an increase in production during the period 2011 2015.
- i. The Applicant's production increased by 26% over the analyzed period while the other producers increased their production by 57%, indicating that this is the internal competition that may limit the production and sales growth of the applicants.
- j. While the Indian authorities are trying to evidence an increase in the market share of imports by only relying on the period 2013-14 to 2014-15, an analysis over a longer period (such as the one used in the Petition) shows that the market share of imports remained stable at a level of 10% and even decreased by 1% over the period 2011-2015.

- k. The recent financial results and public statements of the companies composing the Indian industry evidence a good financial health of the Indian industry.
- 1. There is no causal link between the alleged serious injury (if any) and imports. There is hardly any evidence of coincidence of alleged increased imports and alleged serious injury and the existence of a causal link.
- m. The Indian authorities imposed provisional safeguard measures only 7 days after the initiation. Such an early imposition of provisional measures is exceptional in view of the practice of the Indian authorities in safeguard cases.
- n. AM brasil questions the inclusion of Brazilian imports within the scope of Application of safeguard measures under Article 9.1 of the WTO Safeguard Agreement.
- o. There seems to be nothing in the non-confidential version of the petition regarding the question of the shares of developing countries within total imports, and on which the Indian authorities may have relied to preliminary conclude that developing countries should be included within the imposition of provisional measures.
- p. By failing to substantiate their analysis, the Indian authorities breached their obligations under Article 3.1 of the WTO Safeguard Agreement.
- q. There is beach of Article 12(1) as a result of a failure to notify immediately. AM Brasil notes that the case was initiated on 7th September and was notified to the WTO Committee on Safeguards on 15th September, i.e., 8 days after the initiation of the investigation.
- r. There is breach of Article 12(4) as a result of a failure to notify before taking a provisional safeguard measure.

XII. JFE Steel Corporation, Nissin Steel Co. Ltd, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation and Kobe Steel Ltd represented by M/s. AZB & Partners

- a. The DG Safeguards has failed to examine the accuracy and adequacy of evidence as required under Rule 5(3) of the SG Rules. The initiation of the investigation is not grounded in law.
- b. The DG Safeguards has erred in issuing the Preliminary Findings in absence of critical circumstances. The absence of clear evidence of increased imports causing serious injury or threatening to cause serious injury, the existence of critical circumstances is itself untenable.
- c. The product produced by the Domestic Industry is not a like product" as compared to the imported product. The Petitioner has not provided a coherent methodology for determination of the Product under Consideration. The DG Safeguards accepted the definition of the PUC without an objective assessment of the Conditions of Competition in the market.
- d. Products exported by the Japanese Mills are not manufactured/supplied by the domestic industry and the same should be excluded from the scope of the Product Under Consideration. Further, some hot rolled products exported by the Japanese mills to India differ in chemical composition of components.
- e. Hot Rolled Coils imported from Japan are able to meet the specific quality requirements that the domestic industry is unable to meet. Hot Rolled flat products exported from Japan significantly differ from those manufactured by the domestic industry and must be excluded from the definition of the PUC.
- f. It is not clear as to how the DG Safeguards has verified the data with respect to the PUC as the PUC consists of denied and specific set of products and there is no evidence to show that the Petitioners maintain segregated data with respect to the PUC.
- g. The conditions for the application of a safeguard measure are not satisfied in the present case. The finding on 'unforeseen development' by the DG Safeguards is inconsistent with article XIX of GATT and the SGA. Unforeseen developments must be made for each specific product and not only for steel in general.
- h. The analysis of 'unforeseen developments' does not take into account other relevant events such as depreciation of Indian Rupee, reduction in imports by industrial users to source the raw material locally and signing of the India-Japan CEPA.
- i. The POI selected by DG Safeguards is not long enough to analyse the import trends.
- j. There is no serious injury or threat of serious injury to the domestic industry. There is no decline in production levels, employment, and capacity utilization during the POI. The market share of the Petitioners has decreased due to inter-se competition among the Indian producers and increase in captive consumption. Further, existing levels of production of DI are already high.

- k. The movement in profit/loss is not correlated with imports. Imports have increased in 2014-15 by 97% and during the same period domestic industry saw a rise in profits by 35%.
- 1. Injury, if any suffered by the domestic industry is not caused by increased imports. Domestic Industry is suffering from diversion of supply for internal captive consumption, delayed implementation of projects, no lending support by the Government, exposure to global price shocks, handicaps in capacity building and generation, competitive products from other countries, lower-quality iron ores which require more coal, lower quality of coal, problems in acquisition of raw material etc.
- m. High transportation costs and poor infrastructure are impacting Indian producers' efficiency.
- n. Injury caused by dumping of the PUC into India must be segregated from alleged injury due to increased imports.
- o. The adoption of safeguard measure is against public interest because Hot rolled flat products are not manufactured in sufficient quantities by the domestic industry and imports are necessary for downstream industrial users. As per JPC data, imports of HR Coil in the past 5 years have been essential to meet the requirements of the domestic market.
- p. The imposition of safeguard duty will also prove to be detrimental to the Indian auto industry and downstream producers of Cold Rolled products.
- q. DG Safeguard is requested to exclude the hot-rolled coils exported by the Japanese Mills that are used in the production of auto/home appliances from the scope of PUC.
- r. We further request the DG Safeguards to apply Tariff-rate quotas (TRQ) on HRCs for construction use, as the domestic industry does not produce these products in sufficient quantities.

XIII. POSCO, Korea and POSCO Maharashtra Steel Private Limited filed submissions through their legal representative M/s. Shardul Amarchand Mangaldas & Co.

- a. The company has filed submissions in response to the petition filed by the Applicant.
- b. The Applicant has misrepresented the market share of other producers of the PUC and has shown the market share of domestic supporters as the market share of other producers of the PUC in the market. As a result, the market share of only Tata Steel Limited, Bhushan Steel Limited, Jindal Steel and Power Limited are included in the market share of other producers.
- c. In order to facilitate fair comparison of data at the same level of trade, the volume of imports which is used for captive consumption must be excluded from total demand if the captive consumption of domestic producers is excluded from total demand.
- d. Total demand of the PUC is incorrect as sales of other producers have not been included. Therefore, as demand is more, the market share of imports would also decline.
- e. Imports have shown minor fluctuations with no significant increase the market share of the domestic industry has remained mostly constant with only minor variations. There has however been a significant rise in the market share of domestic supporters by approximately 6%.
- f. Applicants have experienced an increase in profits in the previous financial year and the decrease in sales is due to capacity underutilization and high debt/finance costs. Various news reports and press releases indicate that demand in India has declined as a result of which Indian steel companies have accumulated huge debt over the last few years because of capacity expansions, acquisitions and rupee depreciations.
- g. Applicants sell the PUC in the domestic market at a higher rate whereas export the same product at prices prevailing in the global market.
- h. There is no causal link between imports and injury or threat to the domestic industry as rise in imports has been negligible and the same is attributable to the inability of the domestic industry to meet domestic demand. Despite being unable to meet domestic demand has resorted to exporting part of its production outside India.
- i. The provisional duty imposed by the DG, Safeguards was without proper analysis of the facts and circumstances of the case. Further, interested parties were not given an opportunity to file their comments.
- j. The domestic industry cannot meet the quality requirements of downstream consumers. Further, certain grades of the PUC should be excluded form the investigation as the same are not being produced by the domestic industry.

- k. Imposition of a safeguard duty will contravene India's commitments under the India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement as under the Agreement the duties on the PUC have been brought down to zero. Further, the Agreement provides that safeguard actions taken under Article XIX may to the extent consistent with the obligations under the WTO Agreement, exclude imports of an originating good if such imports are not a substantial cause of serious injury or threat. Therefore, imports from Korea are covered under this clause.
- 1. Safeguard measures are emergency actions to be imposed in special and exceptional circumstances intended to give the domestic industry only temporary and short term protection.
- m. As per findings of the Hon'ble Delhi Court in *United Phosphorous v. Director General, Safeguards* the existence of serious injury to the domestic industry and a causal link being established with the increase in imports does not bind the authority to impose a safeguard duty.
- n. Applicant has not provided any statement on efforts being taken, or planned to be taken, or both to make a positive adjustment to import competition.
- o. Applicant has not established any unforeseen circumstances that led to the increase of imports of the PUC into India. Applicant has stated that imports have risen due to various geo-political and economic conditions such as tensions between Ukraine and Russia as well as Europe and Russia, crises in the global steel market due to sluggish demand.
- p. Imports from Korea cannot be considered as an unforeseen development as it cannot be expected that the negotiators making the concessions could not foresee at the time when the concessions were negotiated that such a development would not have occurred. When the Agreement was signed, both the domestic industry ad global steel producers were investing heavily in new manufacturing facilities and anyone in the industry could have been aware that imports would start to rise to satisfy the fast growing demand.
- q. The Agreement on Safeguards and Article XIX do not specifically define what the period of investigation is but the definitions of the terms serious injury and threat of injury indicate that determinations must be based on objective facts and assertions, opinions and conclusions that are not based on factual evidence must be rejected. The period taken by the DG relating to merely 2013-14 to 2015-16 is artificial data of a micro-period. Data should be taken for atleast a five year data base commencing from 2010-11 to 2015-16. The period of 2013-14 cannot be taken as a base year as it was a rock-bottom year for the steel industry.
- XIV. **Hyundai Steel Company, Korea (dated 08.11.2015):** Hyundai Steel is a producer and exporter of the subject goods from Korea RP. The company has requested confidential treatment on their submissions. In view of this request, their contentions are summarised below in a non-confidential manner to the extent possible:
 - a. After reviewing the preliminary findings, there is no clear evidence that Hyundai Steel caused serious injury to the domestic industry/producers of hot-rolled coil in India.
 - b. Hyundai Steel's export selling prices were higher than the prices that were offered by the domestic manufacturers in India and other foreign exporters. The quantity exported to India was at average during the past several years without any drastic increase. The other findings and observations in the notice also appear to be irrelevant to Hyundai Steel.
 - c. For these reasons, Hyundai Steel asks the Director General to immediately terminate the safeguards investigation and the 20% provisional duty. As a result of this unexpected and inappropriate measure, a number of Indian manufacturers are losing their competitiveness and struggling to compete with other global corporations. These firms need the services of Hyundai Steel as the company produces merchandise that Indian companies cannot manufacture. Hyundai Steel offers just-in-time supply, and make superior quality hot-rolled coils at a reasonable price.
 - d. Hyundai Steel's sales of hot-rolled coils with pickling and oiling to Hyundai Steel India Limited (HSIL) should be especially exempted from this investigation. These products are manufactured mainly for the production of Hyundai Motors automobiles.
 - e. In addition, HSIL, an Indian entity by law, evidently generates important benefits to the domestic economy and general public in India. It is, therefore, not in public interest to impose such a measure.
 - f. Continuation of this investigation and consideration to impose safeguard measure will damage the overall Indian economy and bring negative effects to hot-rolled coil importers, as well as general public.
 - g. Serious Injury:
 - i. Import Increase: The Director General failed to illustrate how the increase in imports was caused by the Republic of Korea and Hyundai Steel. The Director General should have examined not only the increased imports but also other factors as well, as he is obligated to do so pursuant to the WTO Safeguard Agreement.

- ii. Import Price: In the preliminary findings, the Director General relied on an alleged increase in low priced imports to find surge in imports. In the imposition of safeguard duty, however, the investigating authority must review whether there is surge in imports, not surge in low priced product imports.
- iii. Causal Link: The investigating authority must provide a non-attribution analysis, which is required by law, to separate and distinguish the injurious effects of other possible factors.
- h. Principles of Natural Justice: The preliminary findings cannot be issued without offering opportunity to all interested parties and allow them to file their comments on the petitioner's claim. This practice goes against the principles of natural justice which demands a due investigation and presents an opportunity to be defend oneself.
- i. Unforeseen Development: It is difficult for the Republic of Korea and Hyundai Steel to become responsible for the Director General's arguments on unforeseen development as nowhere in his findings mentions any causes by Korea and Hyundai.
- j. Adjustment Plan: The safeguard investigation requires the petitioners to build a comprehensive adjustment plan and explain that they need time and emergency relief to restructure their organisations. Simply put, the instant case is missing this requirement.
- k. Undue Protection: India is known to over-protect its domestic industries. This should risk their relations and future trade status with the Republic of Korea and the rest of the international community.
- 1. Public Interest: The imports of subject goods from Hyundai Steel have contributed in satisfying the Indian industry's demand and it is far more important to protect the different interests of end-users and consumers rather than to reinforce the dominant position of the petitioners by means of over-protecting the domestic producers against imports from various countries.
- m. Hot-rolled coil with pickling and oiling (PO): Hyundai Steel Korea sells the PO product to HSIL, which, in turn sells the merchandise to an affiliated customer, Hyundai Motor India Limited, to be utilised as raw material for its automobile production. These PO products are manufactured mainly and particularly for the production of Hyundai Motor automobiles. Hyundai Steel performs special testing and manufacturing process to produce the PO products for Hyundai Motors. They are, therefore, irreplaceable; they cannot be substituted with other merchandises. Doing so would cause a significant quality performance issue for Hyundai vehicle, which would result in risking the safety of automobiles drivers in India. This is the reason why the export selling prices are much higher for these PO products than other hot-rolled coil products. These PO products thus should have not been included in the scope of the product under consideration and should have been listed along with the API grade steel, silicon electrical steel and five (5) other excluded product types.

Submissions by Importers, Users and Associations

- XV. **Federation of Associations of Maharashtra** (**FAM**): FAM is a Mumbai based apex organisation of trade associations of Maharashtra consisting of 1000 transport, small-scale and trade associations in Maharashtra.
 - a. The steel sector is facing excessive debts and losses due to such factors are not attributable to import prices of steel in India.
 - b. Quantities imported under advance authorisation cannot injure the Applicants.
 - c. There has been undue haste in imposition of provisional safeguard duty in this case.
 - d. The PUC only accounts for 9% of the capacity of the applicants.
 - e. JPC is an officially empowered agency in India for the collection and maintenance of data, by the Ministry of Steel. There is deviation in JPC data and IBIS data relied upon in the application.
 - f. It has been alleged that there has been a surge in imports, drastic drop in sales turnover, decline in capacity utilization, consistent losses and reduction in employment levels which are clear indicators of injury. All these basic parameters are missing altogether in the present case of the applicants.

 Alleged surge in imports ('000 tonnes)

Particulars	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Imports (as per JPC)	1812	1871	1104	2006
Indexed	100	103	60	109

As per JPC data, the increase over the period of 4 years (which is a more logical period for a trend analysis) is only about 9%. While alleging surge in imports in 2014-15 over the period of 2013-14, a due thought has not been given to the fact that there was an abnormal drop of roughly 40% in the earlier year mainly due to the unprecedented dollar volatility during that period.

Moreover, the applicants took the advantage of this dollar volatility and increased imports and hence keeping domestic prices much higher at the cost of the Indian consumer.

- g. On perusing the sales figures of the JSW Steel Ltd. it shows an increase of about 29% over the period. On a similar analysis of the Steel Authority of India (SAIL) figures, it shows a more or less stable trend in the sales turnover.
- h. In cases of both these applicants, it shows a fairly increasing / stable trend in the annual sales in spite of the drop in the prices of the major raw materials such as iron ore, coaking coal and coke by almost about 40-60%
- i. For the same period, capacity utilization of JSW Steel Ltd. had surged from the base year of 2012-13 to the year 2014-15 by about 62% thereby achieving almost about 88% of productivity.
- j. Essar Steel India Ltd. on the other hand has underutilization of capacity which is basically attributable to financial indiscipline and non-availability of raw materials. However, by combining their performance with the performance figures of the other applicants tends to show an incorrect grim picture of the whole domestic industry.
- k. SAIL and JSW Steel have been showing reasonable profits over the period of last four years barring a somewhat dim picture in the recent quarter. Infact, in case of JSW Steel, losses incurred by the foreign subsidiaries when consolidated / transferred to Indian operations displays an incorrect picture as is seen in its financial statements.
- 1. The profitability of these applicants, especially at the time when the entire steel industry globally is making the huge losses only demonstrates how the Indian consumers are being over-charged.
- m. It is submitted that from the above Applicants, there are some Applicants who are facing serious problems of financial indiscipline. These books of accounts of these Companies does not appear to be giving true and fair view of its state of affairs and are apparently pursuing to window dressing techniques. The interested party only requests this Authority to order for the CAG Audit to check the fairness of the affairs of these companies.
- n. Instead of an alleged drop in the basic wages and salaries, there has been a consistent increase in the employment costs of these applicants over the last four years.
- o. The major raw materials used for the manufacturing of the subject steel goods are iron ore and coaking coal. The prices of these raw materials have dropped between 40-60%.
- p. It is fairly logical that the selling prices of these subject goods be accordingly adjusted. However, it is interesting to note that in spite of that the sales of the applicants have been increasing.
- q. The subject goods which are used as raw materials for certain re-roller mills such as POSCO, Uttam Steel, National Steels, Asian Color Coated etc. it needs to be noted that PUC is a raw material and not a product for trade. In such cases, PUC is further worked upon and converted into cold rolled sheets / galvanized sheets / corrugated sheets etc. POSCO alone had imported around 0.95 million tonnes of the subject goods for this purpose between the period of May 2014 to September 2015 for their own Steel Plant in Maharashtra.
- r. It is submitted that, if these imports as well as the quantity of imports attributable to other cold roller mills is removed from the total import figures as produced by the applicants, there is actually the decline in the imports of the subject goods in India over this period. In fact, local plants have declined POSCO to provide the subject goods due to their own inability to produce the required quality and quantity of those goods. The quantum of such imports of raw material may be around 35-40% of the total imports of PUC in India.
- s. The applicants have argued that the countries like Thailand and Malaysia had also taken recourse to these tariff barriers by imposing the safeguard and anti-dumping duties respectively. However, it is hereby submitted that the scenario of surge in imports and other parameters have been very critical at that point in time in those countries. These could not be in any manner comparable to present situation in India.
- t. All the aspects when examined in detail with facts and figures substantiate that there is no sudden or sharp increase in imports of alloy steel imports so as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry.
- u. There is no threat of or serious injury caused to the domestic industry due to the imports of alloy steel products and imposition of the Safeguard Duty in the absence of any threat of or serious injury to the domestic industry is violative of Article 14, 19 & 21 of the Constitution of India.
- v. The pre-requisites as prescribed under the Safeguard Rules does not exist and as such there is no significant overall impairment of domestic industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the product concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by the increased imports, changes in the levels of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses and employment, none of these is adversely affected as misrepresented by the Applicants.
- w. The Applicants have sought for imposition of Safeguard Duty on products which are distinctly categorized as different products with separate identity of their own.
- x. The Applicants have not excluded the imports on account of captive consumption which needs to be excluded for the computation of total imports. The Applicants have not excluded the imports under advance authorizations i.e. imports for exports which needs to be excluded for computation of total imports. There is no nexus between the imposition of safeguard duty in the absence of any emergency and the objective to be achieved by such imposition. The capacity utilization of the Applicants has reached its optimum well above the International Standards. Despite optimum capacity utilization, the alloy steel production by the domestic industry is negligible. The Applicants have wrongly relied on safeguard measures like imposition of safeguard duty by other countries viz. Thailand and anti-dumping duty by Malaysia which is completely irrelevant and does not apply to the situation in India as it prevails today.

y. The nature and quantum of safeguard duty sought to be imposed is arbitrary and without any basis. The Applicants intend to make windfall profits by seeking imposition of safeguard duty and should not be allowed misrepresent facts before the Authority. All the aforesaid aspects substantiate that there is no sudden or sharp increase in imports of alloy steel imports so as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry.

XVI. Purva Metal Sections Pvt. Ltd.

- a. We require HR coils as raw material for manufacturing Steel Pipes & Tubes. Imposition of safeguard duty will shoot up our raw material procurement cost and our product cost will increase unreasonably, thereby we will lose competitiveness in the market.
- b. One side we will incur higher cost of production while on the other side there is always threat of competition from foreign exporters.
- c. By implementing safeguard duty, you will be knowingly creating & supporting monopolistic trade practices in India.
- d. If safeguard duty is being recommended in this investigation, then we request you to impose the safeguard duty on import of Steel pipes & tubes into India also.

XVII. Bharat Chamber of Commerce

- a. Imposition of safeguard duty will seriously affect the automobile, construction and other industries which are consuming HR steel coil as raw material.
- b. Engineering industry will lose its competitiveness globally.
- c. Imposition of safeguard duty will affect the manufacturing industry and thus Make-in-India campaign will get affected.
- XVIII. **Mitsui & Co. India Pvt. Ltd:** Mitsui & Co. India Pvt. Ltd. have invested in ISC (Indian Steel Corporation) as Joint Venture. ISC is involved cold rolling & galvanizing and painting steel mill. They are importing HRC from Japan. Their submissions are as under:
 - a. Substituting imports with local procurement of HRC might not be possible in short terms in terms of financial (payment terms), quality and various size availability and economical point (price) of view.
 - b. Steel or HRC is basic raw material for broad industries and segments. However, HRC safeguard duty, if implemented, would damage or destroy viability and growth potential of downstream industry.
- XIX. **Nezone strips Limited and Nezone Tubes Limited:** Nezone strips Limited and Nezone Tubes Limited are the producers of Black Pipes, C.R. Strips and Precision Tubes. Their submissions are as under:
 - a. We have been importing HR coil in thickness 2.00 mm and below because our regular supplier M/s Tata Steel Ltd. had stopped supplying due to availability constraints. Therefore, we are forced to import this specific product and this should be excluded from the product scope.
 - b. We have already entered into contact with our exporter and duty is levied on transaction which has effectively been completed before the imposition of duty and thus is retrospective in nature which we believe was never the intension of Government.
 - c. The fair level capacity utilization of 76% indicates that the situation is not as threatening as has been made out to be.
 - d. Market share of 12% is not alarming if we view it in the light of the fact that domestic production have not increased to cater to higher demand.
 - e. Steel material prices have fallen internationally due to fall in iron ore, coal and oil prices. Since basic raw material prices are witnessing a fall, there is no reason why the profitability of domestic industry should fall.
 - f. The demand for H.R. Coil in India will diminish as all downstream products will be imported and thus defeating the very purpose of Safeguard Duty of protecting domestic industries.
 - g. This will dent the government policy of "MAKE IN INDIA" and will result in dumping of final consumable products into India wiping out lacs of industries in India.

XX. Prabhat Steel Traders Pvt. Ltd.

- a. 1/5th of the steel exposure of PSU banks has already been restructured. This exercise usually takes 12 to 18 months. This means that the companies were already in default from years which can be attributed to the indiscipline in cost, political issues of raw material supply etc. Imports are not the reason of this condition of steel industry.
- b. JPC data shows export of approx. one million ton at prices lower than domestic prices which created a deficit which has been filled by the imports.
- c. Imposition of safeguard duty will lead to increase in import of finished goods making Indian manufacturers more non-competitive.

- d. In the increased imports figure, one of the largest constituent is has been the import quantity of POSCO and China Steel Corporation who are importing HR coil from their parent companies to convert it into cold rolled and electrical sheets in their new steel plants commissioned in Maharashtra and Gujarat respectively.
- e. Some industries have been forced to import due to lack of availability of their products in right sizes, quality and correct prices.

XXI. Cold rolled steel manufacturers Association of India (CORSMA)

- a. The imports of HR Coil were high during 2014-15 because the Indian producer despite a shortage situation in domestic market exported over 1 million tonnes of HR Coil well below the global prices in order to maintain shortage in the domestic market.
- b. Data examined should be based on 5 year data commencing from 2010-2011 to 2015-16. It may be pointed out that 2013-14 was one of the worst years for steel industry as the consumption and imports of steel were rock bottomed and it cannot be taken as base year for investigations.
- c. HR coil producers are already protected by 12.5% custom duty. Ocean freight of USD 30 and incidental charges of around USD 15 along with custom duty @ 12.5% amounts to USD 90 per ton and domestic prices fixed on landed costs basis are higher by around USD 90 per MT eroding global competitiveness of manufacturing sector both in domestic and global market resulting in import of manufactured steel product at the cost of Indian industry. Imposition of safeguard duty @ 20% will further hike protection level and domestic prices by 64 USD which will be disastrous for Indian manufacturing industry and 'Make in India' mission.
- d. Imposition of safeguard duty will result in erosion of global competitiveness of the manufacturing sector.
- e. The past three Petitions were rejected by the Anti-Dumping directorate and Safeguard directorate as well as Calcutta and Delhi High court due to misrepresentation of the facts.
- f. Provisional duty should have been imposed after a public hearing to ascertain the facts.
- g. Petition is not based on authentic JPC data. Joint Plant Committee under the Ministry of Steel is the official and authentic data bank for the Steel industry and HR coil producers regularly submit comprehensive data to JPC for compilation of its reports. The Petition for the imposition of Safeguard duty has been based on data from a private agency which is not authentic and also manipulated by the petitioners.
- h. It is observed that the period of investigation has been reduced to 2 years and 1 quarter by DGSG which is considered too short and against the norms to establish any trend. The POI should be extended to at least 5 years.
- i. At least 4 more grades should be added to the PUC exclusion list to ensure that heavy custom duty do not lead to import of manufactured goods instead of HR Coils.
- j. There is no injury to the domestic industry from excessive imports because the production of HR coils has increased. Moreover, neither there is any decline in the capacity utilization nor there is laying off of the workers
- k. Reduction in global prices of HR Coils due to sharp fall in prices of raw materials. The global and domestic prices of basic inputs for steel making like Iron ore, coking coal, oil and lubricants have registered a steep decline of leading to a decline in the global prices of HR Coils.
- 1. Allegation of cheap imports of steel from China flooding the Indian market is also baseless as imports from China constituted only 28% of total imports in April-June 2015 while for HR Coils it was around 30%
- m. HR Coils producers have incurred heavy debt mainly due to indiscreet and unproductive investments
- n. Domestic HR coils producers have not been able to match the global prices despite having captive iron ore and coal mines because of absence of technological and product development.

XXII. Surya Roshni Limited

- a. If injury is found to be suffered by the HR coil producers, then all the downstream products including Cold Rolled, GP/GC Sheets/ Coil, MS ERW and Spiral Pipe, Color coated steel etc. should also be considered for safeguard duty.
- b. If safeguard duty is imposed on HR coil without imposing the duty on downstream products then it will cause serious injury to the downstream industry using HR coil as raw material.
- XXIII. **EEPC India (Formerly Engineering Export Promotion Council):** Most of the members of EEPC India, who are MSME engineering manufacturing units and exporters, have represented their concern over possible imposition of safeguard duty on HR coil which is a basic raw material for an entire range of engineering industry.
 - a. Industries like automobile, transportation equipment, construction equipment, fabricated steel products etc. will be affected due to imposition of safeguard duty on HR Coil.
 - b. The engineering industry consuming HR coil as raw material will become uncompetitive globally. Imports of the finished goods will increase thereby affecting the domestic manufacturing and Make in India initiative.

XXIV. Sunil Tripathi

- a. There has already been two-stage rise in custom duty for the subject goods, two anti-dumping actions on cold-rolled products already in force and non-tariff barriers that require suppliers abroad to be registered with BIS.
- b. Imposition of safeguard duty will further affect the downstream industry and other small manufacturers.

- XXV. Godrej & Boyce Mfg. Ltd.: Godrej & Boyce Mfg. Ltd. is an importer of the subject goods during the POI.
 - a. Safeguard duty imposed at 20% on H.R, products over 600 MM would benefit few large integrated Steel producer only, but it would be detrimental to the Steel users in the organized, as well as unorganized sector.
 - b. The contribution made by steel user to the Ex-chequer by way of direct and indirect taxes is higher that of the Steel manufacturers. The employment generated by the Steel user's runs into millions, these factors should be considered by the Government, as both these factors have a direct impact on the economic growth.
 - c. The 20% Safeguard Duty over and above the regular Customs Duty of 12%, making the import from all other countries, beside China is Prohibitive. Indiscriminative increase in price would impact the growth of steel user industries, which is already on the decline and at all-time low, at the expense of a few.
 - d. No rationale of imposing Safeguard Duty on entire range of H.R, which are not currently produced in the Indian Steel Industries viz. High Tensile, High Strength Impact Resistant and need to be imported for end user.
 - e. China is exporting steel at FOB rates, the Government may curb import from China and not restrict blanket import from other countries such as Japan. Korea, with whom we have existing Free Trade Agreements.
 - f. Safeguard Duty will affect our relationship with ETA countries and our exports to these countries may be severely affected.
 - g. Safeguard Duty and Customs Duty on H.R. Coils, aggregate to 32.5%, whereas the Customs Duty on finished goods is much lower (average 10 %) and hence imports of finished goods would increase, particularly from China which would be contrary to our "Make in India" policy.
- XXVI. **Textile Machinery Manufacturers Association (India):** The representation is made for one of its member Lakshmi Machine Works Ltd., Coimbatore, who is an importer of the subject goods.
 - a. There are no manufacturers in the country who are supplying above 4mm thickness of hot rolled skin passed pickled and oiled laser stabilised sheets.
 - b. It would be unwise to impose safeguard duty of 20% on all types of hot rolled flat products of 600 mm width or more
- XXVII. **Automotive Component Manufacturers Association of India ("ACMA"):** ACMA is an association of importers/ users of the subject goods:
 - a. The cost of raw material price had major impact on the Steel Industry:
 - i. HR prices declined in August- September 2014, October-November 2014, amid sluggish demand in China and rising Global surplus from Chinese exports. Prices dipped in December 2014-January 2015, due to weak demand from the US energy sector and oversupply in the global market.
 - ii. The safeguard duty will make it more expensive for the domestic component manufacturers to procure the raw material. This will render them completely non-competitive in the domestic market, as also for the exports.
 - iii. During 4Q- FY 15, automotive industry reported YOY production growth of 9% (vehicle volume) on the back of significant growth in two wheelers and three wheelers segment and strong exports.
 - iv. The Indian auto-component industry is today, burdened with high raw material price and declining profitability.
 - v. At a time when the auto component industry is facing increased competition from countries having an FTA with India, it is imperative that the industry is insulated against such arbitrary increase in cost of raw material
 - vi. Unforeseen and sudden moves are against the India's "Make in India" programme.
 - vii. The Automotive Mission Plan 2016-26 has a vision of the Indian automotive industry ranking among the top three of the world in engineering and in manufacture and export of vehicles and auto components. To grow in value to over 12 % of India's GDP, and generate an additional 65 million jobs. The auto component industry is expected to grow five –fold from the current level of USD 40 billion to cross the USD 200 billion mark in the next 10 years with exports growing from the current level of USD 11.2 billion to USD 80 Billion by 2026.
- XXVIII. **HB Sons, Nagoan (Assam):** They are user/ retailer of steel items in Nagaon. They contend that the imposition of safeguard duty will allow middle players to take the advantage of the situation and they will increase the price abnormally.
 - XXIX. Asian Containers (Virat Industries): They are users of electrolytic tin plates for manufacture of aerosol cans.

- a. The local manufacturers of tinplate are not in a position to cater to our requirement both in quality as well as quantity. Unreasonable pricing make it difficult to cater to the consumer's budget and service & delivery is extremely poor.
- b. The custom duty on tin plates have increased from 7.5% to 12.5 % which has made tinplates competitive compared to other packaging material. Moreover the local tinplate has deficiency in quality like pin holes etc., which are hindrance to market safety and environment.
- XXX. **World Trade Scanner:** They are a weekly magazine and contend that the matter needs further investigation from other points of view besides that the Indian producers.
- XXXI. United Human Rights Federation ("UHRF"): The UHRF is engaged in taking up various common problems of the peoples for redressal and engaged in safeguarding public interest. The submissions are based on the letter filed by Manufacturers Association of India (CORSMA). UHRF had also filed writ petition in the Hon'ble Supreme Court Writ Petition No. (Civil) No. 764 of 2015, against the decision of imposition of preliminary safeguard duty on the product concerned. The Supreme Court vide its order dated 30.10.2015, disposed the said Writ Petition while granted permission to the petitioner/ UHRF to withdraw the same with liberty with the liberty to "approach the appropriate forums/ authority for appropriate relief's. The Hon'ble apex court has also directed "If and when such petition(s) is/are filed, we request the appropriate forum(s)/ authority to consider the same as expeditiously as possible". There submissions are summarised as below:
 - a. The duty is imposed on the misrepresentation of the applicant companies (M/s SAIL and others).
 - b. The Notification dated 14.09.2015 as issued by the Directorate General of Safeguard has not followed as per the prescribed Customs Tariff Rules. The Director General (Safeguard) was appointed on 28.08.2015 and had taken charge on 07.09.2015 and issued the notice of initiation of safeguard investigation on 07.09.2015 and recommended the imposition of safeguard duty on09.09.2015, which indicates the decision is hastily taken.
 - c. In order to order to safeguard domestic Industry that relevant investigation period should be effective sufficiently long to allow the conclusion to be drawn on increased import and serious injury.
 - d. The notification dated 09.09.2015, the source of information Director General Safeguard has taken, is from International Business Information Service that for the period 2013-14 and first quarter of 2015, though it in the report.
 - e. The notification dated 09.09.2015, the source of information Director General Safeguard has taken, is from international Business Information Service that for the period 2013-14 and first quarter of 2015, though it is mentioned in the report that the same has been verified on the site visit, but no particular in the notification dated 09.09.2015 about which site has been visited.
 - f. No urgency shown in the notification for imposition of safeguard duty.
 - g. The Notification dated 14.09.2015 read with Notification dated 09.09.2015 the Director General Safeguard failed to justify the reason behind imposing Safeguard duty, exactly as asked by applicant.
 - h. Capitalizing on this, the local steel mills would increase the price and the user industry will be hit hard. The steel industry expert predicts that such a shutdown of Small & Medium Enterprises and Micro, Small & Medium Enterprises industries would leave about 50,000 people jobless across the country directly.
 - i. The efforts of safeguard measure should go hand in hand with commensurate increase in duty drawback to exporters and with the domestic prices being influenced by such levies, the drawback rates should simultaneously go up.
 - j. Neither the prescribed procedure nor the timelines pertaining thereto have been followed.
 - k. There is no difference material difference in the production process between the applicant and the exporters from the subject country.
 - 1. The Notification completely ignores the views of the Domestic Market on the said subject goods, it also does not take into consideration the effects on the final product by virtue of higher cost of the raw material and penalising the end user.
 - m. The levy of import duty on a particular item at the instance of hand of Domestic manufactures of hot rolled coil cannot be a ground for the entire industry to suffer.
 - n. The views of interested parties have not been taken into consideration.
 - o. The said applicants have failed to seek any causal link between imports and alleged serious injury or threat of serious injury and hence, the said notification has been issued in breach of Customs Tariff Rules.
 - p. There is no base in the Notification how exact 20% duty has been imposed as sought by the said applicants. There is a very significant drop in imports between 2009-10 and 2014-15, as per the data available.
 - q. The undue haste with which whole process of imposing of exaggerated safeguard duty has been completed in gross violation of the procedure laid down in the Customs Tariff Act 1975 and Customs Tariff Rules and timelines compels one to infer that there has indeed been a strong motive behind this action, which is ostensibly to favour certain beneficiaries, evidently on a quid pro quo basis.
 - r. The imposition of safeguard duty is against the make in India and instead gives boost to dump in India.

- s. Countries such as Japan and South Korea have also expressed their discontent on the issue. They have been enjoying substantial duty benefits on steel imports as having made large investments in India through their companies Posco, Honda, Toyota and Suzuki etc, which are going to be affected by the levy.
- t. The applicants have mislead the Directorate General safeguard by providing incomplete data with a self-serving motive, and using only fiscal 2012-13 and 2013-14 as reference years to infer that there is huge surge in imports resulting in "serious injury" to them.
- u. The period of investigation should be at least six years. For this investigation the period of investigation should have been considered by comparing the situation in the industry between 2009-10 and 2015, as in 2009-10 the application on similar ground had been rejected by the Director General.
- v. The Authority has itself confirmed on the page 5 of the notification dated 9th September 2015, that there has been no adverse impact on the capacity utilization of the said applicant's plant which remained unchanged throughout the period of investigation.
- w. The notification itself stated that there has actually been a significant rise in the profits of the said applicant during the period of investigation, whereas the indexed profit per ton has increased from Rs. 100/- in 2013-14 to Rs. 135/- in 2014-15. They say that there has been drop in the profit per ton in the subsequent year, viz., 2015-16 annualized based on first quarter figures. This is largely on account of sales realisation, owing to depressed market conditions worldwide.
- x. The surge in inventory levels during the Period of Investigation is completely false and misleading statement, as in real terms, the increase in inventory is mere 11,411 MT during 2014-15 as compared to 2013-14 and a merge of 8,809 MT during quarter one of 2015-16.
- y. The fall in market share and fall in revenues/ profits are prominent global phenomenon, being experienced by even mega steel players worldwide.
- z. The safeguard duty is against the national objective of increasing industrial production and in turns the Gross Domestic Product growth, and makes a mockery of the Central Government's avowed policy dictum of "Make in India".
- aa. The end users are not concerned about the source of hot rolled coils (whether Indian or imported) as long as the quality is not compromised, and the price is more competitive.
- bb. The said applicant do not produce a large range of certain special steel grades which end users are therefore compelled to continue to import, as they have been doing historically and those end users will be penalized by the steep Safeguard Duty, when there is no domestic supply of such requirements, then the consumers end up paying more, just to help the said applicants before the Directorate General of Safeguard earn higher profits.
- cc. The data must be sourced from Joint Plant Committee, Ministry of Steel, Government of India, and assessment /decisions must be based thereon.
- dd. The new process of registration would require 10 to 12 months and would affect the imports of Hot Rolled Steel, as the merchants would have to pay 20% more to the local suppliers. This would in turn monopolized the business of local mills and lead to anti-competitive practices.
- ee. The petition filed was Laconic even on merits and his conclusions of irreversible damage were wrongly founded:
 - i. There is inverse correlation between the inventory of the stock held by petitioners and rate of duty. While the rate of Customs Duty increased from 5 % in 2011-12 to 12.5% in 2015-16, the inventory held by the applicants went up from 331101 Mt to 648290 MT as on 31st March, 2015 making it an Index of 100 to 196.
 - ii. As the duty rate as increased, in two phases from 7.5% to 12.5% only between 16.06.2015 to 12.08.2015. The applicant just desiring to hoard the stock with an eye to profit rather than having any real injury due to higher imports as even their production index during the period 2011 to 12 to 2015-16 had also gone up from 100 to 157.
 - iii. The higher duties have only let higher inventories as the said applicants were expecting to gain substantially blocking imports and doing away with the international competition to secure gains for themselves.
 - iv. No evidence to show that any country was cutting down its prices or was dumping its product in Indian market.
 - v. 20% duty can eventually damage the economy by curbing competitiveness of its manufacturing sector which consumes Steel, an by increasing the cost of building infrastructure.
 - vi. Safeguard duty will create monopoly for the applicants.
- vii. Safeguard duty will hurt small engineering exporters as it increases inputs costs from them and makes imports of finished engineering product from China cheaper, which will erode their competitiveness.

XXXII. **Sri Jagannath Steel Company:** Safeguard duty will be a road block in the growth of the country due to following reasons:

a. From 38 steel companies 25 are into debt. The effective value of loans taken by the segment equivalent to the turnover. Safeguard duty could be attributed to indiscipline in costs, political issues of raw material supply etc.

- b. There is clear evidence from JPC of the export of approx. One million ton at price in line with import price and globally prevailing price. These prices were lower than the domestic price and created a deficit, which is very much the gap, which has been filled by imports.
- c. This is against the "Make in India" concept of reducing tariff barriers ad making available competitive environment.
- d. The largest constituent has been the import quantity from Posco /India and China Steel Corporation. If the imports figures are removed for them the imports quantities would be much softer.
- e. The imports are available in various quantities which are not produced in India, due to size, quality, specification etc.

XXXIII. Manaksia Steels Limited: Manaksia Steels Limited is an importer of the subject goods in India. They contend that:

- a. The imposition of the safeguard duty on the subject goods which is raw material in their industry will compel them to shut down their operations.
- b. The imposition of safeguard duty is against the very purpose of "Make in India" campaign and would culminate the import of finished products.

XXXIV. WhirlpoolIndia Limited: They are a user of the subject goods in India.

- a. There has been decline in the prices of Steel around the world in past one year:
 - 34% in China
 - 22% in USA
 - 10% in Europe
 - 10% in India
- b. India being the lowest, due to:
 - Slowdown in the global economy
 - Decline in price of Iron ore
- c. Indian consumers did not enjoy the decline in prices of steel in India.
- d. Further following questions are important in the light of above argument:
 - Is the Indian industry prices higher because of inherent inefficiencies and therefore not competitive globally?
 - Are safeguard duties therefore a crutch that only perpetuates the lack of competitiveness?
 - Should the Indian Steel Industry not look within to make themselves competitive with global players rather than seek support from the government?
- e. The government should take cognizance of price trends of steel globally and compares steel price in India with those prevailing in other regions.
- f. The government should take assurances from steel industry that during the period for which the safeguard duty is applicable (200 days) there should be no increase in steel prices.

XXXV. **Maruti Suzuki India Limited:** Maruti Suzuki India Limited is an importer of the subject goods in India. They contend the following:

- a. The Preliminary Finding was issued by the DG Safeguard within 2 days of initiation of Investigation, without providing an opportunity of being heard to the importers, exporters and other interested parties. There by violating the Principles of Natural Justice. The Authority has issued the preliminary finding in hustle. They have relied upon:
 - Siemens Engineering & Manufacturing Co of India Ltd. v. Union of India &Anr. [1976] Suppl. S. C.R 489,
 - C.B Gautam V. Union of India (1993) 1 SC 78,
 - Swadeshi Cotton Mills vs. Union of India 1981 SCR (2) 533,
 - Automotive Tyre Manufacturers vs The Designated Authority &Ors. 2011-TIOL-03-SC-CUS.
- b. The Directorate General of Safeguard in the present case was appointed on September 7, 2015. The reliance was placed on in Automotive Tyre Manufacturers vs The Designated Authority &Ors. Where-by it was stated that the new designated authority should have provided a separate hearing.
- c. India being member of Comprehensive Economic Partnership Agreement needs to abide by Article 23 of the FTA. Which states that India needs to follow certain specific guidelines in case of safeguard investigations initiated under FTA. FTA provides for a different regime for the initiation of bilateral safeguard measures with additional mandatory requirements to be complied with. The Authority has completely ignored the provisions of FTA in relation to bilateral safeguards and the special conditions and procedure set out therein.
- d. In the present case no intimation has been provided to the Embassy/ Government of Japan regarding the initiation of the investigation proceeding regarding the import of the product under Consideration from Japan. The act of issuing a Preliminary Finding by the Authority, without providing any intimation or information to the Embassy/ Government of Japan, is an act of clear defiance of the provisions of the FTA. The reliance was

- placed on US- Underwear, Appellate Body Report, US-Underwear, where it was held that prior publication of a measure, as required under Article- X of GATT, could not in and of itself, justify the retroactive effects of applying import quotas with respect to imports during a period starting before the quota's publication date.
- e. No methodology provided for the determination of the Product under Consideration. The transaction wise import data made available by the petitioner has various discrepancies and at various instances proper gradation and series identification with respect to the imported product has not been done by the petitioner. Therefore certain products identified by the petitioner in the petition and thereafter relied upon by the Authority in the Preliminary Finding for the import data are not correct and fall outside the scope of Product under Consideration.
- f. In the past also the Designated Authority in Anti-dumping investigation had excluded certain Colled Rolled Steel Products imported from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand and USA, from the scope of investigation for the reason that those were not considered to be like article within the meaning of the Safeguard Rules.
- g. In the instant case, the petitioner has sought inclusion of all grades including such grades which were specifically excluded and were not considered 'like product' within the scope of the product under consideration.
- h. DGCI&S should be consulted to corroborate and authenticate the import data of the Product under Consideration as provided by the Petitioner.
- i. The Authority has nowhere recorded the Product under Consideration with that of the products imported by the importers on the touchstone of the definition of "like product" as provided in the Rule 2 (e) of the safeguard Rules.
 - The Product from Korea and Japan is not like article in terms of the Rule 2(e) of the safeguard Rule and thus different from the product manufactured by the domestic producers. Product under Consideration imported by the Respondent from Japan and Korea are of superior quality.
 - The need for the import of Product under Consideration from Japan is because of the incapacity of the Domestic Producers to supply the high quality of products as required by Respondent. The Authority should exclude such imported goods that are not being manufactured by the Petitioners. Reliance has been placed on Hon'ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in Magnet Users Association vs. Designated Authority [2003 (157) ELT 150 (Tri-Del)], wherein was held that there is no justification in including those grades that are not manufactured in India.
 - The Product under Consideration are heterogeneous set of products imported and thus they cannot be included in the same grade for comparison with the products manufactured by the domestic producers/ petitioners. The reliance is placed upon Panel Report issued by WTO in DS 427- China- Anti Dumping and Countervailing Duty Measures on Broiler Products from the United States.
 - The inclusion of the non- furnished Product under Consideration by the Authority is unjustified and not required as these products are imported in different volumes and are differently priced.
- j. The Respondent is purchaser of steel products from
 - JSW Steel Limited,
 - Essar Steel Limited,
 - Bhushan Steel Limited,
 - Tata Steel Limited
 - Hero Steel Limited.
- k. 93% of the total raw material and components consumed by the Respondent have been procured from the above-named domestic producers, which also include two Petitioners. It is only the remaining 7% of the special kind of steel, the demand of which is not fulfilled by the Domestic industry, is imported from Japan and Korea by the respondent. Indian products are different from the products that are manufactured from these countries:
 - Imported products are manufactured by Japanese Industrial Standards,
 - Includes better making standard, chemical composition, Categorization, Tensile strength, draw ability and wend ability of the Product.
 - Indian products have no mention of Hole Expansion Role
 - There is difference in quality level (formability, crack generation during rolling etc) for different steel
 makers for the same grade.
 - The respondent being one of the largest producers and manufacturers of the Automobiles, the levels of
 quality for automotive application is a major concern for it in order to avoid any commercial problems and
 complications.
 - The product imported is manufactured by way of patented state of the Art technology and the same has distinct characteristics.
- 1. The Petitioner have claimed excessive confidentiality and sufficient information is not supplied by them in order to determine the manufacturing, production and sales of the Domestic market. The petitioners did not provide any reasons for claiming the confidentiality on the information provided to the Authority. The Respondent have relied upon Sterlite Industries (India) Ltd. vs Designated Authority.

- m. The importers and the interested parties were not intimated by the Authority about the development regarding the examination and corroboration of the information provided by the Domestic Producers. Without corroborating the evidence produced by the Domestic Producers, the Authority heavily relied on the said information and recommended imposition of Safeguard Duty at a whopping rate of 20%.
- n. The Authority did not disclose the methodology adopted to determine the level of safeguard Duty recommended by the Authority. The Authority did not follow the principle laid down in Article XIX of GATT 1994. The initiation notice was silent on the unforeseen development that has led to increase of imports of Product under Consideration. The petitioner also failed to show factual or legal basis to demonstrate that unforeseen development exist in the present matter.
- o. There has been miniscule increase in the import data as provided in the petition. No justification provided to show on which petitioners have annualised the imports for the entire year of 2015. There is gradual increase in the imports of the Product under Consideration and there is no "sharp", significant or "sudden" increase in imports.
- p. The increased import of Product under Consideration has no impact on the domestic production of the goods. The Authority at para 25(a) of the Preliminary Finding has recommended that the production of the Domestic Producers have remained at the same level. The Authority has not substantiated as to what are the critical circumstances to warrant an issue of Preliminary Finding. The Authority has acted in contravention principles of safeguard investigation.
- q. No evidence provided by Petitioner to show serious injury. The Authroity has ignored in the Preliminary Finding that the requirement under Safeguard Rule is to initiate investigation only when there is "sufficient evidence" to suggest that the increased imports of the product has caused an injury to the Domestic Producers.
- r. The Authority has acted in contravention of Paragraph 1 and 2 of the Annexure to the Safeguard Rules. The Respondent relied upon the Appellate Body Report on US- Cotton Yarn. Following submissions are made based on the case sited:
 - Petition does not show any injury whatsoever.
 - Petitioners has fared consistently well in terms of production, domestic sales and total sales and profitability.
 - The methodology prescribed for segregating capacity for the Product under Consideration from total Capacity is still unclear.
 - Essar Steel India Limited has made complete Turn around and earned profits from operations.

Particulars	FY 2014-2015	FY 2013-2014
	(Rs Crores)	(Rs Crores)
Gross Revenue	19,258.50	16,286.59
Net Revenue	17,162.39	14,348.55
Profit/(Loss) before exceptional items and taxation	334.29	(3,916.21)
Profit/(Loss) before Taxation	1,008.96	(2,314.74)
Earnings per share (diluted)	Rs. 2.26	Rs. (5.70)

s. JSW Profitability have increased.

Particulars	FY 2014-2015 (Rs.	FY 2013-2014	Growth %
	- Crores)	(Rs Crores)	
Gross Turnover	49,658	48,527	2%
Net turnover	45,352	44,529	2%
Operating EBIDTA	8,872	8,783	1%
PAT	2,166	1,335	62%
Earnings per share	Rs. 88.24	Rs.53.86	64%
(diluted)			

- Sail has been consistently making profits.
- Price Underselling, depression and suppression data has not been indicated in detailed from in the NCV of the petition filed by the Petitioner.
- There is no change in the capacity utilization of the Domestic Producers as per Para 25 (d) of the Preliminary Finding.
- The Authority in Preliminary Finding has also not pointed out any possibility of likelihood of a sudden decline in the capacity utilisation of the Domestic producers.
- The Authority has not corroborated any piece of information provided by the Petitioner and has without any recording any reasons assumed a prima facie case and initiated the investigation process.

- The safeguard duty will have cascading effect on the overall prices of vehicles and parts on the automobile industry.
- t. A number of Automobile companies and OEMs are extensive importers of the subject products, and levy of any safeguard duty will affect the business interest of the said importers substantially. Safeguard Duty will be inconsistent with fiscal incentives introduced by the Government of India for improving the ailing health of the Automobile Industry.

XXXVI. V.K. Industrial Corporation Limited

- a. Steel imports only constitute 10% of the total steel consumption in India. This is very small share of total market.
- b. Government has already given too many benefits to the steel mills.
- c. Importers are a very small percentage of total market and are catering small and medium sized business and startup companies which require goods on credit basis. Domestic manufacturers are unable to cater to such small requirements.
- d. Prices of raw material fell steeply. Thus domestic mills should also be able to decrease their prices. It is due to fall in raw material prices, other countries are supplying at lower prices
- e. Domestic producers are exporting steel prices lower than domestic prices. Thus domestic mills are able to compete globally with other cheap steel mills and maintain profits.
- f. Small engineering and consumer firms will not be able to compete globally resulting in shutting down of these industries.

XXXVII. Lakshmi Machine Works Limited: Lakshmi Machine Works Limited is textile machinery manufacturer in India.

- a. In India no manufacturer is available to supply above 4mm hot rolled skin passed pickled and oiled laser stabilized sheets. Skin passed is required to meet required flatness in our parts.
- b. No manufacturer is available in India to supply laser stabilized material. Our parts are manufactured in laser cutting for which stabilized material is required.
- c. Most of the items manufactured out of these sheets are functional components with precise tolerance.
- d. Imposition of safeguard duty will lead to un-competitiveness in global market.

XXXVIII. JBM Industries Limited

- a. Domex 650 grade alloy is used for manufacturing high strength components in automotive industry. There is no alternate grade developed by the domestic mills till date so we will continue importing these special grades. Imposition of safeguard duty will lead to increase in our cost which will eventually lead to increase in cost of final product.
- b. A lot of special grade HR steel is imported by secondary mills, direst users and OEMs. The imposition of safeguard duty will increase the cost of raw material which will further increase the cost of vehicles. This will adversely impact the automotive industry.

XXXIX. Neel Metal Products Limited

- a. A lot of special grade HR steel is imported by secondary mills, direst users and OEMs. The imposition of safeguard duty will increase the cost of raw material which will further increase the cost of vehicles. This will adversely impact the automotive industry.
- b. Neel Products may import grade HR material in future that go in manufacturing of safety components of vehicles. Imposition of safeguard duty has increased cost of raw material which will lead to increase in the costs of vehicles.
- c. The imposition of safeguard duty will adversely affect the strained automotive industry and also the infrastructure industry where a lot of steel is used in fabrication work in projects.

XL. Larsen & Toubro Ltd.

- a. Larsen & Toubro has some export equipment orders which were not applied for advance authorization for import of raw material @ 0% duty, but it opted to get the export incentive under "All Industry Rate Draw Back Scheme' @1.9% of export FOB value. Due to provisional safeguard duty of 20%, cost of raw material of these equipment have risen. Larsen & Toubro requests DG Safeguards to waive the safeguard duty for imports of inputs required for manufacture of export products.
- XLI. Uttam Value Steels Ltd.: The Company extends full support for imposition of safeguard duties against imports of the subject goods.

XLII. Tube Investments of India (TII)

- a. Imports by TII are based on agreed specifications with the suppliers. Being an auto component supplier, TII's product undergoes a lot of validation process and imports are done irrespective of international and domestic steel prices.
- b. Levy of safeguard duty on hot rolled coils will impact the cold rolling business heavily as consumers will switch to import of cold rolled coils.
- c. DG Safeguard should look at a fair floor price mechanism for imposition of safeguard duty for HR Coils. Moreover, CR/CRCA should also be considered along with HR for purpose of imposing safeguard duty.

XLIII. Nippon Steel Pipe India Pvt. Ltd. (NPI) represented by AZB & Partners

- a. NPI imports 22 different specifications of PUC which are used for producing tubes for automobile manufacturing. Hot rolled flat products imported by NPI differ in chemical composition of components such as carbon, manganese, silicon, boron and phosphorus which are tailored to meet the needs of the end user.
- b. Indian steel mills are unable to produce special hot rolled coils imported by NPI. Importation of the PUC is necessary to meet the needs of the downstream Industries.
- c. Adoption of safeguard measure will be detrimental to the Indian auto industry which accounts for 7% of India's GDP and provides provide direct and indirect employment to 19 million people.
- d. Levy of safeguard duties on the PUC would affect NPI's supply chain adversely. This would decrease production volumes to the extent that customer demand stemming from the Indian automobile industry would not be able to be met. Further, in view of lower profitability as a company, NPI may also be forced to lay off employees.
- e. NPI requests DG Safeguards to exclude from the scope of the PUC, imports used for the production of Tortion beam, door impact beams, stabilizers in automobiles, front forks in motorbikes and other products imported by NPI. These imports are either not produced locally by the Domestic Industry with quality specifications required by the Indian industrial users of the PUC or have not yet been granted approval from OEMs.

XLIV. The Bombay Iron and Merchants Association (BIMA) represented by M/s. MV Kini Law Firm

- a. The domestic industry is suffering due to excessive borrowings, indiscipline in costs, political issues of raw material supplies etc.
- b. Domestic industry exported approximately 1 million tonnes at a price in line with the import price and globally prevailing price. These prices were lower than the domestic price.
- c. Existing barrier of 12.5% duty and high interest rates will lead to a situation of Indian manufacturers becoming non-competitive and will lead to imports of finished goods.
- d. One of the large constituent in import figures are the imports made by POSCO India and China Steel Corporation for captive consumption. If these figures are removed, so called trumpet of huge increase in imports would sound much softer.
- e. Imports include various quantities that are not produced in India due to size, quality, specification etc.
- f. The Applicants do not constitute Domestic Industry. Applicants have not distinguished between alloy and non alloy products. These are distinctly classified products having different identities and customs classification
- g. Authenticity of the data relied by the Applicants is questionable as it is not from a government recognized entity specifically authorized to collect and maintain such data. Further, the methodology used for sorting the product under consideration is a mere reproduction of the definition of the product under consideration and does not sort the product as claimed
- h. Applicants have misrepresented to the Authority by submitting that one of the uses of the subject goods is for automotive industry. Automotive industry relies on alloy steel products which has negligible domestic production
- i. If alloy steel production is excluded from the total imports, there would be no substantial increase of imports. Moreover, 2013-14 cannot be construed to be a benchmark as it was an abnormal year.
- j. Quarter to quarter comparison has to be of a quarter of a year with the same quarter the previous year.
- k. Imports for captive consumption should not be considered as it does not determine the regular demand. Import by POSCO Maharashtra and China Steel in 2014-15 for captive consumption for industrial set up must be excluded from total imports.
- 1. The Applicants have not excluded the imports under advance authorization i.e. imports for exports which needs to be excluded for computation of total imports.
- m. Decrease in market share of the Applicants is due to increase in market share of the 'supporters' to the Petition.
- The reasons of unforeseen developments specified are mere global scenarios of events which has no "India Only" impact.
- o. The Capacity utilization of the Applicants has reached its optimum well above the International standards. Moreover, even if domestic industry was to achieve 100% capacity utilization, the demand for alloy steel products cannot be met.
- p. Perusal of information from the Annual Reports of the Applicants depicts that that none of the pre-requisites exist for imposition of safeguard duty.

- q. The Applicants have not taken into account their high finance costs incurred due to huge debts.
- r. Comparison with trade measures by countries like Thailand and Malaysia is unsustainable and misleading as the surge in imports and other parameters were very critical in those countries.
- s. The Applicants have nowhere through the Petition specified the measures that the affected party is required to take to check and counter the perceived surge in imports.
- t. The Applicants intend to maintain higher prices in domestic market and create artificial shortage by resorting to exports which is evident from the price comparison of domestic prices vis a vis general import prices and export prices of the Applicants.
- u. Applicants have maintained prices of finished goods steady and are making windfall profits without passing over the benefit of decline in prices of iron ore.
- v. Allegations with regard to price undercutting, price depression and prevention of rise in price is denied and the Applicants be put to strict proof of the same.
- w. There is no decrease in profitability on perusal of the annual reports of the Applicants. Despite being listed companies, the Applicants have not shared the actual profits on ground of confidentiality although the information with regard to profits of a listed company cannot be subjected to confidentiality.
- x. The profitability and ROCE of the domestic industry has no bearing on the alloy steel products. Applicants have made a vague statement that imports during August 2015 is in the range of USD 320-350/MT. Applicants have not provided details of alloy steel imports as two distinct products cannot have the same prices.
- y. The nature and quantum of safeguard duty sought is arbitrary and without any basis. Imposition of safeguard duty on the importers of alloy steel products, the production of which is negligible in nature, is violative of right to livelihood of the Interested Party and the like more specifically Article 14, 19 and 21 of the Constitution of India.

XLV. Honda Cars India Limited (HCIL)

- a. HCIL uses steel products as per its global Honda Engineering Standards. HCIL has developed steel grades as per these standards with various steel mills globally, among which there are various Indian steel mills like Tata, JCAPCPL, JSW, POSCO.
- b. HCIL has been working to localise its raw material requirements to a large extent. However, even after lots of localisation, local steel mills have not been able to meet HCIL's entire steel grades requirement. To meet its requirements, HCIL is importing some of HR material either for direct application or as a raw material for cold-rolling by local mills POSCO-Maharashtra and JSW steel from Japan and Korea.
- c. It is not possible for automotive OEM's to switch sources of raw material supply during the model life. All material sources are decided early during the model development and validation of the product quality through testing is done accordingly. Therefore, to ensure quality of the cars manufactured, steel material sources cannot be changed during the model life.
- d. So with sudden imposition of safeguard duty, HCIL will have to continue use of imported HR material directly or indirectly which will have a huge cost impact, and lead to increase in manufacturing cost of HCIL's cars.
- e. HCIL understands that the safeguard measure is being taken to curb excessive dumping of imported steel in Indian market to save interest of local steel mills, but considering that for some of the automotive grades, there are no appropriate substitutes available with local steel mills or local steel cannot be used due to technical reasons also fall under this category which will directly impact automotive industry.
- f. It is requested that the Indian Government should exempt HR grades for automotive application from the safeguard measures to support in sustainable development of the automotive industry.

XLVI. Bharat Heavy Electricals Limited, Bhopal (BHEL)

- a. Customs authorities are applying safeguard duty notification dated 14 September 2015 on imports of steel plates falling under CTH 7208. BHEL's recent imports of 160 mm thick plates of ASTM 537 Class-I has been assessed by Mumbai Customs under BE No. 2699772 dated 24 September 2015 with 20% safeguard duty. Although Customs clearance of these plates was nil duty under Advance Authorisation No. 1110027559 for an export job, the bond value was debited with 20% safeguard duty and it is apprehended that safeguard duty of 20% may be imposed by Customs on subsequent imports.
- b. The domestic industry does not have capability to manufacture following category of carbon steel plates:
 - i. BQ Steel Plates to IS 2002 (ASTM 515 Gr. 70) of thickness of 120 mm and above;
 - ii. Carbon steel plates for pressure vessels to IS 2041 (ASTM 516 Gr. 70 & A537 Class-I, Furnace normalised) of thickness 100 mm and above;
 - iii. Carbon Steel Plates to ASTM 537 class-II (no equivalent IS available) of 80 mm and above.
- c. The intention of the notification dated 14 September 2015 is to levy safeguard duty of 20% on hot-rolled coils to protect the domestic industry and not Plates described as flat products under CTH 7208. Moreover, the Plates, as indicated above are not manufactured by domestic industry and hence there is no need for levy of safeguard duty.
- d. It is requested that suitable amendment/instructions under Notification No. 02/2015 dated 14 September 2015 should be issued to avoid misinterpretation of safeguard provision and exempt import of Steel Plates (Flat Products) falling under CTH 7208 from imposition of 20% safeguard duty.

C. POST-PUBLIC HEARING WRITTEN SUBMISSIONS

I. Domestic Industry

- a. Domestic Industry reiterates all the facts, contentions, averments and statements presented in the petition and requests that such submissions made earlier shall be deemed to be incorporated herein. The earlier submissions on behalf of Domestic Industry should be treated as part and parcel of the present submissions.
- b. Import data upto 19th October 2015 and costing information has been provided.
- Domestic Industry has excluded the API Grade Steel from scope of PUC keeping in view the availability of API Grade Steel for Indian users.
- a. It is being observed by the domestic industry from various reports in media that some of the Indian importers / foreign exporters are trying to evade the provisional safeguard duty applicable on commercial / base grade structural steels (meant for conventional structural applications) in the guise of 'API 5L' grade, which is exempted from safeguard duty. Therefore, Domestic Industry requests DG Safeguards to kindly clarify the exclusion of API Grade Steel with the following explanation:
 - "API Grade Steel refers to steel intended for manufacturing welded steel pipes used for pipeline transportation systems in the petroleum and natural gas industries"
- d. The Applicants production together accounts for more than 50% of the total production of PUC in India and it represent a major proportion of Indian production of the product under consideration in the country.
- e. The Applicants production together accounts for more than 50% of the total production of PUC in India and it represent a major proportion of Indian production of the product under consideration in the country.
- f. Imports have increased from 2,219,711 MT in the year 2011-12 to 4,167,886 MT in the year 2015-16 (Annualized). Further, imports have increased more than threefold during 2015-16 as compared to 2013-14.
- g. The average quarterly import during 2011-12 and 2012-13 was around 550,000 MT. From that level, average quarterly imports during 2013-14 went down to 323,025 MT. From such low levels, the average quarterly imports during Q2 2015-16 increased to 1,239,103 MT.
- h. Monthly analysis of import data during 2014-15 to Q2 2015-16 indicate that imports have increased aggressively during each month.
- i. There is constant decline in imports prices of PUC.
- j. The year-on-year analysis, quarter-wise analysis and month-wise analysis of imports strongly indicate a sudden, sharp and significant surge in imports of the PUC.
- k. Increased imports of the PUC are causing injury to the domestic industry and are having a significant impact on production, sales, capacity utilization and profits of the applicants.
- 1. The market share of imports of the PUC has almost doubled in total demand including captive in 2014-15 from the previous year 2013-14. A similar trend is also visible for market share of the PUC in total demand excluding captive. The imports have taken away all the increase in demand of the PUC.
- m. The quarterly trends for the recent period indicate that the market share of imports in total demand including captive increased from 7% in the first quarter of 2014-15 to 13% by the fourth quarter. Market share of imports in total demand excluding captive increased from 11% in the first quarter of 2014-15 to 21% by the fourth quarter. The market share of imports in total demand remained high during the first quarter of 2015-16. If imports continue to increase at this pace, the Domestic Industry will be wiped out soon.
- n. During 2014-15, demand (excluding captive) increased by 1,158,614 MT compared to 2013-14. At the same time, sales of the applicant domestic industry decreased by 393,351 MT during the same period. The Domestic Industry has not been able to increase its sales commensurate with the increase in demand.
- o. The domestic industry has made significant investments during 2012-13 and 2013-14 in view of increasing demand of subject goods in India. However, capacity utilization of the Domestic Industry has remained stagnant over the entire period of investigation.
- p. The inventory of Domestic Industry has increased substantially as compared to the base year due to constant pressure of increasing imports.
- q. The domestic industry has turned into losses during Q1 2015-16. Further, the losses have increased during Q2 2015-16. The ROCE of Domestic Industry has declined drastically.
- r. Domestic Industry has been constantly forced to reduce its prices to match with the landed value of imports. If the Domestic Industry does not respond to imports by bringing down its prices, it will loose more customers and the injury would be more severe.
- s. Price underselling which was negative during the first two quarters of 2014-15, has turned positive during the last two quarters of 2014-15 due to the surging imports at alarmingly low prices.
- t. Following are such factors (Unforeseen developments) that may be attributed to the increased imports
 - Crisis in global steel market due to sluggish demand
 - Geopolitical tensions between the European Union and Russia
 - Depreciation of Ruble and Hryvnia
 - Slowdown in China PR led to weak domestic demand and strong urge to export

- Huge surplus capacities in China PR and Japan and rising steel consumption in India
- Trade remedy measures adopted by countries like US, Turkey, Thailand and Malaysia has resulted in diversion of exports from major exporting countries to India.
- u. There exists a strong nexus between the sudden and sharp increase in imports of the subject goods and the serious injury being faced by the Domestic Industry.
- v. The landed value of the imports has been decreasing constantly. From April 2014 to September 2015, the landed value of imports has fallen by approx. 30%.
- w. During the month of October 2015, imports from Korea RP are coming into India at CIF value of US\$ 224 per MT. This clearly shows that provisional safeguard duty imposed by Government of India has been absorbed by the exporters.

Submissions by Embassies and Delegations from countries

II. The Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India

- a. The Russian side is extremely worried by the initiation of special safeguard investigation concerning hot-rolled flat products.
- b. The main volume of import of PUC into India in the first place came from China PR, Korea RP and Japan.
- c. The Russian deliveries of the production to India for the mentioned periods were insignificant and in no way could affect economic performance Indian producers.
- d. The reduction of share of Russian import confirms the lack of intention of the Russian producers to extend their deliveries to India. The considerable part of it plays the fact that the Russian producers do not have significant export potential for delivery the hot-rolled flat products.
- e. The fact that regulations of WTO stipulates the possibility of pointed neutralization of unfair methods of competition with resort to antidumping or countervailing measures. Besides that, India has Free Trade Agreements with Korea RP and Japan and there is opportunity to settle concern of the Indian side with utilization of bilateral mechanisms stipulated by the Agreements.
- f. The WTO Agreement on special safeguard measures specifies high standards of evidence of injury / threat of injury, which, in accordance with the Agreement, should be classified as serious for purposes of taking some kind of measures.
- g. The economic performance of national industry, in spite of increase in deliveries from China PR, Japan and Korea RP, remains at the same level. Investments level of Indian producers shows increase.

III. Federative Republic of Brazil

- a. Safeguard measures are emergency measures, these should be applied only after complying with the high standards set by the WTO Dispute Settlement Body.
- b. India failed to notify imposition of provisional safeguard measure prior to its imposition, India failed to satisfy the requirements under Article 12.4 of the SA.
- c. The Authority only considered domestic industry's data for the period 2013-14, 2014-15 and for 2015-16, the Authority simply multiplied by four the injury parameters based on the first quarter of 2015-16. Brazil argues that such an approach is incorrect as it is inconsistent with general accounting principles, and also because one quarter of 2015-16 is not sufficient enough to indicate domestic industry's performance during 2015-16, as this financial year has not elapsed yet. Brazil further argues that the Indian Authority chose to ignore data for the period April 2011 to March 2012, despite the fact that such data was available with the Authority. This, according to Brazil is a violation of Article 4.2(a) of the SA. Brazil further argues that the period for examination of serious prejudice should be three years as per the recommendation of the WTO Anti-dumping Committee and the period of two years and one quarter in this case is not sufficient. Brazil argues that the period of investigation cannot be reduced on a justification that actual data for most recent period would be collected during the course of the investigation. In light of these contentions, Brazil argues that India has failed to comply with the objectives set out in the SA.
- d. Injury parameters of the domestic industry do not indicate existence of serious injury or threat thereof. It appears that Brazil has only referred to injury parameters as given in the preliminary findings but not in the petition.
- e. There is no causal link in this case, as an analysis of other factors indicates that injury to the domestic industry is not due to imports but other factors.
- f. Share of each exporting country has not been informed by the Authority and a list of developing countries has also not been provided. Brazil also argues that the period taken into account for calculation of the volumes imported from each source has not been specified. Due to lack of such essential information, Brazil argues that it has not been able to exercise its right of defence under Article 3.1 of the SA.
- g. Brazil argues that there is no serious injury or threat thereof to the domestic industry, and there is no causal link as well. Brazil further contends that formal requirements such as notification to the WTO and publication of essential information have not been observed in this case.

IV. China PR

- a. There is no unforeseen development in terms of Article XIX of GATT and what has been experienced by Petitioners is normal market fluctuation which cannot be ruled as unforeseen.
- b. There are no critical circumstances within the meaning of Article 6 of the Agreement on Safeguards ("SA") that warranted imposition of provisional safeguard duty.
- c. There is no serious injury or threat thereof to the domestic industry.
- d. Imposition of safeguard duty is not in public interest as downstream industries such as automotive and consumer durables might suffer.
- e. Provisional safeguard duties should be immediately revoked.

V. Chinese Taipei

Taiwan's primary concern is that its name does not feature in the list of developing countries that was notified by India vide Notification No. 103/98-Cus dated 14 December 1998. Taiwan believes that since it is not on the list, if safeguard duty is imposed, imports from Taiwan would be subjected to safeguard duty even though imports from Taiwan were below 3% during the most recent period as per World Trade Atlas statistics. Taiwan has sought assistance from the Hon'ble Director General to update the aforesaid notification so that Taiwan's economic status as a developing country is reflected correctly.

VI. European Commission

- Safeguard instrument should be used in exceptional circumstances only and the present case is suitable for antidumping or anti-subsidy investigation.
- b. Certain specific grades of the subject goods should be excluded from product scope as the domestic industry may not be manufacturing them.
- c. Use of annualised figures for 2015-16 is not objective and injury analysis as well as causality is not conclusive based on such annualised figures.
- d. Data for a longer period should have been considered for 2015-16. Factors considered in determining serious injury and causality including the market share, production, capacity, utilisation rate, employment, profits, market share etc. are insufficient and these factors do not indicate injury and causality.
- e. Captive sales and sales by other domestic producers should be examined. Indian producers have increased their open market sales by 42%.

VII. Government of Indonesia

- a. Indonesia notes that levy of provisional safeguard duty would impact their exports to India.
- b. Imports have increased by 97% between 2013-14 and 2014-15 but the increase between 2014-15 and 2015-16 (Annualised) was only 33%. Therefore, there is general decline in the level of increase and such imports should not be treated as sudden, sharp, significant and recent.
- c. There were no critical circumstances that warranted levy of provisional safeguard duty.
- d. UN Comtrade data shows that imports of the subject goods from Indonesia were below 3% and therefore, Indonesia should be outside the purview of safeguard duty as it is a developing country.
- e. Indonesian company PT Krakatau Posco only produces specific product under the classification of "not in coil and/or hot rolled plate". There is no export of steel product with specific type of "in coils" from Indonesia.
- f. Consequently, imports from Indonesia cause no serious injury to the domestic industry.
- g. India has increased import duty on steel recently but imports from certain Asian countries are happening at low duty to bilateral trade under India-ASEAN FTA, India-Japan CEPA and India-Korea CEPA.

VIII. Republic of Turkey

- a. Competent authorities are required by the WTO rules to identify the existence of "unforeseen developments" which have led to "increased imports" causing or threatening to cause "serious injury" on the relevant domestic industry.
- b. The notifications by India to the WTO do not contain a reasonable or adequate explanation/analysis concerning the existence of unforeseen developments. The Indian authorities should clarify what are the unforeseen developments that led to alleged increase in imports of the subject goods.
- c. Increase in imports on annualised basis for 2015-16 does not show the correct picture. Extrapolation on figures in the first quarter of 2015-16 and disregarding 2011-13 periods raise questions and pave the way for misleading perceptions in analysing the effects of imports on the Indian domestic industry.
- d. Movement in injury parameters for period 2011-12 and 2012-13 should also be examined. Slight increases in imports in recent period should be regarded as routine.
- e. Upward movement of profitability in 2013-14 and 2014-15, and increases in sales during the injury analysis period do not indicate serious injury to the domestic industry.
- f. There is no causal link between increased imports and serious injury. The domestic industry is suffering injury due to other factors. For example, Annual Report 2014-15 for SAIL shows that profitability was affected due to

- stagnant sales, higher salaries and wages higher usage of imported coal and higher depreciation of capitalisation of new facilities, and reduction in interest earning on term deposits.
- g. Turkey's imports are less than the 3% threshold, and therefore, Turkey should be excluded from the purview of safeguard duty in terms of Article 9.1 of the Agreement on Safeguards ("SA"), as it is a developing country.

IX. Embassy of Ukraine

- a. Imports of the subject goods increased only by 14% in 2014-15, as compared to 2011-12. Such a slight increase in imports cannot be considered as significant enough to cause or threaten to cause serious injury.
- b. The Authority initiated the investigation based on forecasted data for 2015-16, which was annualised based only on the first quarter of 2015-16. Thus, the Authority violated Article 2 of the Agreement on Safeguards ("SA") when it took the decision to initiate this safeguard investigation and impose provisional safeguard duty based on forecasted data.
- c. Ukraine relies on import data from International Trade Centre to demonstrate that there were no increases in imports of hot-rolled products in India under the headings 7208 and 72253090 during the injury analysis period. As per this data, imports into India decreased by 41% in 2014, when compared to 2010 levels.
- d. Consequently, there was no reason for India to initiate the investigation or impose provisional safeguard duty within the meaning of Article 2.1 of SA.
- e. Industry indicators show positive trends for domestic sales, production, market share, capacity, capacity utilisation when parameters are compared in 2014-15 vis-à-vis 2011-12. Therefore, there was no reason for India to come to a positive determination for serious injury under Article 4.1(a) of the SA. Consequently, there were no critical circumstances that warranted levy of provisional safeguard measures under Article 6 of the SA.
- f. There is no causal link in this case in terms of Articles 2.1 and 4.2(b) of the SA, as injury to the domestic industry is due to loss of market share to other domestic producers. Consequently, competition between domestic producers was the other factor causing injury to the domestic industry.

Submissions by Prodcucers/Exporters and Associations

- X. China Iron and Steel Association; Angang Group Hong Kong Co. Limited; Angang Steel Company Limited; Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Limited; Angang Group International Trade Corporation; Baosteel Singapore Pte Ltd; Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.; Benxi Iron & Steel (Group) International Economic & Trading Co., Ltd.; Jiangsu Shagang Group; Handan Iron & Steel Group Co., Ltd. represented by Athena Law Associates
 - a. Safeguard measures are based on a "no fault principle" and applied on imports that are made fairly and not with the intention of hurting the domestic industry. Therefore, recourse to safeguard measures should be taken only in strong cases where there is no other alternative other than imposition of duty to save a dying industry. The Appellate Body in *Korea Dairy* held that safeguard measures are extraordinary remedies which should be adopted only in emergency situations. The present petition does not demonstrate an extraordinary or emergency situation and thus should be dismissed.
 - b. The PUC selected is too wide and placed together heterogeneous products. As per Section 8B(1) of the Act read with Rule 4, a duty is cast upon the DG to specifically identify the article liable for safeguard duty. The PUC needs to be identified in singularity and there may be plurality of articles which can be called like articles. The Delhi High Court in *Andhra Petrochemcials Ltd. v. Designated Authority* supports this argument. In the present investigation, the products classified under subheading 7225 are materially different from the articles classified under subheading 7208. Therefore, the products under the two heading which are not identical and which are plural or heterogeneous in nature cannot be put together in one basket to determine a single PUC.
 - c. Section 8B of the CTA read with the Safeguards Rules and interpretations of the articles of the agreement by the WTO show that the fundamental prerequisites for a safeguard duty to be imposed are sudden and sharp increase in imports; sudden increase should be on account of unforeseen developments; serious injury or threat of serious injury to the domestic industry; causal linkage between injury and increased imports; ability of domestic industry to adjust itself to meet competition after withdrawal of duty; and duty must not be against public interest. The above legal standards have not been met in the present investigation.
 - d. There is no sudden and sharp increase in imports of PUC. Imports were 1.29 million MT in 2013-14 and increased to 3.38 million MT in Q1 of FY 2015-16 (Annualised). An endpoint analysis with the latest period is misleading and the authority should consider a wider and realistic analysis. The AB in *US-Certain Steel Products* held that examination must not be restricted to merely end points but rather must consider a wider examination considering the facts of the case.
 - e. An examination of the import information over the years and even a quarterly examination of imports during FY 2014-15 shows that there is no sudden and sharp increase in the imports in the recent period. Imports have rather declined in Q1 of FY2015-16 from 3.60 million MT in the previous quarter to 3.38 million MT. There were

- sharp increases between 2013-14 and 2014-15 but the domestic industry was in profit then. The increase, if any, was of a temporary nature with a strong reversal character as evident during FY 2015-16 (Q1).
- f. Article XIX of the Safeguards Agreement and the interpretations by the Panel in *Argentina Footwear* and the AB in *US-Certain Steel Products* hold that safeguard actions are of an exceptional nature which should be adopted only in exceptional circumstances. Applicant has relied upon unsubstantiated claims such as crisis in global steel market, geopolitical tension, depreciation in currency, slowdown in China, huge surplus capacities in China and Japan, trade measures by other countries. However, these claims do not establish the existence of unforeseen developments concerning the product. Applicants claim that exports from Russia, Ukraine, China and EU have suddenly increased on account of geopolitical tensions, excess capacity and currency depreciation is a false statement. Imports from China diminished by almost 50% between FY 2014-15 and FY2015-16(Q1). Also there was a dip of 4.22% between 2011-12 and FY2015-16(Q1). Therefore, there is no logical connection between the increase in imports and the alleged injury caused.
- g. The Authority should take into account all relevant factors of an objective and quantifiable nature while evaluating whether the increased imports have caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry. The following facts demonstrate that no serious injury or threat of injury has been caused to Applicant:
 - i. Production of domestic industry has remained stable but production of other producers has increased by almost 15 points.
 - ii. No significant changes in the capacity of the Applicants. Even if the entire demand was met by the Indian producers, there would be excess capacity in India. The excess capacity is obviously targeted towards exports markets
 - iii. Sales of domestic industry increased and that of other domestic producers is much higher.
 - iv. Indian producers hold 88% of the Indian demand and only 12% is held by imports.
 - v. ROCE has increased, particularly in FY2015-16 (Q1) over FY 2012-13. The decline in FY2015-16 (Q1) should be examined by the inverse relation between increases in ROCE at a time when the domestic industry has alleged existence of serious injury.
 - vi. There is no correlation between selling price and landed price of imports. In fact there is an inverse relation, where the landed price increased during FY14-15(Q1) and the selling price of the domestic industry declined. In Fy2014-15(Q1) the profits increased but the landed price declined.
 - vii. Inventory levels do not show any adverse situation.
 - viii. Productivity and employment remain robust.
- h. Indian producers have participated selectively with companies such as Tata Steel, Bhushan Steel not giving injury data. Therefore, DG should examine injury data of the supporting producers as well to comprehensively examine the alleged injury situation of the domestic industry.
- i. The Applicant has not provided information to establish that it is suffering injury. Further, there is no causal link between alleged injury to the domestic industry and the alleged increased imports.
- j. The Annual Reports of JSW indicate that other reasons have a serious bearing on their performance. The other circumstances must be examined by the Authority.
- k. The provisional findings were issued in haste and there did not exist a situation so critical that any delay in imposing provisional measures would cause irreparable damages. The critical circumstances required for provisional measures have not been fulfilled.
- 1. Paragraph 10 of initiation notification stated that interested parties were to be given 30 days to make their views known to the authorities but without waiting for any response the authority issued the preliminary findings.
- m. Applicant do not qualify as domestic industry under Section 6(d) of the CTA as it cannot be concluded that the Applicants constitute 50% of total Indian production.
- n. The Applicant has claimed excessive confidentiality and does not allow a reasonable and meaningful understanding of the domestic industry's case.
- o. Applicant has not provided any adjustment plan and the preliminary findings also do not mention an adjustment plan. In an application filed by United Phosphorus in 1999 for safeguards duty imposition, the authority refused to impose a safeguard duty on the ground of lack of an adjustment plan. Imposition of the safeguard duty is not in public interest. The term "public interest" has not been defined in the safeguards laws but has been interpreted by the Apex Court under different laws. In an application filed by United Phosphorus in 1999 for safeguards duty imposition, the authority refused to impose a safeguard duty on the ground that imposition of the duty would not be public interest.

XI. Metinvest Group represented by Van Bael Bellis

Metinvest Group filed a summary of their contentions taken in the pre-hearing submissions, which have been comprehensively summarised earlier. The contentions are not repeated herein for the sake of brevity.

XII. Dillinger Huttenwerke

- a. Name of the company mentioned in the notice sent to us by the Authority is 'Dillinger and Salzitter' whereas the correct name is 'Dillinger Huttenwerke'.
- b. We are not engaged in production or exports to India of the subject goods. We are producing heavy steel plates which are materially different from PUC.

XIII. JFE Steel Corporation, Nisshin Steel Co., Ltd., Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation and Kobe Steel Ltd. represented by AZB & Partners

- a. DG Safeguards has failed to examine the adequacy and accuracy of evidence in terms of Rule 5(3) of Safeguard Rules.
- b. The DG Safeguards has erred in issuing the preliminary findings in absence of critical circumstances in terms of Article 6 of the Safeguards Agreement and Rule 2(b) of the Safeguards Rules.
- c. Petitioner has not provided any coherent methodology in arriving at the product under consideration. HRC being imported are sued in a variety of downstream industries such as automobiles, home appliances, transportation equipment, fabricated steel products, and construction materials.
- d. There are no manufacturers in India to supply the specific grades of PUC that are exported by the Japanese mills.
- e. HR products exported by the Japanese mills to India differ in chemical composition (content percentage) of components such as carbon, manganese, silicon, boron and phosphorous remedies against impurities, which are tailored to meet the specifications prescribed by the end-user.
- f. Hot-rolled products exported to India satisfy certain OEM required specifications high hole expansion rate, high formability, required tensile strength, conditions of surface, etc., which the domestic industry till date has not been able to produce successfully. The Indian customers rely exclusively on the hot-rolled steel coil supplied by certain Japanese mills, since it is critical for the structural application and no perfectly substitutable product is manufactured by any domestic manufacturer.
- g. The process of selecting an HRC supplier is a long drawn and expensive process and involves many rounds of testing to ensure that the product meets stringent quality standards to ensure reduced weight and high strength of the automobile component. All material sources are decided early during the model development and it is very difficult for an Automotive OEM to switch sources of HRC during the lifetime of the model in order to ensure consistency in the quality of cars manufactured. Therefore, even after imposition of safeguards, automanufacturers will need to continue use of imported HRC directly or indirectly, which will need to continue use of imported HRC directly or indirectly, which will lead to a significant increase in the manufacturing cost of automobiles.
- h. The DG Safeguards has clubbed all grades of hot-rolled coil products into a single PUC. It is not clear from the application and preliminary findings if the PUC excludes hot-rolled coil products which are exported by the Japanese mills but not manufactured by the domestic industry and Petitioners.
- i. There are no unforeseen developments in terms of Article XIX:1(a) of GATT and there are no increased imports in terms of Article 2.1 of the Safeguards Agreement.
- j. There is no serious injury to the domestic industry. There is no decline in production levels of the domestic industry. Market share seems to have declined but such analysis is based on annualisation of data for 2015-16 based on the first quarter, which does not show the correct picture. Market share of domestic industry has declined due to inter-se competition. Captive consumption by Petitioners has increased. There is no decline in productivity and employment, capacity utilisation, profits have increased in 2014-15 when imports have also increased in the same period. The domestic industry is already protected by the high customs duty of 12.5% on HR coils.
- k. There is no causal link in this case. The domestic industry has also failed to identify other factors that may have caused injury.
- 1. The domestic industry is struggling to produce finished steel products with economic efficiency and costeffectiveness due to unavailability and high cost of raw materials. High transportation cost and poor infrastructure is also impacting the domestic industry.
- m. Hot-rolled products are not manufactured in adequate quantities by the domestic industry and imports are necessary for downstream industrial users. Indian producers exported 1.3 million tonnes of HR coils in order to maintain shortages and high prices in the domestic market. Shortage of supply of PUC in the domestic market is evident in the JPC data, which is maintained by the Ministry of Steel. Therefore, safeguard duty will not be in public interest and in particular detrimental to the Indian auto industry. It will also frustrate the aims and objectives of Make in India programme of the Government of India. Safeguard duty will also be detrimental to downstream producers of cold-rolled products.
 - The DG Safeguards may consider applying tariff-rate quotas on HRCs for construction use, as the domestic industry does not produce these products in sufficient quantities.

- a. As a preliminary remark, while the Petitioners provided the volume of imports for the period 2011-2012 to 2014-2015, the Indian authorities, in their notice of initiation, decided to retain an investigation period from 2013-2014 until 2015-2016. AM Brasil highly challenges the investigation period selected by the Indian authorities which also includes 2015-2016 based on annualized data.
- b. In fact, the situation of imports shows a significant decrease from 2011 until 2014: by 13% between 2011-12 and 2012-13, and by 40% between 2012-13 and 2014-15. Between 2011 and 2014, imports decreased by almost 50%.
- c. The decrease in 2013-2014 was followed by a recovery of the imports levels to a level comparable to the level prior to the decrease and can hardly be viewed as "sharp, significant, recent and sudden enough", as such notions were defined by WTO case law.
- d. The way the volume of imports was computed for the most recent period, through annualization based on Q 1 2015-2016 is likely to lead to biased results.
- e. If imports increased (by 14%), it must necessarily be analyzed in conjunction with the evolution rate for consumption (+ 29%)
- f. The (excessive) focus on profit for one quarter of the investigation based on an annual basis is likely to lead to biased results. All the more that all other factors show stability or positive evolutions.
- g. Petitioners lost 5% market share when non petitioners gain 5% market share. It is an indication of a lack of coincidence between alleged injury and imports and that there is in fact an internal competition issue.
- h. While the domestic industry's sales remained stable throughout the period, its captive sales increased by 24%. It is against the demonstration of a serious injury?
- i. There is currently a lack of reasoned and adequate explanations as to the justification for the imposition of safeguard measures in this case
- j. Imports from Brazil must fall within the "developing country" clause
- k. Its imports to its Indian related downstream company must, in any event, be excluded from any safeguard measures, for reasons linked to the public interest, the principle of proportionality (Article 5.1 of the WTO Safeguard agreement), and the need to protect investment

XV. China Steel Corporation

- a. The investigation process followed by the Directorate General (Safeguards) is totally contrary to the instructions given to all the interested parties with regard to filing of responses to the Initiation.
- b. The Directorate General (Safeguards) did not wait for the basic process to complete and in a hasty manner issued its Preliminary findings with thin 3 days of the initiation of the investigation.
- c. Trade Notice SG/TN/1/97 dated 06-09-1997 puts an obligation on the Directorate General (Safeguards) to issue its findings (whether Preliminary or Final) only after due investigation. An investigation is not complete unless all interested parties are given an opportunity to participate.
- d. The Directorate General (Safeguards), being a **Quasi-Judicial Authority** is bound to follow Principles of Natural Justice. The Preliminary Findings issued in the instant Investigation are, however, in gross violation of the **Principles of Natural Justice** as enshrined under the Rules and Trade Notice issued by Directorate
- e. The Domestic Industry had adopted base year as 2011-12 as base year but DG Safeguards has of its own has changed the base year. If DG Safeguards adopted 2011-12 as base year there would not have been any increase in imports rather market share of imports from China in total demand would have shown a decline from 20% to 12%. On the contrary the DG Safeguards has adopted a base year as 2012-13 to show an increase from 6% to 12%. This playing of numbers clearly shows that DG Safeguards has acted in a manner to favour the Domestic Industry.
- f. Domestic Industry has been seeking undue and unwarranted protection from the Government from time to time.
- g. No non-confidential version of the adjustment plan was ever filed by the Domestic Industry.
- h. Article 3(1) of the WTO Agreement on Safeguards requires that the investigation Authority should record its findings as to whether imposition of Safeguard duty will be in public interest or not. The Preliminary Finding is silent on this issue.
- i. Taiwan is widely regarded as a developing country by multiple WTO members and international organizations and hence Imports from Taiwan must fall within the "developing country" clause.
- j. High-strength steels (HSS) used primarily by the Indian automobile industries, including, but not limited to, E34 SS4012A, JSH780RNN-22002OP, SAE 1005M, SAE 1006, SAE 1006M, SAE 1008, SAE 1040, SCM435, SPA-H, SS400, SS490, CUST-S235, JSH590RNN-22002OP, JSH780RNN-22002OP, SAE 1010, SAE 1020, SAPH 440, and SPHC grades, as well as CSC's own standards compatible with the foregoing international standards catering to auto industries should be excluded from the safeguard measure.

- k. A mere 4.35% increase in market share simply cannot be "sharp enough" or "significant enough", and hence cannot constitute a "surge" by any count. ¹ As such, there is no critical circumstance existing whatsoever on the record of this case that justifies the preliminary safeguard duty.
- XVI. **Hyundai Steel Company, Korea:** M/s Hyundai Steel Company, Korea vide their e-mail informed that their earlier submission dated 08.11.2015 (summarized above) may be treated as their final submission in the matter.

Submissions by Importers, Users and Associations

XVII. Mitsui & Co., Ltd./Japan

- a. Mitsui has currently 23 joint ventures in India and one of them is M/s. Indian Steel Corporation (ISC) in Gujarat State.
- b. Currently ISC is suffering from SG duty. SG duty on HRC is at a policy of one-sided and favoring domestic integrated steel mills. The interest of the downstream industries should also be considered properly.
- c. There are certain needs for HRC import from Japan, in terms of demand & supply gap in India HRC, quality difference such as fewer defects, surface quality, higher productivity, size/grade availability.
- d. The ISC does not have enough size to absorb SG duty as integrated mills like Sail, JSW, Tata, etc. and now ISC is facing a serious situation. As such, HRC from Japan for major re-rollers is based on MOU, a kind of long term understanding of supply & purchase.
- e. From foreign investor's point of view or as shareholder of ISC, if favoring HRC or raw material industry through safeguard duty only at the expense of steel user segments or manufacturing, it is hostile environment for growth of manufacturing industries, obstacle for foreign investment and "Make in India" vision.

XVIII. Federation of Industries of India (FII)

- a. HR Coil is a basic raw material consumed by thousands of downstream engineering units in the Country.
- b. 20% Safeguard Duty together with a regular customs duty of 12.5% aggregating to 32.5% on HR Coil, and a lower average of 10% import duty on finished downstream products, would give a fillip to imports of finished goods into India.
- c. The downstream units in India are merely processing the HR Coil to produce CR Coil, GP/GC sheets, Pipes & Tubes, Color Coated Sheets etc.
- d. Safeguard duty imposed on HR Coil without imposing any duty on the downstream products has no meaning and this will finish the value adding downstream Industry in India.

XIX. Nippon Steel & Sumikin Pipe India Co., Ltd.

- a. From a plain reading of Article 2(1) the SGA along with Rule 2 of the SG Rules, it is clear that safeguard measures cannot be imposed on imports that are not <u>identical or alike in all respects</u> to the products produced by the domestic industry.
- b. The Hot Rolled Coils (HRCs) imported by NPI must be excluded from the scope of the PUC as they are not 'like or directly competitive article' to the products manufactured by the Domestic Industry.
- c. NPI imports very specific types of HRCs to make automotive pipes and tubes required by its customers in India.
- d. HRC produced by the DI differ in chemical composition from HRC's imported by NPI
- e. HRC's produced by the DI differ in quality from those imported by NPI
- f. NPI imports HRCs for use in manufacture of automotive pipes that Indian domestic steel manufacturers (i) are unable to supply HRCs of sufficient quality or (ii) have not obtained the approval from the ultimate end users (i.e., the automobile manufacturers).
- g. NPI is unable to use HRCs produced by the Domestic Industry because the Domestic Industry has not secured industrial user approval for their products.

XX. Cold Rolled Steel Manufacturers Association in India (CORSMA)

- a. D.G. Safeguards in his Report dated 09th September 2015 while recommending the imposition of Provisional duty of 20% on the imports of HR Coils has based his decision on the data for <u>only two and a half years in violation of norms.</u>
- b. A casual <u>scrutiny of the data</u> in <u>the Petition</u> regarding production, exports, imports and inventories of HR Coils shall reveal that has been <u>manipulated to confuse</u> the issue by dividing the data in to <u>groups and subgroups</u> and <u>expressing the variations in percentages</u> rather than actual figures.

¹ See Appellate Body Reports, Argentina — Footwear (EC), paragraph 131.

- c. No <u>analysis has been done to identify the reasons for the variations</u> for <u>remedial action</u> for a <u>rational decision on</u> the Petition by the Govt.
- d. The statement made by the Petitioners in <u>regarding surge</u> in imports in April-July 2015 is entirely <u>misleading</u> and as it does not indicated reasons for rise in imports in April-July 2015 y.o.y., simple analysis shall reveal that <u>imports rose</u> from <u>4.71 lakh</u> tonnes in April-July 2014 to <u>1.144 million tonnes in April-July 2015 by 6,73,000</u> tonnes due to <u>decline in domestic production</u> and rise in consumption
- e. The Petitioners have alleged that the <u>domestic producers have suffered an injury</u> due to rise in <u>inventories</u> due the high imports but <u>as per data published by JPC there has been no rise in inventories.</u>
- f. The Petitioners have held that there has <u>been loss in profitability</u> due to imports <u>but</u> it is not tenable as per the JPC data.
- g. It has been held by some producers that the high prices of HR Coils in India are due to high cost of power, interest rates and Land. It may be clarified that most of the Petitioners have their own captive Power Plants and the issue is the high Power consumption per tonne of Steel by around 30% vis a vis the global standards which needs reduction.
- h. The imports of <u>Hot Rolled Coil were essential</u>, <u>diversified and at global prices</u> to bridge the gap between the domestic availability and production <u>both in terms of quantity and quality</u>.
- i. The rise in imports in the <u>first quarter of 2015-16 was due to the facts that</u> while the domestic consumption of <u>HR Coils increased by 3,62,000</u>, the production declined by 2,63,000 resulting in <u>higher imports</u>.
- j. The imports were at global prices in line with the Indian producer exported over 1 million tonne of HR Coil in 2014-15 and 2 lakh 30 thousand tonne in April-Sept 2015-16.
- k. The Hot Rolled Coil producer have been <u>making high profits</u> in <u>the past five years by fixing</u> the domestic prices on <u>landed cost basis and losses</u> incurred by <u>some of them</u> may be <u>directly attributed to indiscreet investments</u> in India and <u>abroad</u> in Steel and other industries incurring debt and interest burden.
- 1. The financial performance should be improved by sale of stake as held by RBI rather than destabilize the industrial and economic growth of the country by <u>blocking Steel imports and monopolistic pricing by the domestic producer</u>.
- m. The imposition of Provisional <u>Safeguard duty on the imports of HR Coils has also led to inverted duty structure as while</u> be total import duty on HR Coil the <u>intermediate product</u> amounts to <u>32.5%</u>, the duty on the finished <u>Cold Rolled products</u> is <u>only 12.5% and lead</u> to <u>heavy imports of value added Cold Rolled products hitting the domestic industry.</u>

XXI. Tubes Limited & Nezone Strips Limited

- a. They produce Black Pipes, Rectangular & Square Hollow Sections and Galvanised Pipes at their plant located at Dankuni, Hooghly, West Bengal and Ranipet, Vellore, Tamilnadu.
- b. They opened the L/C on 21/07/2015. The last date of shipment in the aforementioned Contract and L/C was 30/09/2015 and the material was shipped on 29/09/2015 and 20% Safeguard Duty was imposed on 14/09/2015.
- c. This imposition resulted in huge unforeseen cost to them which is threatening their existence.
- d. All integrated plants also produces downstream products and capitally consume H.R. Coil as Raw material, hence are not in a position to supply H.R. Coil to the standalone downstream industries like them who consume H.R. Coil as Raw material.
- e. The other domestic industries i.e. SME like NTL will have to compete with integrated plants paying 20% Safeguard Duty & 12.5% Custom Duty to the exchequer.
- f. The export of downstream product will be impossible by SME Industries as the prices of H.R. Coil, their Raw material will be arbitrarily hiked by effect of the Safeguard Duty.
- g. Levy of Safeguard Duty on H.R. Coils having width more than 600mm will encourage import of sub-standard H.R. Strips having width less than 600mm.
- h. Safeguard Duty will also encourage import long products like billets etc. for Re-rollers which in turn again suffers with the quality issues.
- i. The demand for H.R. Coil in India will diminish as all downstream products will be imported and thus defeating the very purpose of Safeguard Duty of protecting domestic industries.

XXII. POSCO, Korea & POSCO Steel, Maharashtara

a. A significant percentage of the PUC (almost 90%) has been imported for use exclusively by POSCO Maharashtra from POSCO Korea, as raw materials or their downstream product. Therefore, 90% of the said import of PUC is captively consumed by POSCO and does not compete with like goods in domestic market in India.

- b. The volume of imports which is captively consumed must be excluded from the total volume of imports so as to depict a true picture of the volume of imports competing directly in the market and to enable us to compare data fairly.
- c. Authority has included captive consumption of PUC by the domestic industry and domestic industry supporters for deriving the total demand of PUC in the market, they have excluded the captive consumption of domestic industry while calculating its % market share in domestic market.
- d. However, at the same, no such method has been adopted for calculation of % market share of imports as the volume of imports captively consumed (which is a major proportion) has been considered for calculating the % market share of imports in domestic market.
- e. Market share of other producers have increased from 25% (2011-12) to 31% (2014-15). The market share which is alleged to have been lost by the Petitioners, has been taken up by other producers, and quite evidently, has not been captured by imports.
- f. The surface quality of the PUC supplied by the DI cannot be used and is often rejected due to the low quality.
- g. The exact grade of the PUC which do not meet the quality requirements have been tabulated and are enclosed with submission as **Exhibit V.**
- h. Reasons for alleged decrease in sales of domestic industry are due to: (a) underutilization; (b) high debt/finance cost (being a capital intensive industry); (c) PUC when exported by DI are those prevalent in the global market; (d) PUC when sold by DI in domestic market is much higher than the global/international prices.
- i. The analysis of injury has been done on the basis of first quarter of 2015-which is not a correct method for injury analysis and a significantly long period of time must be considered for this purpose.
- j. A news article dated 05.06.2015, published by Business Standard and uploaded on JSW's website clearly states that JSW has had a 75% increase in net profits while SAIL saw a 24% dip in profits which was attributable to high finance costs.
- k. Safeguard duty imposition in direct contravention of India-Korea Partnership Agreement ("CEPA") signed in 2009, where India has undertaken to bring down duty to zero on PUC.
- 1. There is no causal link between alleged surge in imports and injury suffered by DI.

XXIII. V.K Industrial Corporation Limited

- a. The company is an importer and stocks flat steel products.
- b. Capacity utilization of domestic steel firms is 76% which is higher than the world average of 72.86%. There has been no decline in the capacity utilization.
- c. Production of domestic steel firms has increased proportionately to the increase in capacity.
- d. There have been no job losses in 2014-15 but instead it has increased by 0.2%
- e. There has been hardly any market loss for domestic manufacturers. Three year average of market share of importers was 9% which increased to 10% in 2014-15. The 1% increase cannot be considered as causing injury.
- f. Prices of hot rolled coils have plummeted globally over the last year. Reason for the decline is fall in prices of iron and coal which are the most important raw material required for steel production. Iron ore prices fell by 41% and coal by 21% in 2014-15.
- g. Domestic producers are facing high costs compared to their global counterparts due to the following reasons:
 - i. High freight costs as logistics costs in India are very high. Global steel producers are located near the shore which reduces their costs.
 - ii. The ban on iron ore mines in India has reduced iron ore production as a result the decline in iron ore prices in India was minimal. Not all domestic producers have captive iron ore mines and even those that have captive ore mines have higher costs due to royalties, duties and higher pricing bids.
 - iii. Capital costs in India are very high in comparison to countries like China.
- h. The safeguard measure will protect the domestic industry only temporarily and not strengthen the industry permanently.
- i. Domestic producers are earning profits and sustain high turnovers. The World Steel Association reported that India had a 2.8% growth in steel output while world steel production fell by 3% in 2014-15.
- j. Imports are a lifeline to SMEs that are trying to compete with MNCs. The imposition of the safeguard duty has put the supply chain partners in deep losses.

- k. India thrives on exports of capital goods and steel is one of the main raw materials for production of these capital goods. Exporters of these products will therefore face very high production costs and become incompetent. Imposition of safeguard measures on steel will reduce capital goods export by 25% and increase costs by 15% compared to global competitors.
- 1. The safeguard duty has disappointed many foreign investors and puts India's relationship with Korea in jeopardy. Therefore, foreign investment will decrease in India.
- m. Imposition of safeguard duties will increase the costs to engineering firms in India by 33-35%. Therefore, importing the capital good will make for economic sense rather than manufacturing the same.

XXIV. Hyundai Motor India Limited

- a. It will be retrograde step if safeguard duty is imposed on raw materials like HR coils of steel, since it will raise the prices of passenger cards and make them unsalable in India as well as international markets and our exports will further come down.
- b. Most passenger car companies import Automotive Grade HR Coils for quality reasons, since the imported steel is required to have a delicate balance of "High Tensile Strength" and "Formability" (or ability to take shape). We will continue to import this grade, as safeguard duty will not be an incentive to us to shift our purchases from foreign sources to Indian mill makers.
- c. Automotive Grade Steel is imported at USD 600 USD 700 per ton and there is absolutely no logic to further raise this price by imposing safeguard duty.
- d. Customs duties are about to approach zero under India-Korea CEPA, and in anticipation of this, Korean companies have lot of investments in India. It will be unfair to now impose a 20% safeguard duty on Korean firms, which are importing in the price range of USD 600 USD 700 per ton.
- e. Korean Automotive Grade Steel imported by car manufacturers' OEM should be excluded from the scope of the investigation. If this is not possible, the Authority may fix a reference price of USD 450 USD 500 per ton so that all imports above this price will be exempted from payment of safeguard duty. This will protect domestic industry without affecting genuine importers of high quality material and export volumes.

XXV. Manaksia Steels Limited

Manaksia Steels Limited is an importer of the subject goods in India. They have made the following submissions:

- a. The imposition of Safeguard Duty is forcing the Industry to shut down their operations as the Product under Consideration is one of the major raw material for their finished products.
- b. Landed cost of our raw material "Hot Rolled Steel Coils" is higher than the landed cost of imported "Colled Rolled Steel Coils", which is our finished product.
- c. Due to imposition of Safeguard Duty the import price of Pre-painted Galvanised Coils is less than the imported Hot Rolled Steel Coils as raw material.
- d. The imposition of Safeguard Duty is against the concept of "Make in India".

XXVI. Maruti Suzuki India Limited

- a. The Preliminary Finding was issued by the DG Safeguard within 2 days of initiation of Investigation, without providing an opportunity of being heard to the importers, exporters and other interested parties. There by violating the Principles of Natural Justice. The Authority has issued the preliminary finding in hustle. They have relied upon:
 - Siemens Engineering & Manufacturing Co of India Ltd. v. Union of India &Anr. [1976] Suppl. S. C.R 489.
 - C.B Gautam V. Union of India (1993) 1 SC 78,
 - Swadeshi Cotton Mills vs. Union of India 1981 SCR (2) 533,
 - Automotive Tyre Manufacturers vs The Designated Authority &Ors. 2011-TIOL-03-SC-CUS.
- b. The Directorate General of Safeguard in the present case was appointed on September 7, 2015. The reliance was placed on in Automotive Tyre Manufacturers vs The Designated Authority & Ors. Where-by it was stated that the new designated authority should have provided a separate hearing.
- c. India being member of Comprehensive Economic Partnership Agreement needs to abide by Article 23 of the FTA. Which states that India needs to follow certain specific guidelines in case of safeguard investigations initiated under FTA. FTA provides for a different regime for the initiation of bilateral safeguard measures with additional mandatory requirements to be complied with. The Authority has completely ignored the provisions of FTA in relation to bilateral safeguards and the special conditions and procedure set out therein.
- d. In the present case no intimation has been provided to the Embassy/ Government of Japan regarding the initiation of the investigation proceeding regarding the import of the product under Consideration from Japan. The act of issuing a Preliminary Finding by the Authority, without providing any intimation or information to the Embassy/ Government of Japan, is an act of clear defiance of the provisions of the FTA. The reliance was placed on

- US- Underwear, Appellate Body Report, US-Underwear, where it was held that prior publication of a measure, as required under Article- X of GATT, could not in and of itself, justify the retroactive effects of applying import quotas with respect to imports during a period starting before the quota's publication date.
- e. No methodology for determination of the product under Consideration as the subject product for imposition of safeguard Duty on the import of the Product under consideration. The transaction wise import data made available by the petitioner has various discrepancies and at various instances proper gradation and series identification with respect to the imported product has not been done by the petitioner. Therefore certain products identified by the petitioner in the petition and thereafter relied upon by the Authority in the Preliminary Finding for the import data are not correct and fall outside the scope of Product under Consideration.
- f. In the past also the Designated Authority in Anti-dumping investigation had excluded certain Colled Rolled Steel Products imported from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand and USA, from the scope of investigation for the reason that those were not considered to be like article within the meaning of the Safeguard Rules.
- g. In the instant case, the petitioner has sought inclusion of all grades including such grades which were specifically excluded and were not considered 'like product' within the scope of the product under consideration.
- h. DGCI &S should be consulted to corroborate and authenticate the import data of the Product under Consideration as provided by the Petitioner.
- i. The Authority has nowhere recorded the Product under Consideration with that of the products imported by the imported by the importers on the touchstone of the definition of "like product" as provided in the Rule 2 (e) of the safeguard Rules.
 - The Product from Korea and Japan is not like article in terms of the Rule 2(e) of the safeguard Rule and thus different from the product manufactured by the domestic producers. Product under Consideration imported by the Respondent from Japan and Korea are of superior quality.
 - The need for the import of Product under Consideration from Japan is because of the incapacity of the Domestic Producers to supply the high quality of products as required by Respondent. The Authority should exclude such imported goods that are not being manufactured by the Petitioners. Reliance has been placed on Hon'ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in Magnet Users Association vs. Designated Authority [2003 (157) ELT 150 (Tri-Del)], wherein was held that there is no justification in including those grades that are not manufactured in India.
 - The Product under Consideration are heterogeneous set of products imported and thus they cannot be included in the same grade for comparison with the products manufactured by the domestic producers/ petitioners. The reliance is placed upon Panel Report issued by WTO in DS 427- China- Anti Dumping and Countervailing Duty Measures on Broiler Products from the United States.
 - The inclusion of the non- furnished Product under Consideration by the Authority is unjustified and not required as these products are imported in different volumes and are differently priced.
- j. The Respondent is purchaser of steel products from
 - JSW Steel Limited,
 - Essar Steel Limited,
 - Bhushan Steel Limited.
 - Tata Steel Limited
 - Hero Steel Limited.
- k. 93% of the total raw material and components consumed by the Respondent have been procured from the above-named domestic producers, which also include two Petitioners. It is only the remaining 7% of the special kind of steel, the demand of which is not fulfilled by the Domestic industry, is imported from Japan and Korea by the respondent. Indian products are different from the products that are manufactured from these countries:
 - Imported products are manufactured by Japanese Industrial Standards,
 - Includes better making standard, chemical composition, Categorization, Tensile strength, draw ability and wend ability of the Product.
 - Indian products have no mention of Hole Expansion Role
 - There is difference in quality level (formability, crack generation during rolling etc) for different steel makers for the same grade.
 - The respondent being one of the largest producers and manufacturers of the Automobiles, the levels of quality for automotive application is a major concern for it in order to avoid any commercial problems and complications.
 - The product imported is manufactured by way of patented state of the Art technology and the same has distinct characteristics.
- The Petitioner have claimed excessive confidentiality and sufficient information is not supplied by them in order
 to determine the manufacturing, production and sales of the Domestic market. The petitioners did not provide any

- reasons for claiming the confidentiality on the information provided to the Authority. The Respondent have relied upon Sterlite Industries (India) Ltd. vs Designated Authority.
- m. The importers and the interested parties were not intimated by the Authority about the development regarding the examination and corroboration of the information provided by the Domestic Producers. Without corroborating the evidence produced by the Domestic Producers, the Authority heavily relied on the said information and recommended imposition of Safeguard Duty at a whopping rate of 20%.
- n. The Authority did not disclose the methodology adopted to determine the level of safeguard Duty recommended by the Authority. The Authority did not follow the principle laid down in Article XIX of GATT 1994. The initiation notice was silent on the unforeseen development that have led to increase of imports of Product under Consideration. The petitioner also failed to show factual or legal basis to demonstrate that unforeseen development exist in the present matter.
- o. There has been miniscule increase in the import data as provided in the petition. No justification provided to show on which petitioners have annualised the imports for the entire year of 2015. There is gradual increase in the imports of the Product under Consideration and there is no "sharp", significant or "sudden" increase in imports..
- p. The increased import n Product under Consideration has no impact on the domestic production of the goods. The Authority at para 25(a) of the Preliminary Finding has recommended that the production of the Domestic Producers have remained at the same level. The Authority has not substantiated as to what are the critical circumstances to warrant an issue of Preliminary Finding. The Authority has acted in contravention principles of safeguard investigation.
- q. No evidence provided by Petitioner to show serious injury. The Authroity has ignored in the Preliminary Finding that the requirement under Safeguard Rule is to initiate investigation only when there is "sufficient evidence" to suggest that the increased imports of the product has caused an injury to the Domestic Producers.
- r. The Authority has acted in contravention of Paragraph 1 and 2 of the Annexure to the Safeguard Rules. The Respondent relied upon the Appellate Body Report on US- Cotton Yarn. Following submissions are made based on the case sited:
 - Petition does not show any injury whatsoever.
 - Petitioners has fared consistently well in terms of production, domestic sales and total sales and profitability.
 - The methodology prescribed for segregating capacity for the Product under Consideration from total Capacity is still unclear.
 - Essar Steel India Limited has made complete Turn around and earned profits from operations.

Particulars	FY 2014-2015 (Rs – Crores)	FY 2013-2014 (Rs- Crores)
Gross Revenue	19,258.50	16,286.59
Net Revenue	17,162.39	14,348.55
Profit/(Loss) before exceptional	334.29	(3,916.21)
items and taxation		
Profit/(Loss) before Taxation	1,008.96	(2,314.74)
Earnings per share (diluted)	Rs. 2.26	Rs. (5.70)

JSW Profitability have increased.

Particular	FY 2014-2015 (Rs- Crores)	FY 2013-2014 (Rs- Crores)	Growth %
	(NS- CIUIES)	(RS- Clules)	
Gross Turnover	49,658	48,527	2%
Net turnover	45,352	44,529	2%
Operating EBIDTA	8,872	8,783	1%
PAT	2,166	1,335	62%
Earnings per share (diluted)	Rs. 88.24	Rs. 53.86	64%

- SAIL has been consistently making profits.
- Price Underselling, depression and suppression data has not been indicated in detailed from in the NCV
 of the petition filed by the Petitioner.
- There is no change in the capacity utilization of the Domestic Producers as per Para 25 (d) of the Preliminary Finding.
- The Authority in preliminary Finding has also not pointed out any possibility of likelihood of a sudden decline in the capacity utilisation of the Domestic producers.

- The Authority has not corroborated any piece of information provided by the Petitioner and has without any recording any reasons assumed a prima facie case and initiated the investigation process.
- The safeguard duty will have cascading effect on the overall prices of vehicles and parts on the automobile industry.
- s. A number of automobile companies and OEMs are extensive importers of the subject products, and levy of any safeguard duty will affect the business interest of the said importers substantially. Safeguard Duty will be inconsistent with fiscal incentives introduced by the Government of India for improving the ailing health of the Automobile Industry.

XXVII. Tube Investments of India (TII)

- a. Some of the grades used in automotive applications are imported for reasons such as customer approved source, customer preference, consistent quality, limited availability etc. The following grades must be exempted:
 - i) SAE 1541
 - ii) SAE 1020/1040/1045/1050/1055
 - iii) SCM 435
 - iv) Boron Steel
 - v) 16 MnCr5
 - vi) SAE 1006/1010
 - vii) ST 52.3
- b. Floor price mechanism should be implemented to control cheaper imports.
- c. CR/CRCA should also be included along with HR for effecting safeguard duty.
- d. Quantity of subject goods already contracted as on the date of implementation of provisional safeguard duty should be excluded.

XXVIII. Bombay Iron Merchants Association (BIMA) represented by M/s. MV Kini Law Firm

- a. Imports undertaken with respect of each of the products have to be confirmed to see any surge as alleged. Products of different nature and statistics have been subjected to similar analysis. Segregation of products combined by the Applicants is imperative because alloy steel production capabilities of the Applicants are negligible.
- b. The problems faced by the Applicants is not related due to increased imports but due to high debts, oppression and mismanagement issues in case of Bhushan Steel, problems in procurement of raw materials in case of Essar Steel.
- c. The Applicants kept the domestic prices much higher and increased exports at globally competitive prices. Applicants have decreased their export prices by almost 35% against a mere 4% decrease in domestic prices.
- d. Surge in imports in 2014-15 relates to import by POSCO (approx. 1 million tonnes) in 2014 to set up its plant in Maharashtra. If this import by POSCO is excluded, it would rather show a slump in imports.
- e. Major Applicants have shown a rise in sales turnover. Sales figures of JSW Steel Ltd. show an increase of about 29% from 2012-13 to 2014-15. The sales figures of SAIL also show a stable trend.
- f. The financial statements show that instead of an alleged drop in wages and salaries, there is a consistent increase in employment costs of the Applicants.
- g. Imports under Advance License that are used in the manufacturing of finished goods for exports must be excluded from the import figures as they do not come into the domestic market at all and could not impact the Indian domestic market.
- h. Authenticity of the IBIS data relied by the Applicants is questionable as it reflects inflated figures when compared with the JPC data.
- i. Prices of major raw materials have dropped between 40-60% and the selling prices of the subject goods must be adjusted accordingly.
- j. Comparison with trade measures by countries like Thailand and Malaysia is unsustainable and misleading as the surge in imports and other parameters were very critical in those countries.
- k. Applicants are themselves importing cheaper raw material as well as the PUC. The alleged surge in imports during July- September 2015 is on account of huge imports of the subject PUC by the applicants specifically JSW Steel Ltd.
- Undue haste has been shown in the imposition of safeguard duty without even consulting a cross section of the stakeholders.

XXIX. Federation of Associations of Maharashtra (FAM)

In addition to the contentions already raised by FAM in their pre-hearing submissions, FAM stressed on the following contentions:

- e. The steel sector is facing excessive debts and losses due to such factors are not attributable to import prices of steel in India.
- f. Quantities imported under advance authorisation cannot injure the Applicants.
- g. There has been undue haste in imposition of provisional safeguard duty in this case.

- h. The PUC only accounts for 9% of the capacity of the applicants.
- i. JPC is an officially empowered agency in India for the collection and maintenance of data, by the Ministry of Steel. There is deviation in JPC data and IBIS data relied upon in the application.
- j. It has been alleged that there has been a surge in imports, drastic drop in sales turnover, decline in capacity utilization, consistent losses and reduction in employment levels which are clear indicators of injury. All these basic parameters are missing altogether in the present case of the applicants.

Alleged surge in imports ('000 tonnes)

Particulars	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Imports (as per JPC)	1812	1871	1104	2006
Indexed	100	103	60	109

As per JPC data, the increase over the period of 4 years (which is a more logical period for a trend analysis) is only about 9%. While alleging surge in imports in 2014-15 over the period of 2013-14, a due thought has not been given to the fact that there was an abnormal drop of roughly 40% in the earlier year mainly due to the unprecedented dollar volatility during that period.

Moreover, the applicants took the advantage of this dollar volatility and increased imports and hence keeping domestic prices much higher at the cost of the Indian consumer.

- k. While alleging surge in imports in 2014-15 over the period of 2013-14, a due thought has not been given to the fact that there was an abnormal drop of roughly 40% mainly due to the unprecedented dollar volatility during that period. Interestingly, the applicants took the advantage of this dollar volatility and increased exports at globally competitive prices whereas kept domestic prices much higher at the expense of the Indian consumers and infrastructure development in India and on the other hand, making windfall profits for themselves. The same is evident from JPC data.
- The subject goods which are used as raw materials for certain re-roller mills such as POSCO, Uttam Steel,
 National Steels, Asian Color Coated etc. it needs to be noted that PUC is a raw material and not a product for
 trade. In such cases, PUC is further worked upon and converted into cold rolled sheets / galvanized sheets /
 corrugated sheets etc. POSCO alone had imported around 0.95 million tonnes of the subject goods for this
 purpose between the period of May 2014 to September 2015 for their own Steel Plant in Maharashtra.
- m. It is submitted that, if these imports as well as the quantity of imports attributable to other cold roller mills is removed from the total import figures as produced by the applicants, there is actually the decline in the imports of the subject goods in India over this period. In fact, local plants have declined POSCO to provide the subject goods due to their own inability to produce the required quality and quantity of those goods. The quantum of such imports of raw material may be around 35-40% of the total imports of PUC in India.
- n. The applicants have argued that the countries like Thailand and Malaysia had also taken recourse to these tariff barriers by imposing the safeguard and anti-dumping duties respectively. However, it is hereby submitted that the scenario of surge in imports and other parameters have been very critical at that point in time in those countries. These could not be in any manner comparable to present situation in India.
- o. The pre-requisites as prescribed under the Safeguard Rules does not exist and as such there is no significant overall impairment of domestic industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the product concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by the increased imports, changes in the levels of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses and employment, none of these is adversely affected as misrepresented by the Applicants.
- p. The Applicants have not excluded the imports on account of captive consumption which needs to be excluded for the computation of total imports. The Applicants have not excluded the imports under advance authorizations i.e. imports for exports which needs to be excluded for computation of total imports. There is no nexus between the imposition of safeguard duty in the absence of any emergency and the objective to be achieved by such imposition.

D. REJOINDER SUBMISSIONS

I. Rejoinder by Domestic Industry to the submissions of Interested Parties post public hearing

All contentions raised by Petitioners in their petition, written submissions and during the course of this investigation effectively rebut all the contentions raised by interested parties in their written submissions. All contentions raised by Petitioners in their petition, written submissions and during the course of this investigation should be deemed as part and parcel of this rejoinder and such contentions which are not repeated in the present submissions for the sake of brevity should not be held in prejudice to Petitioners. For all other issues raised by other interested parties, Petitioners provide their rejoinders below:

- a. Imports from developing countries that are below 3% should not be subject to safeguard duty:
 - Many interested parties have argued that developing countries whose respective imports do not exceed 3% and aggregate of imports from such countries do not exceed 9% should be kept outside the purview of safeguard duty. It is also argued that imports from Brazil and Taiwan meet the above requirement and should be outside the purview of safeguard duty. With respect to the contention concerning Taiwan, Petitioners have already addressed this contention in the specific rejoinder to the Embassy of Taiwan. However, Petitioners reiterate their contention here briefly. It is understood that a list of developing countries has been issued by the Government of India vide Notification No. 103/98-Cus dated 14 December 1998. It is pertinent to note that Taiwan's name does not feature in this list. Therefore, even if for the sake argument it is accepted that imports from Taiwan are below 3% and aggregate of imports from developing countries does not exceed 9%, Taiwan can still not be excluded from the purview of safeguard duty, as it is not recognised as a developing country by Government of India as of today. Therefore, the contention with respect to exclusion of Taiwan from the purview of safeguard duty cannot be accepted in light of the Notification No. 103/98-Cus dated 14 December 1998 issued by the Government of India. Further, we understand from perusal of import data that imports from Brazil constitute more than 3% in total imports. Therefore, the contention that Brazil should not be subject to safeguard duty cannot be accepted either.
- No increase in imports within the meaning of Article XIX of GATT and Agreement on Safeguards ("SA"): Many interested parties have argued that imports of the subject goods are not sudden enough, sharp enough, significant enough and recent enough within the meaning of Article XIX of GATT and SA. Therefore, safeguard duty is not warranted in this case. Petitioners wholly object to this contention. Petitioners submit that the data on record clearly demonstrates that imports of the subject goods have rapidly increased during the injury analysis period. In fact, imports were 7% in production of the domestic industry in 2013-14, which doubled to 14% in 2014-15. This situation has become more severe in 2015-16, where imports were 19% in production of the domestic industry during Q1 of 2015-16. During Q2 of 2015-16 imports further increased to 31% in production of the domestic industry. Further, imports were 9% in demand (excluding captive) in 2013-14, which increased to 16% in 2014-15. This has further aggravated in 2015-16, where in Q1 of 2015-16, imports were 19% in demand (excluding captive), which has now sharply increased to 24% in Q2 of 2015-16. If this does not qualify as a sudden, sharp, significant and recent increase in imports, then Petitioners do not know what else would constitute as a sudden surge in imports. The domestic industry is facing an emergency situation. Imports of the subject goods in the first two quarters of 2015-16 have already peaked and based on the available data, it is expected that imports during 2015-16 will exceed 2014-15 levels. Based on the data available for first two quarters of 2015-16, imports of the subject goods are expected to be 4,167,884 MT on annualised basis, which exhibits a 160% increased from 2014-15 levels when imports were 2,540,114 MT. Imports are already coming at significantly low prices causing price undercutting, price underselling, price suppression and depression. Imposition of safeguard duty alone can address the domestic industry's situation.
- c. Source of import data, methodology adopted in sorting import statistics and accuracy of information:

 Many interested parties have argued that import data from a private agency like IBIS is not authentic and tenable and the Authority should consider only JPC data. Interested parties further argue that a detailed methodology for determining product under consideration is not provided in the petition. Interested parties also argue that DGCI&S data should be used to verify the authenticity of IBIS data used in the petition. Interested parties further argue that certain imports fall outside the purview of the product scope. Petitioners object to all the contentions above. It is submitted that IBIS is a renowned agency and its data is regularly used in many trade remedy investigations, be it safeguards or anti-dumping investigations. Further, it is standard practice for the Authority to procure DGCI&S data and compare the data with IBIS data to verify authenticity of the information. The Authority has the discretion to use IBIS or DGCI&S data. Further, Petitioners submit that JPC data cannot be used in this investigation because this data is only available at a broader level for the steel sector and not at PUC level, which is relevant for the purpose of this investigation. Further, interested parties have failed to clarify what kind of imports fall outside the scope of the product under consideration. Such a claim is too vague and cannot be accepted. At least interested parties could have provided the grades or specification of imports which they are concerned with. In absence of such information, such vague claims by interested parties should be rejected.
- d. Excess confidentiality claimed by domestic industry:

Many interested parties have complained that several parameters have been considered as confidential in the petition and no reasons have been provided by the domestic industry for treating them as confidential. Interested parties further argue that even the Authority has not recorded any reasons for granting confidentiality in the preliminary findings. Petitioners strongly object to the above contentions. Petitioners submit that they have exercised due caution while claiming confidentiality in the petition and have considered only such information as confidential disclosure of which could adversely affect the interest of Petitioners. Further, Petitioners have duly provided reasons for claiming confidentiality in the petition. Interested parties wrongly contend that the Authority

has not provided any reasons in the preliminary findings while granting the domestic industry's confidentiality claims. In this regard, Petitioners rely on the following extract from the preliminary findings:

11. The domestic industry has provided some information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted. The domestic industry provided non confidential version of the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dt. 06.09.1997. Further the domestic industry has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application.

12. Rule 7 of the Safeguards Rules, 1997 and Art. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards also provide for confidentiality. The applicant is not required to disclose such information which is confidential information of the company, disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of the company, which is not in public domain and which the applicant has not disclosed before public at large in the past. Accordingly confidentiality, as prayed for by the domestic industry, is granted. (emphasis supplied)

The Authority has clearly observed that Petitioners are not required to disclose such information, disclosure of which would cause serious prejudice to business interests of the domestic industry. In this regard, the Authority has adhered to Rule 7 of the Safeguard Duty Rules read with Article 3.2 of the SA to demonstrate compliance with the legal requirements. In accordance with the above, the Authority has granted confidentiality claims of Petitioners. Therefore, interested parties are wrong in arguing that the Authority has not provided any reasons while granting confidentiality claims of Petitioners.

e. <u>Deficiencies in the petition:</u>

Several interested parties argue that no additional questionnaire was filed by the constituents of the domestic industry. Therefore, the Authority did not have complete information when preliminary findings were issued. Interested parties further argue that no creditable adjustment plan has been provided by the domestic industry and there is no mention of the same in the preliminary findings. Petitioners strongly object to the above contentions. It is submitted that Petitioners had filed their respective questionnaire responses in both confidential and non-confidential versions along with the petition itself. Non-confidential versions of the questionnaire responses were also available in the public file. If interested parties failed to collect the questionnaire responses from the public file, then it shows negligence on their part. Further, all constituents of the domestic industry had provided a proper adjustment plan in their respective questionnaire responses. The Authority had also satisfied itself of the workability of the adjustment plan during the verification visits to the constituents of the domestic industry. Merely because, certain analysis on adjustment plan is not given in the preliminary findings, it does not mean that Petitioners had not provided such information to the Authority. Therefore, contentions by interested parties on deficiencies in the petition are unfounded and should be rejected.

f. Standing of domestic industry:

Interested parties argue that Petitioners do not qualify as domestic industry in this case. Interested parties rely on the table given under paragraph 25(b) of the preliminary findings and argue that market share of the domestic industry was 45% in 2013-14 and for Indian other producers, it was 51%. Similarly, it is argued that in 2014-15 as well as 2015-16 (Annualised), market share of other producers was 51%. Petitioners strongly object to this contention and submit that interested parties cannot be more wrong in advancing this contention. In the table under paragraph 25(b), market share given is a ratio of sales of domestic industry vis-à-vis domestic demand. However, this market share is not a measure of standing. Standing has to be determined in terms of Section 8B(6) of the Customs Tariff Act, 1975, which defines domestic industry as follows:

- "domestic industry" means the producers
- (i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India, or
- (ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.

In terms of the above definition, Petitioners' production was 70% in total production during 2013-14, 68% in 2014-15 and 67% in Q1 of 2015-16. Thus, Petitioners clearly qualify as domestic industry in this case. Contentions of interested parties on standing of domestic industry are, thus, incorrect and should be rejected outright.

g. Imports by domestic industry:

Interested parties argue that surge in imports during Q2 of 2015-16 is because the domestic industry, specifically M/s JSW Steel Ltd. had imported huge quantities of the subject goods during this period. Petitioners strongly object to this contention and submit that interested parties are simply making baseless arguments. Petitioners

have provided their data to the Authority, which has also been duly verified. Imports by the domestic industry were miniscule during the injury analysis period, which fact is also supported by their data on record. Such miniscule imports were only for internal consumption and not for sales in open market. Therefore, the above contentions of interested parties are incorrect and should be rejected.

h. Scope of the product under consideration:

Several interested parties have raised issues on the product under consideration. All such issues are addressed below:

- i. HR Coil in thickness 2.00 mm and below: M/s Nezone Strips Ltd. and M/s Nezone Tube Ltd. argued that they have been importing HR coil in thickness 2.00 mm and below because their regular supplier M/s Tata Steel Ltd. had stopped supplying due to availability constraints. Therefore, they are forced to import this specific product and such products should be excluded from the product scope. Petitioners strongly object to this contention and submit that both companies could have approached any other producer in India who would have easily supplied such material of thin gauge to them. Merely because one Indian manufacturer is not supplying to these companies, it cannot be a ground for exclusion of these products. Requirements of both the companies can be conveniently served by Indian steel manufacturers including Petitioners. Therefore, this specific product cannot be excluded from the product scope.
- ii. Automotive Grade of HR Coils: M/s Hyundai Motors India Ltd. argues that Korean Automotive Grade Steel should be exempted from safeguard duty as even after imposition of safeguard duty, they will have to necessarily import this product. They further argue that their Nanyang R&D Centre does not allow them to change the specifications for the cars manufactured in India. Therefore, they will have to import this grade. Petitioners object to the contention and submit that M/s Hyundai Motors India Ltd. have failed to identify the specific grade which they import. Automotive Grade of HR Coils is a very generic description and cannot be excluded unless they substantiate that Indian steel producers cannot supply this grade. Just because their R&D centre will not allow them to procure from elsewhere does not mean that the domestic industry should be allowed to suffer serious injury by exempting imports of this grade from safeguard duty. It is requested that M/s Hyundai Motors India Ltd. may be directed to specify the grade, along with chemical as well as physical parameters, for which they wish to claim exemption for subject to mutual discussion with the domestic industry. If this information is not provided, their claim cannot be accepted. Petitioners further submit that they are already on the approved vendor list of several automobile makers, their vendors and auto component manufacturers. A list of such automobile makers, their vendors and auto component manufacturers to which Petitioners supply the subject goods has been provided to the Authority.
- iii. <u>Claims by TII:</u> TII argues that the following grades should be excluded from the product scope due to limited availability, quality issues and because TII has already identified and approved sources of supply which they cannot change now:
 - a. SAE 1541
 - b. SAE 1020/1040/1045/1050/1055
 - c. SCM 435
 - d. Boron Steel
 - e. 16 MnCr5
 - f. SAE 1006/1010
 - g. ST 52.3

TII's claims are baseless. They have failed to substantiate the availability and quality issues they are facing from domestic manufacturers. Further, if TII has approved their sources of supply, they can even approve domestic manufacturers for supply of the same grades. It is submitted that the domestic industry has proven capability to manufacture all the grades listed above and have achieved the necessary quality standards as well. The domestic industry is competent to manufacture and supply TII's requirements. Therefore, these grades cannot be excluded from the product scope.

iv. Hot-rolled coil with pickling and oiling ("PO"): M/s Hyundai Steel Korea argues that PO products manufactured by them are sold to M/s Hyundai Steel India Limited, which, in turn sells it to M/s Hyundai Motor India Limited. They argue that such imports are inevitable as stopping it would mean risking safety of passengers in automobiles. They argue that PO products should be kept outside the product scope. Petitioners strongly object to this contention and submit that Petitioners have proven capability to manufacture Auto Grade Steels including steels suitable for higher strength levels. The domestic industry can manufacture various categories of steels including pickled and oiled steels required by auto companies including M/s Hyundai Motors India Ltd. The entire domestic industry

has required facilities for pickling and oiling process and the domestic industry is regularly manufacturing such products. Therefore, these products cannot be excluded from product scope. Further, Petitioners submit that they are already on the approved vendor list of several automobile makers, their vendors and auto component manufacturers. A list of such automobile makers, their vendors and auto component manufacturers to which Petitioners supply the subject goods has been provided to the Authority.

- Hot-rolled coils based on narrowly defined customer specifications: M/s Nippon Steel & Sumikin Pipe India Co. Ltd. argues that hot-rolled coils based on narrowly defined customer specifications should be excluded from the product scope as these imports differ in tensile strength, steel cleanness, grain size and chemical composition. M/s Nippon Steel & Sumikin Pipe India Co. Ltd. has, however, claimed confidentiality on the description and types of products they have imported but they have requested exclusion of these products from product scope anyhow. Petitioners strongly object to the above contentions. How can Petitioners be expected to rebut the above contentions if the specific grades or types of products are not even disclosed by M/s Nippon Steel & Sumikin Pipe India Co. Ltd.? Without such information, Petitioners are not in a position to make an appropriate response to the above contention. The Authority is requested to direct M/s Nippon Steel & Sumikin Pipe India Co. Ltd. to at least disclose specific grades, with chemical and physical characteristics, that this company imports so that Petitioners can appropriately examine and make comments. If M/s Nippon Steel & Sumikin Pipe India Co. Ltd. fails to disclose even this minimal information, their claim should be rejected outright, as Petitioners have been denied an opportunity to effectively defend their case.
- vi. Grade JSH 270/370 and Grade JSH 590: M/s Maruti Suzuki Ltd. argues that these two grades should be excluded from product scope as these grades are imported to meet requirements of customer safety and meeting emission norms. They argue that domestic manufacturers cannot meet the required quality standards and are inconsistent suppliers of raw material. Petitioners strongly object to the above contentions. During the public hearing, M/s Maruti Suzuki Ltd. admitted that they are trying to localise their procurement to the maximum extent. However, Petitioners submit that despite having proven capabilities to manufacture these grades, M/s Maruti Suzuki Ltd. hardly gives an opportunity to domestic manufacturers to supply these grades. This goes contrary to M/s Maruti Suzuki Ltd.'s claim that that they are trying to localise procurement of all raw materials. M/s Maruti Suzuki Ltd. should give an opportunity to domestic manufacturers to supply these grades who can meet the quality that M/s Maruti Suzuki Ltd. requires. Further, Petitioners submit that they are already on the approved vendor list of several automobile makers, their vendors and auto component manufacturers. A list of such automobile makers, their vendors and auto component manufacturers to which Petitioners supply the subject goods has been provided to the Authority.Further, it may be worthy to note that if M/s Maruti Suzuki Ltd. is importing Grade JSH 270/370 and Grade JSH 590 from its parent company M/s Suzuki, Japan, then it would be in their interest to continue such imports from M/s Suzuki instead of sourcing them locally. Therefore, there claim that they are trying to localise procurement is nothing but misrepresentation before the Authority. It is understood that M/s Maruti Suzuki Ltd. has a long-term procurement agreement with M/s Suzuki, Japan to procure the above grades. However, such fact has not been disclosed to the Authority. In light of this, M/s Maruti Suzuki Ltd.'s claim that they are trying to localise their procurement of these grades but are unable to do so because domestic manufacturers cannot meet their requirements is nothing but a false
- vii. Alloy Steel: Federation of Association of Maharashtra ("FAM") argues that alloy steel is produced in negligible quantities in India, so the question of imposition of safeguard duty on alloy steel does not arise. They further argue that imports of non-alloy steel constitutes only 7-8% of total domestic production and more than 90% market share for non-alloy steel is with domestic units. FAM further argues that such low imports of non-alloy steel do not warrant imposition of safeguard duty. Petitioners strongly object to these claims. FAM is relying on JPC data which is not at PUC level. Therefore, the assumptions taken by FAM in their analysis are incorrect. Further, in the later part of this submissions, it can be seen that market share of imports is much higher in domestic production and demand and is constantly on the rise. Further, the product scope covers only one tariff item 7225.30.90 and not the entire alloy steel heading. Therefore, FAM is incorrect in stating that the entire alloy steel category has been included in the product scope. Petitioners have already provided detailed reasons in their letter dated 8 August 2015 as to why alloy steel falling under customs classification 7225.30.90 should be included in product scope. To summarise the issue briefly, it is submitted that imports which are characterised as alloy steel under tariff item 7225.30.90 actually have very minute quantities of boron due to which they get classified under this tariff item. These imports are disguised as alloy steel and are severely affecting the domestic industry, as these imports

- are technically and commercially substitutable with non-alloy flat products of hot-rolled steel in coils produced by the domestic industry. Due to this reason, Petitioners have included imports under the tariff item 7225.30.90 under the product scope. In light of the above, FAM's contentions should be rejected outright. China Iron & Steel Association have also questioned why alloy steel falling under customs tariff heading 7225 has been included in product scope. The above analysis also addresses the contentions by China Iron & Steel Association.
- viii. <u>High Strength Steel ("HSS"):</u> China Steel Corporation, Taiwan argues that HSS grade used in automobile industry should be excluded from product scope. As stated earlier, Petitioners have proven capability to manufacture Auto Grade High Strength Steels (HSS) including higher strength levels. Therefore, HSS grade cannot be excluded from product scope.
- ix. Steel produced by Japanese Mills: M/s JFE Steel Corporation, M/s Nisshin Steel Co. Ltd., M/s Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation and M/s Kobe Steel Ltd. together argue that steel produced by Japanese mills should not be subject to safeguard duty and should be excluded from product scope. Petitioners find such a contention as too vague and difficult to accept. These companies have not provided names of grades or specifications of their products for which they want exclusions. Without such information, such contentions have no merit and should be rejected outright. These companies further argue that the domestic industry cannot produce automotive grade steel. This contention is again incorrect as Petitioners have already substantiated that they produce automotive grades as well.
- i. <u>Critical circumstances that justify levy of provisional safeguard duty:</u> Several interested parties argue that there were no critical circumstances in the present case that warranted imposition of provisional safeguard measures. It is argued that the Authority also failed to demonstrate in their analysis that such critical circumstances existed. Petitioners strongly object to the above contentions and submit that the petition as well as paragraph 34 of the preliminary findings comprehensively throws light on the critical circumstances that warranted imposition of provisional safeguard duty in this case. The Authority has, thus, met the requirements of Article 6 of the SA and Rule 9 of Safeguard Duty Rules in this case.
- Inconsistency with FTAs and other bilateral agreements: Interested parties argue that import duties on the subject goods are about to be eliminated in India-Korea CEPA and India-Japan CEPA. Therefore, it is argued that India should not have levied safeguard duty on imports of the subject goods from Korea RP and Japan as these imports have occurred due to low customs duty on imports from these countries. It is also argued that India could have explored bilateral mechanisms with these two countries under the respective FTAs rather than simply imposing general safeguard duty on Korea RP and Japan. Interested parties also argue that India-Korea CEPA provides that in the event imports from Korea RP are not the reason of injury to the domestic industry, such imports should be excluded from imposition of safeguard duty. Petitioners strongly object to these contentions and submit that imports from both Korea RP and Japan have caused serious injury to the domestic industry. It is immaterial that imports from Korea RP and Japan increased due to low customs duty under the respective FTAs. Imports from these two countries have occurred in huge quantities in the most recent period and these imports are at unfairly low prices causing serious injury to the domestic industry. Further, it is the discretion of the Government of India to explore bilateral mechanisms under the respective FTAs or adopt a general safeguard measure in this case. Both the FTAs nowhere mention that India is obligated to explore bilateral mechanisms first and only after failure of such mechanisms can adopt a general safeguard measure. Further, these FTAs have specific provisions that allow India to impose general safeguard duty. The only exception under SA and Safeguard Duty Rules is exclusion of developing countries whose individual share in imports is below 3% and whose aggregate share in imports is below 9%. Korea RP and Japan do not fall under this exception, as both of them are developed countries. Therefore, contentions of interested parties are incorrect and should be rejected.
- k. Fall in raw material prices justifies fall in steel prices: Interested parties argue that prices of iron ore and coal have declined by 42% and 21% respectively in 2014-15 and consequently there is a fall in prices of the subject goods. Therefore, import prices cannot be considered as low and domestic industry should also translate the decrease in raw materials to their hot-rolled products. Interested parties further argue that the domestic prices of Petitioners are much higher than export prices. Petitioners strongly object to these contentions and submit that they have already decreased their prices in line with decrease in raw material prices. But the contention of parties that there is a steep decline in raw material prices is incorrect as it does not take into account the cost of transporting the raw material to factory. Such costs are inclusive in production cost. Further, transportation cost also has consistently increased during the injury analysis period. Therefore, the overall decline in raw material prices is much lower than what is claimed by interested parties. It is also pertinent to note that during recent periods, landed value of imports of the subject goods have declined much more than the decline in raw material prices. Further, it should not be ignored that imports have come at grossly low prices and the domestic industry has been forced to match such low prices, to the extent that their prices have gone below the cost of production of the domestic industry. Petitioners would like to add that of late, exports are being made even below the marginal

cost of production by certain countries which are also major exporters to India. This poses a serious threat of unfair trade practices. Interested parties are, thus, wrong in claiming that the domestic industry's export prices are lower than domestic prices. It is important to note that international prices of steel products are already suppressed due to rampant dumping by countries like China PR, Russia and Ukraine. Domestic industry's export prices are also suppressed. That does not mean that the domestic industry should also sell their products at suppressed prices in their domestic market as well.

- 2013-14 should not be considered as base year for injury examination: Interested parties argue that 2013-14 should not be considered as base year as it does not take into account the downward trend of imports between 2012-13 and 2013-14. Some interested parties argue that period of analysis should be 5 years and a shorter period is erroneous. Petitioners strongly object to these contentions. It is submitted that the legal provisions nowhere specify the minimum period for which serious injury should be examined. The only available guidance in this respect is in Article XIX of GATT where it is stated that imports should be sudden, sharp and significant in a recent enough period. Further, the only guidance on length of the period for which data should be provided by parties is given in Trade Notice No. SG/TN/1/97 dt. 06.09.1997 where in paragraph 5(i) it is stated that parties should provide information for the most recent period of three years (or longer) for which data is available. However, the Trade Notice also does not prescribe what should be the length of injury analysis period, which the Authority should examine. In light of the above, Petitioners submit that they have provided information from 2011-12 onwards to Q1 of 2015-16 in the petition, which is as close and recent to the initiation of the investigation. In Petitioners' written submission data has now been provided up to Q2 of 2015-16. Therefore, the petition and written submissions satisfy the above requirement of Article XIX of GATT and the aforementioned Trade Notice. With respect to considering 2013-14 as base year, it is the discretion of the Authority to conduct analysis in a manner the Authority deems fit. There is nothing wrong in using 2013-14 as base year. Without prejudice to above, Petitioners submit that even if 2011-12 is considered as base year, the trends would again show that the domestic industry is suffering serious injury due to sudden, sharp, significant and recent increase in imports.
- m. Captive consumption of product under consideration: Several interested parties have argued that captive imports by downstream units should be exempt from safeguard duty. Mostly, these claims have been raised by companies like POSCO Korea and POSCO Maharashtra, and Hyundai Steel Korea and its Indian affiliates. Here the modus operandi is that the foreign steel producer is supplying the subject goods to its Indian affiliate/affiliates. A very surprising claim by these entities is that Indian manufacturers cannot supply hot-rolled steel of high quality, specifications, strength, and meeting environmental or safety norms that these entities require. Basically, on one pretext or the other, these entities are of the view that somehow the domestic industry cannot meet the requirements of their Indian affiliates. Petitioners strongly object to such assumptions by these parties and submit that the subject goods manufactured by the domestic industry fully meets all the requirements that these companies are looking for. The only concern of these companies is that safeguard duty will prevent them from importing unfairly low priced subject goods from Korea RP. Petitioners submit that there is no provision under law that exempts goods imported for captive consumption from the purview of safeguard duty. Therefore, the above contentions by interested parties cannot be entertained.
- n. No unforeseen developments: Many interested parties are of the view that Petitioners have failed to identify unforeseen developments that led to increase of imports of the subject goods. Some interested parties also claim that even the Authority has failed to discuss unforeseen developments in the preliminary findings. A few interested parties also claim that unforeseen developments have been identified but do not correlate with the subject goods. Some interested parties are of the view that depreciation of Indian Rupee and local procurement by users offset unforeseen developments. Petitioners believe that none of the interested parties have actually perused the petition and preliminary findings in entirety. Such negligence on the part of interested parties is astonishing considering they seem to have made significant efforts to rebut Petitioners' claims. The petition documents in very precise terms the unforeseen developments that led to sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods that caused or threatens to cause serious injury to the domestic industry. The preliminary findings also discuss in very precise manner such unforeseen developments. Further, there is no provision in law that suggests that one development can offset an unforeseen development as suggested by one of the parties. Therefore, depreciation of Indian Rupee and local procurement by user industry is irrelevant and immaterial as far as offsetting unforeseen developments is concerned.
- o. Exclusion of imports made to related downstream industry: Some interested parties are of the view that imports made to related downstream industry in India should be excluded from the purview of safeguard duty by practice of market segmentation. Petitioners have heard of such practice for the first time in the context of safeguard investigations. It is irrelevant whether imports are to a related party or an unrelated party. The key here is that sudden, sharp, significant and recent imports of goods should have caused or threatened to cause serious injury to

- a domestic industry so as to merit levy of safeguard duty. The character of imports (to a related party or unrelated party) is immaterial. Therefore, such contentions by interested parties should be rejected outright.
- p. Adverse impact on downstream industry: Some interested parties are of the view that downstream industry would be hurt by imposition of safeguard duty. Petitioners respectfully submit that if the downstream industry had not encouraged huge quantities of imports at unfairly low prices, this situation would have not arisen at all. It is because the domestic industry is now in such a precarious situation that even their survival is difficult, they have come before the Authority. Safeguard duty will only restore balance to market forces. Without safeguard duty, competition in the market will remain distorted and preferences of downstream industry would remain intact on unfairly low priced imports. Further, M/s Mitsui & Co. India Pvt. Ltd. has submitted that they are re-rollers of the subject goods and have long term contracts with a supplier in Japan for procurement of the subject goods. They submit that their size of operations is not large enough to absorb the burden of safeguard duty. Petitioners respectfully submit that safeguard duty would only establish a level playing field and stabilise the distorted competition in the market. Safeguard duty in no way can harm the small re-rollers, rather it is a measure to provide temporary protection to the domestic industry from low priced imports that are coming in increased quantities into India.
- q. Non-applicability of safeguard duty on those hot-rolled flat products in coil form for which contracts were entered into before levy of provisional safeguard duty: Some interested parties are of the view that for contracts for which LCs were recently opened before imposition of provisional safeguard duty or on the day such duty was imposed would be affected, as such imports will be subject to safeguard duty. In fact, such parties have also requested for refund of safeguard duty as they are of the view that imposition of provisional safeguard duty was unforeseen to them. Petitioners submit that such contentions cannot be entertained. There is no mechanism under law that allows such exemptions. Such imports should be subject to safeguard duty like all other imports of the subject goods.
- Situations in Thailand/Malaysia cannot be compared: Interested parties argue that countries like Malaysia and Thailand have imposed anti-dumping duties and safeguard duties respectively, on the subject goods in a situation when there was a huge surge in imports to the extent of 1350%, which is not the case in the present investigation. Thus, interested parties argue that comparison with these countries is incorrect. Petitioners object to this contention and submit that if Indian domestic industry waits till imports rise to 1350% in India, by that time there will be no domestic industry left to protect. The domestic industry is already facing an alarming situation by the sudden, sharp and significant increase in imports. The domestic industry cannot be expected to wait for imports to rise further, as the domestic industry is already suffering serious injury from imports. Without prejudice to the above, it is clarified that the petition referred to Malaysia and Thailand in a different context than what is alleged by the interested parties. Petitioners had argued in the petition that levy of anti-dumping duty and safeguard duty on the subject goods by Malaysia and Thailand respectively was an unforeseen event. Due to this unforeseen event, exporters could no longer export to these countries and started to export increased quantities to a country like India, which had and still has better demand. In light of the above, it is submitted that interested parties have simply failed to understand the context in which grounds were raised by Petitioners in their petition. Petitioners submit that contentions of interested parties on unforeseen developments are incorrect and should be rejected outright. The above contentions of interested parties are, thus, unacceptable and should be rejected.
- s. <u>Imports net of captive consumption and net of advance authorization/EPCG:</u> Many interested parties argue that import volumes should be considered after excluding imports meant for captive consumption, or under advance authorization/EPCG. Petitioners strongly object to such claims and submit that for the purposes of safeguard investigation, total imports are to be examined. Character of imports, whether for captive consumption, under advance authorization or EPCG is irrelevant.
- t. <u>Cumbersome process of claiming duty drawback:</u> M/s Hyundai Motor India Limited claims that the process for claiming duty drawback is very cumbersome in India and safeguard duty should not be imposed until this process is simplified. This contention is irrelevant for the purpose of this investigation and should be rejected outright.
- u. <u>Effect on export competitiveness:</u> Interested parties have also argued that imposition of safeguard duty would hurt the export competitiveness of India. Petitioners wholly object to the above contention and submit that export competitiveness cannot be hurt by imposition of safeguard duty, because producers/exporters in India always have the option to import the subject goods under advance license, wherein subject goods are exempt from payment of safeguard duty. The above contention of interested parties is, thus, unacceptable and <u>should be rejected.</u>
- v. <u>Safeguard duty would threaten employment and create monopoly:</u> Many interested parties wrongly claim that imposition of safeguard duty would threaten employment in India. Petitioners humbly submit that if safeguard

duty is not imposed, huge employment of domestic industry would be at stake. It is in public interest to impose safeguard duty immediately and protect the domestic industry. Further, imposition of safeguard duty would not create a monopoly as there are several manufacturers of the subject goods in India and there is healthy competition among them. Imports of the subject goods that are distorting the competition have to be checked by imposition of safeguard duty. Further, imposition of safeguard duty does not ban imports of the subject goods. Further, safeguard duty is just a temporary protection for the domestic industry to correct the market distortion create by huge quantities of low priced imports of the subject goods into India.

Other procedural issues in the investigation: Several interested parties are concerned that India failed to notify to the WTO about imposition of provisional safeguard duty before adopting such measure. Even exporters are concerned about India's non-compliance with such notification requirements. Further, a few interested parties are of the view that a list of developing countries whose imports were below the legal threshold of 3% should be excluded from the purview of safeguard duty. Interested parties are also of the view that provisional safeguard duty was imposed in haste without giving an opportunity to be heard. Petitioners object to these contentions and submit that merely because there was slight delay by India to notify the measure to the WTO, it does not mean that imposition of provisional safeguard duty itself is per se inconsistent with provisions of Article 12.4 of SA. Mere non-compliance with a procedural requirement such as late notification to the WTO does not compromise the substantive merits of the provisional safeguard duty. Further, exporters need not worry about such notification requirements by India. It is the prerogative of WTO member countries to bring such concerns to the Government of India and not foreign exporters. Petitioners further submit that the Authority already has data on record for volume of exports from each exporting country. Further, Petitioners have also clarified the same by their letter dated 9 November 2015 to the Authority. Therefore, the Authority may examine the same while finalising this case and notify the list of developing countries who are exempt from application of safeguard duty. Further, interested parties have been able to exercise their right of defence fully at all stages of this investigation. Therefore, it is incorrect to argue that imposition of safeguard duty in a span of few days is a violation of natural justice. Petitioners, in their letter dated 27 July 2015 have provided instances where WTO member countries have imposed provisional safeguard duty on the same day on which the investigation was initiated. In this case, provisional safeguard duty was imposed after one full week of initiation of the investigation. This, in no event is a violation of any WTO provision. Further, Rule 9(1) of the Safeguard Duty Rules allows the Authority to proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, record a preliminary finding regarding serious injury or threat of serious injury. As critical circumstances existed in this case, the Authority expeditiously issued preliminary findings in this case, and thereafter customs notification was issued after one week of initiation of this investigation. Therefore, all legal requirements have been met in this case keeping in view existence of critical circumstances.

Contentions by interested parties on injury parameters

Petitioners object to the submissions made by interested parties with respect to injury and causal link issues and would like to draw the attention of the Authority to the following key submissions in this respect:

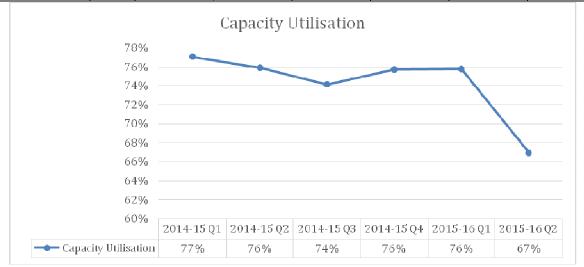
i) Injury indicators including sales, production, capacity, investment levels, inventories, employment have remained stable and some indicators show positive trend:

Petitioners have provided updated information on all economic parameters with rejoinder.

- x. Petitioners object to the contention of interested parties that injury indicators including sales, production, capacity, investment levels, inventories, employment, etc. have remained stable and some indicators show positive trend.
- y. The demand for the subject goods in India has increased in the injury analysis period. Despite increase in demand, the production, employment and sales of Petitioners have remained stagnant. While inventories have increased, the capacity utilisation of the domestic industry has declined. Imports have taken away all the increase in demand of the subject goods. In 2014-15, while demand excluding captive increased by 1,158,614 MT and imports increased much more by 1,248,015 MT. This shows the aggressive manner in which imports of the subject goods are entering the Indian market.
- z. Further, POSCO Maharashtra has contended that the surge in imports in 2014-15 is mainly because of imports by them for setting up manufacturing facility and if the same is excluded, there would be a slump in imports. Petitioners strongly reject this contention and submit that imports have surged not only in 2014-15 but also in Q1 and Q2 of 2015-16. Moreover, POSCO itself is admitting that it has made most of the imports during the first two quarter of 2015-16, which substantiates the point that are causing serious injury to the domestic industry by importing huge quantities of the subject goods at unfairly low prices from Korea RP.

- aa. Had there been no serious injury due to imports of the subject goods, the capacity utilisation, production, employment and sales would have increased commensurate to the increase in demand in India. However, sales and employment of the domestic industry have remained stagnant over the period of investigation.
- bb. Capacity utilisation has come down from 77% in Q1 of 2014-15 to 67% in Q2 of 2015-16 as evident from the following table below:

Particulars	Unit	2014-15 Q1	2014-15 Q2	2014-15 Q3	2014-15 Q4	2015-16 Q1	2015-16 Q2
Capacity of Domestic Industry	MT	5,884,372	5,915,879	5,915,879	5,852,865	5,884,372	5,884,372
Production of Applicant Domestic Industry	МТ	4,532,770	4,488,093	4,386,470	4,429,604	4,456,795	3,941,208
Capacity Utilisation	%	77%	76%	74%	76%	76%	67%



cc. **Inventory levels** of domestic industry have increased substantially as compared to the base year due to constant pressure of increasing imports. The domestic industry has raised its capacities foreseeing the increasing demand in India. However, the domestic industry is unable to increase its production and sales which is leading to a situation of inventory accumulation over the injury period.

Particulars	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 Q1	2015-16 Q2
Inventory (MT)	331,101	583,311	636,879	648,290	657,099	871,440
Indexed	100	176	192	196	198	263

dd. It is, therefore, evident that the contentions of interested parties are wrong. Sales, production, capacity utilisation, investment levels, and employment are showing negative trend indicating injury to the domestic industry.

ii) Domestic Industry has been earning profits till 2014-15 whereas losses have been incurred only in Q1 of 2015-16

ee. Interested parties have argued that profits of the domestic industry have followed an upward trend and losses have been suffered only in Q1 of 2015-16 and therefore it cannot be concluded that domestic industry has suffered serious injury. Petitioners object to the above contention that there is no serious injury because profits

have increased. Petitioners submit that the domestic industry has not only suffered losses in Q1 of 2015-16 but also in Q2 of 2015-16. It is to be noted that not only the profits of domestic industry have vanished rather substantial losses are being incurred thereby substantiating the claim of Petitioners to impose safeguard duty in such an extraordinary situation. Profit trends are shown in the following table:

Particulars	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 Q1	2015-16 Q2
Profits (INR crores)	****	****	****	****	****	****
Profits (INR Indexed)	100	34	96	79	(59)	(87)
Profits (INR per MT)	****	****	****	****	****	****
Profits (INR per MT Indexed)	100	27	68	95	(90)	(227)

- ff. It can be seen from the above table that Petitioners' profitability has gone down drastically during the recent periods. The domestic industry has been suffering severe losses since Q1 2015-16. Further, the losses have increased during Q2 2015-16. From profit per MT of 100 indexed units in 2011-12, the domestic industry is now facing losses of (90) indexed units during Q1 2015-16 and further losses of (227) indexed units during Q2 2015-16.
- gg. Quarter-wise analysis of 2014-15 and the first six months of 2015-16 shows a grim picture. Profits started declining in 2014-15 itself, and position of the domestic industry further worsened in Q1 and Q2 of 2015-16. In Q1 of 2014-15, profits were 100 indexed points, which sharply declined to 52 indexed points in Q4 of 2014-15. The domestic industry suffered severe losses in Q1 of 2015-16, when it suffered losses to the extent of (36) indexed points. This further worsened in Q2 of 2015-16 when losses increased to (52) indexed points.

Particulars	Unit	2014-15 Q1	2014-15 Q2	2014-15 Q3	2014-15 Q4	2015-16 Q1	2015-16 Q2
Profits	INR(Cr.)	****	****	****	****	****	****
Indexed		100	118	42	52	(36)	(52)
Profits per MT	INR/MT	****	****	****	****	****	****
Indexed		100	111	48	45	(17)	(42)

hh. The major reason for decline in profitability and losses of domestic industry is increased imports at reduced prices. If the same trend continues, the domestic industry fears that they would be forced to shut down their operations. If appropriate remedial measures are not put in place immediately, the domestic industry runs a risk of banks/financial institutions recalling their loans and thereby inflicting a sudden death to the domestic industry.

iii) Market share of imports is not significant to cause injury

- ii. Many interested parties have argued that there is no sudden or sharp increase in imports that have caused serious injury to the domestic industry. Further, interested parties have argued that the market share of imports is insignificant to cause injury. Some of the interested parties have also contested that there is no increase in imports in absolute terms. Further, a few interested parties have added that increase in imports is of temporary nature and allegation of surge in imports is misleading. Some interested parties have also submitted that imports from Korea RP, Russia and Japan are insignificant to cause serious injury.
- jj. Petitioners wholly object to the above contentions of the interested parties that imports, being insignificant, are not causing injury to the domestic industry and that there is no sharp increase in imports of the subject goods. In fact, sudden increase in imports is the only reason of serious injury to the domestic industry. The quarterly trends for the recent period indicate that market share of imports in total demand including captive increased from 7% in the first quarter of 2014-15 to 13% by the fourth quarter. Market share of imports in total demand (excluding captive) increased from 11% in the first quarter of 2014-15 to 21% by the fourth quarter. The market share of imports in total demand remained high during the first and second quarter of 2015-16. The data on record shows a gradual increase in demand in all quarters of 2014-15 and Q1 and Q2 of 2015-16. In contrast, imports show a sharp increase in every quarter of 2014-15 and in Q1 and Q2 of 2015-16. The share of imports in total demand

(excluding captive) increased from 11% in Q1 of 2014-15 to 19% in the Q1 of 2015-16 and further to 24% in Q2 of 2015-16. If imports continue to increase at this pace, the domestic industry will be wiped out soon.

kk. Further, regarding the submission that imports from Korea RP, Japan and Russia are insignificant, Petitioners strongly object the same and submit that the imports from the abovementioned countries are very significant as evident from the table given below. Also, law provides that only a developing country which satisfies the 3%/9% criteria can be excluded. Therefore, the contention that Korea RP, Japan and Russia should be excluded is not correct because these countries are not developing countries but developed countries, and at the same time imports from these countries are significant.

Country	Import Qty (MT)	Share in total imports
JAPAN	1,957,260	33.08%
KOREA	1,586,318	26.81%
RUSSIA	361,511	6.11%
Other	2,011,066	33.99%
Grand Total	5,916,155	100.00%

iv) Injury is caused due to internal problems and factors other than imports

- II. Interested parties have submitted that injury being suffered by the domestic industry is due to their own internal factors including the following:
 - High interest cost, depreciation and fixed cost burden
 - High freight cost and poor infrastructure
 - Raw material crisis
 - Underutilised capacities
 - Inability to meet the quality requirements of specific downstream industry
- mm. Petitioners object to the above claims of the interested parties. These claims are very general and without any facts and figures to support. The fact that injury has been caused due to increased quantities of imports of the subject goods in India has already been established above. The domestic industry has been in existence since many years and has been doing well in the past. Infrastructure and capacities are in place with the domestic industry to meet the demand of the subject goods. But now it is alleged that the domestic industry is facing losses due to abovementioned internal issues. If such internal issues actually existed, the domestic industry would not have done well in the past also. Therefore, the allegation that the domestic industry is facing losses due to the above internal problems is not correct. It is the sudden and significant surge in imports of the subject goods which have caused injury to the domestic industry. Moreover, interested parties, in their contentions, are unable to substantiate the quality requirement which the domestic industry cannot produce.

v) Domestic industry is facing competition from other Indian manufacturers and therefore, losses suffered cannot pertain to imports in increased quantity

nn. Interested parties have argued that other Indian producers are giving competition to domestic industry because of which domestic industry is suffering losses. Further interested parties have argued that other Indian producers have increased their open market sales by 42% (2,994,323 MT in 2013-14 to 4,263,888 MT in 2015-16(A)). Petitioners submit that share of other Indian producers is very small in absolute terms and therefore, rise in their open market sales is also limited in absolute terms.

Financial Year	Total Import (MT)	Sales of DI (MT)	Sales of other Indian Producers (MT)	Captive sale of DI(MT)	Captive sale of Others (MT)	Total Demand (MT)	Market Share (%)	
							DI	Import
2013-14	1292099	10342565	2994323	4274000	4000724	22903711	45	6
2014-15	2540114	9949214	3298273	5019741	4615864	25423206	39	10
2015-16(Q1)	844840	2589929	1065972	1321497	1180681	7002919		
2015-16(A)	3379360	10359716	4263888	5285988	4722724	28011676	37	12

- oo. From the above table, it can be seen that from 2013-14 to 2015-16 (A) combined open market sales of all Indian producers have increased only by 9.6% (1,286,716 MT in absolute terms) whereas imports have increased by a massive 160% (2,087,261 MT in absolute terms) in the same period.
- pp. Interested parties are trying to mislead the Authority by highlighting rise of 42% in sales of other Indian producers whereas a comprehensive study of the data shows that this rise in sales is trivial when compared with the demand in India.

vi) Other Issues

1) Use of Q1 data for annualising 2015-16 figures

- qq. Interested parties have submitted that annualising the Q1 figures of 2015-16 in order to arrive at annualised figures of 2015-16 is not a correct method for injury analysis. They further added that this method does not provide objective and reasonable basis for injury analysis and is misleading. One of the interested parties has submitted that longer period should be considered for annualisation.
- rr. In this regard, Petitioners submit that in the petition filed with the Authority, Petitioners have provided data for the period January 2015 to June 2015 (6 Months), based on which figures were annualised for the year 2015. It is worth noting that nowhere in Article XIX of GATT, SA, Section 8B of the Custom Tariff Act, 1975 and the Safeguard Duty Rules, the method of annualisation is given. The only legal requirement is to provide data for a period as recent as possible and the same has been complied with by the domestic industry. Further, in the written submissions post public hearing, Petitioners have provided data for both Q1 and Q2 of 2015-16. Now annualisation is done based on data of the first six months of 2015-16, which is sufficient enough for the purpose of annualisation.

2) Effect of cheaper imports on competition

ss. China Iron and Steel Association has argued that cheaper imports in India would encourage competition in the Indian industry and increase in imports or availability of goods at low prices is not bad and should not be discouraged. Petitioners wholly object to this contention. Imports of the subject goods are not bad as long as they are not unfairly priced and causing any serious injury to the domestic industry. If imports are causing serious injury or threat of serious injury to the domestic industry, then such imports need to be controlled by way of safeguard measures. Moreover, levy of safeguard duty would only provide a level playing field to domestic manufacturers. Imports can still happen subject to payment of appropriate duty. Also, it is not a permanent measure but a temporary protection for the domestic industry to ensure huge quantities of unfairly low priced imports of the subject goods do not distort competition in the Indian market. Safeguard duty would in fact encourage healthy and fair competition in the Indian market.

3) Safeguard duty on floor price mechanism`

- tt. M/s Tube Investment and M/s Hyundai Motors have suggested that floor price mechanism should be put in place to control cheaper imports. Petitioners agree with this proposal and submit that floor price mechanism may be resorted to after taking into account the manufacturing cost of the domestic industry and serious injury suffered by the domestic industry due to low priced imports. The Authority may invite views from the domestic industry if such a mechanism is required to be put in place.
- uu. In light of the above contentions, Petitioners submit that there is no merit in the contentions raised by interested parties.

II. Rejoinder by Domestic Industry to the submissions of Federative Republic of Brazil post public hearing

Petitioners provide rejoinder to the written submissions by the Federative Republic of Brazil ("Brazil") in subsequent paragraphs:

Opening two paragraphs of the written submissions: In the first two opening paragraphs of the written submissions, Brazil makes very general submissions on the requirement to follow Article XIX of GATT 1994 ("GATT") and the Agreement on Safeguards ("SA"). Brazil, then cautions India that since safeguard measures are emergency measures, these should be applied only after complying with the high standards set by the WTO Dispute Settlement Body. Petitioners agree with Brazil's general comments and submit that the Authority has complied with the requirements under Article XIX of GATT and the SA in the present case. The petition contains all the relevant information that merits imposition of safeguard duty. Such information has been duly examined by the Authority in line with the requirements under GATT, SA, Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 and Customs Tariff

(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 ("Safeguard Duty Rules"). Only after satisfying itself of the rigorous legal standards, the Authority initiated the present investigation.

- a. Notification to the WTO: In paragraphs 3 to 8 of the written submissions, Brazil contends that since India failed to notify imposition of provisional safeguard measure prior to its imposition, India failed to satisfy the requirements under Article 12.4 of the SA. Petitioners object to this contention and submit that merely because there was slight delay by India to notify the measure to the WTO does not mean that imposition of provisional safeguard duty itself is per se inconsistent with provisions of SA. Mere non-compliance with a procedural requirement such as notification to the WTO does not compromise the substantive merits of the provisional safeguard duty. Brazil's contention cannot be accepted.
- b. Period of investigation of serious injury (and threat thereof) and increased imports: In paragraphs 9 to 16 of the written submissions, Brazil argues that the Authority only considered domestic industry's data for the period 2013-14, 2014-15 and for 2015-16, the Authority simply multiplied by four the injury parameters based on the first quarter of 2015-16. Brazil argues that such an approach is incorrect as it is inconsistent with general accounting principles, and also because one quarter of 2015-16 is not sufficient enough to indicate domestic industry's performance during 2015-16, as this financial year has not elapsed yet. Brazil further argues that the Indian Authority chose to ignore data for the period April 2011 to March 2012, despite the fact that such data was available with the Authority. This, according to Brazil is a violation of Article 4.2(a) of the SA. Brazil further argues that the period for examination of serious prejudice should be three years as per the recommendation of the WTO Anti-dumping Committee and the period of two years and one quarter in this case is not sufficient. Brazil argues that the period of investigation cannot be reduced on a justification that actual data for most recent period would be collected during the course of the investigation. In light of these contentions, Brazil argues that India has failed to comply with the objectives set out in the SA. Petitioners object to all the contentions by Brazil. Petitioners submit that though the WTO Anti-dumping Committee has specifically suggested that the period of data collection for injury analysis in an anti-dumping investigation should be three years, however, the same requirement cannot be simply transposed in a safeguard investigation. Brazil is incorrect in arguing that in the present investigation, since the Authority has only considered data for a period of two years and one quarter, the Authority has failed to comply with the requirement of examining three years of data. There is no such requirement under GATT, the SA, the Act and the Safeguard Duty Rules that the Authority has to collect and examine data for at least three years to carry out analysis of serious injury to the domestic industry. Further, Brazil also fails to point out the specific provisions under general accounting principles which have not been met in this case. Petitioners submit that the legal requirement under Article XIX is that imports should be recent enough, and such requirement was discharged by the domestic industry by providing data up to the first quarter of 2015-16 in the petition. Merely because the Authority chose to extrapolate data of one quarter for the whole year does not mean that this itself violates any provision of GATT, the SA, the Act and the Safeguard Duty Rules. Petitioners have been regularly assisting the Authority during the course of this investigation and have been providing data on imports for recent quarters as well. Information on updated injury parameters up to the second quarter of 2015-16 has also been provided in Petitioners' written submissions. Interested parties have full opportunity to comment on such updated information. In light of these contentions, Petitioners respectfully submit that Brazil's contentions in paragraphs 9 to 16 are unwarranted and should be rejected.
- c. Serious injury and threat thereof: In paragraph 17 to 23 of the written submissions, Brazil argues that injury parameters of the domestic industry do not indicate existence of serious injury or threat thereof. It appears that Brazil has only referred to injury parameters as given in the preliminary findings but not in the petition. Petitioners reject Brazil's contention and submit that there is serious injury to the domestic industry and threat of serious injury thereof. This is evident from the data on record with the Authority, which has also been duly verified. Therefore, Brazil's contention should be rejected.
- d. Causal Link: In paragraphs 24 to 28 of the written submissions, Brazil argues that there is no causal link in this case, as an analysis of other factors indicates that injury to the domestic industry is not due to imports but other factors. Petitioners strongly object to this contention and submit that there is clear causal link in this case. Petitioners have comprehensively established during the investigation that imports of the subject goods had increased both relative to production and consumption in India. Imports were 7% in production of the domestic industry in 2013-14, which doubled to 14% in 2014-15. Quarter-wise analysis of 2014-15 and Q1/Q2 2015-16 also shows that share of imports has been consistently on the rise in relation to production of the domestic industry. Market share of imports has also increased in total demand during 2015-16. The domestic industry is not able to increase its production and sales commensurate to increase in demand. Capacity utilisation, production, sales and profitability of the domestic industry has suffered. There is significant price depression, suppression, undercutting and underselling due to imports of the subject goods. Profitability and ROCE of the domestic industry have severely deteriorated during Q1 and Q2 of 2015-16. Inventories of the domestic industry

have also increased. All of these factors clearly establish existence of causal link in this case. There are no other factors causing injury to the domestic industry other than sudden, sharp, significant and recent increase of imports of the subject goods.

- e. Special treatment given to developing countries: In paragraphs 29 to 31 of the written submissions, Brazil argues that share of each exporting country has not been informed by the Authority and a list of developing countries has also not been provided. Brazil also argues that the period taken into account for calculation of the volumes imported from each source has not been specified. Due to lack of such essential information, Brazil argues that it has not been able to exercise its right of defence under Article 3.1 of the SA. Petitioners object to these contentions and submit that the Authority already has data on record for volume of exports from each exporting country. Further, Petitioners have also clarified the same by their letter dated 9 November 2015 to the Authority. Therefore, the Authority may examine the same while finalising this case and notify such information in the final findings as well. Further, Brazil has been able to exercise its right of defence fully at all stages of this investigation. There is, thus, no inconsistency in terms of Article 3.1 of the SA. Further, since Brazil's share of imports is more than 3% in total imports as per the available data, it cannot be excluded from the purview of safeguard duty.
- f. Conclusion: In paragraphs 32 and 33 of the written submissions, Brazil argues that there is no serious injury or threat thereof to the domestic industry, and there is no causal link as well. Brazil further contends that formal requirements such as notification to the WTO and publication of essential information have not been observed in this case. Petitioners object to these contentions and submit that the data on record comprehensively establishes that there is serious injury and threat of serious injury to the domestic industry in this case. There is causal link between sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods and serious injury to the domestic industry. Merely because there was slight delay by India to notify the measure to the WTO does not mean that imposition of provisional safeguard duty itself is per se inconsistent with provisions of SA. Petitioners submit that all essential information has been published in this case which has enabled interested parties to exercise their right of defence.

In light of the above contentions, Petitioners submit that there is no merit in Brazil's contentions.

III. Rejoinder by Domestic Industry to the submissions of China PR post public hearing

Petitioners object to all the contentions made by China PR. China PR's submissions are mere general statements that are not supported by concrete data. Petitioners provide their rejoinder to China PR's contentions below:

- a. There are unforeseen development that led to the sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods in India. Petitioners have provided very detailed analysis in this regard in the petition. China PR has failed to take notice of such analysis in the petition.
- b. The petition as well as the preliminary findings comprehensively throw light on the critical circumstances that warranted imposition of safeguard duty in this case. China PR has failed to take notice of the same. The Authority has met the requirements of Article 6 of the SA in this case.
- c. The petition as well as the preliminary findings establish that there is a sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods which has caused serious injury to the domestic industry and is also threatening to cause serious injury to the domestic industry. There is clear causal link in this case. China PR's contention, thus, has no merit.
- d. If safeguard duty is not imposed, the domestic industry will not be able to survive. Public interest of downstream industries alone cannot be the sole criteria in this case. It is in public interest that Indian steel producers should be protected from sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods otherwise, the domestic industry would be wiped out.
- e. Provisional safeguard duty should not be revoked as there exist critical circumstances that warrant continued imposition of provisional safeguard duty for 200 days.

In light of the above contentions, Petitioners submit that there is no merit in China PR's contentions.

IV. **Rejoinder by Domestic Industry to the submissions of Chinese Taipei post public hearing:** Petitioners submit that the Authority may look into Taiwan's request for assistance to deem it as a developing country and take it forward appropriately. Further, whether imports from Taiwan are below 3% or not may be examined from the data on record and only then an appropriate decision may be taken. As Taiwan has not made any substantive comments on the merits of the petition or any other aspect, Petitioners have no further comments on Taiwan's written submissions.

- V. **Rejoinder by Domestic Industry to the submissions of European Commission post public hearing:** Petitioners provide rejoinder to the written submissions by the European Commission ("Commission") in subsequent paragraphs:
 - a. The Commission has submitted in the introductory lines that safeguard instrument should be used in exceptional circumstances only and the present case is suitable for anti-dumping or anti-subsidy investigation. Petitioners object to this contention because at present the Indian steel industry is going through a very critical phase due to sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods. The Indian steel producers are suffering serious injury due to such imports as a result of unforeseen developments and in order to protect their interest from the sudden surge in imports, safeguard duty is the only suitable measure. Due to this reason, the domestic industry has approached the Authority to take an emergency action to protect the domestic industry.
 - b. Regarding Commission's contention that certain specific grades of the subject goods should be excluded from product scope as the domestic industry may not be manufacturing them, it is submitted that the Commission has failed to identify what all grades the domestic industry does not produce, for which exclusions are required. In the absence of information on specific grades, Petitioners cannot effectively rebut such vague contentions. The Commission should give clarifications on the grades of the subject goods that is concerned with, otherwise, the Authority should reject the Commission's above contention.
 - The Commission has raised a number of issues in order to conclude that there is no injury and causality. The Commission argues that use of annualised figures for 2015-16 is not objective and injury analysis as well as causality is not conclusive based on such annualised figures. The Commission argues that data for a longer period should have been considered for 2015-16. The Commission further argues that the factors considered in determining serious injury and causality including the market share, production, capacity, utilisation rate, employment, profits, market share etc. are insufficient and these factors do not indicate injury and causality. Petitioners object to the arguments raised by the Commission. Serious injury and causality are clearly evident from the facts and figures given in the petition and written submission dated 16 November 2015. Petitioners have comprehensively established during the course of this investigation that imports of the subject goods had increased both relative to production and consumption in India. Imports were 7% in production of the domestic industry in 2013-14, which doubled to 14% in 2014-15. Quarter-wise analysis of 2014-15 and Q1/Q2 2015-16 also shows that share of imports have been consistently on the rise in relation to production of the domestic industry. Market share of imports has also increased in total demand during 2015-16. The domestic industry is not able to sell its production and sales commensurate to increase in demand. Capacity utilisation, production, sales and profitability of the domestic industry has suffered. There is significant price depression, suppression, undercutting and underselling due to imports of the subject goods. Profitability and ROCE of the domestic industry have severely deteriorated during Q1 and Q2 of 2015-16. Inventories of the domestic industry have also increased. All of these factors clearly establish existence of serious injury and causal link in this case. There are no other factors causing injury to the domestic industry other than sudden, sharp, significant and recent increase of imports of the subject goods. As a result, there is no violation of Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguards.
 - d. The Commission argues that captive sales and sales by other domestic producers should be examined. The Commission further adds that other Indian producers have increased their open market sales by 42%. Petitioners object to these contentions and submit that share of other Indian producers is very small in absolute terms and therefore, the rise in their open market sales is also limited in absolute terms. Moreover, imports have taken away all the increase in demand of the subject goods. In 2014-15, demand (excluding captive) increased by 1,158,614 MT and imports increased by 1,248,015 MT. When demand (including captive) increased to 25,423,206 MT and (excluding captive) increased to 15,787,601 MT in 2014-15, imports almost doubled to 2,540,114 MT. This shows the aggressive manner in which imports of the subject goods are entering the Indian market. There is no need for the Authority to wait for development of the domestic industry for a longer period as suggested by the Commission, as the domestic industry was established a long time back. The economic parameters of the domestic industry present a fair and accurate picture of the state of the domestic industry.

In light of the above contentions, Petitioners submit that there is no merit in the Commission's contentions.

VI. Rejoinder by Domestic Industry to the submissions of Government of Indonesia post public hearing: Petitioners provide their rejoinder to Indonesia's contentions below:

- a. Imports were 7% in production of the domestic industry in 2013-14, which doubled to 14% in 2014-15. Quarterwise analysis of 2014-15 and Q1/Q2 2015-16 also shows that share of imports has been consistently on the rise in relation to production of the domestic industry. Market share of imports has also increased in total demand during 2015-16. Therefore, Indonesia's analysis is incorrect. Imports have almost doubled from 2013-14 to 2015-16 (Annualised).
- b. The petition as well as the preliminary findings comprehensively throw light on the critical circumstances that warranted imposition of safeguard duty in this case. Ukraine has failed to take notice of the same. The Authority has met the requirements of Article 6 of the SA in this case.

- c. The data from UN Comtrade relied upon by Indonesia is incorrect as it does not represent data for the product under consideration. Any analysis based on such data would give an incorrect picture.
- d. The Indonesian company PT Krakatau Posco should provide complete data for its exports to India to substantiate that it did not export the subject goods to India. Further, Indonesia should also substantiate with the aid of concrete data its producers/exporters never exported the subject goods to India. Such data should also be provided to Petitioners for examination and comments. Without such data, such claims by Indonesia would have no meaning.
- e. The domestic industry is not able to increase its production and sales commensurate to increase in demand.
- f. India's import policy and general increases or decreases in customs duty on steel is not relevant in this case. Petitioners are aware that imports from certain Asian countries like Korea RP, Japan and ASEAN countries that include Indonesia are occurring at concessional rates of duty. However, this is just factual information and Indonesia has not substantiated how this information is relevant in this case.

VII. **Rejoinder by Domestic Industry to the submissions of Russian Federation post public hearing:** Petitioners provide their rejoinder to Russia's contentions below:

- a. Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975 clearly provides that no safeguard duty can be imposed on imports of an article from a developing country if the share of imports from that country does not exceed 3% as long as the aggregate of imports from all such countries taken together does not exceed 9% of total imports. Petitioners submit that in the present case, since Russia is a developed country, it cannot be excluded from the purview of safeguard duty.
- b. There exist substantial reasons to invoke safeguard duty in this case, and it cannot be argued that since substantial imports took place from China PR, Korea RP and Japan, safeguard duty cannot be invoked.
- c. Petitioners respectfully submit that a WTO member country like Russia has no locus to tell domestic industry or the investigating authority of another country that anti-dumping or countervailing measures are more appropriate in a case than safeguard measures. Petitioners have suffered serious injury due to sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods. The circumstances were critical and warranted immediate redressal of the situation by imposition of safeguard duty. Whether India should also explore bilateral mechanism with Korea RP or Japan is the sole discretion of the Government of India.
- d. Economic performance of the domestic industry has in fact deteriorated due to sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods. Petitioners have comprehensively established during the investigation that imports of the subject goods had increased both relative to production and consumption in India. Imports were 7% in production of the domestic industry in 2013-14, which doubled to 14% in 2014-15. Quarter-wise analysis of 2014-15 and Q1/Q2 2015-16 also shows that share of imports has been consistently on the rise in relation to production of the domestic industry. Market share of imports has also increased in total demand during 2015-16. The domestic industry is not able to sell its production and sales commensurate to increase in demand. Capacity utilisation, production, sales and profitability of the domestic industry has suffered. There is significant price depression, suppression, undercutting and underselling due to imports of the subject goods. Profitability and ROCE of the domestic industry have severely deteriorated during Q1 and Q2 of 2015-16. Inventories of the domestic industry have also increased. All of these factors clearly establish existence of causal link in this case. There are no other factors causing injury to the domestic industry other than sudden, sharp, significant and recent increase of imports of the subject goods.
- e. Provisional safeguard duty has been imposed only after thorough examination of the critical circumstances in this case. The Authority has taken a balanced view by initiating this investigation to safeguard the interests of the domestic industry. It is the practice of the Authority to examine public interest as well while examining the need of safeguard duty. Whether safeguard duty should be recommended or not will be decided only after taking into account views of all stakeholders. Therefore, Russia need not worry whether the Authority has taken a balanced view or not, as the Authority examines the need of safeguard duty only after rigorous analysis of all facts and considerations.

In light of the above contentions, Petitioners submit that there is no merit in Russia's contentions.

VIII. **Rejoinder by Domestic Industry to the submissions of Republic of Turkey post public hearing:** Petitioners provide their rejoinder to Turkey's contentions below:

- a. The Authority has notified unforeseen developments that led to sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods. The Authority has, thus, satisfied the requirements under Article XIX and the SA.
- b. India has notified to the WTO about the initiation and levy of provisional safeguard duty based on the notification requirements under the SA. It cannot be said that the notification did not contain a detailed examination of unforeseen developments. The notification expressly refers to the preliminary findings of the Authority dated 9 September 2015. Interested parties including governments can access the preliminary findings from the website of the Authority, which can be easily accessed. India's notification to the WTO when read with the preliminary findings of the Authority very clearly specifies examination all the parameters including unforeseen developments in this case.

- c. It is to be noted that Petitioners have not annualised data in the petition based on the first quarter of 2015-16. Petitioners have annualised data for the year 2015 on basis of six months' data for January June 2015, which is on the record of this investigation. The Authority has also duly examined the same data during the course of this investigation. Petitioners have now provided data for the second quarter of 2015-16 as well in their written submissions dated 16 November 2015. Data has now been annualised based on the first six months data for 2015-16, which also shows existence of serious injury to the domestic industry.
- d. Petitioners have duly put on record injury parameters for the years 2011-12 and 2012-13. The Authority has also duly verified this information. The Authority has the discretion to consider and examine data for these periods as well. Such analysis will again show the extent of serious injury the domestic industry has suffered and will continue to suffer if definitive safeguard measures are not imposed. Further, import data does not show slight increase; rather the increase is significant. Imports in 2014-15 almost doubled in comparison to 2013-14. Imports in 2015-16 are expected to almost double than 2014-15 levels based on the available data for the first six months of 2015-16.
- e. Profitability for 2013-14 and 2014-15 cannot be examined in isolation. Profitability figures have to be examined for recent periods as well. The domestic industry's profitability has sharply declined to (613) and (1,547) during the first two quarters of 2015-16 itself. This is going to further decrease as imports are still coming at very significant levels and hurting the domestic industry. The domestic industry has been unable to increase its sales during the injury analysis period due to sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods.
- f. Economic parameters of the domestic industry should be examined for the product under consideration as specified in the petition. Mere reference to annual reports of individual petitioners without appreciating the surrounding circumstances would not give the correct picture.
- g. Petitioners have already put on record the detailed break-up of imports of the subject goods from all sources. The Authority can examine the same and take an appropriate view on whether Turkey should be excluded from application of safeguard duty or not.
- h. Turkey's contention that it should be excluded from the purview of safeguard duty as it is a developing country is incorrect. India does not recognise Turkey as a developing country in terms of Notification No. 103/98-Cus dated 14 December 1998. Therefore, Turkey cannot be excluded from the purview of safeguard duty.

In light of the above contentions, Petitioners submit that there is no merit in Turkey's contentions.

- IX. Rejoinder by Domestic Industry to the submissions of Embassy of Ukraine post public hearing: Petitioners submit that Ukraine has indulged in end-to-end analysis of domestic industry's parameters for the period 2011-12 vis-à-vis 2014-15. This kind of selective analysis leads to skewed observations. The WTO Panel in *Dominican Republic Safeguard Measures on Polypropylene Bags and Tubular Fabric* has clearly noted that mere end-to-end analysis is not enough. As per the Panel report, an investigating authority should also consider year-on-year analysis to holistically examine variations in domestic industry's parameters. As all of Ukraine's submissions are based only on end-to-end analysis, all the contentions raised by Ukraine are inconsistent with the aforesaid WTO Panel Report. End-to-end analysis alone is incorrect. End-to-end analysis along with year-on-year analysis is the correct legal methodology as established by the WTO Panel in aforesaid case. Petitioners have conducted both end-to-end and year-on-year analysis in the petition and their written submissions dated 16 November 2015. Based on the above analysis, the following are submitted:
 - a. Imports were 7% in production of the domestic industry in 2013-14, which doubled to 14% in 2014-15. Quarterwise analysis of 2014-15 and Q1/Q2 2015-16 also shows that share of imports have been consistently on the rise in relation to production of the domestic industry. Market share of imports has also increased in total demand during 2015-16.
 - b. The domestic industry is not able to sell its production and sales commensurate to increase in demand.
 - c. Capacity utilisation, production, sales and profitability of the domestic industry has suffered.
 - d. There is significant price depression, suppression, undercutting and underselling due to imports of the subject goods.
 - e. Profitability and ROCE of the domestic industry have severely deteriorated during Q1 and Q2 of 2015-16. Inventories of the domestic industry have also increased.
 - f. All of these factors clearly establish existence of causal link in this case. There are no other factors causing injury to the domestic industry other than sudden, sharp, significant and recent increase of imports of the subject goods.
 - g. The petition as well as the preliminary findings comprehensively throw light on the critical circumstances that warranted imposition of safeguard duty in this case. Ukraine has failed to take notice of the same. The Authority has met the requirements of Article 6 of the SA in this case.
 - h. The data from International Trade Centre relied upon by Ukraine is incorrect as it does not represent data for the product under consideration. Any analysis based on such data would give an incorrect picture.

In light of the above contentions, Petitioners submit that there is no merit in Ukraine's contentions. India has, thus, not committed any violation of Aritcles 2.1, 4.1(a), 4.2(b) and 6 of the SA.

- X. **Rejoinder by Domestic Industry to the submissions of Dillinger Huttenwerke post public hearing:** Petitioners provide rejoinder to the written submissions by Dillinger Huttenwerke ("Dillinger") in subsequent paragraphs:
 - a. Dillinger has submitted that the name of the company mentioned in the notice sent to them by the Authority is 'Dillinger and Salzitter' whereas the correct name is 'Dillinger Huttenwerke'. Further it is submitted that Dillinger is not engaged in production or exports to India of the subject goods. Dillinger has admitted on record that it is a producer of heavy steel plates.
 - b. Petitioners request the Authority to examine the veracity of the above claims by Dillinger and also examine whether Dillinger is producing any other products falling under definition of the subject goods, which it has exported to India. Petitioners request the Authority that if any further information is provided by Dillinger, it should be provided to Petitioners for examination and comments.

XI. Rejoinder by JFE Steel Corporation, Nisshin Steel Co., Ltd, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation and Kobe Steel, Ltd. (together referred as "Japanese Mills") represented by M/s. AZB & Partners

- a. The Japanese Mills deny all the contentions averred in the DI's submissions and submit that no part of the rejoinder may be read to be or deemed to be an admission of the facts and contentions pleaded in the DI submissions, unless and insofar as specifically admitted in this rejoinder.
- b. The DI's post hearing submissions do not provide adequate evidence that is necessary for the initiation of a safeguard duty investigation on imports of the subject goods.
- c. The DI does not manufacture the kind of HRC that is identical or alike in all respects to the products exported by the Japanese Mills.
- d. The DI had requested exclusion of API Grade Steel based on end-usage substitutability. On similar lines, the Japanese Mills also request that the products manufactured and exported by them are not substitutable with those produced by the DI as these are guided and tailored to meet its end consumer preferences and specifications. Therefore, the type of HRC supplied by the Japanese Mills are not like or directly competitive with the HRCs produced by the DI. The Authority should examine if the DI is manufacturing the specific grades of HRC exported by the Japanese Mills and accordingly, exclude the same from the scope of the product under consideration.
- e. There is no consistent trend of increase in imports. This is notwithstanding the fact that JSW Steel is importing about 150,000 MT of HRC into India from China to artificially inflate import figures. If there is any increase in imports, it is due to the increase in demand of HRCs in the domestic market coupled with the low global prices of HRCs and the inability of the DI to meet the needs of the domestic market by supplying products of sufficient quality and quantities to meet the needs of industrial users.

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Particulars (Excluding Captive Consumption)				
Market share of DI	66%	68%	71%	63%
Market share of other domestic producers	15%	17%	20%	21%
Market share of imports	18%	14%	9%	16%

- f. Market share of the DI has consistently increased in the years 2011-12, 2012-13 and 2013-14. The DI's market share has only decreased in the year 2014-15. The market share of the DI, excluding captive consumption, has only fallen from 66% in 2011-12 to 63% in 2014-15. Whereas there has been a significant increase in the market share of other producers from 15% in 2011-12 to 21% in 2014-15.
- g. Domestic sales of other domestic producers have also increased from 1,880,877 MT in 2011-12 to 2,994,323 MT in 2013-14 and then further to 3,298,273 MT in 2014-15. It is evident from this data that the loss in market share of the DI is due to inter-se competition between the DI and other domestic producers.
- h. Contrary to the submissions of the DI, the market share of Imports fell from 18% in 2011-12 to 9% in 2013-14, and then increased to 16% in 2014-15, still lower than the imports in 2011-12. Even monthly analysis of import data doesn't lead to a conclusion of a consistent surge in Imports, for instance imports fell from 153,500 MT in April 2014, to 98,192 MT in May 2014, and then rose to 277,891 MT in October 2014 only to fall again to 171,927 MT in November 2014.
- i. On an analysis of the data in the DI Written Submissions for 2011-12 to 2014-15, it is evident that there has been an increase in the sales of the DI in absolute terms. Moreover, any decrease in sales between 2013-14 and 2014-15 can be attributed to the DI willfully diverting HRCs to be sold in the domestic market towards captive consumption. This is evident from the increase in captive consumption of the DI from 4,274,000 MT in 2013-14 to 5,019,741 MT in 2014-15.

- j. Sales of the DI increased only marginally from 10,039,219 MT in 2012-13 to 10,342,565 MT in 2013-14 even while imports fell from 2,120,996 MT in 2012-13 to 1,292,099 MT in 2013-14. The DI was unable to increase its supply of HRCs to the Domestic Market to make good for the significant decrease in imports. This is a clear indication of the lack of correlation between increased imports and domestic sales.
- k. The capacity utilization of the DI increased from 4,429,604 MT in Q4 2014-15 to 4,456,795 in Q1 2015-16. It is pertinent to note that JSW, which is one of the Petitioners in the present Petition/Applicants, topped the industry in capacity utilization. In the fourth quarter of 2014, it operated its plants at 90 per cent rated capacity. JSW's revenue run-rate clearly indicates that it had higher utilization levels compared to its peers.
- 1. In addition, Steel Authority of India Limited ("SAIL"), which is one of the Petitioners in this investigation announced a production of 15.4 million tonnes (MT) of hot metal in financial year 2014-2015, registering an increase of 7% over the financial year 2013-2014 and its saleable production was 13.5 MT which was 3% higher than the previous financial year.
- m. The decline in capacity utilization if any in Q2 2015-16, is due to excess newly added capacity by the DI with no corresponding increase in demand. The recent report of India Ratings and Research (Ind-Ra) which expects the capacity utilization of Indian steel manufacturers to decline, as close to 12-14 million tonnes of crude steel capacity will come on board by FY16 with no significant hike in consumption demand. The report found that the total Indian capacity for FY15, was 46 per cent higher than at FY10 ,whereas, the domestic steel consumption growth, which was a robust 11.9 per cent during FY11, had declined by 2.4 per cent each year over the last two years due to a slump in construction, capital goods and automobile industries. This also demonstrates that the increased inventory of the DI is not caused by the pressure from increasing imports but from the over-production by the DI.
- n. Reduced capacity utilisation is also due to the inefficiencies of the Indian Steel Mills and challenges in infrastructure, building design and engineering capabilities and high production costs due to shortage of raw material
- o. The reasons for high operating expenditure can be attributed to reasons like handicaps in capacity building and generation, delayed implementation of their projects due to land acquisition and environmental clearances, less or no lending support by the Government, exposure to global price shocks, competitive products both in terms of price and quality from other countries, lower-quality iron ores which require more coal, and lower quality of coal.
- p. These are challenges that cannot be resolved by imposing Safeguard duties on imports. It is pertinent to note that even after the imposition of Safeguard Duties, Moody's Investors Service cut JSW Ltd.'s outlook to negative this November and Fitch Ratings has also observed that the safeguard duty on certain steel products would not be adequate to reform the Steel sector.
- q. The DI has claimed excessive confidentiality in the non-confidential version of the post-hearing written submissions filed with the Authority with respect to the inventories lying unsold with them. The DI has also not provided data on how long does the DI take to turn its inventory into sales, so as to ascertain the "Days Sales on Inventory" value. In light of the lack of data, the Authority is requested to put the DI to the strict proof of the same.
- r. The DI has provided indexed figures for profits, instead of actual figures despite the fact that all the companies are listed companies.
- s. ROCE of the DI has not only been positive but also shows signs of improvement and recovery in the first quarter (Q1) of FY 2015-16 in comparison to FY 2012-13.
- t. Unforeseen developments alleged by the DI in their submissions are neither unexpected, nor reasoned and adequate, and neither has the Authority been able to demonstrate such alleged unforeseen developments resulted in surge in imports of specific category of products under the product under consideration.
- u. The DI has only alleged general arguments with reference to "steel", as a whole, which is clearly not the PUC and not been able to address each specific product under the PUC. The alleged developments mentioned by the DI have a global scenario and as such their impact is not just "India specific".
- v. Imposition of safeguard duty is inconsistent with India's obligations under the India-Korea CEPA. It could severely strain the relations between the two countries and risk jeopardising any future investment from Japan into India.
- w. In light of the above, the Authority may terminate the investigation, recall the preliminary findings and decline to apply a safeguard measure on imports of the PUC. Alternatively, the Authority may exclude the hot-rolled coils exported by the Japanese Mills as identified in Annexure 1 of the post-public hearing written submissions dated 23 November 2015 from the scope of the PUC as the products exported by the Japanese Mills significantly differ from those produced in India in terms of quality and specifications.

XII. Rejoinder by Nippon Steel & Sumikin Pipe India Co., Ltd. (NPI) represented by M/s. AZB & Partners

- x. NPI reiterates its arguments contained in its submissions dated 9 November 2015 and 23 November 2015 and requests the Authority to read NPI's rejoinder in conjunction with these submissions
- y. The DI's post hearing submissions do not provide adequate evidence that is necessary for the initiation of a safeguard duty investigation on imports of the subject goods.

- z. The DI does not manufacture the kind of HRC that is identical or alike in all respects to the products imported by NPI.
- aa. The DI had requested exclusion of API Grade Steel based on end-usage substitutability. On similar lines, NPI also requests that the products imported by them are not substitutable with those produced by the DI as these are guided and tailored to meet its end consumer preferences and specifications. Therefore, the type of HRC imported by NPI are not like or directly competitive with the HRCs produced by the DI. The Authority should examine if DI is manufacturing the specific grades of HRC imported by NPI and accordingly, exclude the same from the scope of the product under consideration.
- bb. NPI's customers are original equipment manufacturers and Tier 1 parts makers' who supply parts to automobile manufacturers including ****. NPI's customers require highly customized products, which undergo different levels of testing mainly in Japan before being approved by customers. NPI imports very specific types of HRCs to make automotive pipes and tubes required by its customers in India.
- cc. The products with specifications imported by NPI from Japan are not produced by the Domestic Industry or have not been granted approval from end customers despite of the local availability.
- dd. The HRCs imported by NPI to India differ in "Tensile strength", "Steel cleanness", "Grain size", and "Chemical composition" (especially for the nitrogen, controlled range is much narrower than domestic one), all of which are tailored to meet the specifications prescribed by the end user. Due to the highly specific and specialized nature of each product type imported into India, even minor differences can lead to substantial differences in quality.
- ee. The DI does not manufacture all types of automotive-grade steel and that industrial users must import this steel in order to meet their requirements. Importation of the PUC into India is necessary to meet the needs of the downstream auto industry.
- ff. NPI imports HRCs for use in manufacture of automotive pipes that Indian domestic steel manufacturers (i) are unable to provide with sufficient quality specifications or (ii) have not obtained the approval from the ultimate end users (i.e., the automobile manufacturers). The vast majority of these imported coils are raw materials used in the manufacture of automotive pipes used in automotive parts and which are necessary to ensure automobile safety and fuel efficiency through reduced weight of vehicles. The specifications in relation to the quality of these products are particularly strict.
- gg. These strict specifications pertain to formability, appearance and size of the relevant automotive parts. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation ("NSSMC"), which is NPI's parent company and a producer and exporter of Hot-rolled Coils, is able to satisfy these specifications by precisely controlling the chemical composition, mechanical characteristics, surface quality and size of the products. Thus, when NPI needs to import these special coils, it imports such coils produced by NSSMC. Other than these special coils, NPI procures its materials for automotive pipe production from Indian domestic steel manufacturers.
- hh. NPI is not able to use all HRCs produced by the Domestic Industry because the Domestic Industry has not secured industrial user approval for their products. In this regard, it is submitted that once a supplier is selected by the end-customer, the supplier cannot be changed during the lifetime of the model to maintain consistency in product quality and the long term nature of supply contracts. If safeguard measures are imposed, the automotive user will continue to import the PUC at higher prices and be forced to pay higher prices which will be passed on to the customers.
- ii. The DI have not furnished any evidence of the actual manufacture of the specific type of hot rolled flat products being imported into India by NPI from Japan. To establish that the products were manufactured by them, the DI ought to have furnished technical information affirming the likeness (in all respects) of their products with the imported hot rolled flat products. The DI's failure on this critical requirement is fatal to the ongoing investigation and for this reason alone the investigation must be terminated.
- jj. Notwithstanding this submission, NPI submits that the HRCs imported by it are distinct from the products manufactured by the Domestic Industry. The products being imported by NPI differ from the products manufactured by the Domestic Industry in terms of their physical characteristics, chemical composition and end usage. Specifically, the HRCs imported by NPI differ in "Tensile strength", "Steel cleanness", "Grain size" and "Chemical composition" (especially for the nitrogen, the controlled range is much narrower than domestic one).
- kk. NPI therefore requests the Authority to exclude from the scope of the PUC, imports used for the production of Tortion beam, door impact beams, stabilizers in automobiles, front forks in motorbikes and other products imported by NPI listed in Annexure 1 of the Confidential Version of its post-public hearing written submissions dated 23 November, 2015. These imports are either not produced locally by the Domestic Industry with quality specifications required by the Indian industrial users of the PUC or have not yet been granted approval from OEMs.

- XIII. Rejoinder by China Iron and Steel Association; Angang Group Hong Kong Co. Limited; Angang Steel Company Limited; Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Limited; Angang Group International Trade Corporation; Baosteel Singapore Pte Ltd; Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.; Benxi Iron & Steel (Group) International Economic & Trading Co., Ltd.; Jiangsu Shagang Group; Handan Iron & Steel Group Co., Ltd. and Rizhao Steel Wire Co. Ltd represented by M/s. Athena Law Associates
 - a. The submissions made by the above entities in their previous submissions have not been repeated here for the sake of brevity.
 - b. Applicant has resorted to excessive confidentiality in the written submissions and also meaningless summaries are provided to other parties. The Applicant has reduced the process of the rejoinder on crucial aspects to a meaningless exercise by restricting even bare minimum information to the opposing interested parties.
 - c. Applicant is silent on a viable and creditable adjustment plan. Applicant has stated on page 39 of petition that an adjustment plan has been provided separately along with the producer questionnaire response but the producer specific questionnaire is not part of the petition but rather is a separate document. In addition, the producer specific questionnaires also do not have a creditable adjustment plan. In an application filed by United Phosphorus in 1999 for safeguards duty imposition, the authority refused to impose a safeguard duty on the ground of lack of an adjustment plan.
 - d. The preliminary determination did not contain anything to show the urgency and critical circumstances to warrant imposition of preliminary duties.
 - e. The product scope consists of a number of specialty grades which are not homogenous items inter se to fall in one basket. Expansion of the product scope to stop evasion of duty is neither the remedy nor the permissible method.
 - f. Other producers should also be required to provide injury information considering the disputable position of alleged injury to the Applicant.
 - g. Alleged injury is self-inflicted on account of high interest burden, capacity pressures, dumping, FTA, raw material crisis, etc that have caused pressure on the performance of the Applicants as evident in their annual reports.
 - h. The points below establish that the Applicant are not suffering serious injury or threat of serious injury:
 - i. Major parameters such as production, sales, capacity, utilization, inventory employment, productivity and ROCE have improved in comparison to the previous year.
 - ii. Indian producers hold 88% of domestic demand and imports are merely 12% which is incapable of inflicting serious injury on the domestic industry.
 - iii. Alleged injury is due to high interest and fixed cost burden on account of excess capacity.
 - iv. No price pressure from imported products as landed price of imports were higher than the selling price.
 - v. Selling price of domestic industry being lower than landed price is a *prima facie* indication of *inter se* competition between the Indian producers.
 - Applicant has made certain claims on the methodology of calculation of landed price for computation of price undercutting/underselling which has no legal or factual basis. Landed value should be computed as per its consistent practice.
 - j. Applicant has cited towards 4 instances for unforeseen developments and 3 of the instances are anti-dumping duties. Applicant has failed to establish unforeseen developments which triggered the alleged situation of injury to the Applicant.
 - k. The increase in imports from Russia, Ukraine, China and EU on account of geopolitical tensions, excess capacity and currency depreciation has been cited as unforeseen developments. However, the trend share of imports from the aforesaid countries contradicts submission of the Applicant:

Share of Country	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16(Q1)
China	18.94%	14.01%	24.06%	28.65%	14.72%
EU-27	15.82	10.38%	1.20%	0.67%	0.74%
Japan	18.34%	29.25%	36.50%	30.79%	35.15%
Korea	14.94%	18.53%	12.97%	25.70%	41.11%
Russia	12.88%	10.56%	3.62%	5.55%	4.56%
Ukraine	7.92%	0.67%	6.34%	3.08%	3.63%

- 1. The above data shows that imports from China diminished by almost 50% between FY2014-15 and FY2015-16(Q1). Therefore, there is no sudden and sharp increase in imports from China due to unforeseen developments.
- m. Applicant has not established the reasons for which it was forced to sell at a price less than that of the import price when there was ample room to keep the prices at significantly higher levels.

- n. The Annual Reports of JSW indicate that other reasons have a serious bearing on their performance. The other circumstances must be examined by the Authority under the non-attribution analysis.
- o. Therefore, there is no causal link as the annual reports admit that the cause of injury is duping and issues related to FTA regime, price undercutting has constantly been negative, injury claimed in 2015-16 when imports were declining, imports increased in 2014-15 when domestic industry earned profits. Reasons for any alleged injury is solely other reasons and any such alleged injuries are not driven by any sudden and sharp surge in imports.

XIV. Rejoinder by POSCO, Korea and POSCO Maharashtra Steel Private Limited represented by M/s. Shardul Amarchand Mangaldas& Co.

- d. The parties relied on all their earlier submissions.
- e. The data provided in the petition is not from an authentic source. The petition is based on data from a private agency rather than from JPC data. The JPC data is based on information provided by the Applicants and TATA Steel.
- f. The injury analysis has been done based on information only for the first quarter of 2015-16 and 2013-14 has been selected as the base year as it was the worst period in the history of the steel industry.
- g. The volume of the PUC imported and captively consumed by POSCO must be excluded while calculating the market share of imports.
- h. The Applicants consume almost 34% of the PUC captively for production of downstream goods and therefore the aforesaid quantity of the PUC does not compete in the domestic market and must be excluded from the total demand of PUC in the market. The Authority in the safeguards investigation concerning imports of Sodium di-Chromate terminated the investigation in similar circumstances.

	Domestic Sales	Captive consumption	% of PUC captively consumed
2013-14	10,342,565 MT	4,274,000 MT	30%
2014-15	9,949,214 MT	5,019,741 MT	34%

- The Applicants are already enjoying protection in the form of high rate of customs duty applicable on imports of PUC.
- j. The scope of the PUC is very large and the products under sub-headings 7225 and 7208 are not identical and are plural and heterogeneous in nature and this cannot be put together in one basket.
- k. The end-to-end point analysis of the imports of the PUC is not the appropriate methodology for evaluating surge in imports. The findings in *US-Certain Steel Products* makes it clear that examination of increase in imports must not be restricted to mere end points but rather a wider examination of the facts must be done.
- 1. The volume of PUC imported by POSCO should be excluded while evaluating a sudden surge in imports of PUC during the POI. POSCO Maharashtra captively consumes 90% of the PUC imported by it and are not competing in the domestic market. The import data must distinguish between imports offered for sale directly in the merchant market from that of the volume used for captive consumption. POSCO Maharashtra imported nearly 427,800 MT from POSCO Korea in 2014 and 118,132 MT during the first quarter of 2015, most of which was captively consumed. If this volume is excluded from total volume of imports, there would be no surge in imports. Evidence of captive use has been provided in the Form ER-1.
- m. The Authority has failed to undertake a uniform method of calculation in deriving a percentage market share of imports and percentage market share of domestic industry in the preliminary findings. Captive consumption of domestic industry and domestic producers has been included while calculating total demand of the PUC in the market but captive consumption of domestic industry has been excluded while calculating its market share. Therefore, total demand is inflated by inclusion of captive consumption and market share has been deflated and distorted by exclusion of captive consumption.
- n. The market share lost by the Applicants has been taken up by other domestic producers.
- o. The alleged injury caused to the Applicants is at best self-inflicted injury. The decrease in sales of the domestic industry is on account of quality issues in the PUC supplied by the Applicants. The PUC supplied by the domestic industry can only be used by POSCO to manufacture for industries which need low quality such as construction and general engineering. Exhibits have been provided relating to the quality issues faced and the grades which do not meet quality requirements.
- p. Reasons for the alleged decrease in sales of domestic industry are due to: (a) underutilization; (b) high debt/finance cost (being a capital intensive industry); (c) PIC when exported by domestic industry are those prevalent in the global market; (d) PUC when sold by domestic industry is much higher than the global/international prices.
- q. The landed price of imports are higher than the prices of the domestic industry as evident from the negative price undercutting. This shows that imports are not offered at lower levels to penetrate into the Indian market.

- r. Safeguard action is a fair trade measure and while imposing such measures countries should take into account its exceptional nature. It should be adopted only in emergency situations.
- s. The claims relied upon by the Applicants for unforeseen developments such as the crisis in the global steel market, geopolitical tension, depreciation in currency, slow-down in China, huge surplus capacities in China and Japan, trade measures by other countries, etc do not establish existence of unforeseen developments. There is no logical connection between the aforesaid circumstances and unforeseen developments.
- t. Imposition of the duty would be in direct contravention of the India-Korea CEPA. Article 22.7 in the CEPA mandates that a party taking a safeguard measure under Article XIX of GATT 1994 and the Safeguards Agreement may, to the extent consistent with the obligations under the WTO Agreement, exclude imports of an originating good of the other party if such imports are not a substantial injury or threat. Imports of the PUC from Korea fall under this clause.
- u. The imports of PUC have been at global prices as evident from the fact that the Indian HR Coil producers also exported the same product at global prices, well below the domestic prices apparently to retain shortages and high prices in the domestic market.

XV. Rejoinder by Federation of Industries of India (FII) to the submissions of Domestic Industry post public hearing

- a. Import of HR Coil in thickness of 1.2mm, 1.4mm & 1.6mm as these thicknesses are either not produced by the domestic steel producers or are scarcely available, be place under exemption category in the Safeguard Duty Notification.
- b. HR Coils in grades such as SAE 1541, SAE 1020 / 1040 / 1045 / 1050 / 1055, SCM 435, Boron Steel, 16 MnCr5, SAE 1006 / 1010 & ST 52.3 imported for automobiles applications, the domestic availability of which is not only limited but also erratic, be also placed under exemption category in the Safeguard Duty Notification.
- c. HR Coil for which import contracts were signed and for which irrevocable financial arrangements were made long before the date of issue of the SGD Notification and the imported material was also in transit, should not attract Safeguard Duty.
- d. HR Coil imported for captive consumption should not be included in the import figures shown in the Domestic Producers petition to prove injury.

XVI. Rejoinder by Cold Rolled Steel Manufacturers Association of India (CORSMA)

- a. Prescribed procedure for preliminary investigation and soliciting views of all stakeholders for a rational decision in the matter was not adhered to by D.G. Safeguards and decision to impose the 20% duty taken within 3 days, ignoring even the information available with D.G. Safeguards that in the past 2 Petitions for the imposition of Anti-Dumping duty on imports of HR Coils were rejected by the designated Authority as well as Calcutta and Delhi High courts due to misrepresentation of facts. Besides, safeguard duty Directorate itself had rejected a similar Petition by HR Coil producers, based on the same grounds in 2009, in breach of Articles X and Articles XIX of the GATT Agreement as well as Indian customs Tariff Act.
- b. Apart from the foregoing, D.G. Safeguards while recommending the imposition of Provisional duty of 20% as demanded by the Petitioners has arbitrarily reduced the period of investigation to 2.5 year against the norm of 5 years, which is essential to establish the casual relationship between domestic production and imports, surge in imports and reasons thereof.
- c. The Petition is not based on data published by official data bank i.e. Joint Plant Committee/Ministry of Steel, which is utilized for policy decisions by the Ministries of Steel, Commerce and Industry and Finance but data from a private Agency. Besides, the data has been twisted and manipulated by dividing into groups and subgroups, expressing the variations in percentages rather than the authentic figures.
- d. The Petitioners have mentioned six specifications which may be exempted from the Safeguard duty since the domestic industry is unable to produce the requisite quality and meet the demand. However there are another half a dozen qualities/thicknesses which are not available from the domestic sources.
- e. The gap between domestic availability and consumption in April-September 2015 was 1.757 million tonnes as per JPC Report, necessitating imports of 1.852 million tonnes, including qualities, sizes not available from domestic sources and imports for export production.
- f. Allegation of cheap imports of Steel from China flooding the Indian market is also baseless as imports from China constituted only 28% of total imports in April-June 2015 while for HR Coils it was around 30%.
- g. The allegation of surge in imports in April-July 2015 is entirely misleading and as it does not explain the reasons for rise in imports in April-July 2015 y.o.y.,
- h. Steel is raw material based industry and raw material account for 70% of the production costs of Steel including HR Coils. The global and domestic prices of basic inputs for steel-making have registered a

- steep decline in the past one year leading to a decline in the global prices of HR Coils. The imports of HR Coils have been at global prices.
- i. There has been no flood of imports as alleged by the Petitioners and imports for industrial development have not caused any injury to domestic industry.
- j. The Petitioners have alleged that the domestic producers have suffered an injury due to rise in inventories due the high imports but as per data published by JPC there has been no rise in inventories.
- k. It may be clarified that there have been no sudden and unforeseen developments in the global Steel industry in the year 2014-16.
- 1. The imports essential for industrial and economic development of the country have not caused an injury to Indian HR Coil producers and injuries are self-inflicted due to factors like neglect of technological up gradation and heavy debt and interest burden.
- m. The Petitioners should explain that why the threat is always confined to only HR Coils and not to other Steel products. In fact the foreign producers in the prevalent recessionary conditions prefer to export cold rolled products to optimize capacity utilization of both Hot Rolling and Cold Rolling Mills and the governments also offer higher incentives on the exports of Cold Rolled products. The Petitioners are also major producers of Cold Rolled products but always petition for hike in duties on HR Coils apparently to exploit monopolistic potential.
- n. Indian HR Coil producers are already over protected by customs duty of 12.5% or USD 40 per MT at the current global price of USD 300 PMT, overage ocean freight of USD 30 PMT, Port, Financial and incidental charges of USD 15 per MT adding up to USD 85 (Rs 5500) PMT.
- o. The impositions of additional 20% Safeguard duty has added another USD 60 PMT and enabled the domestic producers to hike prices based on import parity basis by USD 149 (Rs 10,000) over and above the global prices. It is be disastrous for the manufacturing sector and instead of HR Coils shall lead to imports of value added Cold Rolled products and manufactured goods and sharp reduction in exports. Apart from customs duty of HR Coils are also protected from imports by technical barriers on imports.
- p. The high prices of HR Coils have eroded the global competitiveness of downstream Cold Rolling and the manufacturing sector has led to imports of value added Steel and manufactured products including Engineering goods, Components and Spares, Plant and Equipment, hitting the Indian industry, particularly the SMEs, resulting in retrenchment of workers.
- q. The arbitrary hikes in customs duties after the Union Budget of 2015 and imposition of Provisional Safeguard duty in undue haste have destabilized downstream industries.
- r. Indian producers have lagged behind South Korea, China and other countries due to protectionist policies and neglect of R & D, in the past decade. There is ample scope for reduction in production costs through technology to make globally competitive.
- s. The Petitioners have mentioned six grades of HR Coils which may be exempted from Safeguard duty as these are not available from the indigenous sources. However there are should more grades like SAE 1541, SAE 1040/1050/1055 and Steels for the production of Auto Beams etc. which are not available from domestic sources.
- t. Steel is a basic input and raw material for industrial and infrastructure development but it is presently subject to heavy Tax burden starting from levy of Royalty on Iron ore, levy of 12% Excise duty and Taxes by State Govts. and local bodies. It is necessary to reduce the Tax burden to stimulate industrial production and infrastructure development as well as higher consumption Steel and Steel products by the Common man. The Excise duty on all Steel products may be reduced from 12.5% to 10% to stimulate industrial development.

XVII. Rejoinder by Bombay Iron Merchants Association represented by M/s. MV Kini Law Firm

- a. The submissions made by the above party in their previous submissions have not been repeated here for the sake of brevity.
- b. In regard to API Grade exclusion, allegations cannot be made only on media reports. Every user has a choice to use material as permitted by their project authority and importer cannot assert any control over where the material is eventually utilised.
- c. DG Safeguards should not be interfering in customs issue as customs is well equipped to do so.
- d. Petitioner cannot decide the end use of a particular grade. The ultimate decision is of the user. The end use is always indicative in nature and not binding. It is preposterous to suggest that some of India's importers are importing PUC in guise of API.
- e. For the recent surge in imports in Q2 of 2015-16, DG must obtain factual data for the period for which plants of the domestic industry were under maintenance or under restricted production capacity. Reduced availability as well as their own imports has been one of the major causes of increased imports.

- f. Imports in 2015-16 should be considered in light of various other factors such as imports for captive consumption, imports by petitioners and for export and advance licenses and bifurcation of alloy and non-alloy steel etc.
- g. Evaluation period of 2 to 3 years seems short. "Sudden and sharp" surge needs to be evaluated over such periods and not 1 or 2 quarters.
- h. Measures in US and Turkey have been of anti-dumping duty which is completely different from the situations required for safeguard duty.
- i. The Applicants have considered a cluster of products. To ascertain the necessity of the imposition of the safeguard duty, imports undertaken with respect to each of these products have to be confirmed. Furthermore, it is important to segregate the products combined by the Applicants as the production capabilities of the Applicants to produce alloy steel products are negligible.
- j. The problems faced by the Applicants are not related to increased imports but due to the factors such as high debts, oppression and mismanagement issues in case of Bhushan Steel, problems in procurement of raw materials in case of Essar Steel.
- k. Alloy steel is produced in negligible quantities in India, thus question of imposition of safeguard duty does not arise. In respect of non-alloy steel, Applicants cater to about 92-93% of the total market share of domestic demand. Thus, even this category of PUC does not require imposition of safeguard duty.
- 1. If imports in 2014-15 are compared with 2011-12, the increase is only about 9% and cannot be regarded as surge. While alleging surge in imports in 2014-15 over 2013-14, a due thought has not been given to abnormal drop of roughly 40% during the period.
- m. If imports by POSCO Maharashtra are excluded, then it would rather show a slump in imports.
- n. The major applicants have shown a rise in turnover, thus the question of any alleged injury does not arise at all. There has been a consistent increase in the employment costs of the applicants.
- o. Raw material imported under advance license is used in manufacturing of the finished goods which are exported. Such imports could not impact the India domestic market.
- p. The applicants have relied on data provided by IBIS, an unrecognized private agency ignoring the official JPC data available.
- q. Despite a drop in international raw materials, the prices in the domestic market have not reduced and are much higher than the export prices.
- r. The Applicants themselves are importing cheaper raw materials.
- s. The alleged surge in imports during July-Sept 2015 is on account of huge imports of the subject PUC by the applicants themselves, specifically, JSW Steel Ltd.
- t. In view of the timelines of events followed in the present case, it clearly shows an undue haste in the imposition of safeguard duty.

XVIII. Federation of Association of Maharashtra (FAM) represented by Advocate Tavinder Sidhu

- a. The submissions made by the above party in their previous submissions have not been repeated here for the sake of brevity.
- b. In regard to API Grade exclusion, allegations cannot be made only on media reports. Every user has a choice to use material as permitted by their project authority and importer cannot assert any control over where the material is eventually utilized.
- c. Petitioner cannot decide the end use of a particular grade. The ultimate decision is of the user. The end use is always indicative in nature and not binding. It is preposterous to suggest that some of India's importers are importing PUC in guise of API.
- d. For the recent surge in imports in Q2 of 2015-16, DG must obtain factual data for the period for which plants of the domestic industry were under maintenance or under restricted production capacity. Reduced availability as well as their own imports has been one of the major causes of increased imports
- e. Imports in 2015-16 should be considered in light of various other factors such as imports for captive consumption, imports by petitioners and for export and advance licenses and bifurcation of alloy and non-alloy steel, etc.
- f. Evaluation period of 2 to 3 years seems short. "Sudden and sharp" surge needs to be evaluated over such periods and not one or two quarters.
- g. Measures in US and Turkey have been of anti-dumping duty which is completely different from the situations required for safeguard duty.
- h. The problems faced by the Applicants are not related to increased imports but due to the factors such as high debts, oppression and mismanagement issues in case of Bhushan Steel, problems in procurement of raw materials in case of Essar Steel.
- i. Alloy steel is produced in negligible quantities in India, thus question of imposition of safeguard duty does not arise. In respect of non-alloy steel, Applicants cater to about 92-93% of the total market share of domestic demand. Thus, even this category of PUC does not require imposition of safeguard duty.

- j. If imports in 2014-15 are compared with 2011-12, the increase is only about 9% and cannot be regard as surge. While alleging surge in imports in 2014-15 over 2013-14, a due thought has not been given to abnormal drop of roughly 40% during the period.
- k. If imports by POSCO Maharashtra are excluded, then it would rather show a slump in imports.
- 1. The major applicants have shown a rise in turnover, thus the question of any alleged injury does not arise at all. There has been a consistent increase in the employment costs of the applicants.
- m. Raw material imported under advance license is used in manufacturing of the finished goods which are exported. Such imports could not impact the Indian domestic market.
- The applicants have relied on data provided by IBIS, an unrecognized private agency ignoring the official JPC data available.
- o. Despite a drop in international raw materials, the prices in the domestic market have not reduced and are much higher than the export prices.
- p. The Applicants themselves are importing cheaper raw materials.
- q. The alleged surge in imports during July-Sept 2015 is on account of huge imports of the subject PUC by the applicants themselves specifically JSW Steel Ltd.
- r. In view of the timelines of events followed in the present case, it clearly shows an undue haste in the imposition of safeguard duty.

XIX. Additional submissions by the Domestic Industry after Introduction of Minimum Import Price (MIP) by Ministry of Commerce

After the introduction of MIP on Steel products by the Ministry of Commerce vide Notification No. 38/2015-2020 dated 5th February 2016, Domestic Industry, in response, have made the following additional submissions:-

a. The domestic industry vide their letter dated 17/02/2016 stated as follows: -

"Recently, DGFT has issued Minimum Import Prices (MIP) on items being imported under Chapter 72 of ITC (HS), 2012 vide Notification No. 38/2015-2020 dated 5 February 2016. It is pertinent to note that MIP is in force for a period of six months or until further orders by DGFT, whichever is earlier. This means that MIP could be revoked at any time before the six months period.

It is worthy to note that the domestic industry has requested for imposition of safeguard duty for a period of 3 years. Though MIP addresses most of the concerns of the domestic industry, but it is in place only for six months or a lesser period. Once MIP expires, the domestic industry would be left without any protection from the surging imports at predatory prices. It is submitted that only safeguard duty is a more efficacious and long term remedy for protection of the domestic industry. In light of this, it is most respectfully requested that the DG Safeguards may be pleased to conclude the captioned investigation and recommend definitive safeguard duty on the subject goods.

To avoid any confusion of the applicable levy, safeguard duty may be levied from the date when MIP expires"

b. The domestic industry vide their another letter 17/02/2016 further stated as follows:-

"It is respectfully submitted that levy of provisional safeguard duty has not been able to protect the domestic industry as exporters of the subject goods have absorbed the 20% ad valorem duty in their prices. Further, many users in India have also raised concerns that even if they import the subject goods at more than the fair prices (including special grade steels), they are still subject to 20% ad valorem duty. To address the concerns of both the domestic industry and users in India, it is requested that the DG Safeguards may be pleased to levy safeguard duty on reference price basis."

E. EXAMINATION & FINDINGS OF DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)

- 14. I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producers, users/importers, exporters and exporting nations. The written submissions and the rejoinder submissions made by them have also been considered appropriately. The submissions made by various parties and the issues arising there from are dealt with at appropriate places in the findings below:
- 15. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports. Its sub-section (1) provides for imposition of Safeguard duty by the Central Government on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.

- 16. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provides the manner and principles governing investigation.
- 17. The investigation has been conducted in accordance with the said rules and the Final Findings are recorded through this notification.

A. The Product Under Consideration (PUC):

- 18. The product under consideration (hereinafter referred to as PUC) in the present case is "Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more" classified under Customs Tariff sub-heading nos. 7208 and 72253090 of Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975. The applicant has claimed that these products are not further worked than hot-rolled and are flat products of iron, alloy or non-alloy steel, in prime or non-prime condition having 'as-rolled' edge or 'trimmed' edge or 'slit' edge. These products may be pickled or non-pickled (with or without skin-pass or tempering), slit or non-slit and having nominal width of greater than or equal to 600mm. These products may be as-rolled or thermo-mechanically rolled or thermo-mechanically controlled rolled or controlled rolled. These products may have patterns in relief derived directly from rolling. These products may have been subjected to various processing steps like pickling, oiling, rewinding, temper rolling, heat treatment, etc. The following are not included in the scope of the product under consideration:
 - a) Hot-rolled flat products of steel with nominal width less than 600mm;
 - b) API grade steel;
 - c) Silicon electrical steel;
 - d) Hot-rolled flat products of steel of spring steel quality;
 - e) Hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc;
 - f) Hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc; and
 - g) Hot-rolled flat products of stainless steel.
- 19. Domestic Industry has submitted that they have observed from various reports in media that some of the Indian importers / foreign exporters are trying to evade the provisional safeguard duty applicable on commercial / base grade structural steels (meant for conventional structural applications) in the guise of 'API 5L' grade. Therefore, Domestic Industry requested that inclusion of the following explanation in the exclusion clause of API Grade Steel will help the customs authorities to effectively enforce the exclusion of API Grade Steel in proper spirit:
 - "API Grade Steel refers to steel intended for manufacturing welded steel pipes used for pipeline transportation systems in the petroleum and natural gas industries"
- 20. In this regard, some of the interested parties objected to this and submitted that allegations cannot be made only on media reports. Every user has a choice to use material as permitted by their project authority and importer cannot assert any control over where the material is eventually utilized and also petitioner cannot decide the end use of a particular grade. The ultimate decision is of the user. The end use is always indicative in nature and not binding. It is preposterous to suggest that some of India's importers are importing PUC in guise of API. I observe that the scope of the PUC can not be enhanced at a later date after the issue of notice of initiation. API grade can be defined only by the published API specifications, not by the type of use to which these are put to. Therefore, the PUC in this case remains the same as described above.
- 21. Several interested parties have raised issues on the product under consideration. All such issues are addressed below:
 - i. <u>HR Coil in thickness 2.00 mm and below</u>: M/s Nezone Strips Ltd. and M/s Nezone Tube Ltd. argued that they have been importing HR coil in thickness 2.00 mm and below because their regular supplier M/s Tata Steel Ltd. had stopped supplying due to availability constraints. Therefore, they are forced to import this specific product and such products should be excluded from the product scope. I observe that the interested parties have not stated to have made any efforts to procure the same from the domestic market nor have they stated anywhere that other Domestic Producers can not supply them the goods. Therefore, their contention is not accepted.
 - ii. Automotive Grade of HR Coils:
 - M/s Hyundai Motors India Ltd. submitted that Korean Automotive Grade Steel should be exempted from safeguard duty as even after imposition of safeguard duty, they will have to necessarily import this product as their Nanyang R&D Centre does not allow them to change the specifications for the cars manufactured in India. Applicants in their submission have objected that Automotive Grade of HR Coils is a very generic description and cannot be excluded unless they substantiate that Indian steel producers cannot supply this grade. Just because their R&D centre will not allow them to procure from elsewhere does not mean that the domestic

industry should be allowed to suffer serious injury by exempting imports of this grade from safeguard duty. I find no reason to disagree with the contention of the Domestic Industry.

- iii. Claims by Tube Investments of India Ltd. (TII):
 - a) TII argues that the following grades should be excluded from the product scope due to limited availability, quality issues and because TII has already identified and approved sources of supply which they cannot change now:
 - a. SAE 1541
 - b. SAE 1020/1040/1045/1050/1055
 - c. SCM 435
 - d. Boron Steel
 - e. 16 MnCr5
 - f. SAE 1006/1010
 - g. ST 52.3
 - b) In this regard the DI submitted that they have not filed any material evidence to substantiate their claim for exclusion from the product scope and hence claims or issues are merely based on conjectures. Therefore, these grades cannot be excluded from the product scope. I observe that merely because the interested party has an approved source of supply, it can not be a reason to exclude them from the Safeguard action. They can also start the process of approving the domestic sources of supply, as well.
- iv. Hot-rolled coil with pickling and oiling ("PO"): M/s Hyundai Steel Korea argues that PO products manufactured by them are sold to M/s Hyundai Steel India Limited, which, in turn sells it to M/s Hyundai Motor India Limited. They argue that such imports are inevitable as stopping it would mean risking safety of passengers in automobiles. They argue that PO products should be kept outside the product scope. Domestic Industry strongly object to this contention and submit that Domestic Industry have proven capability to manufacture Auto Grade Steels including steels suitable for higher strength levels. I observe that Indian steel industry is sufficiently advanced to provide the necessary grades of steel and hence the contention of M/s Hyundai Steel Korea is not accepted.
- v. Hot-rolled coils based on narrowly defined customer specifications: M/s Nippon Steel & Sumikin Pipe India Co. Ltd. argues that hot-rolled coils based on narrowly defined customer specifications should be excluded from the product scope as these imports differ in tensile strength, steel cleanness, grain size and chemical composition. M/s Nippon Steel & Sumikin Pipe India Co. Ltd. has, however, claimed confidentiality on the description and types of products they have imported but they have requested exclusion of these products from product scope. The domestic industry in reply raised objections that the specific grades or types of products have not been shared with the domestic industry and hence they are not in a position to defend its interest. In this regard I reiterate my observations that the Indian industry is sufficiently advanced to supply diverse grades of steel.
- vi. Grade JSH 270/370 and Grade JSH 590: M/s Maruti Suzuki Ltd. argues that these two grades should be excluded from product scope as these are special grades of steel which are imported to meet requirements of customer safety and meeting emission norms. They argue that domestic manufacturers cannot meet the required quality standards and are inconsistent suppliers of raw material. Petitioners strongly object to the above contentions. I find that the Indian steel industry is sufficiently advanced and capable of supplying different grades of materials.
- Alloy Steel: Federation of Association of Maharashtra ("FAM") argues that alloy steel is produced in negligible quantities in India, so the question of imposition of safeguard duty on alloy steel does not arise. They further argue that imports of non-alloy steel constitutes only 7-8% of total domestic production and more than 90% market share for non-alloy steel is with domestic units. FAM further argues that such low imports of non-alloy steel do not warrant imposition of safeguard duty. I find that the main determining factor for a decision on imposition of safeguard duty is not the imports as a percentage of domestic production but whether the domestic industry is suffering serious injury because of the increased imports. So far as alloy steel is concerned, the product scope covers only one tariff item 7225.30.90 and not the entire alloy steel heading. It is further noted that domestic industry have already provided detailed reasons in their letter dated 8 August 2015 as to why alloy steel falling under customs classification 7225.30.90 should be included in product scope. The imports classified as alloy steel under tariff item 7225.30.90 can actually have very minute quantities of boron or other alloying elements to circumvent the classification as non-alloy steel. These imports severely affect the domestic industry, as these imports technically and commercially substitute non-alloy flat products of hot-rolled steel in coils produced by the domestic industry. Due to this reason, domestic industry has included imports under the tariff item 7225.30.90 under the product scope. I accept the contention of the DI on this point. China Iron & Steel Association have also questioned why alloy steel falling under customs tariff heading 7225 has been included in product scope. The above analysis also addresses the contentions made by China Iron & Steel Association.

- viii. <u>High Strength Steel ("HSS")</u>: China Steel Corporation, Taiwan argues that HSS grade used in automobile industry should be excluded from product scope. No material evidence to substantiate their claim for exclusion from the product scope has been produced. As discussed previously, the Indian industry is sufficiently advanced to supply such materials.
 - ix. Steel produced by Japanese Mills: M/s JFE Steel Corporation, M/s Nisshin Steel Co. Ltd., M/s Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation and M/s Kobe Steel Ltd. together argue that special grades steel produced by them should not be subject to safeguard duty and should be excluded from product scope. However, they have not come out with any evidence to suggest that the same can not be supplied by the Indian industry. Hence the argument advanced by them is not accepted.
- 22. In view of above, it is confirmed that the product under investigation is "Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more" classified under Customs Tariff sub-heading nos. 7208 and 72253090 of Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975. These products are not further worked than hot-rolled and are flat products of iron, alloy or non-alloy steel, in prime or non-prime condition having 'as-rolled' edge or 'trimmed' edge or 'slit' edge. These products may be pickled or non-pickled (with or without skin-pass or tempering), slit or non-slit and having nominal width of greater than or equal to 600mm. These products may be as-rolled or thermomechanically rolled or thermomechanically controlled rolled or controlled rolled. These products may have patterns in relief derived directly from rolling. These products may have been subjected to various processing steps like pickling, oiling, rewinding, temper rolling, heat treatment, etc. The following are not included in the scope of the product under consideration:
 - a) Hot-rolled flat products of steel with nominal width less than 600mm;
 - b) API grade steel;
 - c) Silicon electrical steel;
 - d) Hot-rolled flat products of steel of spring steel quality;
 - e) Hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc;
 - f) Hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc; and
 - g) Hot-rolled flat products of stainless steel."
- 23. Accordingly, it is also held that domestically produced "Hot-rolled flat products of non-alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more" falls under the ambit of like or directly competitive article in all respects to the imported product under investigation and that the domestically produced "Hot-rolled flat products of non-alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more" is a like article to the imported "Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more" (fully defined as PUC), within the meaning of Rule 2(e) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997.

B. Domestic Industry (DI):

- 24. Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act 1975 defines Domestic Industry as follows:
 - "(b) "Domestic Industry" means the producers -
 - (i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
 - (ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India;"
- 25. Interested parties argue that Applicant do not qualify as domestic industry in this case. Interested parties rely on the table given under paragraph 25(b) of the preliminary findings and argue that market share of the domestic industry was 45% in 2013-14 and for Indian other producers, it was 51%. Similarly, it is argued that in 2014-15 as well as 2015-16 (Annualised), market share of other producers was 51%. In this regard, I find no merit in this objection as in the table under paragraph 25(b), market share given is a ratio of sales of domestic industry vis-à-vis domestic demand. However, this market share is not a measure of standing because domestic demand figures include figures of imports as well and sale of domestic industry does not include captive consumption.
- 26. The application is filed by M/S Steel Authority of India Limited; M/S Essar Steel India Limited, and M/S JSW Steel Limited and together they account for more than 50% of the Indian production and hence are major producers. It is evident from the table given under Para 13 and Para 25 (a) of the preliminary findings. Accordingly, it is held that the applicant domestic producer constitutes and represents the Domestic Industry (DI) within the definition of DI under Sec 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act,1975.

C. Source of information:

- 27. The product under investigation is imported into India under Custom Tariff Heading 7208 and 72253090 of Chapter 72 of First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The Safeguard investigation was initiated on the basis of import data of IBIS (International Business Information Services) from 2013-14 to 2015-16 (April to June 2015). The domestic data from 2011-12 to 2015-16 (Till June 2015) has been submitted by the domestic industry and the same has been verified by on-site visit by the departmental officers on the basis of excise records to the extent considered necessary. The import data as well as the domestic data from July, 2015 to Sept., 2015 in respect of various economic parameters has been furnished by the applicant, in their written submissions/rejoinder. Many interested parties have argued that import data from a private agency like IBIS is not authentic and tenable and the Authority should consider only JPC data and that a detailed methodology for determining product under consideration is not provided in the petition. Interested parties also argue that DGCI&S data should be used to verify the authenticity of IBIS data used in the petition.
- 28. It may be pointed out that IBIS data has earlier also been used in a number of investigations done by DG (Safeguard). IBIS is a known source of information in the trade and mere allegation of data not being authentic is not tenable. Also, the data from Govt. sources has a time lag and it is not available for the latest period. Therefore, at times, it becomes necessary to source data from reliable private sources as well. However, in the analysis done for the final recommendations, the import data from DGCI&S (Ministry of Commerce) has been taken and it is showing similar trends.
- 29. A few interested parties argue that no additional questionnaire was filed by the constituents of the domestic industry. Therefore, the Authority did not have complete information when preliminary findings were issued. They further argued that no creditable adjustment plan has been provided by the domestic industry and there is no mention of the same in the preliminary findings. In this regard it is observed that the domestic industry had filed their respective questionnaire responses in both confidential and non-confidential versions along with the application itself. Non-confidential versions of the questionnaire responses were also available in the public file. Even though the adjustment plan was not given in the application, all the constituents of the domestic industry had provided a proper adjustment plan in their respective questionnaire responses.

D. Period of Investigation (POI):

30. Some Interested parties argue that 2013-14 should not be considered as base year as it does not take into account the downward trend of imports between 2012-13 and 2013-14. Some interested parties argue that period of analysis should be 5 years and a shorter period is erroneous. In this regard it has been observed that neither the Customs Tariff Act, 1975, nor the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, specifically define 'period of investigation' or the minimum period to be considered for a Safeguard investigation. The WTO Agreement on Safeguards does not contain any general or specific provision or guidelines for choosing the investigation period. However the issue of period of investigation has been dealt in detail in Panel findings in US-Line Pipe Case against Korea (Para 7.196,7.199 and 7.201). The Panel in this case ruled that it is up to the discretion of the investigating authority of the importing Country to decide the "length of the period of investigation" and its "breakdown".

"We note that the Agreement contains no requirements as to how long the period of investigation in a safeguards investigation should be, nor how the period should be broken down for purposes of analysis. Thus, the period of investigation and its breakdown is left to the discretion of the investigating authorities. In the case before us the period selected by the ITC was five years and six months, which is a period similar in length to the one used by the Argentine investigating authority in Argentina — Footwear Safeguard. However, we note that the Appellate Body, in the findings relied upon by Korea to argue the question of the length of the period of investigation, emphasized not the length of the period per se, but that there should be a focus on recent imports and not simply trends over the period examined. In the case of the line pipe investigation the ITC did not merely compare end points, or look at the overall trend over the period of investigation (as Argentina had done in the investigation at issue in Argentina — Footwear Safeguard). It analyzed the data regarding imports on a yearto-year basis for the 5 complete years, and also considered whether there was an increase in interim 1999 as compared with interim 1998. We are of the view that by choosing a period of investigation that extends over 5 years and six months, the ITC did not act inconsistently with Article 2.1 and Article XIX. This conclusion is based on the following considerations: first, the Agreement contains no specific rules as to the length of the period of investigation; second, the period selected by the ITC allows it to focus on the recent imports; and third, the period selected by the ITC is sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding the existence of increased imports." (paras. 7.196, 7.199 and 7.201)

31. In view of above, considering these facts, and source of information stated above, it is considered appropriate to adopt data for the period 2013-14 to 2015-16(annualized on the basis of Q1) for the purpose of the present investigations.

E. Confidentiality of information submitted:

- 32. Rule 7 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 and Article. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provides for confidentiality treatment to certain information. The rules provide that an Interested Party is not required to disclose such information on actual basis which is confidential information of the company and disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of such party, which is not in public domain and which the petitioner has not disclosed before public at large in the past.
- 33. Many interested parties have raised objections that several parameters have been considered as confidential in the petition and no reasons have been provided by the domestic industry for treating them as confidential. Interested parties further argue that even the Authority has not recorded any reasons for granting confidentiality in the preliminary findings. I find that the Domestic Industry provided confidential and non-confidential versions of the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997. Further, the Domestic Industry claimed confidentiality of financial and costing data by way of hiding them in their non-confidential version, which I find appropriate.

F. Increased Imports:

- 34. Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose safeguard duty and provides as follows:
 - "(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to Domestic Industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article:"
- 35. The Rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have "increased in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms or in relation to domestic production.
- 36. Rule 2 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines 'increased quantity' as follows:
 - "(c) "increased quantity" includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production."
- 37. With regard to the nature of the increase in imports, the Appellate Body in *Argentina—Footwear (EC)*, in contrast to the Panel, held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract is as follows:
 - "131. [T]he determination of whether the requirement of imports 'in such increased quantities' is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be 'such increased quantities' as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause 'serious injury'."
- 38. The Panel on US Wheat Gluten, interpreted the phrase "in such increased quantities" as follows:
 - "8.31 [Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1[of the Agreement on Safeguards ("SA")] do not speak only of an 'increase' in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the 'increase' in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body's finding in Argentina Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury."

39. The analysis of the increased imports of the product under consideration has been conducted in the light of the above mentioned law and WTO jurisprudence.

Increased Import in absolute terms:

- 40. The analysis of the trend in imports of PUC in the light of the above mentioned provisions has been done. PUC is imported into India from a number of countries including China PR, Russia, Ukraine, Japan and Korea. Interested parties raised objections that imports of the subject goods are not sudden enough, sharp enough, significant enough and recent enough within the meaning of Article XIX of GATT and SA and therefore, safeguard duty is not warranted in this case.
- 41. In this regard, I find no merit in the objection from the interested parties as the analysis by taking into account DGCI&S import data for the Period of Investigation (up to 15-16 Q1) reveals as under:

Financial Year	Total Imports (MT)	Trend
2013-14	1252441	100
2014-15	2644911	211
2015-16(Q1)	881233	
2015-16(A)	3524932	281

42. It is apparent from the data in the table above that there is a surge in import in absolute terms i.e Import increased from 1252441 MT during the period 2013-14 to 3524932 MT during 2015-16 (Annualised).

Import in relation to Production:

43. The imports of product under consideration in India during the period of investigation have increased in relation to all Indian production. The import with respect to total production increased from 5% in 2013-14 to 13% in 2015-16(A).

Financial Year	Total Imports (MT)	All India Production (MT)	% of import with respect to production
2013-14	1252441	25510777	5
2014-15	2644911	26395795	10
2015-16(Q1)	881233	6646258	
2015-16(A)	3524932	26585032	13

44. It is apparent from the above that there is a sudden, sharp and significant surge in imports during the Period of Investigation, both in absolute terms as well as in relation to total domestic production.

G. <u>Determination of Serious Injury and Threat of Serious Injury:</u>

45. Section 8B subsection 6(c) of Customs Tariff Act, 1975 provides as follows:

"Serious injury" means an injury causing overall impairment in the position of a Domestic Industry;

- 46. Section 8B sub section 6(d) of Customs Tariff Act, 1975 provides as follows:
 - "threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.
- 47. The Paragraph 1 of Annex to Rule 8 of the Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 provides as follows:

"In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment."

- 48. With regard to the overall impairment in the position of the industry, the Appellate Body in Argentina—Footwear (EC),in contrast to the Panel, held that an evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining" to justify a finding of serious injury. Relevant extract is as follows:
 - "139. In our view, it is only when the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry, that it can be determined whether there is "a significant overall impairment" in the position of that industry. Although Article 4.2(a) technically requires that certain listed factors must be evaluated, and that all other relevant factors must be evaluated, that provision does not specify what such an evaluation must demonstrate. Obviously, any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant declines in sales, employment and productivity that will show "significant overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of whether the competent authorities in a particular case have evaluated all the listed factors and any other relevant factors, we believe that it is essential for a panel to take the definition of "serious injury" in Article 4.1(a) of the Agreement on Safeguards into account in its review of any determination of "serious injury".
- 49. Accordingly, in analysing serious injury or threat of serious injury all factors, which are mentioned in the Rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry which are as under:
 - a. **Production**: As seen from the table below, the production of the Domestic Industry marginally decreased from 17881187 MT in 2013-14 to 17827180 MT in 2015-16(A).

YEAR	Production of DI (MT)	Trend
2013-14	17881187	100
2014-15	17836937	100
2015-16(Q1)	4456795	
2015-16(A)	17827180	100

b. Changes in the level of Sales: It is seen from the table below that the sales of the Domestic Industry decreased from 1,03,42,565 MT in 2013-14 to 99,49,214 MT in 2014-15. Further the Sales of the applicant during 2015-16 (A) increased to 1,03,59,716 MT as seen from the table below. There is not much variation in the level of sales.

Financial Year	Total Import (MT)	Sales of DI (MT)	Sales of other Indian Producers (MT)	Captive sale of DI(MT)	Captive sale of Others (MT)	Total Demand (MT)		xet Share (%)
							DI	Import
2013-14	12,52,441	1,03,42,565	29,94,323	42,74,000	40,00,724	2,28,64,053	45	5
2014-15	26,44,911	99,49,214	32,98,273	50,19,741	46,15,864	2,55,28,003	39	10
2015-16(Q1)	8,81,233	25,89,929	10,65,972	13,21,497	11,80,681	70,39,312		
2015-16(A)	35,24,932	1,03,59,716	42,63,888	52,85,988	47,22,724	2,81,57,248	37	13

c. **Market Share:** It is seen from the table above that the Imports had a market share of 5% in 2013-14 which increased to 13% during 2015-16(A) whereas the market share of Domestic industry decreased from 45% to 37% during the same period.

d. Capacity Utilisation: Capacity utilization of the Domestic Industry has remained more or less the same, as seen from the table below:

Financial Year	Installed Capacity (MT)	Capacity Utilisation (%)
2013-14	23568996	75.9
2014-15	23568996	75.7
2015-16(Q1)	5884372	
2015-16(A)	23537488	75.7

e. **Employment & Productivity:** The trend of employment and productivity has remained same over the injury period, as seen from the table below:

Financial Year	No. of Employees (Indexed)	Productivity per employee(MT) (Indexed)
2013-14	100	100
2014-15	100	100
2015-16(Q1)	100	
2015-16(A)	100	100

f. **Profit & Loss (Indexed):** The profitability of the Domestic Industry has declined sharply during 2015-16 (Q1) and domestic industry recorded losses. This is evident from the table below:-

Financial Year	Profitability (Rs. /MT) (Indexed)
2013-14	100
2014-15	136
2015-16(Q1)	(114)

g. Other Important Factors:-

(i) **Inventories:** Inventories have marginally increased from 100 Points in 2013-14 to 103 Points in 2015-16 (Q1), as seen from the table below:

F' '137		Inventory (MT)
Financial Year	Inventory (MT)	(Indexed)
2013-14	636879	100
2014-15	648290	102
2015-16 (Q1)	657099	103

(ii) Price undercutting, suppression/depression:

a. The landed price of imports has been calculated by taking in to consideration the customs duty @7.5% for the period from April, 2013 to March, 2015 & @10% (on average) for rest of the period on assessable value of import and then adding duties to CIF value of import which reveals that the domestic Industry was always under consistent pressure to either reduce their prices to match the import prices or to hold on to their prices. The penetration of increased imports at an unprecedented high level was such that even after reducing the prices, the domestic industry was not able to keep on to

its market share. This has resulted into losses during 2015-16(Q1) for the domes	ic industry. The
variation of landed prices of imports, cost of Sales, selling price are as under:-	

Components (Indexed)	Unit	2013-14	2014-15	2015-16 (Q1)
Cost of Sales	Rs./MT	100	97	94
Weighted average sales realisation	Rs./MT	100	99	83
Landed price of imports	Rs./ MT	100	95	78
Profit/ (Loss)	Rs./ MT	100	136	(114)

- b. It is seen from above that while the Index of cost of sales come down from 100 to 94, the landed price of imports declined sharply from 100 to 78 leading to reduction in sales realization which declined from 100 to 83. While comparing the sales realization vis-à-vis cost of sales, it is observed that the sales realization declined much more sharply than the cost of sales. There was as substantial decline in profitability index from 136 in 2014-15 to (114) in 2015-16 (Q1).
- 50. Examination of all of the above factors shows that while some of the factors such as capacity utilization, inventories, employment etc. remained stable, there was a sharp decline in profitability leading to losses and there was a decline in the market share of DI due to increased imports and decline in imports prices leading to serious injury by way of financial losses.
- 51. Interested parties have submitted that injury being suffered by the domestic industry is due to their own internal factors including the following:
 - High interest cost, depreciation and fixed cost burden
 - High freight cost and poor infrastructure
 - Raw material crisis
 - Under utilised capacities
 - Inability to meet the quality requirements of specific downstream industry
- 52. These claims are very general and without any facts and figures to support. The fact that injury has been caused due to increased quantities of imports of the PUC in India has already been established above. I find that the domestic industry has been in existence since many years and has been doing well in the past. Infrastructure and capacities are in place with the domestic industry to meet the demand of the PUC. The efficiency of a unit depends on several factors and if their efficiencies were of a higher order, probably there was no need for the DI to ask for safeguard action. Mere existence of inefficiencies in certain areas cannot be a reason to deny safeguard protection to the Domestic Industry. The very reason why safeguard protection is sought and given and is provided for under SA is that the DI is unable to handle competition and can get some time to adjust to the International competition over a period of time. The main determining factor is that there should be a serious injury or threat of serious injury and there is a causal link with the increased imports. I observe that there is a significant increase in imports of the subject goods which have caused serious injury to the domestic industry which has been duly substantiated in the foregoing paras.
- 53. Further, POSCO Maharashtra has contended that the surge in imports in 2014-15 is mainly because of imports by them for further use in manufacturing activity in India and if the same is excluded, there would be a slump in imports. In this regard it has been observed that imports have surged not only in 2014-15 but also in Q1of 2015-16. Moreover, POSCO has stated that it has made most of the imports during the first two quarter of 2015-16. HRC by its very nature is a raw material for the downstream industry and mostly has uses only for further manufacturing. So, POSCO's case is no different from other consumers of HRC and therefore, the imports made by them cannot be excluded from the total while determining the increased imports.
- 54. Captive consumption of product under consideration: Several interested parties have argued that captive imports by downstream units should be exempt from safeguard duty. Mostly, these claims have been raised by companies like POSCO Korea and POSCO Maharashtra, and Hyundai Steel Korea and its Indian affiliates. In this regard I find that there is no provision under law that exempts goods imported for captive consumption from the purview of safeguard duty.
- 55. <u>Inconsistency with FTAs and other bilateral agreements</u>: Interested parties argue that import duties on PUC are about to be eliminated in India-Korea CEPA and India-Japan CEPA. Therefore, it is argued that India should not have levied

safeguard duty on imports of the subject goods from Korea RP and Japan as these imports have occurred due to low customs duty on imports from these countries. It is also argued that India could have explored bilateral mechanisms with these two countries under the respective FTAs rather than simply imposing general safeguard duty on Korea RP and Japan. Interested parties also argue that India-Korea CEPA provides that in the event imports from Korea RP are not the reason of injury to the domestic industry, such imports should be excluded from imposition of safeguard duty. Domestic industry submitted that imports from both Korea RP and Japan have caused serious injury to the domestic industry. I observe that it is immaterial that imports from Korea RP and Japan increased due to low customs duty under the respective FTAs. Imports from these two countries have occurred in huge quantities in the most recent period and these imports are at very low prices causing serious injury to the domestic industry. Further, it is the discretion of the Government of India to explore bilateral mechanisms under the respective FTAs or adopt a general safeguard measure in this case. Both the FTAs nowhere mention that India is obligated to explore bilateral mechanisms first and only after failure of such mechanisms can adopt a general safeguard measure. The imports from non-FTA countries had also significantly increased, therefore, safeguard action under the FTA would have left the door open for non-FTA countries to further increase their exports. Secondly, the safeguard action on the FTA limits the safeguards duties only to the level not exceeding the MFN rates, which is not by itself sufficient to mitigate the present situation. It may be noted that these FTAs have specific provisions that allow India to impose general safeguard duty. The only exception under SA and Safeguard Duty Rules is exclusion of developing countries whose individual share in imports is below 3% and whose aggregate share in imports is below 9%. Korea RP and Japan do not fall under this exception, as both of them are developed countries.

- 56. From the above analysis it is seen that the demand for the PUC in India has increased in the injury analysis period. Despite increase in demand, the production, employment and sales of domestic industry have remained stagnant, while inventories have somewhat increased. Imports have taken away most of share of the increase in demand of the subject goods. In 2014-15, while demand excluding captive increased by 13,03,069 MT and imports increased much more by 13,92,470 MT. This shows the aggressive manner in which imports of the PUC are entering the Indian market. The domestic industry had raised its capacities foreseeing the increasing demand in India. However, the domestic industry is unable to increase its capacity utilization, production and sales. The profitability has gone down drastically and even turned to losses during 2015-16(Q1). The major reason for decline in profitability of domestic industry is the increased imports at reduced prices. If the same trend continues, the domestic industry fears that they would be forced to shut down their operations.
- 57. The imports of the PUC have increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India. As a result of the significant surge in imports, the Domestic Industry has suffered serious injury. Domestic Industry has performed inversely to the imports, with deterioration in finances from profits to losses.
- 58. Thus, an evaluation of the overall position of the DI, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of the DI, shows a 'significant overall impairment'. It is thus concluded that Domestic Industry has suffered serious injury as a result of increased imports of the PUC.
- 59. There is a serious injury to the domestic industry due to the surge of imports and the most recent trend of import volumes entering India. The volume of imports continues to increase, despite already being at high levels. The market share of imports has also substantially increased over the period. Considering the surplus production capacities available with the foreign producers, the imports will continue to increase, as is evident from the post POI analysis at Para-100 resulting in further injury to the domestic industry. The likelihood of further increased import leads to a conclusion that there is a threat of further serious injury to the domestic market. In view of the fact, that the domestic industry is unable to make profitable sales in the Indian market, I am of the view that in absence of levy of safeguard duty, the Domestic Industry faces serious injury and a further threat of greater serious injury.

H. Other issues raised by the interested parties:

- 60. Applicability of safeguard duty on those hot-rolled flat products in coil form for which contracts were entered into before levy of provisional safeguard duty: Some of the interested parties are of the view that for contracts for which LCs were recently opened before the imposition of provisional safeguard duty should be exempted from safeguard duty as they are of the view that imposition of provisional safeguard duty was unforeseen and the impact of additional duty would be harsh. However, I find there is no provision under the law that allows such exemptions.
- 61. Other procedural issues in the investigation: A number of interested parties have expressed concern that India took time to notify the WTO, about the imposition of provisional safeguard duty. Interested parties have also submitted that provisional safeguard duty was imposed in haste without giving an opportunity to be heard. In this regard it is observed that there was a slight delay, however, it would not mean that imposition of provisional safeguard duty per se is

inconsistent with provisions of Article 12.4 of SA. A slight delay in meeting with the procedural requirement such as notifying WTO does not by itself compromise with the substantive merits of the provisional safeguard duty.

62. Rule 9(1) of the Safeguard Duty Rules allows the Authority to proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, record a preliminary finding regarding serious injury or threat of serious injury. As critical circumstances existed in this case, the preliminary findings were issued. Under such circumstances, it is not mandatory for the designated authority to conduct a public hearing or hold any consultations with other interested parties before taking provisional safeguard action. I find that the action is well within the ambit of provisions of SA.

I. Causal Link between Increased Import and Serious Injury or Threat of Serious Injury:

63. As per Rule 8 of the Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997, The Director General(Safeguards) is obligated to "determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the principles laid down in Annex to the these rules". Further, paragraph 2 of the Annex requires the establishment of causal link between alleged increased imports and serious injury or threat thereof. The Paragraph 2 of Annex to Rule 8 provides as follows:

The determination referred to in paragraph (1) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports.

64. The Panel on Korea — Dairy set forth the basic approach for determining "causation":

"In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the domestic industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports. To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the imports of some injury to the domestic industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the domestic industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors."

- 65. For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry have been evaluated. A comprehensive evaluation of parameters enumerated in preceding paras demonstrates that serious injury and threat of serious injury is being caused by increased imports. In the instant case, the following are relevant in this regard, when comparing the figures from 2013-14 to 2015-16 (annualized on the basis of Q1):
 - i) The volume of imports has increased significantly from 100 points (1252441MT) to 281 points (3524932MT).
 - ii) Market share of imports has increased from 5% to 13% and, consequently, market share of the Domestic Industry has declined from 45% to 37%;
 - iii) The decreasing import prices are preventing the Domestic Industry from sustaining its prices;
 - iv) Due to increased imports on low prices, the Domestic Industry is unable to increase its production and sales as compared to the rate of increase in demand/consumption of product under consideration in India:
 - v) The profitability of the Domestic Industry has declined sharply during 2015-16 (Q1) and domestic industry recorded losses due to increased imports.
- 66. In view of the above I find that there is a direct correlation between the increase in imports and serious injury suffered by the domestic industry as import in absolute term increased approximately three times during the year 2015-16(Annualised on the basis of Q1) as compared to base year 2013-14 and domestic industry is losing market share which has declined from 45% to 37%. The landed price of imports per ton has declined sharply. Consequently, the domestic industry has suffered losses. It is, thus, evident that injury to the domestic industry has been caused by the increased imports.

J. Adjustment Plan:

- 67. Rule 5(2) (b) of the Safeguard Duty Rules requires the DI to submit a statement on "efforts being taken or planned to be taken or both to make positive adjustment to import competition". Further Article 7.1 of WTO Agreement on Safeguard provides that a member shall apply safeguard measure only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment.
- 68. The purpose of a definitive safeguard measure is to provide the domestic producers a limited period of time to restructure themselves for effectively competing with the imports. Section 8B(4) of the Customs Tariff Act, 1975 and Rule 16(2) of the Safeguard Duty Rules prohibits any possible extension of a measure if there is no evidence that the domestic producers are adjusting.
- 69. The domestic industry has submitted detailed adjustment plans along with the respective domestic producers' questionnaire, showing year-wise projected savings. A brief of the adjustment plans laid down is as under:

a. Steel Authority of India Limited

- i. Savings in procurement costs of coking coal, iron ore, fluxes and ferro alloys;
- ii. Optimising the raw material linkages to the plants for minimizing the landed cost and minimizing procurement cost of various items like stores and spares, refractories, rolls, lubricants, etc.
- iii. Improving the operating efficiency of available assets;
- Reduction in coal blend cost by increase in usage of imported soft coking coal in each plant as a replacement of imported hard coking coal and maximize production/use of coking coal from captive washeries;
- v. Reduction in gross metallic input and enhancing concast production
- vi. Reducing the cost of power and other fuels by maximising recovery of gases like CO gas, BF Gas and LD gas to replace boiler coal in captive/JV power plant
- vii. Improvement in the efficiency of different processes by improvement in the yield of blooming mill/slabbing mill etc.
- viii. Modernisation plans in SAIL will lead to increase in volume of production, productivity, improvement in yields, conservation of energy and improvement in product quality.

b. Essar Steel Limited

- Commissioning of multi fuel power plant at Hazira will help in reduction in costs by utilisation of surplus Corex gas and coal fines;
- ii. The high quality of iron ore fines from mines acquired under the government auction scheme will provide flexibility to enhance the quality of raw material and thereby improve the productivity and lower the cost;
- iii. Essar plans to acquire mines nearby its established beneficiation and pellet facilities located in Odisha and utilise slurry pipeline to transport the same. Use of slurry pipeline for transport will have significant costs savings;
- iv. Commissioning of pellet plant 2 in Paradeep will increase in-house availability of pellets at lower costs;
- v. Commissioning of captive coke oven will result in reduction in cost of coke and consistent quality;
- vi. Reconfiguring the technological units and installing related facilities to reduce dependence on natural gas and improving steelmaking capacity.

c. JSW Steel Limited

- i. Reduction of fuel consumption by improving hot blast temperature, increasing Eta CO;
- ii. Reduction in logistics cost by reduction in idle freight, extra movement from Goa & reduced movement from Mangalore Port, etc.;
- iii. Savings in LPG consumption by changing flare stack burners at SMS 1 from LPG to coke oven gas;
- Improvement in HSM yield by reduction of cobbles and reduction in scale loss, salvage loss, and cropend loss;
- v. Commissioning of new line from Steel Melt shop to Corex gas holder for better LD gas recovery;
- vi. Reduction in solid fuel in sinter plants by using CDQ fines in micro pellets;
- vii. Reduction in anthracite consumption at sinter, reduction in aluminum consumption;
- viii. Intense condition monitoring, preventive maintenance and predictive breakdown maintenance.
- 70. It was further stated by the domestic industry that owing to the above adjustment plans, the companies would be in a fair position to reduce their cost significantly leading to better margins & increase in sales realization. I find that the

applicants have provided viable adjustment plans which focuses on cost reduction, optimum utilization and expansion of production capacities which will enable them to adjust to the international competition.

K. <u>Unforeseen developments:</u>

- 71. The Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT obligates the national authorities to examine the "unforeseen developments" which led to the serious injury to the Domestic Industry. It is, therefore, considered important to examine the unforeseen developments or circumstances which have led to increased imports.
- 72. The Appellate Body in Argentina Footwear (EC case) held that the phrase Unforeseen Developments means the developments which were unexpected. 'Unforeseen developments' require that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been 'unexpected'.
- 73. The Appellate Body, in Argentina Footwear (EC), then held that the requirement of "unforeseen developments" did not establish a separate "condition" for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of "circumstances":
- 74. The panel on US- Steel Safeguards concluded that the confluence of several events can unite to form the basis of an unforeseen development:
 - "The United States argues that the robustness of the US dollar was a development which combined with the other developments, namely, the currency crises in Asia and the former USSR and the continued growth in steel demand in the United States' market as other markets declined, lead to increased imports."
- 75. The applicant has pointed out that Steel manufacturers in a number of countries including China PR, Russia, Ukraine, Japan and Korea have developed huge capacities to cater to demand of steel by developed countries and rest of the world. Most of the developed countries that were traditionally the biggest importers of steel such as United States and the European Union have reduced their dependence on imported steel. This development adversely affected exports of steel from China PR, Russia, Ukraine etc. to developed countries. Manufacturers in these countries had to think of ways to dispose off their production. India being a growing economy happened to be one of the natural choice for these manufacturers to offload their excess capacity.
- 76. As per a report by a reputed journal Steel360, Russian steel exporters have been experiencing high realization for their exports due to their currency that has weakened in the recent past. Weakening of currency arising due to drop in oil prices was unforeseen. A weak currency has led to an export push by Russian steel. Further, the Russian exporters have faced, due to conflict in Ukraine, a restricted access to traditional markets like the European Union and Ukraine resulting in export push to India. All these developments are unforeseen.
- 77. As a result of political unrest in Ukraine due to Russia's intervention, there was a sharp depreciation of about 60% in the currency of Ukraine "Hryvnia" during 2014 alone. This was an unforeseen development. Due to long period of unrest in Ukraine, its economy contracted and its currency sharply depreciated to US dollar. However, depreciation in Ukraine's currency helped its steel producers/exporters to leverage their low priced exports to put further pressure on the global steel market. It is well documented in many leading international newspapers and journals how Ukraine has joined Russia and China PR to drive down steel prices and divert its surplus steel to countries with good demand.
- 78. China PR is experiencing weak domestic demand after a sustained growth rate for last many decades. This drop in growth rate was sudden and unexpected/ unforeseen. Infrastructure sector, mainly housing, which has been the biggest consumer of steel in China PR is going through a slowdown. Manufacturers in China PR can no longer dispose off their production in the domestic market. As a result China has an excess capacity of a few hundred million tones. This situation is likely to remain unchanged in the short term and Chinese steel use will continue to record a negative growth of -0.5% in 2015 and 2016. As a result, exports to countries like India are a natural choice as demand of steel has been on the rise in India. Such intrinsic factors in China PR led to sudden surge of imports from China PR.
- 79. Many interested parties are of the view that Petitioners have failed to identify unforeseen developments that led to increase in imports of the subject goods. Some interested parties claim that even the Authority has failed to discuss unforeseen developments in the preliminary findings and a few interested parties also claim that unforeseen developments have been identified but do not correlate with the subject goods. Some interested parties are of the view that depreciation of Indian Rupee and local procurement by users offset unforeseen developments. In this regard I find that the petition explains in detail all the unforeseen developments that led to sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the PUC that caused or threaten to cause serious injury to the domestic industry. The preliminary

findings and the present findings also discuss these unforeseen developments in sufficient detail which are well reasoned.

80. Some of the interested parties are of the view that the Authority should examine in terms of Article XIX of the GATT how as a result of the effect of obligations incurred by India under GATT, including tariff concessions, imports of the PUC increased in sudden, sharp, significant and recent manner. Though the Safeguard Duty Rules and the Agreement on Safeguards do not mandate the Authority to conduct such analysis, the obligation to do so, however, arises from Article XIX of the GATT. The Appellate Body has observed the following in this respect:

The phrase "of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions" means that it must be demonstrated, as a matter of fact, that the importing Member has incurred obligations under the GATT 1994, including tariff concessions...

(WTO Appellate Body Report in Korea — Dairy)

- 81. In this regard, I find that India's bound rates on PUC as per its Schedule of Concessions to the WTO is 40% ad valorem. It is further observed that India has been reducing its applied tariff rates on goods across many sectors. The sole purpose of this exercise is to encourage international trade so that India better assimilates into global trade. This is particularly true for the PUC for which India had a reduced applied rate of 7.5% in 2013-14 and 2014-15. It can been seen that due to the effect of such low applied tariffs, there was a chance for the imports of the PUC, under the present circumstances and market conditions to actually increased in sudden, sharp, significant manner into India.
- 82. It is clear from the above discussion that as a result of unforeseen developments and as an effect of obligations under GATT including tariff concessions, imports of the PUC has increased in a sudden, sharp, significant and recent manner into India.

L. Public Interest:

- 83. Article 3.1 of the Agreement on Safeguards states as follows:
 - "A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law."
- 84. Some interested parties are of the view that downstream industry would be hurt by imposition of safeguard duty. They have also contended that imposition of safeguard duty would result in increase in imports of downstream products.
- 85. In this regard, I observe that there is a sizable downstream industry in India that processes the HR Coil to produce CR Coil, GP/GC sheets, Pipes & Tubes, Color Coated Sheets etc. Steel is a basic raw material and it is consumed in a large number of products such as automobiles, machinery, infrastructure, construction, oil and gas industry etc. Therefore, any increase in price of HR Coils has an impact on the downstream industries. Safeguard duty imposed on HR Coil without imposing any duty on the downstream products will impact the value adding downstream Industry in India. Imposition of safeguard duty will add to the cost of production of these goods. Further, Safeguard duty on raw materials alone, without giving a similar cover to the downstream industry creates an inverted duty structure that makes downstream products expensive and makes it relatively cheaper to import. This would be particularly true in case of industry where HR Coil is a major constituent and cost of the input. Industry such as CR Coil, Pipes and tubes etc that have HR Coil as its major cost would be most affected. Due to these reasons profitability of these downstream industries would be significantly affected.
- 86. Imposition of safeguard measures would also affect small exporters of engineering goods who source their requirements of HR Coils from local suppliers and importers. With imposition of safeguard duty, HR Coil as a raw material would be more expensive. Also, there is no general rate of duty drawback that takes care of the impact of safeguard duties. This would render these exporters less competitive in the world market.
- 87. On the other hand, public investments of lakhs of crores in the steel industry is at the risk of becoming Non performing Assets. Therefore, adequate cover of protection to the DI is also desirable. If unattended, both the prices and market share of domestic industry will further decline, resulting in financial losses to the domestic industry to the extent of

getting the domestic industry unviable with possible loss of employment as well as loss of strategic and economic interest of the country.

88. Therefore, Imposition of safeguard duty at a reasonable level would be in order as it is in the consumers' long term interest to have a competitive and vibrant Indian domestic industry capable of supplying the product under consideration to the consumers and be able to compete with foreign producers. This is possible only when the domestic industry is able to get some temporary support for the injury suffered due to the increased imports. It is in the interest of the public at large to have a strong, competitive Indian domestic industry.

M. Developing Nations:

89. The percentages of imports from developing nations have also been examined for the period 2013-14, 2014-15 & 2015-16(Q1). Except China PR and Ukraine which constitutes 24% & 4% of total imports into India respectively, other developing nations individually and collectively have less than 3% and 9% share respectively of total imports into India. Therefore, in terms of Notification No.103/98-cus dated 14-12-1998 read with Notification No.19/2016-Customs (N.T.) dated 05-02-2016, imports of the product under consideration originating from developing nations except China PR and Ukraine will not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B (1) of the Customs Tariff Act, 1975.

N. Provisional Measures:

- 90. In the Preliminary Findings, it was held that increased imports of PUC have caused and threatened to cause serious injury to domestic producers of PUC. It was also observed that critical circumstances existed, where any delay in application for safeguard measures would cause irreparable damage to the industry. Considering the serious injury suffered by domestic industry during the first quarter of 2015-16 in a number of injury parameters as explained in the paragraphs above, it is held that the provisional measures were justified in this case in order to thwart the possibility of irreparable damage. The final findings are now being issued after considering the views of all the interested parties and DI.
 - O. Reply to the specific objections raised by Foreign Governments/ Embassies which are not discussed in above findings:

Republic of Turkey

- 91. Turkey contends that it should be excluded from the purview of safeguard duty as it is a developing country. In this regard, I find that India in terms of Notification No. 103/98-Cus dated 14th December 1998 does not recognise Turkey as a developing country. However, vide Notification No.19/2016-Customs (N.T.) dated 05.02.2016, Turkey has been included in the list of developing country and its share being less than 3% of total imports into India during the period 2013-14 to 2015-16(Q1), imports of the product under consideration originating from Turkey will not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B (1) of the Customs Tariff Act, 1975 w.e.f. 05.02.2016.
- 92. With regard to Turkey's contention that notifications by India to the WTO do not contain a reasonable or adequate explanation/analysis concerning the existence of unforeseen developments is not accepted. I find that in the preliminary findings dated 09/09/2015 in the matter, all the parameters have been clearly examined and discussed including unforeseen developments in this case.

Chinese Taipei

93. Taiwan contended that its name does not feature in the list of developing countries notified vide Notification No. 103/98-Cus dated 14 December 1998 and requested to update the aforesaid notification so that Taiwan's economic status as a developing country is reflected correctly so that exemption available to developing countries is available to them. However, since Taiwan is not recognised as a developing country so far by Government of India under Notification No. 103/98-Cus dated 14-12-1998 read with Notification No.19/2016-Customs (N.T.) dated 05.02.2016, the benefit of exemption to developing countries would not be available to Taiwan.

Embassy of Ukraine

94. Ukraine has examined the parameters on end-to-end basis for the period 2011-12 vis-à-vis 2014-15 and contended that the import is not significant enough to cause or threaten to cause serious injury, Industry indicators show positive trends for domestic sales, production, market share, capacity, capacity utilization and there is no causal link in this case

in terms of Articles 2.1 and 4.2(b) of the SA, as injury to the domestic industry is due to loss of market share to other domestic producers. In this regard, the contention of Ukraine is not accepted as the period of investigation has been taken from 2013-14 to 2015-16 (Annualised on the basis of Q1) and during this period the imports of PUC have shown an increasing trend, whereas, the domestic indicators like market share and profitability show negative trends as discussed in the foregoing paras. The question as to what is an acceptable period to consider for determining injury, the issue has been discussed in detail in Para-30. As such there is no bar in taking a particular period of investigation so long as the injury analysis also pertains to that period and the surge in imports is recent and significant.

European Commission

- 95. The Commission has submitted that safeguard instrument should be used in exceptional circumstances only and the present case is suitable for anti-dumping or anti-subsidy investigation. In this regard, I find, that at present, the Indian steel industry is going through a very critical phase due to sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods. The Indian steel producers are suffering serious injury due to such imports as a result of unforeseen developments as discussed in the foregoing paras. I find that the safeguard duty has been correctly recommended and which has been done in order to protect them f from the sudden surge in imports.
- 96. With regard to the Commission's contention that certain specific grades of the subject goods should be excluded from the product scope as the domestic industry may not be manufacturing them, I observe that the Commission has not identified the specific grades the domestic industry does not produce, for which exclusions are required. In the absence of information on specific grades, the domestic industry is not in a position to respond to their contention and hence no action can be taken on the suggestion of the Commission.
- 97. The Commission argues that captive sales and sales by other domestic producers should be examined. The Commission further adds that other Indian producers have increased their open market sales by 42%. In this regard, I observe that the market share of other Indian producers has increased by 2% whereas, the market share of domestic industry has decreased by 2% during the period 2014-15 & 2015-16 (Q1). [Para-49(b) of the finding]. Moreover, imports have taken away all the increase in demand of the subject goods. In 2014-15, demand (excluding captive) increased by 1303069 MT and imports increased by 1392470 MT.

Republic of Brazil

- 98. Brazil contends that since India has failed to notify imposition of provisional safeguard measure prior to its imposition, India failed to satisfy the requirements under Article 12.4 of the SA. In this regard, I am of the opinion that a procedural requirement such as notification to the WTO does not compromise the substantive merits of the provisional safeguard duty. This issue has been discussed in detail in Para-61.
- 99. Brazil has raised the issue that the share of each exporting country has not been informed by the Authority and a list of developing countries has also not been provided. Brazil also argues that the period taken into account for calculation of the volumes imported from each source has not been specified. Due to lack of such essential information, Brazil argues that it has not been able to exercise its right of defence under Article 3.1 of the SA. In this regard I observe that the country-wise transactions of imports into India provided by the domestic industry alongwith its application were circulated to all interested parties while circulating the Notice of initiation in the matter. The same documents have also been placed in the public file for inspection by the interested parties. There is, thus, no inconsistency in terms of Article 3.1 of the SA. Further, since Brazil's share of imports has been determined to be not more than 3% in total imports during the period 2013-14, 2014-15 & 2015-16 (Q1), imports of PUC from Brazil is excluded from the purview of safeguard duty.

P. Examination of Post POI data:

100. In the given circumstances, an attempt was made to analyse the trend in the period after the POI i.e. upto 2nd quarter of 2015-16 to draw a clear inference about the possibility of accentuation of the injury to the domestic industry. The domestic industry vide their post Public Hearing submissions submitted the domestic data pertaining to certain economic parameters for the subject "product under consideration" imported into India. The data analysis is as under:

	2013-14	2014-15	2015-16 (Annualised on the basis of Q1)	2015-16 (Annualised on the basis of Q1+Q2)
Total Imports (MT)	1252441	2644911	3524932	4587168
Production (MT)	17881187	17836937	17827180	16796006
Domestic Sales(MT)	10342565	9949214	10359716	10504640
Total Demand(MT)	22864053	25528003	28157248	30268388
Market Share of Import(%)	5	10	13	15
Market Share of DI(%)	45	39	37	35
Inventory(MT)	636879	648290	657099	871440
Profit/ (Loss) (Indexed)	100	136	(114)	(120)

101. On scrutiny of the above data it is observed that during the post POI i.e 2015-16(Q1+Q2)(Annualised), between the period Q1 to Q2, there is a increase in the imports by about 30%. The market share of imports have increased by about 2% as against the corresponding decline of the market share of the domestic industry by about 2%. Further, there is a decline of about 6% in production whereas domestic sales increased only by approximately 1% during the post POI. This shows that the industry parameters deteriorated sharply between Q1 and Q2 of 2015-16.

Q. Conclusion:

- 102. On the basis of the above examination and analysis done, it is concluded that:
 - There has been a significant increase in imports of the PUC in absolute terms as well as in relation to domestic
 production over the entire POI. This surge in imports is also quite significant in relation to total demand as
 well.
 - ii. The investigation has indicated that the domestic industry has suffered serious injury, considering overall performance, on the basis of listed economic parameters such as market share, and profitability, which have sharply declined from the base year till 2015-16(Annualised) whereas market share of imports have increased during the same period. This has caused significant overall impairment to the domestic industry. This establishes causal link between the rise in imports and serious injury caused to the domestic industry during the POI.
 - iii. The domestic industry has been able to demonstrate that the developments in the market for surge in imports of the PUC were unforeseen.
 - iv. There will be a negative impact on the downstream industry as a result of safeguard duty on the PUC which is a raw-material for them.
 - v. It is also established that imposition of safeguard duty in this case would be in public interest because it will aid in recovery of the domestic industry and ensure that end users get a stable supply of subject goods from the domestic industry.
 - vi. From the analysis of post POI data, it has been observed that the position of domestic industry further deteriorated on account of production, sales & market share. Thus, I conclude that serious injury/ threat of serious injury exists and further protection to the domestic industry is required to be extended.

R. Recommendations:

a. The increased imports of 'PUC' into India, have caused serious injury and are threatening to cause serious injuries to the domestic producers of "PUC" and it will be in the public interest to impose safeguard duty on imports of "PUC" into India in terms of Rule 12 of the Customs Tariff (Identification And Assessment of Safeguard Duty) Rules'97, for a period of two Years and Six months. This period shall be computed from the date of levy of provisional safeguard duty vide notification no.2/2015-Cus (SG) dated 14.09.2015.

Considering the average cost of sales of "PUC" by the domestic producer after allowing a reasonable return on cost of sales, safeguard duty as indicated below, which is considered to be the minimum required to protect the interest of domestic industry on PUC being imported falling under sub-heading 7208 and 72253090 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975, is recommended to be imposed.

Year	Safeguard duty recommended	Period
First Year	Safeguard duty @ 20% ad valorem (minus Anti-dumping duty, if	14.09.2015
	any).	to
		13.09.2016
Second Year	Safeguard duty @ 18% ad valorem (minus Anti-dumping duty, if	14.09.2016
(For first 6-months)	any).	to
		13.03.2017
Second Year	Safeguard duty @ 15% ad valorem (minus Anti-dumping duty, if	14.03.2017
(For next 6-months)	any).	to
		13.09.2017
Third Year	Safeguard duty @ 10% ad valorem (minus Anti-dumping duty, if	14.09.2017
(For 6-months)	any).	to
		13.03.2018

b. As the imports from developing nations except China PR and Ukraine do not exceed 3% individually and 9% collectively, the import of product under consideration originating from developing nations except China PR and Ukraine will not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B (1) of the Customs Tariff Act, 1975. Turkey vide Notification No. 19/2016-Customs (N.T.) dated 05.02.2016 has been recognised as a developing nation. Therefore, Imports of the product under consideration originating from Turkey will not attract Safeguard Duty w.e.f. 05.02.2016.

[F.No. D-22011/26/2015/Pt-III]

VINAY CHHABRA, Director General